



विदेश मंत्रालय
नई दिल्ली
वार्षिक रिपोर्ट 2024





सत्यमेव जयते

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली

वार्षिक रिपोर्ट 2024



प्रकाशित:

नीति नियोजन एवं अनुसंधान प्रभाग, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली

यह वार्षिक रिपोर्ट वेबसाइट पर भी देखी जा सकती है। www.mea.gov.in

अभिकल्पन एवं मुद्रण:

क्रिएटिव ऑफसेट प्रेस # 9136434848

विषय सूची

परिचय और सार-संक्षेप (सिनोप्सिस)	4
1. भारत के पड़ोसी देश	32
2. हिंद महासागर क्षेत्र	55
3. दक्षिण पूर्व एशिया और ओशिनिया	61
4. पूर्व एशिया	77
5. यूरेशिया और शंघाई सहयोग संगठन	82
6. जीसीसी, पश्चिम एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका	92
7. अफ्रीका	118
8. यूरोप और यूरोपीय संघ	139
9. अमेरिका	174
10. हिंद प्रशांत क्षेत्र	201
11. बिम्स्टेक और सार्क	206
12. संयुक्त राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन	208
13. जी 20	227
14. बहुपक्षीय आर्थिक संबंध	230
15. निरस्त्रीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामले	233
16. आर्थिक राजनय	239
17. आतंकवाद का प्रतिकार	247
18. विकासीय सहयोग	249
19. नीति नियोजन एवं अनुसंधान	261
20. विधिक एवं संधियाँ	268
21. ई गवर्नेंस और आईटी	274
22. कांसुलरी, पासपोर्ट एवं वीजा सेवाएं	275
23. उत्प्रवास नीति, कल्याण और प्रवासी भारतीय समुदाय की सहभागिता (विदेशी भारतीय मामले)	280
24. राज्य प्रभाग	287
25. नई उभरती और रणनीतिक प्रौद्योगिकियां (नेस्ट) और साइबर राजनय	289
26. नयाचार प्रभाग	292
27. बाह्य प्रचार-प्रसार एवं सार्वजनिक राजनय	295
28. प्रशासन, स्थापना, वैश्विक संपदा प्रबंधन एवं सूचना का अधिकार	300
29. राजभाषा नीति का कार्यान्वयन	303
30. वित्त एवं बजट	305
31. संसद एवं समन्वय प्रभाग	311
32. सम्मेलन एवं शिखर-वार्ताएं	313
33. त्वरित सहायता प्रकोष्ठ	314
34. सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान	319
35. भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद	322
36. नालंदा विश्वविद्यालय	325
37. अभिलेखागार और अभिलेख प्रबंधन	327
अनुलग्नक	329
संक्षिप्तीकरण	377

परिचय और सार-संक्षेप

2024 में भारत और विश्व व्यवस्था

वर्ष 2024 में भारत तेजी से विकसित हो रहे वैश्विक परिदृश्य में अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने में विश्व के साथ सक्रिय रहा। भारतीय विदेश नीति ने जीवंतता और प्रगति पर बल दिया जिससे महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुईं और भारत का वैश्विक कद एवं प्रतिष्ठा भी बढ़ी। समान विचारधारा वाले भागीदारों के साथ बहुपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय संबंधों को भारत की सक्रिय पहलों एवं नेतृत्व द्वारा बढ़ाया गया।

विदेश मंत्रालय (एमईए) ने भारत की विदेश नीति और प्रगतिशील लक्ष्यों की दिशा में वैश्विक राजनय को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। भारत अपनी नीति की स्वायत्तता का विस्तार करने और बहुपक्षीय संस्थाओं में सार्थक सुधार लाने में, वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित करने में तथा अपनी सुरक्षा को नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के ढांचे के भीतर सुरक्षित रखने में दृढ़ रहा। इन प्रयासों ने एक न्यायसंगत और समावेशी वैश्विक व्यवस्था को आकार देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।

इस वर्ष आर्थिक उतार-चढ़ावों, जलवायु परिवर्तन प्रभावों, भू-राजनैतिक तनावों, और वैश्विक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के क्षेत्रों पर लगातार चुनौतियों के साथ सामाजिक व्यवधानों का दौर रहा। भारत वैश्विक मंच पर सक्रिय रूप रहा और उसने प्रमुख वैश्विक चुनौतियों का समाधान उच्च स्तरीय चर्चाओं तथा सहयोग के माध्यम से किया। इसमें भागीदारों को मजबूत करना और संयुक्त राष्ट्र, जी20, जी7, क्वाड, और ब्रिक्स जैसे उल्लेखनीय क्षेत्रीय एवं वैश्विक समूहों में द्विपक्षीय तथा सक्रिय भागीदारियां शामिल थीं।

पूर्ववर्ती जी-20 के अध्यक्ष होने के नाते भारत ने ट्रोइका समूह (भारत, ब्राजील, और दक्षिण अफ्रीका) के तहत ब्राजील के साथ मिलकर काम करना जारी रखा। भारत की जी-20 अध्यक्षता के दौरान किए गए कार्यों को आगे बढ़ाते हुए, ब्राजील ने 2024 के लिए तीन प्राथमिकताओं को चिह्नित किया जिसमें मौटे तौर पर सामाजिक समावेशन, ऊर्जा परिवर्तन और बहुपक्षीय शासन संस्थाओं में सुधार लाना शामिल था। प्रधानमंत्री ने 18-19 नवंबर को रियो डी जेनेरियो में 19^{वें} जी20 शिखर सम्मेलन में सहभागिता की। प्रधानमंत्री के संबोधन को विकसित और विकासशील देशों द्वारा व्यापक सराहना प्राप्त हुई जिसमें उन्होंने मानव-केंद्रित, रचनात्मक और विकास-उन्मुख रहने की बात की। यह पहला जी-20 शिखर सम्मेलन था जिसमें अफ्रीकी संघ ने सितंबर 2023 में नई दिल्ली जी20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के उपरांत स्थायी सदस्य के रूप में भाग लिया।

अगस्त में, भारत ने वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के तीसरे संस्करण की मेज़बानी ओवरआर्चिंग थीम 'एन इम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर के तहत वर्चुअल मोड में की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्राध्यक्षों/शासनाध्यक्षों के सत्र का उद्घाटन किया और अपने संबोधन में वैश्विक दक्षिण में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक ढांचे के रूप में काम करने हेतु एक "वैश्विक विकास संधि" का प्रस्ताव रखा। इस समझौते में व्यापार, क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी साझाकरण और वित्तीय सहायता पर जोर दिया गया ताकि वैश्विक दक्षिण का सशक्तिकरण किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकास संतुलित और टिकाऊ, दोनों हो। राजनेताओं के सत्र के बाद दस मंत्रिस्तरीय सत्र आयोजित किए गए जिनमें स्वास्थ्य मंत्रियों, युवा मामले मंत्रियों, वाणिज्य/व्यापार मंत्रियों, सूचना एवं



नवंबर 2024 में रियो डी जेनेरियो में 19^{वें} जी-20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जोसेफ बाइडन और ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा



प्रधानमंत्री ने अगस्त 2024 में वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के तीसरे संस्करण के राजनेता सब को संबोधित किया

प्रौद्योगिकी मंत्रियों, ऊर्जा मंत्रियों, शिक्षा मंत्रियों, पर्यावरण मंत्रियों के सत्रों के साथ-साथ भारत के विदेश मंत्री (ईएएम) की अध्यक्षता में विदेश मंत्रियों के दो सत्र शामिल थे।

शिखर सम्मेलन में 123 वैश्विक दक्षिण देशों से 173 गणमान्य प्रतिनिधिमंडलों ने सहभागिता की जिनमें 21 राष्ट्राध्यक्ष/शासनाध्यक्ष तथा 34 विदेश मंत्री शामिल थे। यह पहला ऐसा बहुपक्षीय शिखर सम्मेलन था

जिसका आयोजन प्रधानमंत्री द्वारा ऐतिहासिक तीसरी बार चुनाव जीतने और नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद किया। नई सरकार के प्रथम 100 दिनों के भीतर आयोजित किए गए इस शिखर सम्मेलन में वैश्विक दक्षिण के सामूहिक विकास के उत्थान के प्रति भारत की ईमानदारी और प्रतिबद्धता को परिलक्षित किया गया और प्रधानमंत्री ने वैश्विक दक्षिण के नेताओं एवं देशों से बातचीत करने के लिए प्राथमिकता जताई।

इससे पहले जून में, प्रधानमंत्री ने इटली में जी7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में सहभागिता की और प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर वैश्विक नेताओं से चर्चा की। शिखर सम्मेलन में, प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि प्रौद्योगिकी मानव-केंद्रित दृष्टिकोण से निर्देशित होनी चाहिए, जिसके लिए उन्होंने सार्वजनिक सेवा प्रदान करने हेतु डिजिटल उन्नयनों का लाभ उठाने में भारत की सफलता को रेखांकित किया। उन्होंने वैश्विक प्रगति और कल्याण को बढ़ावा देने में एआई की भूमिका की वकालत करते हुए “ए आई फॉर ऑल” के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को उजागर किया। उन्होंने जी20 में अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने में भारत की भूमिका को याद करते हुए, वैश्विक दक्षिण, विशेष रूप से अफ्रीका की चिंताओं का प्राथमिकीकरण करने की महत्ता पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने भारत-इटली रणनीतिक भागीदारी को और अधिक मजबूती प्रदान करने हेतु इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी के साथ भी चर्चा की।

पूरे वर्ष, भारत ने आतंकवाद और उसके सभी रूपों एवं स्वरूपों से निपटने के लिए वैश्विक समुदाय के साथ सक्रियता से सहयोग किया और क्षमता निर्माण, आतंकवाद-रोधी क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान करने तथा सूचना साझा करने की दिशा में भागीदार देशों से बात की। इस वर्ष भारत ने क्वाड समूह के भीतर तथा फ्रांस, कजाकिस्तान एवं ऑस्ट्रेलिया सहित आतंकवाद की गतिविधियों से निपटने पर अपने भागीदारों से बातचीत करने हेतु विभिन्न आतंकवाद-रोधी कार्यसमूहों में भाग लिया। एफएटीएफ (फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स) म्यूचुअल इवेलुवेशन ऑफ इंडिया का आयोजन सिंगापुर में एफएटीएफ प्लेनरी के साथ जून में किया गया जिसमें

भारत की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया और एफएटीएफ प्लेनरी ने यह कहा कि भारत एफएटीएफ की अपेक्षाओं के तकनीकी अनुपालन के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। इससे यह स्पष्ट हुआ कि भारत की धनशोधन-रोधी, आतंकवाद के लिए वित्तपोषण और काउंटर प्रोलिफरेशन (सीपीएफ) नीति प्रभावशाली परिणाम प्राप्त कर रही है।

भारत ने वर्ष के दौरान तीन प्रमुख मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) कार्यक्रम चलाकर अपने पड़ोसी देशों तथा उनसे परे देशों में भी संकट के समय पर एक विश्वसनीय ‘प्रथम सहायताकर्ता’ के रूप में अपनी साख को सुदृढ़ किया है। नागरिक अशांति के बीच हैती से भारतीय नागरिकों को संकट से बाहर निकालने के लिए मार्च में ऑपरेशन इंद्रावती शुरु किया गया। जून में, कुवैत में एक विशेष मानवीय एयरलिफ्ट ऑपरेशन चलाया गया जिसके कारण 45 मृत भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर को वापस लाया गया। सितंबर में, म्यांमार में तूफान ‘यागी’ के कारण आई बाढ़ के बाद आपातकालीन मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए अभियान सद्भाव शुरु किया गया। इन अभियानों के अलावा, भारत ने वर्ष के दौरान 20 से अधिक देशों को एचएडीआर सहायता प्रदान की। 2024 में, भारत ने पश्चिम एशिया के संघर्षशील क्षेत्रों में मानवीय सहायता प्रदान करना भी जारी रखा। भारत ने सीरिया को कैसर रोधी दवाइयां पहुंचाई और संयुक्त राष्ट्र राहत एवं बचाव कार्य एजेंसी (यूएनआरडब्ल्यूए) के साथ तथा फिलिस्तीन के लोगों के लिए 30 टन मानवीय सहायता और आवश्यक जीवन रक्षक दवाइयां उपलब्ध कराने में समन्वय किया। जुलाई में, भारत ने ओमानी अधिकारियों के साथ एक संयुक्त खोज अभियान में एमटी प्रेस्टीज फाल्कन, जो कोमोरोस ध्वज के साथ एक पोत/जहाज था, से आठ भारतीयों सहित नौ चालक दल के सदस्यों को बचाया, जो ओमान के तट के पास पलट गया था।

वर्ष के दौरान भारत ने कई महत्वपूर्ण कूटनीतिक व राजनय उपलब्धियां भी हासिल कीं और भागीदार देशों के साथ दशकों से चले आ रहे संबंधों का उत्सव मनाया। ये उपलब्धियां ऐतिहासिक एवं विकासशील भागीदारियों को पोषित करने में भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।



इटली में जून 2024 में जी-7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में अन्य विश्व नेताओं के साथ प्रधानमंत्री



प्रधानमंत्री को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा मॉस्को में 22^{वां} भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान “ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल” से सम्मानित किया गया, जुलाई 2024

2024 में, कई द्विपक्षीय भागीदारियों को रणनीतिक और व्यापक रणनीतिक भागीदारियों के स्तर तक बढ़ाया गया। भारत ने सिंगापुर और मलेशिया के साथ संबंधों को ‘व्यापक रणनीतिक भागीदारी स्तर’ तक बढ़ाया। इसके अलावा, कुवैत और पोलैंड के साथ राजनयिक संबंधों को रणनीतिक भागीदारी में अपग्रेड किया गया। इन घटनाक्रमों ने अपनी रणनीतिक भागीदारी को मजबूत करने में भारत की सक्रियता को रेखांकित किया।

वर्ष के दौरान, प्रधानमंत्री को दुनियाभर के देशों से अनेक नागरिक सम्मान प्राप्त हुए जो विश्व में उनकी राजनीतिज्ञता और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में योगदान की मान्यता के सूचक हैं। मार्च में, भूटान की राजकीय यात्रा के दौरान उन्हें राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक द्वारा अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान “ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो” प्रदान किया गया। जुलाई में, 22^{वां} भारत-रूस वार्षिक शिखर वार्ता के लिए रूस की आधिकारिक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा “ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल” से सम्मानित किया गया। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और महामारी सहायता प्रयासों के लिए, प्रधानमंत्री के नेतृत्व के सम्मान में, उन्हें “ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस” से भी नवाज़ा गया। प्रधानमंत्री को डोमिनिका सिल्वेनी बर्टन के कॉमनवेल्थ प्रेजिडेंट द्वारा जॉर्जटाउन, गुयाना में सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार “डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर” से भी सम्मानित किया गया। नवंबर 2024 में, नाइजीरिया ने उन्हें “ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर” से सम्मानित किया, जबकि गुयाना और कुवैत ने उन्हें अपने क्रमशः सर्वोच्च सम्मान - “ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस” और “द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर” से सम्मानित किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) ने 2024 में नए देशों और उनके अनुसमर्थन के साथ अपनी सदस्यता का विस्तार किया। माल्टा (फरवरी), पैराग्वे (जून), लेबनान (अगस्त) और मोल्दोवा (दिसंबर) ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए, जबकि पनामा (मार्च), न्यूजीलैंड (अगस्त) और आर्मेनिया (नवंबर) ने संधि का अनुसमर्थन किया। इन घटनाक्रमों ने सौर ऊर्जा का विस्तार करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने में वैश्विक प्रयासों को आगे बढ़ाने में भारत की पहलों को उजागर किया।

कई उच्चस्तरीय द्विपक्षीय यात्राएं करके दीर्घकालिक राजनयिक संबंधों में नई जान डाली गई। महामहिम राष्ट्रपति ने अल्जीरिया, फिजी, मलावी, मॉरिटानिया, मॉरीशस, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते जैसे देशों की राजकीय यात्रा की। अल्जीरिया की यात्रा इस देश की उनकी पहली राजकीय यात्रा थी जहां भारत-अल्जीरिया आर्थिक मंच की पहली बैठक आयोजित की गई, जो कि द्विपक्षीय संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत है। माननीय राष्ट्रपति ने फिजी और तिमोर लेस्ते की भी यात्रा की, जो कि किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की इन देशों की पहली यात्रा थी।

तिमोर लेस्ते की यात्रा के दौरान, महामहिम राष्ट्रपति को राष्ट्रपति जोस रामोस-होर्ता द्वारा आने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान “ग्रैंड-कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर-लेस्ते” से सम्मानित किया गया। महामहिम राष्ट्रपति को अगस्त में सुवा में आयोजित एक समारोह में फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार “कम्पेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी” से सम्मानित किया गया। इन यात्राओं से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों के तहत चल रहे अभियान को गति प्राप्त हुई।



महामहिम राष्ट्रपति तिमोर-लेस्ते के राष्ट्रपति जोस रामोस-होर्ता द्वारा दीली में अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर-लेस्ते से सम्मानित होते हुए, अगस्त 2024

माननीय उपराष्ट्रपति ने ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. सैय्यद इब्राहिम रईसी के दुखद निधन पर तथा ईरान के तत्कालीन विदेश मंत्री डॉ. हुसैन अमीर-अब्दुल्लाहियन की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु पर संवेदना व्यक्त करने हेतु राजकीय कार्यक्रम में ईरान का दौरा किया।

भागीदार देशों के साथ भारत की उच्च स्तरीय बातचीत को जारी रखते हुए प्रधानमंत्री ने विभिन्न उच्च स्तरीय द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और बहुस्तरीय कार्यक्रमों के भाग लेने के लिए ऑस्ट्रिया, भूटान, ब्राज़ील, ब्रुनेई, गुयाना, इटली, कुवैत, लाओस, नाइजीरिया, पोलैंड, कतर, रूस, सिंगापुर, यूक्रेन, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा किया।

जुलाई में, प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रिया का दौरा किया, जो चार दशकों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। अगस्त में यूक्रेन की ऐतिहासिक यात्रा की गई, जो 1992 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के उपरांत किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। नवंबर में, प्रधानमंत्री मंत्री ने नाइजीरिया का राजकीय दौरा किया, जो 17 वर्षों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा था। अंततः दिसंबर में, प्रधानमंत्री ने कुवैत का दौरा किया, जो उनकी कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात की पहली यात्रा थी और यह 43 वर्षों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी।

प्रधानमंत्री ने कई वर्चुअल और व्यक्तिगत शिखर-स्तरीय बैठकों में भी भाग लिया जिनमें संयुक्त राष्ट्र में भावी शिखर सम्मेलन, जी-20 शिखर सम्मेलन, जी-7 शिखर सम्मेलन का आउटरीच सत्र, क्लाड लीडर्स शिखर सम्मेलन, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, एससीओ शिखर सम्मेलन और वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण शामिल था।

वर्ष के दौरान विदेश मंत्री ने विभिन्न राजनयिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ईरान, इटली, जापान, कजाकिस्तान, कुवैत, लाओस पीडीआर, मलेशिया, मालदीव, मॉरीशस, नेपाल, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, कतर, कोरिया गणराज्य, सऊदी अरब, सिंगापुर, श्रीलंका, स्विट्जरलैंड, युगांडा, संयुक्त अरब अमीरात, और संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा किया।

जनवरी में, विदेश मंत्री ने ईरान का दौरा किया और चाबहार बंदरगाह के विकास एवं संचालन पर ईरान के तत्कालीन विदेश मंत्री डॉ. हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन से मुलाकात करके चर्चा की। उन्होंने नेपाल की यात्रा भी की, जहां उन्होंने राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और तत्कालीन प्रधानमंत्री कमल दहल 'प्रचंड' से मुलाकात की तथा नेपाल के तत्कालीन विदेश मंत्री श्री एन.पी. सऊद के साथ काठमांडू में 7^{वाँ} भारत-नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक की सह-अध्यक्षता की। विदेश मंत्री ने पहली बार नाइजीरिया का दौरा किया और विदेश मंत्री यूसुफ टुग्गर के साथ 6^{वाँ} भारत-नाइजीरिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह-अध्यक्षता की। इसी महीने में, उन्होंने कंपाला में आयोजित 19^{वाँ} गुटनिरपेक्ष आंदोलन (एनएएम) शिखर सम्मेलन के एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। मार्च में, विदेश मंत्री जापान गए, जहाँ उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री फूमिओ किशिदा से मुलाकात की और तत्कालीन विदेश मंत्री योको कामिकावा के साथ 16^{वाँ} भारत-जापान रणनीतिक वार्ता की सह-अध्यक्षता की। उन्होंने

मलेशिया का भी दौरा किया और द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने हेतु प्रधानमंत्री दातो' सेरी अनवर बिन इब्राहिम एवं विदेश मंत्री दातो' सेरी उतामा हाजी मोहम्मद बिन हाजी हसन से से मुलाकात की। इसी महीने के अंत में उन्होंने फिलीपींस का दौरा किया और राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर. मार्कोस जूनियर तथा विदेश मंत्री एनरिक ए. विदेश मंत्री मनालो के साथ चर्चा की। विदेश मंत्री ने दक्षिण कोरिया का भी दौरा किया, जहां उन्होंने तत्कालीन विदेश मंत्री चो ताए-युल के साथ 10^{वाँ} भारत-आरओके संयुक्त आयोग की बैठक की सह-अध्यक्षता की। सिंगापुर में, उन्होंने प्रधानमंत्री ली हसियन लूंग से तथा उप प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की इसके अलावा, उन्होंने फिनटेक, डिजिटलीकरण और हरित अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा करने के लिए अपने समकक्ष विवियन बालाकृष्णन से मुलाकात की।

विदेश मंत्री ने जून में श्रीलंका का दौरा किया, जहां उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, तत्कालीन प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने और तत्कालीन विदेश मंत्री एम.यू.एम. अली साबरी से मुलाकात की। भारत के जन-केंद्रित विकास सहयोग को मजबूत करने के लिए विदेश मंत्री और राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने कैडी, मटाले और नुवारा एलिया में भारतीय आवास परियोजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 106 घरों के साथ-साथ कोलंबो और लिकोमाली जिलों में आदर्श ग्राम आवास परियोजना के तहत 48 घरों का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर (एमआरसीसी), जो कि समुद्र में खोज करने तथा बचाव कार्यों के संचालन के लिए एक प्रमुख केंद्र है और जिसे 6 मिलियन अमरीकी डॉलर के भारतीय अनुदान से स्थापित किया गया है, को वर्चुअल रूप में चालू किया। विदेश मंत्री ने श्रीलंका के बंदरगाह मंत्रालय, नौवहन मंत्रालय और विमानन मंत्रालय, कृषि और वृक्षारोपण मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, और बिजली एवं ऊर्जा मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ भी विचार-विमर्श किया। इस महीने के अंत में, उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात का दौरा किया और भारत-यूएई व्यापक रणनीतिक भागीदारी की समीक्षा करने हेतु विदेश मंत्री मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान से बातचीत की। जुलाई में, विदेश मंत्री ने आस्ताना के लिए 24^{वाँ} एससीओ शिखर सम्मेलन हेतु भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। मॉरीशस की अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। अगस्त में, विदेश मंत्री ने कुवैत का दौरा किया, जहां उन्होंने हमारे द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा करने हेतु क्राउन प्रिंस शेख सबा खालिद अल-हमद अल-मुबारक अल-सबाह, प्रधानमंत्री अहमद अब्दुल्ला अल-अहमद अल-जबर अल-सबा, और विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अल-याह्या से मुलाकात की। इसके बाद वे मालदीव गए, जहां उन्होंने राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद मुइज़ू और तत्कालीन विदेश मंत्री मूसा ज़मीर से मुलाकात की, जिनके साथ विदेश मंत्री ने 28 द्वीपों में भारत की ऋण सहायता प्राप्त जल एवं मलजल परियोजनाओं का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया।

सितंबर में, विदेश मंत्री ने जर्मनी का दौरा किया और तत्कालीन चांसलर ओलाफ स्कॉलज़ एवं तत्कालीन विदेश मंत्री अन्नालेना बैरबॉक से मुलाकात



विदेश मंत्री ने सितंबर 2024 में रियाध में आयोजित रणनीतिक वार्ता के लिए पहली भारत-जीसीसी संयुक्त मंत्रिस्तरीय बैठक के उद्घाटन सत्र की सह-अध्यक्षता की

की। इसके बाद वे जिनेवा गए, जहां उन्होंने यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) राष्ट्रों के साथ भारत के व्यापार संबंधों पर चर्चा करने हेतु स्विट्स विदेश मंत्री इग्नाज़ियो कैसिस से मुलाकात की और जिनेवा में भारत के स्थायी मिशन की नई इमारत का उद्घाटन किया। बाद में इसी महीने में, उन्होंने वाशिंगटन डी.सी. का दौरा किया और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करने हेतु तत्कालीन विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, तत्कालीन वाणिज्य मंत्री जीना रायमोंडो, तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) जेक सुलिवन, और अन्य वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों से मुलाकात की। अक्टूबर में, विदेश मंत्री ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया और प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ तथा अन्य प्रमुख राजनेताओं से मुलाकात की। उन्होंने विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ 15^{वें} फॉरेन मिनिस्टर्स फ्रेमवर्क डायलॉग की सह-अध्यक्षता भी की और ब्रिस्बेन में भारत के महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। नवंबर में, उन्होंने जी-7 विदेश मंत्रियों के आउटरीच सत्र में भाग लेने और रोम में एमईडी मेडिटेरेनियन डायलॉग के 10^{वें} संस्करण में भाग लेने के लिए इटली का दौरा किया। इटली में, विदेश मंत्री ने इटली तथा जी-7 में अन्य सहभागी राष्ट्रों के अपने समकक्षों से द्विपक्षीय वार्ता की। दिसंबर में, विदेश मंत्री ने कतर और बहरीन की यात्रा की। कतर में, उन्होंने 22^{वें} दोहा फोरम में सहभागिता की तथा प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से मुलाकात की। बहरीन में, उन्होंने विदेश मंत्री डॉ. अब्दुल्लातिफ बिन राशिद अल ज़ायनी के साथ 4^{वें} भारत-बहरीन उच्च संयुक्त आयोग (एचजेसी) की बैठक की सह-अध्यक्षता की। दिसंबर में, विदेश मंत्री और विदेश सचिव ने अमेरिका का दौरा किया, जहां उन्होंने तत्कालीन एनएसए सुलिवन, तत्कालीन विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और माइकल वाल्ट्ज, एनएसए पद के लिए नव-निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के नामिती सहित प्रमुख वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की।

वर्ष के दौरान, विदेश मंत्री ने कई बहुपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकों में भी भाग लिया जिसमें आस्ट्रेलिया में 7^{वें} हिंद महासागर सम्मेलन; कजाकिस्तान में एससीओ राष्ट्राध्यक्ष परिषद की 24^{वें} बैठक; जापान में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक; वियनतियाने, लाओ पीडीआर में आसियान फ्रेमवर्क अर्थात आसियान- भारत, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच के अंतर्गत विदेश मंत्रियों की बैठकें; जी-20 विदेश मंत्रियों की बैठक और न्यूयॉर्क में 79^{वें} यूपएनजीए उच्च-स्तरीय सत्र; रणनीतिक वार्ता के लिए भारत- सऊदी अरब में भारत-जीसीसी मंत्रिस्तरीय बैठक और पाकिस्तान में एससीओ राष्ट्राध्यक्ष परिषद की बैठक शामिल है।

फरवरी में, विदेश मंत्री ने क्षेत्रीय महत्व पर जोर देते हुए पर्थ में 7^{वें} हिंद महासागर सम्मेलन को संबोधित किया। जुलाई में, विदेश मंत्री ने अस्ताना में 24^{वें} एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, जहां नेताओं ने पिछली गतिविधियों की समीक्षा की और बहुपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। इस महीने के अंत में, उन्होंने टोक्यो में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया, जिसमें इंडो पैसिफिक और क्वाड पहलों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया। सितंबर में, विदेश मंत्री ने न्यूयॉर्क में ब्राज़ील की दूसरी जी-20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया और संयुक्त राष्ट्र के पुनर्गठन, वित्तीय व्यवस्था और व्यापार प्रणालियों सहित वैश्विक शासन सुधारों की वकालत की। उन्होंने भारत 79^{वें} संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के राष्ट्रीय वक्तव्य को भी रखा और और रियाद में भारत-जीसीसी संयुक्त मंत्रिस्तरीय बैठक की सह-अध्यक्षता की जिससे खाड़ी देशों के साथ रणनीतिक वार्ता को आगे बढ़ाया गया। अक्टूबर में, विदेश मंत्री ने इस्लामाबाद में 23^{वें} एससीओ राष्ट्राध्यक्ष परिषद की बैठक में भारत के वक्तव्य को प्रस्तुत किया और बहुआयामी सहयोग, संतुलित विकास तथा क्षेत्रीय स्थिरता पर बल दिया।

वर्ष के दौरान, विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में फ्रांस, ग्रीस, भूटान, यूक्रेन, मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, जमैका, जर्मनी और थाईलैंड के विदेश मंत्रियों की मेज़बानी की। विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में दूसरे बिस्मटेक विदेश मंत्री रिट्रीट के लिए बिस्मटेक विदेश मंत्रियों की भी जुलाई में मेज़बानी की और रक्षा मंत्री के साथ तीसरे भारत-जापान 2+2 मंत्रिस्तरीय बैठक की सह-अध्यक्षता की।

मंत्रालय में राज्य विदेश मंत्री ने भी विभिन्न भागीदार देशों के साथ बातचीत की और भारत की वैश्विक पहुंच को आगे बढ़ाया। राज्य विदेश मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने ग्रुप ऑफ 77 के तीसरे दक्षिण शिखर सम्मेलन में तथा जी-20 विदेश मंत्रियों की बैठकों में भाग लेने हेतु क्रमशः युगांडा (जनवरी) और ब्राजील (फरवरी) का दौरा किया।

भारत की नई सरकार द्वारा पदभार ग्रहण करने के पश्चात, विदेश राज्य मंत्री (श्री कीर्ति वर्धन सिंह) ने कुवैत (जून), नॉर्वे (अगस्त), आर्मेनिया (सितंबर), मलेशिया (सितंबर), कतर (अक्टूबर), कोलंबिया (अक्टूबर-नवंबर), जाम्बिया (नवंबर), और अज़रबैजान (नवंबर) का दौरा किया।

विदेश राज्य मंत्री (श्री प्रविता मार्गेरिता) ने डोमिनिकन गणराज्य (अगस्त), कतर (अगस्त), ग्वाटेमाला (अगस्त), अल साल्वाडोर (अगस्त), पनामा (अगस्त), लिनिदाद और टोबैगो (अगस्त), मैक्सिको, ग्रेनेडा, बारबाडोस, एंटीगुआ और बारबुडा (सितंबर-अक्टूबर), और इंडोनेशिया (अक्टूबर) का दौरा किया।

इन यात्राओं का उद्देश्य विविध क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाना था, जिनमें राजनीतिक और आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, व्यापार और स्वास्थ्य में सहयोग, और प्रवासी भारतीय समुदाय से संपर्क स्थापित करना शामिल था।

वर्ष के दौरान भारत ने विभिन्न उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडलों की मेज़बानी भी की, जिनमें विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष/ शासनाध्यक्ष/ विदेश मंत्री और अन्य उच्च-स्तरीय गणमान्य व्यक्ति शामिल थे। भारत ने बांग्लादेश, भूटान, डोमिनिका, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, जमैका, कुवैत, मालदीव, मलेशिया, मोल्दोवा, स्पेन, श्रीलंका, यूक्रेन, संयुक्त अरब अमीरात, वेनेजुएला, और वियतनाम से राजनयिकों का स्वागत किया।

2024 में, भारत ने 35 देशों के साथ विदेश कार्यालय परामर्श (एफओसी) आयोजित किया। एफओसी विदेश मंत्रालय और भागीदार देशों के विदेश मंत्रालयों के बीच संवाद के लिए एक संस्थागत तंत्र है। वर्ष के दौरान पुर्तगाल (जनवरी); जापान (फरवरी); फ्रांस (मार्च); कोटे डी आइवर (मार्च), काबो वर्डे (मार्च); मॉरिटानिया (मार्च); लक्ज़मबर्ग (अप्रैल); बेल्जियम (अप्रैल); कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (अप्रैल); क्रोएशिया (अप्रैल); नीदरलैंड (मई); स्वीडन (मई); नॉर्वे (मई); इरिट्रिया (मई); यूके (मई); बेनिन (जून); टोगो (जून); जर्मनी (जुलाई); कुवैत (जुलाई); जिम्बाब्वे (अगस्त); जाम्बिया (अगस्त); इजराइल (अगस्त); अर्जेंटीना (सितंबर); उरुग्वे (सितंबर); इंडोनेशिया (सितंबर); मोलदोवा (अक्टूबर); कोलंबिया (अक्टूबर); गिनी (अक्टूबर); कतर (अक्टूबर); मोंटेनेग्रो (अक्टूबर); साइप्रस (नवंबर); बोस्निया और हर्जगोविना (नवंबर); सीरिया (नवंबर); रवांडा (दिसंबर); और लाइबेरिया (दिसंबर) के साथ एफ.ओ.सी. बैठकें आयोजित की गईं।

ये गतिविधियां विभिन्न देशों के साथ मजबूत द्विपक्षीय संबंध और सहयोग को बढ़ावा देने में भारत के अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए जारी कूटनीतिक प्रयासों को रेखांकित करती।

अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत भारत ने अपने निकटतम पड़ोसी देशों के साथ कनेक्टिविटी और विकास भागीदारियों को बढ़ाने का प्रयास किया। पड़ोसी देशों में प्रमुख देशों तक भारत की पहुंच बढ़ाने के एक हिस्से के रूप में, कई नेताओं को जून में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया गया। बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना, सेशेल्स के तत्कालीन उपराष्ट्रपति अहमद अफिफ, मॉरीशस के तत्कालीन प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ, मालदीव के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद मुइज्जु, श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरींग तोबगे, और नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' समारोह में शामिल हुए।

अफगानिस्तान के प्रति भारत का दृष्टिकोण उसके (भारत) ऐतिहासिक संबंधों, अफगानिस्तान के नागरिकों के साथ मित्रता और संबद्ध यूएन संकल्पों से निर्देशित होता रहा है। 2021 से, भारत ने महत्वपूर्ण मानवीय सहायता प्रदान की है जिसमें 50,000 मीट्रिक टन गेहूं, 300 टन चिकित्सा आपूर्ति, 28 टन राहत सहायता और 40,000 लीटर मैलाथियान (कीटनाशक) शामिल है। संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और अपराध कार्यालय (यूएनओडीसी) के साथ सहयोग व कोलाब्रेशन करते हुए, भारत ने कमजोर आबादी, विशेष रूप से महिलाओं को लक्षित करते हुए आवश्यक कल्याणकारी वस्तुएं वितरित कीं। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) ने अफगान छात्रों को 2,000 ऑनलाइन छात्रवृत्तियां दीं जिसमें लगभग 600 छात्रवृत्तियां महिलाओं के लिए थीं। जारी मानवीय सहायता को सुविधाजनक बनाने के लिए एक तकनीकी टीम अभी भी काबुल में तैनात है।

भारत और बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक, भाषाई, सांस्कृतिक और कई अन्य क्षेत्रों में संबंध हैं। समानताएँ। यह संबंध विविध क्षेत्रों यानी राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग, व्यापार और आर्थिक संबंध, विकास भागीदारी, पिछले कुछ वर्षों में सांस्कृतिक और लोगों के बीच आदान-प्रदान में सहयोग के साथ पोषित हुआ है। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है और भारत एशिया में बांग्लादेश का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन गया है।

जून में, बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना नई दिल्ली में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुईं। जुलाई-अगस्त में बांग्लादेश में हुए घटनाक्रमों के उपरांत, भारत बांग्लादेश में मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार के साथ बातचीत करता रहा। प्रधानमंत्री मुख्य सलाहकार यूनस को बधाई देने वाले पहले विश्व नेता थे, जिन्हें उन्होंने 17 अगस्त को तीसरे वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भी आमंत्रित किया था। विदेश मंत्री ने न्यूयॉर्क में सितंबर में 79^{वीं} संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के सलाहकार तौहीद हुसैन से मुलाकात की। दिसंबर में, विदेश सचिव ने ढाका का दौरा किया और बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार तथा विदेश मामलों के सलाहकार से मुलाकात की। एक लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लोदेश के लिए भारत का समर्थन इन बातचीतों के दौरान स्पष्ट रूप से जताया गया।

बांग्लादेश आज भारत का सबसे बड़ा विकास भागीदार है। भारत ने सड़कों, रेल मार्गों, नौवहन और बंदरगाहों सहित विभिन्न क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पिछले आठ वर्षों में बांग्लादेश को तीन ऋण सुविधाएं (एलओसी) दी हैं, जो कि लगभग 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। इसके अलावा, उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाएं (एचआईसीडीपी) बांग्लादेश में भारत की विकास सहायता के एक सक्रिय स्तंभ हैं जिनमें छात्रावासों, शैक्षणिक भवनों, कौशल विकास और प्रशिक्षण संस्थानों, सांस्कृतिक केंद्र, अनाथालयों के निर्माण तथा साझी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार शामिल है।

वर्ष के दौरान कई विकास परियोजनाएं पूरी की गईं। 2023 में खुलना-मोंगला पोर्ट रेल लाइन के सफल निर्माण के बाद, अखौरा-अगरतला सीमा पार रेल संपर्क परियोजना का कार्य नवंबर 2024 में पूरा किया गया। यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है क्योंकि यह भारत के उत्तर पूर्व को बांग्लादेश के साथ रेल मार्ग से जोड़ता है, जिससे इस क्षेत्र में रेल-संपर्क बढ़ेगा।

भारत और भूटान के बीच द्विपक्षीय संबंध अनूठे हैं, जो सभी स्तरों पर आपसी विश्वास, समझ और सद्भावना तथा लोगों के बीच आपसी संबंधों पर आधारित हैं। 2024 में कई उच्च-स्तरीय आदान-प्रदानों के साथ द्विपक्षीय संबंधों में सभी क्षेत्रों में निरंतर प्रगति देखी गई, जिसमें प्रधानमंत्री की भूटान

की राजकीय यात्रा, महामहिम भूटान के राजा की भारत की आधिकारिक यात्रा, भूटान के प्रधानमंत्री की भारत की आधिकारिक यात्राएं और अन्य मंत्री-स्तरीय यात्राएं शामिल हैं। भूटान के साथ विकास सहयोग का विस्तार हुआ, और भारत ने भूटान को उसकी 13^{वीं} पंचवर्षीय योजना (2024-2029) हेतु भारत ने अपनी सहायता दोगुनी कर दी है। भारत की सहायता से भूटान में निर्माणाधीन जलविद्युत अर्थात् हाइड्रोपावर परियोजनाओं में प्रगति देखी गई, और पुनात्सांगचू II जलविद्युत परियोजना पूरी होने के करीब है। सितंबर में आयोजित वाणिज्य सचिव स्तर की वार्ता के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने के कारण दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग का और अधिक विस्तार हुआ। असम के दर्रागा में आप्रवासन चौकी का उद्घाटन और रेल संपर्क स्थापित करने की प्रगति ने सीमा पार संपर्क पहलों को सकारात्मक गति प्रदान की है।

भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित प्रमुख विकास परियोजनाओं में से एक, ग्याल्त्सुएन जेत्सुन पेमा वांगचुक मातृ एवं बाल अस्पताल मार्च में बनकर तैयार हो गया। इस अस्पताल की क्षमता 150 बिस्तरों की है और इसमें बाल चिकित्सा, स्त्री रोग और प्रसूति, एनेस्थेसियोलॉजी, एक ऑपरेशन थियेटर, नवजात शिशुओं के गहन देखभाल के लिए एक सुविधा केंद्र और एक बाल चिकित्सा गहन देखभाल इकाई के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं हैं।



प्रधानमंत्री मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री शेरींग तेंबगे ने मार्च 2024 में थिम्पू में भारत सरकार की सहायता से निर्मित अत्याधुनिक अस्पताल ग्याल्त्सुएन जेत्सुन पेमा वांगचुक मातृ एवं शिशु अस्पताल का उद्घाटन किया।

मालदीव एक समुद्री पड़ोसी देश है जिसके साथ भारत जातीय, भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक और वाणिज्यिक संबंध संबंध साझा करता है। दोनों देश हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) की सुरक्षा व सुरक्षा को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और मालदीव को भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में तथा क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास (सागर) सिद्धांत की दृष्टि से अहम स्थान प्राप्त है।

मालदीव के साथ द्विपक्षीय सहयोग के तहत समुद्री सुरक्षा, कनेक्टिविटी, लोगों के बीच आदान-प्रदान, तथा सामुदायिक निर्माण अवसंरचना परियोजनाओं के विकास पर फोकस किया गया है। अगस्त में, विदेश मंत्री ने मालदीव का दौरा किया जहां उन्होंने राष्ट्रपति, तत्कालीन विदेश मंत्री और विदेश मंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। इस यात्रा के दौरान, विदेश मंत्री ने अड्ड रिक्लेमेशन एंड शोर प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट और अड्ड डेटोर लिंक ब्रिज प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। ये दोनों ही प्रोजेक्ट ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट (जीएमसीपी) के लिए भारत की सहायता का हिस्सा हैं। इसके अतिरिक्त, विदेश मंत्री और मालदीव के विदेश मंत्री मंत्री ने भारत की ऋण व्यवस्था द्वारा समर्थित एक जल एवं मलजल नेटवर्क परियोजना का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया, जो 28 द्वीपों के साथ-साथ छह एचआईसीडीपी में फैली है। भारत में प्रशिक्षण के माध्यम से मालदीव के 1,000 सिविल सेवकों के लिए क्षमता निर्माण का आदान-प्रदान किया गया तथा मालदीव में एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) प्रणाली शुरू की गई।

अक्टूबर में, मालदीव के राष्ट्रपति ने भारत की राजकीय यात्रा की और माननीय राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इस यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मुइज़ ने 'व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा भागीदारी' के लिए भारत-मालदीव विजन को अंगीकृत किया, जो कि आपसी संबंधों के लिए पहला संकल्प था। आपसी हित के विभिन्न क्षेत्रों को कवर करते हुए कई समझौता ज्ञापनों और अनुबंध पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए। यात्रा की प्रमुख उपलब्धियों में, हनीमाधू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक नए रनवे का उद्घाटन शामिल था, जिससे मालदीव की विमानन क्षमता का विस्तार हुआ। इसके अतिरिक्त, मालदीव में आवास की जरूरतों को पूरा करने के लिए, भारत के एक्जिम बैंक क्रेता ऋण सुविधा के तहत निर्मित 700 सामाजिक आवास इकाइयां आधिकारिक तौर पर सौंपी गईं। इसके अलावा, इस यात्रा के दौरान मालदीव में रुपये कार्ड भी पेश किया गया।

म्यांमार एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है जो भारत के साथ एक लंबी भूमि सीमा और समुद्री सीमा साझा करता है। भारत की नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसियों के केंद्र-बिंदु में होने के कारण, म्यांमार भारत के लिए आसियान राष्ट्रों सहित दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों से कनेक्ट होने में अहम है। भारत और म्यांमार के बीच मजबूत सभ्यतागत, ऐतिहासिक और लोगों के बीच संबंध हैं। बौद्ध धर्म एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कड़ी है जो म्यांमार के साथ भारत की साझा विरासत का एक हिस्सा है।

फरवरी 2021 से, म्यांमार में राजनीतिक और सुरक्षा स्थिति खराब हुई है। म्यांमार में मौजूदा सुरक्षा और मानवीय स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है क्योंकि इसका भारत पर सीधा असर पड़ता है। भारत ने हिंसा को पूरी तरह से समाप्त करने, बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझाने, राजनीतिक बंदियों

को रिहा करने और म्यांमार को जल्द से जल्द लोकतांत्रिक संक्रमण की राह पर लौटने का आह्वान किया है।

भारत और नेपाल अपने अनूठे, बहुआयामी और मजबूत संबंधों को आगे बढ़ा रहे हैं जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक और सभ्यतागत संबंधों पर आधारित हैं। भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा और नागरिकों की मुक्त आवाजाही इन मजबूत और गहरे संबंधों को दर्शाती है। नेबरहुड फर्स्ट दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, ऊर्जा, व्यापार, रेलवे, डिजिटल बुनियादी ढांचे और संस्कृति सहित विभिन्न संपर्क जोड़ने वाली पहलों का तेजी से विस्तार और सुदृढ़ीकरण हुआ है।

नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' जून में नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। जुलाई में, प्रधानमंत्री ने नेपाल के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली को बधाई संदेश भेजा। इसके बाद, प्रधानमंत्री ओली ने अगस्त में भारत द्वारा आयोजित तीसरे वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में वर्चुअल रूप से भाग लिया। दोनों नेताओं ने सितंबर में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79^{वें} सत्र के इतर भी मुलाकात की।



प्रधानमंत्री ने सितंबर 2024 में न्यूयॉर्क में आयोजित 79^{वें} संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के इतर नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली से मुलाकात की।

विदेश मंत्री ने जनवरी में नेपाल का दौरा किया और नेपाल के तत्कालीन विदेश मंत्री नारायण प्रकाश सऊद के साथ बैठक की तथा द्विपक्षीय सहयोग के संपूर्ण स्पेक्ट्रम की समीक्षा की। बाद में अगस्त में, नेपाल की नई विदेश मंत्री डॉ. आरजू राणा देउबा ने भारत की आधिकारिक यात्रा की, जिस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की।

भारत और श्रीलंका के बीच बौद्धिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई संपर्क की विरासत है तथा दोनों देशों के बीच संबंध 2500 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। श्रीलंका पड़ोसी प्रथम नीति तथा सागर सिद्धांत (सागर) दोनों दृष्टिकोणों से एक महत्वपूर्ण भागीदार है। वर्ष के दौरान, द्विपक्षीय संबंध विभिन्न नेतृत्व-स्तरीय वार्ताओं तथा आर्थिक, विकासात्मक, सांस्कृतिक और लोगों के बीच संबंधों को गहरा करने पर केंद्रित पहलों के माध्यम से जारी रहा।

फरवरी में प्रधानमंत्री ने श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के साथ मिलकर श्रीलंका में यूपीआई का उद्घाटन किया। इसके बाद, राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए 9-10 जून को भारत का दौरा किया तथा बाद में अगस्त में वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के तीसरे संस्करण में भाग लिया।

विदेश मंत्री ने जून में श्रीलंका का दौरा किया और अपने तत्कालीन समकक्ष विदेश मंत्री एम.यू.एम. अली साबरी के साथ विस्तृत चर्चा की। मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर (एमआरसीसी), जो कि समुद्री खोज और बचाव कार्यों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है और जिसे 6 मिलियन अमरीकी डालर के भारतीय अनुदान से स्थापित किया गया है, का उद्घाटन भी 20 जून को विदेश मंत्री की कोलंबो यात्रा के दौरान किया गया।



श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने भारत की अपनी पहली राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री से मुलाकात की और दोनों नेताओं ने दिसंबर 2024 में नई दिल्ली में “फोस्टरिंग पार्टनरशिप फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर” शीर्षक शीर्षक से एक संयुक्त वक्तव्य को अंगीकृत किया।

श्रीलंका में नई सरकार और राजनीतिक नेतृत्व के निर्वाचन के उपरांत, विदेश मंत्री अक्टूबर में श्रीलंका गए और नवनियुक्त राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से मिलने वाले पहले विदेशी गणमान्य बने। यात्रा के दौरान, भारत के विदेश मंत्री ने श्रीलंका विदेश मंत्री विजिता हेराथ के साथ भी चर्चा की। 15-17 दिसंबर को, राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके भारत की राजकीय यात्रा पर आए। राष्ट्रपति पद संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा थी। राष्ट्रपति दिसानायके और प्रधानमंत्री द्वारा “फोस्टरिंग पार्टनरशिप फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर” शीर्षक से एक संयुक्त वक्तव्य को अंगीकृत किया गया।

पाकिस्तान के साथ सामान्य पड़ोसी संबंधों की इच्छा रखते हुए, भारत का मानना है कि दोनों देशों के बीच मुद्दों को आतंक, शत्रुता और हिंसा से मुक्त माहौल में द्विपक्षीय और शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाना चाहिए। ऐसा अनुकूल माहौल बनाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर है। यह स्पष्ट किया गया कि भारत राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर समझौता नहीं करेगा और भारत अपनी सुरक्षा एवं क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर करने के सभी प्रयासों से निपटने के लिए दृढ़ और निर्णायक कदम उठाएगा।

भारत पाकिस्तान के साथ कैदियों और मछुआरों के आदान-प्रदान और तीर्थयात्राओं के आयोजन जैसे मुद्दों को आगे बढ़ा रहा है। भारत और पाकिस्तान ने जनवरी में उन परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान-प्रदान किया, जो भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं के खिलाफ हमले के निषेध पर समझौते के तहत शामिल थे। विदेश मंत्री ने अक्टूबर में 23^{वां} एससीओ शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक में भाग लेने के लिए पाकिस्तान का दौरा किया।

क्षेत्रीय संपर्क और सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से, भारत ने बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक) के भीतर विभिन्न पहलों में भी योगदान दिया। विदेश मंत्री ने जुलाई में नई दिल्ली में दूसरे बिम्सटेक विदेश मंत्रियों के रिट्रीट के लिए अपने बिम्सटेक समकक्षों की मेजबानी की। इसके बाद अगस्त में, भारत ने नई दिल्ली में पहले बिम्सटेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जिसमें बंगाल की खाड़ी क्षेत्र से 300 से अधिक हितधारकों ने भाग लिया।

प्रधानमंत्री ने जून में बिहार के राजगीर के पास नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। यह प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल के 100 दिनों के भीतर उद्घाटन की गई पहली महत्वाकांक्षी परियोजना थी। विश्वविद्यालय का उद्देश्य बौद्धिक, दार्शनिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक अध्ययन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के रूप में नालंदा के प्राचीन गौरव को पुनर्जीवित करना है। भारत सहित, इस परियोजना में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान, ब्रुनेई दारुस्सलाम, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओस, मॉरीशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम सहित 17 सहभागी देश हैं। इन देशों के राजनयिकों ने विश्वविद्यालय परिसर के उद्घाटन समारोह में भाग लेने हेतु नालंदा की यात्रा भी की।

पूरे वर्ष के दौरान, भारत ने उच्च-स्तरीय कूटनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों के माध्यम से कोमोरोस, मेडागास्कर, मॉरीशस और सेशेल्स सहित

हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया। भारत ने कोमोरोस, अज़ाली असौमानी के राष्ट्रपति, और सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ सहित क्षेत्र के नेताओं की मेजबानी करके अपने सागर विजन को मजबूत किया। ये बैठकें द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने और क्षेत्रीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर केंद्रित थीं।

प्रधानमंत्री और मॉरीशस के तत्कालीन प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने भारत सरकार की वित्तीय सहायता से कार्यान्वित छह सामुदायिक विकास परियोजनाओं के साथ-साथ अगले दशक पर एक नई हवाई पट्टी और जेटी का वर्चुअल उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने विश्व शासनाध्यक्षों के शिखर सम्मेलन के दौरान मेडागास्कर के राष्ट्रपति एंड्री राजोइलिना से मुलाकात की। रक्षा सहयोग के अंतर्गत 'मिलान 2024' जैसा संयुक्त युद्धाभ्यास किया गया और मैरीटाइम हेड्स फॉर एक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन (महासागर) की बैठकें आयोजित की गईं।

भारतीय नौसेना द्वारा नवंबर में उच्च-स्तरीय वर्चुअल इंटरैक्शन महासागर का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया, जिस दौरान नौसेना प्रमुख ने भारतीय महासागर क्षेत्र के तटीय देशों, जैसे कि बांग्लादेश, कोमोरोस, केन्या, मेडागास्कर, मालदीव, मॉरीशस, मोजाम्बिक, सेशेल्स, श्रीलंका और तंजानिया के नौसेना प्रमुखों/समुद्री एजेंसियों और वरिष्ठ नेतृत्व के साथ बातचीत की। बातचीत का विषय था 'आईओआर में सामान्य समुद्री सुरक्षा चुनौतियों के शमन के लिए प्रशिक्षण सहयोग', जो हिंद महासागर क्षेत्र में सामान्य समुद्री चुनौतियों के शमन की दिशा में क्षमता निर्माण में सहयोग के लिए वर्तमान और आवश्यक अनिवार्यताओं पर प्रकाश डालता है।

बहु-राष्ट्र युद्धाभ्यास 'मिलन' का 12^{वां} संस्करण फरवरी में शुरू किया गया। यह संस्करण सबसे बड़ा था जिसमें भारतीय जहाजों और 16 विदेशी

युद्धपोतों तथा अन्य भागीदार देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया। इस युद्धाभ्यास ने समुद्री सुरक्षा, शांति और समृद्धि के साझा उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक क्षेत्रीय तालमेल स्थापित करने की दिशा में संयुक्त रूप से प्रशिक्षण और संचालन के लिए समान विचारधारा वाले देशों को एक साथ एकल किया।



प्रधानमंत्री ने अगस्त 2024 में नई दिल्ली में मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम से मुलाकात की।



अक्टूबर 2024 में वियनतियाने में आयोजित 21^{वां} आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में आसियान नेताओं के साथ प्रधानमंत्री

एक्ट ईस्ट नीति के समग्र ढांचे के तहत दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों और हिंद-प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ भारत की भागीदारी इस वर्ष विभिन्न स्तरों पर विस्तारित और गहन होती रही। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने अगस्त में भारत की राजकीय यात्रा की और प्रधानमंत्री के साथ चर्चा की। इस यात्रा के दौरान, भारत-मलेशिया द्विपक्षीय संबंध 2015 में स्थापित संवर्धित रणनीतिक भागीदारी से आगे बढ़कर एक व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंच गए।

प्रधानमंत्री ने 03-04 सितंबर को ब्रुनेई की ऐतिहासिक यात्रा की, जो किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय आधिकारिक यात्रा थी और यह राजनयिक संबंधों की स्थापना की 40^{वीं} वर्षगांठ के अवसर पर की गई। प्रधानमंत्री ने 21^{वें} आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 19^{वें} पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के लिए 10-11 अक्टूबर को वियनतियाने, लाओस का दौरा किया। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने लाओ पीडीआर के प्रधानमंत्री सोनेक्सैसिफ़ंडन के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की।

प्रधानमंत्री ने 04-05 सितंबर को सिंगापुर का दौरा किया। यह प्रधानमंत्री की सिंगापुर की 5^{वीं} यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान भारत-सिंगापुर संबंधों को व्यापक रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक बढ़ाया गया और सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र, डिजिटल प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य परिचर्या और कौशल विकास के क्षेत्रों में सहयोग पर चार समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान किया गया।

विदेश मंत्री ने जुलाई में वियनतियाने में आसियान-भारत विदेश मंत्रियों की बैठक और मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भाग लिया। वर्ष के दौरान, विदेश मंत्री ने ब्रुनेई (जुलाई), कंबोडिया (जुलाई), इंडोनेशिया (अक्टूबर और नवंबर), मलेशिया (मार्च, जुलाई और अक्टूबर), फिलीपींस (मार्च), सिंगापुर (अगस्त) और थाईलैंड (नवंबर) से अपने समकक्षों से मुलाकात की और चर्चा की। रक्षा मंत्री ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने और क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए 11^{वें} आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस (एडीएमएम प्लस) के लिए 20-22 नवंबर को वियनतियाने का दौरा किया।

भारत-ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों में विभिन्न क्षेत्रों में उच्च स्तरीय बातचीत हुई और सहयोग गहन हुआ। दूसरा भारत-ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन नवंबर में रियो डी जेनेरियो में जी-20 शिखर सम्मेलन के इतर आयोजित किया गया। द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीस ने भारत-ऑस्ट्रेलिया नवीकरणीय ऊर्जा भागीदारी के शुभारंभ की सलाहना की। नवंबर में कैनबरा में आयोजित 15^{वें} इंडो-ऑस्ट्रेलिया फॉरेन मिनिस्टर्स फ्रेमवर्क डायलॉग के तहत, भारत के विदेश मंत्री और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉंग ने द्विपक्षीय सहयोग के संपूर्ण स्पेक्ट्रम की समीक्षा की। विदेश मंत्री ने फरवरी में पर्थ में हिंद महासागर सम्मेलन में भी भाग लिया। ब्रिस्बेन में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन विदेश मंत्री ने नवंबर में अपनी यात्रा के दौरान क्वींसलैंड के गवर्नर जीनेट यंग के साथ किया। अक्टूबर में विदेश और रक्षा सचिवों के चौथे 2+2 परामर्श के साथ रक्षा सहयोग में काफी प्रगति हुई।

न्यूजीलैंड के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध उच्च-स्तरीय आदान-प्रदानों के साथ मजबूत हुए। महामहिम राष्ट्रपति ने अगस्त में न्यूजीलैंड की राजकीय यात्रा की। अपनी यात्रा के दौरान, एक द्विपक्षीय सीमा शुल्क सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, और जुलाई में न्यूजीलैंड अपनी संसद के अनुसमर्थन के बाद आईएसए में शामिल हो गया। अक्टूबर में, प्रधानमंत्री ने विएंटियाने में आसियान-भारत शिखर सम्मेलन के इतर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से मुलाकात की। बाद में नवंबर में, विदेश मंत्री ने कैनबरा में 'रायसीना डाउन अंडर' के इतर न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स के साथ बैठक की।



महामहिम राष्ट्रपति का न्यूजीलैंड के गवर्नर जनरल डेम सिंडी कीरो द्वारा गवर्नमेंट हाउस में पारंपरिक माओरी "पोव्हीरी" समारोह में भव्य स्वागत।

भारत ने अपनी एक्ट ईस्ट नीति के तहत प्रशांत द्वीप देशों (पीआईसी) के साथ मजबूत और बहुआयामी भागीदारी स्थापित की है, जिसके तहत विकास सहयोग, जलवायु से संबंधित प्रयास (क्लाइमेट एक्शन), स्वास्थ्य पहलों और सांस्कृतिक संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। दक्षिण-दक्षिण सहयोग के माध्यम से, भारत फिजी, पापुआ न्यू गिनी, नाउरू, सोलोमन द्वीप, टोंगा, तुवालु, किरिबाती, पलाऊ, वानुअतु और मार्शल द्वीप गणराज्य सहित सभी 14 पीआईसी को वार्षिक अनुदान सहायता प्रदान करता है, ताकि सौर विद्युतीकरण, जल संचय, आपदा राहत और स्वास्थ्य परिचर्या प्रणालियों जैसी विविध विकास परियोजनाओं को समर्थन दिया जा सके। फिजी ग्लोबल बायोफ्यूल्स एलायंस के 28^{वें} सदस्य के रूप में नवंबर में इसमें शामिल हुआ। फिजी के उप प्रधानमंत्री मनोआ कामिकामिका ने



प्रधानमंत्री ने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन द्वारा जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ के साथ विलमिंगटन में सितंबर 2024 में आयोजित 6^{वाँ} क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन में सहभागिता की।

नवंबर में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (आईसीए) महासभा और वैश्विक सम्मेलन में भाग लिया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने दिल्ली में किया। आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन और आईसीए महासभा का आयोजन आईसीए (जो वैश्विक सहकारी आंदोलन के लिए प्रमुख निकाय है) के 130 साल के इतिहास में पहली बार भारत में किया गया।

राज्य मंत्री (पीएम) ने 53^{वाँ} प्रशांत द्वीप समूह फोरम (पीआईएफ) नेताओं की बैठक में भाग लेने के लिए अगस्त में टोंगा साम्राज्य का अलग से दौरा किया और उन्होंने 14 पीआईसी के प्रत्येक के लिए उनकी संबंधित जरूरतों के आधार पर त्वरित प्रभाव परियोजना (क्यूआईपी) हेतु भारत की सहायता की घोषणा की, जो 50,000 अमेरिकी डॉलर मूल्य की थी। यह पीआईएफ बैठक में भारत की ओर से मंत्री स्तर पर पहली सहभागिता थी। भारत ने भूस्खलन राहत कार्य के लिए पापुआ न्यू गिनी को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर और भूकंप के बाद वानुअतु को 500,000 अमेरिकी डॉलर सहित महत्वपूर्ण मानवीय सहायता भी प्रदान की। जलवायु कार्रवाई को प्राथमिकता के रूप में रखते हुए, सौरकरण परियोजनाएं और व्यापक पहलों को सोलोमन द्वीप और टोंगा में आईएसए के तहत कार्यान्वित किया गया। पीआईएफ सदस्य देशों के साथ स्वास्थ्य सहयोग के अंतर्गत दवाओं और उपकरणों की आपूर्ति, सोलोमन द्वीप और नाउरू द्वारा भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देना, और वर्ष के दौरान नाउरू में पहले जन औषधि केंद्र की स्थापना शामिल है।

भारत का हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति दृष्टिकोण एक ऐसे क्षेत्र की वकालत करने पर केंद्रित है जो स्वतंत्र, खुला, समावेशी और अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा शासित हो। इस वर्ष भारत की एक्ट ईस्ट नीति और सागर सिद्धांत के तहत हिंद-

प्रशांत क्षेत्र के लिए भारत के दृष्टिकोण का एक दशक पूरा हुआ। प्रधानमंत्री ने 21 ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए के अपने समकक्षों के साथ अमेरिका के विलमिंगटन में क्वाड सितंबर 2024 को लीडर्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया। क्वाड लीडर्स ने स्वास्थ्य, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, जलवायु और बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करते हुए कल्याण के लिए वैश्विक शक्ति के रूप में इस समूह की भूमिका पर प्रकाश डाला। इस समूह के प्रमुख परिणामों में, सर्वाइकल कैंसर से निपटने के लिए क्वाड कैंसर मूनशॉट पहल और महामारी के लिए बेहतर तैयारी शामिल है। क्वाड के तत्वावधान के तहत समुद्री सुरक्षा प्रयासों को समुद्री क्षेत्र जागरूकता के लिए हिंद-प्रशांत भागीदारी और एक नई प्रशिक्षण पहल के माध्यम से संबल प्रदान हुआ। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, यानी भावी भागीदारी के क्वाड पोर्ट्स और समुद्र के नीचे केबल अपग्रेडेशन से कनेक्टिविटी और प्रतिरोध को बल मिला। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, क्वाड नेताओं ने एआई, जैव प्रौद्योगिकी और सेमीकंडक्टर में पहले शुरू करने की घोषणा की।

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) के बीच एक व्यापक वैश्विक रणनीतिक भागीदारी है, जिसके अंतर्गत साझा लोकतांत्रिक मूल्यों से चालित मानवीय प्रयत्न के लगभग सभी क्षेत्रों, कई मुद्दों पर हितों के अभिसरण, और दोनों देशों के लोगों के बीच के संपर्कों को कवर किया गया है। नेताओं के बीच नियमित संवाद द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण तत्व है। भारत और अमेरिका ने 2+2 मंत्रिस्तरीय द्विपक्षीय वार्ता के साथ-साथ जी20, I2U2 और क्वाड सहित बहुपक्षीय ढांचे के तहत मजबूत सहयोग बनाए रखना जारी रखा। इन आदान-प्रदानों के परिणाम दोनों देशों के बीच बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में सहायक रहे हैं।

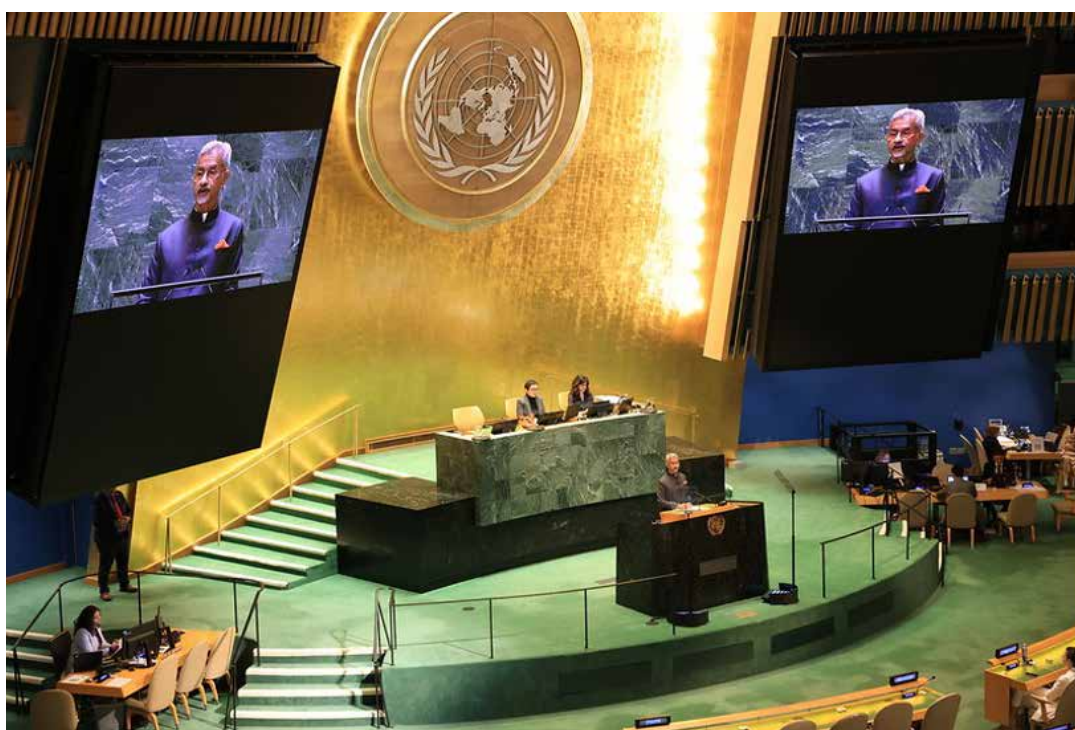
विलमिंगटन में सितंबर में क्वाड लीडर्स समिट के इतर अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान, भारत और अमेरिका ने चार प्रमुख दस्तावेजों को अंगीकार किया। इनमें दोनों देशों की भागीदारी पर एक संयुक्त फैक्ट शीट, सुरक्षित और संरक्षित वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए अमेरिका-भारत पहल के लिए एक रोडमैप, और स्तंभ III एवं IV के लिए हिंद-प्रशांत आर्थिक तंत्र (आईपीईएफ) के अनुसमर्थन के लिखतों का जमा शामिल था।

तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) जेक सुलिवन ने जून में नई दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात की और आपसी हितों के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। यात्रा के दौरान, विदेश मंत्री ने एनएसए सुलिवन के साथ भी बातचीत की। एनएसए सुलिवन के साथ वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल भी आया था, जिसमें तत्कालीन अमेरिकी उप विदेश मंत्री कर्ट कैपबेल, नेशनल साइंस फाउंडेशन (एनएसएफ) के निदेशक, अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, ऊर्जा विभाग, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा), एनएसएफ और अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (यूएसएआईडी) के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल थे। दोनों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों (एनएसए) ने महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पर पहली भारत-अमेरिका पहल (आईसीईटी) की वार्षिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग के लिए भावी परिदृश्य और लंबित मुद्दों के समाधान पर चर्चा की। अंतरिक्ष में अंतर-संचालन को गहन बनाने के लिए मानव अंतरिक्ष उड़ान सहयोग के

लिए एक रणनीतिक तंत्र भी बनाया गया। इस बैठक के बाद एक संयुक्त फैक्टशीट जारी की गई। भारत और अमेरिका ने सितंबर में द्विपक्षीय 2+2 अंतर-सत्रीय बैठक भी की।

हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन रिप्रजेंटेटिव माइकल मैककॉल के नेतृत्व में एक द्विदलीय अमेरिकी कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने जून में अलग से भारत का दौरा किया और प्रधानमंत्री से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने विदेश सचिव और उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ भी अलग-अलग बैठकें कीं। प्रतिनिधिमंडल ने धर्मशाला का दौरा किया और 14^{वें} दलाई लामा से मुलाकात की।

भारत ने कई प्रमुख बहुपक्षीय और बहुपक्षीय कार्यक्रमों में भी भाग लिया। यूएनजीए के 79^{वें} सत्र में, विदेश मंत्री ने समकालीन वैश्विक मुद्दों पर भारत का रुख प्रस्तुत किया और जी-4, जी-20, आईबीएसए, ब्रिक्स, बिम्सेटेक, भारत-कैरेबियन समुदाय (कैरीकॉम), और भारत-लैटिन अमेरिकी एवं कैरेबियाई राज्यों का समुदाय (सेलैक) सहित कई विदेश मंत्रियों की बैठकों में भाग लिया। विदेश मंत्री ने वैश्विक शासन सुधार “कॉल टू एक्शन” का अनुसमर्थन किया और बायोडाइवर्सिटी बियोन्ड नेशनल जुरीस्टिक्शन (बीबीएनजे) समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके अतिरिक्त, विदेश मंत्री ने नशीली दवाओं के खतरों, विकास प्रतिमानों और वैश्विक स्तर पर भारत की भूमिका पर चर्चा में भाग लिया, जिसमें एशिया सोसाइटी और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ) जैसे थिंक टैंक द्वारा आयोजित विदेश नीति आउटरीच सेमिनार शामिल थे।



विदेश मंत्री ने न्यूयॉर्क में, सितंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79^{वें} सत्र में भारत के वक्तव्य का प्रस्तुतीकरण किया

भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग भी वर्षभर प्रगाढ़ होता रहा। प्रधानमंत्री और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जोसेफ आर. बाइडन ने प्रधानमंत्री बीच सी-130जे सुपर हरक्यूलिस विमान पर टीमिंग समझौते की साराहना की, जो सितंबर में भारत के प्रधानमंत्री की विलमिंगटन यात्रा के दौरान लॉकहीड मार्टिन और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड के बीच किया गया था। दोनों नेताओं ने रक्षा मंत्रालय के इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस (आईडीईएक्स) और यूएस (रक्षा विभाग) डीओडी की डिफेंस इनोवेशन यूनिट (डीआईयू) के बीच बढ़ते सहयोग का भी स्वागत किया, जिसे सितंबर में सिलिकॉन वैली शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से सुगम बनाया गया था।

जनवरी में, भारतीय नौसेना ने गुआम में अमेरिकी नौसेना द्वारा आयोजित एंटी-सबमरीन वारफेयर प्रशिक्षण के चौथे संस्करण - “एक्सरसाइज सी ड्रैगन 24” में भाग लिया। वर्ष के दौरान, भारत और अमेरिका ने कई प्रमुख द्विपक्षीय रक्षा युद्धाभ्यासों में भाग लिया, जिनमें भारत-अमेरिका द्विपक्षीय त्रि-सेवा एचएडीआर एम्फिबियस युद्धाभ्यास और युद्धाभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 24 (विशाखापत्तनम, मार्च) शामिल है। इसके फलस्वरूप, भारतीय नौसेना, थल सेना और वायु सेना अमेरिकी नौसेना, मरीन कॉर्प्स और थल सेना के सानिध्य में आए। अप्रैल में, दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने हवाई में अमेरिकी थल सेना प्रशांत मुख्यालय में भारत-अमेरिका थल सेना कार्यकारी संचालन समूह (ईएसजी) की 7^{वीं} बैठक अलग से आयोजित की। उनकी चर्चाएँ उभरते खतरों, संघर्ष समाधान रणनीतियों और आधुनिक रक्षा चुनौतियों से निपटने पर केंद्रित थीं।

भारत-कनाडा संबंध पारंपरिक रूप से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों पर और मजबूत आर्थिक संबंधों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री ने 14 जून को इटली के अपुलिया में जी-7 शिखर सम्मेलन के इतर कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से संक्षिप्त मुलाकात की। कनाडा के साथ हमारे अनिवार्य द्विपक्षीय संबंधों में आपसी समझ, एक-दूसरे की चिंताओं के प्रति सम्मान और एक-दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता एवं संप्रभुता के प्रति अटूट सम्मान शामिल है। इस संबंध में, भारत ने कनाडा सरकार से अपनी धरती से सक्रिय सभी भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करने का बार-बार आग्रह किया।

वर्ष के दौरान भारत-रूस संबंधों में प्रगति जारी रही। प्रधानमंत्री ने 22^{वें} वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जुलाई में मास्को का दौरा किया और 16^{वें} ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अक्टूबर में कज़ान का दौरा किया। रूस के साथ द्विपक्षीय व्यापार 2023-24 में 65.7 बिलियन अमरीकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर को छू गया, जिसके कारण रूस भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। व्यापार-आर्थिक-वैज्ञानिक-तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग (आईआरआईजीसी-टीईसी) का 25^{वां} सत्र नवंबर में नई दिल्ली में आयोजित किया गया जिसकी सह-अध्यक्षता विदेश मंत्री और रूसी संघ के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव ने की। दिसंबर में, रक्षा मंत्री ने सैन्य और सैन्य-तकनीकी सहयोग पर भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग (आईआरआईजीसी-एमएंडएमटीसी) के 21^{वें} सत्र की सह-अध्यक्षता करने के लिए अलग से रूस का दौरा किया। विदेश मंत्री



नई दिल्ली में जनवरी 2024 में आयोजित 75^{वें} गणतंत्र दिवस समारोह में महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों

और उनके रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव ने वर्ष के दौरान कई द्विपक्षीय बैठकें कीं, जिनमें जुलाई में अस्ताना में एससीओ शिखर सम्मेलन के इतर बैठक, जुलाई में वियनतियाने में आसियान फ्रेमवर्क के तहत विदेश मंत्रियों की बैठक, सितंबर में रियाद में खाड़ी सहयोग परिषद् की बैठक और सितंबर में 79^{वाँ} यूएनजीए सत्र के इतर न्यूयॉर्क में हुई बैठकें शामिल हैं। भारत के एनएसए ने सितंबर में ब्रिक्स एनएसए की बैठक के लिए सेंट पीटर्सबर्ग का अलग से दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान, एनएसए ने राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की और अपने रूसी समकक्ष सर्गेई शोइगु के साथ द्विपक्षीय बैठक की।

यूरोपीय देशों और यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ भारत के संबंधों को कई उच्च-स्तरीय वार्ताओं के कारण गति प्राप्त हुई। भारत और ईयू ने अपनी रणनीतिक भागीदारी के 2024 में 20 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। इस वर्ष व्यापार और निवेश, उभरती प्रौद्योगिकियों, नवाचार, हरित संक्रमण, सुरक्षा तथा पलायन और गतिशीलता के क्षेत्रों में उच्च-स्तरीय संवादों का दौर रहा जिसके परिणामस्वरूप दोनों पक्षों के बीच सहयोग प्रगाढ़ हुआ।

यूरोपीय परिषद् के तत्कालीन अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने अक्टूबर में वियनतियाने में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री के साथ बैठक की। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने नवंबर में रियो डी जेनेरियो में जी-20 शिखर सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री से मुलाकात की।

फ्रांसीसी गणराज्य के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों भारत के 75^{वाँ} गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में भारत की राजकीय यात्रा पर आए। प्रतिनिधिमंडल

स्तर की वार्ता के दौरान, दोनों पक्षों ने 2026 को 'भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष' के रूप में मनाने का निर्णय लिया। दोनों पक्षों ने रक्षा, अंतरिक्ष, नागरिक उड्डयन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, लोक प्रशासन और शहरी विकास सहित प्रमुख क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों/समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए।

प्रधानमंत्री ने इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर आउटरीच पार्टनर के रूप में जी-7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जून में इटली का दौरा किया। जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने इटली की प्रधानमंत्री, जर्मनी के संघीय गणराज्य के चांसलर, फ्रांस के राष्ट्रपति और यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री के साथ अलग-अलग बैठकें कीं।

प्रधानमंत्री ने जुलाई में ऑस्ट्रिया का दौरा किया, जो 41 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी और यह दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75^{वाँ} वर्ष के समारोह के अवसर पर थी। यात्रा के दौरान भारत-ऑस्ट्रिया भागीदारी बढ़ाने पर एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वान डेर बेलन से भी मुलाकात की और चांसलर कार्ल नेहमर के साथ द्विपक्षीय वार्ता की।

पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री ने अगस्त में पोलैंड का दौरा किया, जो दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70^{वीं} वर्षगांठ के अवसर पर थी। यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ चर्चा की और राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा से मुलाकात की। इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम भारत-पोलैंड द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक भागीदारी में बदलने की घोषणा थी।



प्रधानमंत्री ने अगस्त 2024 में वारसों में कोल्हापुर स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की।



विदेश मंत्री ने फरवरी 2024 में नई दिल्ली में रायसीना वार्ता के दौरान नॉर्डिक-बाल्टिक ऐट (एनबी8) के विदेश मंत्रियों की मेजबानी की।

स्पेन के राष्ट्रपति पेद्रो सांचेज ने अक्टूबर में भारत का दौरा किया। यात्रा के दौरान भारत के प्रधानमंत्री और स्पेन के राष्ट्रपति सांचेज ने वडोदरा में C295 विमान के फाइनल असेंबली लाइन प्लांट का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया, जिसे टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स ने एयरबस स्पेन के सहयोग से बनाया है।

सितंबर में न्यूयॉर्क में 79^{वाँ} संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर, विदेश मंत्री ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री से मुलाकात की और बेल्जियम, फ्रांस, नीदरलैंड, यूके और स्पेन के अपने समकक्षों के साथ अलग-अलग बैठकें कीं।

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, भारत और स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और लिक्टेन्स्टीन सहित यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) ने मार्च में एक व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते (टीईपीए) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री (सीआईएम) ने स्विस् फेडरल काउंसिलर गाय परमेलिन, आइसलैंड के विदेश मंत्री बजरनी बेनेडिक्टसन, लिक्टेन्स्टीन के विदेश मंत्री डोमिनिक हस्लर और नॉर्वे के व्यापार एवं उद्योग मंत्री जान क्रिश्चियन वेस्ट्रे द्वारा हस्ताक्षर किए। टीईपीए में 2039 तक अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन अमरीकी डालर के निवेश और 1 मिलियन प्रत्यक्ष नौकरियों के सृजन की प्रतिबद्धता शामिल है।

सितंबर में, विदेश मंत्री ने जर्मनी का दौरा किया और चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज से मुलाकात की। उन्होंने विदेश मंत्री एनालेना बैरबॉक, रक्षा मंत्री बोर्गिस पिस्टोरियस, चांसलर के विदेश और सुरक्षा नीति सलाहकार जेन्स प्लोटनर के साथ तथा संसद सदस्यों (बुंडेस्टैग) से अलग-अलग मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों के पूरे दायरे पर विस्तृत चर्चा की। इसी महीने विदेश मंत्री ने स्विट्जरलैंड का दौरा किया और विदेश मंत्री इग्नाज़ियो कैसिस के

साथ द्विपक्षीय बैठक की तथा भारत-ईएफटीए मुक्त व्यापार समझौते के ज़रिए व्यापार और निवेश बढ़ाने पर विचार-विमर्श किया।

नवंबर में, विदेश मंत्री ने जी-7 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए इटली का दौरा किया। इस बैठक के इतर, विदेश मंत्री ने इटली के विदेश मंत्री के साथ-साथ फ्रांस और यूके के अपने समकक्षों से अलग से मुलाकात की।

अल्बानिया, बोस्निया और हर्जोगोविना, चेकिया, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, ग्रीस, हंगरी, लातविया, लिक्टेन्स्टीन, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाक गणराज्य और स्वीडन के विदेश मंत्रियों ने फरवरी में नई दिल्ली में रायसीना वार्ता के 9^{वें} संस्करण में भाग लिया। विदेश मंत्री ने रायसीना वार्ता के इतर नॉर्डिक-बाल्टिक ऐट (एनबी8) के विदेश मंत्रियों की मेजबानी की। बैठक में स्वच्छ और हरित प्रौद्योगिकियों को उन्नत बनाने, डिजिटल और साइबर सहयोग को मजबूत करने तथा उच्च गुणवत्ता वाले कौशल विकास और लचीली वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

इस वर्ष भारत-जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक भागीदारी की 10^{वाँ} वर्षगांठ मनाई गई। भारत और जापान ने इस वर्ष के दौरान उच्च स्तरीय यात्राओं, प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे और व्यापार सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोगात्मक (कोलाब्रेटिव) पहलों के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र, जी-20 और क्वाड में सहयोग के माध्यम से अपने संबंधों को गहरा किया। वर्ष के दौरान, प्रधानमंत्री ने जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा से दो बार मुलाकात की : इटली में जी-7 शिखर सम्मेलन (जून) में और फिर

विलमिंगटन में क्वाड शिखर सम्मेलन (सितंबर) में। इन आदान-प्रदानों के माध्यम से, नेताओं ने बहुआयामी संबंधों की समीक्षा की और सहयोग को और भी गहन बनाने के लिए विचारों का आदान-प्रदान किया। अक्टूबर में, प्रधानमंत्री ने लाओस में भारत-आसियान शिखर सम्मेलन के इतर नवनियुक्त प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा से मुलाकात की, जिसमें दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, रक्षा, सेमीकंडक्टर और सांस्कृतिक आदान-प्रदान में सहयोग को गहरा करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।



प्रधानमंत्री ने अक्टूबर 2024 में लाओस में भारत-आसियान शिखर सम्मेलन के इतर जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ द्विपक्षीय बैठक की।

अगस्त में, जापान के विदेश और रक्षा मंत्रियों ने तीसरी 2+2 मंत्रिस्तरीय बैठक के लिए भारत का दौरा किया, जिसकी रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री द्वारा सह-अध्यक्षता की गई। विदेश मंत्री ने नवंबर में इटली में जी-7 विदेश मंत्रियों के आउटरीच सत्र के इतर जापान के विदेश मंत्री ताकेशी इवाया से भी मुलाकात की।

भारत और चीन ने जून 2020 से परामर्श और समन्वय कार्य तंत्र (डब्ल्यू एम सीसी) की 18 बैठकें और वरिष्ठ सैन्य कमांडरों के स्तर पर 21 दौर की बैठकें कीं। अक्टूबर में, राजनयिक और सैन्य, दोनों स्तरों पर बातचीत और चर्चा के बाद, वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के समीप कुछ क्षेत्रों में गश्त की व्यवस्था पर एक समझौता हुआ, जिससे 2020 में इन क्षेत्रों में उत्पन्न हुए मुद्दों का समाधान हुआ। इसके बाद, प्रधानमंत्री ने अक्टूबर में रूस के कज़ान में 16^{वें} ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के इतर राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल स्तर पर यह लगभग पांच वर्षों में उनकी पहली द्विपक्षीय बैठक थी। वर्ष के दौरान, विदेश मंत्री ने तीन मौकों पर विदेश

मंत्री वांग यी से मुलाकात की - जुलाई में अस्ताना में एससीओ काउंसिल ऑफ स्टेट की बैठक के दौरान, जुलाई में वियनतियाने में आसियान से संबंधित विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान और नवंबर में रियो डी जेनेरियो में जी-20 शिखर सम्मेलन के इतर। दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधियों ने दिसंबर में बीजिंग में भी मुलाकात की।



प्रधानमंत्री ने अक्टूबर 2024 में कज़ान में 16^{वें} ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के इतर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की।

भारत और कोरिया गणराज्य (आरओके) के बीच विशेष रणनीतिक भागीदारी कई उच्च स्तरीय आदान-प्रदान और द्विपक्षीय वार्ताओं के फलस्वरूप और भी घनिष्ठ हुई है। प्रधानमंत्री और आरओके के तत्कालीन राष्ट्रपति यून सुक येओल ने अक्टूबर में वियनतियाने में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के इतर और नवंबर में रियो डी जेनेरियो में जी-20 शिखर सम्मेलन के इतर मुलाकात की। विदेश मंत्री ने मार्च में सियोल का अलग से दौरा किया और विदेश मंत्री चो ताए-यूल के साथ 10^{वां} भारत-आरओके संयुक्त आयोग की बैठक की सह-अध्यक्षता की। दोनों मंत्रियों ने जुलाई में आसियान क्षेत्रीय मंच के इतर और पुनः सितंबर में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79^{वें} सत्र के इतर और दिसंबर में इटली में जी-7 शिखर सम्मेलन के इतर भी मुलाकात की।

भारत और डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) के बीच संबंध उच्च स्तर पर बने रहे। भारत हमेशा ऐसे प्रयासों का समर्थक रहा जिनसे कोरियाई महाद्वीप में वार्ता एवं राजनय के जरिए शांति एवं स्थिरता आए।



(बाएं से दाएं) प्रधानमंत्री ने यूएई (फरवरी) में 'अहलान मोदी' और कुवैत (दिसंबर) में 'हला मोदी' में वहां रह रहे भारतीय समुदाय को संबोधित किया।

भारत और मंगोलिया सभ्यता, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों को साझा करते हैं। चूंकि मंगोलिया चीन और रूस की सीमा से सटा एक स्थल-रुद्ध अर्थात लैंड लॉक देश है, इसलिए भारत उसे एक महत्वपूर्ण 'तीसरा' और 'आध्यात्मिक पड़ोसी' देश मानता है। विकास भागीदारी दोनों देश के बीच संबंधों में विशेष महत्व रखती है।

वर्ष के दौरान खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंध उच्च-स्तरीय यात्राओं के आदान-प्रदान, व्यापार और निवेश में वृद्धि और ऊर्जा, सुरक्षा, रक्षा, परमाणु, संस्कृति, शिक्षा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा सहित विविध क्षेत्रों के विस्तार के साथ मजबूत और गहरे हुए हैं। खाड़ी देश भारत के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में से एक हैं। 162 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक के द्विपक्षीय व्यापार के साथ, खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) 2023-24 में भारत का प्रमुख क्षेत्रीय व्यापार भागीदार बनकर उभरा। भारत में निवेश प्रवाह भी अधिक रहा और इस क्षेत्र से भारत का ऊर्जा आयात भी पर्याप्त स्तर पर कायम है। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने जनवरी में अहमदाबाद में वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भारत का दौरा किया। यात्रा के दौरान नवोन्मेषी स्वास्थ्य परिचर्या परियोजनाओं, नवीकरणीय ऊर्जा और खाद्य पार्कों के विकास में निवेश सहयोग पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।

प्रधानमंत्री ने फरवरी 2024 में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की द्विपक्षीय यात्रा की और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम के साथ चर्चा की। यात्रा के दौरान महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों/समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें एक द्विपक्षीय निवेश संधि, भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईईसी) पर अंतर-सरकारी फ्रेमवर्क समझौता (आईजीएफए),

डिजिटल अवसंरचना परियोजनाओं पर समझौता ज्ञापन, और राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (एनएमएचसी) आदि शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने फरवरी में अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर बीएपीएस मंदिर का उद्घाटन किया।

नवंबर में, विदेश मंत्री ने सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के दुबई परिसर का उद्घाटन किया। यूएई के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान ने दिसंबर में चौथी रणनीतिक वार्ता और 15^{वां} संयुक्त आयोग की बैठक के लिए भारत का दौरा किया।

विदेश मंत्री ने रणनीतिक वार्ता के लिए पहली भारत-जीसीसी संयुक्त मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए सितंबर में रियाद का दौरा किया। यह भारत और खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के सदस्य देशों के बीच विदेश मंत्रियों के स्तर पर पहली बैठक थी। जून में, विदेश मंत्री ने कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी, जो विदेश मंत्री भी हैं, के साथ द्विपक्षीय बैठक करने के लिए दोहा का दौरा किया। दिसंबर में, विदेश मंत्री ने दोहा फोरम के 22^{वें} संस्करण में भाग लिया और 'नए युग में संघर्ष समाधान' पर एक पैनल को संबोधित किया।

विदेश मंत्री ने अगस्त में कुवैत का दौरा किया और क्राउन प्रिंस शेख सबा अल-खालिद अल सबा, प्रधानमंत्री शेख अहमद अल अब्दुल्ला अल सबा और विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अल याहा से मुलाकात की। कुवैत के विदेश मंत्री ने भी दिसंबर में भारत का दौरा किया और विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता की तथा प्रधानमंत्री से मुलाकात की।

2024 में भारत ने कूटनीतिक, रक्षा और मानवीय पहलों के माध्यम से पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को काफी मजबूत किया है। इन संबंधों के प्रमुख आकर्षक बिंदुओं में महामहिम राष्ट्रपति की अल्जीरिया की ऐतिहासिक यात्रा शामिल है, जो किसी भारतीय

राष्ट्राध्यक्ष की पहली यात्रा है। उन्होंने भारत-अल्जीरिया आर्थिक मंच का उद्घाटन किया। उच्च स्तरीय यात्राओं और सैन्य सहयोग समझौते के माध्यम से अल्जीरिया के साथ रक्षा सहयोग को और भी अधिक मजबूत किया गया। भारत ने मिस्र, इज़राइल और मोरक्को के साथ भी अपने संबंधों को घनिष्ठ किया, जिसमें रक्षा सहयोग से लेकर आर्थिक आदान-प्रदान और रणनीतिक संवाद शामिल हैं। भारत ने जुलाई में त्रिपोली में अपना दूतावास फिर से खोला।

भारत ने फिलिस्तीन को मानवीय सहायता प्रदान की, जिसमें चिकित्सा सहायता का महत्वपूर्ण योगदान भी शामिल है। भारत ने वर्ष 2024-25 के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और वर्क्स एजेंसी फॉर फिलिस्तीन रिफ्यूजीज इन द नियर ईस्ट (यूएनआरडब्ल्यूए) को 5 मिलियन अमरीकी डॉलर का अपना वार्षिक योगदान दिया। पिछले कुछ वर्षों में, भारत ने यूएनआरडब्ल्यूए के मुख्य कार्यक्रमों में कुल 40 मिलियन अमरीकी डॉलर का योगदान दिया है। इन मुख्य कार्यक्रमों में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और राहत सेवाएँ शामिल हैं। इसके अलावा, सूडान, सीरिया और दक्षिण सूडान में चिकित्सा एवं शैक्षिक आउटरीच जारी रही। पूरे वर्ष लीबिया, ट्यूनीशिया और जिबूती के साथ राजनयिक यात्राएँ और सहयोग बढ़ा, जिसमें भारत ने क्षेत्रीय मानवीय प्रयासों में सक्रिय भूमिका निभाई।

इसके अतिरिक्त, जॉर्डन और सोमालिया के साथ भारत ने रक्षा और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाया। इस वर्ष शैक्षिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान भी जारी रहा, जो पूरे क्षेत्र में गहरे संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

भारत और ईरान के बीच द्विपक्षीय सहयोग ने वर्ष के दौरान अपनी सकारात्मक गति बनाए रखी। अक्टूबर में, प्रधानमंत्री ने रूस के कज़ान में 16^{वें} ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के इतर इस्लामी गणराज्य ईरान के नव-निर्वाचित राष्ट्रपति मसूद पेजेशक्रियन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण पहलुओं की समीक्षा की और पश्चिम एशिया की स्थिति सहित क्षेत्रीय

विकास पर चर्चा की। जनवरी में, विदेश मंत्री ने ईरान का दौरा किया और तत्कालीन राष्ट्रपति सैय्यद इब्राहिम रईसी से मुलाकात की। यात्रा के दौरान, उन्होंने तत्कालीन विदेश मंत्री हुसैन अमीर-अब्दुल्लाहियन, सड़क और शहरी विकास मंत्री मेहरदाद बजरपाश, और सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली अकबर अहमदियन से भी मुलाकात की। इसी महीने, विदेश मंत्री ने कंपाला में एनएएम शिखर सम्मेलन के इतर तत्कालीन प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोखबर से मुलाकात की। अक्टूबर में, विदेश मंत्री ने कज़ान में ब्रिक्स आउटरीच सत्र के इतर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची से मुलाकात की। कनेक्टिविटी परियोजनाओं में सहयोग को इस वर्ष के दौरान और अधिक सुदृढ़ किया गया। चाबहार बंदरगाह के शाहिद बेहेश्टी टर्मिनल को सुसज्जित और संचालित करने के लिए दीर्घकालिक मुख्य अनुबंध पर इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गनाइजेशन ऑफ ईरान के बीच हस्ताक्षर 13 मई को किए गए।

रूस की अध्यक्षता में 16^{वें} ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अक्टूबर में रूस के कज़ान में आयोजित किया गया। शिखर सम्मेलन का विषय था “न्यायसंगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद का सुदृढ़ीकरण।” जून में, रूस ने निज़नी नोवगोरोड में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की, जिसमें ‘विकासशील देशों के साथ ब्रिक्स संवाद’ पर एक मंत्रिस्तरीय सत्र शामिल था। बैठक में सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने भाग लिया। इससे पहले सितंबर में, विदेश मंत्री ने न्यूयॉर्क में 79^{वें} यूएनजीए के इतर आयोजित ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में देश का प्रतिनिधित्व किया। अक्टूबर में शिखर सम्मेलन के दौरान, प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, जबकि विदेश मंत्री ने ब्रिक्स प्लस/आउटरीच सत्र में भाग लिया। शिखर सम्मेलन का समापन 16^{वें} ब्रिक्स कज़ान घोषणापत्र को अंगीकृत करने तथा ‘संभावित ब्रिक्स भागीदार देशों की सूची’ के साथ-साथ ब्रिक्स भागीदार देशों की श्रेणी के तौर-तरीकों को अंतिम रूप देने के साथ हुआ।



प्रधानमंत्री ने अक्टूबर 2024 में कज़ान में 16^{वें} ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया



प्रधानमंत्री ने अगस्त 2024 में कीव की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेन्स्की को 4 भीष्म क्यूब्स सौंपे

एससीओ में भारत की प्राथमिकताएं प्रधानमंत्री के 'सिक्थोर' एससीओ के दृष्टिकोण से संबल प्राप्त करती हैं, जिसमें सिक्थोर का अर्थ है सुरक्षा, आर्थिक विकास, संपर्क, एकता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान, और पर्यावरण का संरक्षण। भारत एससीओ ढांचे के भीतर विभिन्न तंत्रों/पहलों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा रहा, और उसने संप्रभुता, स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता, समानता, पारस्परिक लाभ तथा आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के लिए आपसी सम्मान पर पुनः बल दिया। विदेश मंत्री ने जुलाई में अस्ताना में आयोजित 24^{वाँ} एससीओ शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया, और एससीओ राष्ट्राध्यक्ष परिषद की विस्तारित प्रारूप बैठक में प्रधानमंत्री की ओर से भाषण दिया। विदेश मंत्री ने अक्टूबर में इस्लामाबाद में शासनाध्यक्ष परिषद (सीएचजी) की बैठक में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। अस्ताना घोषणा के अलावा, एससीओ शिखर सम्मेलन में कुल 23 दस्तावेज़ अंगीकृत किए गए। घोषणापत्र में क्षेत्र में परिवहन और संपर्क पहलों का स्वागत करते हुए निष्पक्ष और संतुलित आधार पर तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और एससीओ चार्टर के लक्ष्यों एवं सिद्धांतों के अनुसार सहयोग के महत्व को रेखांकित किया गया। इसके अलावा, घोषणापत्र में आतंकवाद की भी निंदा की गई, जिसमें विशेष रूप से आतंकवादियों के वित्तपोषण और आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही के मुद्दों को हल करने की आवश्यकता पर बल दिया गया, साथ ही उन देशों को अलग-थलग करने और उनको बेनकाब करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया, जो आतंकवादियों को सुरक्षित पनाह देते हैं।

भारत-यूक्रेन द्विपक्षीय संबंध लगातार विकसित हो रहे हैं। अगस्त में प्रधानमंत्री ने यूक्रेन की ऐतिहासिक यात्रा की, जो किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यूक्रेन यात्रा थी। प्रधानमंत्री ने जून में इटली में जी-7 शिखर सम्मेलन और सितंबर में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79^{वें} सत्र के इतर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेन्स्की से भी मुलाकात की। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने विदेश मंत्री के निमंत्रण पर मार्च में नई दिल्ली का आधिकारिक दौरा भी किया।

बेलारूस गणराज्य के विदेश मंत्री सर्गेई एलीनिक ने विदेश मंत्री के निमंत्रण पर मार्च में भारत का दौरा किया। दोनों मंत्रियों ने भारत-बेलारूस द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति की समीक्षा की और व्यापार, अर्थव्यवस्था, बीमा, रक्षा, शिक्षा, आईटी और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विकास भागीदारी और द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की।

सितंबर में, केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री ने आर्मेनिया का दौरा किया और येरेवन वार्ता के उद्घाटन में भाग लिया, जो एक ट्रैक 1.5 वार्ता थी जिसमें मंत्रियों, राजनयिकों, थिंक-टैंक और शिक्षाविदों ने भाग लिया। उन्होंने आर्मेनिया के उप प्रधानमंत्री मेहर हरबर्टी प्रिगोरियन से मुलाकात की और आर्मेनिया के विदेश मंत्री अरारत मिर्जोयान के साथ द्विपक्षीय चर्चा की।

वर्ष के दौरान, अफ्रीकी देशों के साथ भारत के जुड़ाव को उच्च स्तरीय राजनयिक यात्राओं, व्यापार विस्तार और विकास भागीदारी को बढ़ावा दिया गया। माननीय राष्ट्रपति जी ने अक्टूबर में मलावी और मॉरिटानिया

की महत्वपूर्ण यात्राएँ कीं। यात्रा के दौरान, माननीय राष्ट्रपति जी ने अफ्रीकी नेताओं के साथ बातचीत की, जिससे द्विपक्षीय और आर्थिक संबंध मजबूत हुए।

अगस्त में, बुरुंडी, द गाम्बिया, लाइबेरिया, मॉरीशस और जिम्बाब्वे के उपराष्ट्रपतियों सहित कई अफ्रीकी नेताओं ने 19^{वाँ} सीआईआई भारत-अफ्रीका सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया। इसी महीने, वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के तीसरे संस्करण में अल्जीरिया, अंगोला, बेनिन, बोत्सवाना, बुर्किना फासो, बुरुंडी, केप वर्डे, चाड, कोमोरोस, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, मिस्र, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, एस्वातिनी, इथियोपिया, गैबॉन, गाम्बिया, घाना, गिनी, गिनी बिसाऊ, आइवरी कोस्ट, केन्या, लेसोथो, लाइबेरिया, लीबिया, मेडागास्कर, मलावी, माली, मॉरिटानिया, मॉरीशस, मोरक्को, मोजाम्बिक, नामीबिया, नाइजर, नाइजीरिया, रवांडा, साओ तोम और प्रिंसिपी, सेनेगल, सेशेल्स, सिंप्रा लियोन, सोमालिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण सूडान, सूडान, तंजानिया, टोगो, ट्यूनीशिया, युगांडा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे सहित कई अफ्रीकी देशों ने सहभागिता की।



प्रधानमंत्री को नवंबर 2024 में अबुजा में नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टीनूबू द्वारा 'ग्रेड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर' पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

प्रधानमंत्री ने जनवरी में गांधीनगर में मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप न्यूसी से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने नवंबर में नाइजीरिया की राजकीय यात्रा की, जो 17 वर्षों में

किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान सीमा शुल्क सहयोग, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और भूमि सर्वेक्षण सहयोग पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टीनूबू ने प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय पुरस्कार "ग्रेड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर" से सम्मानित किया।

विदेश मंत्री ने न्यूयॉर्क में सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74^{वाँ} सत्र के इतर इथियोपिया के विदेश मंत्री ताये अत्सके सेलासी के साथ, कंपाला में जनवरी में एनएएम शिखर सम्मेलन के इतर युगांडा के विदेश मंत्री जेजे ओडोंगो के साथ और फरवरी में नई दिल्ली में रायसीना वार्ता के दौरान घाना की विदेश मंत्री शर्ली अयोरकोर बोचवे के साथ अलग-अलग बैठकें कीं।

भारत ने गैबॉन और काबो वर्डे में नए दूतावास खोलकर अफ्रीका में अपने राजनयिक पदचिह्न का विस्तार किया। इथियोपिया भारत के समर्थन से ब्रिक्स में जनवरी में शामिल हो गया और भारत अफ्रीका में तंजानिया का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बन गया, जिसका द्विपक्षीय व्यापार 7.9 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुँच गया है। इसके अलावा, भारत ने रवांडा को मिडवाइफरी विकास के लिए 1 मिलियन अमरीकी डॉलर की अनुदान सहायता प्रदान की और मलावी में एक स्थायी आर्टिफिशियल लिम्ब फिटमेंट सेंटर की स्थापना में सहायता की तथा मोजाम्बिक को दो फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट (एफआईसी) दान किए।

प्रमुख रक्षा संबंधी वार्ताओं में केन्या (सितंबर), तंजानिया (अक्टूबर) और दक्षिण अफ्रीका (अक्टूबर) में आईएनएस तलवार मेकिंग पोर्ट कॉल्लस की स्थापना तथा मार्च में उत्तरी मोजाम्बिक के नाकाला में पहला भारत-मोजाम्बिक-तंजानिया लिपक्षीय नौसेना युद्धाभ्यास का संचालन शामिल था।

अफ्रीका में प्रमुख विकास पहलों के अंतर्गत, घाना की टेमा-मपाकदान रेलवे लाइन के लिए 447 मिलियन अमरीकी डॉलर का वित्तपोषण, केन्या में एक्विजम बैंक (भारतीय निर्यात-आयात बैंक) का नया पूर्वी अफ्रीका प्रतिनिधि कार्यालय खोलना और नामीबिया एवं टोगो में डिजिटल भुगतान बुनियादी ढांचे का विस्तार करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। मानवीय मोर्चे पर, भारत ने नामीबिया, केन्या और जाम्बिया को सूखा और बाढ़ राहत के लिए सहायता प्रदान की, साथ ही हैजा के प्रकोप से निपटने के लिए जाम्बिया को 3.5 टन चिकित्सा आपूर्ति भी प्रदान की। पूरे वर्ष क्षमता निर्माण के प्रयास जारी रहे, जिनमें पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका को 1,800 से अधिक आईटीईसी प्रशिक्षण स्लॉट, मध्य और पश्चिम अफ्रीका के लिए 1,272 आईटीईसी स्लॉट आवंटित किए गए और 251 आईसीसीआर छात्रवृत्तियाँ एवं ई-विद्या भारती आरोग्य भारती (ई-वीबीएबी) ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम में 7,600 अफ्रीकी छात्रों का पंजीकृत शामिल है। ये पहलें व्यापार, रक्षा और विकास सहयोग के माध्यम से अफ्रीका के प्रति भारत की बढ़ती प्रतिबद्धता को उजागर करती हैं।

वर्ष के दौरान, भारत और लैटिन अमेरिका और कैरिबियन (एलएसी) क्षेत्र के बीच राजनीतिक जुड़ाव ने इस क्षेत्र के देशों के साथ हमारे संबंधों को और अधिक गति प्रदान की है।

प्रधानमंत्री ने नवंबर में रियो डी जेनेरियो में जी-20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के लिए ब्राजील का दौरा किया। जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान,



(ऊपर बाएं से दाएं घड़ी की दिशा में) प्रधानमंत्री ने जॉर्जटाउन में नवंबर 2024 में दूसरे भारत-कैरिबिअन शिखर सम्मेलन के इतर एंटीगुआ और बारबुडा, द बहामास, बारबाडोस, डोमिनिका, सेंट लूसिया और त्रिनिदाद तथा टोबैगो के नेताओं से मुलाकात की।

उन्होंने ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली और चिली के राष्ट्रपति गेब्रियल बोरिक फॉन्ट से अलग-अलग मुलाकात की।

नवंबर में, प्रधानमंत्री ने गुयाना की आधिकारिक यात्रा भी की, जहाँ उन्होंने गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफ़ान अली के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। जॉर्जटाउन में स्टेट हाउस में आयोजित एक समारोह में, प्रधानमंत्री को गुयाना के राष्ट्रपति द्वारा गुयाना का सर्वोच्च पुरस्कार, “ऑर्डर ऑफ़ द एक्सीलेंस” प्रदान किया गया।

प्रधानमंत्री ने जॉर्जटाउन, गुयाना में ग्रेनेडा के प्रधानमंत्री डिकॉन मिशेल के साथ दूसरे भारत-कैरेबियन समुदाय (कैरीकॉम) शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता भी की। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने एंटीगुआ और बारबुडा, बारबाडोस, सेंट लूसिया, डोमिनिका राष्ट्रमंडल, ग्रेनेडा, त्रिनिदाद और टोबैगो और सूरीनाम के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं। जॉर्जटाउन में आयोजित एक समारोह में डोमिनिका राष्ट्रमंडल की राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने प्रधानमंत्री को डोमिनिका का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार, “डोमिनिका अवार्ड ऑफ़ ऑनर” प्रदान किया।

इस वर्ष कैरेबियाई देशों के नेताओं ने भारत की यात्राएं भी कीं। गुयाना के प्रधानमंत्री मोहम्मद इरफ़ान अली ने फरवरी में भारत का दौरा किया। उन्होंने माननीय राष्ट्रपति जी और माननीय उपराष्ट्रपति से मुलाकात की और विदेश मंत्री एवं विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री के साथ अलग-अलग बैठकें कीं। त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री ने मई में मुंबई और जामनगर का दौरा किया। जमैका के प्रधानमंत्री ने अक्टूबर में भारत का दौरा किया और माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय उपराष्ट्रपति

और प्रधानमंत्री के साथ अलग-अलग बैठकें कीं। वेनेजुएला के कार्यकारी उपाध्यक्ष ने अक्टूबर में एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए भारत का दौरा किया और माननीय उपराष्ट्रपति तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री से मुलाकात की।



(ऊपर बाएं से दाएं घड़ी की दिशा में) विदेश मंत्री ने सितंबर 2024 में न्यूयॉर्क में आयोजित यूएनजीए के इतर क्यूबा, अल साल्वाडोर, गुयाना और वेनेजुएला के अपने समकक्षों से मुलाकात की।

2024 में ब्राजील का दौरा किया। अगस्त में, विदेश राज्य मंत्री (पीएम) ने डोमिनिकन गणराज्य, ग्वाटेमाला, अल साल्वाडोर, पनामा और त्रिनिदाद और टोबैगो का आधिकारिक दौरा किया। इसके बाद, उन्होंने मैक्सिको (सितंबर), ग्रेनेडा (अक्टूबर), बारबाडोस (अक्टूबर) और एंटीगुआ एवं बारबुडा (अक्टूबर) का दौरा किया। विदेश राज्य मंत्री (केवीएस) ने सीओपी16 बैठक में भाग लेने के लिए अक्टूबर में कैली, कोलंबिया का दौरा किया। सितंबर में ला पाज़, बोलीविया में एक नया मिशन खुलने के साथ, अब भारत के एलएसी क्षेत्र में 17 आवासीय मिशन हैं।

भारत ने बहुपक्षवाद और वैश्विक व्यवस्था में सुधार लाने में अग्रणी भूमिका निभाते हुए संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के रूप में सक्रिय रूप से भाग लिया। जनवरी में, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष ने माननीय राष्ट्रपति जी से मुलाकात की और विदेश मंत्री के साथ एक अलग बैठक की। जुलाई में, प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) विश्व धरोहर समिति की बैठक के अपने 46^{वें} सत्र को संबोधित किया। यह भारत द्वारा आयोजित यूनेस्को का अपने आप में पहला सत्र था।

भारत ने नवंबर में बाकू, अज़रबैजान में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के 29^{वें} सम्मेलन (सीओपी29) में भाग लिया।

सितंबर में, प्रधानमंत्री ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में 'समिट ऑफ द फ्यूचर' को संबोधित किया। शिखर सम्मेलन में पाँच क्षेत्रों में 56 कार्य बिंदुओं के साथ "पैक्ट फॉर द फ्यूचर" को अंगीकृत किया गया। प्रधानमंत्री ने नेपाल के प्रधानमंत्री, कुवैत के क्राउन प्रिंस, फिलिस्तीन राज्य के राष्ट्रपति, वियतनाम के राष्ट्रपति और यूक्रेन के राष्ट्रपति सहित कई नेताओं के साथ अलग-अलग द्विपक्षीय बैठकें कीं। इसके अलावा, विदेश मंत्री ने यूएनजीए के 79^{वें} सत्र में उच्च स्तरीय सप्ताह के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का

नेतृत्व किया और 28 सितंबर को न्यूयॉर्क में 79^{वें} यूएनजीए के उच्च स्तरीय खंड की आम बहस को संबोधित किया।

यूएनजीए सत्र के इतर, विदेश मंत्री ने जी20, जी4, आईबीएसए, ब्रिक्स, एल-69 और सी-10, भारत-कैरिबियन, भारत-सीईएलएसी और बिस्मटेक सहित विभिन्न बहुपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठकों में भाग लिया।

भारत ने अपने भागीदार देशों की ज़रूरतों के आधार पर परियोजनाओं, अनुदानों और ऋणों के ज़रिए विकास सहायता प्रदान की है। पिछले कुछ वर्षों में, इसका दायरा तकनीकी परामर्श, आपदा राहत, मानवीय सहायता, विरासत का पुनरुद्धार, शिक्षा छात्रवृत्ति, क्षमता निर्माण कार्यक्रम, अवसंरचना के क्षेत्रों में सिविलियन एवं सैन्य पाठ्यक्रम, जलविद्युत, बिजली पारेषण, कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुरातत्व संरक्षण, और सीमा पार कनेक्टिविटी तक विस्तारित किया गया है। इसके अंतर्गत प्रमुख विकास सहयोग परियोजनाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, जल, ऊर्जा और कनेक्टिविटी सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। भारत लाइन ऑफ़ क्रेडिट भी प्रदान करता है, जो भागीदार देशों को दिए जाने वाले रियायती ऋण हैं। पूरी हो चुकी प्रमुख एलओसी परियोजनाओं में, बुरुंडी के काबू में 20 मेगावाट की जलविद्युत परियोजना, ज़िम्बाब्वे और तंजानिया में जलापूर्ति प्रणालियों का उन्नयन, श्रीलंका में रेलवे ट्रैक उन्नयन परियोजना, और गुयाना को विमान की आपूर्ति शामिल हैं। इस वर्ष मॉरीशस में जल पाइपलाइन प्रतिस्थापन परियोजना के लिए पहली बार रुपया मूल्यवर्गित ऋण-सीमा बढ़ाई गई। भारत विदेशी सरकारी पेशेवरों व वृत्तिकों के लिए नवप्रवर्तन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करके अपने भागीदार देशों के लिए क्षमता निर्माण की सुविधा भी प्रदान करता है। वर्ष के दौरान नागरिक (10,200 स्लॉट) और रक्षा पाठ्यक्रमों (3,300+ स्लॉट) में 13,500 से अधिक प्रशिक्षण स्लॉट आवंटित किए गए, जिसके परिणामस्वरूप नागरिक पाठ्यक्रमों के संदर्भ में 115 से अधिक देशों तक और रक्षा-संबंधी पाठ्यक्रमों के लिए लगभग 80 देशों तक पहुँच बढ़ाई गई है।



प्रधानमंत्री ने सितंबर 2024 में न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन्स 'समिट ऑफ द फ्यूचर' शिखर सम्मेलन में भाषण दिया



विदेश मंत्री ने सितंबर 2024 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79^{वें} सत्र के इतर एल-69 समूह की संयुक्त मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया।



भारत ने गुयाना के सैन्य बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए 23.37 मिलियन अमरीकी डॉलर की रक्षा ऋण-सीमा (एलओसी) के हिस्से के रूप में दो डोर्नियर एचएएल-228 विमान सौंपे, नवंबर 2024

भारत ने उत्प्रवासन नीति (इमिग्रेशन पॉलिसी), कल्याण और प्रवासी भारतीय समुदाय से जुड़ाव में महत्वपूर्ण प्रगति की। सरकार ने डेनमार्क, इज़राइल, मलेशिया, ताइवान और यूके के साथ आप्रवासन और गतिशीलता भागीदारी समझौते (एमएमपीए) और श्रम गतिशीलता समझौते (एलएमए) सहित कई समझौतों के माध्यम से सुरक्षित और कानूनी आप्रवासन को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया।

श्रम गतिशीलता और रोजगार तंत्रों को सुव्यवस्थित करने के लिए यूके और इटली के साथ संयुक्त कार्यसमूह की बैठकें आयोजित की गईं। अबू धाबी वार्ता, बुडापेस्ट प्रोसेस, कोलंबो प्रोसेस और आप्रवासन एवं गतिशीलता पर भारत-यूरोपीय संघ उच्च स्तरीय वार्ता (एचएलडीएमएम) जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग ने वैश्विक आप्रवासन शासन में भारत की भूमिका को मजबूत किया। भारत ने 2024-26 के लिए कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता की और अबू धाबी वार्ता की सलाहकार समिति में सहभागिता की। सरकार ने भारतीय समुदाय कल्याण कोष (आईसीडब्ल्यूएफ) के तहत विदेशों में 3.5 लाख से अधिक भारतीय श्रमिकों की सहायता के लिए कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार किया और भारतीय प्रवासी श्रमिकों के सॉफ्ट स्किल को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रस्थान-पूर्व अभिविन्यास प्रशिक्षण को भी विस्तारित किया। नव-निर्मित ई-माइग्रेट वर्जन 2.0 पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, जिससे उत्प्रवासन प्रक्रिया सरल हो गई क्योंकि इनमें डिजिटल एकीकरण, शिकायत निवारण और ई-सत्यापन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। सरकार ने छात्रों के मुद्दों, एनआरआई महिलाओं के लिए वैवाहिक विवाद समाधान पर भी ध्यान केंद्रित किया तथा *प्रवासी भारतीय बीमा योजना* (पीबीबीवाई), *नो इंडिया प्रोग्राम* (केआईपी), और *विदेश संपर्क कार्यक्रम* जैसी पहलों के माध्यम से प्रवासी भारतीय समुदाय के साथ संपर्क साधा।

वर्ष के दौरान, मंत्रालय ने ट्रेक 1.5 और 2.0 डायलॉग जैसी कई विदेश नीति आउटरीच गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए थिंक-टैंक और शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग किया। मंत्रालय ने रायसीना संवाद, एशियाई आर्थिक संवाद, हिंद महासागर सम्मेलन, भारत-अमेरिका मंच, भारत-जापान मंच, भारत-नॉर्डिक संवाद, और भारत-यूरोपीय संघ ट्रेक 1.5 संवाद सहित प्रमुख विदेश नीति आउटरीच संवाद भी किए। मंत्रालय ने जापान, फ्रांस, नॉर्वे के विदेश मंत्रालयों के समकक्ष नीति नियोजन प्रभागों/ब्यूरो और ऑस्ट्रेलिया, जापान तथा अमेरिका के क्वाड सदस्य-देशों के साथ संयुक्त रूप से नीति नियोजन संवाद भी आयोजित किए। वर्ष के दौरान पहली लिपक्षीय भारत-जापान-कोरिया नीति नियोजन संवाद भी आयोजित किया गया।

भारत की बाह्य प्रचार और सार्वजनिक कूटनीति में डिजिटल कूटनीति, क्षेत्रीय मीडिया से जुड़ाव और प्रभावशाली सहयोग के माध्यम से 2024 में काफी विस्तार हुआ। इसकी प्रमुख पहलों में एक एमईए व्हाट्सएप चैनल शुरू करना, सोशल मीडिया उपस्थिति का विस्तार करना, विदेशी पत्रकारों की यात्राओं के लिए सुविधा प्रदान करना, फिल्म समारोहों का आयोजन करना, वृत्तचित्रों का निर्माण करना और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना शामिल हैं। इंडिया कॉर्नर, समीप (समीप) व्याख्यान और *भारत को जानिए* *क्विज* के माध्यम से सार्वजनिक संपर्क को बढ़ाया गया।



विदेश मंत्री और डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन ने फरवरी 2024 में गतिशीलता और आप्रवासन भागीदारी पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।



बाएं से दाएं घड़ी की दिशा में: मंत्रालय ने भारत-अमेरिका फोरम (नई दिल्ली), वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन नवाचार संवाद (बेंगलुरु), एशिया आर्थिक संवाद (पुणे), भारत-जापान फोरम (नई दिल्ली), हिंद महासागर सम्मेलन (पर्थ) और रायसीना संवाद (नई दिल्ली) सहित कई विदेश नीति आउटरीच गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए थिंक-टैंक एवं शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग किया।



विदेश मंत्री और क्वींसलैंड की गवर्नर जीनेट यंग ने ब्रिसबेन में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया, नवंबर 2024



सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान (एस एस आई एफ एस) में दूसरा ग्लोबल साउथ यंग डिप्लोमैट्स फोरम (जीएसवाईडीएफ) सितंबर 2024 में आयोजित किया गया।

वर्ष के दौरान, भारत ने लातविया, जॉर्जिया, गैबोनीज गणराज्य और तिमोर-लेस्ते में नए राजनयिक मिशन खोले। मार्सिले (फ्रांस), बार्सिलोना (स्पेन), ब्रिसबेन (ऑस्ट्रेलिया) और ऑकलैंड (न्यूजीलैंड) में नए वाणिज्य दूतावासों ने भी अपना संचालन शुरू कर दिया है।

सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान ने मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मियों, अन्य सिविल सेवाओं के सदस्यों और विदेशी राजनयिकों के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। ग्लोबल साउथ यंग डिप्लोमैट्स फोरम (जीएसवाईडीएफ) का दूसरा संस्करण सितंबर में ग्लोबल साउथ के 29 देशों के 32 राजनयिकों की भागीदारी के साथ आयोजित किया गया।

विदेशी राजनयिकों के लिए 71^{वाँ} व्यावसायिक पाठ्यक्रम (पीसीएफडी) अप्रैल-मई के दौरान 30 देशों के 34 राजनयिकों की भागीदारी के साथ आयोजित किया गया।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) ने सांस्कृतिक आदान-प्रदान और भारत की 'सॉफ्ट पावर' की वैश्विक पहुंच को बढ़ावा देता आ रहा है। शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में, आईसीसीआर ने अपनी 20 छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत विदेशी नागरिकों को 3960 छात्रवृत्ति स्लॉट

की पेशकश की, जिसमें ऑनलाइन स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की पढ़ाई करने हेतु अफगान नागरिकों के लिए 1000 छात्रवृत्तियाँ शामिल हैं। आईसीसीआर ने भारत से 62 सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडलों को दुनियाभर के देशों में प्रायोजित किया और नामतीचीन भारतीय नेताओं की 9 प्रतिमाएं एवं मूर्तियां विभिन्न देशों को दानस्वरूप भेंट कीं। आईसीसीआर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में 38 भारतीय सांस्कृतिक केंद्रों (आईसीसी) को सहायता प्रदान की।



विदेश मंत्री ने नाइजीरिया के अबुजा में उच्चायोग परिसर में (जनवरी) और जापान के टोक्यो में भारतीय दूतावास में (जुलाई) महात्मा गांधी की प्रतिमाओं का अनावरण किया।

अध्याय

1

भारत के पड़ोसी देश

अफ़गानिस्तान

भारत और अफ़गानिस्तान के बीच ऐतिहासिक संबंधों, सांस्कृतिक संबंधों और लोगों के बीच मज़बूत संबंधों के आधार पर घनिष्ठ संबंध हैं। अगस्त 2021 के बाद, अफ़गानिस्तान के प्रति भारत का दृष्टिकोण अपनी ऐतिहासिक मित्रता और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) संकल्प 2593 द्वारा निर्देशित है।

अगस्त 2021 से, भारत ने अफ़गानिस्तान के लोगों को मानवीय सहायता के कई खेप भेजी हैं, जिसमें 50,000 मीट्रिक टन गेहूँ और 300 टन दवाइयाँ तथा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा मदें शामिल हैं। जनवरी में, भारत ने अफ़गानिस्तान में टिड्डियों के खतरे से निपटने के लिए कीटनाशक मैलाथियान की 40,000 लीटर खुराक दी। मैलाथियान की आपूर्ति देश और अन्य मध्य एशियाई देशों में फसल सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है। भारत ने अफ़गानिस्तान में नशीली दवाओं और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनओडीसी) के साथ भी भागीदारी की है ताकि अफ़गान नशीली दवाओं का उपयोग करने वाली आबादी के लिए, विशेष रूप से महिलाओं के कल्याण के लिए सहायता प्रदान की जा सके। इस भागीदारी के तहत भारत ने 11,000 यूनिट महिला स्वास्थ्यकर/हाइजीन किट, शिशु आहार, सामान्य उपयोग वाली स्वास्थ्यकर किटें, कंबल, कपड़े, जूते, चिकित्सा सहायता और अन्य विविध वस्तुओं की आपूर्ति की है। ये वस्तुएं पूरे अफ़गानिस्तान में यूएनओडीसी के ड्रग ट्रीटमेंट सेंटर द्वारा वितरित की जा रही हैं। भारत ने इस साल हबीबिया हाई स्कूल, काबुल को सर्दियों के कपड़ों की 500 यूनिट और 1.2 टन स्टेशनरी किटों की सहायता भी दी है।

शिक्षा और क्षमता निर्माण कार्यक्रम अफ़गानिस्तान के साथ भारत की विकास भागीदारी का एक महत्वपूर्ण पहलू हैं। 2023 से, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) छात्रवृत्ति योजना के तहत ई-विद्याभारती पोर्टल के माध्यम से 580 लड़कियों सहित 2000 अफ़गान छात्रों को ऑनलाइन छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। भारत ने अफ़गानिस्तान राष्ट्रीय कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एएनएएसटीयू) के सहयोग से कृषि से संबंधित क्षेत्रों में अफ़गान छात्रों के लिए ऑनलाइन छात्रवृत्ति प्रदान की। कंधार में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय अफ़गान छात्रों के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान करता है। एएनएएसटीयू की स्थापना भारत सरकार के समर्थन से की गई थी।

दोनों देशों ने इस वर्ष खेल के क्षेत्र में बातचीत जारी रखी। अफ़गान क्रिकेट बोर्ड (एसीबी) और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने जून में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे अफ़गान क्रिकेट टीम ग्रेटर नोएडा और कानपुर में क्रिकेट स्टेडियमों का उपयोग घरेलू मैदान के रूप में कर सकेगी।

2024 में, भारत ने अफ़गानिस्तान में स्थिरता और शांति बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में सक्रिय रूप से भूमिका निभाई और दोहा में संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में बैठकों, मॉस्को फ़ॉर्मेट और ओस्लो फ़ोरम सहित विभिन्न बैठकों/फ़ॉर्मेट में भाग लिया। इसके अतिरिक्त, 2022 से काबुल में एक भारतीय तकनीकी टीम तैनात है, जो मानवीय सहायता के साथ अफ़गानिस्तान के लोगों को सक्रिय रूप से सहायता प्रदान कर रही है।



भारत ने अफगानिस्तान में टिड्डियों के खतरे से निपटने के लिए 40,000 लीटर मैलाथियान कीटनाशक की मंजूरी प्रदान की, जनवरी 2024.

बांग्लादेश

भारत और बांग्लादेश इतिहास, भाषा, संस्कृति और कई अन्य समानताओं को साझा करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में, भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग, व्यापार और आर्थिक संबंधों, विकास भागीदारी, सांस्कृतिक और लोगों के बीच आदान-प्रदान जैसे विविध क्षेत्रों में सहयोग स्थापित करके विकसित हुए हैं।

बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जबकि भारत हाल ही के वर्षों में एशिया में बांग्लादेश का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन गया है। इसके अतिरिक्त, बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा विकास भागीदार है, और भारत ने बांग्लादेश को लगभग 10 बिलियन अमरीकी डॉलर की रियायती ऋण राशि प्रदान की है, जिसमें इसकी तीन सबसे बड़ी द्विपक्षीय ऋण सुविधाएं (एलओसी) शामिल हैं।

जून 2024 के अंत में बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के लिए नौकरियों में कोटा और आरक्षण के मुद्दे पर मुख्य रूप से छात्रों के नेतृत्व में सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों का सामना करना पड़ा। ये विरोध प्रदर्शन विशेष रूप से जुलाई 2024 के मध्य से हिंसक हो गए थे। ढाका में अवामी लीग सरकार गिर गई और उसकी जगह मुख्य सलाहकार के रूप में प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बनी।

उच्च स्तरीय दौरे

इस वर्ष दोनों पक्षों के बीच लगातार उच्च स्तरीय बातचीत हुई। बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अन्य हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) नेताओं के साथ 09 जून को राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। उन्होंने 21-22 जून को भारत की

राजकीय यात्रा भी की। जून में केंद्र सरकार के गठन के बाद यह भारत की पहली द्विपक्षीय राजकीय यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग, समुद्र विज्ञान, उपग्रह के संयुक्त प्रक्षेपण में सहयोग, हरित भागीदारी, डिजिटल भागीदारी, स्वास्थ्य, मत्स्य पालन, आपदा प्रबंधन और रेल संपर्क से जुड़े दस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।

बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन के बाद प्रधानमंत्री मुख्य सलाहकार यूनुस को बधाई देने वाले पहले विश्व नेता थे। दोनों पक्षों ने 16 अगस्त को टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर मुख्य सलाहकार यूनुस ने 17 अगस्त को वर्चुअल मोड में आयोजित वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट (वीओजीएसएस) के तीसरे संस्करण में भाग लिया। विदेश मंत्री ने 24 सितंबर को न्यूयॉर्क में आयोजित 79^{वां} संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के इतर बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन से मुलाकात की।

बांग्लादेश के तत्कालीन विदेश मंत्री हसन महमूद ने 07-09 फरवरी को भारत की आधिकारिक यात्रा की। विदेश सचिव ने दोनों देशों के बीच यात्राओं और आदान-प्रदान की गति को बनाए रखने के लिए 08-09 मई को ढाका का दौरा किया। विदेश सचिव ने 09 दिसंबर को ढाका का दौरा किया और मुख्य सलाहकार यूनुस तथा विदेश मामलों के सलाहकार हुसैन से मुलाकात की। अपनी यात्रा के दौरान, विदेश सचिव ने बांग्लादेश के विदेश सचिव जशीम उद्दीन के साथ विदेश कार्यालय परामर्श (एफओसी) भी किया। इसके अतिरिक्त, विदेश सचिव ने हाल ही के घटनाक्रमों और मुद्दों पर चर्चा की और भारत की चिंताओं, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा एवं कल्याण से संबंधित चिंताओं से अवगत कराया। उन्होंने आपसी विश्वास, सम्मान और एक-दूसरे की चिंताओं एवं हितों के प्रति आपसी संवेदनशीलता के आधार पर बांग्लादेश के साथ सकारात्मक और रचनात्मक संबंध बनाने की भारत की इच्छा को दोहराया।



विदेश मंत्री ने न्यूयॉर्क में 79^{वाँ} यूएनजीए सम्मेलन के इतर बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन से मुलाकात की, सितम्बर 2024.

रक्षा और सुरक्षा सहयोग

भारत और बांग्लादेश सशस्त्र बलों के प्रमुखों की आगता एवं निर्गामी (इनकमिंग एंड आउटगोइंग) यात्राओं तथा दोनों देशों के युद्ध-निपुण सैनिकों और सेवारत अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ 2023-2024 में महत्वपूर्ण द्विपक्षीय आदान-प्रदान हुआ।

विजय दिवस के अवसर पर मुक्तिजोधाओं (लिबरेशन वार वेटरन्स) की वार्षिक यात्रा के हिस्से के रूप में, मुक्तिजोधाओं और बांग्लादेश सशस्त्र बलों (बीडीएफ) के कुछ सेवारत अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिसंबर 2023 में कोलकाता में 'विजय दिवस 2023' समारोह में भाग लिया। बदले में, 30 युद्ध-निपुण सैनिकों और भारतीय सशस्त्र बलों (आईएएफ) के 6 सेवारत अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने ढाका में विजय दिवस समारोह में भाग लिया। मुक्तिजोधाओं के लिए छात्रवृत्ति योजना के तहत, भारत सरकार बांग्लादेश में उच्चतर माध्यमिक और स्नातकपूर्व शिक्षा के

लिए युद्ध-निपुण सैनिकों के बच्चों को सालाना 2000 छात्रवृत्तियाँ प्रदान करती है। अब तक 24,018 छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जा चुकी हैं। 2019 से मुक्तिजोधाओं को मुक्तिजोधा चिकित्सा योजना के तहत भारत में चिकित्सा उपचार प्राप्त करने की सुविधा भी दी जा रही है।

बांग्लादेश के निमंत्रण पर, आईएएफ प्रमुख ने 26 फरवरी-01 मार्च को ढाका का दौरा किया। बांग्लादेश की अपनी तीन दिवसीय यात्रा के दौरान, आईएएफ प्रमुख ने बांग्लादेश वायु सेना अकादमी, जेसोर और राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, मीरपुर का दौरा किया। कमांडेंट एनडीसी के नेतृत्व में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय (एनडीसी), बांग्लादेश के तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मई में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, नई दिल्ली का दौरा किया। भारत के नौसेना प्रमुख ने जुलाई में बांग्लादेश का दौरा किया और बांग्लादेश नौसेना अकादमी में पासिंग आउट परेड की समीक्षा की। भारत और बांग्लादेश के सेना प्रमुखों ने 05 नवंबर को एक वर्चुअल बैठक की और सहयोग के क्षेत्रों की पहचान की।



भारत के नौसेना प्रमुख जुलाई 2024 में चटगाँव में बांग्लादेश नौसेना अकादमी में पासिंग आउट परेड की समीक्षा करने वाले पहले विदेशी सेवा प्रमुख थे।

आर्थिक और व्यापार सहयोग

बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जबकि भारत एशिया में बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। बांग्लादेश ने वित्त वर्ष 2023-24 में भारत को 1.84 बिलियन अमरीकी डॉलर का सामान निर्यात किया, जबकि अप्रैल से सितंबर 2024 के बीच भारत को उसका निर्यात 0.97 बिलियन अमरीकी डॉलर था। वित्त वर्ष 2023-24 में कुल द्विपक्षीय व्यापार 12.90 बिलियन अमरीकी डॉलर था और सितंबर 2024 तक द्विपक्षीय व्यापार 6.168 बिलियन अमरीकी डॉलर था।

विकास सहयोग

बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा विकास भागीदार है और भारत ने पिछले 8 वर्षों में बांग्लादेश को 3 ऋण सुविधाएं (एलओसी) प्रदान की हैं, जो कि सड़क, रेलवे, शिपिंग और बंदरगाहों सहित विभिन्न क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए लगभग 8 बिलियन अमरीकी डॉलर की राशि है। एलओसी के अलावा, भारत सरकार बांग्लादेश को विभिन्न बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिए अनुदान सहायता प्रदान कर रही है, जिसमें अखौरा-अगरतला रेल लिंक का निर्माण और बांग्लादेश में अंतर्देशीय जलमार्गों की ड्रेजिंग शामिल है। अखौरा-अगरतला सीमा पार रेल लिंक परियोजना नवंबर 2024 में पूरी हुई, जो एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई क्योंकि इसने भारत के पूर्वोत्तर को बांग्लादेश से रेल द्वारा पहली बार जोड़ा और इस क्षेत्र में रेल-संपर्क बढ़ाने में सहायता की। इसके अतिरिक्त, खुलना-मोंगला पोर्ट रेल लाइन, जो कि एक महत्वपूर्ण एलओसी परियोजना है, नवंबर 2023 में पूरी हुई। यह मोंगला पोर्ट को जोड़ने वाली पहली रेल परियोजना है।

उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाएँ (एचआईसीडीपी) भी बांग्लादेश में भारत की विकास सहायता का एक सक्रिय स्तंभ हैं, जिसके

तहत छात्रावासों, शैक्षणिक भवनों, कौशल विकास और प्रशिक्षण संस्थानों, सांस्कृतिक केंद्रों, अनाथालयों का निर्माण और साझा सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार शामिल है।

कनेक्टिविटी

कनेक्टिविटी द्विपक्षीय सहयोग का एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र रहा है। दोनों पक्ष द्विपक्षीय और उप-क्षेत्रीय दृष्टि से नागरिकों और वस्तुओं की निर्बाध आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। रेल, सड़क और जलमार्गों को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं क्योंकि इनसे दोनों पक्षों के नागरिक एवं अर्थव्यवस्थाएं पारंपरिक रूप से आपस में जुड़ती हैं और नई सुविधाएं स्थापित होती हैं।

भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्गों पर ब्रह्मपुत्र और कुशियारा नदी के दो महत्वपूर्ण हिस्सों की ड्रेजिंग भारत और बांग्लादेश संयुक्त रूप से कर रहे हैं। यह अनुदान सहायता के तहत चल रही एक परियोजना है, जिसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश के साथ-साथ देश के बाकी हिस्सों से जोड़ना है। भारत ने बांग्लादेश रेलवे को 420 रेलवे फ्रेट वैगन भी दिए हैं।

दोनों देश उप-क्षेत्रीय संपर्क व कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल (बीबीआईएन) मोटर वाहन समझौते के कार्यान्वयन को अंतिम रूप दे रहे हैं।

26 अक्टूबर को, पश्चिम बंगाल के पेट्रापोल में एकीकृत चेक पोस्ट (आईसीपी) पर एक नए अत्याधुनिक यात्री टर्मिनल भवन और एक द्वितीय द्वार नामतः “मैत्री द्वार” का उद्घाटन किया गया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार सुविधा को काफी ज्यादा बढ़ाना है।



भारत ने भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार सुविधा को और भी अधिक बढ़ाने के लिए पश्चिम बंगाल के पेट्रापोल में एकीकृत चेक पोस्ट (आईसीपी) पर एक यात्री टर्मिनल भवन और द्वितीय द्वार नामतः “मैत्री द्वार” का उद्घाटन किया, अक्टूबर 2024.

बिजली और ऊर्जा सहयोग

बिजली और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग भारत-बांग्लादेश संबंधों के महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) को 2023 में G2G आपूर्तिकर्ता के रूप में पंजीकृत किया गया था और तब से यह बांग्लादेश को पेट्रोलियम, तेल और लुब्रीकेंट (पीओएल) उत्पादों की आपूर्ति करता आ रहा है। ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) एक कंशोरियम में अपतटीय (ऑफ-शोर) तेल अन्वेषण का कार्य करता है।

बिजली पर संयुक्त कार्यसमूह (जेडब्ल्यूजी)/संयुक्त संचालन समिति (जेएससी) दोनों देशों के बीच बिजली के सीमा पार व्यापार में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक संस्थागत ढांचा प्रदान करता है। बांग्लादेश वर्तमान में भारत और मैती सुपर थर्मल पावर प्लांट (2 x 600 मेगावाट) से 1160 मेगावाट बिजली आयात करता है। यह संयंत्र 2023 में चालू हो गया था और बांग्लादेश ग्रिड को बिजली की आपूर्ति कर रहा है।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनईए), एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (एनवीवीएन) और बांग्लादेश विद्युत विकास बोर्ड (बीपीडीबी) के बीच लिपक्षीय विद्युत बिक्री समझौते पर 03 अक्टूबर 2024 को हस्ताक्षर किए गए जिसे नवंबर में क्रियान्वित किया गया। इस समझौते का उद्देश्य भारतीय ग्रिड के माध्यम से नेपाल से बांग्लादेश को 40 मेगावाट जलविद्युत की बिक्री को सुगम बनाना है और यह ऊर्जा एवं बिजली क्षेत्र में उप-क्षेत्रीय सहयोग स्थापित करने की दिशा में पहला कदम है।

क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास

मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण बांग्लादेश में भारत के विकास सहयोग प्रयासों का एक प्रमुख घटक है, जिसे कई चालू प्रशिक्षण कार्यक्रमों और छात्रवृत्तियों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है। भारत बांग्लादेशी अधिकारियों को सिविल सेवाओं, पुलिस, न्यायपालिका के साथ-साथ अन्य पेशवरों को भारत के विभिन्न प्रमुख प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। वर्ष 2023-24 में, 558 सिविल सेवकों और 249 न्यायिक अधिकारियों ने प्रशासन, पुलिस, सीमा शुल्क, मादक पदार्थों की जांच और परमाणु विज्ञान सहित अनेक क्षेत्रों में भारतीय संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त किया। अगस्त-नवंबर 2024 के बीच, 40 बांग्लादेशी नागरिकों को आईटीईसी छात्रवृत्ति प्रदान की गई। भारत सरकार ने 524 बांग्लादेशी छात्रों को आईसीसीआर छात्रवृत्ति प्रदान की और 700 बांग्लादेशी छात्रों को 2024-25 के दौरान भारत में स्व-वित्तपोषित कॉलेजों में दाखिला लेने में सहायता की। भारत द्वारा बांग्लादेशी पुलिस और न्यायिक अधिकारियों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम भी फिर से शुरू किए जा रहे हैं।

सांस्कृतिक सहयोग

सांस्कृतिक मोर्चे पर, 100 सदस्यीय बांग्लादेशी युवा प्रतिनिधिमंडल ने फरवरी में भारत का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने शैक्षणिक और सांस्कृतिक हितों के कई प्रमुख स्थलों का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल ने

माननीय राष्ट्रपति जी से भी मुलाकात की। ढाका स्थित प्रसिद्ध नृत्य विद्यालय 'कोलपोटोरू' के नौ सदस्यीय बांग्लादेशी नृत्य दल ने 15-22 नवंबर को कटक में आयोजित 'बाली यात्रा महोत्सव 2024' में भाग लिया। बांग्लादेशी कलाकारों ने रवींद्रनाथ टैगोर और काजी नजरुल इस्लाम की कृतियों से प्रेरित होकर नृत्य प्रदर्शन किए।

भूटान

भारत और भूटान के बीच द्विपक्षीय संबंध बेहतरीन हैं, जो आपसी विश्वास, समझ और सभी स्तरों पर सद्भावना तथा लोगों के बीच बेहतरीन संपर्कों के सूचक हैं। द्विपक्षीय संबंधों में सहयोग के सभी क्षेत्रों यानी व्यापार और आर्थिक संपर्क, ऊर्जा, कौशल विकास और क्षमता निर्माण, विकास सहयोग, खेल और युवाओं का आदान-प्रदान, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्यायपालिका, पर्यावरण का संरक्षण, प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्रों में निरंतर प्रगति देखी गई।

पूरे वर्ष में कई उच्च स्तरीय आदान-प्रदान हुए, जिनमें प्रधानमंत्री की भूटान की राजकीय यात्रा, भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक की भारत की आधिकारिक यात्रा, भूटान के प्रधानमंत्री की भारत की आधिकारिक यात्रा और अन्य मंत्रिस्तरीय यात्राएँ शामिल हैं। इन यात्राओं के फलस्वरूप तीन संयुक्त वक्तव्यों का प्रकाशन हुआ, जिससे द्विपक्षीय भागीदारी को राजनीतिक दिशा और गति मिली।

भूटान के साथ विकास सहयोग और भी विस्तारित हुआ है, क्योंकि भूटान ने 2024 से 2029 तक अपनी 13^{वाँ} पंचवर्षीय योजना (एफवाईपी) में प्रवेश किया है, जिसके लिए भारत सरकार ने योजना के लिए भूटान को अपनी सहायता दोगुनी कर दी है। भारत की सहायता से भूटान में निर्माणाधीन जलविद्युत परियोजनाओं में भी प्रगति आई है। पुंतासांगछू II जलविद्युत परियोजना पूरी होने वाली है। दोनों पक्षों ने ऊर्जा भागीदारी पर एक ज्वाइंट विजन स्टेटमेंट के जरिए पारस्परिक रूप से लाभकारी ऊर्जा सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की।

सितंबर में आयोजित वाणिज्य सचिव-स्तरीय वार्ता के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने के कारण व्यापार और आर्थिक सहयोग का विस्तार हुआ। असम के दर्रागा में आईसीपी का उद्घाटन और रेल संपर्क स्थापित करने की प्रगति ने सीमा पार कनेक्टिविटी पहलों को सकारात्मक गति प्रदान की है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) की भूटान यात्रा के साथ न्यायपालिका क्षेत्र में सहयोग को गति प्राप्त हुई। स्वास्थ्य, खेल और युवा पहलें, शिक्षा एवं क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों में भी वर्ष के दौरान प्रगति देखी गई।

उच्च स्तरीय आदान-प्रदान

प्रधानमंत्री ने 22-23 मार्च को भूटान की ऐतिहासिक राजकीय यात्रा की। उन्हें भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक द्वारा भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान “ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो” से सम्मानित किया गया।



प्रधानमंत्री को भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरींग तोबगे की उपस्थिति में भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक द्वारा भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान “ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो” से सम्मानित किया गया, अक्टूबर 2024.

उनकी यात्रा के दौरान ऊर्जा दक्षता, पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति, खेल और युवा मामले, फार्माकोपिया, अंतरिक्ष, डिजिटल नेटवर्क और खाद्य सुरक्षा सहित सात समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।

भूटान के राजा ने 05-06 दिसंबर को भारत का आधिकारिक दौरा किया और प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री तथा भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरींग तोबगे ने इस साल भारत की चार आधिकारिक यात्राएँ कीं, जिसमें मार्च में उनकी पहली विदेश यात्रा और जून में प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में यात्रा शामिल है। नवंबर में, उन्होंने असम के दर्रागा में आईसीपी के उद्घाटन में और नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (आईसीए) के वैश्विक सहकारी सम्मेलन में भाग लिया।

सीजेआई ने 07-10 अक्टूबर को भूटान का दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान, सीजेआई ने भूटान में जिग्मे सिंग्ये वांगचुक (जेएसडब्ल्यू) स्कूल ऑफ लॉ के तीसरे स्नातक समारोह में भाग लिया। विधिक सहयोग के क्षेत्र में न्यायपालिका सहयोग पर दो उच्चतम न्यायालयों के बीच समझौता ज्ञापन सहित चार समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।

असम के मुख्यमंत्री ने भूटान के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने और असम-भूटान सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए 16-19 दिसंबर को भूटान का दौरा किया।

2024 में, भारत और भूटान ने नियमित मंत्रिस्तरीय बैठकों के माध्यम से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना जारी रखा। भूटान के विदेश मामलों और विदेश व्यापार मंत्री ल्योनपो डी.एन. धुंग्येल ने रायसीना



विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से मुलाकात की, दिसंबर 2024.



विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित रायसीना वार्ता के दौरान भूटान के विदेश मामलों और विदेश व्यापार मंत्री ल्योनपो डी.एन. धुंग्येल से मुलाकात की, फरवरी 2024.

वार्ता के लिए फरवरी में भारत का दौरा किया और जुलाई में आयोजित बंगाल खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल (बिम्सटेक) विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक में भाग लिया। मंत्री धुंग्येल ने अपनी दोनों यात्राओं के दौरान विदेश मंत्री से मुलाकात की।

भूटान के ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन मंत्री ल्योनपो जेम शेरिंग ने जुलाई में पुनात्सांगचू-II जलविद्युत परियोजना प्राधिकरण की बैठक के लिए भारत का दौरा किया। 14-18 अक्टूबर को देश की अपनी दूसरी यात्रा के दौरान, उन्होंने बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री के साथ बैठक की।

इस वर्ष भूटान के मंत्रियों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों द्वारा भारत के कई दौरे भी किए गए। अवसंरचना और परिवहन मंत्री ल्योनपो चंद्र बहादुर गुरुंग ने नागरिक उड्डयन पर दूसरे एशिया-प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के लिए सितंबर में भारत का दौरा किया। कृषि और पशुधन मंत्री ल्योनपो यूंटेन फुंत्शो ने नई दिल्ली में आयोजित तीसरे विश्व खाद्य भारत कार्यक्रम के लिए सितंबर में भारत का दौरा किया। वित्त मंत्री ल्योनपो लेके दोरजी ने अक्टूबर में तीसरे कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन के लिए भारत का दौरा किया। मंत्री दोरजी ने दिसंबर में नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक आर्थिक नीति फोरम में भी भाग लिया। स्वास्थ्य मंत्री ल्योनपो टंडिन वांगचुक ने अक्टूबर में दक्षिण पूर्व एशिया के लिए डब्ल्यूएचओ क्षेत्रीय समिति के 77^{वाँ} सत्र के लिए भारत का दौरा किया। उद्योग, वाणिज्य और रोजगार मंत्री ल्योनपो नामग्याल दोरजी ने दिसंबर में सीआईआई भागीदारी शिखर सम्मेलन के लिए भारत का दौरा किया।

असम के मुख्यमंत्री ने भूटान के राष्ट्रीय दिवस में भाग लेने और असम-भूटान सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए 16-19 दिसंबर को भूटान का दौरा किया।

भूटान के विदेश सचिव पेमा चोडेन ने भूटान की 13^{वाँ} पंचवर्षीय योजना के दूसरी भारत-भूटान विकास सहयोग वार्ता (योजनाबद्ध वार्ता) की सह-अध्यक्षता करने के लिए मार्च में भारत का दौरा किया। 2024 में, विदेश सचिव ने जुलाई में योजनाबद्ध वार्ता की तीसरी बैठक की सह-अध्यक्षता करने और नवंबर में द्विपक्षीय चर्चाओं में भाग लेने के लिए दो बार भूटान का दौरा किया।

विकास सहयोग

मार्च में प्रधानमंत्री की भूटान यात्रा के दौरान, भारत सरकार ने भूटान की 13^{वाँ} पंचवर्षीय योजना के लिए 11.5 बिलियन अमरीकी डॉलर के विकास समर्थन की प्रतिबद्धता जताई। भारत की सहायता परियोजना-बद्ध सहायता (पीटीए), एचआईसीडीपी, भूटान के आर्थिक प्रोत्साहन कार्यक्रम (ईएसपी) और कार्यक्रम अनुदान के लिए निमित्त किया जाएगा। भारत सरकार के पीटीए के तहत 61 परियोजनाओं की पहली किश्त, जो कि लगभग 576 मिलियन अमरीकी डॉलर की राशि है, पर दोनों पक्षों के बीच सहमति जुलाई में आयोजित योजनाबद्ध वार्ता के दौरान हुई। एचआईसीडीपी परियोजनाओं के पहले बैच, जिसकी राशि लगभग 480 मिलियन अमरीकी डॉलर है, पर दोनों पक्षों के बीच सहमति दिसंबर में आयोजित पहली एचआईसीडीपी समिति की बैठक के दौरान हुई।

2024 में पूरी की गई उल्लेखनीय विकास परियोजनाओं में, ग्यालत्सुएन जेट्सन पेमा वांगचुक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल, थिम्पू एक्वाटिक सेंटर, चुखा में तकती ब्रिज और थिम्पू में पंगरीज़ाम्पा ब्रिज, लिंग्ज़ी द्ज़ोंग, और उन्नत प्राथमिक बोर्डिंग स्कूल शामिल हैं। इसके अलावा, क्रिकेट और शूटिंग के लिए रामा सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस का शिलान्यास समारोह 01 दिसंबर को आयोजित किया गया।

व्यापार और कनेक्टिविटी

आयात स्रोत के साथ-साथ निर्यात गंतव्य के रूप में भी भारत भूटान का शीर्ष व्यापारिक भागीदार है, जिसमें भूटान के कुल व्यापार में भारत का हिस्सा 80 प्रतिशत से अधिक है। सितंबर 2024 तक भूटान के साथ भारत का वस्तुओं का कुल व्यापार 10.28 बिलियन अमरीकी डॉलर था, जबकि भूटान को निर्यात 7.73 बिलियन अमरीकी डॉलर और आयात 2.54 बिलियन अमरीकी डॉलर था।

21-22 मार्च को प्रधानमंत्री की भूटान की राजकीय यात्रा के दौरान, दोनों देशों ने द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें भारत से भूटान को पीओएल और संबंधित उत्पादों की सामान्य आपूर्ति पर समझौता ज्ञापन, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (फसाई) द्वारा भूटान खाद्य और औषधि प्राधिकरण (बीएफडीए) द्वारा किए गए आधिकारिक नियंत्रण को मान्यता देने के लिए समझौता, और भारत एवं भूटान के बीच रेल-लिंक की स्थापना पर समझौता ज्ञापन के पाठ को अंतिम रूप देना शामिल है। रेल मंत्रालय रेल लिंक के लिए अंतिम स्थान का सर्वेक्षण (एफएलएस) कर रहा



भूटान के राजकुमार जिग्येल उग्येन वांगचुक और भूटान में भारत के राजदूत ने रामा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्रिकेट एंड शूटिंग के शिलान्यास समारोह में भाग लिया, जो 20,000 सीटों वाला अत्याधुनिक क्रिकेट स्टेडियम और एक आधुनिक शूटिंग रेंज है। यह सेंटर भूटान-भारत मैत्री परियोजना के तहत निर्मित की गई है, दिसंबर 2024।

है जिसकी सहमति दोनों देशों के बीच कोकराझार-गोलेफू रेल लिंक और बनारहाट-समस्ते रेल लिंक सहित एमओयू के तहत हुई।

भूटान सहित दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) देशों हेतु 2024-27 की अवधि के लिए मुद्रा विनिमय व्यवस्था (एफसीएसए) पर एक नया फ्रेमवर्क जून में लागू हुआ। भूटान ने एफसीएसए सुविधा का लाभ फ्रेमवर्क के तहत शुरू की गई आईएनआर विंडो के माध्यम से उठाया।

वाणिज्य सचिव ने भारत-भूटान वाणिज्य सचिव स्तरीय बैठक (सीएसएलएम) की सह-अध्यक्षता करने के लिए सितंबर में भूटान का दौरा किया। सीएसएलएम के दौरान लिए गए प्रमुख निर्णयों में, भूटान से सुपारी के आयात के लिए अतिरिक्त मार्गों की अधिसूचना, भूटान से खाद्य पदार्थों के आयात के लिए अतिरिक्त प्रवेश मार्ग की अधिसूचना, भारत-भूटान सीमा से सेटे सीमा हाटों की स्थापना, भूटान से आयात के लिए लकड़ी की अतिरिक्त प्रजातियों को समावेशन और पादप संगरोध निरीक्षण सेवाओं (पीक्यूआईएस) के लिए लैंड कस्टम्स स्टेशन (एलसीएस) दर्रागा में कर्मियों की तैनाती शामिल है।

नवंबर में, तीसरे देश के नागरिकों के भूमि मार्ग से प्रवेश और निकास को सुविधाजनक बनाने तथा कनेक्टिविटी एवं पर्यटन को बढ़ाने के लिए दर्रागा (असम) में एक आईसीपी का उद्घाटन किया गया। चेक पोस्ट खोलने पर पिछले साल भूटान के राजा की भारत यात्रा के दौरान सहमति बनी थी।

ग्यालसुंग-भूटान के राष्ट्रीय सेवा कार्यक्रम पर द्विपक्षीय सहयोग

भारत सरकार ने भूटान के राष्ट्रीय सेवा कार्यक्रम 'ग्यालसुंग' का समर्थन किया है, जो भूटान के राजा की एक विशेष पहल है, जिसका उद्देश्य भूटानी युवाओं को महत्वपूर्ण कौशल से सशक्त करना और राष्ट्र निर्माण के प्रयासों में योगदान देना है। 20 जनवरी को, भारत ने भूटान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत भारत द्वारा ग्यालसुंग एकेडमियों के

लिए बुनियादी ढाँचा बनाने के लिए लगभग 1.73 बिलियन अमरीकी डॉलर का रियायती ऋण दिया गया। इससे पहले, भारत ने ग्यालसुंग कार्यक्रम के लिए भूटान को 230 मिलियन अमरीकी डॉलर की अनुदान सहायता प्रदान की थी।

बिजली और ऊर्जा सहयोग

जलविद्युत क्षेत्र में सहयोग भारत-भूटान संबंधों का एक केंद्रीय स्तंभ है। भारत-भूटान ऊर्जा भागीदारी पर संयुक्त विज्ञान दस्तावेज़ मार्च में प्रधानमंत्री की भूटान यात्रा के दौरान जारी किया गया। विज्ञान दस्तावेज़ के अनुसार, दोनों पक्ष ऊर्जा भागीदारी को बढ़ाने और जलविद्युत, सौर और हरित हाइड्रोजन के क्षेत्रों में नई ऊर्जा परियोजनाओं को विकसित करने पर सहमत हुए, जिसमें रणनीतिक साझेदारों के रूप में भारतीय संस्थाओं की भागीदारी भी शामिल है। निकाछू जलविद्युत परियोजना (एचईपी) ने मई में भारतीय ऊर्जा के विनिमय के माध्यम से अधिशेष बिजली का निर्यात शुरू किया। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के अवसरों की पहचान करने के लिए 28 अक्टूबर को थिम्पू में भारत-भूटान रिन्यूवेबल एनर्जी राउंडटेबल सम्मेलन आयोजित किया गया।

वर्तमान में, भारत भूटान में दो जलविद्युत परियोजनाओं का निर्माण कर रहा है - 1200 मेगावाट की क्षमता वाली पुनात्सांगछू-I परियोजना और 1020 मेगावाट की क्षमता वाली पुनात्सांगछू-II परियोजना। पुनात्सांगछू-II एचईपी की पहली दो इकाइयाँ दिसंबर में चालू की गईं।

पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन

पर्यावरण पर पहला संयुक्त कार्यसमूह 21 अक्टूबर को भूटान में आयोजित किया गया। चर्चाएं संस्थागत संबंध बनाने और पर्यावरण, अपशिष्ट प्रबंधन तथा जलवायु के क्षेत्र में भागीदारी को मजबूत करने पर केंद्रित थीं।

अंतरिक्ष सहयोग

मार्च में प्रधानमंत्री की भूटान यात्रा के दौरान, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और भूटान की गव टेक एजेंसी ने एक संयुक्त कार्य योजना (जेपीओए) पर हस्ताक्षर किए, जो अंतरिक्ष क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के लिए एक ठोस रोडमैप प्रदान करती है। अंतरिक्ष सहयोग पर जेपीओए के तहत भारत-भूटान जेडब्ल्यूजी की पहली बैठक 06 सितंबर को थिम्पू में हुई। जेपीओए के अनुरूप, इसरो ने दक्षिण एशिया उपग्रह पर भूटान को अतिरिक्त 16 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ आवंटित किया।

शिक्षा और क्षमता निर्माण

आईटीईसी के तहत सरकारी अधिकारियों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के प्रशासनिक और तकनीकी कौशल को उन्नत करने के लिए भूटान को 325 व्यक्तिगत प्रशिक्षण स्लॉट आवंटित किए गए हैं। भूटानी सिविल सेवा अधिकारी हर साल अग्रणी भारतीय प्रशासनिक तथा अन्य विशेष प्रशिक्षण संस्थानों और अकादमियों में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। भारत सरकार द्वारा भूटानी छात्रों को भारत में अध्ययन करने के लिए सालाना 1,200 से अधिक छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जा रही हैं। भारत सरकार ने इस वर्ष भूटानी स्कूलों में पढ़ाने के लिए स्टेम विषयों में 24 नए भारतीय शिक्षकों की भर्ती भी की। युवा विनिमय कार्यक्रम के तहत, जनवरी में गणतंत्र दिवस के लिए एक भूटानी स्काउट्स प्रतिनिधिमंडल ने भारत का दौरा किया और दिसंबर

में आयोजित भूटान के राष्ट्रीय दिवस समारोह में एक राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया।

खेल सहयोग

खेल और युवा मामले संबंध भारत-भूटान भागीदारी के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में उभरा है। प्रधानमंत्री की भूटान यात्रा के दौरान, दोनों पक्षों ने खेल और युवा मामले क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य दोनों देशों की खेल एजेंसियों के बीच संबंधों को आगे बढ़ाकर और खेल गतिविधियों/कार्यक्रमों का आयोजन करके दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को आगे बढ़ाना है। भूटान के दो प्रतिनिधिमंडलों ने धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम सहित भारत में खेल परिसरों का दौरा किया।

मालदीव

भारत और मालदीव के बीच जातीय, भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक और वाणिज्यिक संबंध प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं। मालदीव भारत की 'पड़ोसी पहले' नीति और 'क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास' (सागर) के दृष्टिकोण के तहत एक विशेष स्थान रखता है। इस वर्ष द्विपक्षीय बातचीत में और तेज़ी आई, जिसमें नेतृत्व और मंत्रिस्तरीय स्तर पर बातचीत शामिल है।



मालदीव गणराज्य के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद मुइज़ू ने भारत में अपनी पहली राजकीय यात्रा के दौरान नई दिल्ली में माननीय राष्ट्रपति जी से मुलाकात की, अक्टूबर 2024.



विदेश मंत्री ने अड्डू शहर में भारत सरकार की सहायता से पूर्ण किए गए अड्डू रिक्लेमेशन और शोर प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट के हस्तांतरण समारोह में अपनी टिप्पणियां दीं, अगस्त 2024.

उच्च स्तरीय यात्राएँ

मालदीव के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद मुइजु ने इस वर्ष दो बार भारत का दौरा किया। उन्होंने जून में प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया और 06-10 अक्टूबर को देश की अपनी पहली राजकीय यात्रा की। राजकीय यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मुइजु ने भारत-मालदीव के बीच 'व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा भागीदारी' विज़न को अंगीकृत किया, जो दोनों के बीच संबंधों के लिए पहला था। विज़न दस्तावेज़ में कार्रवाई-उन्मुख तरीके से द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के तरीकों की रूपरेखा दी गई है। यात्रा के दौरान दोनों पक्षों के बीच एक मुद्रा विनिमय समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए, जिससे मालदीव को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) से 400 मिलियन अमरीकी डॉलर (यूएसडी/यूरो विंडो में) और 3,000 करोड़ रुपये (भारतीय रुपये विंडो में) प्राप्त करने में सहायता मिली।

मालदीव के तत्कालीन विदेश मंत्री मूसा ज़मीर ने 08-10 मई को भारत का दौरा किया और उसके बाद पर्यटन मंत्री इब्राहिम फैसल ने जुलाई में भारत का दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान, मंत्री फैसल ने पर्यटन मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने 09-11 अगस्त को मालदीव की यात्रा की, जो जून में केंद्र सरकार के गठन के बाद उनकी पहली विदेश यात्राओं में से एक थी। विदेश मंत्री ने मालदीव के नेतृत्व के साथ बातचीत की, जिसमें मालदीव ने भारत की निरंतर विकास सहायता की

सराहना की और द्विपक्षीय संबंधों को और गहन बनाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। तत्कालीन विदेश मंत्री मूसा ज़मीर और तत्कालीन युवा मामले सशक्तिकरण, सूचना और कला राज्य मंत्री अली शमन ने 17 अगस्त को आयोजित वॉयस ऑफ़ ग्लोबल साउथ समिट के तीसरे संस्करण के क्रमशः विदेश मंत्रियों और युवा मामले मंत्रियों के सत्र में भाग लिया।

दोनों देशों के नेतृत्व के मार्गदर्शन में, भारत और मालदीव ने भागीदारी को बढ़ाने के लिए आवश्यक कदमों की पहचान करने हेतु भारत-मालदीव उच्च स्तरीय कोर ग्रुप (एचएलसीजी) का गठन किया, जिसमें चालू विकास सहयोग परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाना और मालदीव के लोगों को मानवीय एवं चिकित्सा सहायता (मेडवैक) सेवाएं प्रदान करने वाले भारतीय विमानन प्लेटफार्मों के संचालन को जारी रखने के लिए पारस्परिक रूप से व्यावहारिक समाधान ढूंढना शामिल है। एचएलसीजी की 2024 में चार बार बैठक हुई। मई तक, मालदीव सरकार के अनुरोध के अनुसार, इन विमानन प्लेटफार्मों को सहायता देने के लिए भारतीय तकनीकी कर्मियों को प्रतिनियुक्त किया गया।

मालदीव के पिछले अनुरोध के आधार पर, भारत ने अतिरिक्त एक वर्ष की अवधि के लिए मई और सितंबर प्रत्येक में 50 मिलियन अमरीकी डालर के दो ब्याज-मुक्त ट्रेजरी-बिलों के पुनः सब्सक्रिप्शन की सुविधा प्रदान की। ये सहायताएँ भारत सरकार द्वारा आपातकालीन वित्तपोषण सहायता के रूप में दी गई थीं।

विकास सहयोग

भारत मालदीव का एक पारंपरिक विकास भागीदार है और देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मालदीव को वित्तीय और बजटीय सहायता प्रदान करता है। अगस्त में विदेश मंत्री की मालदीव यात्रा के दौरान, दोनों पक्षों ने भारत-समर्थित एलओसी के साथ पूरी की गई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इनमें मालदीव के 28 द्वीपों में जल और सीवरेज नेटवर्क परियोजनाएँ, अडू रिक्लेमेशन एंड शोर प्रोटेक्शन परियोजना और अडू डिटोर लिंक ब्रिज परियोजना शामिल थीं। दोनों देशों ने मानसिक स्वास्थ्य, विशेष शिक्षा, स्पीच थेरेपी और स्ट्रीट लाइटिंग के क्षेत्रों में छः एचआईसीडीपी का संयुक्त रूप से उद्घाटन भी किया। इन सभी परियोजनाओं को भारत की अनुदान सहायता के तहत पूर्ण किया गया।

प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मुइज्जु ने हनीमाधू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए रनवे का उद्घाटन संयुक्त रूप से किया और भारत की वित्तीय सहायता से विकसित 700 सामाजिक आवास इकाइयों को अक्टूबर में भारत की राजकीय यात्रा के दौरान सौंपा। दोनों देश भारत-मालदीव महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा परियोजना यानी ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट (जीएमसीपी) के कार्यान्वयन पर भी मिलकर काम कर रहे हैं, जो राजधानी माले को मालदीव के तीन द्वीपों से जोड़ेगा और उथुरु थिला फाल्हू (यूटीएफ) द्वीप पर मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल (एमएनडीएफ) तटरक्षक बंदरगाह 'एकथा' का निर्माण होगा। भारत हलहुमाले चरण-II में क्रेता ऋण सुविधा के तहत 4000

सामाजिक आवास इकाइयों के निर्माण और अनुदान के आधार पर द्वीपों में 65 एचआईसीडीपी को लागू करने का भी समर्थन कर रहा है।

व्यापार और आर्थिक सहयोग

भारत और मालदीव ने 1981 में एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जो विशेष रूप से मालदीव के लिए आवश्यक वस्तुओं के निर्यात में सुविधा प्रदान करता है। अप्रैल में, इसी समझौते के तहत और मालदीव सरकार के अनुरोध पर, भारत ने वर्ष 2024-25 के लिए 9 आवश्यक वस्तुओं के निर्यात की अनुमति दी और प्रत्येक वस्तु के लिए मात्रा के कोटा को संशोधित किया गया।

भारत-मालदीव द्विपक्षीय व्यापार 2024 में 434.6 मिलियन अमरीकी डॉलर था। अगस्त में, दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को और अधिक बढ़ाने के लिए मालदीव में यूपीआई जैसी त्वरित भुगतान प्रणाली शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अक्टूबर में मालदीव में रुपये कार्ड क्रियान्वित किया गया और नवंबर में दोनों देशों ने सीमा पार लेन-देन के लिए स्थानीय मुद्राओं (आईएनआर और मालदीवियन रूफिया - एमवीआर) के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु एक फ्रेमवर्क स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इन पहलों से, अन्य बातों के अलावा, मालदीव में भारत से पर्यटन में वृद्धि होगी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था में योगदान मिलेगा।



विदेश मंत्री और मालदीव के तत्कालीन विदेश मंत्री मूसा ज़मीर ने मालदीव में डिजिटल भुगतान प्रणाली शुरू करने हेतु भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम और मालदीव के आर्थिक विकास एवं व्यापार मंत्रालय के बीच विदेश मंत्री की माले यात्रा के दौरान एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, अगस्त 2024.



भारत, मालदीव और श्रीलंका के तटरक्षकों ने माले में लिपक्षीय युद्धाभ्यास 'दोस्ती' का संयुक्त रूप से संचालन किया, फरवरी 2024.

रक्षा और सुरक्षा सहयोग

भारत-मालदीव रक्षा और सुरक्षा भागीदारी द्विपक्षीय संबंधों के स्तंभों में से एक है। 2024 में, भारत ने मालदीव के तटरक्षक जहाज 'हुरवी' की मरम्मत निःशुल्क आधार पर शुरू की, जिसकी मार्च-अप्रैल 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। इस वर्ष दोनों देशों ने नियमित रूप से रक्षा वार्ता भी की। भारत-मालदीव-श्रीलंका लिपक्षीय युद्धाभ्यास 'दोस्ती' फरवरी में मालदीव में संचालित किया गया और द्विपक्षीय युद्धाभ्यास 'एकाथा' का 7^{वां} संस्करण अक्टूबर-नवंबर में संचालित किया गया। 7^{वां} संयुक्त सैन्य वार्ता जून में मालदीव में आयोजित की गई, जबकि 5^{वां} रक्षा सहयोग वार्ता सितंबर में भारत में आयोजित की गई। अगस्त में, भारत, मालदीव, श्रीलंका और मॉरीशस ने कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन (सीएससी) के संस्थापक दस्तावेजों पर कोलंबो में हस्ताक्षर किए।

शिक्षा और क्षमता निर्माण

भारत मानव संसाधन विकास में मालदीव का दशकों से पारंपरिक भागीदार रहा है, जो आईटीईसी और आईसीसीआर ढांचे के तहत सालाना प्रशिक्षण स्लॉट प्रदान करता है। भारत सरकार सार्वजनिक नीति, शासन और क्षेत्र प्रशासन, न्यायपालिका, स्थानीय शासन आदि क्षेत्रों में मालदीव की आवश्यकताओं के अनुसार मालदीव के पेशेवरों के लिए कस्टमाज्ड, टेलर-मेड मॉड्यूलों और कार्यक्रमों को प्रदान करता है।

2024 में, दोनों पक्षों ने भारत में 1,000 मालदीव के सिविल सेवकों और 200 न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए समझौता ज्ञापनों को नवीनीकृत किया तथा खेल और युवा मामले में सहयोग पर समझौता ज्ञापन भी किया। अक्टूबर में, दोनों देशों ने भ्रष्टाचार को रोकने और उसका प्रतिकार करने और शैक्षणिक एवं व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान में सहयोग स्थापित करने पर द्विपक्षीय सहयोग के लिए समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए।

म्यांमार

म्यांमार एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है जो भारत के साथ 1643 किलोमीटर लंबी भूमि सीमा और 1100 किलोमीटर से अधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा साझा करता है। भारत की 'पड़ोसी पहले' और 'एक्ट ईस्ट' नीति के केंद्र बिंदु में, म्यांमार आसियान सहित दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों से कनेक्ट होने में भारत के लिए महत्वपूर्ण है। भारत और म्यांमार मजबूत सभ्यतागत, ऐतिहासिक और लोगों के बीच संबंध साझा करते हैं। बौद्ध धर्म एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कड़ी है जो म्यांमार के साथ भारत की साझा विरासत का एक हिस्सा है।



विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में बिम्सटेक विदेश मंत्रियों के रिट्रीट के दौरान म्यांमार के यू थान स्वे से मुलाकात की, जुलाई 2024.

फरवरी 2021 से, म्यांमार में राजनीतिक और सुरक्षा स्थिति खराब रही है। म्यांमार में मौजूदा सुरक्षा और मानवीय स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि इसका सीधा असर भारत पर भी पड़ रहा है। भारत ने हिंसा को पूरी तरह से रोकने, बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझाने, राजनीतिक बंदियों की रिहाई और म्यांमार को लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ने की अपील की है।

उच्च स्तरीय दौरे और बैठकें

जून में, विदेश मंत्री ने म्यांमार के यू थान स्वे के नई दिल्ली से पारगमन के दौरान उनसे मुलाकात की। दोनों पक्षों की मुलाकात जुलाई में आयोजित दूसरे बिस्मटेक विदेश मंत्रियों के रिट्रीट के दौरान भी हुई। एनएसए ने जुलाई में बिस्मटेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक में भाग लेने के लिए म्यांमार का दौरा किया। विदेश सचिव ने 19 दिसंबर को बैंकॉक में म्यांमार और उसके पड़ोसी देशों के बीच अनौपचारिक परामर्श के इतर थान स्वे के साथ द्विपक्षीय बैठक की।

व्यापार, बिजली, दालों पर संयुक्त कार्यसमूह (जेडब्ल्यूजी) की बैठकें सितंबर में आयोजित की गईं और भारतीय वैश्विक परिषद (आईसीडब्ल्यूए) ने म्यांमार के हितधारकों के लिए 'संविधानवाद और संघवाद' पर व्याख्यान श्रृंखला के दूसरे दौर की मेज़बानी नवंबर में की। भारत-म्यांमार सर्वेक्षण विभाग प्रमुखों की 12^{वीं} बैठक 03-04 दिसंबर को आयोजित की गई।

व्यापार और आर्थिक सहयोग

भारत म्यांमार का 7^{वाँ} सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार 1.74 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा, जिसमें भारत का निर्यात 670 मिलियन अमरीकी डॉलर था। 2024 में, फार्मास्यूटिकल्स, बीन्स और दालें क्रमशः म्यांमार से भारत के निर्यात और आयात की प्रमुख वस्तुएँ थीं। वर्तमान में, भारत म्यांमार में 11वाँ सबसे बड़ा निवेशक है, जिसमें 39 भारतीय उद्यमों द्वारा 782.821 मिलियन अमरीकी डॉलर का स्वीकृत निवेश है। व्यापार का निपटान 26 जनवरी से राष्ट्रीय मुद्राओं में चालू हो गया है, जिससे भारतीय रुपये (आईएनआर) में द्विपक्षीय व्यापार संभव हो गया है।

विकास सहयोग

भारत के पास म्यांमार में लगभग 2 बिलियन अमरीकी डॉलर का बड़ा विकास सहयोग पोर्टफोलियो है, जिसमें से अधिकांश परियोजनाएँ अनुदान सहायता के तहत क्रियान्वित की जा रही हैं। मौजूदा सुरक्षा स्थिति से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद, इस वर्ष चल रही सामाजिक-आर्थिक विकास परियोजनाओं और कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (केएमटीटीपी) तथा भारत-म्यांमार-थाईलैंड (आईएमटी) लिपक्षीय राजमार्ग सहित प्रमुख कनेक्टिविटी परियोजनाओं में प्रगति पाई गई।

म्यांमार में पुलों, सड़कों, विद्यालयों तथा छोटे स्वास्थ्य केंद्रों, आदि सहित नागरिक अवसंरचना के निर्माण के लिए भारत सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) फ्रेमवर्क, रखाइन राज्य विकास कार्यक्रम (आरएसडीपी), एचआईसीडीपी तथा त्वरित प्रभाव वाली परियोजनाओं (क्यूआईपी) के अंतर्गत पूरे म्यांमार में जन-केंद्रित विकास परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है।

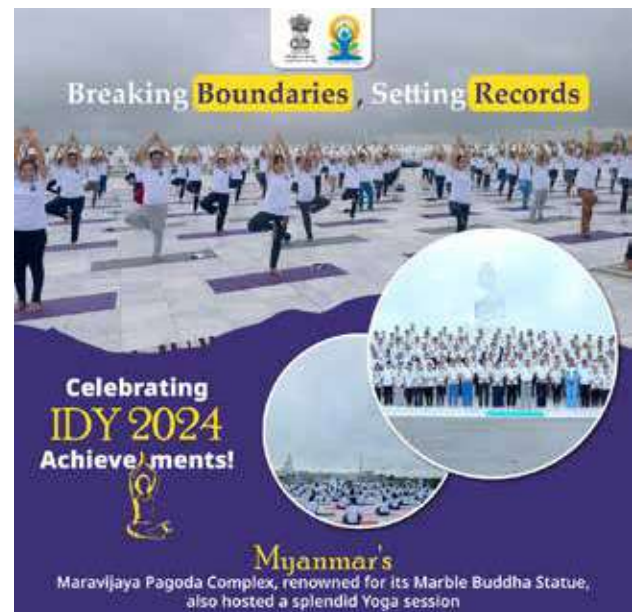
शिक्षा तथा क्षमता निर्माण

क्षमता निर्माण पहले पूरे वर्ष जारी रहीं और आईटीईसी, आईसीसीआर छात्रवृत्ति तथा अन्य विशेषीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रमों सहित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत म्यांमार में मानव संसाधन विकास पर फोकस किया गया। म्यांमार के 37 छात्रों ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में आईसीसीआर छात्रवृत्ति स्लॉट का उपयोग किया तथा कई छात्रों ने आसियान छात्रों को प्रदान की जाने वाली विभिन्न पीएचडी फेलोशिप के अंतर्गत भारतीय विश्वविद्यालयों में छात्रवृत्ति का लाभ उठाया। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने प्रतिस्पर्धा विधि (कॉम्पिटिशन ला), अंग्रेजी, सूचना प्रौद्योगिकी, बैंकिंग, लेखापरीक्षा और लेखाओं सहित विविध क्षेत्रों में विभिन्न क्षमता निर्माण पहलों के तहत लगभग 175 म्यांमार अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया।

सांस्कृतिक सहयोग

आईसीसीआर के महानिदेशक ने 31 मई को यांगून में प्रसिद्ध बौद्ध स्कॉलर और सितागु अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध अकादमी के संस्थापक सितागु सयादाव आशिन न्यानिस्सारा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए आईसीसीआर का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 प्रदान किया।

म्यांमार के सांस्कृतिक कलाकारों ने 13-19 अक्टूबर को आयोजित कुल्लू दशहरा महोत्सव में कला-प्रदर्शन किया। 250 से अधिक आयुर्वेद विद्वानों और छात्रों ने आयुर्वेद दिवस 2024 समारोह में भाग लिया जिसका आयोजन 24 अक्टूबर को मांडले में पारंपरिक चिकित्सा विश्वविद्यालय में किया गया था।



म्यांमार का मारविजय पैगोडा कॉम्प्लेक्स, जो अपनी भव्य संगमरमर बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है, जहां मांडले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 10^{वीं} वर्षगांठ मनाने के लिए जून 2024 में योग सत्र का आयोजन किया गया।



भारत ने म्यांमार में टाइफून यागी से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए 'ऑपरेशन सद्भाव' के तहत 53 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) सहायता प्रदान की, सितंबर 2024.

स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र ने म्यांमार के नागरिकों के लिए भरतनाट्यम, योग और हिंदी में नियमित शिक्षा प्रदान की। यंगून के राष्ट्रीय संग्रहालय में 'रामायण' पर एक कला प्रदर्शनी 08-15 नवंबर को आयोजित की गई। इसके अतिरिक्त, बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक 'गीता रहस्य' का बर्मी भाषा में अनुवाद किया गया।

मानवीय सहायता

म्यांमार के लोगों के साथ एकजुटता दिखाते हुए और क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं के लिए 'प्रथम सहायताकर्ता' के रूप में, भारत ने टाइफून यागी के कारण आई बाढ़ से प्रभावित लोगों को मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) प्रदान करने के लिए 'ऑपरेशन सद्भाव' शुरू किया। इस पहल के तहत, भारत सरकार ने 17 सितंबर को म्यांमार को 53 टन एचएडीआर सहायता प्रदान की। सहायता सामग्री में उपयोग की आवश्यक वस्तुओं (खाद्य और गैर-खाद्य) के पैलेट के साथ-साथ चिकित्सा पैलेट तथा दवाइयाँ, भोजन, रसोई किटें, कपड़े, हाइजीन किटें, टेंट, मच्छरदानियां, सौर लैंप और जल शोधन आपूर्ति शामिल थी।

भारत ने म्यांमार के लोगों के लिए 2200 मीट्रिक टन भारतीय चावल का भी दान किया। इस योगदान से म्यांमार के बच्चों, महिलाओं, युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों तथा दिव्यांगजनों सहित लगभग 140,000 जरूरतमंद लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

नेपाल

भारत और नेपाल अपने अद्वितीय, बहुआयामी और मजबूत संबंधों को आगे बढ़ा रहे हैं, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक और सभ्यतागत संबंधों पर आधारित हैं। भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा और नागरिकों

की मुक्त आवाजाही इन मजबूत और गहरे संबंधों का प्रतिबिंब है। पिछले कुछ वर्षों में, भारत सरकार ने व्यापार और आर्थिक संबंधों के साथ-साथ लोगों के बीच आवाजाही के क्षेत्रों में सीमा पार संबंधों को मजबूत करने के लिए कई पहल की हैं।

'पड़ोसी पहले' दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, इस वर्ष ऊर्जा, व्यापार, रेलवे, डिजिटल बुनियादी ढांचे के क्षेत्र और संस्कृति में विभिन्न कनेक्टिविटी पहलों का तेजी से विस्तार और सुदृढ़ीकरण हुआ। जनवरी में विदेश मंत्री की नेपाल यात्रा के दौरान, दोनों देशों ने दीर्घकालिक बिजली व्यापार के लिए एक समझौते को अंतिम रूप दिया, जिसमें 10 वर्षों की समय सीमा के भीतर नेपाल से भारत को बिजली निर्यात की मात्रा में 10,000 मेगावाट तक की वृद्धि की परिकल्पना की गई है। इस यात्रा के दौरान, विदेश मंत्री ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय केंद्रीय पुस्तकालय भवन को सौंपे जाने के अवसर पर समारोह में भी भाग लिया और 25 स्कूलों तथा कई स्वास्थ्य पहलों सहित अनेक परियोजनाओं का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया, जो नेपाल के विकास के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

व्यापारिक बुनियादी ढांचे के मोर्चे पर एक उल्लेखनीय उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए, नेपालगंज में आईसीपी को सफलतापूर्वक सौंपा गया जो मई 2024 को पूर्ण रूप से चालू हुआ। इसका उद्घाटन जून 2023 में भारत और नेपाल के प्रधानमंत्रियों द्वारा किया गया था। नवंबर में, नेपाल ने भारतीय ग्रिड के माध्यम से बांग्लादेश के साथ अपना पहला बिजली लेनदेन किया, जिससे द्विपक्षीय ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा मिला।

उच्च स्तरीय दौरे

प्रधानमंत्री ने 2014 से अब तक पांच बार नेपाल का दौरा किया है, जबकि नेपाल के उनके समकक्षों ने इसी अवधि के दौरान नियमित रूप से भारत

का दौरा किया है। 09 जून को, नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया और इस कार्यक्रम के बाद एक संक्षिप्त शिष्टाचार बैठक की। 15 जुलाई को, प्रधानमंत्री ने तत्कालीन प्रधानमंत्री प्रचंड के विश्वास मत हारने के बाद, नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त होने पर के.पी.शर्मा ओली को बधाई दी। भारत के प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री ओली ने 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79^{वें} सत्र के इतर मुलाकात की। प्रधानमंत्री ओली ने 17 अगस्त को भारत द्वारा वर्चुअल मोड में आयोजित वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के तीसरे संस्करण में भी भाग लिया।

विदेश मंत्री ने नेपाल के तत्कालीन विदेश मंत्री नारायण प्रकाश सऊद के निमंत्रण पर 04-05 जनवरी को नेपाल की आधिकारिक यात्रा की। 04 जनवरी को, दोनों मंत्रियों ने भारत-नेपाल संयुक्त आयोग की 7^{वीं} बैठक की सह-अध्यक्षता की, जिसमें द्विपक्षीय सहयोग के संपूर्ण स्पेक्ट्रम की समीक्षा की गई। तत्कालीन विदेश मंत्री सऊद ने 21-23 फरवरी को नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग 2024 में भाग लिया। यात्रा के दौरान, उन्होंने विदेश मंत्री तथा अन्य सहभागी देशों के उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात की। नेपाल की विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा ने 18-22 अगस्त को भारत की आधिकारिक यात्रा की, जिस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से मुलाकात की।

मंत्री स्तरीय यात्राएँ

भारत में आगता यात्राओं के भाग के रूप में, नेपाल के तत्कालीन युवा मामले और खेल मंत्री दिग बहादुर लिम्बू ने 06-09 फरवरी को नई दिल्ली

में आयोजित बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में भाग लिया और उन्होंने तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण तथा युवा मामले और खेल मंत्री से मुलाकात की। नेपाल के उद्योग, वाणिज्य और आपूर्ति मंत्री दामोदर भंडारी ने बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र में भाग लेने के लिए अगस्त में भारत का दौरा किया। इसके बाद, उन्होंने 29^{वें} भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) भागीदारी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दिसंबर में नई दिल्ली का दौरा किया। शिखर सम्मेलन के इतर, मंत्री भंडारी ने विदेश मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री के साथ बैठकें कीं। नेपाल के संस्कृति, पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्री बद्री प्रसाद पांडे ने नागरिक उड्डयन पर दूसरे एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए सितंबर में नई दिल्ली का दौरा किया। नेपाल के स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्री प्रदीप पौडेल ने दक्षिण-पूर्व एशिया विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) क्षेत्रीय समिति के 77^{वें} सत्र के लिए अक्टूबर में भारत का दौरा किया। नेपाल के ऊर्जा, जल संसाधन और सिंचाई मंत्री दीपक बहादुर खड्का ने 05 नवंबर को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) की 7^{वीं} आम सभा में भाग लिया। उन्होंने शिखर सम्मेलन के इतर भारत के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री से मुलाकात की।

नेपाल की अपनी यात्रा के भाग के रूप में, युवा मामले और खेल राज्य मंत्री ने 24 अगस्त को काठमांडू का दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान, उन्होंने और नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखक ने 16 भारतीय नागरिकों से मुलाकात की, जो सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे और उनका इलाज चल रहा था।



नेपाल की विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा ने भारत की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री से मुलाकात की, अगस्त 2024.

अन्य महत्वपूर्ण दौरे

नेपाल के विदेश सचिव सेवा लामसल ने इस वर्ष भारत की दो दौरे किए। सचिव लामसल ने 29 फरवरी-02 मार्च को पुणे में आयोजित 8^{वीं} एशिया आर्थिक वार्ता (एईडी) में भाग लिया और 11 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित दूसरे बिस्मटेक विदेश मंत्रियों के रिट्रीट में भाग लिया।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) ने नेपाल के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ के निमंत्रण पर 03 मई को तीन दिवसीय यात्रा के लिए काठमांडू का दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान, सीजेआई ने किशोरों के न्याय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी में मुख्य भाषण भी दिया।

जून में नई सरकार के गठन के बाद, विदेश सचिव ने सचिव लामसल के निमंत्रण पर 11-12 अगस्त को नेपाल का आधिकारिक दौरा किया। बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने विभिन्न द्विपक्षीय पहलों के साथ-साथ विकास परियोजनाओं में हुई प्रगति की समीक्षा की और भावी सहयोग अवसरों पर चर्चा की।

भारत के लोकसभा अध्यक्ष ने नेपाल के राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण प्रसाद दहल से स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 16 अक्टूबर को अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) की 149^{वीं} आम सभा के इतर मुलाकात की।

प्रतिनिधिमंडल स्तर की यात्राएँ

नेपाल के निर्गामी प्रतिनिधिमंडल (आउटगोइंग डेलिगेशन) स्तर की यात्राओं के भाग के रूप में, विद्युत क्षेत्र सहयोग पर संयुक्त कार्यसमूह (जेडब्ल्यूजी) की 11^{वीं} बैठक 03 जनवरी को काठमांडू में आयोजित की गई। जेडब्ल्यूजी की सह-अध्यक्षता विद्युत मंत्रालय के संयुक्त सचिव तथा नेपाल के ऊर्जा, जल संसाधन और सिंचाई मंत्रालय के संयुक्त सचिव नवीन राज सिंह ने की। भारत के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय (एनडीसी) के 64^{वें} पाठ्यक्रम का एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें भारत के सिविल सेवाओं और रक्षा बलों के साथ-साथ ऑस्ट्रेलिया, भूटान, जापान, कजाकिस्तान, ओमान और यूएसए

जैसे मिल देशों के 21 वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे, ने 01-05 सितंबर को नेपाल का दौरा किया।

आगता प्रतिनिधिमंडल (इनकमिंग डेलिगेशन) स्तर की यात्राओं के भाग के रूप में, नेपाल से एक 8 सदस्यीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल, जिसका नेतृत्व अंतर्राष्ट्रीय संबंध और पर्यटन पर संसदीय समिति (पीसीआईआरटी) के अध्यक्ष राज किशोर यादव ने किया, ने 30 जनवरी-07 फरवरी को भारत का दौरा किया। विदेश मंत्रालय ने 22-31 जुलाई को शहरी विकास प्रथाओं को जानने-समझने के लिए नई दिल्ली, हापुड़, शिमला, अहमदाबाद और अयोध्या शहरों को कवर करते हुए नेपाल के हुमला से भारत के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के लिए एक ज्ञानवर्धन यात्रा अर्थात एक्सपोजर विजिट का आयोजन किया। यह यात्रा भारत सरकार द्वारा अनुदान के तहत कवर की गई थी। नेपाल सरकार के 26 राजनयिकों और अधिकारियों ने 20-29 नवंबर को नई दिल्ली में सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान (एसएसआईएफएस) द्वारा नेपाल के राजनयिकों और अधिकारियों के लिए आयोजित प्रथम विशेष पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया।

द्विपक्षीय तलों की बैठकें

फरवरी में, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी से संबंधित तीसरी संयुक्त परियोजना निगरानी समिति ने प्रगति की समीक्षा करने और विभिन्न परियोजना-संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए वर्चुअल मोड में बैठक की। 8^{वीं} भारत-नेपाल सशस्त्र सीमा बल-सशस्त्र पुलिस बल (एसएसबी-एपीएफ) समन्वय बैठक 18 नवंबर को काठमांडू में आयोजित की गई। दोनों पक्षों ने खुली सीमाओं पर दोनों देशों के नागरिकों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए समन्वय को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।

रक्षा और सुरक्षा सहयोग

भारत ने विभिन्न प्रकार के रक्षा भंडारों की व्यवस्था करके और उसके कर्मियों को नियमित प्रशिक्षण देकर नेपाली सेना के आधुनिकीकरण



11^{वीं} गोरखा राइफल्स की एक बटालियन द्वारा गठित भारतीय सेना की टुकड़ी ने सालझंडी में नेपाली आर्मी बैटल स्कूल में आयोजित भारत-नेपाल द्विपक्षीय युद्धाभ्यास 'सूर्य किरण' के 18^{वें} संस्करण में भाग लिया, दिसंबर 2024।

और क्षमता संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय सेना प्रमुख (सीओएएस) ने 20-24 नवंबर को नेपाल का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान उन्हें नेपाल के राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल द्वारा नेपाली सेना (एनए) के जनरल का मानद रैंक प्रदान किया गया। सीओएएस ने यात्रा के दौरान नेपाल के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से मुलाकात की। उन्होंने पोखरा का भी दौरा किया और नेपाल निवासित गोरखा भूतपूर्व सैनिकों की एक रैली को संबोधित किया। दूसरी ओर, नेपाली सेना प्रमुख (सीओएएस) जनरल अशोक राज सिंगडेल ने भारतीय सेना के मानद जनरल के रूप में अपने अभिषेक समारोह के लिए 11-14 दिसंबर को भारत की यात्रा की। यात्रा के दौरान जनरल सिंगडेल ने रक्षा मंत्री, एनएसए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस), रक्षा सचिव और विदेश सचिव के साथ महत्वपूर्ण चर्चा की।

युद्धाभ्यास 'सूर्य किरण' का 18^{वां} संस्करण 29 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक नेपाल के सलझंडी में नेपाली आर्मी बैटल स्कूल (एनएबीएस) में आयोजित किया गया। भारतीय सेना की टुकड़ी में 300 नियमित सैनिक और 34 विशेष बल सैनिक शामिल थे। वार्षिक युद्धाभ्यास दोनों देशों में बारी-बारी से बटालियन स्तर पर संचालित किया जाता है। नेपाल की सेना से 505 कर्मियों ने इस वर्ष भारत में विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भाग लिया।

नेपाली सेना ने रक्षा भंडार की आपूर्ति के लिए इस वर्ष भारतीय कंपनियों को 82 मिलियन अमरीकी डॉलर के आपूर्ति आदेश भी जारी किए हैं। वर्तमान में, नेपाल के लगभग 32,000 गोरखा सैनिक भारतीय सेना में सेवारत हैं। इन सैनिकों के अलावा, नेपाल में लगभग 1.20 लाख भारतीय सशस्त्र बल पेंशनभोगी निवासित हैं। भारतीय सेना ने अपने पेंशनभोगियों की सहायता के लिए व्यापक कल्याणकारी योजनाएँ बनाई हैं।

व्यापार और आर्थिक सहयोग

वित्त वर्ष 2023-2024 में भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था, जिसका द्विपक्षीय व्यापार 7.87 बिलियन अमरीकी डॉलर था। नेपाल में भारतीय फर्मों द्वारा किया गया निवेश उसके एफडीआई स्टॉक का लगभग 33 प्रतिशत है, जो कि 7.44 बिलियन अमरीकी डॉलर है। नेपाल को भारत के शीर्ष निर्यातों के रूप में पेट्रोलियम, लोहा और इस्पात मशीनरी, अनाज और वाहन शामिल हैं, जबकि नेपाल से भारत के शीर्ष आयातों में खाद्य तेल, चाय, मसाले, सीमेंट, प्लाईवुड और सिंथेटिक यार्न शामिल हैं।

भारत की यूपीआई और नेपाल की फ़ोनपे भुगतान सेवा के बीच अंतर-संचालन मार्च में चालू किया गया। इससे भारतीय आगंतुकों को भारतीय यूपीआई ऐप का उपयोग करके नेपाली व्यापारिक प्रतिष्ठानों में फ़ोनपे-समर्थित क्यूआर कोड पर लेनदेन करने में सहायता मिलेगी।

बिजली और ऊर्जा सहयोग

नेपाल ने भारत को 900 मेगावाट से अधिक बिजली का निर्यात शुरू किया, जैसा कि 04 जनवरी को भारत और नेपाल सरकारों के बीच

हस्ताक्षरित दीर्घकालिक बिजली व्यापार समझौते में प्रावधान किया गया था। जनवरी में विदेश मंत्री ने नेपाल यात्रा के दौरान तीन महत्वपूर्ण 132 केवी क्रॉस-बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइनों का उद्घाटन किया, जिससे दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग को और अधिक बढ़ावा मिला। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य नेपाल से भारत को दस वर्षों के भीतर 10,000 मेगावाट तक बिजली निर्यात बढ़ाना है, जिससे नेपाल के जलविद्युत क्षेत्र और ट्रांसमिशन बुनियादी ढांचे में पारस्परिक रूप से लाभकारी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। एक उल्लेखनीय उपलब्धि के रूप में, नेपाल से बांग्लादेश तक भारतीय ग्रिड के माध्यम से पहला त्रिपक्षीय बिजली लेन-देन 15 नवंबर को शुरू हुआ।

विकास सहयोग

नेपाल में 2015 के गोरखा भूकंप के बाद, भारत सरकार ने पुनर्निर्माण में नेपाल सरकार के प्रयासों को पूरक बनाने के लिए 1 बिलियन अमरीकी डॉलर देने की प्रतिबद्धता जताई। इसके अतिरिक्त, दोनों सरकारों ने आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक विरासत जैसे चार क्षेत्रों में भूकंप के बाद पुनर्निर्माण के तहत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 250 मिलियन अमरीकी डॉलर के अनुदान प्रतिबद्धता पर हस्ताक्षर किए।

पिछले दशक में, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सांस्कृतिक विरासत क्षेत्र सहित सभी चार क्षेत्रों में एचआईसीडीपी में पर्याप्त प्रगति हुई है। भारत सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में 32 परियोजनाएँ, शिक्षा क्षेत्र में 1 परियोजना (त्रिभुवन विश्वविद्यालय केंद्रीय पुस्तकालय) और सांस्कृतिक विरासत क्षेत्र में 3 परियोजनाएँ नेपाली सरकार को सौंपी। भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में 43 परियोजनाएँ और सांस्कृतिक विरासत क्षेत्र में 9 परियोजनाएँ भी पूरी कीं। इसके अतिरिक्त, इस अवधि में नेपाल सरकार को 14.9 मिलियन अमरीकी डॉलर (सांस्कृतिक विरासत में 5.4 मिलियन अमरीकी डॉलर और स्वास्थ्य क्षेत्र में 9.5 मिलियन अमरीकी डॉलर) का भुगतान किया गया है।

04 जनवरी को, विदेश मंत्री ने घोषणा की कि भारत सरकार लगभग 720 मिलियन अमरीकी डॉलर का वित्तीय सहायता पैकेज देगी, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा जाजरकोट भूकंप के बाद पुनर्निर्माण प्रयासों का समर्थन करने के लिए अनुदान सहायता के तहत होगा। विदेश मंत्री की यात्रा के दौरान एचआईसीडीपी के कार्यान्वयन के लिए एक संशोधित समझौते पर हस्ताक्षर भी किए गए, जिसका उद्देश्य प्रत्येक एचआईसीडीपी की वित्तीय सीमा को 5,75,805 अमरीकी डॉलर से बढ़ाकर 23.03 मिलियन अमरीकी डॉलर करना था।

14 अप्रैल को, काठमांडू में भारतीय दूतावास ने देश के विभिन्न जिलों में स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले विभिन्न संगठनों को सरकारी अधिकारियों और सामुदायिक प्रतिनिधियों की उपस्थिति में एक समारोह के दौरान एम्बुलेंस और स्कूल बसें उपहार में दीं। इस पहल का उद्देश्य भारत और नेपाल के बीच सहयोग और सद्भावना के भाव को मजबूत करना था।



विदेश मंत्री और नेपाल के तत्कालीन विदेश मंत्री एन.पी. सऊद ने नेपाल के सबसे बड़े त्रिभुवन विश्वविद्यालय केंद्रीय पुस्तकालय तथा नेपाल के शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में भारत के भूकंप-उपरांत पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत 32 स्कूलों और 25 अस्पतालों का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया, जनवरी 2024.

शिक्षा, सांस्कृतिक सहयोग और लोगों के बीच आदान-प्रदान

ललितपुर में जेष्ठ वर्ण महाविहार और काठमांडू में नेपाल भाषा परिषद के उद्घाटन के साथ भारत और नेपाल के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान फला-फूला, जो विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक प्रयास को दर्शाता है। नेपाल भाषा परिषद का उद्घाटन 11 अगस्त को नेपाल के विदेश सचिव और शहरी विकास मंत्रालय के सचिव द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इसके अतिरिक्त, सिंधुपालचौक में लिस्टीकोट गुंबा के लिए 21 मार्च को भूमिपूजन किया गया और दिसंबर में भारतीय दूतावास और लुबिनी विकास ट्रस्ट द्वारा आयोजित भारत-नेपाल सांस्कृतिक महोत्सव का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया तथा सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए द्विपक्षीय पहलों पर और अधिक जोर दिया गया।

1245 नेपाली छात्रों ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के परिसरों, जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (जेआईपीएमईआर), राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निमहंस) तथा भारत में स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (पीजीआईएमईआर) सहित विभिन्न संस्थानों में अध्ययन हेतु पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों (एमडी/एमएस/डीएम) में प्रवेश हेतु राष्ट्रीय महत्व के संस्थान की संयुक्त प्रवेश परीक्षा (आईएनआई-सीईटी) में बैठने के लिए आवेदन किया। भारत सरकार की स्व-वित्तपोषण योजना (एसएफएस) के अंतर्गत इस वर्ष 05 नेपाली छात्रों को बीई / बी.फार्मेसी / आर्किटेक्ट/ डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए यूजी सीटें आवंटित की गईं और 30 छात्रों को एमबीबीएस / बीडीएस पाठ्यक्रम आवंटित किए गए।

नेपाली छात्रों को भारत और नेपाल दोनों के संस्थानों में विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए सालाना लगभग 1,400 छात्रवृत्ति स्लॉट भी मिलते हैं। दिसंबर तक, भारत सरकार द्वारा नेपाली छात्रों को 1001 छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं हैं। आईटीईसी कार्यक्रम के तहत, नेपाल के 265 प्रतिभागियों को इस अवधि के दौरान प्रशिक्षित किया गया।

संकट की स्थिति में सहायता

तनहु जिले के अंबुखैरेनी क्षेत्र में अगस्त में एक सड़क दुर्घटना के बाद, जिसमें 27 भारतीय नागरिकों की जान चली गई थी और 16 यात्री घायल हो गए थे; भारत सरकार ने मृतकों के पार्थिव शरीर को जलगांव (भारत) ले जाने तथा घायलों को विशेषज्ञ चिकित्सा उपचार के लिए काठमांडू ले जाने में समन्वय किया।

अक्टूबर में, भारत ने नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए 25 टन से अधिक मानवीय सहायता प्रदान की, जिसमें आवश्यक स्वच्छता आपूर्ति, दवाइयाँ, जीवन रक्षक जैकेट, स्लीपिंग बैग, खाद्य पदार्थ, फुलाने योग्य रबर की नावें, मोटर, तिरपाल, स्लीपिंग बैग, कंबल, क्लोरीन की गोलियाँ और बोटलबंद पानी शामिल है। इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा नेपाल को दस प्रीफैब्रिकेटेड स्टील पुलों के लिए घटकों की एक खेप सौंपी गई। नेपाल सरकार के अनुरोध पर, ये पुल हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण बाधित सड़क संपर्क को बहाल करने में नेपाल के पुनर्निर्माण प्रयासों में योगदान देंगे।



भारत ने जाजरकोट भूकंप उपरांत राहत आपूर्ति की 5^{वीं} खेप नेपाल को सौंपी, जनवरी 2024.

पाकिस्तान

भारत पाकिस्तान के साथ सामान्य पड़ोसी संबंध चाहता है और लगातार यह कहता रहा है कि दोनों देशों के बीच मुद्दों को द्विपक्षीय और शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाना चाहिए। इसके लिए एक अनुकूल वातावरण बनाने की आवश्यकता है, जो आतंक, हिंसा और शत्रुता से मुक्त हो। तथापि, भारत को सीमा पार आतंकवाद के साथ-साथ पाकिस्तान द्वारा शत्रुतापूर्ण और मनगढ़ंत प्रचार का सामना करना पड़ रहा है। अगस्त 2019 में, पाकिस्तान ने भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को कमजोर किया है, जिसके कारण द्विपक्षीय व्यापार, कनेक्टिविटी और लोगों के बीच आदान-प्रदान को निलंबित करना पड़ा है।

पाकिस्तान भारत को बदनाम करने के लिए विश्व स्तर पर दुष्प्रचार अभियान और भारत विरोधी प्रचार में लगा हुआ है। भारत सरकार ने अपने आंतरिक मामलों पर पाकिस्तान द्वारा की गई ऐसी सभी कार्रवाइयों और बयानों को पूरी तरह से और स्पष्ट रूप से खारिज किया है। भारत सरकार क्षेत्र में आतंकवाद को बढ़ावा देने और सहायता देने में पाकिस्तान की भारत के खिलाफ भूमिका के साथ-साथ अपनी स्थिति पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ, खास तौर पर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा उससे परे बातचीत करती रहती है।

पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद एक मुख्य चिंता का विषय बना हुआ है। भारत ने पाकिस्तान से जनवरी 2004 की प्रतिबद्धता का सम्मान करने के लिए बार-बार कहा है कि वह अपने नियंत्रण में अपनी धरती/क्षेत्र का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए नहीं होने दे। सीमा पार आतंकवाद में कोई कमी नहीं आई है। सैन्य-ग्रेड हथियारों, ड्रोन, संचार उपकरणों और आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ के लिए भूमिगत

सुरंगों का उपयोग तथा नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार भारत में हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी स्पष्ट रूप से भारत के खिलाफ एक राज्य समर्थित आतंकवादी पारिस्थितिकी तंत्र की मौजूदगी की ओर इशारा करती है।

भारत ने पाकिस्तान से निरंतर आग्रह किया कि वह अपने देश में पनपे आतंकवाद को रोकने के लिए ठोस, सत्यापन योग्य और स्थायी कदम उठाए। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित कई आतंकवादी और आतंकवादी संस्थाएँ पाकिस्तान में पनप रही हैं। पाकिस्तान ने 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों के परिवारों को न्याय दिलाने में कोई ईमानदारी नहीं दिखाई।

भारत संयुक्त राष्ट्र सहित विभिन्न द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर पाकिस्तान से भारत के विरुद्ध आतंकवाद के मुद्दे को उठाता रहता है। सीमा पार से घुसपैठ, संघर्ष विराम उल्लंघन, सीमा पर अवैध निर्माण, मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी और द्विपक्षीय समझौतों के उल्लंघन के मामलों को भी पाकिस्तान के साथ राजनयिक चैनलों के माध्यम से नियमित रूप से उठाया जाता रहा है। इससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को स्टेटक्राफ्ट के एक टूल के रूप में उपयोग करने के बारे में काफी जागरूकता पैदा हुई है।

फरवरी 2021 में, भारत और पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशकों (डीजीएमओ) के बीच संघर्ष विराम पर सहमति बनी थी।

उच्च स्तरीय द्वारे

05 मार्च को, प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी। बदले में, प्रधानमंत्री शरीफ ने 10 जून को प्रधानमंत्री के फिर से चुने जाने पर

उन्हें शुभकामनाएं दीं। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' के माध्यम से प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दीं।

विदेश मंत्री ने 15-16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में आयोजित एससीओ शासनाध्यक्ष परिषद की 23^{वीं} बैठक में भाग लिया। सचिव (वाणिज्य) ने 12 सितंबर को विदेशी आर्थिक और विदेशी व्यापार गतिविधि के मंत्रियों की 23^{वीं} एससीओ बैठक में वर्चुअल मोड में भाग लिया।

धार्मिक तीर्थयात्रा

भारत और पाकिस्तान के बीच तीर्थयात्रियों की यात्रा को धार्मिक स्थलों की यात्रा से संबंधित 1974 के द्विपक्षीय प्रोटोकॉल के तहत सुगम बनाया गया है। वर्ष 2024 में भारत ने बैसाखी, महाराजा रणजीत सिंह की बरसी, गुरुपर्व के अवसर पर और दो बार कटासराज धाम के लिए 5609 भारतीय तीर्थयात्रियों को पाकिस्तान में विभिन्न तीर्थस्थलों की यात्रा करने में सुविधा प्रदान की। इसी अवधि के दौरान, सरकार ने पांच तीर्थयात्राओं (हजरत अमीर खुसरो का उर्स, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स, हजरत मुजहिद अल्फ सानी का उर्स, हजरत ख्वाजा अल्लाहुद्दीन अली अहमद साबिर का उर्स और हजरत निजामुद्दीन औलिया का उर्स) के हिस्से के रूप में भारत में धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए 570 पाकिस्तानी तीर्थयात्रियों को भी सुविधा प्रदान की।

अक्टूबर 2024 में, भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर में पवित्र गुरुद्वारा दरबार साहिब (करतारपुर समझौता) की तीर्थयात्रा की सुविधा के लिए समझौते की वैधता को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाया। इस कदम का उद्देश्य भारतीय तीर्थयात्रियों के साथ-साथ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्डधारकों के लिए पूरे वर्ष दैनिक आधार पर भारत से पाकिस्तान के करतारपुर में स्थित पवित्र गुरुद्वारा दरबार साहिब तक सुगम पहुंच और वीजा-मुक्त यात्रा की सुविधा प्रदान करना है। इस समझौते पर अक्टूबर 2019 में हस्ताक्षर किए गए थे और यह 5 वर्षों की अवधि के लिए वैध था। 2024 में, भारत सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर के माध्यम से पाकिस्तान के नारोवाल में करतारपुर में पवित्र गुरुद्वारा दरबार साहिब में 1,14,702 तीर्थयात्रियों की यात्रा में सुविधा प्रदान की।

मानवीय मुद्दे - कैदी और मछुआरे

कांसुलर ऐक्सेस पर 2008 के द्विपक्षीय समझौते के तहत की गई सहमति के अनुरूप, भारत और पाकिस्तान ने 01 जुलाई को एक-दूसरे की हिरासत में कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान-प्रदान किया। पाकिस्तान ने 43 नागरिक कैदियों और 211 मछुआरों की हिरासत को स्वीकार किया, जो या तो मूल रूप से भारतीय हैं या माना जाता है कि वे भारतीय ही हैं। इसी तरह, भारत की हिरासत में पाकिस्तान के 366 नागरिक कैदी और 86 मछुआरे हैं। सरकार के लगातार प्रयासों के परिणामस्वरूप, 2014 से अब तक 2639 भारतीय मछुआरों और 71 भारतीय नागरिक कैदियों को पाकिस्तान से वापस लाया गया है। भारत ने पाकिस्तान की हिरासत में शेष भारतीय नागरिकों की शीघ्र कांसुलर ऐक्सेस, रिहाई और स्वदेश वापसी की मांग की है।

पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार

पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों के उत्पीड़न को देखते हुए, भारत सरकार ने कई मौकों पर पाकिस्तान में इन समूहों के सदस्यों के खिलाफ अत्याचारों का मुद्दा उठाया है। भारत ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों के पूजा स्थलों और सांस्कृतिक विरासत तथा भेदभाव, हत्या, अपहरण, अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों का जबरन धर्म परिवर्तन करके विवाह करने के बारे में भी अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं।

श्रीलंका

भारत श्रीलंका का बहुत ही करीबी पड़ोसी है और भारत की 'पड़ोसी पहले' नीति और 'क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास' (सागर) नीति में एक केंद्रीय स्थान रखता है। 2022 में शर्तरहित वित्तीय सहायता प्रदान के आधार पर तथा 2023 में विज्ञान डॉक्यूमेंट शीर्षक "प्रमोटिंग कनेक्टिविटी, कैटलाइजिंग प्रॉस्पेरिटी: इंडिया - श्रीलंका इकोनॉमिक पार्टनरशिप विजन" को अंगीकृत करने के बाद द्विपक्षीय संबंध और प्रगाढ़ हुए हैं। आर्थिक, विकास, सांस्कृतिक तथा लोगों के बीच संबंधों को गहरा करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए विभिन्न नेतृत्व-स्तरीय वार्ताओं तथा पहलों के माध्यम से द्विपक्षीय संबंधों को संबल प्रदान किया गया।

उच्च स्तरीय दौरे

श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए 09-10 जून को भारत आए। तत्कालीन राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने 17 अगस्त को वर्चुअल मोड में आयोजित वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के तीसरे संस्करण में भी भाग लिया।

श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके 15-17 दिसंबर को भारत की राजकीय यात्रा पर आए। राष्ट्रपति पद संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा थी। उनके साथ विदेश मंत्री विजिता हेराथ भी आए थे। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दिसानायके ने "साझा भविष्य के लिए भागीदारी को बढ़ावा देना" शीर्षक से एक संयुक्त वक्तव्य को अंगीकृत। यात्रा के एक हिस्से के रूप में, प्रधानमंत्री ने जाफना विश्वविद्यालय और पूर्वी विश्वविद्यालय प्रत्येक से 100 नए छात्रों के लिए एक वार्षिक वित्तीय सहायता योजना की घोषणा की। उन्होंने रेलवे सिग्नलिंग परियोजना के लिए 14.9 मिलियन अमरीकी डालर की अनुदान सहायता की भी घोषणा की। इसके अलावा, भारत के नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस (एनसीजीजी) और श्रीलंका इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन (एसएलआईडीए) ने पांच वर्षों में श्रीलंका के 1500 सिविल सेवकों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम पर एक एमओयू पर तथा दोहरा कराधान परिहार समझौता यानी डबल टैक्सटेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में संशोधन के लिए एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। राजकीय यात्रा के आधिकारिक कार्यक्रमों से परे, राष्ट्रपति दिसानायके ने नई दिल्ली में आयोजित एक व्यावसायिक कार्यक्रम के भाग के रूप में, आईटी, स्टार्ट-अप इकोसिस्टम, कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा, कपड़ा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों के चुनिंदा सीईओ के साथ भी बातचीत की।



श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके का नई दिल्ली की अपनी राजकीय यात्रा के दौरान राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया, दिसंबर 2024.

नेशनल पीपुल्स पावर के लीडर के रूप में, दिसानायके ने पूर्व में फरवरी 2024 में आईसीसीआर के 'विशिष्ट आगंतुक कार्यक्रम' के तहत भारत का दौरा किया था। यात्रा के दौरान, उन्होंने विदेश मंत्री, एनएसए और तत्कालीन विदेश सचिव से मुलाकात की और अहमदाबाद एवं तिरुवनंतपुरम का भी दौरा किया।

विदेश मंत्री ने 20 जून को श्रीलंका का आधिकारिक दौरा किया। जून में उनकी पुनर्नियुक्ति के बाद यह विदेश मंत्री द्वारा की गई पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। यात्रा के दौरान, विदेश मंत्री ने तत्कालीन राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, तत्कालीन प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने से मुलाकात की और तत्कालीन विदेश मंत्री एम.यू.एम. अली साबरी से विस्तृत चर्चाएं कीं। विदेश मंत्री ने नेता प्रतिपक्ष सजीथ प्रेमदासा और श्रीलंकाई तथा तमिलों का प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं से भी मुलाकात की।

04 अक्टूबर को, विदेश मंत्री इस वर्ष श्रीलंका की अपनी दूसरी यात्रा के दौरान, नव-निर्वाचित राष्ट्रपति दिसानायके द्वारा किए गए स्वागत की दृष्टि से पहले विदेशी गणमान्य व्यक्ति थे। विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति दिसानायके, प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या से मुलाकात की और अपने समकक्ष मंत्री हेराथ के साथ चर्चा की। विदेश मंत्री ने भारत की 'पड़ोसी प्रथम' नीति और सागर दृष्टिकोण के आधार पर द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की मजबूत प्रतिबद्धता व्यक्त की।

एनएसए ने सीएससी के संस्थापक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए 29-30 अगस्त को कोलंबो का दौरा किया। यात्रा के दौरान, एनएसए ने तत्कालीन राष्ट्रपति विक्रमसिंघे, तत्कालीन प्रधानमंत्री गुणवर्धने से मुलाकात की और श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सागाला रत्नायका के साथ द्विपक्षीय चर्चा की।

व्यापार और आर्थिक सहयोग

भारत और श्रीलंका ने आर्थिक और तकनीकी सहयोग समझौता (ईटीसीए) पर चर्चाओं को जारी रखा, जिसमें 13^{वाँ} दौर की वार्ता 08-10 जनवरी को नई दिल्ली में और 14^{वाँ} दौर की वार्ता 24-26 जुलाई को कोलंबो में हुई।

12 फरवरी को, श्रीलंका में एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) क्यूआर-आधारित भुगतान की शुरुआत मॉरीशस के तत्कालीन प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की मौजूदगी में प्रधानमंत्री और तत्कालीन राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने वर्चुअल मोड में संयुक्त रूप से की। बिजली क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत-श्रीलंका संयुक्त कार्यसमूह (जेडब्ल्यूजी) की 5^{वाँ} बैठक और नवीकरणीय ऊर्जा पर संयुक्त कार्यसमूह (जेडब्ल्यूजी) की प्रारंभिक बैठक क्रमशः 28 फरवरी और 11 मार्च को कोलंबो में आयोजित की गई। श्रीलंका में यूपीआई सेवाओं को अधिकाधिक गति देते हुए, फोनपे ने लंकापे के साथ भागीदारी में 15 मई को श्रीलंका में फोनपे यूपीआई भुगतान प्रणाली शुरू की।

भारत में नागपट्टिनम और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत में जाफना के पास कांकेसेथुराई (केकेएस) के बीच यात्री फेरी सेवा 16 अगस्त को फिर से शुरू की गई। फेरी सेवा पूर्व में अक्टूबर 2023 में शुरू की गई थी, लेकिन कुछ ही समय बाद इसे निलंबित कर दिया गया था। भारत के पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड (पीएलएल) और श्रीलंका के एलटीएल होल्डिंग्स लिमिटेड ने 20 अगस्त को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत एलएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और श्रीलंका को एलएनजी आपूर्ति की जाएगी।

आधिकारिक ऋणदाता समिति के सह-अध्यक्ष के रूप में, भारत ने द्विपक्षीय ऋणदाताओं के साथ ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम को शीघ्र अंतिम रूप देने के



प्रधानमंत्री और श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने मॉरीशस के तत्कालीन प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के तत्कालीन गवर्नर की मौजूदगी में श्रीलंका में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) क्यूआर -आधारित भुगतान प्रणाली को संयुक्त रूप से वर्चुअल मोड में रूप से शुरू किया, फरवरी 2024.

लिए श्रीलंका को अपना समर्थन दिया। एशिएन क्लिअरिंग यूनियन और स्वेप फ्रेमवर्क के बकाया को भारत द्वारा छह महीने की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया। इसके अतिरिक्त, भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ श्रीलंका के संवाद में उसका समर्थन करता रहा है।

विकास सहयोग

जून में, श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और विदेश मंत्री ने कोलंबो और त्रिंकोमाली जिलों में मॉडल विलेज हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत 48 घर और कैंडी, मटाले तथा नुवारा एलिया जिलों में भारतीय हाउसिंग प्रोजेक्ट के तीसरे चरण के तहत 106 घर सौंपे, जो भारत-श्रीलंका विकास सहयोग की व्यापक एवं जन-केंद्रित प्रतिबद्धता का प्रमाण है। 04 अक्टूबर को कोलंबो में विदेश मंत्री की यात्रा के दौरान, उन्होंने पूर्ण हो चुकी एलओसी परियोजनाओं से संबंधित भुगतानों को कवर करने के लिए 20.66 मिलियन अमरीकी डॉलर की अनुदान सहायता और कांकेसथुराई बंदरगाह के आधुनिकीकरण के लिए 61.5 मिलियन अमरीकी डॉलर की अनुदान सहायता की घोषणा की। उन्होंने श्रीलंकाई रेलवे को 22 डीजल इंजन उपहार में देने की भी घोषणा की।

टीचिंग हॉस्पिटल बट्टिकलोआ में दो मंजिला अत्याधुनिक नई सर्जिकल यूनिट का उद्घाटन नवंबर में किया गया, जिसे 1.01 मिलियन अमरीकी डॉलर की भारतीय अनुदान सहायता से निर्मित किया गया था। भारत सरकार ने अपनी 17 मिलियन अमरीकी डॉलर की सहायता के हिस्से के रूप में पूरे श्रीलंका में 5000 धार्मिक स्थलों पर सोलर पीवी रूफटॉप सिस्टम भी स्थापित किए।

2024 में, भारत ने लगभग 8.64 मिलियन अमरीकी डॉलर की बहु-क्षेत्रीय अनुदान सहायता के हिस्से के रूप में, वृक्षारोपण समुदाय के लिए तीन कार्यक्रम शुरू किए जिनकी घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा जुलाई 2023 में श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिल समुदाय के आगमन की 200^{वीं} वर्षगांठ मनाने के अवसर पर की गई थी। इन कार्यक्रमों में, प्लांटेशन स्कूलों में 2000 से अधिक शिक्षकों के लिए STEM विषयों में 3 महीने का शिक्षक

प्रशिक्षण कार्यक्रम, छात्रों को 10,000 स्कूल बैग और 30,000 नोटबुक का वितरण और भारतीय आवासन परियोजना के लाभार्थियों को 4000 सौर लालटेन का दान शामिल है।

शिक्षा और क्षमता निर्माण

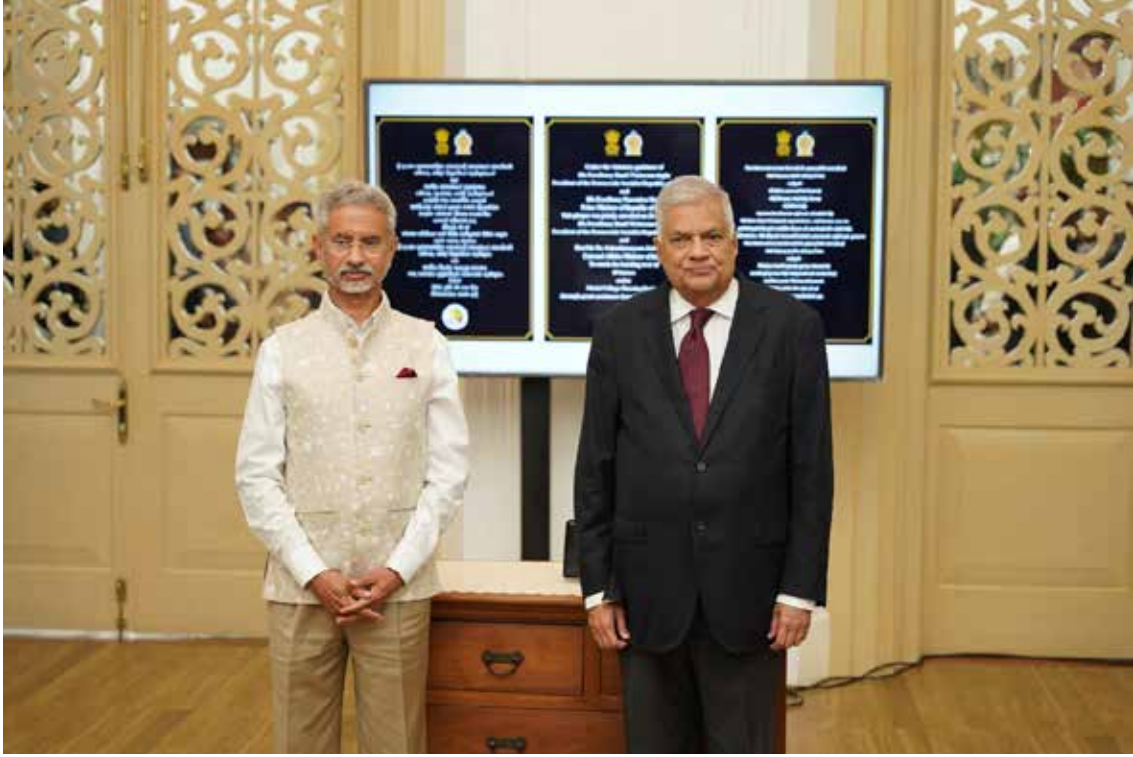
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सचिव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने जुलाई में श्रीलंका का दौरा किया और भारत में श्रीलंका के सिविल सेवा अधिकारियों की क्षमता निर्माण पर चर्चा की। आईटीईसी फ्रेमवर्क के तहत 2024 में एनसीजीजी में चार प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरे किए गए, जिससे 160 श्रीलंकाई सिविल सेवा अधिकारी लाभान्वित हुए।

श्रीलंका के विदेश मंत्रालय के अनुरोध पर, सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान (एस एस आई एफ एस), नई दिल्ली में श्रीलंका के राजनयिकों और अधिकारियों के लिए 05-13 अगस्त को सात दिवसीय विशेष पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया।

रक्षा सहयोग

श्रीलंका नौसेना के कमांडर वाइस एडमिरल प्रियंता परेरा ने गोवा में इंडो-यूएस ज्वाइंट नेवल वार कॉलेज कान्फ्रेंस में भाग लेने के लिए 14-19 अप्रैल को भारत का दौरा किया।

समुद्री बचाव समन्वय केंद्र (एमआरसीसी) की स्थापना 20 जून को विदेश मंत्री की कोलंबो यात्रा के दौरान शुरू की गई जिसे 6 मिलियन अमेरिकी डॉलर के भारतीय अनुदान से स्थापित किया गया था और यह समुद्र में खोज और बचाव कार्यों के लिए एक प्रमुख केंद्र है। भारत-श्रीलंका सेना प्रमुखों की एक दूसरे से 10^{वीं} वार्ता 09 जुलाई को कोलंबो में हुई, जबकि भारतीय तटरक्षक-श्रीलंका तटरक्षक 7^{वीं} उच्च स्तरीय बैठक 10-13 नवंबर को कोलंबो में आयोजित की गई।



विदेश मंत्री और श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कोलंबो में समुद्री बचाव समन्वय केंद्र (एमआरसीसी) का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया, जून 2024.

कई भारतीय नौसेना जहाजों/तटरक्षक जहाजों और पनडुब्बियों ने 2024 में श्रीलंका का दौरा किया, जिससे बंदरगाहों पर कुल कॉल्स संख्या 12 हो गई थी। भारतीय तटरक्षक जहाज 'सचेत' ने 19-21 जून को कोलंबो का दौरा करते हुए श्रीलंका के तटरक्षक जहाज 'सुरक्षा' के लिए 1.2 मिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य के आवश्यक स्पेयर पार्ट्स निःशुल्क सौंपे। जयपुर स्थित भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति द्वारा 03 मई-24 जून को कोलंबो और जाफना में कृत्रिम अंग शिविर आयोजित किए गए, जिससे श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय और नागरिक कर्मियों को लाभ हुआ।

मत्स्य पालन

मत्स्य पालन पर संयुक्त कार्यसमूह (जेडब्ल्यूजी) का छठा दौर 29 अक्टूबर को कोलंबो में आयोजित किया गया। जेडब्ल्यूजी ने मछुआरों और मत्स्य पालन क्षेत्र से संबंधित सभी प्रासंगिक मुद्दों की व्यापक समीक्षा की।

अध्याय

2

हिंद महासागर क्षेत्र

कोमोरोस

भारत और कोमोरोस के बीच मधुर संबंध हैं, जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों का प्रतिबिंब है। भारत कोमोरोस को हिंद महासागर क्षेत्र में अपने विजन 'क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास (सागर)' के अनुरूप एक करीबी पड़ोसी के रूप में देखता है। दोनों देशों के बीच सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में विकास भागीदारी, क्षमता निर्माण और प्रवासी भारतीय समुदाय से संपर्क शामिल हैं।

द्विपक्षीय सहयोग

कोमोरोस में भारत के राजदूत ने 26 मई को मोरोनी में कोमोरोस के राष्ट्रपति अज़ाली असौमानी के अभिषेक समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

कोमोरोस के आंतरिक मंत्री और तत्कालीन कार्यवाहक विदेश मंत्री फ़करीदीन महमूद ने 17 अगस्त को वीओजीएसएस के तीसरे संस्करण के दूसरे विदेश मंत्री सत्र में वर्चुअल रूप से भाग लिया।

आर्थिक, व्यापार और डिजिटल सहयोग

2023-24 में, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 46.6 मिलियन अमरीकी डॉलर रहा, जिसमें भारतीय निर्यात 27.95 मिलियन अमरीकी डॉलर और आयात 18.65 मिलियन अमरीकी डॉलर था। शीर्ष आयात वस्तुओं में लोहा

और इस्पात, तांबा, एल्युमीनियम और लौंग शामिल थे, जबकि शीर्ष निर्यात वस्तुओं में चावल, मांस, कपास, चीनी, वस्त्र आदि शामिल थे।

रक्षा और सुरक्षा

मोरोनी नौसेना बेस के कमांडर लेफ्टिनेंट सिरादजी चामसिडीन ने 19-27 फरवरी को विशाखापत्तनम में आयोजित "मिलन 2024" नौसेना युद्धाभ्यास में पर्यवेक्षक के रूप में कोमोरोस का प्रतिनिधित्व किया।

कोमोरियन तटरक्षक बल के संचालन प्रमुख कैप्टन एलमीर मोहम्मद अहमद ने 02 अप्रैल को तत्कालीन नौसेना प्रमुख द्वारा वर्चुअल रूप से आयोजित महासागर (क्षेत्र में सभी के लिए सक्रिय सुरक्षा और विकास की देखरेख करने वाले समुद्री प्रमुख) की बैठक के दूसरे संस्करण में भाग लिया।

कोमोरियन तटरक्षक बल के कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल आज़ाद अहमदा ने 05 नवंबर को नौसेना प्रमुख द्वारा वर्चुअल प्रारूप में आयोजित महासागर के तीसरे संस्करण में भाग लिया।

सांस्कृतिक और दोनों देशों के नागरिकों के बीच सहयोग

कोमोरोस के एक 12 सदस्यीय सांस्कृतिक समूह ने हरियाणा के सूरजकुंड में 02-18 फरवरी के दौरान आयोजित 37^{वाँ} सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में भाग लिया।



प्रधानमंत्री ने दुबई में फरवरी 2024 में विश्व सरकारों के शिखर सम्मेलन के दौरान मेडागास्कर के राष्ट्रपति एंड्री राजोइलिना से मुलाकात की

बहुपक्षीय सहयोग

कोमोरोस के तत्कालीन विदेश मंत्री धोइहिर धौलकमल ने ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में 09-10 फरवरी के दौरान आयोजित 7^{वें} हिंद महासागर सम्मेलन में भाग लिया।

मेडागास्कर

2024 में भारत-मेडागास्कर द्विपक्षीय संबंधों में और जभी अधिक मजबूती आई, क्योंकि मेडागास्कर भारत के विजन सागर में एक विशेष स्थान रखता है।

द्विपक्षीय संवाद

14 फरवरी को, प्रधानमंत्री ने दुबई में विश्व सरकारों के शिखर सम्मेलन के दौरान मेडागास्कर के राष्ट्रपति एंड्री राजोइलिना के साथ द्विपक्षीय बैठक की और भारत-मेडागास्कर संबंधों को और अधिक मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की।

मंत्रिस्तरीय स्तर पर बातचीत 2024 में भी जारी रही। विदेश मंत्री ने 10 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में 7^{वें} हिंद महासागर सम्मेलन के दौरान मेडागास्कर के विदेश मंत्री रसता राफारा विताफिका के साथ बातचीत की। अगस्त में, मेडागास्कर का प्रतिनिधित्व अर्थव्यवस्था और वित्त मंत्री और युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के महासचिव ने वीओजीएसएस (VoGSS) के तीसरे संस्करण में किया।

मेडागास्कर के स्वतंत्र राष्ट्रीय चुनाव आयोग (सीईएनआई) के अध्यक्ष ने 29-31 जनवरी को भारत का दौरा किया और मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की। सीईएनआई के दो प्रतिनिधियों ने 2024 के आम चुनावों के लिए 04-09 मई के दौरान नई दिल्ली में भारत के चुनाव आयोग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन आगंतुक कार्यक्रम में भी भाग लिया।

विकास सहयोग, अर्थव्यवस्था और संस्कृति

मेडागास्कर के 15 सदस्यीय सांस्कृतिक दल ने हरियाणा के सूरजकुंड में 02-18 फरवरी तक आयोजित 37^{वें} सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में भाग लिया।

पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच विकास सहयोग गहरा हुआ है। 27 जून को, दोनों पक्षों ने सीमा शुल्क मामलों में सहयोग और पारस्परिक प्रशासनिक सहायता पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिससे सीमा शुल्क मामलों में आपसी क्षमता निर्माण को मजबूती मिली। जून में, 14 मालागासी राजनयिकों ने नई दिल्ली में सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान में आयोजित प्रथम विशेष पाठ्यक्रम में भाग लिया।

04 सितंबर को, भारत की अनुदान सहायता के तहत मेडागास्कर की नेशनल असेंबली में स्थापित सौर ऊर्जा प्रणाली का उद्घाटन मेडागास्कर की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष, कार्यवाहक विदेश मंत्री और मेडागास्कर में भारत के राजदूत द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।

एंटानानारिवो में 12 नवंबर से प्रथम 'जयपुर फुट कैप' आयोजित किया गया, जिसमें मेडागास्कर के 500 से अधिक दिव्यांगजनों को निःशुल्क

कृत्रिम अंग प्रदान किए गए। शिविर के उद्घाटन समारोह में मेडागास्कर की प्रथम महिला, मालागासी के लोक स्वास्थ्य मंत्री और अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारी उपस्थित थे।

एंटानानारिवो में 06 दिसंबर को इंडिया कॉर्नर का शुभारंभ मेडागास्कर के राष्ट्रीय पुस्तकालय में मेडागास्कर के संचार और संस्कृति मंत्री और मेडागास्कर में भारत के राजदूत द्वारा किया गया।

10 दिसंबर को, भारत ने मेडागास्कर में नगरपालिका चुनावों के आयोजन से पहले सीईएनआई को तीन ट्रक उपहार में दिए। इन्हें सौपने के लिए आयोजित समारोह में सीईएनआई के अध्यक्ष और मेडागास्कर के परिवहन और मौसम विज्ञान मंत्री ने भाग लिया।

रक्षा सहयोग

भारत और मेडागास्कर ने नियमित नौसैनिक युद्धाभ्यासों के माध्यम से अपनी नौसेनाओं के बीच संचार को बढ़ाया है। मेडागास्कर के नौसेना प्रमुख ने फरवरी में विशाखापत्तनम में 'मिलन 2024' युद्धाभ्यास में एक पर्यवेक्षक के रूप में देश का प्रतिनिधित्व किया। मेडागास्कर ने अप्रैल और नवंबर में वर्चुअल प्रारूप में भारत द्वारा आयोजित महासागर की बैठकों में भी भाग लिया।

मॉरीशस

भारत और मॉरीशस के नागरिकों के बीच प्रगाढ़ संबंधों के चलते दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंध हैं। ये संबंध हमारे विजन सागर और ग्लोबल साउथ के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के केंद्र-बिंदु पर स्थित हैं। समुद्री सुरक्षा, आईसीटी, स्वास्थ्य परिचर्या, विकास भागीदारी और आपदा प्रबंधन में सहयोग के लिए संबंध विस्तारित होते जा रहे हैं।

द्विपक्षीय सहयोग

2024 में कई उच्च-स्तरीय दौरें हुए। माननीय राष्ट्रपति जी ने 11-13 मार्च के दौरान मॉरीशस की राजकीय यात्रा की। मॉरीशस सरकार के निमंत्रण पर वह 12 मार्च को मॉरीशस राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। उन्होंने भारतीय मूल के सातवीं पीढ़ी के मॉरीशसवासियों को ओसीआई कार्ड देने और गंगा तालाब परिसर के पुनर्विकास के लिए भारत की सहायता की भी घोषणा की। अन्य बातों के अलावा, माननीय राष्ट्रपति जी ने वित्त, सिविल सेवाओं, कराधान और भ्रष्टाचार विरोधी क्षेत्रों में चार समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान भी किया।



माननीय राष्ट्रपति जी ने पोर्ट लुइस में मॉरीशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रुपुन के साथ वार्ता की, मार्च 2024.



प्रधानमंत्री और मॉरीशस के तत्कालीन प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने अगालेगा में हवाई पट्टी और जेटी का वर्चुअल उद्घाटन किया , फरवरी 2024.

मॉरीशस की तत्कालीन उपराष्ट्रपति मैरी सिरिल एडी बोइसेज़न ने 20-22 अगस्त तक 19^{वें} सीआईआई इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव में भाग लिया।

प्रधानमंत्री और मॉरीशस के तत्कालीन प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने 12 फरवरी को संयुक्त रूप से यूपीआई और रुपे कार्ड सेवाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने 29 फरवरी को अगालेगा में हवाई पट्टी और जेटी का भी उद्घाटन किया।

तत्कालीन प्रधानमंत्री जगन्नाथ ने प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए 09-11 जून के दौरान भारत का दौरा किया। उन्होंने 17 अगस्त को वीओजीएसएस के तीसरे संस्करण के उद्घाटन करने वाले नेताओं के सत्र में भी भाग लिया।

10 नवंबर को मॉरीशस में हुए आम चुनावों के बाद, प्रधानमंत्री ने नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री डॉ. नवीनचंद्र रामगूलम को बधाई दी और उन्हें भारत आने का निमंत्रण दिया।

विदेश मंत्री ने 16-17 जुलाई के दौरान मॉरीशस का आधिकारिक दौरा किया। इस यात्रा के दौरान भारत द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया और अंतरिक्ष, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान किया गया। मॉरीशस के अर्दोर्नी जनरल और तत्कालीन विदेश मंत्री मनीष गोबिन ने भारत का दौरा किया और 21-23 फरवरी के दौरान 9^{वें} रायसीना डायलॉग में भाग लिया। तत्कालीन वित्तीय सेवा मंत्री सूमिल दुथ भोला ने वित्तीय सेवा प्रोत्साहन अभियान में भाग लेने के लिए 14-24 मार्च और 04-11 अगस्त तक भारत का दौरा किया।

24 जनवरी को, मॉरीशस की मुख्य न्यायाधीश बीबी रेहाना मुंगली-गुलबुल ने भारत का दौरा किया और भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना के 75^{वें} वर्ष के स्मरणोत्सव में भाग लिया। मॉरीशस नेशनल असेंबली के

तत्कालीन अध्यक्ष एड्रियन डुवाल ने 16-18 अगस्त के दौरान भारत का दौरा किया और दोनों देशों की संसदों के बीच संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की।

बैंक ऑफ मॉरीशस के गवर्नर ने वित्त मंत्रालय के साथ चर्चा करने के लिए 02-05 अक्टूबर को भारत का दौरा किया। मॉरीशस के चुनाव आयुक्त मोहम्मद इरफान अब्दुल रहमान ने 29 मई से 09 जून तक अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन आगंतुक कार्यक्रम के लिए भारत का दौरा किया।

बहुपक्षीय सहयोग

मॉरीशस ने 30 अगस्त को श्रीलंका में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन सचिवालय की स्थापना के लिए चार्टर और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के हिस्से के रूप में विकसित 25 किलोवाट की सोलर रूफटॉप प्रदर्शन परियोजना का उद्घाटन 03 जून को मॉरीशस के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में किया गया।

विकास सहयोग

अगालेगा में हवाई पट्टी और जेटी तथा न्यू ग्रोव और कैप माल्हेरेक्स में सिविल सेवा कॉलेज, मेडिकल क्लिनिक और क्षेत्रीय स्वास्थ्य केंद्र जैसी परियोजनाओं को पूरा करके विकास सहयोग को बढ़ाया गया। विदेश मंत्री ने ग्रैंड बोइस में भारत-सहायता प्राप्त मेडिकल क्लिनिक और प्रथम विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन 17 जुलाई को किया।

चल रही परियोजनाओं में, ई-बसों की आपूर्ति, राष्ट्रीय अभिलेखागार एवं पुस्तकालय भवन, और फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला आदि शामिल हैं।

17 अक्टूबर को, भारत ने भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (आईडीईएएस) के तहत जल पाइपलाइन प्रतिस्थापन परियोजना के वित्तपोषण के लिए मॉरीशस को आईएनएन 487.60 करोड़ का पहला रुपया मूल्यवर्गित एलओसी दिया। इस परियोजना में मॉरीशस में लगभग 100 किलोमीटर लंबी जल पाइपलाइन को बदलने की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा, भारत द्वारा वित्तपोषित 50 उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाएं पूरी की गई हैं।

रक्षा और सुरक्षा सहयोग

भारत ने अप्रैल में सीजीएस विक्ट्री की मरम्मत का काम निःशुल्क पूरा कर लिया, जबकि विशाखापत्तनम में सीजीएस वैलिंट की मरम्मत का काम चल रहा है। भारत ने आने वाले महीनों में सीजीएस बाराकुडा की मरम्मत का काम भी करने की प्रतिबद्धता जताई है। एनएसजी ने भारत में मॉरीशस पुलिस बल के चार बैचों को अपहरण विरोधी, बंधकों को छुड़ाने और आतंकवाद विरोधी अभियानों के बारे में प्रशिक्षण दिया। एसपीजी ने 01-05 जुलाई तक मॉरीशस की वीआईपी सुरक्षा इकाई के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया। भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल के जहाजों, जैसे कि आईएनएस तीर, आईएनएस सुजाता, आईसीजीएस सारथी ने इस वर्ष मॉरीशस के बंदरगाहों पर दौरा किया।

अर्थव्यवस्था, व्यापार और डिजिटल सहयोग

माननीय राष्ट्रपति जी की 11-13 मार्च की यात्रा के दौरान, भारत-मॉरीशस दोहरा कर परिहार समझौता (डीटीएए) को संशोधित करने के लिए एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए ताकि इसे बेस ईरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग (बीईपीएस) के न्यूनतम मानकों के अनुरूप बनाया जा सके। इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (गिफ्ट सिटी) तथा मॉरीशस के वित्तीय सेवा आयोग के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। 25 अप्रैल को, अफ्रीकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की स्थापना में तकनीकी और वित्तीय सहयोग के लिए अफ्रीकी पीयर रिव्यू मैकेनिज्म और भारत स्थित केयर रेटिंग्स (अफ्रीका) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

06 मई को, भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशालय ने मॉरीशस को 14,000 मीट्रिक टन सफेद गैर-बासमती चावल के निर्यात के लिए एक विशेष छूट को मंजूरी दी।

सांस्कृतिक और नागरिकों के बीच सहयोग

मॉरीशस के दस युवा प्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने 14-29 जनवरी को दिल्ली में गणतंत्र दिवस शिविर में भाग लिया और राष्ट्रीय कैडेट कोर युवा विनिमय कार्यक्रम के भाग के रूप में आगरा और जयपुर का दौरा किया। मॉरीशस ने 07-09 अगस्त तक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन विश्वरंग 2024 की मेजबानी की। यह कार्यक्रम विश्व हिंदी सचिवालय और भोपाल में रवींद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय सहित कई संस्थानों के सहयोग से

आयोजित किया गया था। रवींद्रनाथ टैगोर संस्थान में विश्वरंग 2024 के दौरान, मॉरीशस के तत्कालीन राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन ने रवींद्रनाथ टैगोर की एक प्रतिमा का अनावरण किया। इस कार्यक्रम में 20 देशों के लगभग 150 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

सेशेल्स

भारत और सेशेल्स के बीच मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंध हैं। भारत सेशेल्स को हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में मानता है, जो उसके विजन सागर से संरेखित है। सेशेल्स भारत को विकास सहायता और क्षमता निर्माण के लिए एक विश्वसनीय भागीदार मानता है, साथ ही बहुपक्षीय मंचों पर भी भारत का समर्थन करता है। दोनों देशों के बीच सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में विकास भागीदारी, रक्षा सहयोग, क्षमता निर्माण पहल और प्रवासी भारतीय समुदाय से संपर्क शामिल हैं।



विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ से मुलाकात की, जून 2024।

द्विपक्षीय जुड़ाव

सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ ने 08-10 जून तक नई दिल्ली का दौरा किया। यात्रा के दौरान उन्होंने माननीय राष्ट्रपति जी से मुलाकात की, प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया और विदेश मंत्री के साथ बातचीत की।

सेशेल्स के कृषि, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण मंत्री फ्लेवियन जौबर्ट ने 06-09 फरवरी को गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह में भाग लिया, जिसमें



10वां भारत-सेशेल्स युद्धाभ्यास लामितिये मार्च 2024 में विक्टोरिया में आयोजित किया गया।

ऊर्जा और जलवायु सहयोग पर चर्चा की गई। उन्होंने 17 अगस्त को वीओजीएसएस के तीसरे संस्करण में सेशेल्स का प्रतिनिधित्व भी किया।

संस्थागत सहयोग में सीएजी इंडिया द्वारा 21-22 अक्टूबर को सेशेल्स की यात्रा के दौरान सार्वजनिक खेल उपक्रम की लेखापरीक्षा के बारे में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना शामिल था। सेशेल्स निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष डैनी लुकास सहित अधिकारियों ने आम चुनावों के संचालन और प्रक्रिया का निरीक्षण करने के लिए 05-07 मई तक भारत का दौरा किया।

विकास सहयोग

भारत ने 2024 में 10 मिलियन अमरीकी डॉलर का एलओसी कार्यक्रम पूरा करके तथा 60 अशोक लीलैंड बसें आपूर्ति करके, सेशेल्स के साथ अपनी सामाजिक-आर्थिक भागीदारी को बढ़ाया। उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं (एचआईसीडीपी) के तहत, तीन स्कूलों का जीर्णोद्धार पूरा किया गया, और 2.9 मिलियन अमरीकी डॉलर के एचआईसीडीपी चरण-II के तहत सड़क परियोजनाएं शुरू हुईं। उम्मीद है कि ये परियोजनाएं 2025 के मध्य तक पूरा हो जाएंगी। भारत ने आईटीईसी नागरिक और रक्षा कार्यक्रमों के तहत 75 सेशेल्स नागरिकों को प्रशिक्षित किया। जुलाई में, विशेष निर्यात छूट के तहत 200 टन गैर-बासमती चावल सौंपा गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा वित्तपोषित 5 मीट्रिक टन सोलर कोल्ड स्टोरेज सुविधा-केंद्र अक्टूबर में प्रस्लिन द्वीप पर चालू किया गया।

आर्थिक और व्यापार सहयोग

भारत-सेशेल्स द्विपक्षीय व्यापार में 2023-24 में 14.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अप्रैल से सितंबर के बीच व्यापार का मूल्य 40.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसमें भारतीय निर्यात 38.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर और आयात 2.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर था।

रक्षा सहयोग

सेशेल्स रक्षा बलों के पोत पीएस ज़ोरोस्टर ने फरवरी में विशाखापत्तनम में 'मिलन 2024' युद्धाभ्यास में भाग लिया। जून में सेशेल्स में लौटने

से पहले कोलकाता में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई) में इसकी मरम्मत की गई। 10^{वां} भारत-सेशेल्स युद्धाभ्यास लामितिये (लामितिये) मार्च में विक्टोरिया में आयोजित किया गया।

सेशेल्स में अमेरिका के नेतृत्व में 'कटलैस एक्सप्रेस' युद्धाभ्यास में आईएनएस तीर ने भाग लिया, जो आईओआर की सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को परिलक्षित करता है। आईएनएस सुनयना ने जून में 48^{वां} राष्ट्रीय दिवस समारोह के लिए सेशेल्स का दौरा किया, जिसमें इसके एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ने फ्लाई-पास्ट और डेमन्स्ट्रेशन किया।

फरवरी में, भारत द्वारा उपहार में दिए गए दो डोर्नियर विमानों की एचएएल कानपुर में मरम्मत की गई, जिसके पुर्जे आईएनएस तीर द्वारा सुपुर्द किए गए। सेशेल्स ने कई भारतीय बहुपक्षीय रक्षा कार्यक्रमों में भाग लिया, जिसमें महासागर, गोवा समुद्री संगोष्ठी और सीएससी सेमिनार शामिल हैं। भारत के हाइड्रोग्राफिक कार्यालय के एक प्रतिनिधिमंडल ने परिवहन मंत्री एंटनी डेरजैक और सेशेल्स रक्षा बलों के प्रमुख ब्रिगेडियर माइकल रोसेट की उपस्थिति में हाइड्रोग्राफी पर नवगठित सेशेल्स स्थायी समिति के साथ हाइड्रोग्राफी सहयोग बढ़ाने के लिए नवंबर में सेशेल्स का दौरा किया।

सांस्कृतिक सहयोग

2024 में दोनों पक्षों के नागरिकों के बीच जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। सेशेल्स-भारत दिवस को भारतीय प्रवासी समुदाय संगठनों के साथ भागीदारी में छह साल बाद फिर से शुरू किया गया। 03-15 अगस्त के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट, पुरुष और महिला क्रिकेट मैच, आईसीसीआर नृत्य मंडली द्वारा प्रदर्शन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और भारत-सेशेल्स व्यंजन खाद्य महोत्सव शामिल थे।

आईसीसीआर नृत्य मंडली ने 12-15 अगस्त तक सेशेल्स का दौरा किया और राष्ट्रीय इतिहास संग्रहालय, आईसीसीएस राष्ट्रीय सभागार तथा राष्ट्रीय खेल परिषद हॉल में प्रदर्शन किया। मंडली ने कथक कार्यशाला का भी आयोजन किया।

अध्याय

3

दक्षिण पूर्व एशिया और ओशिनिया

इस वर्ष दक्षिण पूर्व एशिया और ओशिनिया क्षेत्रों के साथ भारत का संबंध विभिन्न स्तरों पर विस्तारित तथा और गहरा हुआ।

ऑस्ट्रेलिया

भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी (सीएसपी) के अंतर्गत रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और निवेश, शिक्षा और अनुसंधान, साइबर और अंतरिक्ष, खेल, खनन और महत्वपूर्ण खनिजों, नवीकरणीय ऊर्जा और लोगों की गतिशीलता सहित विविध क्षेत्रों में परिवर्तनकारी वृद्धि देखी गई तथा इसे और अधिक मजबूती प्रदान की गई।

दूसरा भारत-ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन 19 नवंबर को रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया। इस अवसर पर एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। भारत-ऑस्ट्रेलिया नवीकरणीय ऊर्जा भागीदारी का शुभारंभ वार्षिक शिखर सम्मेलन से पहले किया गया, जो मार्च 2023 में आयोजित प्रथम वार्षिक शिखर सम्मेलन में सहमत प्रतिबद्धता को उजागर करता है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने 11 अक्टूबर को आयोजित आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में और 21 सितंबर को अमेरिका के विलमिंगटन में आयोजित छठे क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीस से मुलाकात की। विदेश मंत्री और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने 05 नवंबर को 15^{वें} विदेश मंत्री फ्रेमवर्क वार्ता यानी फॉरेन मिनिस्टर्स फ्रेमवर्क डायलॉग का आयोजन किया और द्विपक्षीय सहयोग के संपूर्ण पहलुओं की समीक्षा की। इस वर्ष विदेश मंत्री ने

ऑस्ट्रेलिया की दो आधिकारिक यात्राएँ कीं, जिनमें फरवरी में पर्थ में पहली बार ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित हिंद महासागर सम्मेलन और नवंबर में कैनबरा में आयोजित रायसीना डाउन अंडर वार्ता शामिल है।



विदेश मंत्री ने ब्रिस्बेन में प्रशांत क्षेत्र में एचएडीआर आपूर्ति के लिए ऑस्ट्रेलिया के मानवीय रसद क्षमता (एचएलसी) गोदाम का दौरा किया, नवंबर 2024.

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा ऑस्ट्रेलिया के व्यापार और पर्यटन मंत्री डॉन फैरेल ने सितंबर में एडिलेड में 19^{वें} भारत-ऑस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्रिस्तरीय आयोग (जेएमसी) की सह-अध्यक्षता की और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों पक्ष व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (सीईसीए) के लिए बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि आर्थिक और व्यापार संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (ईसीटीए) के परिणामस्वरूप, द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि हुई है जिससे भारतीय अनार सहित ऑस्ट्रेलियाई बाजारों में नए भारतीय उत्पादों के लिए बाजार खुल गया है।

महत्वपूर्ण खनिजों, खनन, नवीकरणीय ऊर्जा और शिक्षा में सहयोग का विस्तार किया गया। भारत-ऑस्ट्रेलिया नवीकरणीय ऊर्जा भागीदारी की शुरुआत 19 नवंबर को दूसरे वार्षिक शिखर सम्मेलन से पहले की गई थी, जो मार्च 2023 में आयोजित पहले वार्षिक शिखर सम्मेलन में जताई गई प्रतिबद्धता का परिचायक है। इससे पहले, महत्वपूर्ण खनिजों पर संयुक्त कार्यसमूह ने अक्टूबर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय खनन और संसाधन सम्मेलन (आईएमएसी) के इतर बैठक की। दूसरी ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद (एआईईएससी) की बैठक 24 अक्टूबर को सिडनी में हुई, जिसकी सह-अध्यक्षता शिक्षा और कौशल विकास मंत्री और ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा और युवा मामले मंत्री जेसन क्लेयर ने ऑस्ट्रेलिया के कौशल और प्रशिक्षण मंत्री एंड्रयू जाइल्स के साथ की। भारत में परिसर स्थापित करने में ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय, डीकिन और वोलोंगोंग पहले विदेशी विश्वविद्यालय हैं।

अंतरिक्ष क्षेत्र में चल रहे सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष एजेंसी (एएसए) के बीच गगनयान मिशन के लिए चालक दल और चालक दल मॉड्यूल की रिकवरी से संबंधित एक कार्यान्वयन व्यवस्था पर 20 नवंबर को हस्ताक्षर किए गए। इसके अलावा, ऑस्ट्रेलिया ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष निवेश भारत (आईएसआई) परियोजना कार्यक्रम में अंतरिक्ष अनुदान के हिस्से के रूप में सहयोगात्मक अंतरिक्ष परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए 11.62 मिलियन अमरीकी डॉलर की भी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया बेंगलुरु स्पेस एक्सपो का इनोवेशन कंट्री पार्टनर था।

रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 2+2 सचिव-स्तरीय वार्ता की प्रक्रिया व तंत्र को बहाल किया तथा 2+2 विदेश एवं रक्षा सचिव परामर्श का चौथा संस्करण 14 अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने नियमित रक्षा युद्धाभ्यास किए, जिनमें युद्धाभ्यास सदरन डिस्कवरी (फरवरी), युद्धाभ्यास सदरन जैकारू (जून), युद्धाभ्यास पिच ब्लैक (जुलाई-अगस्त), युद्धाभ्यास काकाडू (सितंबर), युद्धाभ्यास तरंग शक्ति (सितंबर), युद्धाभ्यास मालाबार (अक्टूबर) और ऑस्ट्रे-हिंद (नवंबर) शामिल हैं। ऑस्ट्रेलियाई नौसेना प्रमुख ने अप्रैल में भारत का दौरा किया। रक्षा बलों के बीच स्टाफ वार्ता भी हुई। नवंबर में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सैन्य विमानों के एयर-टू-एयर रिफ्यूलिंग की व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए गए।



विदेश सचिव और सचिव (रक्षा) ने सचिव, रक्षा विभाग ग्रेग मोरियार्टी और सचिव, विदेश मामले एवं व्यापार विभाग, जान एडम्स के साथ चौथे (4^{वां}) भारत-ऑस्ट्रेलिया 2+2 सचिव-स्तरीय परामर्श में भाग लिया, नई दिल्ली, अक्टूबर 2024.



फॉरेन ट्रेनिंग नोड, पुणे में संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास ऑस्ट्रेलिया-हिंद का तीसरा संस्करण, नवंबर 2024

यह पहली बार है कि, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई), कोलकाता के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के नेतृत्व में भारतीय डिफेंस शिपयार्ड का एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय शिपयार्ड के लिए औद्योगिक सहयोग के संभावित अवसरों का पता लगाने के लिए 08-12 अप्रैल को ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया।

भारतीय रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) ने 24-26 जुलाई को पर्थ में हिंद महासागर रक्षा और सुरक्षा सम्मेलन में एक पेवेलियन की मेजबानी भी की। रक्षा राज्य मंत्री ने 11-13 सितंबर को मेलबर्न में आयोजित लैंड फोर्स इंटरनेशनल लैंड डिफेंस एक्सपोजिशन में पहली बार भाग लिया।

दोनों देशों के नागरिकों के बीच संपर्क-सूत्र, भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों का आधार हैं। दिसंबर 2024 तक, 1,35,301 की संख्या में भारतीय छात्र ऑस्ट्रेलिया में विदेश में जन्मे छात्रों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या हैं। भारतीय समुदाय की जरूरतों को पूरा करने और ऑस्ट्रेलिया में राजनयिक उपस्थिति का विस्तार करने के लिए, 04 नवंबर को विदेश मंत्री द्वारा ब्रिस्बेन में भारत के एक नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया गया। अक्टूबर में वर्क एंड होलीडे वीजा कार्यक्रम के संचालन और 09 दिसंबर को टेलेंटेंड अर्ली-प्रोफेशनल्स स्कीम (एमएटीईएस) के लिए मोबिलिटी व्यवस्था के संचालन ने ऑस्ट्रेलिया में युवा पेशेवरों की गतिशीलता को बढ़ाने में सहायता की। भारत ऑस्ट्रेलिया के लिए चौथा सबसे बड़ा पर्यटन बाजार बन गया है।

ऑस्ट्रेलिया गोवा में 20-28 नवंबर को आयोजित 55^{वां} भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 'कंट्री ऑफ फोकस' था।

ब्रुनेई

प्रधानमंत्री ने 03-04 सितंबर को ब्रुनेई की ऐतिहासिक यात्रा की, जो किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय आधिकारिक यात्रा थी और यह यात्रा दोनों देशों के परस्पर राजनयिक संबंधों की स्थापना की 40^{वीं} वर्षगांठ के अवसर पर हुई। सैटेलाइट और लॉन्च व्हीकल के लिए टेलीमेट्री ट्रेकिंग

एवं टेलीकमांड स्टेशन के संचालन में सहयोग और अंतरिक्ष अनुसंधान, विज्ञान और अनुप्रयोगों के क्षेत्र में सहयोग पर 04 सितंबर को एक समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान किया गया। भारत-ब्रुनेई संवर्धित भागीदारी पर एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया।



आधिकारिक यात्रा के लिए ब्रुनेई पहुंचने पर प्रधानमंत्री का क्राउन प्रिंस हाजी अल-मुहतादी बिल्लाह द्वारा स्वागत, सितंबर 2024.

विदेश मंत्री ने 26 जुलाई को आसियान-भारत विदेश मंत्रियों की बैठक और मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (पीएमसी) के दौरान वियनतियाने में ब्रुनेई के द्वितीय विदेश मंत्री दातो एरीवानपेहिन यूसुफ से मुलाकात की। दोनों मंत्रियों ने भारत और ब्रुनेई के बीच राजनयिक संबंधों के 40 वर्षों के उपलक्ष्य में एक लोगो का अनावरण किया। ब्रुनेई के विदेश मंत्री दातो हाजी एरीवान ने भी 17 अगस्त को वर्चुअल मोड में आयोजित वीओजीएसएस के तीसरे संस्करण के दो सत्रों में भाग लिया।



प्रधानमंत्री ने एक कमेमरेटिव फ्लैक (स्मारक पट्टिका) का अनावरण करके बंदर सेरी बेगवान में भारतीय उच्चायोग के चांसरी भवन का उद्घाटन किया, सितंबर 2024

आईसीजीएस समुद्र पहरदार और आईएनएस किल्टन ने क्रमशः 09-12 अप्रैल और 25-28 मई को ब्रुनेई का दौरा किया, जिससे दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध मजबूत हुए। चार भारतीय शिक्षकों ने 3 अक्टूबर को आयोजित ब्रुनेई शिक्षक दिवस के अवसर पर ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया से पुरस्कार प्राप्त किए। भारत क्षमता निर्माण पहलों के माध्यम से ब्रुनेई के दीर्घकालिक विकास में सहायता कर रहा है।

रॉयल ब्रुनेई एयरलाइंस ने 05 नवंबर को भारत से ब्रुनेई (चेन्नई-बंदर सेरी बेगावान) के लिए सीधी उड़ानें भरीं, जिससे दोनों देशों के बीच संपर्क बढ़ा।

कंबोडिया

विदेश मंत्री ने जुलाई में लाओ पीडीआर के वियनतियाने में आसियान-भारत विदेश मंत्रियों की बैठक और मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के इतर कंबोडिया के उप प्रधानमंत्री और विदेश मामले एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री सोक चेंडा सोफिया से मुलाकात की। कंबोडिया के संस्कृति और ललित कला मंत्री फोएंगसैकोना ने जुलाई में नई दिल्ली में विश्व धरोहर समिति के 46^{वें} सत्र में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया। कंबोडिया के नागरिक उड्डयन के राज्य सचिवालय के प्रभारी मंत्री माओ हवन्नल ने जनवरी में हैदराबाद में विंग्स इंडिया 2024 और सितंबर में नई दिल्ली में नागरिक उड्डयन पर दूसरे एशिया-प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भाग लिया। कंबोडिया के डाक और दूरसंचार मंत्रालय के राज्य सचिव सोक पुथिवुथ ने नई दिल्ली में आईटीयू विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा (डब्ल्यूटीएसए-24) में भाग लेने के लिए अक्टूबर में भारत का दौरा किया।



विदेश मंत्री ने वियनतियाने में आसियान बैठकों के इतर कंबोडिया के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री सोक चेंडा सोफिया से मुलाकात की, जुलाई 2024.

17 अगस्त को, विदेश मामले और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्रालय के राज्य सचिव वेंटिंग पुथिरस्मे और कंबोडिया के स्वास्थ्य मंत्रालय के राज्य सचिव लो वेसनाकिरी ने वीओजीएसएस के तीसरे संस्करण के क्रमशः विदेश मंत्रियों के सत्र और स्वास्थ्य मंत्रियों के सत्र में अपने देश का प्रतिनिधित्व किया।

भारत और कंबोडिया के बीच रक्षा सहयोग 23-25 जुलाई को सिकंदराबाद, भारत में सेना-से-सेना स्टाफ वार्ता के दूसरे दौर के साथ आगे बढ़ा। राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज (एनडीसी), नई दिल्ली के एक प्रतिनिधिमंडल में भारत के 14 अधिकारी और मित देशों के 7 अधिकारी शामिल थे, जिन्होंने 01-05 सितंबर को स्ट्रेजिक नेबरहुड स्टडी दौरे के लिए कंबोडिया का दौरा किया। इसके अतिरिक्त, कंबोडिया के 32 रक्षा कर्मियों ने भारत में रक्षा आईटीईसी कार्यक्रम और एक टेलर-मेड कोर्स के तहत प्रशिक्षण प्राप्त किया।

नई दिल्ली में 19 जून को व्यापार और निवेश पर भारत-कंबोडिया संयुक्त कार्यसमूह की दूसरी बैठक के साथ भारत और कंबोडिया के बीच व्यापार और निवेश संबंध और अधिक मजबूत हुए। पर्यटन सहयोग पर भारत-कंबोडिया संयुक्त कार्यसमूह की चौथी बैठक फरवरी में वर्चुअल रूप में आयोजित की गई और पहला भारत-कंबोडिया पर्यटन वर्ष जून में नई दिल्ली में शुरू किया गया।

कुल 258 कंबोडियाई नागरिकों ने आईटीईसी कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण का लाभ उठाया, जिसमें 8 कस्टमाइज्ड प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शामिल हैं। 65

कंबोडियाई छात्रों ने भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) के तहत छात्रवृत्ति का लाभ उठाया, जिसमें मेकांग-गंगा सहयोग (एमजीसी) की 10 छात्रवृत्तियाँ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, 27 कंबोडियाई नागरिकों ने एमजीसी कार्य योजना के तहत भारत में विभिन्न प्रशिक्षणों में भाग लिया। सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान (एसएसआईएफएस) में कंबोडियाई राजनयिकों के लिए 27 मार्च-5 अप्रैल को एक कस्टमाइज्ड प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 15 कंबोडियाई राजनयिक शामिल हुए। भारत और कंबोडिया ने 22 अप्रैल को सिविल सेवा में मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

विकास सहयोग के मोर्चे पर, बारूदी सुरंगों से तीन जिलों और एक कम्यून को मुक्त करने के लिए कार्य भारतीय अनुदान सहायता के तहत कंबोडिया के कोह कांग प्रांत में शुरू किया गया। इसके अतिरिक्त, मेकांग-गंगा सहयोग (एमजीसी) के तहत तीन त्वरित प्रभाव परियोजनाएं (क्यूआईपी) पूरी की गईं।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा कंबोडिया में ता प्रोहम और ग्रीह विहियर मंदिरों में विरासत संरक्षण कार्य में प्रगति आई है। अथोरिटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द साइट एंड मैनेजमेंट ऑफ द रीजन ऑफ अंगकोर (एपीएसएआरए), कंबोडिया के राष्ट्रीय प्राधिकरण के निर्माण कार्य में तथा अनुदान सहायता के तहत कंबोडिया के सिएम रीप में वाट राजा बो पैगोडा चित्रकलाओं के जीर्णोद्धार एवं संरक्षण के कार्य में भी प्रगति देखी गई।



कंबोडिया की महिला मामले मंत्री इंग कांथा फावी और कंबोडिया में भारत के राजदूत ने मेकांग गंगा सहयोग के हिस्से के रूप में त्वरित प्रभाव परियोजना योजना के तहत 3-पाठशाला वाली इमारत का उद्घाटन किया, कंबोडिया, जुलाई 2024

एक पर्यवेक्षक के रूप में, कंबोडिया नवंबर में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन (जीबीए) में शामिल हुआ। उसने सदस्य देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट गठबंधन (आईबीसीए) में शामिल होने के लिए अपनी सहमति भी व्यक्त की। नोम पेन्ह और नई दिल्ली के बीच सीधी उड़ानें 16 जून को शुरू हुईं।

इंडोनेशिया

भारत और इंडोनेशिया ने इस वर्ष राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो को मार्च में इंडोनेशिया का राष्ट्रपति चुना गया। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो और उपराष्ट्रपति जिब्रान राकाबुमिंग के जकार्ता में 20 अक्टूबर को उद्घाटन समारोह के दौरान विदेश राज्य मंत्री (पीएम) ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। प्रधानमंत्री ने 18 नवंबर को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में जी20 शिखर सम्मेलन के इतर राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो से मुलाकात की। यह दोनों नेताओं के बीच पहली मुलाकात थी। विदेश मंत्री और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने 23 अक्टूबर को ब्रिक्स प्लस शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के कज़ान में और पुनः नवंबर में इटली के फिउगी में जी-7 विदेश मंत्रियों की बैठक के इतर मुलाकात की। वीओजीएसएस के तीसरे संस्करण के वाणिज्य/व्यापार मंत्रियों के सत्र में 17 अगस्त को व्यापार उप मंत्री जेरी साम्बुआगा ने भाग लिया।



विदेश राज्य मंत्री (पीएम) इंडोनेशिया के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो से मुलाकात करते हुए, 20 अक्टूबर।

आठवां भारत-इंडोनेशिया विदेश कार्यालय परामर्श (एफओसी) 26 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 23 अगस्त को, जकार्ता में आतंकवाद-रोधी संयुक्त कार्यसमूह (जेडब्ल्यूजी) की छठी बैठक आयोजित की गई। मार्च में बेंगलुरु और बाली के बीच सीधी उड़ानें भी शुरू हुईं, जिससे कनेक्टिविटी और बेहतर हुई।

मार्च में भारत और इंडोनेशिया के बीच तीन अनुबंध/एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए: (i) स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली (एलसीसीएस) पर 07 मार्च को समझौता ज्ञापन, (ii) इंटीग्रेटेड बियाक टेलीमेट्री, ट्रेकिंग एंड कमांड (टीटीसी) सुविधाओं के स्वामित्व के हस्तांतरण पर 19 मार्च को कार्यान्वयन समझौता, और (iii) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और राष्ट्रीय अनुसंधान और नवोन्मेष एजेंसी (बीआरआईएन) के बीच उपग्रहों और प्रक्षेपण वाहनों के लिए इंटीग्रेटेड बियाक टेलीमेट्री, ट्रेकिंग और कमांड (टीटीसी) सुविधाओं के संचालन, रखरखाव और उपयोग पर 19 मार्च को कार्यान्वयन व्यवस्था।

सेना-से-सेना स्टाफ 10^{वां} वार्ता मार्च में हुई, जबकि पांचवीं वायु सेना स्टाफ वार्ता 02-04 जुलाई को भारत में हुई। 12^{वां} नौसेना-से-नौसेना स्टाफ वार्ता 11 सितंबर को हुई। इंडोनेशिया ने भारत के मिलन-बहुपक्षीय नौसेना युद्धाभ्यास में भी भाग लिया, जो 19-27 फरवरी को विशाखापत्तनम में हुआ। भारतीय और इंडोनेशियाई नौसेनाओं के बीच भारत-इंडोनेशिया समन्वित गश्ती (इंड-इंडो कॉर्पेट) का 42^{वां} संस्करण 16-25 मई को आयोजित किया गया और सातवीं भारत-इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक 03 मई को नई दिल्ली में हुई।

लाओ पीडीआर

प्रधानमंत्री ने 21^{वां} आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 19^{वां} पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के लिए 10-11 अक्टूबर को वियनतियाने, लाओस का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने लाओ पीडीआर के प्रधानमंत्री सोनेक्स सिफांडोने के साथ द्विपक्षीय बैठक की और राष्ट्रपति थोंगलाउन सिसोउलिथ से भी मुलाकात की। दोनों प्रधानमंत्रियों ने रक्षा, प्रसारण, सीमा शुल्क सहयोग और मेकांग-गंगा सहयोग के तहत क्यूआईपी के तीन क्षेत्रों में एमओयू/अनुबंध-पत्रों का आदान-प्रदान किया। लाओस में पोषण सुरक्षा में सुधार के लिए लगभग 1 मिलियन अमरीकी डॉलर की अनुदान सहायता की भी घोषणा की गई।

रक्षा मंत्री ने 11^{वां} एडीएमएम प्लस के लिए 20-22 नवंबर को वियनतियाने का दौरा किया। यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री ने लाओस के उप प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय रक्षा मंत्री जनरल चांसमोन चान्यालथ के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। विदेश मंत्री ने आसियान-भारत विदेश मंत्रियों की बैठक और मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए 25-27 जुलाई को वियनतियाने का दौरा किया। विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री सोनेक्स सिफांडोने से शिष्टाचार भेंट की और उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री सेलेमक्स कोमासिथ के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों मंत्रियों ने एमजीसी के तहत लाओस के लिए 10 त्वरित प्रभाव परियोजनाओं (क्यूआईपी) पर समझौता ज्ञापनों के आदान-प्रदान और डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या स्तर पर कार्यान्वित सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के क्षेत्र में सहयोग के लिए हस्ताक्षर किए। भारत-लाओ पीडीआर साझा सांस्कृतिक धरोहरों का स्मरणोत्सव मनाते हुए दोनों मंत्रियों ने रामायण और बौद्ध धर्म की एक विशेष डाक टिकट का भी शुभारंभ किया।



विदेश मंत्री ने लाओस के वियनतियाने में आसियान-भारत विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया, जुलाई 2024.

वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने 20-21 सितंबर को लाओस में 21^{वीं} आसियान-भारत आर्थिक मंत्रियों (ईएएम-भारत) बैठक और 12^{वीं} पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन आर्थिक मंत्रियों की बैठक (ईएएस ईएमएम) में भाग लिया। वीओजीएसएस के तीसरे संस्करण में, लाओस के प्रधानमंत्री सोनेक्सई सिफानडोन ने उद्घाटन के लिए आए नेताओं के सत्र में भाग लिया। उप विदेश मंत्री थोंगफेन सावनफेट ने विदेश मंत्रियों के प्रथम सत्र में भाग लिया, जबकि उप स्वास्थ्य मंत्री सोंग थोंगसना ने स्वास्थ्य मंत्रियों के सत्र में भाग लिया। संसद सदस्य (राज्यसभा) के नेतृत्व में दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 19-22 अक्टूबर को आसियान-अंतर संसदीय सभा (एआईपीए) और संबंधित बैठकों में पर्यवेक्षक के रूप में भारतीय संसद का प्रतिनिधित्व करने के लिए लाओस का दौरा किया। सचिव (पूर्व) ने आसियान से संबंधित वरिष्ठ अधिकारी बैठकों (एसओएम) के लिए 06-09 जून और 21-23 अगस्त को लाओस का दौरा किया।

वट फो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पर एएसआई द्वारा किए गए कार्य को इस वर्ष 15 वर्ष पूरे हुए। वट फो के जीर्णोद्धार और संरक्षण कार्य पर एएसआई द्वारा प्रकाशित एक विशेष प्रकाशन 04 नवंबर को लाओस के गृह मंत्री विलायवोंग बौडुखम और शिक्षा एवं खेल संघ मंत्री फाउट सिम्मालावोंग द्वारा लॉन्च किया गया।

15 लाओ राजनयिकों ने 27 मार्च-5 अप्रैल को एसएसआईएफएस में एक विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लिया। 2024 में आईटीईसी योजना के तहत 25 लाओ अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया और 12 लाओ

छात्र आईसीसीआर छात्रवृत्ति योजना के तहत भारत में अध्ययन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, एक मीडिया प्रतिनिधिमंडल ने 01-03 जुलाई को लाओस का दौरा किया। लाओस के एक पत्रकार ने 18-27 अगस्त को मीडिया परिचय कार्यक्रम में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया।

टाइफून यागी के मद्देनजर, भारत ने ऑपरेशन सद्भाव के तहत लाओस और वियतनाम को आपातकालीन मानवीय सहायता प्रदान की। 10 टन की खेप प्रदान की गई।

मलेशिया

मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने 19-21 अगस्त को भारत का राजकीय दौरा किया और प्रधानमंत्री के साथ चर्चा की। इस यात्रा के दौरान, भारत-मलेशिया ने द्विपक्षीय संबंधों को 2015 में स्थापित की गई भागीदारी यानी एन्हांसड रूस्टैटिजिक पार्टनरशिप (सीएसपी) तक बढ़ाया। दोनों देशों के बीच 08 समझौता ज्ञापनों/अनुबंध-पत्रों का आदान-प्रदान किया गया। इनमें श्रमिकों की भर्ती, रोजगार और प्रत्यावर्तन, आयुर्वेद और अन्य पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों, डिजिटल प्रौद्योगिकियों, संस्कृति, कला और विरासत, पर्यटन, लोक प्रशासन और शासन सुधार, युवा मामले एवं खेल, और वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन शामिल हैं।

मलेशिया के प्रधानमंत्री की भारत में राजकीय यात्रा के दौरान की गई कुछ महत्वपूर्ण घोषणाओं में, मलेशिया को 200,000 मीट्रिक टन सफेद

चावल का विशेष आवंटन; मलेशियाई नागरिकों के लिए 100 अतिरिक्त आईटीईसी स्लॉट का आवंटन, संस्थापक सदस्य के रूप में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (आईबीसीए) में मलेशिया का शामिल होना, मलेशिया के टुंकू अब्दुल रहमान विश्वविद्यालय (यूटीएआर) में आयुर्वेद चैयर की स्थापना, मलेशिया के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय मलाया में भारतीय संस्कृति के अध्ययन से संबंधित तिरुवल्लुवर चैयर की स्थापना, भारत-मलेशिया स्टार्टअप अलायंस के तहत दोनों देशों में स्टार्ट-अप इकोसिस्टम के बीच सहयोग और मलेशिया इंडिया डिजिटल काउंसिल की स्थापना शामिल है। नौवां भारत-मलेशिया सीईओ फोरम 19 अगस्त को नई दिल्ली में यात्रा के दौरान आयोजित किया गया। टुंकू अब्दुल रहमान विश्वविद्यालय (यूटीएआर) में आयुर्वेद पीठ सितंबर में शुरु की गई।



प्रधानमंत्री ने मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम से हैदराबाद हाउस, नई दिल्ली में मुलाकात की, अगस्त 2024

27-28 मार्च को मलेशिया की अपनी यात्रा के दौरान, विदेश मंत्री ने मलेशिया के विदेश मंत्री गोबिंद सिंह देव, जो मलेशिया डिजिटल मंत्रालय के मंत्री भी हैं, के साथ द्विपक्षीय चर्चा की। विदेश मंत्री ने मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम से भी मुलाकात की। विदेश मंत्री ने 26 जुलाई को वियनतियाने, लाओ पीडीआर में आसियान-भारत विदेश मंत्रियों की बैठक और मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के इतर मलेशिया के विदेश मंत्री मोहम्मद हसन के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं और 23 अक्टूबर को रूस के कज़ान में 16^{वें} ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के इतर मलेशिया के अर्थव्यवस्था मंत्री रफीजी रामली के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं। विदेश राज्य मंत्री (केवीएस) ने भारतीय मूल नागरिक दिवस (पीआईओ) 'प्रवासी दिवस' समारोह के दूसरे संस्करण का उद्घाटन करने के लिए 13 से 15 सितंबर तक मलेशिया का दौरा किया और भारतीय मूल के लोगों के 15^{वें} वैश्विक संगठन (जीओपीआईओ) अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया।

मलेशियाई नौसेना के कावेंट केडी लेकर ने 19-24 फरवरी को विशाखापत्तनम में बहुआयामी नौसेना युद्धाभ्यास 'मिलन' में भाग लिया। युद्धाभ्यास के बाद, आईएनएस किल्टन और रॉयल मलेशियाई जहाज केडी लेकर ने 28 फरवरी-02 मार्च को द्विपक्षीय समुद्री युद्धाभ्यास 'समुद्र लक्ष्मण' में भाग लिया। आईएनएस दिल्ली और आईएनएस शक्ति ने

12-15 मई तक पूर्वी मलेशिया के कोटा किनाबालु बंदरगाह का दौरा किया। भारतीय नौसेना और रॉयल मलेशियाई नौसेना (आरएमएन) के बीच नौसेना-से-नौसेना नवीं स्टाफ वार्ता 22-25 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारतीय वायुसेना और रॉयल मलेशियाई वायु सेना (आरएमएएफ) के बीच द्विपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास 'उदार शक्ति' 04-10 अगस्त को मलेशिया के कुआंतन एयर बेस पर आयोजित किया गया। भारतीय वायुसेना और आरएमएएफ के बीच वायु सेना स्टाफ वार्ता 05-07 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारतीय सेना और मलेशियाई सेना के बीच द्विपक्षीय सैन्य युद्धाभ्यास 'हरिमाउ शक्ति' 02-15 दिसंबर को मलेशिया के बेटोंग में आयोजित किया गया।



मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की भारत की राजकीय यात्रा के दौरान हैदराबाद हाउस में भारत और मलेशिया के बीच समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान, अगस्त 2024

पारस्परिक वीजा उदारीकरण उपाय के रूप में, भारत ने 01 जुलाई से 30 जून 2025 तक या अगले आदेश तक मलेशियाई नागरिकों को सिंगल/डबल एंट्री के साथ 30 दिनों का ई-टूरिस्ट वीजा देने के लिए एक निःशुल्क वीजा व्यवस्था लागू की।

न्यूजीलैंड

भारत-न्यूजीलैंड संबंध घनिष्ठ द्विपक्षीय सहयोग, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और लोगों के बीच आपसी संपर्क पर आधारित हैं। इस वर्ष, द्विपक्षीय संबंधों में तेजी आई, जिसमें कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम शामिल हैं, जिसके फलस्वरूप संबंधों को और गति प्राप्त हुई।

माननीय राष्ट्रपति जी ने 07-09 अगस्त को न्यूजीलैंड की राजकीय यात्रा की। सीमा शुल्क सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और न्यूजीलैंड इसके अनुसमर्थन के बाद अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो गया। माननीय राष्ट्रपति जी ने न्यूजीलैंड अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में भाषण दिया, जहां भारत "सम्मानित देश" अर्थात कंट्री ऑफ ऑनर की भूमिका में था, और उन्होंने ऑकलैंड में एक सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय प्रवासियों से मुलाकात की।



माननीय राष्ट्रपति जी ने वेलिंगटन में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ चर्चा की, अगस्त 2024.

अक्टूबर में, प्रधानमंत्री ने लाओ पीडीआर के वियनतियाने में आसियान-भारत शिखर सम्मेलन के इतर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने नवंबर में कैनबरा में 'रायसीना डाउन अंडर' वार्ता के दौरान न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री विंस्टन पीटर्स, जो विदेश मंत्री भी हैं, के साथ बैठक की। न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स ने भी इससे पहले 10-13 मार्च को भारत का दौरा किया था।



प्रधानमंत्री ने वियनतियाने में 21^{वें} आसियान-भारत शिखर सम्मेलन के इतर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से मुलाकात की, अक्टूबर 2024.

व्यापार और आर्थिक मोर्चे पर, पीछे अप्रैल में दोनों पक्षों के बीच वेलिंगटन में वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर संयुक्त व्यापार समिति की बैठक हुई थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने जुलाई में नई दिल्ली में न्यूजीलैंड के व्यापार और कृषि मंत्री टॉड मैक्ले से मुलाकात की और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय

व्यापार एवं आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।

रॉयल न्यूजीलैंड नौसेना के प्रमुख रियर एडमिरल डेविड प्रॉक्टर ने फरवरी में भारत का दौरा किया और भारत के नौसेना प्रमुख के साथ चर्चा की।

प्रशांत द्वीपीय देश (पीआईसी)

भारत का प्रशांत द्वीपीय देशों (पीआईसी) के साथ एक्ट ईस्ट नीति के तहत मजबूत ऐतिहासिक संबंध है, इसलिए भारत-प्रशांत क्षेत्र में बातचीत को प्राथमिकता दी जाती है।

भारत सरकार ने कई उच्च-स्तरीय यात्राओं और ऐतिहासिक पहल - भारत-प्रशांत द्वीप सहयोग मंच (एफआईपीआईसी) के तहत इस क्षेत्र के देशों के साथ संपर्क बढ़ाने में अपने प्रयासों को आगे बढ़ाया है। माननीय राष्ट्रपति जी ने अगस्त में फिजी के तत्कालीन राष्ट्रपति रतु विलियम मैवालिली काटोनिवरे के निमंत्रण पर फिजी की आधिकारिक यात्रा की। यह भारत के किसी राष्ट्राध्यक्ष की फिजी की पहली यात्रा थी। फिजी के उप प्रधानमंत्री मनोआ कामिकामिका ने 25-27 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (आईसीए) महासभा और वैश्विक सम्मेलन में भाग लिया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने दिल्ली में किया। उन्होंने विदेश मंत्री से भी मुलाकात की और गुजरात में गिफ्ट सिटी और अमूल का दौरा किया। फिजी नवंबर में ग्लोबल बायोफ्यूल्स एलायंस में 28^{वें} सदस्य के रूप में शामिल हुआ।

वर्ष 2002 से, भारत प्रशांत द्वीप मंच (पीआईएफ), जो कि प्रशांत क्षेत्र में शीर्ष क्षेत्रीय तंत्र है, का संवाद भागीदार अर्थात डायलॉग पार्टनर रहा है। भारत ने पहली बार मंत्री स्तर पर पीआईएफ में भाग लिया, जब अगस्त में टोंगा में 53^{वें} पीआईएफ नेताओं की बैठक में राज्य मंत्री (पीएम) शामिल हुए। इस यात्रा के दौरान, भारत ने 14 प्रशांत द्वीप देशों में से प्रत्येक में उनकी संबंधित आवश्यकताओं के आधार पर 50,000 अमेरिकी डॉलर मूल्य की एक त्वरित प्रभाव परियोजना (क्यूआईपी) की घोषणा की।

विकास सहयोग

भारत की पीआईसी के साथ निरंतर भागीदारी का एक बड़ा हिस्सा दक्षिण-दक्षिण सहयोग के तहत विकास सहायता के रूप में है, जिसे मुख्य रूप से आईटीईसी, आईसीसीआर छात्रवृत्ति और अनुदान सहायता परियोजनाओं के तहत सिविल और डिफेंस प्रशिक्षण के साथ क्षमता निर्माण के माध्यम से प्रदान किया जाता है। भारत समुदाय-उन्मुख परियोजनाओं के माध्यम से पीआईसी को उनके सामाजिक-आर्थिक विकास में सहायता करता है जिसके लिए भारत ने रोल-ओवर सुविधा के साथ प्रत्येक पीआईसी को 200,000 अमेरिकी डॉलर के साथ 2.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वार्षिक अनुदान सहायता प्रदान की। ये परियोजनाएँ सामुदायिक विकास, सौर विद्युतीकरण, कृषि उपकरणों की खरीद और आपूर्ति, कंप्यूटर, स्कूलों के लिए एलईडी बल्ब, सिलाई मशीन, डायलिसिस मशीन, पोर्टेबल आरा मिल, नाव और पिक-अप ट्रक, समुद्री दीवार का निर्माण और कोरल (प्रवाल) फार्म जैसे विविध क्षेत्रों में चल रही हैं। भारत सरकार ने जून में 10^{वें} माइक्रोनेशियन



माननीय राष्ट्रपति जी सुवा में स्टेट हाउस में फिजी के राष्ट्रपति रतु विलियम मैवालिली काटोनिवरे के साथ, अगस्त 2024.

खेलों और जुलाई में प्रशांत महिलाओं के 15^{वें} त्रिवार्षिक सम्मेलन की मेजबानी में विकास भागीदार के रूप में मार्शल द्वीप गणराज्य का समर्थन किया और इस प्रयोजनार्थ अनुदान सहायता के रूप में 200,000 अमरीकी डालर दिए। भारत अनुदान सहायता परियोजना के तहत पलाऊ को 12 जल भंडारण टैंकों की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग की प्रक्रिया में भी है।

मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (एचएडीआर) और जलवायु परिवर्तन का शमन

भारत अग्रेसरी सहायताकर्ता के रूप में, पीआईसी को मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) प्रदान कर रहा है। मई में पापुआ न्यू गिनी के एंगा प्रांत में हुए बड़े पैमाने पर भूस्खलन के बाद, भारत ने पापुआ न्यू गिनी के लोगों के साथ एकजुटता दिखाते हुए राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण प्रयासों में समर्थन देने के लिए 1 मिलियन अमरीकी डॉलर की तत्काल राहत सहायता प्रदान की। 17 दिसंबर को दक्षिण प्रशांत महासागर में वानुअतु के तट के पास 7.4 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे भारी तबाही हुई और जानमाल का नुकसान हुआ। वानुअतु के लोगों के साथ एकजुटता दिखाते हुए, भारत ने राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण प्रयासों का समर्थन करने के लिए 500,000 अमरीकी डॉलर की राहत सहायता प्रदान की।

सभी पीआईसी जलवायु परिवर्तन और बढ़ते समुद्री जलस्तर के प्रभावों से प्रवण व संवेदनशील हैं। उन्हें पर्यावरण, सतत विकास, शमन और अनुकूलन संबंधी मुद्दों से संबंधित चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) और आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (सीडीआरआई) जैसी पहलें पीआईसी के साथ हमारी विकास भागीदारी को संपूरित करती हैं।

स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग: द्विपक्षीय अनुदानों के माध्यम से पीआईसी को नियमित रूप से दवाइयाँ और चिकित्सा आपूर्तियाँ दान की जाती हैं। अप्रैल में फिजी को आवश्यक एकीकृत बाल रोग प्रबंधन (आईएमसीआई) कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए दवा और इंजेक्शन सहित चिकित्सा आपूर्ति की एक खेप सौंपी गई थी। एंटी रेट्रो-वायरल दवाएँ और विशेष दवाएँ नियमित रूप से फिजी और अन्य पीआईसी को आपूर्ति की जाती हैं।

सोलोमन द्वीप और नाउरू के साथ भारतीय फार्माकोपिया की मान्यता पर क्रमशः अगस्त और सितंबर में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। पीआईसी में पहला जन औषधि केंद्र नाउरू में स्थापित किया जा रहा है।



विदेश राज्य मंत्री (पीएम) ने भारत द्वारा वित्तपोषित सोलराइजेशन ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट प्रोजेक्ट को मौसम विज्ञान, ऊर्जा, सूचना, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और संचार मंत्री फेकिटामोएलोआउतोइकमानु, टोंगा के साथ टोंगन नेशनल काउंसिल फॉर वूमैन में संयुक्त रूप से शुरु किया।

भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास भागीदारी निधि: द्विपक्षीय संवादों के अलावा, 2017 में भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास भागीदारी निधि (यूएनडीपी) बनाई गई। इसका उद्देश्य विकासशील देशों में मांग-चालित सतत विकास परियोजनाओं का समर्थन करना है, जो मुख्य रूप से एलडीसी और एसआईडीएस पर केंद्रित है। पीआईसी इस निधि के लाभार्थी रहे हैं। इस निधि के माध्यम से भारत द्वारा कोविड-19 के मद्देनजर चिकित्सा उपकरणों और आपूर्ति की खरीद के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को मजबूत करने के लिए सोलोमन द्वीप, नाउरू, पापुआ न्यू गिनी, किरिबाती, टोंगा, तुवालु और पलाऊ को सहायता प्रदान की गई। भारत-यूएनडीपी निधि के तहत, भारत सरकार ने सोलोमन द्वीप के होनियारा में सरकारी आवास के लिए एक सौरकरण परियोजना शुरू की, जो अगस्त में 1 मिलियन अमरीकी डालर की लागत से पूरी हुई। इस परियोजना को भारत-यूएनडीपी निधि के तहत शुरू किया गया था। इसके अतिरिक्त, टोंगा राज्य की यात्रा के दौरान नुकूआलोफा में राष्ट्रीय महिला परिषद के परिसर में एक सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की गई। अगस्त में 53^{वें} प्रशांत द्वीप फोरम (पीआईएफ) नेताओं की बैठक के लिए विदेश राज्य मंत्री (पीएम) टोंगा गए। यह परियोजना भारत-यूएनडीपी फंड के तहत शुरू की गई थी।



एंगा प्रांत में भूस्खलन के मद्देनजर भारत की तत्काल राहत सहायता देने की घोषणा के बाद पोर्ट मोरेस्बी हवाई अड्डे पर पहुंची एचएडीआर राहत सहायता, जून 2024.

दोनों पक्षों के नागरिकों के बीच संबंध और सांस्कृतिक संबंध: भारत के प्रशांत द्वीप देशों के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध हैं, जो सांस्कृतिक आदान-प्रदान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के आलोक में हैं। भारत के साथ मजबूत सांस्कृतिक संबंधों वाला फिजी प्रवासी भारतीय समुदाय का एक प्रमुख देश है, जिसकी कुल आबादी का लगभग 33 प्रतिशत भारतीय मूल का है। चार प्रशांत द्वीप देशों, अर्थात् फिजी, पापुआ न्यू गिनी, नाउरू और सोलोमन द्वीप के नई दिल्ली में अपने निवासीय मिशन हैं। भारत के फिजी और पापुआ न्यू गिनी में अपने निवासीय मिशन हैं, जबकि शेष पीआईसी क्रमशः कैनबरा, वेलिंगटन, टोक्यो और मनीला में भारत के मिशनों द्वारा समवर्ती प्रत्यायन के माध्यम से कवर किए गए हैं।

भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित तमिल भाषा शिक्षण कार्यक्रम आधिकारिक तौर पर 27 नवंबर को फिजी के राकिराकी में पेनांग संगम स्कूल में शुरू किया गया। राकिराकी में पेनांग संगम स्कूल और लाबासा में संगम प्राथमिक विद्यालय में स्कूली छात्रों और इच्छुक समुदाय के सदस्यों के लिए तमिल कक्षाएं संचालित करने के लिए भारत के दो तमिल शिक्षकों को तैनात किया जाएगा।

वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के तीसरे संस्करण में पीआईसी की उच्च भागीदारी थी। मार्शल द्वीप गणराज्य की राष्ट्रपति हिल्डा सी. हेन और पापुआ न्यू गिनी के विदेश मंत्री जस्टिन तकाचेको, नाउरू के विदेश मंत्री लियोनेल रुवेन एंगिमिया और सोलोमन द्वीप के विदेश मंत्री पीटर शानेल अगोवाका ने शिखर सम्मेलन में भाग लिया।

फिलीपींस

प्रधानमंत्री और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने 10 अक्टूबर को लाओस के वियनतियाने में आयोजित 21^{वां} आसियान-भारत शिखर सम्मेलन के दौरान संक्षिप्त बातचीत की। नवंबर में दोनों देशों ने राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे किए। 75^{वां} वर्षगांठ समारोह के लिए

संयुक्त आधिकारिक लोगो (LOGO) 13 नवंबर को नई दिल्ली में विदेश मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया।

रक्षा मंत्री ने 22 नवंबर को लाओस के वियनतियाने में 18^{वां} आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक (एडीएमएम) और 11^{वां} एडीएमएम प्लस के इतर राष्ट्रीय रक्षा सचिव गिल्बर्ट टेओडोरो से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने 25-27 मार्च को फिलीपींस का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर. मार्कोस जूनियर से मुलाकात की और विदेश मामलों के सचिव एनरिक ए. मनालो तथा राष्ट्रीय रक्षा सचिव गिल्बर्ट टेओडोरो से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने 20 जनवरी को कंपाला में एनएएम शिखर सम्मेलन के इतर और पुनः 25 जुलाई को विएंटियाने में आसियान-भारत विदेश मंत्रियों की बैठक के इतर सचिव मनालो से भी मुलाकात की।

स्वास्थ्य विभाग के सचिव टेओडोरो हर्बोसा ने 17 अगस्त को एक वीडियो संदेश के माध्यम से वीओजीएसएस के तीसरे संस्करण के स्वास्थ्य मंत्री के सल को संबोधित किया। फिलीपींस के परिवहन विभाग के सचिव जैमे जे. बॉतिस्ता 11-12 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित नागरिक उड्डयन पर दूसरे एशिया-प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (एपीएसी-एमसी) में भाग लेने के लिए भारत आए। राज्य मंत्री (गृह) के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 14-17 अक्टूबर को आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण (एपीएमसीडीआरआर) पर एशिया-प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए फिलीपींस का दौरा किया।

14^{वां} भारत-फिलीपींस नीति परामर्श और पांचवीं रणनीतिक वार्ता 09 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित की गई। पांचवीं संयुक्त रक्षा सहयोग समिति (जेडीसीसी) और तीसरी सर्विस टू सर्विस बातचीत 11-13 सितंबर को मनीला में आयोजित की गई। फिनटेक पर पहली जेडब्ल्यूजी बैठक नई दिल्ली में 12 सितंबर को आयोजित की गई। पर्यटन पर दूसरी जेडब्ल्यूजी बैठक मनीला में 21 मई को हुई। चौथी संयुक्त कांसुलर परामर्श बैठक (जेसीसीएम) 13 अप्रैल को मनीला में आयोजित की गई। भारतीय नौसेना और फिलीपींस तटरक्षक बल के बीच 23 अगस्त 2023 को हस्ताक्षरित

व्हाइट शिपिंग इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज पर एसओपी 09 अगस्त को प्रभाव में आई।

आईएनएस दिल्ली, आईएनएस शक्ति और आईएनएस किल्टन ने ऑपरेशनल टर्न अराउंड (ओटीआर) के लिए 19-22 मई को मनीला में बंदरगाहों ठहराव किया। फिलीपीनी नौसेना के 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 19-23 फरवरी को विशाखापत्तनम में पर्यवेक्षक के रूप में मिलन-24 युद्धाभ्यास में भाग लिया।

दोनों देशों ने कृषि, आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवा और आजीविका सहायता के क्षेत्रों में त्वरित प्रभाव परियोजनाओं पर 15 जुलाई को 06 व्यक्तिगत समझौता ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए।

वर्ष 2024 में भारत में आयोजित आईटीईसी पाठ्यक्रमों में सिविलियन पक्ष से कुल 08 सरकारी अधिकारी तथा फिलीपींस सशस्त्र बलों से 23 अधिकारी शामिल हुए। फिलीपींस सरकार ने 28 अक्टूबर को भारत से फिलीपींस आने वाले यात्रियों के लिए ई-वीजा सुविधा शुरू की। ई-वीजा का बीटा संस्करण 5 अप्रैल को नई दिल्ली में फिलीपींस दूतावास द्वारा लॉन्च किया गया।

अंत में, फिलीपींस वर्ष 2025-2028 की अवधि के लिए भारत-आसियान संबंधों के लिए समन्वयक देश बना।

सिंगापुर

प्रधानमंत्री ने 04-05 सितंबर को सिंगापुर का दौरा किया। यह प्रधानमंत्री की सिंगापुर की पांचवीं यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान भारत-सिंगापुर संबंधों को व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक बढ़ाया गया तथा सेमीकंडक्टर



प्रधानमंत्री और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली हसैन लोंग ने सिंगापुर में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की अग्रणी सिंगापुरी कंपनी एईएम होल्डिंग्स लिमिटेड का दौरा किया, सितंबर 2024.

पारिस्थितिकी तंत्र, डिजिटल प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास के क्षेत्रों में सहयोग पर 04 समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान किया गया। 22 सितंबर को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने सिंगापुर में इन्वेस्ट इंडिया कार्यालय का उद्घाटन किया, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने निवेश को सुगम बनाने के लिए की थी। प्रधानमंत्री ने यह भी घोषणा की कि सिंगापुर में तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की जाएगी। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय साइबर नीति



विदेश मंत्री, वित्त एवं कॉर्पोरेट मामले मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री तथा रेल, सूचना एवं प्रसारण, और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री सिंगापुर में द्वितीय भारत-सिंगापुर मंत्रिस्तरीय राउंडटेबल सम्मेलन में भाग लेते हुए, अगस्त 2024



भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं ने विशाखापत्तनम में आयोजित सिंगापुर-भारत समुद्री द्विपक्षीय युद्धाभ्यास (सिम्बेक्स) में भाग लिया, अक्टूबर 2024.

वार्ता शुरू करने पर भी सहमति जताई, जिसका पहला दौर 17 अक्टूबर को सिंगापुर में आयोजित किया गया। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम भागीदारी पर समझौता ज्ञापन के तत्वावधान में, पहली भारत-सिंगापुर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम नीति वार्ता 05 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित की गई।

प्रधानमंत्री और सिंगापुर के प्रधानमंत्री वोंग ने नवंबर में जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान संक्षिप्त बातचीत की।

रक्षा मंत्री और रक्षा मंत्री एनजी इंग हेन ने 22 अक्टूबर को नई दिल्ली में छठी भारत-सिंगापुर रक्षा मंत्रिस्तरीय वार्ता की सह-अध्यक्षता की। दोनों पक्षों ने अगले पांच वर्षों के लिए संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण पर द्विपक्षीय समझौते को बढ़ाने पर सहमति जताई।

भारत-सिंगापुर मंत्रिस्तरीय राउंडटेबल सम्मेलन (आईएसएमआर) का दूसरा दौर 26 अगस्त को सिंगापुर में आयोजित किया गया। विदेश मंत्री, वित्त एवं कॉर्पोरेट मामले मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री तथा रेल, सूचना एवं प्रसारण, और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राउंडटेबल सम्मेलन के लिए सिंगापुर गए। सिंगापुर की ओर से उप प्रधानमंत्री एवं व्यापार एवं उद्योग मंत्री गन किम योंग, विदेश मंत्री विवियन बालकृष्णन, गृह मंत्री एवं विधि मंत्री शनमुगम, डिजिटल विकास एवं सूचना मंत्री एवं गृह मामले द्वितीय मंत्री जोसेफिन टेओ, जनशक्ति मंत्री तथा व्यापार एवं उद्योग द्वितीय मंत्री तान सी लेंग, और परिवहन मंत्री एवं वित्त द्वितीय मंत्री ची होंग टैट ने बैठक में भाग लिया। विदेश मंत्री ने 23-25 मार्च और 08-09 नवंबर को सिंगापुर का दौरा किया।

भारत की ओर से अन्य उच्च स्तरीय यात्राओं में शिक्षा मंत्री (20-21 अक्टूबर) और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी राज्य मंत्री (15-17 अक्टूबर) शामिल हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने 17-20 नवंबर तक सिंगापुर का दौरा किया।

परिवहन मंत्री और वित्त मंत्री ची होंग टैट (12-13 सितंबर), गृह मंत्री के. शानमुगम और जनशक्ति मंत्री तथा व्यापार एवं उद्योग मंत्री तान सी लेंग (07-09 नवंबर), डिजिटल विकास एवं सूचना मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ राज्य मंत्री जनिल पुथुचेरी और प्रधानमंत्री कार्यालय में वरिष्ठ राज्य मंत्री डेसमंड तान (17-21 नवंबर) ने इस वर्ष भारत का दौरा किया।

इसके अतिरिक्त, भारत ने सिंगापुर के साथ कई द्विपक्षीय सैन्य युद्धाभ्यासों की मेजबानी की, जैसे किअग्नि योद्धा (25 अक्टूबर - 11 दिसंबर), SIMBEX (24-29 अक्टूबर) और संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण (04 अक्टूबर- 16 दिसंबर)। चौथा सिंगापुर-भारत-थाईलैंड समुद्री युद्धाभ्यास (SITMEX) भी 08-11 नवंबर को भारत में आयोजित किया गया। सिंगापुर वायु सेना ने युद्धाभ्यास तरंग शक्ति के उद्घाटन संस्करण में भाग लिया।

थाईलैंड

प्रधानमंत्री ने वियनतियाने में 11 अक्टूबर को आसियान संबंधित शिखर सम्मेलन के इतर थाईलैंड की प्रधानमंत्री पैतोंगटार्न शिनावाला से मुलाकात की। इससे पहले, प्रधानमंत्री ने 06 जून को थाईलैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीथा थाविसिन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की थी।



प्रधानमंत्री ने वियनतियाने में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के इतर थाईलैंड की प्रधानमंत्री पैतोंगटार्न शिनावाला से मुलाकात की, अक्टूबर 2024.

थाईलैंड के विदेश मंत्री मैरिस सांगियाम्मोंगसा ने 02 नवंबर को नई दिल्ली में विदेश मंत्री से मुलाकात की। इससे पहले, थाईलैंड के विदेश मंत्री मैरिस सांगियाम्मोंगसा ने विदेश मंत्री द्वारा आयोजित बिम्सटेक विदेश मंत्रियों के दूसरे रिट्रीट में भाग लेने और 11-13 जुलाई को आधिकारिक द्विपक्षीय यात्रा के लिए नई दिल्ली का दौरा किया। थाईलैंड के तत्कालीन उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री परनप्रीबहिद्धा-नुकारा ने 26-28 फरवरी को नई दिल्ली में विदेश मंत्री के साथ 10^{वीं} भारत-थाईलैंड संयुक्त आयोग की बैठक की सह-अध्यक्षता करने हेतु भारत का दौरा किया।

थाईलैंड सरकार के अनुरोध पर, भारत ने भगवान बुद्ध के दो मुख्य शिष्यों सहित उनके (बुद्ध) पवित्र अवशेषों को 22 फरवरी-19 मार्च को सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए भेजा। पवित्र अवशेषों को थाईलैंड के चार शहरों में स्थापित किया गया, जहां थाईलैंड के विभिन्न भागों तथा अन्य स्थानों से 4.1 मिलियन से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र अवशेषों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

भारत ने 06 फरवरी-06 मार्च को थाईलैंड में आयोजित कोबरा गोल्ड समुद्री युद्धाभ्यास के 43^{वां} संस्करण में भागीदार देश के रूप में भाग लिया। थाईलैंड के टाक प्रांत में दोनों देशों की सेनाओं के बीच एक्स-मैत्री का 13^{वां} संस्करण 01-15 जुलाई को आयोजित किया गया। रॉयल थाई नौसेना के कमांडर-इन-चीफ एडमिरल अडुंग पैन-डूम ने 01-03 अप्रैल को भारत की आधिकारिक यात्रा की तथा भारत के वायु सेना प्रमुख ने 18-23 अगस्त को थाईलैंड का दौरा किया।

अंत में, पारस्परिक वीजा उदारीकरण उपाय के रूप में, भारत ने 01 जुलाई से 31 दिसंबर तक या अगले आदेश तक थाई नागरिकों को एकल/दोहरे प्रवेश के साथ 30 दिनों का ई-पर्यटक वीजा प्रदान करने के लिए एक निःशुल्क वीजा व्यवस्था लागू की। भारत और थाईलैंड ने 15 मार्च को बैंकॉक में वायु सेवाओं पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

तिमोर लेस्ते

तिमोर-लेस्ते के राष्ट्रपति जोस रामोस-होर्ता ने जनवरी में 10^{वां} वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री से मुलाकात की। तिमोर-लेस्ते के प्रधानमंत्री के राला ज़नाना गुस्माओ ने वर्चुअल मोड में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस के तीसरे संस्करण के नेताओं के उद्घाटन सत्र में वर्चुअल रूप से भाग लिया।

माननीय राष्ट्रपति जी ने 10 अगस्त को तिमोर-लेस्ते का दौरा किया जो किसी भारतीय राष्ट्रध्यक्ष की पहली यात्रा थी। अपनी यात्रा के दौरान, माननीय राष्ट्रपति जी ने राष्ट्रपति जोस रामोस-होर्ता और प्रधानमंत्री के राला ज़नाना गुस्माओ से मुलाकात की। राष्ट्रपति होर्ता ने माननीय राष्ट्रपति जी को तिमोर-लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'ग्रैंड-कॉलर ऑफ़ द ऑर्डर ऑफ़ तिमोर-लेस्ते' से सम्मानित किया। यात्रा के दौरान, भारत और तिमोर-लेस्ते ने सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम, प्रसार भारती और तिमोर-लेस्ते रेडियो एवं टेलीविजन के बीच सहयोग और राजनयिक, आधिकारिक एवं सेवा पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा आवश्यकता से छूट पर केंद्रित 03 समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान किया।



प्रधानमंत्री ने तिमोर-लेस्ते के राष्ट्रपति जोस रामोस-होर्ता से गांधीनगर में मुलाकात की, जनवरी 2024

05 सितंबर को, दिल्ली, तिमोर-लेस्ते में एक भारतीय दूतावास चालू किया गया। इसके बाद, तिमोर-लेस्ते ने अक्टूबर में नई दिल्ली में अपना रेजिडेंट मिशन भी स्थापित किया।

वियतनाम

वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चीन्ह ने 30 जुलाई से 01 अगस्त तक भारत का राजकीय दौरा किया। उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ चर्चा की, जहां दोनों नेताओं ने 2024-2028 की अवधि के लिए भारत-वियतनाम व्यापक रणनीतिक भागीदारी के कार्यान्वयन के लिए कार्ययोजना पर सहमति व्यक्त की। देशों ने 08 द्विपक्षीय दस्तावेजों का आदान-प्रदान किया, जिसमें सीमा शुल्क क्षमता, कृषि अनुसंधान और शिक्षा, विधिक क्षेत्र, रेडियो और टेलीविजन, औषधीय पौधे, गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर का विकास, वियतनाम के माई सन में एफ ब्लॉक का संरक्षण और जीर्णोद्धार, एक राजनयिक मिशन या कांसुलर पद के सदस्यों के आश्रितों को लाभकारी रोजगार में नियोजित करने के लिए अधिकृत

करने वाला समझौता और 300 मिलियन अमरीकी डालर की रक्षा खरीद के लिए दो डॉलर क्रेडिट लाइन समझौते शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, दोनों प्रधानमंत्रियों ने न्हा ट्रांग के दूरसंचार विश्वविद्यालय में आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क का वर्चुअल मोड में उद्घाटन किया। यह सुविधा भारत द्वारा 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान से स्थापित की गई थी। वियतनाम ने कोआलेशन फॉर डिस्टास्टर रेजिलिएंट इन्फ्रास्ट्रक्चर (सीडीआरआई) में शामिल होने के लिए 01 अगस्त को अपने निर्णय की जानकारी दी।



प्रधानमंत्री की वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चीन्ह से मुलाकात, नई दिल्ली, अगस्त 2024.

प्रधानमंत्री और वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव टो लैम ने भविष्य के शिखर सम्मेलन के इतर न्यूयॉर्क में सितंबर में द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री और वियतनाम के प्रधानमंत्री ने अक्टूबर में आसियान से संबंधित शिखर सम्मेलन के दौरान वियनतियाने में अनौपचारिक रूप से बातचीत की। प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चीन्ह ने वीओजीएसएस के तीसरे संस्करण के नेताओं के उद्घाटन सत्र में वर्चुअल रूप से भाग लिया और उसे संबोधित किया, जबकि वियतनाम के उद्योग और व्यापार उप मंत्री फान थी थांग ने वीओजीएसएस के तीसरे संस्करण के वाणिज्य मंत्रियों के सत्र को संबोधित किया।

विदेश मंत्री ने 23 अप्रैल को हनोई में “जन-केंद्रित आसियान समुदाय के लिए व्यापक सुरक्षा सुनिश्चित करना” शीर्षक पर आसियान फ्यूचर फोरम (एटीएफ) सत्र में वर्चुअल रूप से भाषण दिया।

वियतनाम के उप प्रधानमंत्री ट्रान लू क्वांग ने 10-12 जनवरी को गांधीनगर में आयोजित 10^{वां} वाइब्रेट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन में भाग लिया।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने 24-25 जुलाई को हनोई में वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व महासचिव गुयेन फु ट्रोंग के राजकीय अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए वियतनाम का दौरा किया।

रक्षा के क्षेत्र में, सचिव (रक्षा) और वियतनाम के उप रक्षा मंत्री की सह-अध्यक्षता में 14^{वां} वार्षिक रक्षा नीति वार्ता 01 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित की गई। इसके अतिरिक्त, नौसेना-से-नौसेना छठी वार्ता 19-21 नवंबर को नई दिल्ली में, भारतीय और वियतनाम तटरक्षकों के बीच पांचवीं उच्च स्तरीय बैठक 22 फरवरी को नई दिल्ली में और हाइड्रोग्राफिक सहयोग पर पहली संयुक्त कार्यसमूह बैठक 07-09 मई को वियतनाम के हा लॉन्ग बे में आयोजित की गई। पांचवां वियतनाम-भारत द्विपक्षीय सैन्य युद्धाभ्यास- 04-23 नवंबर को भारत में आयोजित किया गया और वियतनाम पीपुल्स नेवी फ्रिगेट ने फरवरी में विशाखापत्तनम में 12^{वां} बहुपक्षीय नौसेना युद्धाभ्यास मिलन में भाग लिया। आईएनएस किल्टन ने 12-15 मई को पासेक्स युद्धाभ्यास के साथ कैम रान्ह खाड़ी में एक बंदरगाह पर ठहराव लिया, जबकि तटरक्षक जहाज समुद्र पहरदार ने 02-05 अप्रैल को हो ची मिन्ह सिटी बंदरगाह का दौरा किया। चौथा भारत-वियतनाम समुद्री सुरक्षा संवाद 16 अगस्त को हनोई में आयोजित किया गया।



प्रधानमंत्री ने न्यूयॉर्क में आयोजित यूएनजीए में भविष्य के शिखर सम्मेलन के दौरान कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव और वियतनाम के समाजवादी गणराज्य के राज्य अध्यक्ष टो लैम से मुलाकात की, सितंबर 2024.

2024 में, 61 वियतनामी छात्र भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) छात्रवृत्ति योजना के तहत भारत में स्नातकपूर्व, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट कार्यक्रमों में शामिल हुए। 100 से अधिक वियतनामी अधिकारियों और विशेषज्ञों ने आईटीईसी और अन्य कार्यक्रमों के तहत भारत में अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भाग लिया। सामुदायिक घरों,

पाठशालाओं और जलापूर्ति संरचना निर्माण जैसे क्षेत्रों में एमसीजी के तहत 09 त्वरित प्रभाव परियोजनाएं (क्यूआईप) क्रियान्वित की गईं।

वियतनाम के लिए 35 टन मानवीय सहायता की खेप भेजी गई। एयर इंडिया ने 01 जून से नई दिल्ली और हो ची मिन्ह सिटी के बीच दैनिक उड़ानें शुरू कीं, जिससे दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानों की संख्या बढ़ गई है।

अध्याय

4

पूर्वी एशिया

चीन

जून 2020 से, भारत और चीन ने भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र (डब्ल्यूएमसीसी) की 18 बैठकें और वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर पर 21 दौर की बैठकें की हैं। पूरे वर्ष में, मार्च और अगस्त में बीजिंग में और जुलाई और दिसंबर में नई दिल्ली में डब्ल्यूएमसीसी की चार दौर की बैठकें आयोजित की गईं। भारत-चीन कोर कमांडर स्तर की बैठक का 21^{वां} दौर फरवरी में आयोजित किया गया। कूटनीतिक और सैन्य दोनों स्तरों पर बातचीत और चर्चा के बाद, दोनों देश अक्टूबर में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के बारे में गंभीर व्यवस्था पर एक समझौते पर सहमत हुए, जिससे 2020 में इन क्षेत्रों में उत्पन्न मुद्दों का समाधान हुआ।

इसके बाद, प्रधानमंत्री ने 23 अक्टूबर को 16^{वें} ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के इतर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। यह लगभग पांच वर्षों में प्रतिनिधिमंडल स्तर पर उनकी पहली द्विपक्षीय बैठक थी। बैठक में प्रधानमंत्री ने सीमा संबंधी मामलों पर मतभेदों को रोकने की बात पर बल दिया ताकि सीमा पर शांति और स्थिरता बनी रहे। इस संदर्भ में, दोनों नेताओं ने सीमा के प्रश्न के समाधान और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने में भारत-चीन सीमा प्रश्न पर विशेष प्रतिनिधि कार्यतंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया। दोनों नेताओं ने यह भी इस बात पर भी बल दिया कि विदेश मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के स्तर पर संबद्ध संवाद तंत्र का उपयोग द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर और पुनर्निर्माण करने के लिए भी किया जाएगा।



प्रधानमंत्री ने रूस के कज़ान में 16^{वें} ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के इतर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की, अक्टूबर 2024.

विदेश मंत्री ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से तीन मौकों पर मुलाकात की - 4 जुलाई को अस्ताना में एससीओ राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की बैठक के इतर, 25 जुलाई को वियनतियाने में आसियान से संबंधित विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान और 18 नवंबर को रियो डी जेनेरियो में जी20 शिखर सम्मेलन के इतर। 18 नवंबर को हुई बैठक में दोनों पक्षों ने भारत-चीन संबंधों के अगले कदमों पर चर्चा की, जिसमें कैलाश मानसरोवर यात्रा को बहाल करना, सीमा पार नदियों पर डेटा साझा करना, भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानें और मीडिया का आदान-प्रदान जैसे मुद्दे शामिल थे। रक्षा मंत्री ने 20 नवंबर को लाओ पीडीआर के वियनतियाने में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस (एडीएमएम-प्लस) के इतर चीन के रक्षा मंत्री डोंग जून के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की।

भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच 23^{वीं} बैठक 18 दिसंबर को बीजिंग में हुई। भारत ब्रिक्स, एससीओ, जी-20 और संयुक्त राष्ट्र सहित बहुपक्षीय मंचों पर चीन के साथ बातचीत करता रहता है।

डीपीआरके

दिसंबर 1973 में राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद, भारत और डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण रहे हैं। भारत संवाद और कूटनीति के माध्यम से कोरियाई प्रायद्वीप में शांति और स्थिरता लाने के प्रयासों का लगातार समर्थन करता रहा है।

जापान

वर्ष 2024 में भारत-जापान विशेष सामरिक और वैश्विक भागीदारी की 10^{वीं} वर्षगांठ मनाई जाएगी। भारत और जापान ने इस वर्ष उच्च स्तरीय यात्राओं, प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे और व्यापार सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोगात्मक पहलों के तथा संयुक्त राष्ट्र, जी20 और क्वाड जैसे बहुपक्षीय मंचों में सहयोग के माध्यम से अपने संबंधों को घनिष्ठ बनाया है। इस वर्ष प्रधानमंत्रियों के बीच तीन बैठकें, मंत्रिस्तरीय दौरे, उच्च स्तरीय रक्षा आदान-प्रदान और विभिन्न द्विपक्षीय तलों और कार्यसमूहों की नियमित बैठकें हुईं।

प्रधानमंत्रियों की भागीदारी

प्रधानमंत्रियों के बीच बैठकों में जून में इटली में जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय बैठक शामिल थी, जिसके दौरान दोनों नेताओं ने संबंधों में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया तथा नए और उभरते क्षेत्रों को जोड़ते हुए सहयोग को समग्र तरीके से और अधिक गहरा करने के उपायों पर चर्चा की।

प्रधानमंत्री ने सितंबर में विलमिंगटन, डेलावेयर में क्वाड शिखर सम्मेलन के इतर निवर्तमान प्रधानमंत्री किशिदा से पुनः मुलाकात की। दोनों प्रधानमंत्रियों ने बहुआयामी संबंधों की समीक्षा की तथा सहयोग को और अधिक गहरा करने के लिए विचारों का आदान-प्रदान किया।

प्रधानमंत्री ने अक्टूबर में लाओस में भारत-आसियान शिखर सम्मेलन के इतर जापान के नवनियुक्त प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ द्विपक्षीय बैठक की, जो उनके पदभार ग्रहण करने के कुछ ही दिनों के भीतर हुई।

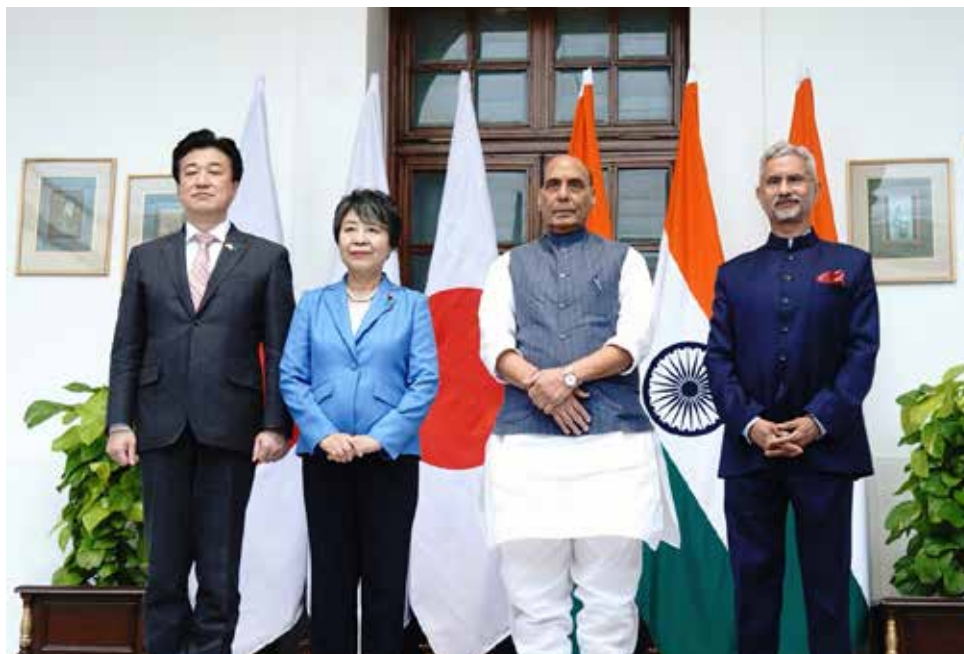


प्रधानमंत्री ने इटली में जी-7 शिखर सम्मेलन के इतर जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय बैठक की, जून 2024।

दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, बुनियादी ढांचे के विकास, रक्षा और सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, कौशल, संस्कृति और दोनों देशों के नागरिकों के बीच आदान-प्रदान सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाकर भारत-जापान विशेष सामरिक एवं वैश्विक भागीदारी को और भी अधिक मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।

विदेश मंत्री की बैठकें

2024 के दौरान, विदेश मंत्री ने जापान के विदेश मंत्री के साथ भी कई बैठकें कीं। विदेश मंत्री ने जापान के तत्कालीन विदेश मंत्री योको कामिकावा के साथ 16^{वीं} भारत-जापान रणनीतिक वार्ता की सह-अध्यक्षता करने और मार्च एवं जुलाई में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए दो बार जापान का दौरा किया। मार्च में टोक्यो की अपनी यात्रा के दौरान, विदेश मंत्री ने रायसीना राउंडटेबल सम्मेलन में भी भाग लिया और उभरते वैश्विक रुझानों के व्यापक संदर्भ में भारत-जापान द्विपक्षीय संबंधों पर टिप्पणी की। विदेश मंत्री ने भारत-जापान भागीदारी पर निकेई फोरम को भी संबोधित किया और उन्होंने दोनों पक्षों के बीच संबंधों में ऐतिहासिक और वर्तमान प्रक्षेपवक्र व प्रगति को रेखांकित किया और नई संभावनाओं को उजागर किया। भारत के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री तथा जापान के विदेश मंत्री एवं रक्षा मंत्री ने नई दिल्ली में तीसरी 2+2 विदेश और रक्षा मंत्रिस्तरीय बैठक की। विदेश मंत्री ने 2+2 मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान 17^{वीं} भारत-जापान



रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में जापान के तत्कालीन विदेश मंत्री योको कामिकावा और जापान के तत्कालीन रक्षा मंत्री मिनोरो किहारा के साथ भारत-जापान 2+2 मंत्रिस्तरीय बैठक के तीसरे दौर में भाग लिया, अगस्त 2024.

सामरिक वार्ता की सह-अध्यक्षता भी की। इन चर्चाओं ने दोनों देशों की सामरिक प्राथमिकताओं, विशेष रूप से रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी में सहयोग को रेखांकित किया। विदेश मंत्री ने नवंबर में इटली में जी7 विदेश मंत्रियों की बैठक के आउटरीच सत्र के इतर जापान के मौजूदा विदेश मंत्री ताकेशी इवाया के साथ बैठक की। विदेश मंत्री ने सातवें भारत-जापान हिंद-प्रशांत फोरम और 10^{वें} भारत-जापान ट्रैक 1.5 संवाद के साथ-साथ तीसरे भारत-जापान फोरम में भी भाषण दिया।

रक्षा सहयोग

भारत और जापान ने तीनों रक्षा सेवाओं के बीच नियमित उच्च स्तरीय बातचीत और युद्धाभ्यास के माध्यम से इस वर्ष अपने रक्षा और सुरक्षा संबंधों में अच्छी गति कायम रखी। तीसरी भारत-जापान 2+2 बैठक में रक्षा प्रौद्योगिकी, संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास और समुद्री सुरक्षा के बारे में सहयोग पर जोर दिया गया। नवंबर में, रक्षा मंत्री ने लाओस की अपनी तीन दिवसीय यात्रा के दौरान जापान के निवर्तमान रक्षा मंत्री जनरल नाकातानी से मुलाकात की। अन्य उच्च स्तरीय कार्यक्रमों में जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल हिरोआकी उचिकुरा की जोधपुर, भारत यात्रा शामिल थी, जहां वे गणमान्य आगंतुक (डीवी) दिवस में शामिल हुए और उन्होंने 10-13 सितंबर 2024 को तरंग शक्ति-24 युद्धाभ्यास का निरीक्षण किया। जापान सेल्फ डिफेंस फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ, जनरल योशीहिदे योशिदा ने अक्टूबर में भारत की यात्रा की, जहां वे मालाबार-24 युद्धाभ्यास के डीवी दिवस में शामिल हुए। भारत के सेना प्रमुख ने अक्टूबर में जापान यात्रा की।

नियमित युद्धाभ्यासों ने द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा सहयोग को गति प्रदान की। जापान ने फरवरी में आयोजित बहुपक्षीय नौसैनिक युद्धाभ्यास मिलन-2024 के 12^{वें} संस्करण में भाग लिया। जून में, दोनों नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय समुद्री युद्धाभ्यास JIMEX-24 का आठवां संस्करण योकोसुका में आयोजित किया गया। भारतीय नौसेना के जहाज शिवालिक ने भी योकोसुका में बंदरगाह पर ठहराव लिया। जापान ने मालाबार-24 युद्धाभ्यास के 28^{वें} संस्करण में भाग लिया जिसे अक्टूबर में विशाखापत्तनम में/उसके निकट संचालित किया गया। भारतीय नौसेना के जहाजों पर फिट करने के लिए यूनिर्कोर्न मस्तूल के सह-विकास के लिए 15 नवंबर को टोक्यो में भारतीय दूतावास में कार्यान्वयन ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

संसदीय आदान-प्रदान

वर्ष के दौरान संसदीय आदान-प्रदान में, जनवरी में तारो होंडा के नेतृत्व में जापान की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के संसद सदस्यों की भारत यात्रा और अगस्त में जापान के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अध्यक्ष/स्पीकर फुकुशिरो नुकागा की भारत यात्रा शामिल थी। अध्यक्ष नुकागा ने एक जापानी संसदीय और व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, जिस दौरान उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री से मुलाकात की।

आर्थिक सहयोग

वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री ने अगस्त में जापान इंटरनेशनल सीफूड एंड टेक एक्सपो में टोक्यो में भारत मंडप का उद्घाटन किया। जापानी व्यापार

जगत के नेताओं के साथ उनकी बातचीत ने रणनीतिक निवेश गंतव्य के रूप में भारत की क्षमता को उजागर किया। सितंबर में, रेल मंत्री ने मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल (एमएचएसआर) परियोजना और डिजिटल बुनियादी ढांचे के विकास पर जापानी अधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिए टोक्यो का दौरा किया। विदेश सचिव ने 27 नवंबर को टोक्यो में जापान के विदेश मंत्रालय के उप मंत्री मासाताका ओकानो के साथ सामरिक व्यापार और प्रौद्योगिकी सहित आर्थिक सुरक्षा पर भारत-जापान वार्ता के पहले दौर की सह-अध्यक्षता की। दोनों देशों की सरकारों के हितधारक मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों द्वारा किए गए विमर्श व संवाद की घोषणा 20 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित भारत-जापान 2+2 मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान की गई।

अन्य संयुक्त जेडब्ल्यूजी और द्विपक्षीय वार्ता

इस वर्ष आयोजित अन्य महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ताओं में, फरवरी में नई दिल्ली में आयोजित नीति नियोजन वार्ता, अप्रैल में टोक्यो में आयोजित निरस्तीकरण, अप्रसार और निर्यात नियंत्रण पर परामर्श, मई में नई दिल्ली में आयोजित आतंकवाद निरोध पर संयुक्त कार्यसमूह, सितंबर में टोक्यो में आयोजित दूसरी भारत-जापान वित्त वार्ता (जिसमें भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग के सचिव ने भाग लिया), जून में नई दिल्ली में आयोजित भारत-जापान औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता भागीदारी, और नवंबर में नई दिल्ली में आयोजित उप एनएसए-स्तरीय वार्ता, आदि शामिल हैं।

राज्य प्रतिनिधिमंडल

राजस्थान के मुख्यमंत्री ने "उभरते राजस्थान" पर केंद्रित रोड शो के लिए सितंबर में जापान का दौरा किया। हिमाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के अध्यक्ष/स्पीकर के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने एक अध्ययन दौरे के लिए अक्टूबर और नवंबर में जापान का दौरा किया। अन्य राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडलों में, कर्नाटक के उद्योग मंत्री और तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल शामिल थे।

सांस्कृतिक और नागरिकों के परस्पर आदान-प्रदान

भारत-जापान पर्यटन आदान-प्रदान वर्ष, जिसे पहली बार 2023 में मनाया गया था, को 2024 तक बढ़ाया गया, जिसका विषय था 'हिमालय को माउंट फूजी से जोड़ना'। सितंबर 2024 में, जापान में 'इंडिया मन्थ' और भारत में 'जापान मन्थ' का आयोजन किया गया। टोक्यो में स्थित भारत के दूतावास ने इस उत्सव के हिस्से के रूप में, विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें जापान के विदेश मामलों के संसदीय उप मंत्री द्वारा इंडिया मन्थ का उद्घाटन, दूतावास में "एक जिला, एक उत्पाद" (ओडीओपी) प्रदर्शनी, जापान में आईसीसीआर द्वारा समर्थित भारत से दो प्रतिष्ठित कथकली और पुरलिया छऊ नृत्य मंडलियों द्वारा प्रदर्शन, जापान में पर्यटन एक्सपो में "भारत इकोटूरिज्म" अभियान का शुभारंभ, आदि शामिल हैं।

मंगोलिया

भारत और मंगोलिया सभ्यतागत, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंध साझा करते हैं। चीन और रूस की सीमा से सटा एक भूमिबद्ध (लैंडलॉक) देश होने के नाते, मंगोलिया भारत को एक महत्वपूर्ण 'तीसरा' और 'आध्यात्मिक' पड़ोसी मानता है। दोनों देशों ने 2015 में प्रधानमंत्री की मंगोलिया यात्रा के दौरान रणनीतिक भागीदारी स्थापित की। तब से, भारत-मंगोलिया संबंधों और सहयोग के प्रक्षेपवक्र में निरंतर वृद्धि देखी गई है। इस वर्ष भी उच्च स्तरीय आदान-प्रदान की गति बनी रही। भारत की सहायता से मंगोलिया में निर्मित की जा रही कुछ प्रमुख विकास परियोजनाओं में इस वर्ष उल्लेखनीय प्रगति देखी गई।

भारत-मंगोलिया द्विपक्षीय संबंधों में प्रमुख घटनाक्रम

मंगोलिया के प्रधानमंत्री ओयुन-एर्दीन लुवसन्नमराय ने 17 अगस्त को तीसरे वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के लिए एक विशेष वीडियो संदेश भेजा। विदेश मंत्री ने अक्टूबर में इस्लामाबाद में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शासनाध्यक्षों की परिषद (सीएचजी) की 22^{वां} बैठक के इतर मंगोलिया के प्रधानमंत्री ओयुन-एर्दीन लुवसन्नमराय से मुलाकात की। इसके अलावा, इस वर्ष वरिष्ठ अधिकारियों और संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के दौरे भी हुए।

रक्षा के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ावा देने के लिए भारत और मंगोलिया के बीच 15-18 मई को उलानबटार में रक्षा पर 12^{वां} संयुक्त कार्यसमूह (जेडब्ल्यूजी) बैठक सफलतापूर्वक आयोजित की गई। इसके अतिरिक्त, मंगोलियाई सशस्त्र बलों की 150^{वां} रेजिमेंट की एक टुकड़ी ने 03-16 जुलाई तक शिलांग, मेघालय में आयोजित द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण युद्धाभ्यास - नोमैडिक एलीफेंट में भाग लिया। एमएएफ के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने जनरल ऑफिसर कमांडिंग (जीओसी), भारतीय सेना की 33 कोर, के साथ 16 जुलाई को समापन समारोह में सहभागिता की।

भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने 25-29 जून के दौरान मंगोलिया में आम चुनावों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन आगंतुक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए एक उच्च स्तरीय 4-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। भारत ने मंगोलिया को अमिट स्याही प्रदान की जिसका उपयोग संसदीय चुनावों के संचालन के दौरान किया गया।

विकास परियोजनाएँ

विकास परियोजनाओं में भारत-मंगोलिया सहयोग के लिए 2024 एक ऐतिहासिक वर्ष रहा। भारत की सबसे बड़ी ओवरसीज लाइन ऑफ क्रेडिट (एलओसी) परियोजना, ऑयल रिफाइनरी परियोजना (ओआरपी) मंगोलिया में कार्यान्वित की जा रही है। मंगोलिया द्वारा इस परियोजना को राष्ट्रीय रणनीतिक महत्व का माना जाता है। ओआरपी के निर्माण का पहला चरण मंगोल रिफाइनरी को सफलतापूर्वक 22 नवंबर को सौंप दिया गया। ओआरपी के दूसरे और तीसरे चरण का काम अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है।

कोरिया गणराज्य

भारत और कोरिया गणराज्य (आरओके) के बीच विशेष रणनीतिक भागीदारी कई उच्च स्तरीय आदान-प्रदान और द्विपक्षीय वार्ता तंत्रों के कारण गहरी हुई है। प्रधानमंत्री और आरओके के तत्कालीन राष्ट्रपति यून सुक येओल ने अक्टूबर में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के इतर और नवंबर में रियो में जी-2 शिखर सम्मेलन के इतर मुलाकात की। विदेश मंत्री ने कोरिया गणराज्य का दौरा मार्च में किया और आरओके के विदेश मंत्री चो ताए-युल के साथ 10^{वाँ} भारत-कोरिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह-अध्यक्षता की। दोनों मंत्रियों ने जुलाई में आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक, सितंबर में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा और दिसंबर में इटली में विदेश मंत्रियों की बैठक के इतर भी मुलाकात की।

रक्षा मंत्री ने नवंबर में लाओस में आरओके के रक्षा मंत्री किम योंग-ह्यून से मुलाकात की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने सितंबर में लाओ पीडीआर

के 12^{वें} पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन आर्थिक मंत्रियों की बैठक के दौरान आरओके के व्यापार मंत्री इंकियो चेयोंग से मुलाकात की। तत्कालीन राज्य मंत्री (आरआरएस) ने मार्च में सियोल में लोकतंत्र-मंलिस्तरीय सम्मेलन के लिए तीसरे शिखर सम्मेलन में भाग लिया। रक्षा मंत्री ने 21 नवंबर को आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक के इतर लाओस में आरओके के तत्कालीन रक्षा मंत्री किम योंग-ह्यून से मुलाकात की।

महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर भारत-आरओके-अमेरिका त्रिपक्षीय प्रारंभिक वार्ता और भारत-आरओके-जापान त्रिपक्षीय नीति नियोजन वार्ता क्रमशः मार्च और अक्टूबर में सियोल में हुई।

भारत और कोरिया ने कोरियाई कंपनियों के लिए फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म अगस्त में लॉन्च किया। फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म ने अपनी पहली बैठक दिसंबर में आयोजित की ताकि कोरियाई कंपनियों के लिए भारत में व्यापार करने में सुगमता सुनिश्चित की जा सके।



प्रधानमंत्री ने वियनतियाने में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के इतर दक्षिण कोरिया के तत्कालीन राष्ट्रपति यू सुक येओल से मुलाकात की, अक्टूबर 2024.

अध्याय

5

यूरेशिया और शंघाई सहयोग संगठन

आर्मेनिया

भारत-आर्मेनिया द्विपक्षीय संबंधों में वर्ष के दौरान उच्च स्तरीय द्विपक्षीय संपर्क जारी रहे। प्रधानमंत्री ने सितंबर में न्यूयॉर्क में यूएनजीए-79 के इतर आर्मेनियाई प्रधानमंत्री निकोल पाशिनयान से संक्षिप्त मुलाकात की। विदेश मंत्री ने अपने आर्मेनियाई समकक्ष अरारत मिर्जोयान से फरवरी में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के इतर मुलाकात की। विदेश राज्य मंत्री (केवीएस) ने येरेवन डायलॉग के उद्घाटन संस्करण में भाग लेने के लिए 09-11 सितंबर को आर्मेनिया का दौरा किया। यात्रा के दौरान, उन्होंने आर्मेनिया के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से भी मुलाकात की।

लोकसभा अध्यक्ष ने अक्टूबर में जिनेवा में अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) की 149^{वाँ} सभा के दौरान नेशनल असेंबली के आर्मेनियाई अध्यक्ष एलन सिमोनियन से मुलाकात की और उन्हें भारत की आधिकारिक यात्रा के लिए आमंत्रित किया। यह यात्रा 16-20 दिसंबर को हुई। एलन सिमोनियन के नेतृत्व में आर्मेनियाई प्रतिनिधिमंडल ने माननीय राष्ट्रपति जी और माननीय उपराष्ट्रपति से मुलाकात की और लोकसभा अध्यक्ष के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक की। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संसदीय आदान-प्रदान को और गहरा करने में आपसी रुचि व्यक्त की।

आर्मेनियाई वित्त मंत्री वाहे होवनहिस्थान ने वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के तीसरे संस्करण के वित्त मंत्रियों के सत्र में भाग लिया। आर्मेनिया ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में भी भाग लिया। आर्मेनिया ने 10 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) फ्रेमवर्क अनुबंध का अनुसमर्थन

किया और वह आईएसए का 104^{वाँ} सदस्य बना। दूसरा भारत-ईरान-आर्मेनिया त्रिपक्षीय परामर्श 12 दिसंबर को महानिदेशक/संयुक्त सचिव स्तर पर नई दिल्ली में आयोजित किया गया।



विदेश मंत्री ने जर्मनी में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के इतर आर्मेनिया के विदेश मंत्री अरारत मिर्जोयान से मुलाकात की, फरवरी 2024.

अज़रबैजान

विदेश मंत्री ने 19 जनवरी को कंपाला में गुटनिरपेक्ष आंदोलन (एनएएम) शिखर सम्मेलन के इतर अज़रबैजान के विदेश मंत्री जेहुन बायरामोव से मुलाकात की। राज्य मंत्री (केवीएस) ने 11-22 नवंबर को बाकु में आयोजित कॉप 29 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।



विदेश मंत्री ने कंपाला में 19^{वें} एनएएम शिखर सम्मेलन के इतर अज़रबैजान के विदेश मंत्री जेहुन बायरामोव से मुलाकात की, जनवरी 2024.

अज़रबैजान ने वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के तीसरे संस्करण के पर्यावरण मंत्रियों के सत्र में भाग लिया। उप विदेश मंत्री याल्चिन राफियेव के नेतृत्व में अज़रबैजानी प्रतिनिधिमंडल ने सीओपी 29 शिखर सम्मेलन के एजेंडे पर परामर्श के लिए नई दिल्ली का दौरा किया। अज़रबैजान के युवा मामले और खेल मंत्री फ़रीद गेइबोव ने खेल में डोपिंग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से संबंधित बैठकों के लिए भारत का दौरा किया।

बेलारूस

तत्कालीन बेलारूसी विदेश मंत्री सर्गेई एलीनिक ने 12-13 मार्च को नई दिल्ली का दौरा किया। उन्होंने विदेश मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, रसायन, उर्वरक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तथा वित्तीय सेवा विभाग के सचिव से मुलाकात की। यह यात्रा युगांडा में एनएएम शिखर सम्मेलन के इतर 18 जनवरी को हुई। यह उनकी पिछली मुलाकात के क्रम में थी। विदेश मंत्री ने जुलाई में अस्ताना में एससीओ शिखर सम्मेलन के इतर तथा बाद में सितंबर में न्यूयॉर्क में 79^{वें} यूएनजीए सत्र के इतर अपने बेलारूसी समकक्ष मैक्सिम रायजेनकोव से मुलाकात की। पहली भारत-बेलारूस वाणिज्य दूतावास वार्ता 28 जून को मिन्स्क में आयोजित की गई। राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के तीसरे संस्करण के लिए अपना वीडियो संदेश भेजा।



विदेश मंत्री ने अस्ताना में एससीओ शिखर सम्मेलन के इतर बेलारूस के विदेश मंत्री मैक्सिम रायजेनकोव से मुलाकात की, जुलाई 2024.

जॉर्जिया

निवासी भारतीय मिशन जॉर्जिया में 22 जुलाई को खोला गया। जॉर्जिया के शिक्षा, विज्ञान और युवा मामले उप मंत्री तारिएल गुगावा ने वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के तीसरे संस्करण के शिक्षा मंत्रियों के सत्र में भाग लिया। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने डिजिटलीकरण और स्थिरता में योगदान देने वाले सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों (एसएआई) की लेखापरीक्षा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 17-20 नवंबर को त्बिलिसी का दौरा किया।

कजाकिस्तान

विदेश मंत्री ने 03-04 जुलाई को एससीओ राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अस्ताना का दौरा किया। उन्होंने कजाख उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मूरत नूरतेलेउ से मुलाकात की और द्विपक्षीय सहयोग के साथ-साथ एससीओ, सीआईसीए आदि जैसे बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग पर विचारों के आदान-प्रदान के लिए कजाख राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट टोकायेव से मुलाकात की। कजाख उप ऊर्जा मंत्री अक्केनझेनोव एरलान ने वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के तीसरे संस्करण के ऊर्जा मंत्रियों के सत्र में भाग लिया। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के 22-24 जून को दौरे से और भारत के मुख्य न्यायाधीश के 19-20 मई को दौरे से चुनाव और न्यायिक क्षेत्रों में सहयोग को और अधिक मजबूती मिली।

काजिंद-2024 संयुक्त युद्धाभ्यास से रक्षा सहयोग में प्रगति आई है, जिसे कजाख अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों और नौसेना एवं वायु सेना के बीच सहयोग के साथ 30 सितंबर से 13 अक्टूबर के दौरान संचालित किया गया।



विदेश मंत्री ने अस्ताना में कजाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मूरत नूरतलेउ से मुलाकात की, जुलाई 2024.

किर्गिस्तान

अफगानिस्तान के संदर्भ में 16 फरवरी को बिश्केक में सुरक्षा परिषदों के सचिवों/राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की छठी क्षेत्रीय वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व तत्कालीन उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने किया।

किर्गिज़ गणराज्य ने वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के तीसरे संस्करण में भाग लिया। स्वास्थ्य मंत्रियों के सत्र में मेदर इस्माइलोव, प्रथम स्वास्थ्य उप मंत्री और युवा मामले मंत्रियों के सत्र में असकर शैकिडिनोव, संस्कृति, सूचना, खेल और युवा मामले मंत्रालय के युवा मामले विभाग के प्रमुख ने भाग लिया।

वार्षिक संयुक्त विशेष बल युद्धाभ्यास 'खंजर-XI' विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल, बकलोह/हिमाचल प्रदेश में 22 जनवरी से 03 फरवरी के दौरान आयोजित किया गया। रक्षा सचिव ने 25 अप्रैल को अस्ताना में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक के इतर किर्गिज़ गणराज्य के रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल बेकबोलोटोव बक्तीबेक से मुलाकात की। रक्षा सहयोग पर संयुक्त कार्यसमूह की दूसरी बैठक 08-09 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित की गई। मध्य एशिया के 100 सदस्यीय युवा प्रतिनिधिमंडल की यात्रा के एक भाग के रूप में, एक 20 सदस्यीय किर्गिज़ युवा प्रतिनिधिमंडल ने 06-12 मार्च को भारत का दौरा किया।

रूस

भारत-रूस विशेष और सामरिक भागीदारी को नियमित उच्च-स्तरीय बातचीत और राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा और दोनों देशों के नागरिकों के परस्पर संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में संबल प्राप्त हुआ है। 2023-24 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार 65.70 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, जिसके फलस्वरूप रूस भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है।

प्रधानमंत्री ने 22^{वें} भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए 08-09 जुलाई को रूस की आधिकारिक यात्रा की। यात्रा के दौरान, उन्हें सर्वोच्च रूसी राजकीय सम्मान, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया। नेताओं ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार का संशोधित लक्ष्य 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर निर्धारित किया। शिखर सम्मेलन के दौरान 2030 तक की अवधि के लिए भारत-रूस आर्थिक सहयोग के सामरिक क्षेत्रों के विकास पर नेताओं का एक अलग संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया।

कज़ान शहर में 16^{वें} ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री ने पुनः 22-23 अक्टूबर को रूस का दौरा किया। प्रधानमंत्री और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2024 में चार बार (15 जनवरी, 20 मार्च, 05 जून और 27 अगस्त) दूरभाष पर भी बातचीत की।



प्रधानमंत्री ने मास्को में 22^{वें} भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, जुलाई 2024.



(नीचे बाएँ से दाएँ) प्रधानमंत्री ने कज़ान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के इतर मिश्र, चीन, ईरान, यूएई, उज्बेकिस्तान और रूस के नेताओं से मुलाकात की, अक्टूबर 2024.

लोकसभा अध्यक्ष ने 11-12 जुलाई को 10^{वें} ब्रिक्स संसदीय मंच के लिए सेंट पीटर्सबर्ग का दौरा किया और अपने समकक्ष स्टेट ड्यूमा के अध्यक्ष व्याचेस्लाव वोलोडिन और फेडरेशन काउंसिल की अध्यक्ष वेलेंटीना मतविएन्को से भी मुलाकात की।

रक्षा मंत्री ने सैन्य और सैन्य-तकनीकी सहयोग पर भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग (आईआरआईजीसी-एम एंड एमटीसी) के 21^{वें} सत्र के लिए 08-10 दिसंबर को रूस का दौरा किया, जिसकी सह-अध्यक्षता दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने की।

विदेश मंत्री और उनके रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव ने 03 जुलाई को अस्ताना में एससीओ शिखर सम्मेलन के इतर, 26 जुलाई को वियनतियाने, लाओस में आसियान फ्रेमवर्क के तहत विदेश मंत्रियों की बैठक के इतर, 09 सितंबर को रियाद में खाड़ी सहयोग परिषद की बैठक के इतर और 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में 79^{वें} यूनजिए सत्र के इतर द्विपक्षीय बैठकें कीं।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) ने ब्रिक्स एनएसए की बैठक के लिए 11-12 सितंबर को सेंट पीटर्सबर्ग का दौरा किया। यात्रा के दौरान, एनएसए ने राष्ट्रपति पुतिन से भी मुलाकात की और अपने रूसी समकक्ष सर्गेई शोइगु के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इससे पहले, एनएसए ने सुरक्षा मामलों के लिए जिम्मेदार उच्चाधिकारियों के 12^{वें} अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए 24 अप्रैल को सेंट पीटर्सबर्ग का दौरा किया, जहाँ उन्होंने अपने तत्कालीन समकक्ष निकोलाई पैतुशेव से मुलाकात की। गृह राज्य मंत्री ने रूसी संघ के

मंत्री (नागरिक सुरक्षा, आपात स्थिति और प्राकृतिक आपदाओं के परिणामों का उन्मूलन) (रूस का EMERCOM) अलेक्जेंडर कुरेनकोव के साथ ऊर्जा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर भारत-रूस संयुक्त आयोग की 28-29 जुलाई के दौरान दूसरी बैठक के आयोजन के लिए मास्को का दौरा किया। यात्रा के दौरान, 2025-2026 के लिए आपातकालीन प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग की कार्ययोजना पर हस्ताक्षर किए गए।

सचिव (पश्चिम) ने आतंकवाद के खिलाफ भारत-रूस संयुक्त कार्यसमूह के 13^{वें} दौर तथा संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय मुद्दों पर द्विपक्षीय परामर्श के लिए 19-20 दिसंबर को मास्को का दौरा किया।

रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव ने 10-12 नवंबर को भारत का दौरा किया और 12 नवंबर को नई दिल्ली में विदेश मंत्री के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग (आईआरआईजीसी-टीईसी) पर भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग के 25^{वें} सत्र की सह-अध्यक्षता की। आईआरआईजीसी-टीईसी के 25^{वें} सत्र के लिए एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए। आईआरआईजीसी-टीईसी सत्रों से पहले भारत-रूस व्यापार मंच की बैठक हुई, जिसे 11 नवंबर को मुंबई में आयोजित किया गया। इसमें भारत और रूस दोनों के व्यवसायघरानों और उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ अधिकारियों तथा हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला ने भाग लिया।



रक्षा मंत्री और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश लिपाठी कलनिनग्राद के यंतर शिपयार्ड में आईएनएस तुशील के कमीशनिंग समारोह में, दिसंबर 2024

भारतीय नौसेना पोत, तबर, ने 28 जुलाई को रूसी संघ की नौसेना की 328^{वीं} वर्षगांठ के अवसर पर मुख्य नौसेना परेड में भाग लेने के लिए 25-30 जुलाई को सेंट पीटर्सबर्ग में ठहराव किया।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने रूस में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भी भाग लिया, जैसे 29 फरवरी से 07 मार्च के दौरान सोची में विश्व युवा महोत्सव, 12-23 जून को कज़ान में ब्रिक्स खेल एवं कूद, 22-24 मई को मास्को में ब्रिक्स अकादमिक मंच और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम।



विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव के साथ भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग की 25^{वीं} बैठक की सह-अध्यक्षता की, नवंबर 2024.

ताजिकिस्तान

इस वर्ष भारत और ताजिकिस्तान के बीच राजनीतिक चर्चाएं जारी रहीं। 17 अगस्त को, ताजिक राष्ट्रपति इमोमाली रहमान ने नेताओं के उद्घाटन सत्र में भाग लिया, जबकि ताजिक विदेश मंत्री सिरोजिद्दीन मुहरिद्दीन ने वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के तीसरे संस्करण के विदेश मंत्रियों के सत्र में भाग लिया।



विदेश मंत्री ने अस्ताना में एससीओ शिखर सम्मेलन के इतर ताजिकिस्तान के विदेश मंत्री सिरोजिद्दीन मुहरिद्दीन से मुलाकात की, जुलाई 2024.

03 जुलाई को, विदेश मंत्री ने अस्ताना में ताजिक विदेश मंत्री सिरोजिद्दीन मुहरिद्दीन से एससीओ शिखर सम्मेलन के इतर मुलाकात की। ताजिकिस्तान गणराज्य के मजलिसी ओली (निचला सदन) के अध्यक्ष महमदतोइर जोकिरजोदा ने 12 जुलाई को सेंट पीटर्सबर्ग में 10^{वें} ब्रिक्स संसदीय मंच के इतर भारत के लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की।

ऊर्जा और जल संसाधन उप मंत्री मनुचेहर सफारजोदा ने गोवा में फरवरी में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 में सामरिक सम्मेलन "पॉवरिंग टुमॉरो - द फ्यूचर आउटलुक फॉर एनर्जी मार्केट्स" में भाग लिया। राज्य भूमि प्रबंधन समिति के प्रथम उपाध्यक्ष और जियोडेसी पिरजोदा दिलोवर अताखोन ने सितंबर में नई दिल्ली में आयोजित पहले भारत-मध्य एशिया रेअर अर्थ फोरम में भाग लिया।

ताजिक विदेश मंत्रालय के ग्यारह युवा राजनयिकों ने अक्टूबर में नई दिल्ली में सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान में मध्य एशिया के राजनयिकों के लिए तीसरे विशेष पाठ्यक्रम में भाग लिया। ताजिकिस्तान के एक 20 सदस्यीय युवा प्रतिनिधिमंडल ने मार्च में दूसरे भारत-मध्य एशिया युवा मंच के हिस्से के रूप में भारत का दौरा किया, जिसमें पाँच मध्य एशियाई देशों के कुल 100 युवा प्रतिनिधि शामिल हुए।

तुर्कमेनिस्तान

विदेश मंत्री ने 27 सितंबर को न्यूयॉर्क में 79^{वें} यूएनजीए के इतर तुर्कमेनिस्तान के विदेश मंत्री राशिद मेरेदोव से मुलाकात की। तुर्कमेनिस्तान ने वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के तीसरे संस्करण के दो सत्रों में भाग लिया। तुर्कमेनिस्तान के विदेश मामलों के उप मंत्री अहमद गुरबानोव ने

विदेश मंत्रियों के सत्र में भाग लिया, जबकि स्टेट कन्सर्न "तुर्कमेनिस्तान" के अध्यक्ष एम. बाबायेव ने ऊर्जा मंत्रियों के सत्र में भाग लिया। पहली बार एक 20 सदस्यीय युवा प्रतिनिधिमंडल ने दूसरे भारत-मध्य एशिया युवा मंच के हिस्से के रूप में 06-12 मार्च को भारत का दौरा किया। तुर्कमेनिस्तान ने 17-18 मई को अपने राष्ट्रीय कवि मैग्टीमगुली फ्रागी की 300^{वीं} जयंती मनाई। समारोह के दौरान, तुर्कमेनिस्तान के सांस्कृतिक पार्क परिसर में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर सहित दुनियाभर के 24 प्रसिद्ध कवियों की मूर्तियों का अनावरण किया गया।

यूक्रेन

2024 के दौरान भारत-यूक्रेन संबंधों का मुख्य आकर्षण बिंदु अगस्त में प्रधानमंत्री की कीव की ऐतिहासिक यात्रा थी। वर्ष 1992 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन की पहली यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडोमिर ज़ेलेन्स्की के साथ सीमित और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। इस यात्रा के दौरान कृषि और खाद्य उद्योग के क्षेत्र में सहयोग, चिकित्सा उत्पाद विनियमन के क्षेत्र में सहयोग, यूक्रेन को भारतीय मानवीय अनुदान सहायता और 2024-2028 के लिए सांस्कृतिक सहयोग कार्यक्रम सहित चार समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। भारत ने यूक्रेन को मानवीय सहायता भी प्रदान की। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन सरकार को चार भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता एंड मैत्री (भीष्म) क्यूब्स और 10 जेनसेट उपहार में दिए। दोनों नेताओं ने जून में इटली में और सितंबर में न्यूयॉर्क में क्रमशः जी-7 शिखर सम्मेलन और यूएनजीए के इतर मुलाकात की और दूरभाष से भी कई बार बातचीत की।



प्रधानमंत्री और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडोमिर ज़ेलेन्स्की ने कीव के मैरिंस्की पैलेस में भारत और यूक्रेन के बीच द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए, अगस्त 2024.



विदेश मंत्री ने यूक्रेन के तत्कालीन विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा से मुलाकात की और नई दिल्ली में यूक्रेनी-भारतीय अंतर-सरकारी आयोग समीक्षा बैठक की सह-अध्यक्षता की, मार्च 2024.

इस वर्ष अन्य उच्च-स्तरीय वार्ताएं हुईं। तत्कालीन यूक्रेनी विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने मार्च में भारत का दौरा किया और विदेश मंत्री तथा तत्कालीन उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ बातचीत की। विदेश मंत्री ने भी नवंबर में इटली में जी-7 विदेश मंत्रियों की बैठक के इतर नए यूक्रेनी विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा से मुलाकात की। इसके अलावा, विदेश मंत्री और यूक्रेनी विदेश मंत्री के साथ तथा एनएसए और यूक्रेन के राष्ट्रपति के कार्यालय प्रमुख एंड्री येरमार्क के बीच कई बार दूरभाष पर बातचीत हुई।

यूक्रेन की उप विदेश मंत्री इरीना बोरोवेट्स ने रायसीना वार्ता में भाग लेने के लिए 20-24 फरवरी को भारत का दौरा किया। यात्रा के दौरान, उन्होंने तत्कालीन विदेश सचिव और तत्कालीन उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों के आगे विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।

उज्बेकिस्तान

23 अक्टूबर को, प्रधानमंत्री ने कज़ान में 16^{वें} ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के इतर उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने 03 जुलाई को अस्ताना में और 28 सितंबर को न्यूयॉर्क में क्रमशः एससीओ शिखर सम्मेलन और यूएनजीए के इतर उज्बेक विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव से मुलाकात की।



प्रधानमंत्री ने कज़ान में 16^{वें} ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के इतर उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय बैठक की, अक्टूबर 2024.

24-28 सितंबर को, वित्त मंत्री ने समरकंद में 9^{वां} एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए उज्बेकिस्तान का दौरा किया। उन्होंने उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति से मुलाकात की और निवेश, उद्योग एवं व्यापार मंत्री लाजीज कुद्रातोव, उज्बेकिस्तान के उप प्रधानमंत्री खोदजायेव जमशेद अब्दुखाकिमोविच और उप प्रधानमंत्री तथा अर्थव्यवस्था एवं वित्त मंत्री कुचकारोव दजामशीद अनवरोविच से मुलाकात की। इस यात्रा के दौरान द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए गए और भारत-उज्बेकिस्तान व्यापार मंच का आयोजन किया गया।

वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के तीसरे संस्करण में, उज्बेकिस्तान ने व्यापार (गुलामोव शोखरुख खासनोविच, कार्यवाहक निवेश, उद्योग और व्यापार उप मंत्री) और पर्यावरण (श्री जुसिपबेक सदिकबेकोविच काज़्बेकोव, पारिस्थितिकी, पर्यावरण संरक्षण उप मंत्री) पर दो मंत्रिस्तरीय सत्रों में भाग लिया।

13 अगस्त को, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने उज्बेकिस्तान की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान अपने उज्बेकी समकक्ष अदिजबोबोयेव, चेयरमैन, चैंबर ऑफ अकाउंट्स के साथ पारस्परिक सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने उज्बेकिस्तान के केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निमंत्रण पर उज्बेकिस्तान में संसदीय चुनावों के पर्यवेक्षक के रूप में 24-27 अक्टूबर को उज्बेकिस्तान का दौरा किया। उन्होंने उज्बेकिस्तान के केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष जैनिद्दीन निजामखोदजायेव के साथ भी बैठक की, जिस दौरान निर्वाचन प्रबंध और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

12 जुलाई को सेंट पीटर्सबर्ग में 10^{वें} ब्रिक्स संसदीय मंच के अवसर पर, लोकसभा अध्यक्ष ने सीनेट की अध्यक्ष तंजिला नरबायेवा से मुलाकात की।

सेना प्रमुख ने 15-18 अप्रैल को उज्बेकिस्तान का चार दिवसीय दौरा किया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने ताशकंद में सशस्त्र बलों की अकादमी में एक सूचना प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया जिसे मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित किया गया था। वार्षिक सैन्य युद्धाभ्यास "डस्टलिक" का 5^{वाँ} संस्करण उज्बेकिस्तान के टर्मेज़ में हुआ। पहली बार, युद्धाभ्यास के दायरे को बढ़ाकर 'द्वि-सेवा' का दर्जा दिया गया, जिसमें भारतीय वायुसेना के गरुड़ से 15 कर्मियों को शामिल किया गया। रक्षा सहयोग पर संयुक्त कार्यसमूह की बैठक अप्रैल में ताशकंद में हुई।

उज्बेकिस्तान से एक 20 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत-मध्य एशिया युवा मंच के लिए पाँच मध्य एशियाई देशों के 100 सदस्यीय युवा प्रतिनिधिमंडल से जुड़ने के लिए 5-13 मार्च को भारत का दौरा किया।

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ)

एससीओ में भारत की प्राथमिकताओं को प्रधानमंत्री के 'सिक्वोर' एससीओ दृष्टिकोण से बल मिला। SECURE का अर्थ है सुरक्षा, आर्थिक विकास, संपर्क/कनेक्टिविटी, एकता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान, और पर्यावरण संरक्षण। भारत एससीओ मंच में सक्रिय रहा, जिसमें एससीओ फ्रेमवर्क के भीतर विभिन्न तंत्र/पहलें शामिल हैं। भारत ने इस बात पर बल दिया कि संप्रभुता, स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता, समानता, पारस्परिक लाभ और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के लिए पारस्परिक सम्मान किया जाना चाहिए। भारत ने आतंकवाद से निपटने, आर्थिक संबंधों

को बढ़ाने, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को बढ़ावा देने, डिजिटल समावेशन, सतत विकास के लिए जीवनशैली और विश्व व्यापार संगठन में सुधार पर भी लगातार वकालत की है। अर्थव्यवस्था, व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप और नवोन्मेष, पारंपरिक चिकित्सा आदि में भारत की प्रगति पर एससीओ की विभिन्न बैठकों में भी प्रकाश डाला गया।

राज्याध्यक्षों की एससीओ परिषद का शिखर सम्मेलन

विदेश मंत्री ने 03-04 जुलाई को अस्ताना में आयोजित 24^{वाँ} एससीओ शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। अस्ताना घोषणा के अलावा, जो कि शिखर सम्मेलन का मुख्य आउटकम डॉक्यूमेंट है, एससीओ शिखर सम्मेलन में कुल 23 दस्तावेजों को अंगीकृत किया गया। गौरतलब है कि, पहली बार शिखर सम्मेलन घोषणा में "एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य" का विषय दोहराया गया। शिखर सम्मेलन व समित ने आतंकवाद की कड़ी निंदा की, विशेष रूप से आतंकवाद के वित्तपोषण, आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही, आतंकवादियों को पनाह देने वाले और सुरक्षित पनाहगाह प्रदान करने वाले देशों को अलग-थलग करने और उन्हें उजागर करने के मुद्दों को संबोधित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। घोषणा-पत्र में क्षेत्र में परिवहन और कनेक्टिविटी पहलों का स्वागत करते हुए, निष्पक्ष और संतुलित आधार पर तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और एससीओ चार्टर के लक्ष्यों और सिद्धांतों के अनुसार सहयोग (कोलाकेशन) के महत्व को रेखांकित किया गया।



विदेश मंत्री ने अस्ताना में एससीओ राज्याध्यक्ष परिषद के 24^{वाँ} शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जुलाई 2024.



विदेश मंत्री ने इस्लामाबाद में एससीओ शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया, अक्टूबर 2024.

विदेश मंत्री ने एससीओ राष्ट्राध्यक्ष परिषद के 24^{वें} शिखर सम्मेलन के एक दिन बाद 04 जुलाई को अस्ताना में एससीओ राष्ट्राध्यक्ष परिषद की विस्तारित प्रारूप बैठक में प्रधानमंत्री के वक्तव्य प्रस्तुत किए। आतंकवाद को समूह के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती के रूप में उठाया गया। लचीली और विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखलाओं की आवश्यकता एवं वैश्विक अर्थव्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाने में भारत के मेक इन इंडिया अभियान की क्षमता पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री के भाषणों ने पुनर्संतुलित विश्व के लिए नए संपर्क-सूत्र स्थापित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया, ताकि राज्यों/देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जा सके तथा पड़ोसी देशों के साथ भेदभाव रहित व्यापार किया जा सके और उन्हें पारगमन (ट्रांजिट) अधिकार दिए जा सकें। प्रधानमंत्री के वक्तव्य में चाबहार बंदरगाह के संबंध में हुई प्रगति और भूमिबद्ध यानी लैंडलॉक्ड मध्य एशियाई देशों के लिए उसके महत्व पर भी प्रकाश डाला गया था। इसके अतिरिक्त, उसमें यह भी संदेश दिया था कि भारत अफगान लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील है। वक्तव्य में उम्मीद जताई गई कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में सुधार लाने के लिए एससीओ की प्रतिबद्धता संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तक भी विस्तारित होगी। वक्तव्य में आग्रह किया गया कि बेहतर ढंग से संचार करने और आम सहमति बनाने के लिए अंग्रेजी को एससीओ की तीसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए।

एससीओ शासनाध्यक्ष परिषद (सीएचजी) की बैठक

विदेश मंत्री ने 15-16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में सीएचजी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। विदेश मंत्री ने एससीओ चार्टर के प्रति प्रतिबद्धता

के महत्व को रेखांकित किया और बताया कि यदि सीमा पार गतिविधियां आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद (तीन बुराइयाँ) के नज़रिए से होगी तो व्यापार, ऊर्जा और कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में सहयोग आगे बढ़ने की संभावना नहीं है। उन्होंने सदस्य देशों से 'तीन बुराइयों' का प्रतिकार करने में दृढ़ रहने और समझौता नहीं करने की अपील की। बैठक में अंगीकृत संयुक्त विज्ञप्ति में भारत की प्राथमिकताओं को दृढ़ता से दर्शाया गया, जिसके प्रमुख परिणामों में आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने, क्षेत्रीय अखंडता के प्रति सम्मान और विवादों का शांतिपूर्ण समाधान जैसे सिद्धांतों पर पुनः बल; एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की सोच पर संवाद करना; डीकार्बोनाइजेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और सतत विकास पर भारत की पहलों के लिए समर्थन; डब्ल्यूटीओ के मूल में नियम-आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली का समर्थन; और बाजरा जैसी जलवायु-अनुकूल फसलों पर अनुसंधान के माध्यम से वैश्विक खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने की प्रतिबद्धता शामिल है।

एससीओ विदेश मंत्रियों की परिषद (सीएफएम) की बैठक

सचिव (आर्थिक संबंध) ने 20-21 मई को अस्ताना में सीएफएम बैठक में भाग लिया। बैठक में एससीओ में चल रहे सहयोग की समीक्षा की गई, एससीओ शासनाध्यक्ष परिषद के शिखर सम्मेलन की तैयारियों पर चर्चा की गई और साझा चिंता के क्षेत्रीय एवं वैश्विक विकास पर विचारों का आदान-प्रदान किया गया।

अन्य उच्च-स्तरीय एससीओ बैठकें

सचिव (इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) ने 01 फरवरी को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लिए जिम्मेदार मंत्रालयों और एजेंसियों के प्रमुखों के सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व (वर्चुअल) किया। अपर सचिव (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय) ने 14 मार्च को अस्ताना में 7^{वीं} एससीओ स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। एनएसए ने 02-03 अप्रैल को अस्ताना में एससीओ की सुरक्षा परिषद के सचिवों की 19^{वीं} बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। संयुक्त सचिव (शिक्षा मंत्रालय) ने 18 अप्रैल को एससीओ के शिक्षा मंत्रियों के सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व (वर्चुअल) किया। सचिव (रक्षा मंत्रालय) ने 26 अप्रैल को अस्ताना में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया।

संस्कृति मंत्री ने 15 मई को एससीओ के संस्कृति मंत्रियों की 21^{वीं} बैठक (वर्चुअल) में भाग लिया। वन महानिरीक्षक ने 22 मई को अस्ताना में पर्यावरण संरक्षण मुद्दों के लिए जिम्मेदार मंत्रालयों और विभागों के प्रमुखों की 5^{वीं} बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने 23 मई को ताशकंद में आयोजित एससीओ के उच्चतम न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की 19^{वीं} बैठक में भाग लिया। सचिव (युवा मामले और खेल मंत्रालय) ने 24 मई को अल्माटी में डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल कल्चर एंड स्पोर्ट के लिए जिम्मेदार मंत्रालयों और एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक में भाग लिया। अपर सचिव (पर्यटन मंत्रालय) ने 24 मई को अल्माटी में एससीओ के पर्यटन प्रशासन के प्रमुखों के सत्र में भाग लिया। अपर सचिव (कृषि और किसान कल्याण विभाग) 29 मई को एससीओ के कृषि मंत्रियों की 9^{वीं} बैठक में शामिल (वर्चुअल) हुए।

अपर सचिव (विधि और न्याय मंत्रालय) ने 06 जून को आयोजित एससीओ न्याय मंत्रियों की बैठक (वर्चुअल) में भाग लिया। संयुक्त सचिव (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) ने 20 जून को आयोजित एससीओ परिवहन मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। सचिव (पेट्रो लियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय) ने 20-21 जून (वर्चुअल) को एससीओ ऊर्जा मंत्रियों की चौथी बैठक (वर्चुअल) में भारत का प्रतिनिधित्व किया। सचिव (वाणिज्य मंत्रालय) ने 12 सितंबर को एससीओ व्यापार मंत्रियों की बैठक (वर्चुअल) में भारत का प्रतिनिधित्व किया। महिला और बाल विकास मंत्री ने 09 सितंबर (वर्चुअल) को किंगदाओ में महिलाओं पर एससीओ फोरम को संबोधित किया। कार्यकारी निदेशक (इन्फ्रा-II) (रेल मंत्रालय) ने 29 नवंबर को मॉस्को में रेल प्रशासन के प्रमुखों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

भारत द्वारा आयोजित अन्य कार्यक्रम

भारत ने 19 मार्च को स्टार्टअप महाकुंभ के इतर नई दिल्ली में एससीओ स्टार्टअप फोरम के चौथे संस्करण की मेजबानी की। इस फोरम ने एससीओ स्टार्टअप समुदाय के हितधारकों को एक मंच पर एकत्र किया जिससे कि वे सहयोग को बढ़ावा देने, विचारों का आदान-प्रदान करने और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने पर चर्चा कर सकें। एससीओ पैवेलियन में प्रदर्शन दिखाने का एक अवसर प्रदान किया गया, जिसमें 15 से अधिक एससीओ स्टार्टअप ने भाग लिया। स्टार्टअप और इनोवेशन पर विशेष कार्यसमूह का दूसरा सत्र 21 नवंबर को भारत द्वारा वर्चुअल प्रारूप में 'सतत विकास में स्टार्टअप और इनोवेशन की भूमिका' विषय पर आयोजित किया गया।

अध्याय

6

जीसीसी, पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका

खाड़ी देश

उच्च स्तरीय यात्राओं के आदान-प्रदान, व्यापार और निवेश में वृद्धि तथा ऊर्जा, सुरक्षा, रक्षा, परमाणु, संस्कृति, शिक्षा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में संबंधों का विस्तार होने के साथ, खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंध 2024 के दौरान प्रबल होते रहे।

सदस्य देश भारत के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में शुमार रहे। 162 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक के द्विपक्षीय व्यापार के साथ, खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) 2023-24 में भारत का शीर्ष क्षेत्रीय समूह व्यापार भागीदार था। निवेश प्रवाह मजबूत बना रहा। जीसीसी देशों से संचयी एफडीआई लगभग 20 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा। इस क्षेत्र से भारत का ऊर्जा आयात भी पर्याप्त हुआ।

खाड़ी देशों में 9.3 मिलियन का मजबूत भारतीय समुदाय, भारत और खाड़ी देशों के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु के रूप में कार्य कर रहा है।

बहरीन

भारत और बहरीन के बीच द्विपक्षीय संबंध आरोही दिशा में बढ़ रहे हैं और राजनीतिक संबंधों, संस्थागत सहयोग, आर्थिक संबंधों एवं भारतीय प्रवासियों के साथ संपर्क में उल्लेखनीय प्रगति आई है।



बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल्लातिफ बिन राशिद अल जयानी ने विदेश मंत्री का मनामा आगमन पर स्वागत करते हुए, दिसंबर 2024

उच्च स्तरीय आदान-प्रदान

बहरीन के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद बिन ईसा अल खलीफा ने जून में प्रधानमंत्री को उनके फिर से चुने जाने पर बधाई संदेश भेजा। बहरीन के राजा, हमद बिन ईसा अल खलीफा के साम्राज्य के उत्थान के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में, 2024 में 126 भारतीय कैदियों को शाही क्षमा प्रदान की गई। बहरीन में 340,000 भारतीय रहते हैं।

विदेश मंत्री ने 08-09 दिसंबर को बहरीन की आधिकारिक यात्रा की और अपने बहरीनी समकक्ष अब्दुल्लातिफ बिन राशिद अल ज़ायनी के साथ चौथी भारत-बहरीन उच्च संयुक्त आयोग की बैठक की सह-अध्यक्षता की। यात्रा के दौरान विदेश मंत्री ने उप प्रधानमंत्री शेख खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा से भी मुलाकात की। इसके अतिरिक्त, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान (आईआईएसएस) मनामा वार्ता के 20^{वें} संस्करण में "हृदिर रीजनल स्ट्रेटिजिक कोआपरेशन" शीर्षक पर समापीय पूर्णकालीन सत्र को संबोधित किया।



विदेश मंत्री ने मनामा, बहरीन में 20^{वें} अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान (आईआईएसएस) मनामा वार्ता को संबोधित किया, दिसंबर 2024.

दिसंबर 2024 में मनामा पहुंचने पर विदेश मंत्री का स्वागत बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल्लातिफ बिन राशिद अल ज़ायनी ने किया।

विदेश मंत्री ने 19-20 जनवरी को कंपाला में गुटनिरपेक्ष आंदोलन (एनएएम) शिखर सम्मेलन के इतर बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल्लातिफ बिन राशिद अल ज़ायनी से मुलाकात की। सितंबर में, विदेश मंत्री ने रियाद में सामरिक वार्ता के लिए जीसीसी-भारत संयुक्त मंत्रिस्तरीय बैठक के इतर अपने बहरीन समकक्ष से मुलाकात की।

17 जनवरी को, स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की वार्षिक बैठक के इतर, विदेश मंत्री ने बहरीन के सतत विकास मंत्री नूर अली अलखुलैफ से मुलाकात की।

17 अगस्त को, बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल्लातिफ बिन राशिद अल ज़ायनी ने विदेश मंत्री की अध्यक्षता में "ग्लोबल साउथ एंड ग्लोबल गवर्नेंस" पर केंद्रित वीडियो कॉन्फ्रेंस के तीसरे संस्करण में वर्चुअल रूप से भाग लिया। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने संस्थागत संबंधों को मजबूत करने के लिए 25-28 अगस्त को बहरीन का दौरा किया।

बहरीन के सतत विकास मंत्री नूर अली अलखुलैफ और तत्कालीन महिला एवं बाल विकास मंत्री के बीच चर्चा जनवरी में स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की वार्षिक बैठक के इतर भी हुई। इसके अतिरिक्त, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने इसी कार्यक्रम में बहरीन आर्थिक विकास बोर्ड के प्रबंधन मंडल के वरिष्ठ सलाहकार इयान लिंडसे और बहरीन पेट्रोलियम कंपनी (बैपको) के सीईओ मार्क थॉमस से मुलाकात की।

23 जुलाई को, संस्कृति मंत्री ने नई दिल्ली में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46^{वें} सत्र के दौरान बहरीन संस्कृति और पुरावशेष प्राधिकरण (बीएसीए) के अध्यक्ष शेख खलीफा बिन अहमद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा से मुलाकात की। एक प्रतिनिधिमंडल ने बहरीन के सतत विकास मंत्री और बहरीन आर्थिक विकास बोर्ड (ईडीबी) के मुख्य कार्यकारी नूर बिनत अली अलखुलैफ के नेतृत्व में 09-14 सितंबर को भारत का दौरा किया और भारत से बहरीन में आवक निवेश को बढ़ावा देने के लिए संभावित निवेशकों से मुलाकात की। 25 सितंबर को युवा मामले एवं खेल मंत्री और बहरीन के युवा मामले मंत्री रावन बिनत नजीब तौफीकी के बीच युवाओं के आदान-प्रदान को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक वर्चुअल बैठक हुई।

बहरीन के उद्योग और वाणिज्य मंत्री अब्दुल्ला बिन अदेल फखरो के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 02-03 दिसंबर को 29^{वें} पार्टनरशिप समिट 2024 में भाग लिया और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री से मुलाकात की तथा उद्योग, व्यापार और निवेश में सहयोग पर चर्चा की।

आर्थिक और व्यापार सहयोग

भारत और बहरीन के बीच व्यापार और आर्थिक संबंध वित्त वर्ष 2023-24 में मजबूत बने रहे। द्विपक्षीय व्यापार 1.73 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया है, जिसमें बहरीन से आयात 0.82 बिलियन अमरीकी डॉलर और भारत से बहरीन को निर्यात 0.91 बिलियन अमरीकी डॉलर है। भारत बहरीन के शीर्ष पाँच व्यापारिक साझेदारों में से एक और छठा सबसे बड़ा निवेशक है। वित्त वर्ष 2023-24 में बहरीन से संघीय एफडीआई इक्विटी प्रवाह लगभग 1.43 मिलियन अमरीकी डॉलर था।

वर्ष के दौरान, कई भारतीय प्रतिनिधिमंडलों ने बहरीन का दौरा किया, जिनमें भारतीय आर्थिक व्यापार संगठन (आईईटीओ), सीमा शुल्क एंड ओ ज़ोन लिची, सीबीआईसी, वित्त मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के प्रतिनिधिमंडल शामिल थे। इंडियन होटल्स कंपनी



भारतीय नौसेना के प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन जहाज, आईएनएस तीर और आईसीजीएस वीरा ने अक्टूबर 2024 में मीना सलमान पोर्ट, बहरीन का दौरा किया।

लिमिटेड (आईएचसीएल) ने बहरीन में दो ताज होटल स्थापित करने के लिए किंगडम प्रोजेक्ट्स के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए - हमला में एक ताज रिसॉर्ट और सीफ़ में 200 कमरों का ताज होटल। बहरीन की ओर से, बहरीन आर्थिक विकास बोर्ड (ईडीबी) के प्रतिनिधिमंडल ने भारत से बहरीन में आवक निवेश को बढ़ावा देने के लिए सितंबर में मुंबई, बंगलुरु और चेन्नई का दौरा किया।

भारत और बहरीन के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) पर वार्ता का पहला दौर 03-04 सितंबर को वर्चुअल रूप में आयोजित किया गया। एक विशेष कदम के रूप में, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने भारत से प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध से छूट देते हुए बहरीन को 3000 मीट्रिक टन प्याज के निर्यात की अनुमति देने की अधिसूचना जारी की।

रक्षा और सुरक्षा सहयोग

संयुक्त समुद्री बलों (सीएमएफ) के पूर्ण सदस्य के रूप में, जिसका मुख्यालय बहरीन में स्थित है, भारत के पहले वर्ष में बहुपक्षीय और द्विपक्षीय दोनों क्षेत्रों में काफी सक्रियता रही। अप्रैल में, भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस तलवार (जो सीएमएफ के संयुक्त कार्य बल (सीटीएफ) 150 के हिस्से के रूप में कार्य कर रहा था) ने 940 कि.ग्रा. ड्रग्स जब्त किए। भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन जहाजों, आईएनएस तीर और आईसीजीएस वीरा ने अक्टूबर में बहरीन के मीना सलमान पोर्ट का दौरा किया। भारतीय वायु सेना बल की सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने नवंबर में साखिर एयरबेस

पर आयोजित बहरीन अंतर्राष्ट्रीय एयर शो के 7^{वें} संस्करण में भाग लिया।

भारत के एक तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 16-17 अप्रैल को मनामा में संयुक्त समुद्री बलों द्वारा आयोजित समुद्री सुरक्षा सम्मेलन 2024 में भाग लिया। भारतीय नौसेना के चिकित्सा सेवा महानिदेशक ने यूएस नवसेंट द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय कॉम्बैट कैजुअल्टी केयर एक्सचेंज सेमिनार के लिए 01-03 जुलाई को बहरीन का दौरा किया।

ईरान

भारत और ईरान के बीच सदियों से ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंध चले आ रहे हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों को एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं और दोनों देशों के नागरिकों के बीच घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देते हैं। भारत और ईरान के बीच द्विपक्षीय सहयोग ने पूरे वर्ष अपनी सकारात्मक गति कायम रखी।

उच्च स्तरीय आदान-प्रदान

22 अक्टूबर को, प्रधानमंत्री ने रूस के कज़ान में 16^{वें} ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के अवसर पर इस्लामी गणराज्य ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण पहलुओं की समीक्षा की और पश्चिम एशिया की स्थिति सहित क्षेत्रीय विकास पर चर्चा की।



प्रधानमंत्री ने रूस के कज़ान में 16^{वें} ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के इतर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन से मुलाकात की, अक्टूबर 2024

14-15 जनवरी को, विदेश मंत्री ने ईरान का दौरा किया और तत्कालीन राष्ट्रपति सैय्यद इब्राहिम रईसी से मुलाकात की। यात्रा के दौरान, उन्होंने तत्कालीन विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन, सड़क और शहरी विकास मंत्री मेहरदाद बजरपाश और सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली अकबर अहमदियन से भी मुलाकात की। 20 जनवरी को, विदेश मंत्री ने कंपाला में गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन के इतर तत्कालीन प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोखबर से मुलाकात की। 24 अक्टूबर को, विदेश मंत्री ने रूस के कज़ान में ब्रिक्स आउटरीच सत्र के इतर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची से मुलाकात की।



विदेश मंत्री ने तेहरान में तत्कालीन इस्लामी गणराज्य ईरान के राष्ट्रपति सैय्यद इब्राहिम रईसी से मुलाकात की, जनवरी 2024.

राष्ट्रपति सैय्यद इब्राहिम रईसी, विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन और कई अन्य ईरानी अधिकारियों के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन के बाद, भारत ने 21 मई को एक दिवसीय आधिकारिक राजकीय शोक की घोषणा की। माननीय उपराष्ट्रपति ने शोक व्यक्त करने के लिए 22 मई को तेहरान में आधिकारिक समारोह में भाग लिया। जुलाई में, संसद के दोनों सदनों ने दिवंगत राष्ट्रपति रईसी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को श्रद्धांजलि दी, जिनका दुखद दुर्घटना में निधन हो गया था।

जुलाई में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए ईरान का दौरा किया।

वर्ष के दौरान कनेक्टिविटी परियोजनाओं में सहयोग को और अधिक मजबूत किया गया। चाबहार पोर्ट के शाहिद बेहेश्टी टर्मिनल को सुसज्जित और संचालित करने के लिए दीर्घकालिक मुख्य अनुबंध पर 13 मई को इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और ईरान के पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गनाइजेशन के बीच हस्ताक्षर किए गए। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री ने अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए ईरान का दौरा किया। भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान के बीच चाबहार पोर्ट पर तीसरे कार्यसमूह की बैठक 22 नवंबर को मुंबई में हुई।

इराक

भारत लंबे समय से इराक का पारंपरिक भागीदार रहा है, जिसके साथ हमारे गहरे ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंध हैं। पूरे वर्ष के दौरान, विभिन्न स्तरों पर कई द्विपक्षीय बातचीत हुई।

उच्च स्तरीय आदान-प्रदान

25 सितंबर को, विदेश मंत्री ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79^{वें} सत्र के इतर इराक के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री फुआद हुसैन से मुलाकात की। उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने 17 अगस्त को आयोजित वीओजीएसएस के तीसरे संस्करण के विदेश मंत्रियों के सत्र में भी वर्चुअल रूप में भाग लिया। इराक के तेल मंत्रालय के अपस्ट्रीम मामलों के उप मंत्री बशीम मोहम्मद खुदैर ने भी वीओजीएसएस के तीसरे संस्करण के ऊर्जा मंत्रियों के सत्र में वर्चुअल रूप में भाग लिया। 17 जनवरी को, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच की 54^{वीं} वार्षिक बैठक के इतर इराकी प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी से मुलाकात की।

इराकी नौसेना बल के कमांडर, स्टाफ वाइस एडमिरल माजिन अब्दुलवाहिद गुबियन अल-आमेरी के नेतृत्व में एक 3 सदस्यीय इराकी नौसैनिक प्रतिनिधिमंडल ने 19-27 फरवरी को भारत में एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक युद्धाभ्यास मिलन -2024 में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना प्रमुख के निमंत्रण पर 17 फरवरी को विशाखापत्तनम का दौरा किया।

आर्थिक और व्यापार सहयोग

इराक वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का 7^{वां} सबसे बड़ा व्यापार भागीदार रहा, जिसका द्विपक्षीय व्यापार 6.35 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया है। इसमें 3 बिलियन अमरीकी डॉलर का आयात और 3.3 बिलियन अमरीकी डॉलर का निर्यात शामिल है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इराक में संचयी एफडीआई इंक्रीटी प्रवाह लगभग 0.01 मिलियन अमरीकी डॉलर रहा।

वर्ष के लिए भारत का कच्चे तेल का आयात 49.90 एमएमटी था, जो भारत के कुल कच्चे तेल आयात का 21.46 प्रतिशत था। 01 जनवरी से 30 नवंबर तक, ये आयात 47.03 एमएमटी था, जो भारत के कुल कच्चे तेल आयात का 21.1 प्रतिशत था। आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल और गेल के प्रतिनिधियों सहित एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 21-23 मई को इराक का दौरा किया और तेल के विपणन के लिए राज्य संगठन (एसओएमओ) एवं इराक के तेल मंत्रालय के साथ चर्चा की।

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) और भारतीय निर्यात संगठनो महासंघ (एफआईओ) जनवरी में इराक के लिए व्यापार प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व किया। एफआईओ के प्रायोजन के तहत 20 से अधिक बहुक्षेत्रीय भारतीय कंपनियों ने जून में एरबिल और सुलेमानिया का दौरा किया। मई में आयोजित एरबिल निर्माण व्यापार मेले में लगभग 20 भारतीय निर्माण कंपनियों ने भाग लिया। कई चीनी मिट्टी और संगमरमर की आपूर्ति करने वाली कंपनियां कुर्दिस्तान और इराक में सक्रिय रूप से व्यापार कर रही हैं। 17-19 जनवरी को नई दिल्ली में आयोजित इंडिया सॉफ्ट एग्जिबिशन में लगभग आधा दर्जन इराकी व्यापारियों ने भाग लिया। एफआईओ के प्रायोजन के तहत 10-19 जनवरी को बगदाद में आयोजित 47^{वां} बगदाद अंतर्राष्ट्रीय मेले में 47 कंपनियों और लगभग 100 भारतीय व्यापारियों की भागीदारी के साथ एक भारत मंडप स्थापित किया गया।

भारत ने इराक में क्षमता निर्माण का समर्थन करना जारी रखा, सालाना 200 आईटीईसी स्लॉट की पेशकश की और शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए इराकी छात्रों को आईसीसीआर द्वारा 75 छात्रवृत्तियां प्रदान कीं। भारत को चिकित्सा पर्यटन के मामले में, इराक एक महत्वपूर्ण स्रोत रहा है और इस संबंध में वार्षिक रूप से 30,000 से अधिक चिकित्सा वीजा जारी किए गए। इराक में भारतीय समुदाय की संख्या लगभग 35,000 है, जो मुख्य रूप से बगदाद, कुर्दिस्तान क्षेत्र, बसरा, नजफ और कर्बला में रहते हैं। इसके अतिरिक्त, लगभग 100,000 भारतीय हर साल बगदाद, कर्बला, नजफ और समराह जैसे शहरों में धार्मिक तीर्थयात्रा के लिए इराक जाते हैं।

अगस्त में, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) की ओर से कुर्दिस्तान के संस्कृति और युवा मंत्रालय को भारतीय संगीत वाद्ययंत्र उपहार के रूप में भेंट किए गए। आरआईएस में ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने जून में इराकी थिंक-टैंक, अल-रफीदैन सेंटर फॉर डायलॉग (आरसीडी) के साथ और अप्रैल में कुर्दिश थिंक-टैंक तथा मिडिल ईस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट (एमईआरआई) के साथ अप्रैल में एक लेटर ऑफ एसोसिएशन पर हस्ताक्षर किए।

कुवैत

भारत और कुवैत के बीच लंबे समय से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं, जो लोगों के बीच मजबूत संबंधों और व्यापार पर आधारित हैं। वर्ष के दौरान, उच्च-स्तरीय यात्राओं और बातचीत से इन संबंधों को और अधिक मजबूती मिली।

उच्च स्तरीय आदान-प्रदान

प्रधानमंत्री ने 21-22 दिसंबर को कुवैत का आधिकारिक दौरा किया। यह प्रधानमंत्री की कुवैत की पहली यात्रा थी और पिछले 43 वर्षों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। यात्रा के दौरान, उन्होंने कुवैत के अमीर शेख मेशाल अल-अहमद अल-जबर अल-सबाह, कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल-खालिद अल-सबाह अल-हमद अल-मुबारक अल-सबाह और कुवैत के प्रधानमंत्री शेख अहमद अब्दुल्ला अल-अहमद अल-जबर अल-मुबारक अल-सबाह के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री को कुवैत के अमीर द्वारा कुवैत राष्ट्र के सर्वोच्च पुरस्कार 'ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर' से सम्मानित किया गया।



प्रधानमंत्री को कुवैत राष्ट्र के अमीर शेख मेशाल अल-अहमद अल-जबर अल-सबाह द्वारा 'ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर' से सम्मानित किया गया, दिसंबर 2024



प्रधानमंत्री ने कुवैत के मीना अब्दुल्ला क्षेत्र में एक श्रमिक शिविर का दौरा किया और भारतीय श्रमिकों से बातचीत की, दिसंबर 2024



प्रधानमंत्री कुवैत में एक विशेष कार्यक्रम 'हला मोदी' में भारतीय समुदाय के एक बड़े समूह को संबोधित करते हुए, दिसंबर 2024

प्रधानमंत्री ने कुवैत में लगभग 1500 भारतीय नागरिकों के कार्यबल वाले एक श्रमिक शिविर का भी दौरा किया और भारतीय श्रमिकों के एक वर्ग से बातचीत की और बाद में, एक विशेष कार्यक्रम 'हला मोदी' में भारतीय समुदाय के एक बड़े समूह को संबोधित किया।

दोनों पक्ष संबंधों को रणनीतिक भागीदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए। यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित प्रमुख द्विपक्षीय दस्तावेजों में, रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन और कुवैत की अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) की सदस्यता शामिल है।

22 सितंबर को, प्रधानमंत्री ने न्यूयॉर्क में यूएनजीए के 79^{वाँ} सत्र के इतर कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा खालिद अल-हमद अल-मुबारक अल-सबाह से मुलाकात की। यह प्रधानमंत्री और कुवैत के क्राउन प्रिंस के बीच

पहली बैठक थी, और पिछले दशक में दोनों देशों के नेतृत्व के बीच पहली उच्च स्तरीय बातचीत थी।

विदेश मंत्री ने कुवैत के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अल-याह्या के साथ आधिकारिक वार्ता के लिए 18 अगस्त को कुवैत का दौरा किया। यात्रा के दौरान, विदेश मंत्री ने क्राउन प्रिंस शेख सबा अल-खालिद अल सबा और प्रधानमंत्री शेख अहमद अल अब्दुल्ला अल सबा से भी मुलाकात की। विदेश मंत्री ने बाद में 9 सितंबर को रियाद में पहली भारत-जीसीसी विदेश मंत्रियों की बैठक के इतर विदेश मंत्री से मुलाकात की। कुवैत के विदेश मंत्री ने 03-04 दिसंबर को भारत की यात्रा की, जहां उन्होंने विदेश मंत्री से द्विपक्षीय चर्चाएं कीं। 04 दिसंबर को, दोनों मंत्रियों ने विदेशी मंत्रियों के स्तर पर एक संयुक्त सहयोग आयोग (जेसीसी) स्थापित करने हेतु एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए।



विदेश मंत्री और कुवैत के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अल-याह्या ने विदेश मंत्रियों के स्तर पर संयुक्त सहयोग आयोग (जेसीसी) की स्थापना के लिए नई दिल्ली में दिसंबर 2024 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।



कुवैत में जून 2024 में हुई दुखद आग की घटना में मृतकों के पार्थिव शरीर को भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से वापस लाते हुए विदेश राज्य मंत्री (केवीएस), जून 2024.

विदेश राज्य मंत्री (केवीएस) ने 13 जून को कुवैत का दौरा किया, जहां एक दुखद आग की घटना में 46 भारतीयों की जान चली गई थी। उन्होंने कुवैत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और रक्षा एवं आंतरिक मंत्री, विदेश मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की और विभिन्न अस्पतालों में घायल भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। मृतकों के पार्थिव शरीर को 14 जून को एक विशेष भारतीय वायुसेना विमान द्वारा हवाई मार्ग से भारत लाया गया, जिसमें विदेश राज्य मंत्री (केवीएस) स्वयं सवार थे।

भारत-कुवैत विदेश कार्यालय परामर्श (एफओसी) का छठा दौर 24 जुलाई को कुवैत में आयोजित किया गया। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव (सीटी) ने 04-05 नवंबर को कुवैत द्वारा आयोजित संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोधक कार्यालय (यूएनओसीटी) सम्मेलन में भी भाग लिया। हाइड्रोकार्बन पर संयुक्त कार्यसमूह (जेडब्ल्यूजी) की 7^{वीं} बैठक 10-11 दिसंबर को नई दिल्ली में आयोजित की गई।

आर्थिक और व्यापार सहयोग

भारत और कुवैत के बीच द्विपक्षीय व्यापार में लगातार वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2023-24 में, कुल व्यापार 10.47 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया था। कुवैत को भारत का निर्यात 2.1 बिलियन अमरीकी डॉलर था, जबकि कुवैत से कुल आयात 8.4 बिलियन अमरीकी डॉलर था, जिसमें कच्चे तेल और संबंधित उत्पादों का आयात लगभग 75 प्रतिशत था। विमान और पुर्जे, अनाज और कार्बनिक रसायन भारत द्वारा कुवैत को निर्यात की जाने वाली शीर्ष तीन वस्तुएँ थीं।

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुवैत से संचयी एफडीआई इक्विटी प्रवाह लगभग 1.45 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो तेल और गैस, फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य प्रसंस्करण, ऑटो/ईवी, रसायन और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में बढ़ती रुचि को दर्शाता है।

वर्ष के दौरान आयोजित व्यापार और निवेश प्रोत्साहन कार्यक्रमों में, अप्रैल में 'भारत-कुवैत निवेश सम्मेलन 2.0', सितंबर में खाद्य और पेय क्षेत्रों में दो बी2बी नेटवर्किंग कार्यक्रम, और सीआईआई के समर्थन से भारत में आवास कल्याण और रियल एस्टेट कंपनियों के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण के साथ एक ऑनलाइन बैठक शामिल है। सार्वजनिक खाद्य और पोषण प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों और कुवैत उपभोक्ता सहकारी समितियों के संघ के अध्यक्ष ने विश्व खाद्य भारत 2024 में भाग लिया।

ओमान

भारत और ओमान के बीच सदियों पुराना ऐतिहासिक संबंध है, जो दोनों देशों के लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित है। लगभग 700,000 भारतीय नागरिक ओमान में रहते हैं। दोनों देशों ने राजनीतिक, रक्षा, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में अपनी घनिष्ठ और बहुआयामी भागीदारी को मजबूती प्रदान की।



विदेश मंत्री ने रियाद में भारत-जीसीसी विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान ओमान के विदेश मंत्री सैय्यद बद्र बिन हमद अल-बुसैदी से मुलाकात की, सितंबर 2024.

उच्च स्तरीय आदान-प्रदान

ओमान सल्तनत ने जून में प्रधानमंत्री के साथ एक टेलीकांफ्रेंस आयोजित की। गौरतलब है कि सल्तनत प्रधानमंत्री को उनके पुनः चुनाव पर बधाई देने वाले पहले जीसीसी नेताओं में से एक था। विदेश मंत्री ने द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करते हुए ओमान के विदेश मंत्री सैय्यद बद्र बिन हमद अल-बुसैदी के साथ तीन टेलीकांफ्रेंस कीं। दोनों मंत्रियों ने सितंबर में भारत-जीसीसी विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान रियाद में भी मुलाकात की।

3 दिसंबर को, 13^{वाँ} भारत-ओमान सामरिक सलाहकार समूह की बैठक की सह-अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्रालय के सचिव (सीपीवी और ओआईए) और उनके ओमानी समकक्ष, राजनयिक मामलों के अवर सचिव शेख खलीफा अलहार्थी ने नई दिल्ली में की। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोग मामलों के उप प्रधानमंत्री सैय्यद असद बिन तारिक ने प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित वीओजीजीएस के तीसरे संस्करण के नेताओं के सत्र में भाग लिया। उन्होंने शिखर सम्मेलन के दौरान व्यापार और निवेश उप मंत्रियों के सत्र में भी भाग लिया।

फरवरी में, भारत और ओमान के बीच 9^{वाँ} रणनीतिक वार्ता आयोजित की गई। भारत के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने ओमान का दौरा किया और ओमान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के महासचिव मेजर जनरल इदरीस अल-किंदी के साथ वार्ता की सह-अध्यक्षता की। वार्ता में सहयोग के रणनीतिक क्षेत्रों की पूरी श्रृंखला की समीक्षा की गई।

व्यापार और आर्थिक सहयोग

ओमान के वाणिज्य, उद्योग और निवेश संवर्धन मंत्री, कैस अल यूसुफ ने

व्यापार और निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए अगस्त में भारत का दौरा किया। भारत ओमान का चौथा सबसे बड़ा कच्चा तेल निर्यात बाजार और गैर-तेल निर्यात के लिए तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। 2023-24 के दौरान, कुल द्विपक्षीय व्यापार लगभग 8.9 बिलियन अमरीकी डॉलर था। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ओमान से संचयी एफडीआई इंक्रीटी प्रवाह लगभग 5 मिलियन अमरीकी डॉलर था।

द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) वार्ता का अंतिम दौर 30 सितंबर से 1 अक्टूबर तक वर्चुअल रूप में आयोजित किया गया।

भारत-ओमान दोहरा कराधान परिहार समझौता (डीटीए) में संशोधन करने हेतु अद्यतित नवाचार पर सहमति हुई जिसे भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई। दोनों देश भारत-ओमान व्यापक आर्थिक भागीदारी पर भी बातचीत कर रहे हैं, जिसमें कृषि, स्वास्थ्य परिचर्या और विनिर्माण क्षेत्रों में उल्लेखनीय व्यापार-से-व्यापार संपर्क शामिल हैं।

रक्षा और सुरक्षा सहयोग

रक्षा भागीदारी प्रमुख यात्राओं, बैठकों और युद्धाभ्यासों के साथ मजबूत रही। जनवरी में, भारत के रक्षा सचिव ने ओमान के रक्षा मंत्रालय के महासचिव के साथ संयुक्त सैन्य सहयोग समिति (जेएमसीसी) की सह-अध्यक्षता की। जेएमसीसी बैठक के दौरान, दोनों देशों ने रक्षा सामग्री की खरीद पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अक्टूबर में भारतीय नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, दक्षिणी नौसेना कमान ने ओमान का दौरा किया। भारतीय नौसेना ने 13-18 अक्टूबर को गोवा में ओमान के साथ 'नसीम अल-बहर' युद्धाभ्यास की मेजबानी की, और ओमान ने 12-26



आईएनएस लिंकद और डोर्नियर समुद्री गश्ती विमान ने गोवा के समीप रॉयल नेवी ऑफ ओमान के साथ भारत-ओमान द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 'नसीम-अल-बहर' में भाग लिया, अक्टूबर 2024.



भारतीय सेना और रॉयल आर्मी ऑफ ओमान ने ओमान के रबकूट में संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास 'अल नजाह वी' का 5^{वां} संस्करण आयोजित किया, सितंबर 2024.

सितंबर को भारतीय सेना के साथ 'अल नजाह' युद्धाभ्यास और 12-22 सितंबर को भारतीय वायु सेना के साथ 'ईस्टर्न ब्रिज' युद्धाभ्यास की मेजबानी की।

आईएनएस लिंकद और डोर्नियर समुद्री गश्ती विमान ने अक्टूबर 2024 में गोवा के पास रॉयल नेवी ऑफ ओमान वेसल अल सीब के साथ भारत-ओमान द्विपक्षीय नौसैनिक युद्धाभ्यास 'नसीम-अल-बहर' में भाग लिया।

इस प्रशिक्षण भागीदारी में रिकॉर्ड भागीदारी देखी गई, जिसमें 70 से अधिक ओमानी कर्मियों ने भारत में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया, जबकि भारतीय मोबाइल प्रशिक्षण टीमों (एमटीटी) ने ओमान में तदनुकूल पाठ्यक्रम आयोजित किए। भारतीय नौसेना, ओमान समुद्री सुरक्षा केंद्र, रॉयल नेवी ऑफ ओमान और रॉयल एयर फोर्स ऑफ ओमान की भागीदारी में एक संयुक्त खोज और बचाव (एसएआर) अभियान के तहत एमटी फाल्कन

प्रेस्टीज से आठ भारतीयों सहित नौ चालक दल के सदस्यों को बचाया गया।

भारतीय दूतावास ने ओमान हिस्टोरिकल एसोसिएशन और नेशनल म्यूजियम ऑफ ओमान के साथ मिलकर 'मांडवी से मस्कट: भारतीय समुदाय और भारत एवं ओमान का साझा इतिहास' शीर्षक पर एक व्याख्यान श्रृंखला आयोजित की, जिसका उद्घाटन तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री (वीएम) ने किया। इन व्याख्यानों में दोनों देशों के बीच सदियों पुराने ऐतिहासिक संबंधों पर प्रकाश डाला गया था। दूतावास ने ओमान में भारतीय व्यापारी परिवारों के 7,000 से अधिक ऐतिहासिक दस्तावेजों का डिजिटलीकरण भी किया, जिससे भारतीय प्रवासियों की विरासत को संरक्षित किया जा सके। अप्रैल में, ओमान के राष्ट्रीय संग्रहालय ने भारतीय दूतावास के सहयोग से, अनीस अल-हुज्जाज पांडुलिपि का अनावरण किया, जो कि मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय से उधार लिया गया एक ऐतिहासिक दस्तावेज है।

कतर

भारत कतर के साथ एक ऐतिहासिक और बहुआयामी संबंध साझा करता है। दोनों देश उच्च स्तरीय आदान-प्रदान, व्यापार, ऊर्जा सहयोग और दोनों पक्षों के नागरिकों के बीच संपर्कों सहित विभिन्न क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने के पक्षधर हैं। लगभग 830,000 संख्या का भारतीय प्रवासी समुदाय कतर में सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है, जो दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का काम करता है।

उच्च स्तरीय आदान-प्रदान

प्रधानमंत्री ने 14-15 फरवरी को कतर की आधिकारिक यात्रा की। दोहा में, उन्होंने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने के उपायों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी और प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी से भी मुलाकात की। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने 10 जून को टेलीफोन पर बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री को उनके फिर से चुने जाने पर बधाई दी। विदेश मंत्री ने 30 जून को कतर का दौरा किया और प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी के साथ चर्चा की। उन्होंने

भारत-कतर संबंधों को और भी ज्यादा घनिष्ठ बनाने पर चर्चा की। उन्होंने 09 सितंबर को रियाद में भारत-जीसीसी मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान पुनः मुलाकात की। विदेश मंत्री ने 06-07 दिसंबर को कतर का दौरा किया, जहां उन्होंने दोहा फोरम के 22^{वें} संस्करण में भाग लिया और 'नए युग में संघर्ष समाधान' पर एक पैनल में वक्तव्य दिया। विदेश मंत्री ने भी कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी से मुलाकात की और कतर के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। उन्होंने यात्रा के दौरान वाणिज्य और उद्योग मंत्री शेख फैसल बिन थानी बिन फैसल अल थानी और राज्य मंत्री अहमद अल सईद से भी मुलाकात की।

विदेश मंत्री ने 30 दिसंबर को तीसरी बार कतर का दौरा किया और द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने तथा 2025 की शुरुआत में कतर के अमीर की भारत की आगामी वीवीआईपी यात्रा की समीक्षा करने के लिए कतर के अपने समकक्ष शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी से मुलाकात की।

01-04 अक्टूबर को, विदेश राज्य मंत्री (केवीएस) ने दोहा में तीसरे एशिया सहयोग वार्ता (एसीडी) शिखर सम्मेलन के इतर आयोजित दूसरे व्यापार मंच को संबोधित किया। अपनी यात्रा के दौरान, उन्होंने 03 अक्टूबर को कतर के विदेश राज्य मंत्री सुल्तान बिन साद अल मुरैखियन के साथ द्विपक्षीय बैठक की।



प्रधानमंत्री ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ दोहा में चर्चा की, फरवरी 2024.



विदेश राज्य मंत्री (केवीएस) ने दोहा, कतर में तीसरे एशिया सहयोग वार्ता (एसीडी) शिखर सम्मेलन के इतर आयोजित दूसरे व्यापार मंच को संबोधित किया, अक्टूबर 2024

26-27 फरवरी को, रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री ने दोहा का दौरा किया तथा अपने कतर के समकक्षों के साथ बैठकें कीं। राजस्थान सरकार के उद्योग और वाणिज्य मंत्री ने 19-20 सितंबर को कतर का दौरा किया और निवेशकों एवं व्यापारिक समुदाय के साथ बातचीत की तथा उन्हें दिसंबर में 'राइजिंग राजस्थान' निवेश शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया।

फरवरी में, कतर के ऊर्जा राज्य मंत्री और कतर एनर्जी के सीईओ, इंजी. साद शेरिदा अल-काबी ने गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह में भाग लिया और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री से मुलाकात की। इस यात्रा के दौरान, कतर एनर्जी और पेट्रोनेट एलएनजी ने वर्ष 2028 से 20 वर्षों के लिए कतर से भारत को 7.5 एमएमटीपीए एलएनजी की आपूर्ति के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

विदेश मंत्रालय के सचिव (सीपीवी और ओआईए) ने 27 अक्टूबर को कतर का दौरा किया और कतर के विदेश मंत्रालय के महासचिव के साथ भारत तथा कतर के बीच विदेश कार्यालय परामर्श के 5^{वें} दौर की सह-अध्यक्षता की। निवेश पर भारत-कतर संयुक्त कार्यबल की पहली बैठक 06 जून को नई दिल्ली में हुई। बैठक की सह-अध्यक्षता भारत की ओर से आर्थिक मामले विभाग के सचिव और कतर के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अवर सचिव मोहम्मद बिन हसन अल मल्की ने की। व्यापार और वाणिज्य पर संयुक्त कार्यसमूह की प्रारंभिक बैठक 10 जुलाई को दोहा में हुई।

व्यापार और आर्थिक सहयोग

भारत-कतर व्यापार काफी अच्छा रहा। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कुल द्विपक्षीय व्यापार लगभग 14 बिलियन अमरीकी डॉलर था। कतर से भारत का आयात 12.38 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया है, जबकि कतर को निर्यात 1.7 बिलियन अमरीकी डॉलर का था। ऊर्जा ने

व्यापार संबंधों पर अच्छी पकड़ बना रखी है। कतर भारत को एलएनजी और एलपीजी का एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता है। दोनों पक्ष द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को अधिकाधिक बढ़ावा देने के लिए द्विपक्षीय निवेश संधि और संशोधित दोहरे कराधान परिहार समझौते को संपन्न करने के लिए भी बातचीत कर रहे हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए संचयी एफडीआई इक्विटी प्रवाह लगभग 998.66 मिलियन अमरीकी डॉलर था।



विदेश राज्य मंत्री (केवीएस) ने दोहा, कतर में तीसरे एशिया सहयोग वार्ता (एसीडी) शिखर सम्मेलन के इतर कतर के विदेश राज्य मंत्री सुल्तान बिन साद अल मुरैखी से मुलाकात की, अक्टूबर 2024

कई भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडलों और कंपनियों ने व्यापार एवं वाणिज्य के अवसरों का पता लगाने के लिए कतर में आयोजित कार्यक्रमों और प्रदर्शनियों में भाग लिया। इनमें 02-03 जून को भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) प्रतिनिधिमंडल, 11-12 सितंबर को भारतीय निर्यात संगठन महासंघ (एफआईआईओ) प्रतिनिधिमंडल और 11 जुलाई को समुद्री उत्पादों पर एक क्रेता-विक्रेता बैठक शामिल थी। भारतीय कंपनियों ने दोहा आभूषण और घड़ियाँ प्रदर्शनी (05-11 फरवरी), कतर अंतर्राष्ट्रीय कृषि प्रदर्शनी (21-27 फरवरी) और प्रोजेक्ट कतर (27-30 मई) जैसी प्रदर्शनियों में भी भाग लिया। इसी प्रकार, कतर के अनेक व्यवय प्रतिनिधिमंडलों ने व्यवसाय अवसरों के लिए भारत का दौरा किया।

भारतीय प्रवासी समुदाय द्विपक्षीय संबंधों का उत्थान करने में लगातार अहम भूमिका निभा रहा है। भारतीय सामुदायिक संगठनों के सहयोग से कई सांस्कृतिक कार्यक्रम, जैसे कि 'पैसेज टू इंडिया', मजदूर दिवस समारोह और 'भारत उत्सव' आयोजित किए गए। सूक वाकिफ के सहयोग से एक 30 मई-08 जून को भारतीय आम महोत्सव 'अल-हंबा प्रदर्शनी' आयोजित की गई, जिसमें भारतीय आम की भिन्न किस्मों का प्रदर्शन किया गया।

सऊदी अरब

भारत और सऊदी अरब ने सामरिक भागीदारी परिषद (एसपीसी) के फ्रेमवर्क के तहत व्यापक सहयोग की गति को बनाए रखा है, जिसके आधार नियमित उच्च-स्तरीय राजनीतिक और वाणिज्यिक आदान-प्रदान, निवेश पर उच्च स्तरीय टास्क फोर्स (एचएलटीएफ) की स्थापना, रक्षा भागीदारी को गहरा करने तथा सांस्कृतिक और लोगों के बीच संबंधों का विस्तार है।

उच्च स्तरीय आदान-प्रदान

विदेश मंत्री ने 08-09 सितंबर को रियाद का दौरा किया और रणनीतिक व सामरिक वार्ता के लिए पहली बार भारत-जीसीसी संयुक्त मंत्रिस्तरीय बैठक के उद्घाटन सत्र की सह-अध्यक्षता की। इस अवसर पर विदेश मंत्री ने अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की। बैठक में सुरक्षा, व्यापार, परिवहन, ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक संयुक्त कार्य योजना 2024-2028 को अंगीकृत किया गया।

एसपीसी फ्रेमवर्क के तहत राजनीतिक, सुरक्षा, सामाजिक और सांस्कृतिक समिति (पीएसएससी) तथा अर्थव्यवस्था और निवेश समिति (ईएडआई) की मंत्रिस्तरीय, वरिष्ठ अधिकारी और संयुक्त कार्यसमूह की बैठकें आयोजित की गईं। विदेश मंत्री और सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल-सऊद ने 13 नवंबर को नई दिल्ली में पीएसएससी बैठक की सह-अध्यक्षता की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने 30 अक्टूबर को रियाद में सऊदी ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुलअजीज बिन सलमान अल सऊद के साथ ईएडआई बैठक की सह-अध्यक्षता की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने यात्रा

के दौरान फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव समिट में भी भाग लिया। विदेश सचिव और राजनीतिक मामलों के उप मंत्री सऊद अल सती ने 18 अक्टूबर को नई दिल्ली में पीएसएससी समिति के तहत प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की।

तत्कालीन अल्पसंख्यक मामले मंत्री ने तत्कालीन एमओएस (वीएम) के साथ 06-08 जनवरी को जेद्दा का दौरा किया और हज एवं उमराह सम्मेलन के तीसरे संस्करण में भाग लिया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने 01-03 दिसंबर को रियाद का दौरा किया और मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीसीडी) के सीओपी16 में भाग लिया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने 15-16 नवंबर को जेद्दा में एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध पर चौथे वैश्विक उच्च स्तरीय मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भाग लिया। वित्त राज्य मंत्री के नेतृत्व में, एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अध्यक्ष और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के एक सदस्य के साथ 04-05 दिसंबर को रियाद में जकात, कर और सीमा शुल्क प्राधिकरण (जेडएटीसीए) सम्मेलन 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने 28-31 अगस्त को रियाद का दौरा किया और अपने समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं। यात्रा के दौरान, सार्वजनिक क्षेत्र की लेखापरीक्षा पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव ने 29-30 सितंबर को सऊदी अरब का दौरा किया। विदेश मंत्रालय के सचिव (सीपीवी और ओआईए) ने द्विपक्षीय बैठकों के लिए 04-07 मई को सऊदी अरब का दौरा किया।



विदेश मंत्री ने रियाद में आयोजित रणनीतिक वार्ता के लिए पहली बार भारत-जीसीसी संयुक्त मंत्रिस्तरीय बैठक के उद्घाटन सत्र की सह-अध्यक्षता की, सितंबर 2024



भारत-सऊदी अरब संयुक्त भूमि सैन्य युद्धाभ्यास 'सदा तनसीक' का प्रारंभिक चरण जनवरी 2024 में राजस्थान के महाजन में आयोजित किया गया

व्यापार और आर्थिक सहयोग

भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति आई है। भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है, जबकि सऊदी अरब भारत का 5^{वां} सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार 43.37 बिलियन अमरीकी डॉलर था। इस अवधि के दौरान, सऊदी अरब से भारत का आयात 31.81 बिलियन अमरीकी डॉलर था, जबकि सऊदी अरब को निर्यात 11.56 बिलियन अमरीकी डॉलर था। वित्तीय वर्ष 2023-24 में सऊदी अरब के साथ कुल व्यापार भारत के कुल व्यापार का 4.53 प्रतिशत था। भारत और सऊदी अरब से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में; इंजीनियरिंग सामान, चावल, पेट्रोलियम उत्पाद, रसायन, कपड़ा, खाद्य उत्पाद, सिरेमिक टाइलें शामिल हैं। जबकि, सऊदी अरब से भारत के लिए आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं कच्चा तेल, एलपीजी, उर्वरक, रसायन, प्लास्टिक और इसके उत्पाद हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में सऊदी अरब तीसरा सबसे बड़ा क्रूड सोर्सिंग गंतव्य बना रहा। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए संचयी एफडीआई इंक्रीटी प्रवाह लगभग 20.04 मिलियन अमरीकी डॉलर था। राजस्थान के उद्योग और वाणिज्य राज्य मंत्री ने भी व्यापार संवर्धन के लिए रियाद का दौरा किया।

रक्षा और सुरक्षा सहयोग

जनवरी में रॉयल सऊदी नौसेना बल के चीफ ऑफ स्टाफ एडमिरल फहद अल-गुफेली की भारत की पहली आधिकारिक यात्रा के साथ, रक्षा सहयोग ने नई ऊंचाइयों को छुआ। तत्कालीन राज्य मंत्री (रक्षा) ने 04-08 फरवरी को रियाद में दूसरे विश्व रक्षा प्रदर्शनी में भाग लिया। मुनिशन इंडिया लिमिटेड ने नादरा ट्रेडिंग कंपनी के साथ अपनी भागीदारी के माध्यम से सऊदी अरब को तोप व गोला-बारूद की आपूर्ति के लिए 225 मिलियन अमरीकी डॉलर के करार पर हस्ताक्षर किए। 29 जनवरी-10 फरवरी को राजस्थान में पहला भारत-सऊदी संयुक्त भूमि सेना युद्धाभ्यास "सदा तनसीक" आयोजित किया गया।

सऊदी वायु सेना के एक प्रतिनिधिमंडल ने 29 अगस्त-14 सितंबर को जोधपुर में आयोजित 'व्यायाम तरंग शक्ति' में पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया। रक्षा सहयोग पर संयुक्त समिति की छठी बैठक 3 सितंबर को रियाद में आयोजित की गई। भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल ने 19-21 नवंबर को दम्मम में तीसरे सऊदी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मंच में भाग लिया। भारत-सऊदी अरब रक्षा संगोष्ठी का दूसरा संस्करण 28 नवंबर को रियाद में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए पूरे वर्ष अधिकारियों और कैडेटों का नियमित आदान-प्रदान किया गया।

06-10 अक्टूबर को, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार से पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने किंग अब्दुलअजीज फाउंडेशन, रियाद में अभिलेखागार संरक्षण और जीर्णोद्धार पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।

भारतीय कला और सांस्कृतिक समूहों ने सऊदी सरकार द्वारा आयोजित वार्षिक रियाद सीज़न 2024 में भाग लिया। सऊदी अरब में रहने वाले भारतीयों की संख्या बढ़कर लगभग 2.65 मिलियन हो गई है।

यूएई

भारत-यूएई संबंध सदियों से चले आ रहे सहयोग पर आधारित हैं, जो मिद्धता और आपसी सम्मान के गहरे बंधन का परिचायक हैं। यह सहयोग महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ताओं के साथ जारी रहा है। दोनों देशों के नेताओं के बीच तीन उच्च-स्तरीय यात्राएँ की गई हैं। पूरे वर्ष के दौरान, दोनों देशों ने परिवर्तनकारी पहलों को आगे बढ़ाया है, ऐतिहासिक परियोजनाएँ शुरू की हैं और अपने दीर्घकालिक व्यापार, निवेश तथा ऊर्जा संबंधों को काफी सुदृढ़ किया है।

उच्च स्तरीय आदान-प्रदान

प्रधानमंत्री ने 13-14 फरवरी को यूएई का दौरा किया और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, और दुबई के शासक,

प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति तथा यूएई के तत्कालीन रक्षा मंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम से मुलाकात की। 14 फरवरी को, उन्होंने अबू धाबी में बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था (बीएपीएस) हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया, जो एक सांस्कृतिक प्रतीक बन गया है और जिसे देखने के लिए दस लाख से अधिक लोग आते हैं। प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान द्विपक्षीय निवेश संधि, भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईसी) पर अंतर-सरकारी फ्रेमवर्क समझौता (आईजीएफए), और डिजिटल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (एनएमएचसी) पर समझौता ज्ञापन सहित महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए।

यूएई के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने 09-10 जनवरी को अहमदाबाद में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भारत का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान, नवप्रवर्तन स्वास्थ्य सेवा परियोजनाओं, नवीकरणीय ऊर्जा और खाद्य पार्क विकास में निवेश सहयोग के संदर्भ में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। 09-10 सितंबर को, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने भारत की आधिकारिक यात्रा की। इन उच्च-स्तरीय यात्राओं के दौरान, निवेश, आईएमईसी, नवीकरणीय ऊर्जा, खाद्य पार्क विकास, डिजिटल बुनियादी ढांचा, परमाणु, महत्वपूर्ण खनिजों, ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों और अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक भागीदारी को बढ़ावा मिला।



प्रधानमंत्री ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से अबू धाबी में मुलाकात की, फरवरी 2024



प्रधानमंत्री अबू धाबी में बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन करते हुए, फरवरी 2024



प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति एवं अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की उपस्थिति में भारत के विदेश मंत्री और यूएई के निवेश मंत्री मोहम्मद हसन अल सुवेदी गांधीनगर में एमओयू का आदान-प्रदान करते हुए, जनवरी 2024.



प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ गांधीनगर में बातचीत करते हुए, जनवरी 2024.



प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का स्वागत किया, सितंबर 2024

वर्ष के दौरान, विदेश मंत्री ने तीन बार यूएई का दौरा किया। वह फरवरी में प्रधानमंत्री के साथ और बाद में 23 जून और 14 नवंबर को भी यूएई के दौरे पर गए। 23 जून को, विदेश मंत्री ने अपने समकक्ष, यूएई के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। उन्होंने बहुआयामी भारत-यूएई व्यापक रणनीतिक भागीदारी की समीक्षा की और वाणिज्य, आर्थिक सहयोग, फिनटेक, शिक्षा, संस्कृति और दोनों पक्षों के नागरिकों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्रों में प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने आगे के सहयोग के लिए नए रास्ते तलाशे तथा क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। नवंबर में अपनी यात्रा के दौरान, विदेश मंत्री ने फिर से अपने समकक्ष से मुलाकात की तथा सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के दुबई परिसर का उद्घाटन किया।

भारत के विदेश मंत्री एवं यूएई के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान ने 12 दिसंबर को चौथी रणनीतिक वार्ता तथा 13 दिसंबर को नई दिल्ली में 15^{वीं} संयुक्त आयोग बैठक की सह-अध्यक्षता की।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने 27 फरवरी से 01 मार्च तक यूएई का दौरा किया, जिसमें व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) के तहत व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। अबू धाबी निवेश प्राधिकरण के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नाहयान ने संप्रभु निवेशों में सहयोग को गहरा करने पर चर्चा करने के लिए 7 अक्टूबर को भारत का दौरा किया।

22 अक्टूबर को, यूएई के निवेश मंत्री मोहम्मद हसन अलसुवैदी ने राजस्थान का दौरा किया तथा 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के विकास

की संभावना तलाशने के लिए राज्य के साथ एक निवेश ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

भारत-यूएई के पास कई क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए मजबूत संस्थागत तंत्र हैं। वर्ष के दौरान, इनमें से अधिकांश संस्थागत तंत्रों ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी की समीक्षा करने तथा इसे और अधिक आगे बढ़ाने के लिए मुलाकात की। वर्ष के दौरान आयोजित प्रमुख बैठकों में, 7 मई को नई दिल्ली में संयुक्त सुरक्षा समिति की 4^{वीं} बैठक, 14 मई को नई दिल्ली में कांसुलर मामलों की संयुक्त समिति की 5^{वीं} बैठक, 08 जुलाई को अबू धाबी में तीसरी सेना-से-सेना स्टाफ वार्ता और 8^{वीं} नौसेना-से-नौसेना स्टाफ वार्ता, 08-09 जुलाई को 12^{वीं} संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक, 07 अक्टूबर को मुंबई में निवेश पर यूएई-भारत उच्च स्तरीय संयुक्त टास्क फोर्स की 12^{वीं} बैठक और 10 अक्टूबर को दुबई में भारत-यूएई सीईपीए पर संयुक्त समिति की दूसरी बैठक शामिल है।

व्यापार और आर्थिक सहयोग

भारत-यूएई व्यापार और निवेश संबंधों में 2023-24 में काफी वृद्धि हुई। द्विपक्षीय व्यापार 83.64 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया है, जिसमें यूएई से भारत का आयात कुल 48 बिलियन अमरीकी डॉलर और यूएई को निर्यात 35.62 बिलियन अमरीकी डॉलर था। यूएई को भारतीय निर्यात में 12.71 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जिससे यूएई भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य और तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। यूएई भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए संचयी एफडीआई

इक्विटी प्रवाह लगभग 2.92 बिलियन अमरीकी डॉलर था। अप्रैल से सितंबर तक, यूएई भारत के समग्र एफडीआई इक्विटी प्रवाह में चौथा सबसे बड़ा योगदानकर्ता था। दोनों देशों ने पारंपरिक और नवीकरणीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, फूड पार्क, स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल बुनियादी ढांचे में निवेश सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

भारत और यूएई के बीच 13 फरवरी को हस्ताक्षरित द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) 31 अगस्त को प्रभावी हुई, जिससे सितंबर 2024 में 2013 के द्विपक्षीय निवेश संवर्धन और संरक्षण समझौते (बीआईपीपीए) की समाप्ति के बाद निरंतर निवेश संरक्षण सुनिश्चित होगा।

ऊर्जा सहयोग

भारत-यूएई ऊर्जा सहयोग भी नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। सितंबर में, इंडियन स्ट्रैटिजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और यूएई की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (एडीएनओसी) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, ताकि कार्यक्रम के चरण 2 में भारत में कच्चे तेल के भंडारण के अतिरिक्त अवसरों में एडीएनओसी की भागीदारी हो सके। एडीएनओसी और गेल के बीच जनवरी में एक दीर्घकालिक 0.5 एमएमटीपीए एलएनजी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। 2028 से 1 एमएमटीपीए की आपूर्ति के लिए सितंबर में आईओसीएल और एडीएनओसी के बीच एक और दीर्घकालिक एलएनजी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए।

09-10 सितंबर को अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की यात्रा के दौरान, जो इस क्षमता में उनकी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा थी, परमाणु सहयोग पर एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए, जो परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में दो देशों के परस्पर पहला अनुबंध है। इसके अतिरिक्त, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला में वैश्विक सहयोग के लिए इंटरनेशनल रिसोर्सेज होल्डिंग आरएससी लिमिटेड (आईआरएच) और ऑयल इंडिया लिमिटेड, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड तथा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन विदेश लिमिटेड सहित एक संघ (कंसोर्टियम) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता तीसरे देशों में अन्वेषण प्रयासों पर केंद्रित है, जिससे महत्वपूर्ण खनिजों के महत्वपूर्ण क्षेत्र में सहयोग के रास्ते खुलेंगे।

रक्षा और सुरक्षा सहयोग

भारत और यूएई ने पूरे वर्ष अपने रक्षा सहयोग को मजबूत किया, जैसा कि प्रतिनिधिमंडलों के आदान-प्रदान, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यासों से स्पष्ट है।

दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाने के चल रहे प्रयासों के भाग के रूप में, भारतीय नौसेना प्रमुख ने 20-25 अक्टूबर को यूएई का दौरा किया। उन्होंने भारत-यूएई द्विपक्षीय नौसेना युद्धाभ्यास (बीआईएलएटी) के तीसरे संस्करण में भाग लिया।

12^{वीं} संयुक्त रक्षा सहयोग समिति (जेडीसीसी) की बैठक 08-09 जुलाई को अबू धाबी में हुई। जेडीसीसी के दौरान दोनों देशों की नौसेना और सेना के बीच स्टाफ वार्ता भी हुई।

पहला संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास 'डेजर्ट साइक्लोन' 02-15 जनवरी को भारत में आयोजित किया गया। भारत-यूएई द्विपक्षीय नौसैनिक युद्धाभ्यास का तीसरा संस्करण अक्टूबर में आयोजित किया गया। यूएई में, यूएई वायु सेना ने सितंबर में भारत में युद्धाभ्यास 'तरंग शक्ति' में भी भाग लिया। पहला भारत-यूएई रक्षा भागीदारी मंच सितंबर में अबू धाबी में आयोजित किया गया, जिसमें दोनों पक्षों की कंपनियां और अधिकारी एक मंच पर साथ आए।



भारतीय सेना और यूएई थल सेना के सैनिक राजस्थान, भारत में पहले संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास 'डेजर्ट साइक्लोन' के दौरान प्रशिक्षण और सामरिक युद्धाभ्यास करते हुए, जनवरी 2024

यूएई में रहने वाले और वहां जाने वाले भारतीयों की संख्या में हर साल वृद्धि के साथ लोगों के बीच संबंध मजबूत बने हुए हैं। यूएई में दुनिया में भारतीय नागरिकों की सबसे बड़ी आबादी है, और यूएई में भारतीय समुदाय 3.5 मिलियन (2021) से बढ़कर 3.89 मिलियन (2024) हो गया है।

यूएई में 108 भारतीय पाठ्यचर्या स्कूल हैं। जुलाई में, यूएई और भारत से बाहर सीबीएसई स्कूलों को समर्थन देने के लिए दुबई में एक सीबीएसई क्षेत्रीय कार्यालय और उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया।

लिपक्षीय सहयोग

भारत-फ्रांस-यूएई लिपक्षीय फोकल प्वाइंट बैठक 09 जुलाई को वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए बुलाई गई। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव (यूरोप पश्चिम) और विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव (खाड़ी) ने किया। फ्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के

दक्षिण एशिया प्रभाग के प्रमुख टिमोथी टूले ने किया और यूएई पक्ष का नेतृत्व यूएई विदेश मंत्रालय में आर्थिक और व्यापार मामलों के सहायक मंत्री सईद मुबारक अल-हजेरी ने किया। प्रतिभागियों ने फरवरी 2023 में तीनों विदेश मंत्रियों द्वारा सहमत संयुक्त रोडमैप के तहत सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की समीक्षा की।

यमन

यमन के साथ भारत के संबंध सदियों पुराने हैं जिसकी आधारशिला दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध हैं। यमन में कठिन सुरक्षा स्थिति के बावजूद, दोनों देश घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देने के पक्षधर हैं। भारत बातचीत के माध्यम से संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध है, और उसका मानना है कि समाधान यमन के नेतृत्व में और यमन के राजनीतिक संकल्प के जरिए हो।

उच्च स्तरीय आदान-प्रदान

24 सितंबर को विदेश मंत्री ने न्यूयॉर्क में 79^{वाँ} यूएनजीए के इतर यमन गणराज्य के उपराष्ट्रपति मेजर जनरल ऐदारस कासिम अब्दुलअजीज अल-जुबैदी से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध यमन के लिए भारत के समर्थन पर पुनः बल दिया। यमन के शिक्षा मंत्री तारिक अल-अकबरी ने 17 अगस्त को आयोजित वीओजीजीएस के तीसरे संस्करण में भाग लिया।

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत और यमन के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार 1.067 बिलियन अमरीकी डॉलर था और इस अवधि के दौरान यमन को कुल निर्यात 875 मिलियन अमरीकी डॉलर था, जबकि कुल आयात 191 मिलियन अमरीकी डॉलर था।

यमनी विदेश मंत्रालय के दो अधिकारियों ने नई दिल्ली में डेटा फॉर डेवलपमेंट कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव (डी4डी-सीबीआई) पर आईटीईसी एजिक्यूटिव कोर्स सफलतापूर्वक पूरा किया। यह कोर्स 23-29 अक्टूबर को आयोजित किया गया।

2024 में, 48 यमनी छात्रों ने भारत में अध्ययन करने के लिए आईसीसीआर छात्रवृत्ति का लाभ उठाया।

भारत और यमन के बीच मजबूत रक्षा संबंध हैं। प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण इस सहयोग का एक प्रमुख घटक है। छह से अधिक यमनी कैडेट भारत के विभिन्न संस्थानों में प्रशिक्षण ले रहे हैं। दोनों देशों के तटरक्षकों के बीच भी मजबूत सहयोग तंतु है। एक यमनी तटरक्षक ने इस वर्ष भारत में एक लॉन्ग नेविगेशन कोर्स में भाग लिया।

पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र

वर्ष के दौरान, भारत ने विभिन्न राजनयिक, रक्षा और मानवीय पहलों के माध्यम से पश्चिम एशियाई और उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को काफी घनिष्ठ बनाया। द्विपक्षीय संबंधों के मुख्य आकर्षक बिंदुओं में, माननीय राष्ट्रपति जी की अल्जीरिया की ऐतिहासिक यात्रा शामिल है, जो

1962 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद किसी भी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की पहली यात्रा है। उच्च स्तरीय यात्राओं और सैन्य सहयोग समझौते के माध्यम से अल्जीरिया के साथ रक्षा सहयोग को और मजबूत किया गया। भारत ने मिस्र, इजरायल और मोरक्को के साथ अपने संबंधों को भी गहन बनाया, जिसमें रक्षा सहयोग से लेकर आर्थिक आदान-प्रदान और रणनीतिक संवाद शामिल हैं। भारत ने जुलाई में त्रिपोली में अपना दूतावास फिर से खोला।

भारत ने फिलिस्तीन को मानवीय सहायता प्रदान की, जिसमें चिकित्सा सहायता और यूएनआरडब्ल्यूए को वित्तीय सहायता का महत्वपूर्ण योगदान था, जबकि सूडान, सीरिया और दक्षिण सूडान में चिकित्सा और शैक्षिक आउटरीच जारी रही। लीबिया, ट्यूनीशिया और जिबूती में भी राजनयिक यात्राएँ और समझौते किए गए, जहाँ भारत ने क्षेत्रीय मानवीय प्रयासों में सक्रिय भूमिका निभाई।

इसके अतिरिक्त, जॉर्डन और सोमालिया के साथ भारत के संबंध में, सहयोगात्मक रक्षा बैठकें और व्यावसायिक वार्ताएँ शुमार हैं। इस वर्ष शैक्षिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान भी जारी रहा, जिसने पूरे क्षेत्र में गहरे संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को पुनः रेखांकित किया।

भारत ने विभिन्न बहुपक्षीय और क्षेत्रीय मंचों में भाग लिया, जो वाना (WANA) क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विदेश मंत्रालय के सचिव (सीपीवी और ओआईए) ने 25 अप्रैल को मास्को में मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका पर ब्रिक्स उप विदेश मंत्री की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। भारत ने 25 जुलाई को मध्य पूर्व के संदर्भ में 19^{वाँ} भारत-जापान परामर्श आयोजित किया, उसके बाद 27 नवंबर को पहला भारत-जर्मनी परामर्श आयोजित किया गया। दोनों परामर्शों का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव (वाना) ने किया।

अल्जीरिया

यह वर्ष भारत और अल्जीरिया के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण था।

उच्च स्तरीय आदान-प्रदान

माननीय राष्ट्रपति जी ने 13-16 अक्टूबर को अल्जीरिया की राजकीय यात्रा की, जो किसी भारतीय राष्ट्रपति की अल्जीरिया की पहली यात्रा थी। यह यात्रा और भी विशेष थी क्योंकि 17 सितंबर को राष्ट्रपति तेब्बौने के पांच साल का दूसरा कार्यकाल शुरू करने के बाद यह किसी राष्ट्राध्यक्ष की अल्जीरिया की पहली यात्रा थी। यात्रा के दौरान, पहली बार भारत-अल्जीरिया आर्थिक मंच का आयोजन किया गया। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच एक नए युग की शुरुआत हुई।

लोकसभा अध्यक्ष ने 14 अक्टूबर को जिनेवा में आयोजित अंतर-संसदीय संघ की 149^{वाँ} सभा के इतर अल्जीरिया की पीपुल्स नेशनल असेंबली



माननीय राष्ट्रपति जी की अगुवाई पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्देलमदजीद तेब्बौने ने की और उन्हें हवाई अड्डे पर गार्ड ऑफ ऑनर तथा औपचारिक स्वागत दिया गया, अक्टूबर 2024.

के अध्यक्ष से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने 28 सितंबर को न्यूयॉर्क में यूएनजीए के 79^{वें} सत्र के इतर अल्जीरियाई विदेश मंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने 30 नवंबर को उनके साथ टेलीफोन पर भी बात की, जिसमें उन्होंने उन्हें उनकी पुनर्नियुक्ति पर बधाई दी। 17 अगस्त को, अल्जीरियाई वित्त मंत्री लाजीज फैद ने वीओजीजीएस के तीसरे संस्करण के वित्त मंत्रियों के सत्र में भाग लिया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के निमंत्रण पर, अल्जीरियाई घरेलू व्यापार और राष्ट्रीय बाजार विनियमन मंत्री ने 02-03 दिसंबर को नई दिल्ली में आयोजित सीआईआई के 29^{वें} पार्टनरशिप समिट में भाग लेने और उसे संबोधित करने के लिए भारत का दौरा किया।

व्यापार और आर्थिक सहयोग

भारत-अल्जीरिया व्यापार 2023-24 में 1.73 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में अल्जीरिया को भारत के निर्यात में 38 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। भारतीय कंपनियों की अल्जीरिया में प्रमुख कार्यक्रमों में भारी उपस्थिति देखी गई। 48 भारतीय कंपनियों ने 05-07 फरवरी को अल्जीयर्स में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फार्मा प्रदर्शनी, 'मघरेब फार्मा' में भाग लिया। इसके अतिरिक्त, भारतीय निर्यात गठनों के महासंघ ने 22-25 अप्रैल को अल्जीयर्स में खाद्य उत्पादन के लिए इंटरनेशनल बिजनेस शो, दजाजाग्रो के 21^{वें} संस्करण में भाग लिया, जिसमें 32 भारतीय कंपनियों ने अपने उत्पाद प्रदर्शित किए। अपोलो हॉस्पिटल्स ग्रुप ने 03 मई को अल्जीयर्स में अल्जीरियन कार्डियोलॉजी सोसाइटी के लिए एक इंटरैक्टिव कार्डियोलॉजी सत्र का आयोजन किया।

दूतावास ने भारतीय चाय बोर्ड और दक्षिणी भारत के यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन के सहयोग से 01-03 फरवरी को अल्जीयर्स में नीलगिरी काली चाय सहित एक प्रदर्शनी 'टी टेस्टिंग एग्जिबिशन : चाय ऑफ इंडिया-इलिकसर ऑफ लाइफ' का आयोजन किया।

रक्षा और सुरक्षा सहयोग

अल्जीयर्स में भारतीय दूतावास में रक्षा विंग को 30 वर्षों के बाद जून में फिर से खोला गया। अल्जीरिया ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास में अपने रक्षा अताशे भी तैनात किया। पीपुल्स नेशनल आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ के निमंत्रण पर, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने 31 अक्टूबर से 03 नवंबर तक अल्जीरिया का दौरा किया और अल्जीरिया के स्वतंत्रता संग्राम की 70^{वीं} वर्षगांठ में भाग लिया। इस यात्रा के दौरान भारत और अल्जीरिया के बीच सैन्य सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

जिबूती

उच्च स्तरीय आदान-प्रदान

जिबूती के कृषि मंत्री मोहम्मद अहमद अवलेह ने खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) द्वारा 19-22 सितंबर को आयोजित विश्व खाद्य भारत में भाग लिया। जिबूती के ऊर्जा मंत्री योनिस अली गुएदी ने नई दिल्ली का दौरा किया और 03-06 नवंबर को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) सभा के 7^{वें} सत्र में भाग लिया।

रक्षा और सुरक्षा सहयोग

इस अवधि के दौरान जिबूती में भारतीय नौसेना के जहाजों के 33 ऑपरेशनल टर्न अराउंड (ओटीआर) दौरे किए। जिबूती सरकार ने भारतीय जहाजों के प्रवेश को मंजूरी दी और कम समय में उनके ओटीआर दौरों के लिए सुविधा प्रदान की। यह महत्वपूर्ण था क्योंकि भारतीय नौसेना ने भारतीय समुद्री हितों की रक्षा के लिए "ऑपरेशन संकल्प" के हिस्से के रूप में, इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाई है।

भारत-जिबूती बिजनेस फोरम का दूसरा संस्करण 28 नवंबर को आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ाना था। 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

मिस्र

भारत-मिस्र सामरिक भागीदारी मजबूत होती जा रही है। दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय आदान-प्रदान जारी रहा।



प्रधानमंत्री ने रूस के कज़ान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के इतर राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल-सीसी से मुलाकात की, अक्टूबर 2024

उच्च स्तरीय आदान-प्रदान

प्रधानमंत्री ने अक्टूबर में रूस में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और नवंबर में ब्राजील में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन के इतर राष्ट्रपति

अब्देल फत्ताह अल-सीसी से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने 03 अगस्त को विदेश मंत्री बद्र अहमद मोहम्मद अब्देलती से टेलीफोन पर बातचीत की। विदेश मंत्री ने सितंबर में 79^{वें} यूएनजीए के इतर फिर से मंत्री अब्देलती से मुलाकात की। पर्यटन राज्य मंत्री ने नवंबर में जी-7 बैठकों के इतर इटली में मिस्र के पर्यटन मंत्री शेरिफ फथी से मुलाकात की। मिस्र के विदेश उप मंत्री ने वीओजीजीएस के तीसरे संस्करण के विदेश मंत्रियों के सत्र में भाग लिया। लोकसभा अध्यक्ष ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित 10^{वें} ब्रिक्स संसदीय मंच के इतर मिस्र के स्पीकर से मुलाकात की। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने सितंबर में ह्यूस्टन में आयोजित गैसटेक-2024 के इतर मिस्र के अपने समकक्ष से मुलाकात की।

भारत और मिस्र के बीच विदेश कार्यालय परामर्श (एफओसी) का 13^{वां} दौर 05 दिसंबर को दिल्ली में आयोजित किया गया। एफओसी की सह-अध्यक्षता विदेश मंत्रालय के सचिव (सीपीवी एवं ओआईए) और एशियाई मामलों के लिए मिस्र के सहायक विदेश मंत्री अहमद शाहीन ने की। एफओसी ने भारत-मिस्र रणनीतिक भागीदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की तथा उसे और अधिक मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की।

सचिव (आवास और शहरी मामले) के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने नवंबर में काहिरा में 12^{वें} विश्व शहरी मंच में भाग लिया।

मिस्र की हया करीम परियोजना का अध्ययन करने के लिए नीति आयोग के एक 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 02-10 मार्च को मिस्र का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल ने यात्रा के दौरान स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र, असवान, लक्सर और अलेक्जेंड्रिया का भी दौरा किया।

व्यापार और आर्थिक सहयोग

मिस्र पारंपरिक रूप से अफ्रीकी महाद्वीप में भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदारों में से एक रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार 4.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। जनरल अर्थोरेटी फॉर इन्वेस्टमेंट एंड फ्री जोन्स (जीएफआई) के अध्यक्ष होसाम हेइबा के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने अगस्त में नई दिल्ली में सीआईआई-भारत-भूमध्यसागरीय व्यापार सम्मेलन में भाग लिया। प्रतिनिधिमंडल ने कई भारतीय कंपनियों, सीआईआई, स्टार्टअप इंडिया, इन्वेस्ट इंडिया और वाणिज्य मंत्रालय सहित व्यापार संवर्धन निकायों के साथ बातचीत की। भारत और मिस्र के बीच संयुक्त व्यापार समिति की 6^{वां} बैठक सितंबर में नई दिल्ली में हुई। जेटीसी ने विभिन्न द्विपक्षीय व्यापार मुद्दों पर चर्चा की जिसके बाद एक संयुक्त व्यापार आयोग की बैठक हुई। भारत और मिस्र के बीच विशेष रुपया VOSTRO खाता अब कार्यात्मक है, जिसके लिए मिस्र ने एसबीआई में बैंक खाता खोला है। हमारे देश स्थानीय मुद्राओं में व्यापार कर सकते हैं, जिससे निवेश और सहयोग के नए रास्ते खुलेंगे।

मिस्र के पेशेवरों के क्षमता निर्माण के लिए भारत की प्रतिबद्धता अटूट है। इस वर्ष, नियमित आईटीईसी पाठ्यक्रमों के अलावा, मिस्र के निवेश और विदेश व्यापार मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय को क्रमशः मैरी चन्ना रेड्डी मानव संसाधन विकास संस्थान (एमसीएचआरडी) हैदराबाद और राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी (एनएडीटी) नागपुर में दो कस्टमाइज्ड पाठ्यक्रम प्रदान किए गए।

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईआईएलआईटी), आईआईटी गांधीनगर और आईआईआईटीएम ग्वालियर के चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मार्च में मिस्र का दौरा किया और आईटी के क्षेत्र में सहयोग ज्ञापन को लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता ज्ञापन मार्च में मैती (MeITY) के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी संस्थान और मिस्र के आईटी संस्थान के बीच किया गया था।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) लिमिटेड के एक प्रतिनिधिमंडल ने एनएसआईसी के सीएमडी के नेतृत्व में 11-14 दिसंबर को काहिरा में आयोजित *तुरत्ता* (हमारी विरासत) प्रदर्शनी में भाग लिया। 12 दिसंबर को व्यापार मेले के दौरान राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) और मिस्र की सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास एजेंसी (एमएसएमडीई) के बीच एमएसएमडीई क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

रक्षा और सुरक्षा सहयोग

भारत और मिस्र के बीच रक्षा सहयोग प्रबल है जिसका आधार नियमित उच्च स्तरीय आदान-प्रदान, संयुक्त युद्धाभ्यास, प्रदर्शनियों में भागीदारी और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हैं। 10^{वीं} संयुक्त रक्षा समिति (जेडीसी) की बैठक जुलाई में नई दिल्ली में आयोजित की गई। जेडीसी ने रक्षा सहयोग को और अधिक मजबूत करने में सहायता की। 21-26 जून को द्विपक्षीय वायु सेना युद्धाभ्यास किया गया। सारंग हेलीकॉप्टर प्रदर्शन टीम ने सितंबर में पहले मिस्र अंतर्राष्ट्रीय एयरशो में भाग लिया। भारत ने नवंबर-दिसंबर में मिस्र द्वारा आयोजित टैक्टिकल लीडरशिप प्रोग्राम में भी भाग लिया। इस भागीदारी ने दोनों पक्षों को परिचालन संबंधी जानकारी प्रदान की।

मिस्र ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया।

इरिट्रिया राज्य

दूसरा भारत-इरिट्रिया विदेश कार्यालय परामर्श 15 मई को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। चर्चाओं में विकास सहयोग और क्षमता निर्माण के साथ-साथ आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों सहित द्विपक्षीय संबंधों की पूरी श्रृंखला को कवर किया गया।

विकास भागीदारी का मुख्य क्षेत्र, क्षमता निर्माण और मानव संसाधन रहा है। भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) के तहत इरिट्रिया को 60 स्लॉट आवंटित किए गए, जो पिछले वर्ष से 20 स्लॉट की वृद्धि है। 2024-25 में भारत-अफ्रीका मैत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत आईसीसीआर द्वारा स्नातकपूर्व/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 12 छात्रवृत्तियां प्रदान की गई हैं। इरिट्रिया के 10 आईसीसीआर शोधार्थी भारत में अध्ययन कर रहे हैं।

इजराइल

भारत और इजराइल ने पूरे वर्ष मजबूत राजनीतिक चर्चाएं जारी रखीं। प्रधानमंत्री को 6 जून को उनके पुनः चुनाव पर इजराइली समकक्ष द्वारा

बधाई कॉल की गई। दोनों देशों के बीच नियमित संचार भी किया गया। विदेश मंत्री ने 14 अप्रैल, 13 जून और 18 दिसंबर को इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सा'आर के साथ टेलीफोन पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण अवसरों पर एक दूसरे को शुभकामनाएं दीं। माननीय राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने 14 मई को अपने इजरायली समकक्षों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं और 02 अक्टूबर को रोश हशनाह की शुभकामनाएं दीं।

उच्च स्तरीय आदान-प्रदान

इस वर्ष दोनों पक्षों की ओर से महत्वपूर्ण यात्राएं की गईं। परिवहन, राष्ट्रीय अवसंरचना और सड़क सुरक्षा मंत्री मिरी रेगेव ने 01-06 सितंबर को भारत का दौरा किया और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री; बिजली, आवास और शहरी मामले मंत्री; नागरिक उड्डयन मंत्री; पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री के साथ बैठकें कीं। इजरायल के अर्थव्यवस्था और उद्योग मंत्री नीर बरकत ने 02-03 दिसंबर को सीआईआई पार्टनरशिप समिट में भाग लिया और विदेश मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री से मुलाकात की। पूर्व इजरायली प्रधानमंत्री एहुद ओलमर्ट ने 22-27 फरवरी को भारत में फर्स्टपोस्ट डिफेंस समिट में भाग लिया। 28-29 अगस्त को, 17^{वीं} भारत-इजराइल विदेश कार्यालय परामर्श (एफओसी) आयोजित किया गया, जिस दौरान विदेश सचिव और विदेश मंत्रालय के महानिदेशक (डीजी) याकोव ब्लिटश्टाइन ने द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण पहलुओं की समीक्षा की। डीजी ब्लिटश्टाइन ने विदेश मंत्री से भी मुलाकात की और विदेश सचिव, विदेश मंत्रालय के सचिव (ईआर), विदेश मंत्रालय तथा उप एनएसए के साथ बैठकें कीं। मध्य पूर्व मामलों के लिए उप महानिदेशक (डीडीजी) ने 03-04 जून को भारत का दौरा किया और विदेश मंत्रालय के सचिव (ईआर), संयुक्त सचिव (वाना), संयुक्त सचिव (पीएआई), संयुक्त सचिव (खाड़ी) और संयुक्त सचिव (ईडी) के साथ बैठकें कीं। संयुक्त सचिव (सीपीवी), विदेश मंत्रालय, के नेतृत्व में तीसरा कांसुलर संवाद 12 नवंबर को इजराइल में आयोजित किया गया।

अक्टूबर तक, इजराइल में लगभग 32,000 भारतीय कामगार थे। इसमें 6583 ऐसे भारतीय कामगार शामिल हैं, जो 'इजराइल राज्य में विशिष्ट श्रम बाजार क्षेत्रों में भारतीय कामगारों के अस्थायी रोजगार को सुगम बनाने और उसके कार्यान्वयन नवाचार' पर समझौता के तहत इजराइल गए थे।

भारत ने 30 जनवरी को एलायंस फ्रांसेसे द्वारा आयोजित एक समारोह में तत्कालीन राज्य मंत्री (आरआरएस) की भागीदारी के साथ अंतर्राष्ट्रीय नरसंहार स्मृति दिवस मनाया।

पूरे वर्ष के दौरान बहुआयामी वार्तालापों ने राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा आयामों में मजबूत भारत-इजरायल रणनीतिक भागीदारी को प्रदर्शित किया।

जॉर्डन

भारत और जॉर्डन के बीच साझा मैत्रीपूर्ण संबंध मजबूत बने रहे हैं। इस अवधि में भारत और जॉर्डन के बीच बहुआयामी संबंध और भी गहन हुए

हैं। विदेश मंत्री ने 27 सितंबर को न्यूयॉर्क में 79^{वें} यूएनजीए शिखर सम्मेलन के इतर जॉर्डन के विदेश मंत्री अयमान सफादी से मुलाकात की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। जॉर्डन ने मिस्र और संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर 'कॉल फॉर एक्शन: अर्जेंट ह्यूमेनिटेरियन रिस्पोंस फॉर गाज़ा' सम्मेलन की सह-मेजबानी की, जिसमें 11 जून को विदेश मंत्रालय के सचिव (सीपीवी और ओआईए) ने भाग लिया।

रक्षा और सुरक्षा सहयोग

अप्रैल-मई में, जॉर्डन रॉयल नेवी से एक तीन सदस्यीय जॉर्डन प्रतिनिधिमंडल ने द्वितीय संयुक्त रक्षा सलाहकार बैठक के फ्रेमवर्क के भीतर दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि का दौरा किया। जॉर्डन सशस्त्र बलों की रॉयल मेडिकल सर्विसिस से एक और चार सदस्यीय रक्षा प्रतिनिधिमंडल ने अप्रैल में भारत का दौरा किया, जो रक्षा पर द्वितीय भारत-जॉर्डन सलाहकार बैठक के तत्वावधान में एक सैन्य प्रशिक्षण विनिमय कार्यक्रम का हिस्सा था।

जॉर्डन के तत्कालीन पर्यटन मंत्री मकरम मुस्ताफा केशी ने यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46^{वें} सत्र में भाग लेने के लिए जुलाई में भारत का दौरा किया। उन्होंने पर्यटन मंत्री से मुलाकात की।

लेबनान

यह वर्ष भारत और लेबनान के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना का 70^{वां} वर्ष है। विदेश मंत्री ने 25 नवंबर को रोम भूमध्यसागरीय वार्ता के इतर लेबनान के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बी हबीब से बातचीत की। लेबनान के वित्त मंत्री यूसुफ अल खलील ने 17 अगस्त को वीओजीजीएस के तीसरे संस्करण के वित्त मंत्रियों के सत्र में वर्चुअल रूप से भाग लिया।



विदेश मंत्री ने रोम भूमध्यसागरीय वार्ता के दौरान लेबनान के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बी हबीब से मुलाकात की, रोम, इटली, नवंबर 2024

सीरिया से राष्ट्रपति बशर अल असद के देश छोड़ देने के बाद और विद्रोही समूह हयात तहरीर अल शाम (एचटीएस) द्वारा दमिश्क पर कब्ज़ा करने के बाद सीरिया से 77 भारतीय नागरिकों को निकालने के दौरान, दुतावास ने दमिश्क से बेरुत तक भारतीय नागरिकों को पहुंचने में सुविधा प्रदान की और लेबनान में उनके ठहरने की भी व्यवस्था की।

बहुपक्षीय सहयोग

लेबनान के ऊर्जा और जल मंत्री वालिद फयाद द्वारा 21 अगस्त को आईएसए फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ, लेबनान अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) का सदस्य बन गया।

मानवीय सहायता

अक्टूबर में, भारत ने हृदयरोग संबंधी दवाएँ, एनएसएआईडी (गैर-स्टेरोइडल एंटी-इंफ्लेमेटरी ड्रग्स), एंटी-इंफ्लेमेटरी एजेंट्स, एंटीबायोटिक्स और एनेस्थेटिक्स सहित 33 टन दवाएँ उपहार में दीं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री फिरास अबियाद ने यह खेप प्राप्त की।

लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल (यूनिफिल)

यूएनआईएफआईएल में भारतीय बटालियन, जहां दक्षिण लेबनान में शांति स्थापना के लिए लगभग 900 कर्मी तैनात हैं, ने नवंबर में 26 वर्ष पूरे किए।

लीबिया

भारत और लीबिया के बीच पारंपरिक रूप से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं, जो इस वर्ष के दौरान भी मजबूत होते गए। 27-28 मई को लीबिया के राजनीतिक मामलों के उप मंत्री मोहम्मद खलील इस्सा ने भारत का दौरा किया और तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री (वीएम) से मुलाकात की और सचिव (सीपीवी एवं ओआईए), विदेश मंत्रालय; सचिव (ईआर), विदेश मंत्रालय और सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ सफल बैठकें कीं। प्रतिनिधिमंडल ने सीआईआई, फिक्की और पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सहित बिजनेस चैंबर्स से भी मुलाकात की।

लीबिया में भारत का मिशन 22 जुलाई को फिर से खोला गया और 6 अगस्त को भारतीय नागरिकों के लीबिया जाने पर प्रतिबंध में ढील दी गई। यह दर्शाता है कि भारत द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए कितना प्रतिबद्ध है।

भारत ने 11-20 दिसंबर को सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान में 10 लीबियाई राजनयिकों के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम आयोजित किया।

मोरक्को

भारत और मोरक्को के बीच मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। विदेश मंत्री ने 25 सितंबर को यूएनजीए के 79^{वें} सत्र के इतर न्यूयॉर्क में मोरक्को के विदेश



भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े का फ्रंटलाइन फ्रिगेट आईएनएस तबर तीन दिवसीय यात्रा के लिए मोरक्को के कैसाब्लांका पहुंचते हुए, जुलाई 2024

मंत्री नासिर बोरीता से मुलाकात की। मोरक्को के उद्योग और व्यापार मंत्री रियाद मेज़ूर ने भारत का दौरा किया और 10-12 जनवरी को वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 में भाग लिया। उन्होंने वाणिज्य और उद्योग मंत्री से भी मुलाकात की। मोरक्को की ऊर्जा संक्रमण और सतत विकास मंत्री लीला बेनाली ने 17 अगस्त को वीओजीएसएस के तीसरे संस्करण के ऊर्जा मंत्रियों के सत्र में भाग लिया। जल संसाधन पर भारत-मोरक्को संयुक्त कार्यसमूह की चौथी बैठक 20 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित की गई जिसमें जल प्रबंधन और संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई।

भारतीय नौसेना के जहाज 'तबर' ने ठहराव लेने के लिए 08-11 जुलाई को कैसाब्लांका बंदरगाह का दौरा किया और रॉयल मोरक्कन नेवी के साथ पासेक्स संचालित किया। मोरक्को के राष्ट्रीय रक्षा प्रशासन और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (टीएएसएल) ने 27 सितंबर को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स - मोरक्को (टीएएसएम) प्लांट में ग्राउंड कॉम्बैट व्हीकल (WhAP 8x8) का स्थानीय उत्पादन करना है। भारत-मोरक्को रक्षा औद्योगिक संगोष्ठी 09-10 दिसंबर को रबात में आयोजित की गई, जिस दौरान लगभग 13 भारतीय कंपनियों ने मोरक्को के रक्षा अधिकारियों के विभिन्न हितधारकों के समक्ष अपने उत्पादों, प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया।

मोरक्को के 150 अधिकारियों ने 1 जनवरी से 15 दिसंबर के बीच विभिन्न आईटीईसी/ई-आईटीईसी पाठ्यक्रमों में भाग लिया। मोरक्को एजेंसी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट (एमएसडीएन), राष्ट्रीय विद्युत एवं पेयजल कार्यालय (ओएनईई), राष्ट्रीय विद्युत विनियामक प्राधिकरण (एएनआरई) तथा ऊर्जा संक्रमण एवं सतत विकास मंत्रालय के अधिकारियों के लिए सीमा पार ऊर्जा व्यापार पर एक विशेष आईटीईसी पाठ्यक्रम आयोजित किया गया। यह

पाठ्यक्रम 29 अप्रैल से 3 मई तक एनटीपीसी स्कूल ऑफ बिजनेस में आयोजित किया गया।

फिलिस्तीन

भारत ने इजरायल-हमास संघर्ष के बीच फिलिस्तीनी लोगों को अपना निरंतर समर्थन दिया। सितंबर में, प्रधानमंत्री ने 79^{वें} यूएनजीए के इतर न्यूयॉर्क में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने 20 जनवरी को युगांडा के कंपाला में एनएएम शिखर सम्मेलन के इतर तत्कालीन फिलिस्तीनी विदेश मंत्री रियाद अल-मलिकी से मुलाकात की। फिलिस्तीन के कृषि मंत्री रेजक बशीर-सालिमिया 18-23 सितंबर को आयोजित विश्व खाद्य भारत के तीसरे संस्करण में भाग लेने के लिए भारत आए। अपनी यात्रा के दौरान, उन्होंने भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के साथ भी बैठक की।

विकास सहायता

भारत फिलिस्तीन का एक उत्सुक विकास सहायता भागीदार है। वर्तमान में, फिलिस्तीनी लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए फिलिस्तीन में भारत की 40 मिलियन अमरीकी डालर की विकास परियोजनाएँ चल रही हैं। इन परियोजनाओं में जेनिन गवर्नरेट में सुपर-स्पेशलिटी अस्पताल, इंडिया फिलिस्तीन सेंटर फॉर एम्पावरिंग वूमन तुराथी (माई हेरिटेज) परियोजना और फिलिस्तीन में राष्ट्रीय प्रिंटिंग प्रेस की कमीशनिंग शामिल है। हमने फिलिस्तीन में कल्किलिया, नब्लस और बेथलहम में तीन त्वरित प्रभाव परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर

किए हैं। भारत ने आईसीसीआर छात्रवृत्ति के माध्यम से फिलिस्तीन में क्षमता निर्माण की सुविधा भी प्रदान की।

मानवीय सहायता

भारत ने 2024 में फिलिस्तीनी लोगों के लिए अपनी मानवीय सहायता जारी रखी है। अक्टूबर और नवंबर में, भारत ने यूएनआरडब्ल्यूए और फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय दोनों को 65 टन जीवन रक्षक दवाएँ भेजीं। इसके अतिरिक्त, भारत ने यूएनआरडब्ल्यूए को अपना वार्षिक समर्थन जारी रखा, जिसमें दो किस्तों में, यानी एक जून में और दूसरी नवंबर में, कुल 5 मिलियन अमरीकी डॉलर का योगदान दिया गया।

सूडान

सूडान के साथ द्विपक्षीय सहयोग आमतौर पर सौहार्द और मैत्रीपूर्ण रहा है। चेन्नई, भारत के कावेरी अस्पताल से भारतीय डॉक्टरों की एक टीम ने 25 मई को पोर्ट सूडान का दौरा किया जहाँ उसने सी पोर्ट कॉर्पोरेशन के सहयोग से 4 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किया।

सूडान के साथ क्षमता निर्माण विकास सहयोग कार्यक्रम के लिए भारत की प्रतिबद्धता के अनुसार, आईसीसीआर हर साल भारत में उच्च शिक्षा के लिए 60 छात्रवृत्तियाँ प्रदान करता है, जिनका 2024-25 में पूर्ण रूप से उपयोग किया गया है। चूंकि आईसीसीआर छात्रवृत्तियों के लिए अधिक आवेदन आए थे, इसलिए 2024-25 में भारत-अफ्रीका मैत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत सूडानी छात्रों को 12 अतिरिक्त छात्रवृत्तियाँ प्रदान की गईं। इनका भी पूर्ण रूप से उपयोग किया गया है।

दक्षिण सूडान

दक्षिण सूडान के साथ द्विपक्षीय संबंध आमतौर पर मधुर और मैत्रीपूर्ण हैं। वर्ष के दौरान, दक्षिण सूडान में भारत सरकार द्वारा समर्थित तीन त्वरित प्रभाव परियोजनाएँ शुरू की गईं। पहली परियोजना के तहत दक्षिण सूडान में यूएन मिशन (यूएनएमआईएसएस) के अंतर्गत तैनात भारतीय बटालियनों (इंडबैट) द्वारा आठ पशुचिकित्सा सहायता शिविर स्थापित किए गए जिसके लिए भारतीय बटालियनों ने भारत से दवाइयाँ खरीदीं ताकि पशुधन स्वास्थ्य की गंभीर जरूरतों की पूर्ति की जा सके। दूसरी परियोजना के अंतर्गत एक प्रेक्षणशाला भूकंपीय केंद्र अर्थात ऑब्जर्वेटरी सीस्मिक स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। इस केंद्र के अंतर्गत एक नियंत्रण कक्ष, कार्यालय, बैठक कक्ष और प्रेक्षणशाला शामिल हैं। प्रेक्षणशाला तैयार होने के बाद, जिसे नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी (एनईएचयू) शिलांग द्वारा दान स्वरूप दिया गया है, एक सीस्मोग्राफ स्थापित किया जाएगा। तीसरी परियोजना के अंतर्गत जुबा में दक्षिण सूडान लर्निंग सेंटर (एसएसएलसी) का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इस सेंटर ने 2012 से 2015 तक पैन अफ्रीकी ई-नेटवर्क परियोजना के तहत तकनीकी प्रशिक्षण और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए एक केंद्र

के रूप में कार्य किया था, लेकिन 2016 में गृहयुद्ध के दौरान इसे बंद कर दिया गया था। अब यह पुनर्निर्मित केंद्र ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को फिर से शुरू करने में सुविधा प्रदान करने के लिए उन्नत सुविधाएँ, उपकरण और यंत्र प्रदान करेगा।

विदेश मंत्रालय द्वारा 11-20 दिसंबर को सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान (एसएसआईएसएस), नई दिल्ली में दक्षिण सूडान के राजनयिकों के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया। दक्षिण सूडान से पन्द्रह राजनयिकों ने इस पाठ्यक्रम में भाग लिया।

सूचना, संचार प्रौद्योगिकी और डाक सेवा उप मंत्री जैकब मैजू कोरोक ने 14-24 अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजित विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा (डब्ल्यूटीएसए) में भाग लिया। दक्षिण सूडान ने 21-31 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित 46^{वाँ} विश्व विरासत सम्मेलन में एक पर्यवेक्षक के रूप में भी भाग लिया।

भारत ने आईटीईसी कार्यक्रम के माध्यम से क्षमता निर्माण पर अपना फोकस जारी रखा और दक्षिण सूडानी नागरिकों द्वारा 100 से अधिक प्रशिक्षण स्लॉट का उपयोग किया गया। इसके अलावा, वर्ष के दौरान भारत में उच्च शिक्षा के लिए 30 दक्षिण सूडानी छात्रों को आईसीसीआर छात्रवृत्ति प्रदान की गई।

सोमालिया

भारत और सोमालिया के बीच हिंद महासागर में ऐतिहासिक व्यापार संबंधों में निहित एक दीर्घकालिक भागीदारी है। यह संबंध लगातार बढ़ता रहा जिसे मजबूत राजनयिक और आर्थिक सहयोग प्रयासों से बल मिला।



विदेश मंत्री ने न्यूयॉर्क में 79^{वाँ} यूएनजीए के इतर सोमालिया के विदेश मामले और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री अहमद मोआलिम फिकी से मुलाकात की, सितंबर 2024

विदेश मंत्री ने सितंबर में न्यूयॉर्क में 79^{वें} यूएनजीए के इतर सोमालिया के विदेश मामले और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री अहमद मोआलिम फिकी से मुलाकात की।

इस भागीदारी के तहत दोनों पक्षों के नागरिकों के परस्पर संबंध प्राथमिक शक्ति के रूप में कार्य कर रहा है। संबंध को अधिक सुदृढ़ करने और सोमाली नागरिकों को भारतीय वीजा जारी करने में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए, अदीस अबाबा में भारतीय दूतावास के अलावा, नैरोबी में भारतीय उच्चायोग को भी सोमाली नागरिकों के लिए वीजा जारी करने वाले गंतव्य के रूप में जोड़ा गया।

विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव (डब्ल्यूएनए) के नेतृत्व में भारत सरकार के एक प्रतिनिधिमंडल ने 04-05 मार्च के दौरान सोमालिया का दौरा किया और मोगादिशु में स्थिति का व्यापक रूप से आकलन किया और सोमालिया सरकार के साथ बातचीत की। प्रतिनिधिमंडल ने सोमालिया सरकार के वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों से मुलाकात की, जिनमें न्याय और संवैधानिक मामलों

के मंत्री हसन मोआलिम मुहम्मद शेखली, उप विदेश मंत्री इसाक मोहम्मद मुर्सल, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री हिरसी जामा गन्नी और सोमालिया के विदेश मंत्रालय में स्थायी सचिव हमजा अदन हादो शामिल थे।

सोमाली वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अब्दिसलाम शरीफ हुसैन 19-30 अगस्त को भारत आए और 19^{वें} सीआईआई इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया। अपनी यात्रा के दौरान, उन्होंने 28 अगस्त को वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री के साथ बैठक की और नई दिल्ली में व्यापारिक संगठनों के साथ कई चर्चाएँ कीं।

सीरिया

सीरिया के साथ मधुर और ऐतिहासिक संबंधों में इस साल नए घटनाक्रम जुड़े। 26 सितंबर को, विदेश मंत्री ने न्यूयॉर्क में 79^{वें} यूएनजीए शिखर सम्मेलन के इतर सीरिया के तत्कालीन विदेश मंत्री बासम सब्बाग से



विदेश मंत्री ने न्यूयॉर्क में 79^{वें} यूएनजीए के इतर तत्कालीन सीरियाई विदेश मंत्री बासम सब्बाग से मुलाकात की, सितंबर 2024



भारत ने सीरिया को लगभग 1400 किलोग्राम कैसर रोधी दवाएँ भेजीं, अगस्त 2024

मुलाकात की। सीरिया के तत्कालीन विदेश मंत्री फैसल मेकदाद ने अगस्त में वर्चुअल रूप से आयोजित वीओजीएसएस के तीसरे संस्करण में भाग लिया। तत्कालीन अर्थव्यवस्था और विदेश व्यापार उप मंत्री रानिया अहमद ने 6 सितंबर को नई दिल्ली में प्रथम सीआईआई इंडिया मेडिटेरेनियन बिजनेस कॉन्क्लेव में भाग लिया।

भारत और सीरिया ने नौ साल के अंतराल के बाद एफओसी की फिर से बैठक की। 29 नवंबर को, एफओसी का छठा दौर नई दिल्ली में आयोजित किया गया। सीरियाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सीरिया के तत्कालीन विदेश मामलों और निर्वासन उप मंत्री अयमान राद ने किया।

भारत ने सीरिया को मानवीय सहायता देना प्रदान की। अगस्त में सीरिया को लगभग 1400 किलोग्राम कैंसर रोधी दवाएँ भेजी गईं।

भारतीय नागरिकों की निकासी

दिसंबर में सीरिया में बड़े घटनाक्रम हुए। राष्ट्रपति बशर अल असद ने सीरिया छोड़ दिया और विद्रोही समूह हयात तहरीर अल शाम (एचटीएस) द्वारा दमिश्क पर कब्जा कर लिया गया। दमिश्क में स्थित भारतीय दूतावास ने बेरुत में भारतीय दूतावास के साथ मिलकर दमिश्क से बेरुत तक 77 भारतीय नागरिकों की निकासी में सफलतापूर्वक समन्वय किया।

ट्यूनीशिया

भारत ने साझा मूल्यों और साझा सिद्धांतों के आपसी सम्मान के आधार पर, ट्यूनीशिया के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध साझा किए हैं। अंतरिक्ष सहयोग पर दूसरा संयुक्त कार्यसमूह 15 फरवरी को इसरो और ट्यूनीशिया के सेंटर नेशनल डी कार्टोग्राफी एट डी टेलीडिटेक्शन (सीएनसीटी) के बीच

आयोजित किया गया। भारत ने रिमोट सेंसिंग, टेरेन मैपिंग और क्षमता निर्माण में अपनी विशेषज्ञता पेश की। ट्यूनीशिया के एल'इंसटेंस सुपीरियर इंडिपेंडेंट पोर लेस इलेक्शंस (आईएसआईई) के अधिकारियों ने अप्रैल-मई में हुए संसदीय चुनावों के मद्देनजर, चुनाव प्रक्रिया का निरीक्षण करने के लिए भारत का दौरा किया।

सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम 2024-27 के तहत, फरवरी में, कुल 23 ट्यूनीशियाई कलाकारों सहित 02 प्रतिनिधिमंडलों ने भारत द्वारा पूर्ण रूप से वित्तपोषित सूरजकुंड शिल्प मेला उत्सव में भाग लिया। एक 8 सदस्यीय दल ने भी फरवरी में केरल सरकार द्वारा आयोजित केरल अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच महोत्सव में रंगमंच कलाकारों के भाग लिया।

व्यापार और आर्थिक सहयोग

जनवरी-अक्टूबर की अवधि में ट्यूनीशिया को भारतीय निर्यात 491.72 मिलियन अमरीकी डॉलर था, जबकि कुल द्विपक्षीय व्यापार 608.6 मिलियन अमरीकी डॉलर था। ट्यूनीशिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर ट्रांजिशन, ओउएलचौचेन ने ऊर्जा सत्र में भाग लिया, जबकि टेक्नोपार्क के अध्यक्ष एवं महानिदेशक एल गाज़ेला सोफ़ि़एने हेमिसी ने 17 अगस्त को वीओजीएसएस के वर्चुअल तीसरे संस्करण के आईटी सत्र में भाग लिया। भारतीय आर्थिक व्यापार संगठन (आईईटीओ) और भारत-अफ्रीका व्यापार परिषद के अध्यक्ष ने सितंबर में ट्यूनीस में आयोजित भारत-ट्यूनीशिया सम्मेलन में 'अफ्रीका में निवेश व्यापार के वित्तपोषण' पर सत्र में मॉडरेटर के रूप में भाग लिया।

इस वर्ष ट्यूनीशिया द्वारा 60 आईटीईसी स्लॉट का उपयोग किया गया। ट्यूनीस में ट्यूनीशिया-भारत मैत्री संच (टीआईएफए) की स्थापना और पंजीकरण अक्टूबर में आधिकारिक रूप से किया गया।

अध्याय

7

अफ्रीका

मध्य एवं पश्चिम अफ्रीका

भारत के मध्य एवं पश्चिम अफ्रीका (सी एंड डब्ल्यूए) क्षेत्र के 24 देशों के साथ सौहार्दपूर्ण एवं मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। भारत इस क्षेत्र में अपने मित्र देशों की संप्रभुता का सम्मान करता है, जो बहुध्रुवीय विश्व के प्रति उसकी प्रतिबद्धता और गुटनिरपेक्षता के दृष्टिकोण पर आधारित है। भारत ने हाल ही के वर्षों में 13 देशों में राजनयिक मिशन खोलकर इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाई है, जिसमें सबसे नया मिशन 2024 में गैबॉन में खोला गया था। सी एंड डब्ल्यूए देश संयुक्त राष्ट्र में विभिन्न चुनावों में और बहुपक्षीय मंचों पर भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करते रहे हैं। सी एंड डब्ल्यूए देशों के मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने 17 अगस्त को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस के तीसरे संस्करण के 12 सत्रों में 23 भाग लिया। उनमें से 22 ने 03-06 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) की 7^{वां} सभा में भाग लिया। अन्य सदस्य देशों के साथ, 20 सी एंड डब्ल्यूए देशों ने आईएसए फ्रेमवर्क अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें से 16 देशों ने इसका अनुसमर्थन भी कर दिया है।

2023-24 में, राजनयिक भूमिकाओं और उच्च-स्तरीय यात्राओं के अलावा, भारत और सी एंड डब्ल्यूए के बीच व्यापार अच्छा था, यानी 29.25 बिलियन अमरीकी डॉलर। इस क्षेत्र के देश दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण खनिज समृद्ध देशों में से हैं। भारत का प्रयास रहा है कि स्थानीय सरकारें भारतीय कंपनियों और निवेशकों को इस क्षेत्र के साथ-साथ अन्य उच्च क्षमता वाले लेकिन कम खोजे गए क्षेत्रों में व्यापार की माता बढ़ाने और विविधता लाने के लिए आमंत्रित करें।

क्षमता निर्माण और विकास भागीदारी सी एंड डब्ल्यूए के साथ भारत के संबंध के महत्वपूर्ण स्तंभ रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में, इन देशों के कई उम्मीदवार और छात्र हमारे प्रमुख आईटीईसी प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा आईसीसीआर छात्रवृत्तियों के माध्यम से लाभान्वित हुए हैं। 2024 में, सी एंड डब्ल्यूए देशों के उम्मीदवारों को 1272 आईटीईसी प्रशिक्षण स्लॉट और 251 आईसीसीआर छात्रवृत्तियाँ आवंटित की गईं। सीएंडडब्ल्यूए देशों के लगभग 7600 छात्रों को भारत की ई-विद्याभारती-आरोग्यभारती (ई-वीबीएबी) परियोजना के तहत यूजी/पीजी पाठ्यक्रमों के लिए नामांकित किया गया है, जो पूरी तरह से वित्तपोषित ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, आईटीईसी के तहत रक्षा प्रशिक्षण को इन देशों के रक्षा कर्मियों तक विस्तारित किया गया है। 12 सीएंडडब्ल्यूए देशों के 16 उम्मीदवारों ने 23-29 अक्टूबर को नई दिल्ली में ग्लोबल साउथ के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए विकास हेतु डेटा पर प्रथम आईटीईसी कार्यकारी पाठ्यक्रम में भाग लिया। 9 सीएंडडब्ल्यूए देशों के मीडिया पत्रकारों ने 23-30 अक्टूबर के दौरान एक्सपी डिवीजन द्वारा आयोजित 'फैमिलराइजेशन प्रोग्राम' के लिए भारत का दौरा किया।

अंगोला

भारत के अंगोला के साथ घनिष्ठ और सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। अंगोला भारत की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण भागीदार है।

अंगोला के उद्योग और वाणिज्य मंत्री रुई मिगुएन्स डी ओलिवेरा ने अगस्त में आयोजित 19^{वाँ} सीआईआई भारत-अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव में भाग लिया। उनके साथ राष्ट्रीय तेल, गैस और जैवईंधन एजेंसी (एएनपीजी) के अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया था, जिसने अंगोलन पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से भारतीय तेल और गैस कंपनियों के साथ चर्चा की। भारत की ओर से, वाणिज्य विभाग और भारतीय रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के एक प्रतिनिधिमंडल ने किम्बरली प्रक्रिया प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम की समीक्षा और सुधार पर तदर्थ समिति की बैठक में भाग लेने के लिए 17-18 अक्टूबर को लुआंडा का दौरा किया।

अंगोला के तेल और गैस राज्य सचिव जोस एलेक्जेंडर बरोसो और दूरसंचार एवं आईटी के राष्ट्रीय निदेशक मटियास बोगेस ने वीओजीएसएस के तीसरे संस्करण के क्रमशः ऊर्जा मंत्रियों के सत्र और सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रियों के सत्र में भाग लिया।

2023-24 में, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 4.19 बिलियन अमरीकी डॉलर था। भारत से निर्यात 698 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12 प्रतिशत की वृद्धि है। अंगोला से आयात 3.495 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसमें तेल प्रमुख घटक रहा।

अंगोलन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंफॉर्मेशन सोसाइटी प्रमोशन (आईएनएफओएसआई) के महानिदेशक आंद्रे मपुम्बा पेड्रो ने 23-29 अक्टूबर को नई दिल्ली में वैश्विक दक्षिण के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आयोजित डेटा फॉर डेवलपमेंट पर प्रथम आईटीईसी कार्यकारी पाठ्यक्रम में भाग लिया।

प्रिंट और विजुअल मीडिया के तीन अंगोलन पत्रकारों ने 23-30 अक्टूबर के दौरान मंत्रालय द्वारा आयोजित सी एंड डब्ल्यू ए देशों के लिए फैमिलराइजेशन प्रोग्राम में भाग लिया।

बेनिन

अतिरिक्त सचिव (सी एंड डब्ल्यू ए) के नेतृत्व में तीसरा एफओसी 24 जून को बेनिन के कोटोनौ में आयोजित किया गया। भारत से एक बहु-क्षेत्रीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल इस यात्रा का हिस्सा था।

बेनिन सरकार के स्वास्थ्य मंत्री के तकनीकी सलाहकार डॉ. रोड्रिग कोहैन ने 17 अगस्त को वीओजीएसएस के तीसरे संस्करण के स्वास्थ्य मंत्रियों के सत्र में भाग लिया।

भारत और बेनिन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2023-24 में 752 मिलियन अमरीकी डॉलर था। बेनिन में लगभग 90 भारतीय या भारतीय स्वामित्व वाली कंपनियाँ कार्य कर रही हैं, जिनमें ऑटोमोबाइल, कपड़ा और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में ग्लो-डिजिगबे औद्योगिक क्षेत्र भी शामिल है। बेनिन में आईबीएसए (भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका) फ्रेमवर्क के तहत एक नमक उत्पादन अर्थात साल्ट फार्मिंग परियोजना को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया है। बेनिन में भारत, जर्मनी और बेनिन ने 140758.43 अमेरिकी डॉलर मूल्य की द्विपक्षीय कृषि मशीनीकरण परियोजना संयुक्त रूप से शुरू की है।

बेनिन के अधिकारियों को आईटीईसी कार्यक्रम, आईसीसीआर छात्रवृत्ति और ई-विद्याभारती एवं ई-आरोग्यभारती (ई-वीबीएबी) परियोजना के तहत छात्रवृत्ति का लाभ मिलता रहा है।

2024 में, बेनिन के रक्षा बलों को आईटीईसी कार्यक्रम के तहत भारत में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 40 रिक्तियां प्रदान की गईं। मार्च में, बेनिन में उच्चायोग ने भारतीय रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया। इसमें बेनिन रक्षा मंत्रालय के सीडीएस और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इसके अलावा, रक्षा प्रयोजनों के लिए मौजूदा एलओसी के पुनः उपयोग का मामला भी बेनिन वित्त मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के पास विचाराधीन है।

बेनिन ने नवंबर में नई दिल्ली में आयोजित आईएसए की 7^{वाँ} सभा में भाग लिया।

बुर्किना फासो

संचार, संस्कृति, कला और पर्यटन मंत्री रिमताल्बा जीन इमैनुएल ओउएड्वागो ने 21-30 जुलाई के दौरान भारत द्वारा आयोजित विश्व विरासत समिति सम्मेलन में भाग लिया। औद्योगिक विकास, वाणिज्य, हस्तशिल्प और लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ग्रानिओडेम सर्ज पोडा; अर्थव्यवस्था, वित्त और अप्रेषण योजना मंत्री अबूबकर नाकानाबो; डिजिटल संक्रमण और इलेक्ट्रॉनिक संचार मंत्री डॉ. अमिनाता ज़ेरबो सबाने; और विदेश मामलों, क्षेत्रीय सहयोग और बुर्किनाबे विदेश के उप मंत्री काबोरे बेबग्रासग्रन स्टेला ने अगस्त में 19^{वाँ} सीआईआई भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन में भाग लिया। डिजिटल संक्रमण और इलेक्ट्रॉनिक संचार मंत्रालय के महासचिव किसिटो ट्रोरे ने 17 अगस्त को वीओजीएसएस के तीसरे संस्करण में भाग लिया। डिजिटल संक्रमण और इलेक्ट्रॉनिक संचार मंत्री डॉ. अमिनाता ज़ेरबो सबाने ने 15-24 अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजित विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा में भाग लिया।

भारत और बुर्किना फासो के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2023-24 के दौरान बढ़कर 323.89 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो पिछले वर्ष 293.11 मिलियन अमेरिकी डॉलर था।

कैमरून

भारत और कैमरून के बीच सौहार्दपूर्ण द्विपक्षीय संबंध और मजबूत हुए हैं। कैमरून ने जनवरी में नई दिल्ली में अपना रेजिडेंट मिशन खोला।

भारत और कैमरून के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2023-24 में 1.242 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो पिछले वर्ष से 12.60 प्रतिशत अधिक है।

मंत्री डॉ. फेलिक्स मबायू ने 20-22 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित 19^{वाँ} सीआईआई भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन में भाग लिया। डाक और दूरसंचार मंत्री मिनेट लिबोम ली लिकेंग 15-24 अक्टूबर को आयोजित आईटीयू-डब्ल्यूटीएसए असंबली में भाग लेने के लिए भारत आए। कैमरून के विदेश मंत्रालय में नई प्रौद्योगिकी इकाई के प्रमुख अस्सेन अस्सेन जोसेफ ने 23-29 अक्टूबर को नई दिल्ली में नीति आयोग के एनआईएलईआरडी

में 'विकास के लिए डेटा - क्षमता निर्माण पहल' पर आईटीईसी कार्यकारी कार्यक्रम में भाग लिया।

नवंबर में कसावा रोपण परियोजना के लिए भारत से मशीनरी और उपकरण भेजे गए। यह परियोजना 42 मिलियन अमेरिकी डॉलर के एलओसी के तहत संचालित की जा रही है।

कैबो वर्डे

भारत और कैबो वर्डे के बीच मधुर और सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। कैबो वर्डे संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय मंचों में विभिन्न पदों पर भारतीय उम्मीदवारी का समर्थन करता रहा है।

शिक्षा मंत्री डॉ. अमाडेउ क्रूज़ ने 17 अगस्त को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस के तीसरे संस्करण के शिक्षा मंत्रियों के सत्र में भाग लिया।

कैबो वर्डे में एक रेजिडेंट मिशन खोलने के पहले वर्ष के भीतर, भारत और कैबो वर्डे के बीच पहला एफओसी 18 मार्च को आयोजित किया गया। भारतीय पक्ष का नेतृत्व अपर सचिव (सी एंड डब्ल्यूए) ने किया। दोनों पक्षों ने कई विषयों पर चर्चा की और सहयोग के लिए रोडमैप की रूपरेखा तैयार की।

काबो वर्डे से एक 13 सदस्यीय सांस्कृतिक दल ने सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2024 के 37^{वें} संस्करण में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया।

मध्य अफ्रीकी गणराज्य (सीएआर)

भारत और सीएआर के बीच सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्रालय में रक्षा मिशन के प्रभारी डॉ. सैमुअल गोंडजे ने 17 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंस के तीसरे संस्करण में भाग लिया।

चाड

भारत और चाड के बीच द्विपक्षीय संबंध सौहार्दपूर्ण रहे। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री गुडबोलोफांगा मैथ्यू ने 20-22 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित 19^{वें} सीआईआई भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन में भाग लेने के लिए एक पांच सदस्यीय आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इस अवसर पर उन्होंने वाणिज्य एवं उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री से मुलाकात की और आपसी हितों के मामलों पर चर्चा की।

पर्यावरण, मत्स्य पालन और सतत विकास मंत्री डॉ. इदरीस सालेह बाचर ने 17 अगस्त को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस के तीसरे संस्करण के पर्यावरण मंत्रियों के सत्र में भाग लिया।

सीआईआई के एक आठ सदस्यीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने द्विपक्षीय व्यापार अवसरों का पता लगाने के लिए 24-27 सितंबर के दौरान एन'जामेना का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान, एक बी2बी बैठक आयोजित की गई, जिसमें 50 से अधिक चाडियन बिजनेस लीडर्स और उद्योगपतियों ने भाग

लिया। 2023-24 के दौरान, पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में द्विपक्षीय व्यापार में लगभग 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और यह 83.48 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है।

चाड एक आईटीईसी भागीदार देश है। संचार, डिजिटल अर्थव्यवस्था और प्रशासन का डिजिटलीकरण मंत्रालय में निदेशक ज़ारा अहमद सेडिक और विदेश मंत्रालय के निदेशक (अमेरिका और कैरिबियन प्रभाग) मूसा महामत ने 23-29 अक्टूबर को नई दिल्ली में नीति आयोग में 'विकास के लिए डेटा - क्षमता निर्माण पहल' पर आईटीईसी कार्यकारी कार्यक्रम में भाग लिया।

चाड ने नवंबर में नई दिल्ली में आयोजित आईएसए की 7^{वीं} सभा में भाग लिया।

भारत ने चाड सरकार को चिकित्सा सहायता प्रदान की, जिसमें जून में एन'जामेना में घटित घातक आग घटना के पीड़ितों के लिए 2300 कि.ग्रा. आवश्यक जीवन रक्षक दवाएँ शामिल थीं।

कोट डी आइवर

भारत और कोट डी आइवर के बीच द्विपक्षीय संबंध दोनों देशों के साझा मूल्यों और हितों को प्रतिबिंबित करते हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देते हैं। व्यापार और प्रौद्योगिकी से लेकर सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान-प्रदान तक, दोनों देशों के बीच संबंध लगातार बढ़े हैं। दोनों पक्ष संबंधों को गहरा करने और पारस्परिक लाभ के नए क्षेत्रों की खोज करने के प्रति प्रतिबद्ध हैं।

तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और शिक्षता मंत्री एन'गुएसन कोफी ने 17 अगस्त को वर्चुअल रूप में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस के तीसरे संस्करण में भाग लिया। डिजिटल संक्रमण और डिजिटलाइजेशन मंत्री इब्राहिम कलिल कोनाटे ने 20-22 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित 19^{वें} सीआईआई भारत-अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया। अर्थव्यवस्था, योजना और विकास मंत्रालय का एक तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल, जिसका नेतृत्व अर्थव्यवस्था, योजना और विकास मंत्री हिपन टोडो जीन-पॉल के कैबिनेट निदेशक एक प्रतिनिधि ने किया था, ने 20-25 सितंबर को भारत का दौरा किया। यात्रा का एक प्रमुख उद्देश्य अर्थशास्त्र के अन्य क्षेत्रों में जानकारी प्राप्त करने के अलावा, निर्बाध और सुरक्षित वित्तीय लेनदेन के लिए एक मॉडल के रूप में, भारत की यूपीआई प्रणाली को जानना-समझना था। द्विपक्षीय व्यापार गतिविधियों में तेजी लाने के लिए 11 सदस्यीय सीआईआई प्रतिनिधिमंडल ने सितंबर में कोटे डी आइवर का दौरा किया।

आईटीईसी एवं आईसीसीआर कार्यक्रमों के तहत भारत का प्रशिक्षण कार्यक्रम आइवरीयन्स के प्रमुख क्षेत्रों में क्षमता निर्माण को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। वर्ष के दौरान, लगभग 100 आइवरीवासियों ने भारत में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया। इसमें 29 आइवरीवासियों के शिक्षकों को अंग्रेजी भाषा में अपने कौशल को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण देना शामिल था। यह पहल शैक्षिक आदान-प्रदान और विकास के लिए हमारी साझा प्रतिबद्धता का प्रमाण है। डिजिटल संक्रमण और डिजिटलीकरण

मंत्रालय के डिजिटल परिवर्तन और डिजिटलीकरण के महानिदेशक ओलिवियर अवोआ ने 23-29 अक्टूबर को नई दिल्ली में नीति आयोग के एनआईएलईआरडी में 'विकास क्षमता निर्माण पहल के लिए डेटा' पर आईटीईसी कार्यकारी कार्यक्रम में भाग लिया।

कोट डी आइवरी में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, आईसीसीआर द्वारा प्रायोजित एक सांस्कृतिक मंडली ने कोट डी आइवरी का दौरा किया और नृत्य प्रदर्शन किया। कोट डी आइवरी के चार पत्रकारों ने भारत का दौरा किया और 23-30 अक्टूबर तक सी एंड डब्ल्यू देशों के लिए मंत्रालय द्वारा आयोजित फैमिलराइजेशन प्रोग्राम में भाग लिया।

कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (डीआरसी)

भारत और डीआरसी के बीच सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंध हैं। भारत कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन (मोनुस्को) में शांति सैनिकों का सबसे बड़ा योगदानकर्ता है।

रक्षा में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए, कांगो के स्थायी रक्षा सचिव मार्सेल लुकविकिला ने 01-15 जुलाई और 29 जुलाई-08 अगस्त को दो बार भारत का दौरा किया। स्थायी सचिव ने कानपुर, पुणे, बेंगलुरु और मुंबई में रक्षा विनिर्माण सुविधाओं का भी दौरा किया।

डाक, दूरसंचार और नई प्रौद्योगिकी मंत्रालय के महासचिव ऑरिलियन काम्बा नुम्बा ने 17 अगस्त को आयोजित वीओजीएसएस के तीसरे संस्करण में भाग लिया। कांगो के उद्योग मंत्री लुइस वाटम और हाइड्रोलेक संसाधन एवं बिजली मंत्री टेडी ल्वम्बा मुबा ने 19^{वें} सीआईआई भारत-अफ्रीका व्यापार सम्मेलन में भाग लेने के लिए 20-22 अगस्त के दौरान नई दिल्ली का दौरा किया।

सीआईआई के नेतृत्व में एक 15 सदस्यीय बिजनेस प्रतिनिधिमंडल ने 04-08 मार्च को किंशासा और लुबुम्बाशी का दौरा किया। निदेशक (खान) के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 12-14 जून को लुबुम्बाशी में आयोजित डीआरसी खनन सप्ताह एवं एक्सपो में भाग लिया।

इक्वेटोरियल गिनी

इक्वेटोरियल गिनी संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय मंचों पर विभिन्न पदों पर भारतीय उम्मीदवारी का समर्थन करता है।

इक्वेटोरियल गिनी के बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री गर्सेसियो एंगोंगा एम्बीए के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नवंबर में नई दिल्ली में आयोजित आईएसए की 7^{वीं} सभा में भाग लिया।

विदेश मामले, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और डायस्पोरा मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रभारी राज्य सचिव मैरी-कृष्ण इवुना एंडेम ने 17 अगस्त को वर्चुअल रूप से आयोजित वीओजीएसएस के तीसरे संस्करण के विदेश मंत्रियों के दूसरे सत्र में भाग लिया।

इक्वेटोरियल गिनी के स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्रालय के दो वरिष्ठ अधिकारियों ने अगस्त में भारत में आयोजित भारतीय फार्माकोपिया की मान्यता के लिए नीति निर्माताओं के मंच में भाग लिया।

विदेश मामले, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और डायस्पोरा के राज्य मंत्री के राजनयिक अधिकारी और सहायक मारियानो एला एबांग ने 23-29 अक्टूबर को नई दिल्ली में नीति आयोग के एनआईएलईआरडी में 'विकास के लिए डेटा - क्षमता निर्माण पहल' पर आईटीईसी कार्यकारी कार्यक्रम में भाग लिया। इक्वेटोरियल गिनी सरकार के एक अधिकारी ने सितंबर में नई दिल्ली में सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान द्वारा आयोजित दूसरे वैश्विक दक्षिण युवा राजनयिक मंच भी भाग लिया। इक्वेटोरियल गिनी के तीन पत्रकारों ने 23-30 अक्टूबर को मंत्रालय द्वारा आयोजित सी एंड डब्ल्यू देशों के लिए एक फैमिलराइजेशन प्रोग्राम में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया।

इक्वेटोरियल गिनी के साथ भारत के व्यापार संबंधों की खासियत तेल और गैस क्षेत्र में मजबूत भागीदारी है। 2023-24 के दौरान, द्विपक्षीय व्यापार 374.10 मिलियन अमरीकी डॉलर था और इक्वेटोरियल गिनी से कच्चे तेल का आयात 293.63 मिलियन था।

गैबॉन

पारंपरिक रूप से भारत और गैबॉन के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध गैबॉन की स्वतंत्रता के पूर्व के समय से रहे हैं। इसे और मजबूत करने के लिए भारत ने सितंबर में लिब्रेविल में अपना राजनयिक मिशन खोला।

व्यापार के मोर्चे पर, खनन क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं का पता लगाने के लिए मोइल (MOIL) लिमिटेड के एक प्रतिनिधिमंडल ने मार्च में गैबॉन का दौरा किया। अप्रैल में एक 25 सदस्यीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने गैबॉन का दौरा किया। अगस्त में, गैबॉन सरकार के दो महासचिव स्तर के अधिकारियों ने नई दिल्ली में आयोजित 19^{वें} सीआईआई भारत-अफ्रीका व्यापार सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया।

पेट्रोलियम मंत्रालय के महासचिव हर्वे बुबा नेजेंगु ने 17 अगस्त को वीओजीएसएस के तीसरे संस्करण के ऊर्जा मंत्रियों के सत्र में भाग लिया।

घाना

विदेश मामले और क्षेत्रीय अखंडता मंत्री शर्ली अयोर्कर बोचवे ने विदेश मंत्री से मुलाकात की और 21-24 फरवरी के दौरान नई दिल्ली में आयोजित 9^{वीं} रायसीना वार्ता में भाग लिया।

22 नवंबर को, घाना के तत्कालीन राष्ट्रपति अकुफो-एडो ने अक्रा में टेमा-मपाकाडन स्टैंडर्ड गेज रेलवे लाइन (एसजीआरएल) और डीजल मल्टीपल यूनिट ट्रेन्स (डीएमयू) का उद्घाटन किया। 447 मिलियन अमेरिकी डॉलर की 97.7 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन परियोजना, जिसमें वोल्टा नदी पर 300 मीटर लंबा पुल भी है, को भारतीय एक्जिम बैंक के क्रेता ऋण के तहत वित्तपोषित किया गया है। यह परियोजना घाना-बुर्किना फासो अंतर-संपर्क



विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में 9^{वाँ} रायसीना वार्ता के दौरान घाना के विदेश मामले और क्षेत्रीय अखंडता मंत्री शर्ली अग्येमंग बोचवे से मुलाकात की, फरवरी 2024

परियोजना का पहला खंड है, जो घाना के प्रमुख बंदरगाह शहर टेमा को मपाकाइन से जोड़ती है। इस परियोजना का उद्देश्य पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना है।

भारत-घाना संयुक्त व्यापार समिति की बैठक का चौथा सत्र 02-03 मई को अक्रा में आयोजित किया गया। बैठक की सह-अध्यक्षता वाणिज्य विभाग के अपर सचिव तथा व्यापार एवं उद्योग के उप मंत्री माइकल ओक्येरे-बाफी ने की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ सीआईआई के नेतृत्व में एक बिजनेस प्रतिनिधिमंडल भी आया था। उप मंत्री माइकल ओक्येरे ने 17 अगस्त को वीओजीएसएस के तीसरे संस्करण के वाणिज्य मंत्रियों के सत्र में भी भाग लिया।

चार मंत्रियों - वित्त उप मंत्री डॉ. स्टीफन अमोआ, विदेश मामले और क्षेत्रीय अखंडता के उप मंत्री क्वाकू अम्प्राटुवुम-सरपोंग, व्यापार एवं उद्योग उप मंत्री माइकल ओक्येरे बाफी तथा खाद्य एवं कृषि उप मंत्री मोहम्मद हार्डी तुफेइरू सहित एक प्रतिनिधिमंडल ने 20-22 अगस्त के दौरान नई दिल्ली में आयोजित 19^{वाँ} सीआईआई-भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन में भाग लिया।

शिक्षा उप मंत्री जॉन एनटिम फोर्डजौर ने 14-21 फरवरी के दौरान नई दिल्ली में आयोजित शिक्षा ज्ञान आदान-प्रदान शिखर सम्मेलन में भाग लिया। संचार एवं डिजिटलीकरण मंत्री उर्सुला ओवसु-एकुफुल ने 14 अक्टूबर को नई दिल्ली में वैश्विक मानक संगोष्ठी (जीएसएस) और विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा (डब्ल्यूटीएसए 2024) में भाग लिया। घाना के खाद्य एवं औषधि प्राधिकरण (एफडीए) के उप सीईओ सेठ सीनके ने घाना में भारतीय फार्माकोपिया की मान्यता और जन औषधि योजना को अंगीकृत करने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए घाना से औषधि विनियामक विशेषज्ञ के रूप में 19-22 अगस्त के दौरान भारत का दौरा किया।

भारतीय महासर्वेक्षक के नेतृत्व में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 19-23 मई के दौरान अक्रा में आयोजित इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सर्वेयर्स (एफआईजी) वर्किंग वीक 2024 में भाग लिया। नई दिल्ली में आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (सीडीआरआई) सचिवालय के वरिष्ठ निदेशक के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने सितंबर में घाना का दौरा किया।

2024 में आईटीईसी कार्यक्रम के तहत भारत में लगभग 128 नागरिकों और 109 रक्षा कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया और आईसीसीआर के तहत 35 छात्रवृत्तियाँ और आयुष के तहत तीन छात्रवृत्तियाँ घाना के नागरिकों को प्रदान की गईं। वर्तमान में, ई-वीबीएबी पहल के तहत, 1600 से अधिक घानावासी भारत में अध्ययन कर रहे हैं।

विदेश मंत्रालय और क्षेत्रीय अखंडता मंत्रालय के मध्य पूर्व ब्यूरो की निदेशक लुईसा हैनसन ने 23-29 अक्टूबर के दौरान नई दिल्ली में नीति आयोग के एनआईएलआईआरडी में 'विकास के लिए डेटा - क्षमता निर्माण पहल' पर आईटीईसी कार्यकारी कार्यक्रम में भाग लिया।

भारत घाना में शीर्ष निवेशकों में से एक है, जो परियोजनाओं की संख्या के आधार पर निवेश के लिए अमेरिका और ब्रिटेन के साथ दूसरे स्थान पर है (चीन शीर्ष निवेशक है), और एफडीआई के मूल्य के हिसाब से छठे स्थान पर है (शीर्ष 3 देश हैं : स्पेन, चीन और अमेरिका)। घाना निवेश संवर्धन केंद्र (जीआईपीसी) के अनुसार, भारत ने जनवरी-जून के बीच पांच परियोजनाओं में 7.83 मिलियन अमेरिकी डालर का निवेश किया, जो घाना के कुल एफडीआई का 4.20 प्रतिशत है। ये परियोजनाएं विनिर्माण, सेवा, सामान्य व्यापार, निर्यात व्यापार, भवन और निर्माण, पर्यटन, संपर्क और कृषि क्षेत्रों में हैं। 56 भारतीय कंपनियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने 19-21 मार्च के दौरान अक्रा में तीसरी एग्री-टेक वेस्ट अफ्रीका प्रदर्शनी और फूड एंड बेवरेज घाना और फूडपैक टेक घाना प्रदर्शनी में भाग लिया। भारतीय आर्थिक व्यापार संगठन (आईईटीओ) के 13 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए 18-24 फरवरी के दौरान घाना का दौरा किया।

घाना ने नवंबर माह में नई दिल्ली में आयोजित आईएसए की 7^{वाँ} सभा में भाग लिया।

मंत्रालय द्वारा आयोजित मीडिया फैमिलराइजेशन यात्रा के लिए 24-30 अक्टूबर को पांच सदस्यीय मीडिया प्रतिनिधिमंडल ने भारत का दौरा किया। घाना से 20 सदस्यीय सांस्कृतिक दल ने फरवरी में 37^{वाँ} सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में भाग लिया। 26 अक्टूबर को, एचसीआई अक्रा ने विभिन्न भारतीय संघों के सहयोग से अक्रा स्पोर्ट्स स्टेडियम में इंडिया फेस्ट का आयोजन किया।

गिनी-बिसाऊ

संस्कृति, युवा मामले और खेल मंत्रालय की महानिदेशक सिंधिया जेनाबा इवोरा कैसामा ने 17 अगस्त को वीओजीएसएस के तीसरे संस्करण के युवा मामले मंत्रियों के सत्र में भाग लिया।

लाइबेरिया

लाइबेरिया के उपराष्ट्रपति जेरेमिया केपन कोंग ने 20-23 अगस्त के दौरान नई दिल्ली में आयोजित 19^{वाँ} सीआईआई-भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन में भाग लिया। प्रशासन उप मंत्री मार्था सी मॉरिस और स्वास्थ्य मंत्रालय से योजना एवं नीति उप मंत्री मलाया ताम्बा चिएयो ने भी सम्मेलन में भाग लिया।

स्वास्थ्य सेवाओं के उप मंत्री और स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण मंत्रालय के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. कैथरीन टी कॉपर, और बजट एवं विकास योजना के उप मंत्री डॉ. तन्हेह जी. ब्रंसन ने 17 अगस्त को आयोजित वीओजीएसएस के तीसरे संस्करण के क्रमशः स्वास्थ्य मंत्रियों के सत्र और वित्त मंत्रियों के सत्र में भाग लिया।

कृषि विस्तार मंत्रालय के उप मंत्री मोसेस ग्वान्यान ने 19-22 सितंबर के दौरान नई दिल्ली में आयोजित विश्व खाद्य भारत 2024 में भाग लिया। डाक और दूरसंचार मंत्री सेकोउ एम. क्रोमा के नेतृत्व में एक छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 14-15 अक्टूबर के दौरान नई दिल्ली में वैश्विक मानक संगोष्ठी (जीएसएस) / विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा (डब्ल्यूटीएसए) 2024 में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया। खान और ऊर्जा मंत्री विलमोट जेएम पे के नेतृत्व में तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 03-06 नवंबर के दौरान नई दिल्ली में आईएसए की सभा के 7^{वाँ} सत्र में भाग लिया।

माली

भारत और माली के बीच मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। युवा मामले मंत्री के सलाहकार बाबा महमूद अरबी ने 17 अगस्त को वीओजीएसएस के तीसरे संस्करण के युवा मंत्रियों के सत्र में भाग लिया।

भारत ने अपने आईटीईसी कार्यक्रम और आईसीसीआर छात्रवृत्तियों के माध्यम से माली के नागरिकों को कई शैक्षिक, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के अवसर प्रदान करना जारी रखा। वर्ष 2023-24 के दौरान माली को आईटीईसी कार्यक्रम के तहत 70 स्लॉट प्रदान किए गए और भारत में उच्च अध्ययन के लिए माली के छात्रों को 15 आईसीसीआर छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं।

37^{वाँ} सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2024 में भाग लेने के लिए 20 मालीवासियों का एक सांस्कृतिक दल भारत आया।

मॉरिटानिया

भारत-मॉरिटानिया संबंध वर्ष के दौरान मजबूत रहे। माननीय राष्ट्रपति जी ने 16 अक्टूबर को मॉरिटानिया के नौआकचोट की पहली राजकीय यात्रा की। उन्होंने मॉरिटानिया के राष्ट्रपति मोहम्मद औलद गज़ौनी, विदेश मंत्री मोहम्मद सलीम औलद मज़ौंग से मुलाकात की और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। यात्रा के दौरान चार द्विपक्षीय अनुबंधों/समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए अर्थात् राजनयिक और सरकारी पासपोर्ट धारकों के लिए द्विपक्षीय वीजा छूट समझौता, विदेश कार्यालय परामर्श संबंधी प्रोटोकॉल और एसएसआईएफएस तथा मॉरिटानिया की राजनयिक अकादमी के बीच एक समझौता ज्ञापन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम।



माननीय राष्ट्रपति जी ने नौआकचोट में मॉरिटानिया के राष्ट्रपति मोहम्मद औलद गज़ौनी से मुलाकात की, अक्टूबर 2024



प्रधानमंत्री ने अबुजा में नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टीनुबू के साथ वार्ता की, नवंबर 2024

उच्च शिक्षा एवं वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री डॉ. याकूब मोइन ने 17 अगस्त को वीओजीएसएस के तीसरे संस्करण के शिक्षा मंत्रियों के सत्र में भाग लिया।

पहला एफओसी 21 मार्च को नौआकोट में आयोजित किया गया, जिसकी सह-अध्यक्षता भारतीय पक्ष से एस (सी एंड डब्ल्यूए) और द्विपक्षीय सहयोग महानिदेशक, मॉरिटानिया का विदेश मंत्रालय, मोहम्मद एल हंचीकेताब ने की।

नाइजर

भारत और नाइजर के बीच द्विपक्षीय संबंध मधुर और मैत्रीपूर्ण रहे। नाइजर संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय मंचों पर भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करता है।

नाइजर के वाणिज्य और उद्योग मंत्री सेइदो असमान ने अगस्त में 19^{वां} सीआईआई-अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया।

ऊर्जा मंत्री अमादौ हाउआ ने नवंबर में नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 7^{वां} सभा में भाग लिया।

युवा मामले, खेल और संस्कृति मंत्री वरिष्ठ कर्नल अब्दुरहमाने अमादौ ने 17 अगस्त को वीओजीएसएस के तीसरे संस्करण के युवा मामले मंत्रियों के सत्र में भाग लिया।

भारत ने विभिन्न क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से नाइजर का समर्थन किया। भारत ने शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए नाइजर को 156 आईटीईसी प्रशिक्षण स्लॉट, पाँच रक्षा प्रशिक्षण स्लॉट और पाँच आईसीसीआर छात्रवृत्तियाँ प्रदान कीं।

नाइजीरिया

भारत और नाइजीरिया के बीच मधुर, मैत्रीपूर्ण और गहरे द्विपक्षीय संबंध हैं। इन दोनों देशों की भागीदारी व्यापक है और अंतरिक्ष, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा, अनुसंधान और विकास, आतंकवाद निरोध, समुद्री सुरक्षा और खुफिया जानकारी साझा करना, साइबर सुरक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और खाद्य सुरक्षा, फिन टेक, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण सहित क्षेत्रों में विस्तारित हुई है।

उच्च स्तरीय जुड़ाव

प्रधानमंत्री की 16-17 नवंबर के दौरान नाइजीरिया की राजकीय यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिली। यह यात्रा 17 वर्षों के अंतराल के बाद हुई और यह पश्चिम अफ्रीकी क्षेत्र की उनकी पहली यात्रा थी। यात्रा के दौरान, सीमा शुल्क सहयोग, संस्कृति विनिमय कार्यक्रम और भारत एवं नाइजीरिया के महासर्वेक्षकों के बीच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।

विदेश मंत्री ने 21-23 जनवरी के दौरान नाइजीरिया का दौरा किया। उन्होंने छठी संयुक्त आयोग की बैठक की सह-अध्यक्षता की और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दोनों नेताओं ने नाइजीरिया में भारतीय समुदाय को संबोधित किया।

विदेश मंत्री यूसुफ मैतामा तुगार ने 17 अगस्त को वीओजीएसएस के तीसरे संस्करण में भाग लिया।

आर्थिक और व्यापार सहयोग

नाइजीरिया में भारतीय निवेश 27 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होने का अनुमान है, जिसमें 200 से अधिक भारतीय कंपनियाँ नाइजीरिया

में पेट्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग सामान, दूरसंचार, इलेक्ट्रिकल मशीनरी और एलएनजी जैसे विविध क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार 7,893.30 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसमें भारत ने नाइजीरिया से 3,989.66 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का कच्चा तेल आयात किया, जबकि उसने 1,035.69 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के परिष्कृत ईंधन और अन्य पेट्रोकेमिकल (रिफाइनड फ्यूल) उत्पादों का निर्यात किया। भारत ने वित्त वर्ष 2023-24 में नाइजीरिया को 440.14 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के फार्मास्यूटिकल उत्पादों का निर्यात भी किया।

दूसरी संयुक्त व्यापार आयोग की बैठक 29 अप्रैल को अबुजा में हुई।

रक्षा सहयोग

नाइजीरिया के साथ भारत का रक्षा सहयोग वर्ष के दौरान लगातार बढ़ता रहा। अपनी यात्रा के दौरान, विदेश मंत्री ने भारतीय रक्षा विनिर्माण उद्योग के विकास और नाइजीरिया को इससे मिलने वाले लाभों पर प्रकाश डाला। भारत से नाइजीरिया को रक्षा निर्यात बढ़ रहा है, और 2021-22 में यह 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2023-24 में 283 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। नाइजीरियाई राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नुहू रिबाडू ने 04-06 नवंबर के दौरान दूसरी भारत-नाइजीरिया आतंकवाद विरोधी वार्ता के लिए भारत का दौरा किया। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मुलाकात की और आतंकवाद तथा आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। दोनों देशों ने महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की सुरक्षा के लिए गिनी की खाड़ी में नियमित नौसैनिक युद्धाभ्यास और संयुक्त समुद्री-डकैती विरोधी अभियान जारी रखने पर सहमति जताई।

नाइजीरियाई सशस्त्र बलों को 2024-25 के दौरान आईटीईसी कार्यक्रम के तहत विभिन्न रक्षा पाठ्यक्रमों के लिए 126 सीटें आवंटित की गईं।

अन्य आदान-प्रदान

नवीकरणीय ऊर्जा पर संयुक्त कार्यसमूह की पहली वर्चुअल बैठक 19 जुलाई को आयोजित की गई। तीसरी कांसुलर वार्ता 22 अगस्त को नई दिल्ली में हुई। दूसरी आतंकवाद विरोधी वार्ता 04-06 नवंबर के दौरान नई दिल्ली में हुई। नाइजीरिया ने 03-06 नवंबर के दौरान नई दिल्ली में आयोजित 7^{वाँ} आईएसए सभा में भाग लिया।

भारत ने आईटीईसी कार्यक्रम के तहत नाइजीरियाई अधिकारियों को कई स्लॉट प्रदान कीं तथा भारत में विभिन्न पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए आईसीसीआर, आईलर्न, हिंदी छात्रवृत्ति, स्टडी इन इंडिया (एसआईआई) छात्रवृत्ति और सीवी रमन फैलोशिप सहित नाइजीरियाई छात्रों के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति कार्यक्रम भी प्रदान किए गए।

संचार, नवाचार और डिजिटल अर्थव्यवस्था के संघीय मंत्रालय के निदेशक एंड्रयू एडेनियी दादा ने 23-29 अक्टूबर के दौरान नई दिल्ली में नीति आयोग के एनआईएलईआरडी में 'विकास के लिए डेटा - क्षमता निर्माण पहल' पर आईटीईसी कार्यकारी कार्यक्रम में भाग लिया।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) ने नाइजीरियाई छात्रों को भारत में स्नातकपूर्व, स्नातकोत्तर और पीएचडी पाठ्यक्रम का अध्ययन करने के लिए 'आईसीसीआर अफ्रीका छात्रवृत्ति योजना' के तहत 38 छात्रवृत्तियाँ प्रदान कीं। वर्ष 2024 में आईटीईसी / ई-आईटीईसी के तहत नाइजीरिया को कुल 250 नागरिक प्रशिक्षण स्लॉट आवंटित किए गए। वर्ष 2024 में, सैकड़ों नाइजीरियाई छात्रों को स्टडी इन इंडिया (एसआईआई) कार्यक्रम के तहत विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश दिया गया।

10 अक्टूबर को, स्थानीय समुदाय के कौशल विकास के लिए उबंटू केंद्र, कारू को 10 सिलाई मशीनें दान की गईं।

फरवरी में, नाइजीरिया के 20-सदस्यीय सांस्कृतिक दल ने फरीदाबाद में 37^{वाँ} सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में भाग लिया।

23-30 अक्टूबर के दौरान सी एंड डब्ल्यू.ए देशों के मंत्रालय द्वारा आयोजित फैमिलराइजेशन प्रोग्राम में छह नाइजीरियाई पत्रकारों ने भाग लिया।

कांगो गणराज्य (आरओसी)

भारत और आरओसी के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बने रहे। ओएसडी (ईआर और डीपीए) ने 02-05 जुलाई के दौरान ब्राज़ाविल में आरओसी द्वारा आयोजित वनरोपण और पुनर्वनरोपण (सीआईएआर1) पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में माननीय राष्ट्रपति जी का प्रतिनिधित्व किया।

द्विपक्षीय व्यापार को प्रोत्साहित करने और व्यवसाय के अवसरों को और अधिक बढ़ाने के लिए, भारतीय उद्योग परिषद (सीआईआई) के एक 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 03-04 मार्च को आरओसी का दौरा किया। वित्त वर्ष 2023-24 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 298.42 मिलियन अमेरिकी डॉलर था।

सिविल सेवा, श्रम और सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय के विभागाध्यक्ष कौसी अथानासे ने 23-29 अक्टूबर के दौरान नई दिल्ली में नीति आयोग के एनआईएलईआरडी में 'विकास के लिए डेटा - क्षमता निर्माण पहल' पर आईटीईसी कार्यकारी कार्यक्रम में भाग लिया।

अक्टूबर में, सी एंड डब्ल्यू.ए देशों के लिए मंत्रालय द्वारा आयोजित एक फैमिलराइजेशन विजिट हेतु 2 कांगोली मीडिया कर्मी भारत आए।

गिनी गणराज्य

योजना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री इस्माइल नाबे, परिवहन मंत्री महामदौ अब्दुलाये डायलो, स्वास्थ्य और सार्वजनिक स्वच्छता मंत्री उमर दीउहे बाह तथा बुनियादी ढांचा और लोक निर्माण मंत्री उस्मान गौल डायलो सहित एक मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने 20-22 अगस्त के दौरान नई दिल्ली में 19^{वाँ} सीआईआई-अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव में भाग लिया। यात्रा के दौरान, गिनी के मंत्रियों ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठकें भी कीं।

युवा मामले और खेल मंत्रालय के महासचिव मोहम्मद बिली काबा ने 17 अगस्त को वर्चुअल रूप से आयोजित वीओजीएसएस के तीसरे संस्करण के युवा मामले मंत्रियों के सत्र में भाग लिया।

गिनी गणराज्य के विदेश मंत्रालय, अफ्रीकन इंटीग्रेशन एंड गिनियन एब्रॉड ऑफ द रिपब्लिक ऑफ गिनी और भारत गणराज्य के विदेश मंत्रालय के बीच पहला भारत-गिनी एफओसी 18-19 अक्टूबर को कोनाक्री में आयोजित किया गया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व एएस (सी एंड डब्ल्यूए) ने किया और गिनी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय, अफ्रीकन इंटीग्रेशन एंड गिनियन एब्रॉड के राजदूत एवं महासचिव राजदूत अब्दुलाय यूला ने किया। यह यात्रा 2019 में मिशन के उद्घाटन के बाद संबंधों की समीक्षा के लिए पहला उच्च स्तरीय आदान-प्रदान था। चर्चा के दौरान, दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों स्तरों पर आपसी हित के कई मुद्दों पर चर्चा की। भारत ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, रेलवे, खनन, कृषि, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में सहायता प्रदान की, जिससे भारतीय कंपनियों के लिए गिनी में निवेश करने के और अधिक अवसर खुलेंगे।

डाक, दूरसंचार और डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रालय के राष्ट्रीय निदेशक अब्दुलाय टूरे ने 23-29 अक्टूबर के दौरान नीति आयोग, नई दिल्ली के एनआईएलईआरडी में 'विकास के लिए डेटा - क्षमता निर्माण पहल' पर आईटीईसी कार्यकारी कार्यक्रम में भाग लिया।

मध्य और पश्चिम अफ्रीकी देशों के लिए 23-30 अक्टूबर के दौरान विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित फैमिलराइजेशन प्रोग्राम में गिनी के 2 पत्रकारों ने भाग लिया।

सेनेगल

भारत और सेनेगल के बीच बेहतरीन द्विपक्षीय संबंध हैं। सेनेगल सरकार के संचार, दूरसंचार और डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रालय के महासचिव ने 17 अगस्त को आयोजित वीओजीएसएस के तीसरे संस्करण में भाग लिया।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत और सेनेगल के बीच द्विपक्षीय व्यापार 1.572 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। सेनेगल ने नवंबर में नई दिल्ली में आयोजित आईएसए की 7^{वीं} सभा में भाग लिया।

दक्षिण (दक्षिण), आरआईएस में ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और सेनेगल के अफ्रीकाजोम सेंटर ने अप्रैल में एक लेटर ऑफ एसोसिएशन पर हस्ताक्षर किए ताकि वैश्विक साउथ देशों के बीच विकास समाधानों को साझा किया जा सके। दक्षिण ने ग्लोबल साउथ देशों के बीच विकास समाधानों को साझा करने में सक्षम बनाने हेतु मई में सेनेगल के कंसोर्टियम पोर ला रिसर्च इकोनॉमिक एट सोशल (सीआरईएस) के साथ एक लेटर ऑफ एसोसिएशन पर भी हस्ताक्षर किए।

सिएरा लियोन

भारत सिएरा लियोन का एक प्रमुख व्यापार भागीदार है और सिएरा लियोन द्वारा आयात के मामले में चौथे स्थान पर था। वित्त वर्ष 2023-24 में सिएरा लियोन को भारत का निर्यात 298.53 मिलियन अमेरिकी डॉलर था।

सिएरा लियोन के तकनीकी और उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. हाजा रामतुलाई वूरी, और तकनीकी एवं उच्च शिक्षा उप मंत्री एमिली कडियातु गोगरा ने 14-21 फरवरी के दौरान नई दिल्ली में शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के साथ भागीदारी में विश्व बैंक द्वारा आयोजित शिक्षा ज्ञान आदान-प्रदान पर भारत शिखर सम्मेलन में भाग लिया।

सिएरा लियोन के ऊर्जा उप मंत्री डॉ. एल्डेड टुंडे टेलर और संचार, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार उप मंत्री इब्राहिम सन्नोह ने 17 अगस्त को वर्चुअल रूप से आयोजित वीओजीएसएस के तीसरे संस्करण में क्रमशः ऊर्जा मंत्री के सत्र और सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रियों के सत्र में भाग लिया।

कृषि और खाद्य सुरक्षा उप मंत्री डॉ. थेरेसा टेनेह डिक ने एक प्रतिनिधि के साथ 19-22 सितंबर के दौरान भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित विश्व खाद्य भारत के तीसरे संस्करण में भाग लिया।

क्षमता निर्माण को आगे बढ़ाने के लिए, संचार, प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्रालय के प्रौद्योगिकी निदेशक डॉ. अब्दुलई संकोह; व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास के उप निदेशक तथा व्यापार डेटा एवं सांख्यिकी के प्रमुख विक्टर अब्दुलई; और सूचना एवं नागरिक शिक्षा मंत्रालय में परिवहन निदेशक शेखू कामारा ने 23-29 अक्टूबर के दौरान नई दिल्ली में नीति आयोग के एनआईएलईआरडी में 'विकास के लिए डेटा: क्षमता निर्माण पहल' पर पहले आईटीईसी कार्यकारी कार्यक्रम में भाग लिया।

भारत ने सिएरा लियोन को 'सिएरा लियोन में दिव्यांगजनों के लिए आर्थिक रूप से सक्षम बनाना' परियोजना के लिए भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास कोष से 990,000 अमेरिकी डॉलर का अनुदान प्रदान किया।

साओ तोम और प्रिंसिपे

भारत और साओ तोम तथा प्रिंसिपे के बीच मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण संबंध बने रहे। साओ तोम और प्रिंसिपे ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य बहुपक्षीय मंचों में विभिन्न पदों पर भारत के नामांकन का समर्थन किया।

साओ तोम और प्रिंसिपे के विदेश मामले, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समुदाय के मंत्री डॉ. गैरेथ हदाद डो एस्पिरिटो सैंटो ग्वाडालूप ने 17 अगस्त को आयोजित वीओजीएसएस के तीसरे संस्करण के विदेश मंत्रियों के सत्र में भाग लिया।

साओ तोम और प्रिंसिपे के एक तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 3-6 नवंबर के दौरान नई दिल्ली में आयोजित आईएसए असेंबली के 7^{वें} सत्र में भाग लिया। साओ तोम और प्रिंसिपे ने 2025-2029 की अवधि के लिए आईएसए के महानिदेशक के पद हेतु भारत की उम्मीदवारी का भी समर्थन किया।

भारत ने एसटीपी को क्षमता निर्माण सहायता प्रदान की। वर्ष के दौरान, साओ तोम और प्रिंसिपे के 13 अधिकारियों ने भारत में क्षमता निर्माण पाठ्यक्रमों में भाग लिया तथा साओ तोम और प्रिंसिपे के विदेश मंत्रालय के दो अधिकारियों ने 22 अप्रैल-03 मई के दौरान नई दिल्ली

में एसएसआईएफएस में आयोजित विदेशी राजनयिकों के लिए 71वें व्यावसायिक पाठ्यक्रम में भाग लिया। विदेश मंत्रालय के राजनयिक सलाहकार बिलमा एडनी बांडीरा मंडिंगा ने 23-29 अक्टूबर के दौरान नई दिल्ली में नीति आयोग के एनआईएलईआरडी में 'विकास के लिए डेटा - क्षमता निर्माण पहल' पर आईटीईसी कार्यकारी कार्यक्रम में भाग लिया।

अगस्त में भारत और साओ तोम तथा प्रिंसिपे के बीच भारत की ओर से उपहार के रूप में छह स्कूल बसों की आपूर्ति के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

साओ तोम और प्रिंसिपे के 14 सदस्यीय सांस्कृतिक दल ने 37^{वां} सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2024 में भाग लिया।

गाम्बिया

भारत और गाम्बिया के बीच मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। गाम्बिया के उपराष्ट्रपति मुहम्मद बी.एस. जलो ने 20-22 अगस्त के दौरान नई दिल्ली में आयोजित 19वें सीआईआई भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन में भाग लेने के लिए व्यापार एवं उद्योग, पर्यटन एवं संस्कृति, और परिवहन कार्य एवं अवसंरचना के मंत्रियों के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। संचार और डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रालय के स्थायी सचिव हसन जलो ने 17 अगस्त को वर्चुअल रूप से आयोजित वीओजीएसएस के तीसरे संस्करण में भाग लिया।

गाम्बिया ने नवंबर में नई दिल्ली में आयोजित 7वीं आईएसए सभा में भाग लिया।

क्षमता निर्माण के तहत, गाम्बिया के 25 वरिष्ठ सिविल सेवकों के चौथे बैच ने 22 जनवरी-02 फरवरी के दौरान नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) में सार्वजनिक नीति और शासन के बारे में एडवांस्ड लीडरशिप पर एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लिया। 30 मध्य-स्तरीय सिविल सेवकों के एक बैच ने 27 मई-07 जून के दौरान सार्वजनिक नीति पर एक पाठ्यक्रम में भाग लिया। 19 राजनयिकों के तीसरे बैच के लिए 12-21 जून के दौरान एसएसआईएफएस में एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

आरआईएस में ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और गाम्बिया के सेंटर फॉर पॉलिसी, रिसर्च एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज (सेपरास) ने वैश्विक दक्षिण देशों के बीच विकास समाधानों को साझा करने हेतु मई में एक लेटर ऑफ एसोसिएशन पर हस्ताक्षर किए। 'डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या स्तर पर कार्यान्वित सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के क्षेत्र में सहयोग' पर एक समझौता ज्ञापन पर 3 अक्टूबर को नई दिल्ली में मेटी (MeitY) और गाम्बिया के बीच हस्ताक्षर किए गए।

भारत ने 16 मार्च को बांजुल स्थित गाम्बिया के एडवर्ड फ्रांसिस स्मॉल टीचिंग हॉस्पिटल को 385329.91 अमेरिकी डॉलर मूल्य की 40 डायलिसिस मशीनें उपहार में दीं।

टोगो

भारत और टोगो के बीच मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। भारत और टोगो के बीच एफओसी का पहला दौर 27-28 जून को लोम में आयोजित किया गया। भारत की ओर से इसकी अध्यक्षता एसएस (सी एंड डब्ल्यूए) ने की। एफओसी के दौरान, एफओसी तंत्र को औपचारिक रूप देने संबंधी समझौता ज्ञापन और राजनयिक, सरकारी तथा सेवा पासपोर्टों धारकों के लिए पारस्परिक वीजा छूट संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

टोगो डिजिटल एजेंसी के प्रमुख, युवा मामले मंत्रालय के स्थायी सचिव; ईसीओडब्ल्यूएस निवेश और विकास बैंक (ईबीआईडी) के उपाध्यक्ष; और पश्चिम अफ्रीकी विकास बैंक (बीओएडी) के उपाध्यक्ष ने 17 अगस्त को वर्चुअल रूप से आयोजित वीओजीएसएस के तीसरे संस्करण में भाग लिया।

टोगो ने नवंबर में नई दिल्ली में आयोजित 7वीं आईएसए सभा में भी भाग लिया।

दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों में लगातार वृद्धि हो रही है, तथा भारत टोगो का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन गया है।

क्षमता निर्माण, विकास भागीदारी, आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध तथा शैक्षिक संबंध दोनों देशों के बीच संबंधों का मुख्य आधार रहे हैं। अधिकारियों के लिए आईटीईसी सिविलियन और रक्षा स्लॉट के तहत तथा छात्रों के लिए आईसीसीआर की अफ्रीका छात्रवृत्ति योजना के तहत टोगो द्वारा कुल 50 छात्रवृत्तियों का उपयोग किया गया। विदेश मंत्रालय के दस अधिकारियों, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध निदेशक भी शामिल हैं, ने फरवरी में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, गांधीनगर में संघर्ष प्रबंधन के क्षेत्र में दो सप्ताह का कस्टमाइज्ड प्रशिक्षण लिया। 25 राष्ट्रपति गार्डों के दूसरे बैच को जनवरी-मार्च तक राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण अकादमी (आरपीटीसी) जोधपुर में प्रशिक्षित किया गया। इसके बाद, आरटीपीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सहयोग के अगले चरणों पर चर्चा करने के लिए मई में लोम का दौरा किया। टोगो डिजिटल एजेंसी के डेटा वैज्ञानिक डेविड रेहोबोथ फियोग्बे और सरकारी अधिकारी कडोकपे कॉन्स्टेंटे अफो ने 23-29 अक्टूबर के दौरान नई दिल्ली में नीति आयोग के एनआईएलईआरडी में 'विकास के लिए डेटा - क्षमता निर्माण पहल' पर आईटीईसी कार्यकारी कार्यक्रम में भाग लिया।

अक्टूबर में, सी एंड डब्ल्यूए देशों के पत्रकारों के लिए मंत्रालय द्वारा आयोजित एक फैमिलराइजेशन विजिट के हिस्से के रूप में दो पत्रकारों ने भारत का दौरा किया।

पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका

वर्ष 2024 में भारत के पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका के देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रहे। इन देशों के साथ उच्च स्तरीय संबंधों से विकास भागीदारी, रक्षा, व्यापार और अर्थव्यवस्था, कृषि, वाणिज्य, कला एवं संस्कृति, शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा पर्यटन क्षेत्रों में और दोनों पक्षों के नागरिकों के परस्पर आदान-प्रदान सहित द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने और मजबूती प्रदान करने के प्रयास जारी रहे।



माननीय उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली में सीआईआई भारत-अफ्रीका सम्मेलन के 19^{वें} संस्करण का उद्घाटन किया, अगस्त 2024 में

सीआईआई भारत-अफ्रीका सम्मेलन का 19^{वाँ} संस्करण 20-22 अगस्त के दौरान नई दिल्ली में आयोजित किया गया जिसका उद्घाटन माननीय उपराष्ट्रपति ने किया। इसमें पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीकी देशों से उच्च स्तरीय भागीदारी देखी गई। बुरुंडी के उप-राष्ट्रपति प्रॉस्पर बज़ोम्बाज़ा, गाम्बिया के उप-राष्ट्रपति मुहम्मद बी.एस. जलो, लाइबेरिया के उप-राष्ट्रपति जेरेमिया केपन कोंग, मॉरीशस के उप-राष्ट्रपति मैरी सिरिल एडी बोइसेज़ोन और ज़िम्बाब्वे के उप-राष्ट्रपति डॉ. सी.जी.डी.एन. चिवेंगा ने इस सम्मेलन में भाग लिया।

बहुपक्षीय मोर्चे पर, कई राष्ट्राध्यक्षों और मंत्रियों ने अगस्त में वीओजीएसएस के तीसरे संस्करण में भाग लिया।

क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों, छात्रवृत्तियों, ऋण व्यवस्थाओं, अनुदानों, मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों के माध्यम से भारत की विकास भागीदारी पहलों का अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा लाभार्थी बना रहा।

भारत की विकास भागीदारी अफ्रीका के साथ अपने संबंधों को लेकर एक मजबूत स्तंभ थी, विशेष रूप से 2023-24 में आईटीईसी कार्यक्रम के तहत 1,815 लाभार्थियों (1,521 नागरिक और 294 रक्षा कर्मियों) को लाभ मिलने के आधार पर।

बोत्सवाना

कंपाला में 21-22 जनवरी के दौरान आयोजित 77 देशों के समूह और चीन के तीसरे दक्षिण शिखर सम्मेलन के इतर तत्कालीन राज्य मंत्री (वीएम) ने

बोत्सवाना के तत्कालीन विदेश मंत्री डॉ. लेमोगांग क्वापे से मुलाकात की और आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की।

भारत और दक्षिणी अफ्रीकी विकास समुदाय (एसएडीसी) के बीच आर्थिक सहयोग पर गैबोरोन में 2 जुलाई को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस पर भारत की ओर से बोत्सवाना में भारत के उच्चायुक्त और एसएडीसी के विशेष प्रतिनिधि तथा एसएडीसी की ओर से एसएडीसी के कार्यकारी सचिव ने हस्ताक्षर किए।

क्षमता निर्माण कार्यक्रम के तहत, बोत्सवाना के 77 नागरिकों और रक्षा सैनिकों ने आईटीईसी प्रशिक्षण स्लॉट का लाभ उठाया गया। भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बोत्सवाना के नागरिकों को 54 आईसीसीआर छात्रवृत्तियाँ प्रदान की गईं।

गणतंत्र दिवस शिविर के दौरान 16-29 जनवरी को आयोजित युवा मामले आदान-प्रदान कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बोत्सवाना स्काउट्स संघ का एक 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भारत आया।

हरियाणा में 2-18 फरवरी के दौरान आयोजित सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2024 में बोत्सवाना के एक 18 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया, जिसमें एक सांस्कृतिक दल, कारीगर और क्रेता शामिल थे।

बुरुंडी

बुरुंडी के राष्ट्रपति इवरिस्टे नदिशिमीये ने 25 अक्टूबर को भारत-सहायता प्राप्त केएबीयू-16 जलविद्युत संयंत्र का उद्घाटन किया, जिस दौरान

उन्होंने भारत द्वारा प्रदान किए गए समर्थन की सराहना की। भारत ने बांध के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण ऋण सुविधा प्रदान की थी। उन्होंने बुरुंडी का समर्थन करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को सराहा, विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण समय के दौरान जब देश को अन्य देशों से प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा था। यह परियोजना बुरुंडी के ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत के एग्जिम बैंक ने बुरुंडी में 20 मेगावाट की जलविद्युत परियोजना के निर्माण के लिए 80 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया।

बुरुंडी के उपराष्ट्रपति प्रॉस्पर बाज़ोम्बाज़ा ने 20-22 अगस्त के दौरान नई दिल्ली में आयोजित सीआईआई भारत-अफ्रीका सम्मेलन के 19^{वें} संस्करण में भाग लिया।

यूएनएफपीए के माध्यम से, भारत ने स्वास्थ्य, सामाजिक सामंजस्य, उद्यमिता और ई-कॉमर्स क्षेत्रों में मानव पूंजी विकास के लिए एक परियोजना को वित्तपोषित किया। 1.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि में, बुरुंडी के 30 नगरपालिकाओं को कवर करने वाले छह प्रांतों के युवा शामिल थे।

एस्वातीनी

एस्वातीनी के वित्त मंत्री नील रिजकेनबर्ग ने 17 अगस्त को आयोजित वीओजीएसएस के तीसरे संस्करण में वित्त मंत्रियों के सत्र में वर्चुअल रूप से भाग लिया।

एस्वातीनी के आर्थिक नियोजन और विकास मंत्री डॉ. टैम्बो जीना ने 20-22 अगस्त के दौरान नई दिल्ली में आयोजित सीआईआई भारत-अफ्रीका सम्मेलन के 19^{वें} संस्करण के लिए भारत का दौरा किया।

भारत और एस्वातीनी के बीच दूसरी एफओसी 19 फरवरी को मबाबेन में आयोजित की गई। भारतीय पक्ष का नेतृत्व अपर सचिव, पूर्वी और दक्षिण अफ्रीका प्रभाग (ई एंड एसए) ने किया और एस्वातीनी पक्ष का नेतृत्व विदेश मामले और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्रालय के प्रधान सचिव ने किया। एफओसी के दौरान, दोनों प्रतिनिधिमंडलों ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण पहलुओं की समीक्षा की, जिसमें राजनीतिक आदान-प्रदान, विकास भागीदारी परियोजनाएं, रक्षा सहयोग, व्यापार एवं आर्थिक मामले, कांसुलर मुद्दे और कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, कला एवं संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग शामिल है। दोनों पक्षों ने आपसी हित के बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा की, जिसमें यूएनएससी सुधार, पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में शांति और सुरक्षा, पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका के लिए कॉमन बाजार (कॉमसा), दक्षिणी अफ्रीकी विकास समुदाय (एसएडीसी) और दक्षिणी अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ (एसएसीयू) शामिल हैं। उन्होंने जी20 में अफ्रीकी संघ की सदस्यता के पीछे भारत के प्रयासों को भी स्वीकार किया और उसकी सराहना की।

स्वास्थ्य सहयोग पर पहला भारत-एस्वातीनी संयुक्त कार्यसमूह जून में वर्चुअल मोड में आयोजित किया गया।

भारत ने एसएसीयू / एसएडीसी खेलों के लिए एस्वातीनी को 4,764 अमेरिकी डॉलर मूल्य के खेल उपकरण और परिधान दान किए।

वर्ष के दौरान कुल 30 आईसीसीआर छात्रवृत्ति स्लॉट प्रदान किए गए।

इथियोपिया

इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद और वित्त मंत्री अहमद शिदे ने 17 अगस्त को वीओजीएसएस के तीसरे संस्करण में भाग लिया।

79^{वें} यूएनजीए सत्र के इतर 25 सितंबर को विदेश मंत्री ने इथियोपिया के तत्कालीन विदेश मंत्री ताये अत्सके सेलासी से मुलाकात की और आपसी हितों के कई मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।



न्यूयॉर्क में 79^{वें} यूएनजीए के इतर विदेश मंत्री ने इथियोपिया के तत्कालीन विदेश मंत्री ताये अत्सके सेलासी से मुलाकात की, सितंबर 2024

इथियोपिया के उद्योग मंत्री मेलाकु एलेबेल ने फरवरी में नई दिल्ली में “भारत टेक्स 2024” में भाग लिया। व्यापार और क्षेत्रीय अखंडता राज्य मंत्री ने 14-17 फरवरी के दौरान नई दिल्ली में आयोजित ग्लोबल पल्स कॉन्फेडरेशन में भाग लिया।

भारत के समर्थन से इथियोपिया 1 जनवरी से ब्रिक्स का सदस्य बन गया।

फरवरी में, दो भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडलों ने अदीस अबाबा का दौरा किया। मिलेनियल इंडिया इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स के एक 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल और ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम के एक 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने व्यापार और निवेश के अवसरों को बढ़ाने के लिए इथियोपिया के नवाचार एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, खनन मंत्री, कृषि मंत्री और अन्य मंत्रियों से मुलाकात की।

भारत के नागर विमानन मंत्रालय और इथियोपियाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने भारत में इथियोपियाई एयरलाइंस की पहुंच का विस्तार करने के लिए 30 जुलाई को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इथियोपियाई

एयरलाइंस अब हैदराबाद से तीन अतिरिक्त उड़ानें संचालित करेगी, जिससे दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ेगी।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मेती) ने डिजिटल परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग पर इथियोपिया के संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य के सूचना नेटवर्क सुरक्षा प्रशासन (आईएनएसए) के साथ सितंबर में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग के आर्थिक सलाहकार के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने विकास के लिए वित्तपोषण (FfD4) पर चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की प्रारंभिक समिति के पहले सत्र में भाग लिया जिसका आयोजन 21-27 के दौरान अदीस अबाबा में किया गया।

नेशनल बैंक ऑफ इथियोपिया के गवर्नर ने 28-30 अगस्त के दौरान मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में भाग लिया।

अपर महानिदेशक (प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलीफेंट) के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 28-31 जनवरी के दौरान अदीस अबाबा में आयोजित ग्लोबल चीता समिट में भाग लिया।

20 सदस्यीय इथियोपियाई सांस्कृतिक दल ने 02-18 फरवरी के दौरान सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2024 के 37^{वाँ} संस्करण में भाग लिया।

अप्रैल में, भारत द्वारा प्रायोजित जयपुर फुट आर्टिफिशियल लिम्ब फिटमेंट कैंप इथियोपिया में आयोजित किया गया। इस कैंप में 600 से अधिक इथियोपियाई नागरिकों को कृत्रिम अंग प्रदान किए गए।

केन्या

आर्थिक और व्यापार सहयोग

नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन स्कूल ऑफ बिजनेस ने 20-24 फरवरी और 18-22 मार्च को क्रमशः स्मार्ट ग्रिड और पवन ऊर्जा प्रणालियों पर दो कस्टमाइज्ड क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए। ऊर्जा मंत्रालय और पेट्रोलियम विनियामक प्राधिकरण, केन्या विद्युत उत्पादन कंपनी, केन्या विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड और ग्रामीण विद्युतीकरण एवं नवीकरणीय ऊर्जा निगम के 40 व्यावसायिकों व वृत्तिकों ने पाठ्यक्रमों में भाग लिया।

सचिव (ईआर) के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने केन्याई कृषि क्षेत्र में निवेश के अवसरों का आकलन करने के लिए कृषि क्षेत्र में काम करने वाली लगभग 25 भारतीय कंपनियों और संस्थानों के साथ 10-12 अप्रैल के दौरान केन्या का दौरा किया। 10 अप्रैल को, उन्होंने भारत-केन्या व्यापार मंच के दौरान प्रधान सचिव ए.एस.ए.एल. हरसामा केलो और कृषि प्रधान सचिव डॉ पॉल रोमोह के साथ चर्चा की, जिसमें 100 से अधिक कंपनियों ने भाग लिया। उन्होंने राजकोष कैबिनेट सचिव नुगुना नुंग से भी मुलाकात की और विदेश मामलों के प्रधान सचिव कोरिर सिंग'ओई, उसिन गिशू काउंटी के गवर्नर जोनाथन बीई और नारोक काउंटी के गवर्नर पैट्रिक ओले एनटूट के साथ बैठकें कीं। सचिव (ईआर) ने वरिष्ठ सलाहकार और आर्थिक परिवर्तन एवं सचिवालय प्रमुख, स्टेट हाउस, ऑगस्टीन चेरुइयोट और

राष्ट्रपति की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डेविड एनडीआईआई के साथ भी बैठकें कीं।

प्रधान कैबिनेट सचिव और विदेश एवं प्रवासी समुदाय मामले मंत्रालय के कैबिनेट सचिव ने 12 अप्रैल को केन्या में भारत एक्जिम बैंक के पूर्वी अफ्रीका प्रतिनिधि कार्यालय के उद्घाटन के लिए मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किए। सचिव (वित्तीय सेवा विभाग) ने नैरोबी में अफ्रीकी विकास बैंक (एएफडीबी) की 59^{वाँ} वार्षिक आम बैठक के दौरान एक्जिम बैंक और अफ्रीका-भारत भागीदारी दिवस के उद्घाटन में भाग लेने के लिए 29 मई-02 जून के दौरान केन्या का दौरा किया।

चमड़ा निर्यात परिषद (सीएलई) के नेतृत्व में चमड़ा/गैर-चमड़ा फुटवियर क्षेत्र की 38 भारतीय कंपनियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने 29-31 मई के दौरान केन्या का दौरा किया और नैरोबी के सरित एक्सपो सेंटर में एफ्लेक्स (एफ्लेक्स) 2024 में भाग लिया।

रक्षा सहयोग

भारत और केन्या के बीच तीसरी संयुक्त रक्षा सहयोग समिति (जेडीसीसी) की बैठक 03 सितंबर को नई दिल्ली में हुई। दोनों देशों ने सैन्य सहयोग, प्रशिक्षण और रक्षा उद्योग जैसे क्षेत्रों में रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। केन्या के रक्षा कैबिनेट सचिव अदन डुएल ने द्वितीय भारत केन्या रक्षा प्रदर्शनी के उद्घाटन सत्र में भाग लिया। उन्होंने 30 और 31 जनवरी को नैरोबी में केन्या रक्षा बलों और भारतीय उच्चायोग द्वारा सह-आयोजित एक संगोष्ठी में भी भाग लिया। इसमें 21 से अधिक भारतीय रक्षा निर्माताओं ने अपने उत्पादों का प्रदर्शित किया।

रक्षा सहयोग को और अधिक बढ़ाने के एक महत्वपूर्ण प्रयास के क्रम में, रक्षा सचिव ने 25-27 सितंबर के दौरान केन्या का दौरा किया। उन्होंने द्विपक्षीय रक्षा भागीदारी के तहत निर्मित और सुसज्जित किए जा रहे एक नए रेडियोलॉजी कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी।

समुद्री सहयोग को आगे बढ़ाते हुए, 02 अप्रैल को, आईएनएस तरकश ने मोम्बासा में बंदरगाह पर ठहराव किया। आईएनएस तलवार ने 22-25 सितंबर को मोम्बासा में बंदरगाह पर ठहराव किया। केन्या रक्षा बलों के कर्मियों की भागीदारी के साथ जहाज पर एक विशेष योग सत्र आयोजित किया गया।

विकास सहयोग

भारत और केन्या के बीच 23 जनवरी को एक त्वरित प्रभाव परियोजना समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें केडीएफ/केन्या नौसेना को अनुदान सहायता के तहत केन्या नौसेना बेस मटोंगेवे में एक सीटी स्कैन सुविधा स्थापित की जाएगी।

सर्वप्रथम सहायताकर्ता के रूप में, आईएनएस सुमेधा ने केन्या को बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजन, राहत और दवा की आपूर्ति की। भारतीय उच्चायुक्त ने 14 मई को बाढ़ प्रभावित केन्याई लोगों के लिए दवाइयों, चिकित्सा

आपूर्ति और अन्य उपकरणों सहित 40 मीट्रिक टन मानवीय सहायता की दूसरी खेप भेजी।

अन्य आदान-प्रदान

रासायनिक आयुध निषेध संगठन (ओपीसीडब्ल्यू) द्वारा प्रायोजित एक मेंटरशिप कार्यक्रम के तहत, संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय प्राधिकरण रासायनिक आयुध संधि (एनएसीडब्ल्यूसी) के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 3-7 जून के दौरान केन्या का दौरा किया। यह भागीदारी रासायनिक आयुध संधि के पूर्ण कार्यान्वयन हेतु केन्या राष्ट्रीय प्राधिकरण को समर्थन देने के लिए है।

वन महानिदेशक और विशेष सचिव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने वन्यजीव प्रबंधन और संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप देने के लिए 22-26 अक्टूबर के दौरान केन्या का दौरा किया। यात्रा के दौरान, प्रतिनिधिमंडल ने पर्यटन और वन्यजीव के कैबिनेट सचिव और केन्या वन्यजीव सेवा के महानिदेशक के साथ बैठक की।

केन्या के प्रवासी मामले राज्य विभाग की प्रधान सचिव, रोज़ालाइन के. न्जोगु, सीबीएस ने बेंचमार्किंग अध्ययन यात्रा के लिए 12-15 नवंबर के दौरान भारत का दौरा किया। उन्होंने विदेश मंत्रालय के सचिव (सीपीवी और ओआईए) के साथ बैठक की और अपने प्रवासियों के साथ जुड़ने तथा पीबीडी 2025 की तैयारी के लिए भारत की सर्वोत्तम प्रथाओं पर चर्चा की।

पोत परिवहन और समुद्री मामले राज्य विभाग के प्रधान सचिव ज्योफ्रे ई. कैतुको 19 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित 'सागरमंथन: द ग्रेट ओशनस डायलॉग' में भाग लेने के लिए भारत आए।

लेसोथो

लेसोथो राज्य के विदेश मंत्री लेजोन म्पोटजोआना ने 17 अगस्त को विदेश मंत्री की अध्यक्षता में वीओजीएसएस के तीसरे संस्करण के विदेश मंत्रियों के सत्र में वर्चुअल रूप से भाग लिया। सूचना, संचार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्रालय के प्रधान सचिव कनोनोरमाशामोले ने सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रियों के सत्र में भाग लिया, जिसका नाम 'विकास के लिए डीपीआई - एक वैश्विक दक्षिण दृष्टिकोण' था।

मलावी

भारत ने द्विपक्षीय राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60^{वीं} वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मलावी के साथ अपने संबंधों में एक मील का पत्थर स्थापित किया। उच्च स्तरीय आदान-प्रदान, संयुक्त युद्धाभ्यास, आईटीईसी के तहत क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, रक्षा उपकरण भेंट करना और डेफ एक्सपोज के माध्यम से रक्षा उद्योग में आदान-प्रदान के साथ द्विपक्षीय रक्षा सहयोग मजबूत किया गया।

माननीय राष्ट्रपति जी ने 17-19 अक्टूबर के दौरान मलावी का राजकीय दौरा किया। उन्होंने भारत-मलावी व्यापार राउंडटेबल सम्मेलन में शीर्ष



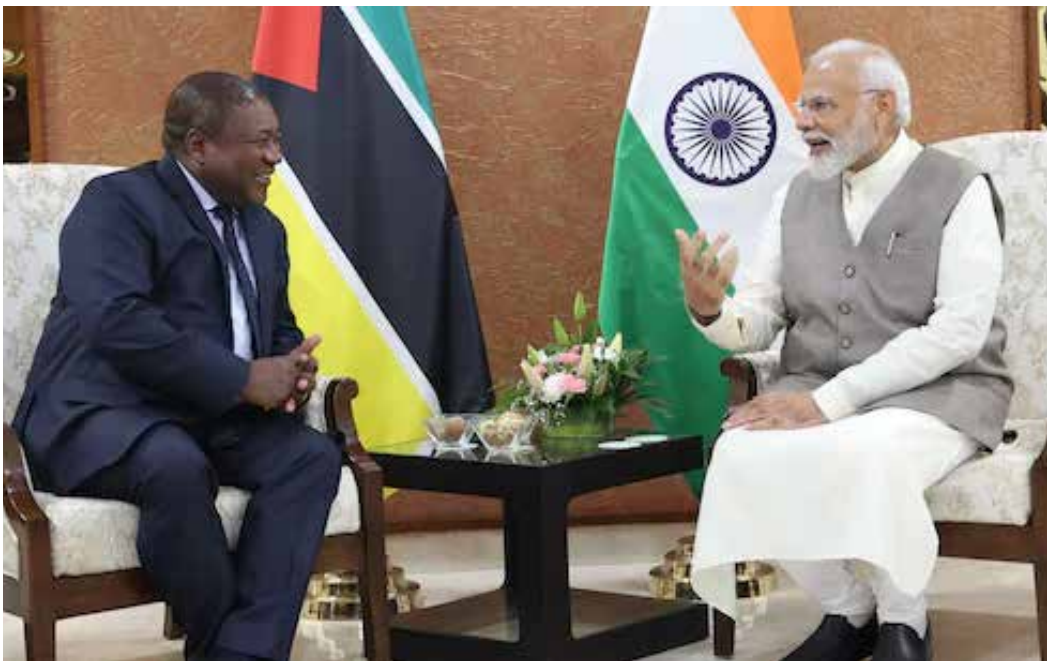
माननीय राष्ट्रपति जी ने लिलोंग्वे में मलावी के राष्ट्रपति डॉ. लाजरस मैकार्थी चकवेरा से मुलाकात की, अक्टूबर 2024

भाषण दिया, जिसमें कई मलावी मंत्रियों और दोनों देशों की 60 से अधिक कंपनियों ने भाग लिया। माननीय राष्ट्रपति जी ने मलावी में भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया। उन्होंने मलावी के राष्ट्रपति डॉ. लाजरस मैकार्थी चकवेरा से मुलाकात की और व्यापार, क्षमता निर्माण, रक्षा और विकास भागीदारी सहित द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। यात्रा के दौरान, भारत और मलावी के बीच कला और संस्कृति, युवा मामले, खेल और फार्माकोपिया सहयोग पर चार समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। भारत ने मलावी को 1000 मीट्रिक टन चावल और भाभाट्रॉन कैसर उपचार मशीनें प्रदान कीं। माननीय राष्ट्रपति जी ने मलावी में एक स्थायी कृत्रिम अंग फिटमेंट सेंटर (जयपुर फूट) की स्थापना की भी घोषणा की।

भारतीय आर्थिक व्यापार संगठन (आईईटीओ) ने व्यापार और निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए 05-13 मई के दौरान 35 भारतीय कंपनियों के एक व्यवसाय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। प्रतिनिधिमंडल ने विभिन्न व्यवसाय बैठकें कीं और राष्ट्रपति डॉ. लाजरस मैकार्थी चकवेरा से भी मुलाकात की।

मलावी के युवा मामले और खेल मंत्री उचिज़ी मकंदवीरे और व्यापार एवं उद्योग सचिव क्रिस्टीना ज़केयो ने 17 अगस्त को आयोजित वीओजीएसएस के तीसरे संस्करण में भाग लिया।

व्यापार और उद्योग मंत्री सोस्टेनवेगवे ने भारत में 20-22 अगस्त के दौरान 19^{वें} सीआईआई-एक्जिम बैंक कॉन्क्लेव में भाग लेने के लिए वित्त



प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन के 10^{वें} संस्करण के इतर मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप जैसिंटो न्यूसी से मुलाकात की, जनवरी 2024

और आर्थिक मामलों के मंत्री एवं स्वास्थ्य उप मंत्री सहित 40 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इसके इतर, व्यापार मंत्री ने 19 अगस्त को राज्य मंत्री (वाणिज्य और उद्योग) के साथ बातचीत की।

प्लास्टिक एक्सपोर्ट काउंसिल ऑफ इंडिया (प्लेक्सकॉन्सिल) और फार्मास्युटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया (फार्मेक्सिल) के सहयोग से प्लास्टिक और फार्मा सेक्टर पर दो हाइब्रिड बिजनेस मीट क्रमशः 11 जनवरी और 15 फरवरी को आयोजित की गई। भारत और मलावी दोनों से बड़ी संख्या में कंपनियों ने B2B बैठक में भाग लिया।

एचसीआई लिलोंगे ने 16 मई को लिलोंगे में ई-विद्या भारती और ई-आरोग्य भारती (ई-वीबीएबी) के तहत विभिन्न विषयों में स्नातक / स्नातकोत्तर / डिप्लोमा पूरा करने वाले 110 मलावी छात्रों के लिए एक स्नातक समारोह (ग्रेजुएशन सेयरमनी) का आयोजन किया। शिक्षा उप मंत्री नैन्सी चाओला मडूको ने छात्रों को प्रमाण पत्र सौंपे। यह एचसीआई लिलोंगे द्वारा आयोजित दूसरा स्नातक समारोह था।

मंत्रालय की मध्यस्था से, मोजाम्बिक के नकाला और बेरा बंदरगाहों पर मलावी के अरहर के निर्यात में आई व्यापार बाधाओं को दूर किया गया और जुलाई में नकाला बंदरगाह से तुर / अरहर की दाल की खेप फिर से आने लगी। भारत ने जून 2021 में, मलावी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे ताकि 2025 तक मलावी से भारत में सालाना 50,000 मीट्रिक टन अरहर का निर्यात किया जा सके।

विकासवादी भागीदारी के हिस्से के रूप में, भारत ने 24 जुलाई से 6 सितंबर तक लिलोंगे के कामुजु सेंट्रल अस्पताल में दूसरा कृत्रिम अंग फिटमेंट कैंप

(जयपुर फूट) आयोजित किया। मलावी के 599 नागरिकों में कृत्रिम अंग स्थापित किए गए।

भारत और मलावी के बीच स्वास्थ्य पर संयुक्त कार्यसमूह की दूसरी बैठक 21 नवंबर को वर्चुअल रूप से आयोजित की गई।

मोजाम्बिक

प्रधानमंत्री ने 9 जनवरी को गांधीनगर में मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप जैसिंटो न्यूसी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा, आतंकवाद निरोध, ऊर्जा, स्वास्थ्य, व्यापार एवं निवेश, कृषि, जल सुरक्षा, खनन, क्षमता निर्माण और समुद्री सहयोग के क्षेत्रों सहित द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के उपायों पर उपयोगी चर्चा की। राष्ट्रपति न्यूसी ने जी-20 में अफ्रीकी संघ (एयू) को शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र समेत बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने जनवरी और नवंबर 2023 में वीओजीएसएस में राष्ट्रपति न्यूसी की भागीदारी की सराहना की। राष्ट्रपति न्यूसी ने विभिन्न विकास परियोजनाओं और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के साथ-साथ समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के समर्थन की भी सराहना की।

मोजाम्बिक के राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार जनरल मैनुअल माजुजे ने 13-15 मार्च के दौरान भारत का दौरा किया।

भारत-मोजाम्बिक-तंजानिया त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास का दूसरा संस्करण 28 मार्च को मोजाम्बिक के नाकाला में संपन्न हुआ। सप्ताह भर चलने वाले

इस युद्धाभ्यास में भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग और अंतर-संचालन के महत्व को रेखांकित किया गया। आईएनएस तीर और सुजाता ने 21-28 मार्च तक 'आईएमटी लिटैट 24' में भाग लिया, जिसमें संयुक्त युद्धाभ्यास, प्रशिक्षण सत्र और सहयोगी गतिविधियों की एक श्रृंखला के माध्यम से नौसेनाओं को ज्ञान का आदान-प्रदान करने, क्षमताओं को बढ़ाने और क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने में सहायता प्राप्त हुई।

मोजाम्बिक के रक्षा शस्त्रागार को बढ़ाने के लिए 25-26 अप्रैल के दौरान मोजाम्बिक में पहला डिफेंस एक्सपो आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 20 भारतीय कंपनियों ने भाग लिया। भारत ने 8 नवंबर को नाकाला में एक समारोह में मोजाम्बिक को दो फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट उपहार में दिए।

भारत और मोजाम्बिक ने 18 जुलाई को भारतीय फार्माकोपिया की मान्यता के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

जुलाई में, मापुटो में भारत में अध्ययन मेला आयोजित किया गया, जिसमें 10 भारतीय विश्वविद्यालयों ने भाग लिया। 26 अगस्त-01 सितंबर के दौरान आयोजित मापुटो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भारत एक भागीदार देश था। फिक्की (फिक्की) और फियो (एफआईआईओ) ने मेले में व्यवसाय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

नामीबिया

लोकसभा अध्यक्ष ने 13 अक्टूबर को जिनेवा में 149^{वाँ} अंतर संसदीय संघ बैठक के दौरान अध्यक्ष पीटर काटजाविवि के साथ बैठक की।

नामीबिया के औद्योगीकरण एवं व्यापार उप मंत्री वर्ना सिनिम्बो ने 19^{वाँ} सीआईआई भारत-अफ्रीका व्यवसाय सम्मेलन में भाग लिया।

नामीबिया के अटॉर्नी-जनरल फेस्टस मबांडेका, महा अभियोजक और विधिक सलाहकार के साथ 02-05 फरवरी के दौरान नई दिल्ली में न्याय देने में सीमा पार चुनौतियों पर राष्ट्रमंडल अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल सम्मेलन 2024 में शामिल हुए।

नामीबिया के निर्वाचन आयोग की अध्यक्ष डॉ. एल्सी तुलेइंगेपोन्धिकेम्बुआ ने 3-8 मई के दौरान भारत में एक 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, जो ईसीआई के अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन आगंतुक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आया था।

भारत ने अल नीनो प्रेरित जलवायु परिस्थितियों के कारण उत्पन्न गंभीर सूखे की स्थिति में नामीबिया को 1000 मीट्रिक टन सफेद चावल और 1000 मीट्रिक टन पीले मक्के की मानवीय सहायता भेजी।

भारत और नामीबिया ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल डोमेन में भागीदारी की शुरुआत की। भारत के एनपीसीआई इंटरनेशनल और बैंक ऑफ नामीबिया ने नामीबिया में रीयल टाइम भुगतान प्रणाली, यूपीआई की शुरुआत के लिए एक प्रौद्योगिकी समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ नामीबिया और एनआईपीएल की भागीदारी में यह सहयोगात्मक प्रयास नामीबिया के वित्तीय बुनियादी ढांचे

के आधुनिकीकरण और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

रवांडा

प्रधानमंत्री ने जुलाई में हुए राष्ट्रपति चुनावों में लगातार चौथी बार जीत हासिल करने पर राष्ट्रपति पॉल कागामे को बधाई दी।

सचिव (ईआर) ने 07 अप्रैल को रवांडा का दौरा किया और 1994 के रवांडा नरसंहार की 30^{वाँ} वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित "क्लिबुका 30: रिमेम्बर, यूनाइटेड एंड रिव्यू" कार्यक्रम में भाग लिया। यात्रा के दौरान, उन्होंने रवांडा के मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकें भी कीं। सचिव (ईआर) की यह यात्रा रवांडा के साथ अपने संबंधों को और अधिक मजबूत करने तथा दोनों देशों के बीच उच्च-स्तरीय संपर्कों की गति को बनाए रखने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया।

दूसरी भारत-रवांडा एफओसी 05-06 दिसंबर के दौरान नई दिल्ली में आयोजित की गई।

रवांडा सरकार के अनुरोध पर, भारत-यूएन विकास भागीदारी निधि से 01 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान का अनुमोदन मई में परियोजना "एम फॉर चेंज ! एडवांसिंग रवांडा'ज मिडवाइफरी टू एक्सीलरेट द रिप्लाइजेशन ऑफ जीरो प्रिवेंटेबल मैटरनल डेथ्स थ्रू साउथ-साउथ कोआपरेशन" के लिए किया।

पहली बार, एक आठ सदस्यीय आईसीसीआर सांस्कृतिक दल 'बॉलीवुड रॉक्स' ने नवंबर में रवांडा का दौरा किया और राजधानी किगाली एवं रुबावु जिले में प्रदर्शन किया।

दक्षिण अफ्रीका

इस वर्ष भारत और दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30^{वाँ} वर्षगांठ मनाई गई।

दक्षिण अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोग उप मंत्री कैडिथ माशेगो-डलामिनी ने नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग 2024 में भाग लेने के लिए 21-24 फरवरी के दौरान भारत का दौरा किया। यात्रा के दौरान दक्षिण अफ्रीका के उप मंत्री ने तत्कालीन राज्य मंत्री (एमएल) के साथ द्विपक्षीय चर्चा की।

दक्षिण अफ्रीका के पर्यटन मंत्री पेटीसिया डी लिली ने नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उच्चायोग द्वारा आयोजित 'लोकतंत्र के 30 वर्ष, राजनयिक संबंधों के 30 वर्ष और दक्षिण अफ्रीका की जी20 अध्यक्षता की मान्यता' कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 02-05 दिसंबर के दौरान भारत का दौरा किया। उन्होंने पर्यटन मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की।

दक्षिण अफ्रीका के संचार एवं डिजिटल प्रौद्योगिकी मंत्री सोली मालत्सी 14 अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक मानक संगोष्ठी के लिए भारत आए। उन्होंने 14 अक्टूबर को पूर्वोत्तर क्षेत्र के संचार एवं विकास मंत्री से भी मुलाकात की। दक्षिण अफ्रीकी प्रतिनिधिमंडल ने 15-24 अक्टूबर के दौरान

नई दिल्ली में आयोजित विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा (डब्ल्यूटीएसए) में भी भाग लिया।

दक्षिण अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं सहयोग उप मंत्री एल्विन बोटेस ने 17 अगस्त को वीओजीएसएस के तीसरे संस्करण के विदेश मंत्रियों के सत्र में भाग लिया। दक्षिण अफ्रीका के व्यापार, उद्योग एवं प्रतिस्पर्धा विभाग के महानिदेशक मालेबो माबित्जे थॉम्पसन ने वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में व्यापार मंत्रियों के सत्र में भाग लिया।

आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय ने 01-04 अक्टूबर के दौरान एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, जो संघ के भवनों के रखरखाव और प्रिटोरिया में प्रेसीडेंसी की सीट के अनुरक्षण पर दक्षिण अफ्रीका के लोक निर्माण विभाग के साथ चर्चा करने के लिए एक अध्ययन दौरे पर गया था।

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य ने 29 फरवरी को जोहान्सबर्ग बिजनेस स्कूल में आयोजित सेमिनार “इंडिया - साउथ अफ्रीका कनेक्ट: ग्लोबल विजन्स मीट डिजिटल रिएलिटीज” के लिए दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया, जहां उन्होंने ‘भारत के उल्लेखनीय आर्थिक विकास यात्रा’ पर बात की। ‘भारत में डिजिटल भुगतान क्रांति और दक्षिण अफ्रीका के साथ सहयोग के संभावित क्षेत्र’ और ‘अपरिहार्य भारत पर दक्षिण अफ्रीकी परिप्रेक्ष्य’ पर दो पैल चर्चाएं भी आयोजित की गईं।

भारत-दक्षिण अफ्रीका ने 30 जनवरी को प्रिटोरिया में एक काउंसुलर वार्ता आयोजित की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने लंबित प्रत्यर्पण और एमएलएटी मामलों पर दक्षिण अफ्रीका के न्याय और संवैधानिक विकास विभाग के साथ भी चर्चा की।

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 30 वर्ष पूरे होने के अवसर पर, 30 दक्षिण अफ्रीकी पेशेवर प्रवक्ताओं के लिए 26 फरवरी से 09 मार्च तक हैदराबाद और दिल्ली में पत्रकारिता और जनसंपर्क पर एक आईटीईसी मीडिया प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

एक 3-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 25-30 अगस्त के दौरान न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) की वार्षिक आम बैठक में भाग लेने के लिए केपटाउन का दौरा किया। ऊर्जा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव ने एनडीबी बैठक के दौरान आयोजित ब्रिक्स ऊर्जा संगोष्ठी में भी भाग लिया।

तकनीकी उच्च शिक्षा नेटवर्क अध्ययन के दक्षिण अफ्रीकी प्रतिनिधिमंडल ने 18-26 अक्टूबर के दौरान भारत का दौरा किया, और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए भारतीय नेटवर्क (आईएनआईएचई), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), आईआईटी-दिल्ली, आईआईटी-बी, आईआईएससी-बंगलुरु और सेल्को फाउंडेशन, बंगलुरु के साथ बैठकें कीं।

भारत में डिजिटल लोक अवसंरचना और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के डिजिटल परिवर्तन के अध्ययन दौरे पर दक्षिण अफ्रीका से एक 25 सदस्यीय अंतर-विभागीय प्रतिनिधिमंडल ने 01-07 दिसंबर के दौरान भारत का दौरा किया।

रक्षा सहयोग

तत्कालीन एयर चीफ मार्शल ने 05-10 मई के दौरान दक्षिण अफ्रीकी वायु सेना के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल डब्ल्यू.एस. मबामो के निमंत्रण पर दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया, जिसका उद्देश्य भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को मजबूत करना था।

वाइस एडमिरल मोंडे लोबेस के नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीकी नौसेना के एक प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय नौसेना के बहुपक्षीय नौसैनिक युद्धाभ्यास मिलन 2024 के 12^{वें} संस्करण में भाग लेने के लिए 18-27 फरवरी के दौरान विशाखापत्तनम का दौरा किया। इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना, भाग लेने वाली नौसेनाओं के बीच



आईएनएस तलवार ने ‘भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका समुद्री युद्धाभ्यास’ (आईबीएसएएमएआर) के 8^{वें} संस्करण में भाग लेने के लिए केप टाउन का दौरा किया, अक्टूबर 2024



विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में अंतर-संसदीय संघ के अध्यक्ष और तंजानिया की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष से मुलाकात की, जुलाई 2024

अंतर-संचालन और समझ को बढ़ावा देना तथा सर्वोत्तम प्रथाओं और विशेषज्ञता को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करना था।

12^{वीं} भारत-दक्षिण अफ्रीका नौसेना स्टाफ वार्ता 27-28 अगस्त के दौरान नई दिल्ली में आयोजित की गई। दक्षिण अफ्रीकी नौसेना के प्रतिनिधिमंडल ने 29-30 अगस्त के दौरान पश्चिमी नौसेना कमान और मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स का दौरा किया। भारतीय नौसेना और दक्षिण अफ्रीकी नौसेना ने दोनों देशों के बीच पनडुब्बी बचाव सहायता को बढ़ाने के उद्देश्य से एक कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किए।

भारतीय नौसेना के आईएनएस तलवार ने 'भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका समुद्री युद्धाभ्यास' (आईबीएसएमएआर) के 8^{वें} संस्करण में भाग लेने के लिए 07-08 अक्टूबर के दौरान केप टाउन का दौरा किया।

18-22 सितंबर के दौरान प्रिटोरिया में आयोजित अफ्रीका एरोस्पेस और रक्षा एक्सपो में आठ रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और दो निजी भारतीय कंपनियों ने भाग लिया।

सांस्कृतिक आदान-प्रदान

एक आठ सदस्यीय आईसीसीआर दल 'ताल चंदम' ने 23-30 जनवरी के दौरान दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया और महात्मा गांधी फीनिक्स इंडियन सेटलमेंट के 120 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में डरबन, पीटरमैरिट्जबर्ग, टोंगाट और फीनिक्स में प्रदर्शन और कार्यशालाएँ आयोजित कीं।

तंजानिया

तंजानिया की नेशनल असेंबली की स्पीकर और अंतर-संसदीय संघ की अध्यक्ष डॉ. तुलिया एक्सन 19-24 जुलाई तक भारत की आधिकारिक

यात्रा पर थीं। उन्होंने माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री से मुलाकात की। उन्होंने वैश्विक दक्षिण में विकास चुनौतियों और बहुपक्षवाद में सुधार पर विचारों का आदान-प्रदान किया। उन्होंने संसद का भी दौरा किया और लोकसभा अध्यक्ष ने उनका स्वागत किया।

तत्कालीन तंजानिया के विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग 2024 में भाग लेने के लिए 21-23 फरवरी के दौरान भारत का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने विदेश मंत्री और वाणिज्य मंत्री के साथ बैठकें कीं।

ज़ांज़ीबार में जलापूर्ति के पुनर्वास और सुधार पर परियोजना, जिसका वित्तपोषण भारत की 92.18 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता से किया गया था, पूर्ण की गई। ज़ांज़ीबार जल प्राधिकरण (जावा) मुख्यालय 'माजी हाउस' का उद्घाटन 07 जनवरी को तंजानिया के उप प्रधानमंत्री और ऊर्जा मंत्री डॉ. डोटो मशाका बिटेको ने किया।

तंजानिया के परिवहन मंत्री मकामे मन्या मबारवा ने हैदराबाद में विंग्स इंडिया 2024 में भाग लेने के लिए 18-21 जनवरी के दौरान भारत का दौरा किया। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान तत्कालीन नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री तथा तत्कालीन नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री से मुलाकात की।

भारत-तंजानिया मैत्री प्रदर्शनी का उद्घाटन 26 जनवरी को तत्कालीन प्राकृतिक संसाधन और पर्यटन मंत्री ने तंजानिया के राष्ट्रीय संग्रहालय में किया, जिसमें दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क और ऐतिहासिक संबंधों को प्रदर्शित किया गया था।

तंजानिया के वित्त मंत्री डॉ. मविगुलुनचेम्बा ने 17 अगस्त को वित्त मंत्री की अध्यक्षता में वीओजीएसएस के तीसरे संस्करण के वित्त मंत्रियों के सत्र में भाग लिया। अपने संबोधन में, डॉ. नचेम्बा ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली में व्यापक सुधारों पर बात की ताकि इसे विकासशील देशों की जरूरतों के प्रति अधिक समावेशी और उत्तरदायी बनाया जा सके। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय

विश्वीय संस्थानों के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में विकासशील देशों के अधिकाधिक प्रतिनिधित्व करने की आवश्यकता पर बल दिया।

ज़ाज़ीबार के व्यापार और औद्योगिक विकास मंत्री उमर सईद शाबान और तंजानिया के राष्ट्रपति के योजना और निवेश कार्यालय के उप राज्य मंत्री स्टेनस्लॉस हारून न्योगो ने 20-22 अगस्त के दौरान नई दिल्ली में 19^{वें} सीआईआई भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन में भाग लिया।

एक रक्षा विंग की स्थापना करके और रेजिडेंट डिफेंस एडवाइजर द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के साथ रक्षा संबंध मजबूत हुए। दो भारतीय नौसेना के जहाज और दो तटरक्षक जहाज इस वर्ष तंजानिया गए। भारतीय तटरक्षक जहाज वराह ने 23-26 फरवरी के दौरान ज़ाज़ीबार का दौरा किया। आईएनएस तीर और आईसीजीएस सारथी ने 21-24 मार्च को ज़ाज़ीबार का दौरा किया। यात्रा के दौरान, आईएनएस तीर ने दूसरे भारत-मोज़ाम्बिक-तंजानिया लिपक्षीय युद्धाभ्यास में भाग लिया। आईएनएस सुवर्णा ने अदन की खाड़ी में चल रही एंटी-पायरेसी डिप्लाइमेंट के दौरान ऑपरेशनल टर्नअराउंड के लिए 19-21 अक्टूबर को दार एस सलाम का दौरा किया। आईएनएस सुवर्णा के स्वागत समारोह के दौरान, भारत सरकार द्वारा उपहार में दिए गए इन्फैंट्री वेपन ट्रेनिंग सिम्युलेटर को तंजानिया पीपुल्स डिफेंस फोर्स को सौंप दिया गया। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तंजानिया की नौसेना के साथ तंजानिया के ईईजेड सर्विलिंस में भी भाग लिया। भारत और तंजानिया के बीच संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की तीसरी बैठक 26-27 नवंबर के दौरान गोवा में आयोजित की गई।

तंजानिया के जल उप मंत्री कुंडो एंड्रिया मैथ्यू ने 17-20 सितंबर के दौरान नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'जल सप्ताह' में भाग लिया। जल शक्ति मंत्री ने 17 सितंबर को तंजानिया के उप मंत्री के साथ बैठक की और जल एवं संबद्ध क्षेत्रों में भारत-तंजानिया सहयोग पर उपयोगी चर्चा की।

2023-24 में, तंजानिया अफ्रीका में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बना। द्विपक्षीय व्यापार 7.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है।

भारतीय उच्चायोग ने तंजानिया के राष्ट्रीय संग्रहालय के सहयोग से 7 मार्च को 'तंजानिया की विकास यात्रा में भारतीय प्रवासियों की भूमिका और भारत-तंजानिया संबंधों को बढ़ाना' पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। संसद सदस्य और संवैधानिक एवं विधिक कार्य मंत्री पालमगाम्बा कबुडी संगोष्ठी के मुख्य अतिथि थे।

जंजीबार के सूचना, युवा, संस्कृति और खेल मंत्री ताबिया मौलिद मविता के नेतृत्व में तंजानिया के 28 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 2-18 फरवरी के दौरान हरियाणा में 37^{वें} सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में भाग लिया।

युगांडा

विदेश मंत्री, तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री (वीएम) और तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री (आरआरएस) एक प्रतिनिधिमंडल के साथ 16-22 जनवरी के दौरान कंपाला में आयोजित 19^{वें} गुटनिरपेक्ष आंदोलन (एनएएम) और



विदेश मंत्री ने कंपाला में 19^{वें} एनएएम शिखर सम्मेलन के इतर युगांडा के विदेश मंत्री जनरल जेजे ओडोंगो से मुलाकात की, जनवरी 2024

तीसरे दक्षिण-दक्षिण शिखर सम्मेलन के लिए युगांडा गए। इस अवसर पर, विदेश मंत्री ने युगांडा के विदेश मंत्री जनरल जेजे ओडोंगो के साथ द्विपक्षीय बैठक की। एनएएम के संस्थापक सदस्य के रूप में, भारत ने एनएएम शिखर सम्मेलन के लिए युगांडा को 808525.8 अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की, जिसमें दस एग्ज्यूक्टिव बसें, पांच एम्बुलेंस, दस ट्रैक्टर और ट्रेलर का दान; और 23 युगांडा के राजनयिकों (जो सीधे शिखर सम्मेलन के आयोजन में शामिल हुए थे) के लिए पूर्ण प्रायोजित प्रशिक्षण शामिल था।

वित्त, योजना एवं आर्थिक विकास राज्य मंत्री मुसासिजी हेनरी अरिगनीरा, और प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के प्रभारी स्वास्थ्य राज्य मंत्री मार्गरेट मुहंगा मुगीसा ने 17 अगस्त को वीओजीएसएस के तीसरे संस्करण में भाग लिया।

युगांडा के राज्य मंत्री (व्यापार) ने कई प्रमुख व्यवसायियों के साथ 20-22 अगस्त के दौरान नई दिल्ली में सीआईआई भारत-अफ्रीका व्यवसाय सम्मेलन में भाग लिया।

राज्य सभा के उपसभापति के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों (CSPOC) के 27^{वें} सम्मेलन में भाग लिया जिसका आयोजन 03-06 जनवरी के दौरान कंपाला में किया गया।

22 मार्च को उच्चायोग में एक भारत-युगांडा व्यवसाय बैठक आयोजित की गई, जिसमें युगांडा के राज्य मंत्री (व्यापार) और भारतीय मूल के

प्रमुख व्यवसायी उपस्थित थे। इसके अलावा, 08-09 अप्रैल को सचिव (ईआर) ने युगांडा में एक उच्च स्तरीय व्यवसाय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। उच्चायोग ने युगांडा में विभिन्न सुविधाओं, उद्योग जगत के नेताओं और संघों के साथ बी2बी बैठकों का भी आयोजन किया। प्रतिनिधिमंडल ने व्यापार, वित्त, कृषि, विदेश मामले के मंत्रियों, युगांडा निवेश एजेंसी (यूआईए), युगांडा राजस्व प्राधिकरण (यूआरए), राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संगठन (एनएआरओ) के सीईओ के साथ बातचीत की और पारस्परिक लाभों के लिए इन क्षेत्रों में सहयोग के लिए आगे के उपायों पर चर्चा की। सचिव (ईआर) की यह यात्रा युगांडा के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने और जी-20 के स्थायी सदस्य के रूप में अफ्रीकन संघ के प्रवेश के बाद भारत और महाद्वीप के देशों के बीच उच्च स्तरीय संपर्कों की गति को बनाए रखने की भारत की प्रतिबद्धता की पुनःपुष्टि करने के संदर्भ में थी।

राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय (एनडीसी) के एक 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 27-31 मई के दौरान युगांडा का दौरा किया।

भारत के डिजिटल लोक अवसंरचनाओं, विशेष रूप से अद्वितीय डिजिटल पहचान के लिए मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म (मोसिप) को शुरू करने के लिए युगांडा सरकार के साथ निरंतर संपर्क जारी है।

युगांडा के कलाकारों और कारीगरों ने सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में भाग लिया। युगांडा ने अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव में भी भाग लिया। आईसीसीआर के आठ सदस्यीय सांस्कृतिक दल, बॉलीवुड रॉकर्स ने 28 अक्टूबर-02 नवंबर के दौरान युगांडा में विभिन्न स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और कार्यशालाएँ प्रदर्शित कीं। भारतीय प्रवासियों के सहयोग से उच्चायोग ने 12-14 नवंबर के दौरान कंपाला में भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया।

जाम्बिया

माननीय राष्ट्रपति जी ने 05 जनवरी को नई दिल्ली में लेसोथो के उच्चायुक्त लेबोहांग वैलेंटाइन मोचाबा और जाम्बिया के उच्चायुक्त पर्सी पी. चंदा से प्रत्यय पत्र (क्रिडेन्शल्स) स्वीकार किए।

राज्य मंत्री (केवीएस) ने 04-07 नवंबर के दौरान जाम्बिया का दौरा किया, जहां उन्होंने विदेश मामले और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री मुलम्बो हैम्बे के साथ 06 नवंबर को लुसाका में आयोजित संयुक्त स्थायी आयोग के छठे सत्र की सह-अध्यक्षता की।

प्रौद्योगिकी और विज्ञान मंत्रालय के स्थायी सचिव डॉ. ब्रिलियंट हबीन्जू ने 17 अगस्त को वीओजीएसएस के तीसरे संस्करण के सूचना और प्रौद्योगिकी सत्र में भाग लिया।

रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव (आईसी) के नेतृत्व में तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा करने के लिए 19-20 फरवरी के दौरान जाम्बिया का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल), म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड (एमआईएल), भारत फोर्ज और एसएमपीपी प्राइवेट लिमिटेड के उद्योग प्रतिनिधि भी थे। प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा मंत्री एम्ब्रोस



राज्य मंत्री (केवीएस) ने लुसाका में जाम्बिया के विदेश मामले और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री मुलम्बो हैम्बे से मुलाकात की, नवंबर 2024

लविजिलुफुमा और वाणिज्य, व्यापार एवं उद्योग मंत्री चिपोका मुलेंगा से मुलाकात की।

सहकारिता मंत्रालय के तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 10-11 अप्रैल के दौरान लुसाका में आयोजित 'राष्ट्रीय एमएसएमई एवं सहकारिता इंडाबा' में भाग लिया। प्रतिनिधिमंडल ने इंडाबा में 'भारत के सफल सहकारी मॉडल' पर एक प्रस्तुति दी। प्रतिनिधिमंडल ने एसएमई विकास मंत्री एलियास मुबांगा से भी शिष्टाचार भेंट की।

खान मंत्रालय के संयुक्त सचिव (आईसी) के नेतृत्व में एक 15 सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने भूविज्ञान एवं खनिज संसाधन के क्षेत्र में सहयोग पर संयुक्त कार्यसमूह की लुसाका में 10-11 जून के दौरान आयोजित दूसरी बैठक में भाग लिया। प्रतिनिधिमंडल ने खान एवं खनिज विकास मंत्री पॉल काबुसवे से भी शिष्टाचार भेंट की।

भारत और जाम्बिया के बीच चौथा एफओसी 08 अगस्त को लुसाका में आयोजित किया गया। दोनों पक्षों ने रक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खान और खनिज संसाधन, लघु एवं मध्यम उद्यम, डिजिटल प्लेटफॉर्म, कांसुलर मुद्दे और सांस्कृतिक आदान-प्रदान जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों पर संतोष व्यक्त किया और उन्हें और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। संयुक्त राष्ट्र जैसे बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की गई।

भारत ने हैजा के विरुद्ध लड़ाई में सहायता के लिए जाम्बिया को 17 फरवरी को 3.5 टन ओआरएस पाउच और क्लोरीन की गोलियां मानवीय सहायता के रूप में प्रदान की।

जिम्बाब्वे

उपराष्ट्रपति चिवेंगा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल 20-22 अगस्त के दौरान 19^{वें} सीआईआई भारत-अफ्रीका व्यवसाय सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आया। प्रतिनिधिमंडल में स्वास्थ्य और बाल देखभाल मंत्री डॉ. डगलस मोम्बेशोरा और मुतापा इन्वेस्ट फंड के चीफ एग्जिक्यूटिव डॉ. जॉन पैनोनेटसा मंगुड्या सहित अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि शामिल थे।

सीआईआई के एक 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 20-21 अक्टूबर के दौरान जिम्बाब्वे का दौरा किया। सीआईआई प्रतिनिधिमंडल ने उपराष्ट्रपति चिवेंगा से मुलाकात की। रक्षा मंत्री ओप्पा मुचिंगुरी काशिरी, स्वास्थ्य और बाल देखभाल मंत्री डॉ. डगलस मोम्बेशोरा, उद्योग और वाणिज्य मंत्री मंगालिसो एनडलोवु, वित्त, आर्थिक विकास और निवेश संवर्धन उप मंत्री कुडक्वाशे मनांगाम्वा ने भी प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की।

उद्योग एवं वाणिज्य उप मंत्री राज मोदी ने भारत के लिए एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया जो गुजरात के राजकोट में 11-15 फरवरी के दौरान आयोजित सौराष्ट्र व्यापार उद्योग महामंडल (एसवीयूएम) 2024 इंटरनेशनल ट्रेड शो के 10^{वें} संस्करण में भाग लेने के लिए आया था।

जिम्बाब्वे से नेशनल डायस्पोरा टास्कफोर्स डेलिगेशन ने 13-15 फरवरी के दौरान भारत का दौरा किया और मंत्रालय में एक बैठक की।

जिम्बाब्वे के सीमा पत्तन प्राधिकरण का एक 20 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 10-16 मार्च के दौरान भारत आया और भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण के साथ चर्चा की।

अफ्रीका-एशिया विश्व आर्थिक मंच द्वारा आयोजित भारत-अफ्रीका राउंडटेबल सम्मेलन में भाग लेने के लिए एक 17 सदस्यीय कृषि प्रतिनिधिमंडल 04 मई को भारत से जिम्बाब्वे पहुंचा।

भारत-जिम्बाब्वे संयुक्त व्यापार समिति का तीसरा सत्र 13-14 मई के दौरान नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 17 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मामले और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्रालय के आर्थिक सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और प्रवासी समुदाय के मुख्य निदेशक ने किया। भारतीय पक्ष का नेतृत्व वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार ने किया।

जिम्बाब्वे इंस्टीट्यूट ऑफ डिप्लोमेसी और द दक्षिण: ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बीच 25 जून को एक लेटर ऑफ एसोसिएशन पर हस्ताक्षर किए गए और उनका आदान-प्रदान किया गया।

भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीसरा एफओसी 06 अगस्त को हरारे में आयोजित किया गया। दोनों पक्षों ने संयुक्त आयोग और संयुक्त व्यापार समिति जैसे मौजूदा संस्थागत तंत्रों सहित दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण पहलुओं की समीक्षा की। रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, खान, खनिज और भूविज्ञान, डिजिटल प्लेटफॉर्म, शिक्षा, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग पर भी चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने संयुक्त राष्ट्र में सहयोग सहित आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

डेका पंपिंग और रिवर वाटर इनटेक सिस्टम, जिसे 48.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर के भारतीय एलओसी के साथ चालू किया गया था, का भी उद्घाटन किया गया और इस वर्ष जिम्बाब्वे को सौंप दिया गया।

सूचना संचार प्रौद्योगिकी, डाक एवं कूरियर सेवा मंत्री टाटेंडा मावेटर्स ने 14-24 अक्टूबर के दौरान अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) विश्व दूरसंचार मानकीकरण सम्मेलन (डब्ल्यूटीएसए 24) में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया।

अध्याय

8

यूरोप और यूरोपीय संघ

मध्य यूरोप

वर्ष के दौरान, उच्च स्तरीय बैठकों और शिखर सम्मेलनों की एक श्रृंखला के माध्यम से मध्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के संबंधों को नई गति मिली। 21-22 फरवरी को ग्रीस के प्रधानमंत्री काइरियाकोस मिस्तोतकिस् की राजकीय यात्रा ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत और विस्तारित किया। जुलाई में प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रिया यात्रा से ऑस्ट्रिया और यूरोपीय संघ के साथ राजनीतिक संवाद और समग्र द्विपक्षीय साझेदारी में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। अगस्त में प्रधानमंत्री की पोलैंड यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ा दिया। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के लिए अपनी भारत यात्रा के दौरान चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री पेट्र फियाला ने 10 जनवरी को प्रधानमंत्री से मुलाकात की, जहाँ दोनों नेताओं ने भारत-चेकिया द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में 'नवाचार पर भारत-चेकिया रणनीतिक साझेदारी के लिए संयुक्त वक्तव्य' को अपनाने का स्वागत किया। विदेश मंत्री की जिनेवा यात्रा ने प्रमुख बहुपक्षीय मुद्दों पर स्विस् नेतृत्व और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ जुड़ाव को गहन किया। रीगा, लातविया और तिराना, अल्बानिया में नए भारतीय मिशन क्रमशः जुलाई और अगस्त में शुरू हो गए।

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, भारत और स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और लिक्टेन्स्टीन वाले यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) ने 10 मार्च को एक व्यापार और आर्थिक साझेदारी करार (टीईपीए) पर हस्ताक्षर किए। इस करार पर भारत के वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, तथा कपड़ा मंत्री के साथ-साथ स्विट्जरलैंड के फेडरल

काउंसिलर और आर्थिक मामलों, शिक्षा और अनुसंधान के संघीय विभाग के प्रमुख गाइ परमेलिन; आइसलैंड के विदेश मामलों के मंत्री बजरनी बेनेडिक्टसन; लिक्टेन्स्टीन के विदेश मामलों के मंत्री डोमिनिक हस्तर और नॉर्वे के व्यापार एवं उद्योग मंत्री जान क्रिश्चियन वेस्ट्रे ने हस्ताक्षर किए। टीईपीए में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन अमरीकी डॉलर के निवेश और 1 मिलियन प्रत्यक्ष नौकरियों के सृजन की बाध्यकारी प्रतिबद्धता शामिल है। यह ऐतिहासिक समझौता मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देगा और भारत के युवा और प्रतिभाशाली कार्यबल के लिए अवसर पैदा करेगा।

अल्बानिया, बोस्निया और हर्जोगोविना, चेकिया, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, ग्रीस, हंगरी, लातविया, लिक्टेन्स्टीन, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाक गणराज्य और स्वीडन सहित कई मध्य यूरोपीय देशों के विदेश मंत्रियों ने 21-23 फरवरी को आयोजित रायसीना वार्ता के 9^{वाँ} संस्करण में भाग लिया। विदेश मंत्री ने रायसीना वार्ता के दौरान यूरोपीय समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। इसके अतिरिक्त, विदेश मंत्री ने नॉर्डिक बाल्टिक (एनबी8) मंत्रियों के साथ एक अलग लंच बैठक की मेजबानी की। फरवरी में आयोजित भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई)-भारत यूरोप व्यापार और स्थिरता सम्मेलन में विभिन्न मध्य यूरोपीय देशों के मंत्रियों, अधिकारियों और व्यापार प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया। विदेश मंत्री ने कार्यक्रम के दौरान मुख्य भाषण दिया।

फरवरी में ऑस्ट्रिया के श्रम एवं अर्थव्यवस्था मंत्री, मार्च में डेनमार्क के शिक्षा मंत्री, अप्रैल में हंगरी के संस्कृति एवं नवाचार मंत्री, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के लिए रोमानिया और बुल्गारिया के सांस्कृतिक मंत्री, भारत



रायसीना वार्ता के 9^{वें} संस्करण में अल्बानिया, बोस्निया और हर्जगोविना, चेकिया, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, ग्रीस, हंगरी, लातविया, लिक्टेनस्टीन, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाक गणराज्य और स्वीडन सहित कई यूरोपीय देशों के विदेश मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री, नई दिल्ली, फरवरी 2024

जल सप्ताह और रीइनवेस्ट 2024 के लिए डेनमार्क के उद्योग, व्यापार एवं वित्तीय मामलों के मंत्री, शिक्षा विश्वव्यापी भारत - शिक्षा शिखर सम्मेलन 2024 के लिए मोल्दोवा के शिक्षा मंत्री और "सागरमंथन : महान महासागर सम्मेलन" के लिए ग्रीस के समुद्री मामलों और द्वीपीय नीति मंत्री जैसी मंत्रिस्तरीय यात्राओं ने विविध क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाया। अल्बानिया, बोस्निया और हर्जगोविना, क्रोएशिया, साइप्रस, मोल्दोवा, मोटेनेग्रो, नॉर्वे और स्वीडन के साथ विदेश कार्यालय और द्विपक्षीय परामर्श ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत किया। 6 सितंबर को नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय और सीआईआई द्वारा सह-मेजबानी किया गया पहला सीआईआई भारत-भूमध्यसागरीय व्यापार सम्मेलन एक महत्वपूर्ण उपलब्धि था। इस कार्यक्रम में कई भूमध्यसागरीय देशों के मंत्रियों, अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं ने भाग लिया, तथा विदेश मंत्री ने मुख्य भाषण दिया।

अल्बानिया

भारत-अल्बानिया संबंध सकारात्मक, मैत्रीपूर्ण और दूरदर्शी हैं तथा दोनों देश बहुपक्षीय मंचों पर भी सहयोग करते हैं। अल्बानिया के यूरोप एवं विदेश मामलों के मंत्री इग्ली हसानी 21-24 फरवरी को रायसीना वार्ता में भाग लेने के लिए भारत आए। उन्होंने इस अवसर पर विदेश मंत्री से मुलाकात की।

भारत सरकार ने 10 अगस्त को तिराना, अल्बानिया में अपना आवासीय मिशन शुरू किया।

अल्बानिया के स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा उप मंत्री डॉ. एंटेला रामोसाकाज ने 17 अगस्त को वीओजीएसएस के तीसरे संस्करण के स्वास्थ्य मंत्रियों के सत्र में भाग लिया। भारत और अल्बानिया ने 31 अक्टूबर को तिराना में द्विपक्षीय परामर्श बैठकें की।

ऑस्ट्रिया

9-10 जुलाई को प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रिया यात्रा के साथ भारत-ऑस्ट्रिया द्विपक्षीय संबंधों में एक नया आयाम देखने को मिला। यह 41 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी और यह राजनयिक संबंधों की 75^{वीं} वर्षगांठ के अवसर पर हुई। भारत-ऑस्ट्रिया साझेदारी बढ़ाने पर एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वान डेर बेलन से मुलाकात की और ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री और चांसलर ने ऑस्ट्रिया-भारत व्यापार मंच को संबोधित किया।

विदेश मंत्री ने 2 सितंबर को ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्रालय के राजदूतों के सम्मेलन को वर्चुअल रूप से संबोधित किया। ऑस्ट्रिया के श्रम एवं अर्थव्यवस्था मंत्री मार्टिन कोचर 19-23 फरवरी को भारत आए। उनके साथ 38 ऑस्ट्रियाई कंपनियों का एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी था। नई दिल्ली में मंत्री कोचर ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री से मुलाकात की। मंत्री कोचर ने रायसीना वार्ता और दूसरे सीआईआई भारत-यूरोप व्यापार और स्थिरता सम्मेलन में भाग लिया। यात्रा के दौरान भारत-ऑस्ट्रिया स्टार्ट-अप ब्रिज का शुभारंभ किया गया।



जुलाई 2024 में ऑस्ट्रिया की अपनी यात्रा के दौरान ऑस्ट्रिया गणराज्य के चांसलर कार्ल नेहमर के साथ प्रधानमंत्री।

बोस्निया और हर्जगोविना

इस वर्ष बोस्निया और हर्जगोविना के साथ भारत के संबंध स्थिर बने रहे। बोस्निया और हर्जगोविना के विदेश मंत्री एल्मेडिन डिनो कोनाकोविक 21-24 फरवरी को नई दिल्ली में आयोजित रायसीना वार्ता 2024 में भाग लेने के लिए भारत आए। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री से भी मुलाकात की।

भारत और बोस्निया एवं हर्जगोविना ने 28 नवंबर को साराजेवो में अपना चौथा विदेश कार्यालय परामर्श (एफओसी) आयोजित किया। एफओसी के दौरान, दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की व्यापक समीक्षा की।

बुल्गारिया

वर्ष 2024 विशेष महत्व रखता है क्योंकि भारत और बुल्गारिया ने अन्य गतिविधियों के साथ-साथ उच्च स्तरीय बैठकों, शुभकामनाओं के आदान-प्रदान, आधिकारिक और सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडलों की यात्राओं के साथ अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70^{वीं} वर्षगांठ मनाई।

बुल्गारिया के राष्ट्रपति रुमेन रादेव ने 20 मार्च को माननीय राष्ट्रपति जी के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और सोमाली समुद्री डाकुओं द्वारा बंधक बनाए गए बल्गेरियाई व्यापारी जहाज एमवी एनएन और सात बल्गेरियाई

नागरिकों वाले उसके चालक दल के सदस्यों को मुक्त कराने के लिए आभार और सराहना व्यक्त की।

विदेश मंत्री ने 16 फरवरी को म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के दौरान बुल्गारिया की तत्कालीन उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मारिया गेब्रियल से मुलाकात की। बैठक के दौरान उप प्रधानमंत्री गेब्रियल ने बताया कि बुल्गारिया के अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने की संभावना है।

भारत और बुल्गारिया के बीच संसदीय सहयोग को और भी मजबूती मिली, जब 4 और 5 जनवरी को बुल्गारिया की नेशनल असेंबली के तत्कालीन अध्यक्ष (स्पीकर) रोसेन जेलियाजकोव के नेतृत्व में 11 सदस्यीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत की यात्रा की। प्रतिनिधिमंडल ने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की।

बुल्गारिया के संस्कृति मंत्री, नैडेन टोडोरोव, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक में भाग लेने के लिए 24-25 जुलाई को नई दिल्ली आए। उन्होंने संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल 16-19 अप्रैल को बुल्गारिया की आधिकारिक यात्रा पर गए। यात्रा के दौरान सीएजी ने बल्गेरियाई राष्ट्रीय लेखा परीक्षा कार्यालय (बीएनएओ) के तत्कालीन अध्यक्ष गोरिट्सा ग्रांचारोवा के साथ एक आधिकारिक बैठक की। लेखा परीक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए भारत के सीएजी कार्यालय और बल्गेरियाई राष्ट्रीय लेखा परीक्षा कार्यालय के बीच निष्पादन लेखा परीक्षा और डेटा विश्लेषण में सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते के हिस्से के रूप में सीएजी के पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 25-29 नवंबर को बुल्गारिया के सोफिया में बीएनएओ द्वारा आयोजित 'रणनीतिक विकास (एसडीपी) कार्यशाला' और 'सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थाओं के अंतर्राष्ट्रीय संगठन (आईएनटीओएसएआई) व्यावसायिक खरीद (एफआईपीपी) के लिए मंच' में भाग लिया।

क्रोएशिया

भारत-क्रोएशिया एफओसी का 11^{वां} सत्र 30 अप्रैल को नई दिल्ली में सचिव (पश्चिम) के नेतृत्व में भारतीय पक्ष और क्रोएशिया के विदेश और यूरोपीय मामलों के मंत्रालय के महानिदेशक डॉ. पेटर मिहातोव के नेतृत्व में क्रोएशियाई पक्ष के बीच आयोजित किया गया। दोनों पक्षों ने व्यापार एवं आर्थिक, रक्षा एवं समुद्री मामले, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, नवाचार, अनुसंधान एवं विकास, पर्यटन, संस्कृति और लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने सहित मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा की।

शीर्ष आनुवंशिक फोरेंसिक वैज्ञानिक डॉ. डैगन प्रिमोरेक ने 7 सितंबर को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात की। बैठक के दौरान, डॉ. प्रिमोरेक और प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य सेवा में भारत और क्रोएशिया के बीच सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा की।



प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में क्रोएशिया के शीर्ष आनुवंशिक फोरेंसिक वैज्ञानिक डॉ. ड्रैगन प्रिमोरेक से मुलाकात की और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की, सितंबर 2024।

प्रमुख सांस्कृतिक आदान-प्रदानों में, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) प्रायोजित दो 8-सदस्यीय समूहों ने क्रोएशिया की यात्रा की। एक भांगड़ा लोक नृत्य समूह ने रिजेका में 41^{वाँ} अंतर्राष्ट्रीय कार्निवल परेड में भाग लेने के लिए फरवरी में क्रोएशिया की यात्रा की, जिसमें 10,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। समूह ने ज़गरेब और बेजलोवर में भी प्रस्तुती दी। जुलाई में रामायण थिएटर ग्रुप - रूपवाणी ने क्रोएशिया की यात्रा की और 2 जुलाई को नोविग्राद में "इंडियन समर इन इस्त्रिया" उत्सव में, सिबेनिक में 64^{वाँ} वार्षिक सिबेनिक चिल्ड्रन फेस्टिवल और कार्लोवैक शहर में प्रस्तुती दी। विश्व हिंदी दिवस 2024 के उत्सव के दौरान, ज़गरेब विश्वविद्यालय के इंडोलॉजी विभाग में, एक विशेष हिंदी कविता पुस्तक 'भारत' का विमोचन 20 मार्च को किया गया। यह कविता संग्रह भारत में क्रोएशिया के प्रथम राजदूत ड्रैगो स्टम्बुक द्वारा लिखित क्रोएशियाई कविता पुस्तक "स्लोन सिरोके" से हिंदी में अनुवादित 30 कविताओं की प्रस्तुति है।

क्रोएशिया के दो शीर्ष मीडिया घरानों के दो पत्रकार - दैनिक समाचार पत्र पोस्लोवनीडनेवनिक के म्लादेन मिलेटिक और साप्ताहिक बिजनेस पत्रिका लिडर के मिओड्रेग साजाटोविक, विदेश मंत्रालय के बाह्य प्रचार प्रभाग द्वारा मध्य मार्च में एक सप्ताह की अवधि के लिए आयोजित परिचयात्मक यात्रा पर भारत आए।

साइप्रस

2024 में, भारत और साइप्रस गणराज्य (आरओसी) के बीच राजनीतिक संबंधों को उच्च स्तरीय बातचीत की एक श्रृंखला के माध्यम से बनाए रखा गया और बढ़ाया गया। अनुसंधान, नवाचार और डिजिटल नीति उप मंत्री डॉ. निकोडेमोस दामियानौ ने 5-6 सितंबर को नई दिल्ली में "सीआईआई इंडिया मेडिटेरेनियन बिजनेस कॉन्क्लेव" में भाग लेने के लिए साइप्रस

के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। कॉन्क्लेव का उद्देश्य भारत और भूमध्यसागरीय देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग और व्यापारिक संबंधों को बढ़ाना था। इस अवसर पर, डॉ. दामियानौ ने वाणिज्य एवं उद्योग और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की और डिजिटल परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और साइबर सुरक्षा में द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए साइप्रस और भारत के बीच आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की।

विदेश मंत्री ने 24 सितंबर को 79^{वाँ} यूएनजीए के दौरान विदेश मंत्री डॉ. कॉन्स्टेंटिनोस कोम्बोस के साथ बैठक की। भारत- आरओसी एफओसी का छठा दौर 26 नवंबर को निकोसिया में आयोजित किया गया।

भारत और आरओसी के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों में 2024 में लगातार वृद्धि देखी गई है। 30 और 31 मई को लिमासोल में आयोजित रिफ्लेक्ट फेस्टिवल 2024 में भारत ने भागीदार देश के रूप में भाग लिया। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के तत्वावधान में आठ भारतीय स्टार्ट-अप और एक यूनिकॉर्न ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। 27 नवंबर को साइप्रस चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बॉम्बे चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

चेक गणराज्य

चेक गणराज्य के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंध कई यात्राओं और अन्य वार्ताओं के साथ और भी गहरे होते गए। चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री पेट्र फियाला ने 9-11 जनवरी को शिक्षाविदों के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए भारत की आधिकारिक यात्रा की। उन्होंने गांधीनगर में



चेक गणराज्य के प्रधान मंत्री, पेट्र फियाला, को एनआईएमएस विश्वविद्यालय, राजस्थान में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करते हुए, जनवरी 2024

वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट निवेश सम्मेलन में भाग लिया, प्रधानमंत्री से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की, विशेषकर ज्ञान, प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में। नेताओं ने भारत-चेकिया द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में नवाचार पर भारत-चेकिया रणनीतिक साझेदारी के लिए संयुक्त वक्तव्य को अंगीकार करने का स्वागत किया। प्रधानमंत्री पेट्र फियाला ने राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान और अनुसंधान संस्थान (एनआईएमएस) का भी दौरा किया, जहां उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई।

चेक गणराज्य के विदेश मंत्री जान लिपावस्की ने 23 फरवरी को आधिकारिक यात्रा पर व्यवसायियों के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। उन्होंने विदेश मंत्री से मुलाकात की और आर्थिक सहयोग, संसाधनों और आपूर्तिकर्ताओं के विविधीकरण, रक्षा औद्योगिक सहयोग और सुरक्षा पर चर्चा की। उन्होंने एक बिजनेस फोरम और रायसीना वार्ता में भी भाग लिया।

डेनमार्क

भारत और डेनमार्क ने अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75^{वीं} वर्षगांठ मनाई। इस वर्ष के दौरान दोनों पक्षों के बीच राजनीतिक बातचीत और यात्राओं के आदान-प्रदान में वृद्धि के साथ भारत-डेनमार्क हरित रणनीतिक साझेदारी और मजबूत हुई।

स्पीकर सोरेन गाडे (3-6 मार्च), विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन (21-22 फरवरी), व्यापार, उद्योग एवं वित्तीय मामलों के मंत्री मोर्टेन बोडस्कोव (16-18 सितंबर) और उच्च शिक्षा एवं विज्ञान मंत्री क्रिस्टीना एगेलंड (3-9 मार्च) द्वारा भारत की आधिकारिक यात्राओं ने विशेष रूप से हरित संक्रमण

क्षेत्र में, आर्थिक और तकनीकी संबंधों को गहरा करने पर केंद्रित वर्तमान सहयोग को गति प्रदान की। विदेश मंत्री रासमुसेन और विदेश मंत्री ने सितंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान न्यूयॉर्क में मुलाकात की।

डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन ने नई दिल्ली में रायसीना वार्ता 2024 के 9^{वां} संस्करण में पैनल चर्चा - "नॉर्डन लाइट्स एंड सर्जन सन: सस्टेनेबल डी-रिस्क एंड द न्यू नॉर्थ-साउथ पार्टनरशिप" में भाग लिया। उन्होंने फरवरी में सीआईआई इंडिया-यूरोप सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव में भी बात की। भारत और डेनमार्क ने नवंबर में कोपेनहेगन में बहुपक्षीय परामर्श आयोजित किया, जहाँ डेनमार्क की यूनिएससी प्राथमिकताओं और संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के साथ द्विपक्षीय समन्वय पर चर्चा की गई।

भारतीय नौसेना के जहाज तबर ने 75^{वीं} वर्षगांठ मनाने के लिए 17-19 अगस्त को डेनमार्क के एस्बर्ज बंदरगाह पर सद्भावना यात्रा की। इस कार्यक्रम में डेनमार्क की संसद के अध्यक्ष सोरेन गाडे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।

निर्धारित संस्थागत तंत्र के तहत विभिन्न बैठकें नियमित रूप से जारी रहीं। स्वास्थ्य, जल, नवीकरणीय ऊर्जा, बिजली और शिपिंग संबंधी संयुक्त कार्य समूहों की बैठकें पूरे वर्ष चलीं। भारत और डेनमार्क ने फरवरी में नई दिल्ली में प्रवासन और आवाजाही पर सहभागिता करार पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद, डेनमार्क के वरिष्ठ अधिकारियों का एक अंतर-मंत्रालयी प्रतिनिधिमंडल भारतीय हितधारकों के साथ चर्चा करने के लिए सितंबर में भारत आया। अक्टूबर में डेनमार्क की उच्च शिक्षा एवं विज्ञान एजेंसी और भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से वित्तपोषित अग्रणी ग्रीन हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी पर द्विपक्षीय मुलाकातों की घोषणा की गई।

व्यापार, वाणिज्य और आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए), राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड (एनपीसीएल) और भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ (एफआईआईओ) सहित व्यापार प्रतिनिधिमंडलों की यात्राओं से मजबूत भागीदारी देखी गई। आईएफएससीए प्रतिनिधिमंडल ने जीआईएफटी सिटी, गांधीनगर के माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से भारतीय वित्तीय बाजार में निवेश के अवसरों का प्रदर्शन किया। डेनमार्क के उद्योग, व्यवसाय और वित्तीय मामलों के मंत्री मोर्टेन बोडस्कोव ने सितंबर में री-इन्वेस्ट और भारत जल सप्ताह में भाग लिया। इसके अलावा, डेनिश व्यापार प्रतिनिधिमंडलों ने “तमिलनाडु ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट”, “वर्ल्ड फूड इंडिया” और “विंडरजी इंडिया 2024” में भाग लिया।

डेनमार्क की एक प्रमुख थिंक टैंक, डेनिश विदेश नीति सोसायटी (डीएफपीएस) ने एक बड़े प्रतिनिधिमंडल के साथ 24 नवंबर से 4 दिसंबर तक भारत की परिचयात्मक यात्रा की, तथा सीआईआई भागीदारी शिखर सम्मेलन में भाग लिया तथा नई दिल्ली और बेंगलुरु में प्रबुद्ध मंडलों से मुलाकात की।

एस्टोनिया

एस्टोनिया के साथ भारत के बढ़ते संबंधों की झलक 21-23 फरवरी को विदेश मंत्री मार्गस त्सखना की भारत यात्रा में देखने को मिली। उन्होंने रायसीना वार्ता 2024 में पैनल स्पीकर के तौर पर हिस्सा लिया। आर्थिक मामलों एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री टिट रिसालो ने भारत का दौरा किया और 10 से 12 जनवरी को ग्लोबल वाइब्रेंट गुजरात समिट में हिस्सा लिया।

साइबर और आईटी क्षेत्रों में सहयोग जारी रखते हुए, पहली भारत-एस्टोनिया साइबर वार्ता 17 जून को तेलिन में आयोजित की गई।

द्विपक्षीय सहयोग को नई दिशा देते हुए, क्षेत्रीय मामलों और कृषि मंत्री पिरैट हार्टमैन ने खाद्य उत्पादन और प्रसंस्करण से जुड़ी 10 कंपनियों के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए 2-4 दिसंबर को मुंबई और दिल्ली की यात्रा की। उन्होंने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री से मुलाकात की और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में भी बैठकें कीं।

फिनलैंड

भारत के फिनलैंड के साथ मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। इस वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे हुए। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को मनाने के लिए, 21-22 फरवरी को फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनन की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के विदेश मंत्रियों द्वारा एक संयुक्त प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया।

भारत और फिनलैंड के बीच शिक्षा में सहयोग पर सचिव स्तर पर एक उच्च स्तरीय वार्ता 31 जनवरी को वर्चुअल रूप से आयोजित की गई। प्रारंभिक से वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, छात्र आवाजाही और कौशल विकास



भारत और फिनलैंड के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, विदेश मंत्री और फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनन द्वारा एक संयुक्त प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया, नई दिल्ली, फरवरी 2024

जैसे क्षेत्रों में सहयोग को शामिल करते हुए एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया।

अक्षय ऊर्जा पर संयुक्त कार्य समूह की चौथी बैठक 20 अगस्त को संयुक्त सचिव स्तर पर वर्चुअल प्रारूप में बुलाई गई थी। सात संसद सदस्यों सहित नौ सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल वाली फिनिश वाणिज्य समिति ने 9-14 सितंबर को भारत की यात्रा की और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री से मुलाकात की। उन्होंने वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री से भी मुलाकात की। सचिव स्तर पर 5^{वीं} संयुक्त विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति की बैठक 24 सितंबर को फिनलैंड में हुई। अपर सचिव स्तर पर संयुक्त आयोग की 21^{वीं} बैठक 17 अक्टूबर को भारत में हुई।



ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस की भारत की आधिकारिक यात्रा के दौरान उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी।
प्रधानमंत्री किरियाकोस फरवरी 2024 में रायसीना वार्ता के 9^{वें} संस्करण के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि थे।

स्टार्टअप इंडिया ने 20 और 21 नवंबर को फिनलैंड में आयोजित स्लश 2024 कार्यक्रम में 39 भारतीय स्टार्टअप कंपनियों का नेतृत्व किया। मध्य प्रदेश को "ऑफबीट मल्टीस्पेशलिटी पर्यटन स्थल" के रूप में प्रदर्शित करने के लिए 18 मार्च को हेलसिंकी में एक पर्यटन रोड शो आयोजित किया गया।

ग्रीस

पिछले वर्ष स्थापित भारत-ग्रीस रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए 2024 में भी प्रयास जारी रहे। ग्रीस के प्रधानमंत्री काइरियाकोस मित्सोताकिस ने प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर 21 और 22 फरवरी को भारत का आधिकारिक दौरा किया। उनके साथ ग्रीक सरकार के मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों तथा 60 से अधिक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। यह यात्रा 16 वर्षों के बाद ग्रीस से पहली राष्ट्राध्यक्ष स्तरीय यात्रा थी। ग्रीस के प्रधानमंत्री 9^{वें} रायसीना वार्ता, 2024 में मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता थे। ग्रीस लौटने से पहले उन्होंने मुंबई का भी दौरा किया।

फरवरी में ग्रीक एनएसए की भारत यात्रा के अवसर पर राष्ट्रीय परिषद सचिवालय और ग्रीक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के कार्यालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के साथ द्विपक्षीय वार्ता तंत्र को और विस्तृत किया गया।

हेलेनिक नेशनल डिफेंस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, जनरल हूपिस ने भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के निमंत्रण पर 7-10 अप्रैल को भारत की यात्रा की, जबकि भारतीय नौसेना प्रमुख ने अपने ग्रीक समकक्ष के निमंत्रण पर 26-29 सितंबर को ग्रीस की यात्रा की। रक्षा सहयोग पर

1998 के समझौता ज्ञापन के तहत संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक 3 जुलाई को नई दिल्ली में हुई। 7 विमानों की एक बड़ी भारतीय वायु सेना टुकड़ी ने ग्रीस के माध्यम से एक पारगमन यात्रा करते हुए 20-25 जून को हेलेनिक वायु सेना के साथ एक संयुक्त हवाई अभ्यास किया। 29 अगस्त-14 सितंबर को पहली बार हेलेनिक एयर फोर्स ने चार लड़ाकू जेट और दो परिवहन विमानों के साथ भारतीय बहुराष्ट्रीय अभ्यास 'तरंग शक्ति-24' में भाग लिया। भारतीय नौसेना के जहाज ताबर ने भूमध्य सागर से अपने परिचालन बदलाव के हिस्से के रूप में 8-11 सितंबर को क्रेते के सौदा खाड़ी में एक पोर्ट कॉल भी किया।

समुद्री मामलों और द्विपक्षीय नीति मंत्री क्रिस्टोस स्टाइलियानाइड्स 18 और 19 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित "सागरमंथन - द ग्रेट ओशनस डायलॉग" में भाग लेने के लिए भारत आए। सम्मेलन के दौरान, उन्होंने शिपिंग और समुद्री क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा करने के लिए भारत के बंदरगाह, शिपिंग एवं जलमार्ग मंत्री से मुलाकात की। विश्व स्तर पर प्रभावशाली ग्रीक शिपिंग उद्योग को भारत की ओर आकर्षित करने के प्रयास में, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर (जीआईएफटी-आईएफएससी) के अध्यक्ष ने 27 मई को एथेंस में "जीआईएफटी-आईएफएससी, भारत में शिप लीजिंग और फाइनेंसिंग के अवसर" विषय पर एक विशेष इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किया। सितंबर में, इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स (कोलकाता) ने ग्रीस के यूरोबैंक एस.ए. के साथ "भारत-ग्रीस-साइप्रस (आईजीसी) बिजनेस काउंसिल" की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जो द्विपक्षीय वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ावा देगा।

द होली सी

भारत और होली सी के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध 1948 में राजनयिक संबंधों की स्थापना के समय से ही हैं। भारत होली सी के साथ अपने मैत्रीपूर्ण संबंधों को बहुत महत्व देता है। प्रधानमंत्री ने 14 जून को अपुलिया में जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान पोप फ्रांसिस से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने 23 सितंबर को न्यूयॉर्क में यूएनजीए के दौरान सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कार्डिनल पिओ परोलिन से मुलाकात की।



प्रधानमंत्री मोदी और होली सी के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कार्डिनल पिओ परोलिन, सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अवसर पर

हंगरी

पूरे वर्ष हंगरी के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों में लगातार वृद्धि होती रही। संसद सदस्य और हंगरी की राष्ट्रीय असेंबली में संसदीय विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष ज़ोल्ट नेमेथ एक प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत आए। उन्होंने 8 जनवरी को राज्य सभा के उपसभापति से मुलाकात की। निर्माण और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री और संसदीय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नंदोर सेप्रेची ने 18-21 जनवरी को बेंगलुरु में विंग्स इंडिया 2024 में अन्य प्रतिनिधियों के साथ नागरिक उड्डयन उद्योग के भविष्य के प्रक्षेपवक्र पर मंत्रिस्तरीय पूर्ण अधिवेशन में भाग लिया।

हंगरी के विदेश मंत्री पीटर सिज्जार्टो 21-22 फरवरी को नई दिल्ली में आयोजित सीआईआई-भारत यूरोप व्यापार और स्थिरता सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली आए। उन्होंने विदेश मंत्री से भी मुलाकात की और

राजनीतिक संबंधों, द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश और शिक्षा क्षेत्रों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति पर चर्चा की।

राज्यसभा के उपसभापति के नेतृत्व में राज्यसभा से एक भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल सभा ने हंगरी की नेशनल असेंबली के उपाध्यक्ष के निमंत्रण पर 6-9 मार्च को हंगरी की यात्रा की। यात्रा के दौरान, उपसभापति ने हंगरी की नेशनल असेंबली के उपाध्यक्ष इस्तवान जकाब से मुलाकात की। राज्यसभा प्रतिनिधिमंडल ने पीटर सेरेसनीस की अध्यक्षता वाले हंगरी-भारतीय मैत्री समूह से भी मुलाकात की।

हंगरी के प्रधानमंत्री कार्यालय में राजनीतिक निदेशक बालाज़ ओरबान ने अगस्त के अंत में भारत का दौरा किया और हंगरी के भाषाविद् और तिब्बती विज्ञान के संस्थापक अलेक्जेंडर स्कोमा डे कोरोस के भारत आगमन की 200^{वीं} वर्षगांठ के अवसर पर लद्दाख के जांगला गांव में एक प्रतिकृति का उद्घाटन किया। निदेशक ओरबान ने अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री से भी मुलाकात की।

आइसलैंड

10 मार्च को नई दिल्ली में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) के साथ व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते (टीईपीए) पर हस्ताक्षर के साथ भारत और आइसलैंड के द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा मिला। आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, लिकटेन्स्टीन और नॉर्वे के साथ चार ईएफटीए देशों में से एक है। आइसलैंड के तत्कालीन विदेश मंत्री बजरनी बेनेडिक्टसन ने भारत-ईएफटीए टीईपीए पर हस्ताक्षर के अवसर पर 9-11 मार्च को भारत की यात्रा की। विदेश मंत्री के साथ एक द्विपक्षीय बैठक भी हुई।

भूतापीय सहयोग पर भारत-आइसलैंड संयुक्त कार्य बल (जेटीएफ) की दूसरी बैठक 3 और 4 मई को रेकजाविक में आयोजित की गई। जेटीएफ की सह-अध्यक्षता पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संयुक्त सचिव (आईसी) और आइसलैंड के जलवायु के लिए विशेष दूत बेनेडिक्ट होस्कुलडसन ने की। भारत की विशाल 10,600 मेगावाट भूतापीय क्षमता का दोहन करने के लिए संयुक्त अनुसंधान एवं विकास, प्रौद्योगिकी साझाकरण, निवेश और क्षमता निर्माण पर चर्चा हुई।

भारत ने 19-21 अक्टूबर को रेकजाविक में आयोजित 2024 आर्कटिक सर्कल असेंबली मीटिंग में भाग लिया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के संयुक्त सचिव ने किया।

लातविया

भारत-लातविया संबंधों ने वर्ष के दौरान अपनी सकारात्मक प्रगति जारी रखी, तथा 25 जुलाई को रीगा में भारतीय दूतावास के उद्घाटन के साथ द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई।

लातविया के तत्कालीन विदेश मंत्री क्रिसजानिस करिन्स फरवरी में रायसीना वार्ता में भाग लेने के लिए भारत आए थे। उन्होंने रायसीना वार्ता 2024 के दौरान भारत-नॉर्डिक-बाल्टिक (एनबी8) मीटिंग, सीआईआई इंडिया-यूरोप बिजनेस एंड सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव में भी भाग लिया।



फरवरी 2024 में 9^{वें} रायसीना डायलॉग के अवसर पर सीआईआई भारत-यूरोप व्यापार और स्थिरता सम्मेलन में लातिविया के तत्कालीन विदेश मंत्री क्रिश्चैनिस् कर्रिस, एस्टोनिया गणराज्य के विदेश मंत्री मार्गस त्सखना, हेलेनिक गणराज्य के विदेश मंत्री जियोर्गोस गेरापेट्रिटिस के साथ विदेश मंत्री।

सितंबर में, लातविया के विदेश मंत्री बैबा ब्राजे, ओआरएफ द्वारा आयोजित "टाइगर्स टेल: क्राफ्टिंग ए न्यू डेवलपमेंट पैराडाइम" विषय पर एक पैनल चर्चा में विदेश मंत्री के साथ शामिल हुए थे।

लिकटेंस्टीन रियासत

1993 में राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद से भारत और लिकटेंस्टीन रियासत के बीच घनिष्ठ और मधुर द्विपक्षीय संबंध हैं। लिकटेंस्टीन के विदेश मंत्री डॉमिनिक हस्लर ने रायसीना वार्ता में भाग लेने के लिए 21-23 फरवरी को भारत की यात्रा की। उन्होंने 22 फरवरी को कार्यक्रम के दौरान विदेश मंत्री से भी मुलाकात की और द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। वह 10 मार्च को भारत-ईएफटीए व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते (टीईपीए) पर हस्ताक्षर करने के लिए फिर से नई दिल्ली आई।

लिथुआनिया

भारत और लिथुआनिया के बीच भाषा के माध्यम से साझा संबंध हैं। लिथुआनियाई भाषा को व्यापक रूप से व्याकरण की दृष्टि से संस्कृत के सबसे करीब की भाषा माना जाता है जो प्राचीन संबंधों को दर्शाती है। लिथुआनिया गणराज्य के क्लेपेडा राज्य बंदरगाह प्राधिकरण के महानिदेशक अल्जीस लताकास ने 28-31 जनवरी को दिल्ली और मुंबई की यात्रा की और पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग राज्य मंत्री से मुलाकात की और मुंबई बंदरगाह का भी दौरा किया।

विदेश मंत्री गेब्रियलियस लैंडसबर्गिस ने भारत की यात्रा की और रायसीना वार्ता 2024 में भाग लिया। अप्रैल में, एक लिथुआनियाई राजनयिक ने

सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस (एसएसआईएफएस) द्वारा आयोजित 71^{वें} प्रोफेशनल कोर्स फॉर फॉरेन डिप्लोमैट्स (पीसीएफडी) में भाग लिया। अगस्त में, लिथुआनिया के प्रोफेसर वितिस विदुनास ने विलनियस में भारतीय दूतावास के सहयोग से नदीसंस्कृतम् (नदीसंस्कृतम् या नदियों पर संस्कृत) का आयोजन किया, जो एक अनूठी विधि है, जिसके माध्यम से वे संस्कृत भाषा को पढ़ाते और बढ़ावा देते हैं। इस पहल का उल्लेख प्रधानमंत्री ने अपने "मन की बात" संबोधन में किया था।

माल्टा

वर्ष के दौरान दोनों देशों के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंधों में और अधिक प्रगति हुई। विदेश मंत्री ने सितंबर में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के दौरान माल्टा के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री डॉ. इयान बर्ग से मुलाकात की।

माल्टा ने फरवरी में नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) रूपरेखा करार पर हस्ताक्षर किए और आईएसए में शामिल होने वाला 119^{वां} देश बन गया।

मोलदोवा

28 दिसम्बर 1991 को भारत ने मोल्दोवा को मान्यता दी तथा 20 मार्च 1992 को उसके साथ राजनयिक संबंध स्थापित किये। भारत और मोल्दोवा के बीच संबंध मैत्रीपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण हैं।

विदेश मंत्री ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अवसर पर 24 सितंबर को मोल्दोवा के विदेश मंत्री मिहाई पोपसोई के साथ द्विपक्षीय बैठक की।

मोल्दोवा के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मिहाई पोपसोई ने विदेश मंत्री के निमंत्रण पर 15-16 दिसंबर को भारत का दौरा किया। मंत्रियों ने नई दिल्ली में हाल ही में खोले गए मोल्दोवा के रेजिडेंट मिशन का उद्घाटन किया। विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक में भारत सरकार और मोल्दोवा सरकार के बीच प्रवासन और आवाजाही साझेदारी पर आशय घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। मोल्दोवा ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने के लिए रूपरेखा करार पर भी हस्ताक्षर किए। दूसरी भारत-मोल्दोवा एफओसी बैठक 4 अक्टूबर को सचिव स्तर पर नई दिल्ली में हुई। मोल्दोवा गणराज्य की पूर्व प्रधानमंत्री नतालिया गवरिलिटा ने 23 जनवरी से 1 फरवरी को आईसीसीआर के विशिष्ट आगंतुक कार्यक्रम (डीवीपी) के तहत भारत का दौरा किया। मोल्दोवा के 11 राजनयिकों ने 10-19 जुलाई को नई दिल्ली के एसएसआईएफएस में आयोजित प्रशांत गठबंधन देशों और मोल्दोवा गणराज्य के राजनयिकों के लिए प्रथम विशेष पाठ्यक्रम में भाग लिया। मोल्दोवा के वित्त मंत्रालय के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इओन गुमेने ने 17 अगस्त को तीसरे वीओजीएसएस के वित्त मंत्रियों के सत्र में भाग लिया। 21 मार्च को चिसीनाउ में आयुर्वेद पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई।

मोंटेनेग्रो

मोंटेनेग्रो के साथ भारत के संबंध परंपरागत रूप से यूगोस्लाविया के समाजवादी संघीय गणराज्य के दिनों से ही मैत्रीपूर्ण रहे हैं, जिसका यह एक घटक गणराज्य था। विदेश मंत्री ने 26 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान मोंटेनेग्रो के विदेश मंत्री एरिन इब्राहिमोविच से मुलाकात की। मोंटेनेग्रो में संभावित निवेश के क्षेत्रों पर चर्चा हुई।

28 अक्टूबर को विदेश कार्यालय परामर्श का तीसरा दौर पोडगोरिका, मोंटेनेग्रो में आयोजित किया गया। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के संपूर्ण पहलुओं की समीक्षा की।

उत्तर मैसेडोनिया गणराज्य

भारत और उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य के बीच द्विपक्षीय संबंध उच्च स्तरीय बैठकों और आदान-प्रदान के साथ आगे बढ़े। विदेश मंत्री और उत्तरी मैसेडोनिया के विदेश मंत्री टिमको मुकुंस्की ने 27 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79^{वें} सत्र के दौरान मुलाकात की। उत्तरी मैसेडोनिया ने 17 अगस्त को आयोजित वीओजीएसएस के तीसरे संस्करण में सक्रिय रूप से भाग लिया। उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य के रोमा रणनीति के कार्यान्वयन मंत्री प्रो. शबान सालिउ ने युवा मामलों के मंत्रियों के सत्र में भाग लिया और दोनों देशों के युवाओं के बीच अधिक सहयोग की वकालत की। विदेश मामलों और विदेश व्यापार के उप मंत्री ज़ोरान दिमित्रोव्स्की ने वीओजीएसएस के तीसरे संस्करण के विदेश मंत्रियों के दूसरे सत्र में भाग लिया। उन्होंने वीओजीएसएस को वैश्विक दक्षिण के देशों के दृष्टिकोण, प्राथमिकताओं और चुनौतियों को स्पष्ट करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बताया तथा वैश्विक अभिशासन में वैश्विक दक्षिण देशों के प्रभाव को मजबूत

करने और उनके बीच संवाद तथा सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए शिखर सम्मेलन की गतिविधियों के प्रति समर्थन व्यक्त किया।

नॉर्वे

भारत और नॉर्वे ने अपने मजबूत और विकसित द्विपक्षीय संबंधों को और दृढ़ बनाए रखना जारी रखा, विशेष रूप से द्विपक्षीय व्यापार, समुद्री अर्थव्यवस्था और ऊर्जा क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। 21-23 अगस्त को, राज्य मंत्री (केवीएस) ने ट्रेक 1.5 नॉर्डिक-इंडिया वार्ता के पहले संस्करण के लिए नॉर्वे की यात्रा की। उन्होंने नॉर्वे के विदेश मंत्री एस्पेन बार्थ ईंडे और पर्यावरण और जलवायु मंत्री एंड्रियास बेजलैंड एरिक्सन से भी मुलाकात की।

25 जुलाई को, विदेश मंत्री ने लाओस में आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक के मौके पर नॉर्वे के विदेश मंत्री से मुलाकात की। 22 और 23 फरवरी को, नॉर्वे के विदेश मंत्रालय में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड्रियास मोट्ज़फेल्ड क्राविक ने रायसीना वार्ता में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा की। इस अवसर पर, वे विदेश मंत्री द्वारा आयोजित लंच मीटिंग में एनबी8 देशों के अन्य मंत्रियों के साथ भी शामिल हुए।



नॉर्वे के विदेश मंत्री एस्पेन बार्थ ईंडे के साथ वियनतियाने, लाओस में 57^{वां} आसियान बैठक के अवसर पर विदेश मंत्री, अगस्त 2024

10 मार्च को नॉर्वे के तत्कालीन व्यापार और उद्योग मंत्री जान क्रिश्चियन वेस्ट्रे ने भारत-यूरोपीय मुक्त व्यापार संच-व्यापार और आर्थिक भागीदारी

समझौते (टीईपीए) पर हस्ताक्षर करने के लिए नई दिल्ली की यात्रा की। बाद में, 14 अगस्त को इन्वेंशन नॉर्वे और नॉर्वे-भारत चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एनआईसीसीआई) ने संयुक्त रूप से टीईपीए के लिए एक विशेष सत्र आयोजित किया, और इस कार्यक्रम में नॉर्वे के विदेश मंत्री ने भाग लिया।

भारत-नॉर्वे विदेश कार्यालय परामर्श का 11^{वाँ} दौर 14 मई को नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसकी सह-अध्यक्षता सचिव (पश्चिम) और नॉर्वे के विदेश मंत्रालय के महासचिव तोरगीर लार्सन ने की।

2024 में, नॉर्वे के संसदीय प्रतिनिधिमंडलों द्वारा भारत की दो यात्राएँ की गईं, पहली बार फरवरी में और फिर सितंबर में। बाद में नवंबर में, 7 सदस्यीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने नॉर्वे की यात्रा की। अन्य आधिकारिक प्रतिनिधिमंडलों में महानिदेशक, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (12-16 मार्च); अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) (13 सितंबर); सचिव, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (20-21 सितंबर); और वाणिज्य सचिव (22 नवंबर) की यात्राएँ शामिल थीं।

फरवरी में गोवा सरकार के मत्स्य पालन मंत्री के नेतृत्व में एक सरकारी सह व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल नॉर्वे गया था।

भारत ने दिसंबर 2023 से नॉर्वे के स्वालबार्ड के न्यू एलेसुंड में स्थित भारत के आर्कटिक अनुसंधान स्टेशन हिमाद्री में शीतकालीन अभियान शुरू किया और 2024 से पूरे वर्ष स्वालबार्ड में भारतीय उपस्थिति को प्रभावी रूप से बनाए रखा।

18 और 19 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित “सागरमंथन: द ग्रेट ओशनस डायलॉग” के प्रथम संस्करण में नॉर्वे एक भागीदार देश के रूप में शामिल हुआ।

पोलैंड

भारत और पोलैंड के बीच दीर्घकालिक मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, जो उच्च स्तरीय राजनीतिक संपर्क, जीवंत आर्थिक जुड़ाव और लोगों से लोगों के बीच अद्वितीय संबंधों की विशेषता से युक्त हैं। पोलैंड के प्रधान मंत्री के निमंत्रण पर, प्रधानमंत्री ने 21 और 22 अगस्त को पोलैंड की आधिकारिक यात्रा की और यह यात्रा भारत और पोलैंड के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70^{वीं} वर्षगांठ के अवसर पर हुई। यह एक ऐतिहासिक यात्रा थी जो किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पोलैंड की पिछली यात्रा के 45 वर्ष बाद हुई थी। प्रधानमंत्री ने पोलिश प्रधान मंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ विचार-विमर्श किया और पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा से भी मुलाकात की। दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत-पोलैंड द्विपक्षीय संबंधों को एक रणनीतिक साझेदारी के रूप में बढ़ाने की घोषणा की और द्विपक्षीय साझेदारी पर एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया। भारत-पोलैंड सामाजिक सुरक्षा करार और सामाजिक सुरक्षा करार के लिए प्रशासनिक व्यवस्था की घोषणा प्रधानमंत्री की पोलैंड यात्रा के दौरान की गई और 25 नवंबर को वारसो में इस पर हस्ताक्षर किए गए।



पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क द्वारा पोलैंड में वारसो के संघीय चांसलरी में प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया, अगस्त 2024

विदेश मामलों के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट व्लादिस्लाव टेओफिल बार्टोजेव्स्की ने 19-23 फरवरी को भारत की यात्रा की और तत्कालीन राज्य मंत्री (एमएल) और उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मुलाकात की। उन्होंने रायसीना वार्ता 2024 के 9^{वें} संस्करण में भी भाग लिया। पोलैंड के डिजिटल मामलों के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मिशाल ग्रामाट्यका ने 15 और 16 अक्टूबर को नई दिल्ली में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा 2024 सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया।

भारत और पोलैंड के बीच आर्थिक संबंध लगातार और मजबूत होते रहे और द्विपक्षीय व्यापार 5.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले दशक की तुलना में 200 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। सीआईआई क्षेत्रीय कार्यालय पश्चिम बंगाल, भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ (एफआईआईओ), भारतीय आर्थिक व्यापार संगठन (आईईटीओ) के नेतृत्व में भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडलों ने पोलैंड में प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों और मेलों में भाग लिया। पोलैंड के कैटोविस में यूरोपीय आर्थिक कांग्रेस के 16^{वें} संस्करण में भारत और पोलैंड के बीच आर्थिक सहयोग और भारत में उपलब्ध निवेश अवसरों पर एक उच्च स्तरीय पैनल चर्चा आयोजित की गई।

भारतीय दूतावास के रक्षा विंग को अप्रैल में पुनः खोला गया, जिसमें एक ब्रिगेडियर स्तर के अधिकारी को स्थानीय रक्षा अताशे के रूप में तैनात किया गया।

रोमानिया

भारत और रोमानिया के बीच द्विपक्षीय संबंध मधुर और मैत्रीपूर्ण हैं। रोमानिया की विदेश मंत्री लुमिनिता ओडोबेस्कु ने 22-24 फरवरी को रायसीना वार्ता में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया। उन्होंने इस दौरान विदेश मंत्री से भी मुलाकात की। इस यात्रा के दौरान भारत और रोमानिया के बीच व्यापक साझेदारी स्थापित करने संबंधी संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर की 10^{वीं} वर्षगांठ के बाद एक संयुक्त घोषणा-पत्र जारी किया गया। 17 सितंबर को, विदेश मंत्री ने संचार मंत्री और भारत में रोमानिया के राजदूत के साथ मिलकर राजनयिक संबंधों की 75^{वीं} वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारत-रोमानिया संयुक्त स्मारकीय डाक टिकट जारी किए। संयुक्त टिकटों का अनावरण बुखारेस्ट में रोमानिया में भारत के राजदूत और रोमफिलाटेलिया के सीईओ द्वारा भी किया गया। विदेश मंत्री ने 26 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अवसर पर रोमानिया के विदेश मंत्री लुमिनिता-टेओडोरा ओडोबेस्कु के साथ द्विपक्षीय बैठक की।

भारत-रोमानिया रक्षा सहयोग करार 14 अप्रैल को लागू हुआ, इस पर 28 मार्च 2023 को हस्ताक्षर किए गए थे। भारत-रोमानिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति (जेसीडीसी) की पहली बैठक 23 अप्रैल को बुखारेस्ट में हुई। 22-24 मई को ब्लैक सी डिफेंस एंड एयरोस्पेस प्रदर्शनी (बीएसडीए) में दस भारतीय रक्षा कंपनियों/स्टार्टअप्स ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया। यह पहली बार था जब बीएसडीए में भारत का मंडप लगाया गया था। भारतीय और रोमानियाई रक्षा उद्योगों के लिए पहला सेमिनार 25 मई को आयोजित किया गया था।



विदेश मंत्री ने 9^{वीं} रायसीना वार्ता के अवसर पर रोमानिया की विदेश मंत्री लुमिनिता ओडोबेस्कु से मुलाकात की, फरवरी 2024

अगस्त में बुखारेस्ट के संसद भवन में "संस्कृतियों को साथ लाना" प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। इसमें कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के ललित कला संकाय के डीन डॉ. राम विरंजन की 75 जलरंग पेंटिंग प्रदर्शित की गई थीं।

सर्बिया

भारत-सर्बिया द्विपक्षीय संबंध, जो ऐतिहासिक और परंपरागत हैं, 2024 के दौरान भी मजबूत और मैत्रीपूर्ण बने रहे। जून 2023 में माननीय राष्ट्रपति जी की सर्बिया की राजकीय यात्रा ने संबंधों को और मजबूती प्रदान की है। हाल ही में, दोनों देशों ने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75^{वीं} वर्षगांठ मनाई। जनवरी में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 19^{वें} शिखर सम्मेलन के अवसर पर विदेश मंत्री ने कंपाला में अपने सर्बियाई समकक्ष पूर्व विदेश मंत्री इविका डेसिक से मुलाकात की।

सर्बिया ने वीओजीएसएस के तीसरे संस्करण के पर्यावरण मंत्रियों के सत्र में भाग लिया, जो अगस्त में वर्चुअल प्रारूप में आयोजित किया गया था और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा आयोजित किया गया था। जनवरी में भारतीय-सर्बियाई चैंबर ऑफ बिजनेस एंड कॉमर्स की स्थापना की गई थी। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने मार्च में बेलग्रेड में आयोजित क्रॉस-कंट्री विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए आठ सदस्यीय टीम की यात्रा को प्रायोजित किया।

स्लोवाकिया

भारत और स्लोवाकिया ने विभिन्न वार्ताओं के माध्यम से अपनी सहभागिता जारी रखी। स्लोवाकिया के विदेश मंत्री जुराज ब्लानार 20-23 फरवरी को रायसीना वार्ता 2024 के लिए भारत आए। उन्होंने नई दिल्ली में विदेश मंत्री और रक्षा सचिव से मुलाकात की। इस यात्रा के दौरान, स्लोवाक विदेश मंत्री के साथ व्यापार और रक्षा कंपनियों का 22 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी था। उन्होंने दूसरे सीआईआई भारत-यूरोप व्यापार और स्थिरता सम्मेलन में भाग लिया। यात्रा के दौरान विदेश मंत्री जुराज ब्लानार ने नई दिल्ली में स्लोवाक नवाचार और प्रौद्योगिकी दिवस का भी उद्घाटन किया और भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) और स्लोवाक गणराज्य के मानक, माप विज्ञान और परीक्षण कार्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।



विदेश मंत्री ने 9^{वीं} रायसीना वार्ता के अवसर पर स्लोवाक विदेश मंत्री जुराज ब्लानार से मुलाकात की, फरवरी 2024

स्लोवेनिया

भारत और स्लोवेनिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों में 2024 के दौरान और भी मजबूत बने रहे। सितंबर 2021 में विदेश मंत्री की यात्रा के दौरान भारत केंद्र की स्थापना की पहल की घोषणा की गई थी। विदेश मंत्री ने 27 सितंबर को यूएनजीए के दौरान स्लोवेनिया के विदेश मंत्री तानजा फाजोन से मुलाकात की। स्लोवेनिया के उच्च शिक्षा, विज्ञान और नवाचार मंत्री डॉ.

इगोर पापिक 4-6 दिसंबर, 2024 को नई दिल्ली में 9^{वाँ} भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन और दूसरे जलवायु निवेश और प्रौद्योगिकी प्रभाव शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए।

स्लोवेनिया के जोसेफ स्टीफन इंस्टीट्यूट (जेएसआई) में 6 फरवरी को पहला भारत-स्लोवेनिया विज्ञान एवं नवाचार दिवस आयोजित किया गया। इस अवसर पर भारत के अनुसंधान एवं सूचना (आरआईएस) और स्लोवेनिया विज्ञान फाउंडेशन के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। उत्तराखंड के नंदा देवी बायो रिजर्व (फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान) और स्लोवेनिया के ट्रिग्लव राष्ट्रीय उद्यान (टीएनपी) के बीच 16 फरवरी को टीएनपी की 100^{वीं} वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

विज्ञान, नवाचार, प्रौद्योगिकी और शिक्षा (एसआईटीई) के क्षेत्र में भारत और स्लोवेनियाई विशेषज्ञों का एक नेटवर्क शुरू किया गया, जिसके तहत दोनों देशों के विशेषज्ञों को नवीन विचारों और आविष्कारों के आदान-प्रदान के लिए एक साथ लाया गया। 9 अप्रैल को भारतीय अध्याय और 21 जून को स्लोवेनिया अध्याय का शुभारंभ किया गया। 26 जुलाई को, लजुब्लजाना चिडियाघर ने भारत के गिर वन से आई एशियाई शेर वंश की 'जीवाना' नामक एक शेरनी का स्वागत किया। जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और स्लोवेनिया के कृषि संस्थान के बीच अनुसंधान, संकाय और छात्र आदान-प्रदान और विकास, विशेष रूप से मधुमक्खी संरक्षण तथा शहद उत्पादन क्षेत्र में सहयोग के लिए 29 अगस्त को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। 9 सितंबर को नोवा विश्वविद्यालय, लजुब्लजाना में एक 'भारत अध्ययन केंद्र' की स्थापना की गई।

स्वीडन

भारत और स्वीडन ने प्रौद्योगिकी, व्यापार, जलवायु बचाव कार्रवाई, नवाचार और सुरक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए कई सहयोगी पहलों के माध्यम से अपनी साझेदारी को गहन किया है। न्यूयॉर्क में 79^{वाँ} यूएनजीए के अवसर पर, विदेश मंत्री ने 26 सितंबर को स्वीडन की विदेश मंत्री मारिया माल्मर स्टेनगार्ड से मुलाकात की।

केंद्रीय पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री और स्वीडन की जलवायु एवं पर्यावरण मंत्री रोमिना पूरमोस्तारी ने बाकू, अजरबैजान में आयोजित सीओपी-29 के दौरान लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन (लीड आईटी) के 6^{ठें} वार्षिक शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता की। दोनों मंत्रियों ने लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन की पांच वर्ष की रिपोर्ट भी जारी की। रिपोर्ट में 2019 में लॉन्च होने के बाद से इस पहल की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है।

2024 में स्वीडन के विदेश मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग और विदेश व्यापार मंत्री के स्टेट सेक्रेटरी हाकन जेवरेले ने पांच बार भारत की यात्रा की। 4 और 5 दिसंबर को अपनी पिछली यात्रा के दौरान, उन्होंने सचिव (पश्चिम) से मुलाकात की और 25^{वाँ} भारत द्विपक्षीय मंच में भाग लिया। इससे पहले, 25 सितंबर को, उन्होंने बेंगलुरु में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव से

मुलाकात की। जनवरी में, स्वीडन के इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टेट सेक्रेटरी जोहान डेविडसन ने भारत की यात्रा की और भारत के आवासन एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री के साथ बैठक की।

स्वीडन के पूर्व विदेश मंत्री टोबियास बिलस्ट्रॉम ने नई दिल्ली में रायसीना वार्ता 2024 में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया, जिसमें उन्होंने नवाचार, हरित प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण में सहयोग के माध्यम से द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया। इसके अलावा, उन्होंने बेंगलुरु में इसरो परिसर का दौरा किया, जो सतत विकास और वैज्ञानिक नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सहयोग को बढ़ावा देने में स्वीडन की रुचि का प्रतीक है।

4 मार्च को स्वीडिश रक्षा निर्माता कंपनी एसएएबी ने हरियाणा के झज्जर में कंधे से दागी जाने वाली हथियार प्रणाली कार्ल गुस्ताफ मार्क IV के लिए अपनी विनिर्माण सुविधा का शिलान्यास किया। यह स्वीडन के बाहर कार्ल गुस्ताफ की पहली विनिर्माण सुविधा थी।

अप्रैल में, भारत और स्वीडन के बीच स्वास्थ्य पर 13^{वें} संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की बैठक स्टॉकहोम में हुई। भारत-स्वीडन उद्योग बदलाव मंच (आईटीपी) ने अप्रैल में नई दिल्ली में अपनी उद्घाटन बैठक के साथ अपना काम शुरू किया। इस पहल का उद्देश्य दोनों देशों के नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और उद्योगों के बीच सहयोग के माध्यम से औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन में तेजी लाना और स्थायी पद्धतियों को बढ़ावा देना है। मई में, भारत-स्वीडन विदेश कार्यालय परामर्श का 7^{वां} दौर स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था, जिसमें सचिव (पश्चिम) के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल शामिल रहा।

भारत-स्वीडन नवाचार दिवस का 11^{वां} संस्करण 14 अक्टूबर को स्टॉकहोम में आयोजित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य समावेशी परिवर्तन के लिए हरित विकास को गति देना था। इस कार्यक्रम में स्वीडन के उप प्रधानमंत्री और ऊर्जा एवं उद्यम मंत्री एब्बा बुश ने व्यक्तिगत रूप से भाग लिया और भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने वर्चुअल रूप से भाग लिया।

स्वीडिश फिल्म निर्माता लेवन अकिन की फिल्म 'क्रॉसिंग' को 28 नवंबर को गोवा में आयोजित 55^{वें} भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई) में प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म, टेलीविजन और दृश्य-श्रव्य संचार परिषद (आईसीएफटी)-यूनेस्को गांधी पदक से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार इस फिल्म में शांति, अहिंसा और मानव अधिकारों के संवर्धन के सशक्त अन्वेषण के लिए दिया गया।

स्विट्जरलैंड

विदेश मंत्री ने 11-14 सितंबर को स्विट्जरलैंड की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा की। उन्होंने 13 सितंबर को जिनेवा में अपने समकक्ष फेडरल काउंसिलर डॉ. इग्राजियो कैसिस के साथ द्विपक्षीय बैठक की।

भारत और स्विट्जरलैंड ने वित्तीय क्षेत्र में सहयोग को मजबूत और तीव्र करने के उद्देश्य से मार्च में वित्तीय वार्ता का छठा दौर आयोजित किया।



विदेश मंत्री की स्विट्जरलैंड की आधिकारिक यात्रा के दौरान विदेश मंत्री और स्विट्जरलैंड के संघीय पार्षद डॉ. इग्राजियो कैसिस, सितंबर 2024

10 मार्च को नई दिल्ली में भारत-ईएफटीए व्यापार एवं आर्थिक भागीदारी करार (टीईपीए) पर हस्ताक्षर के बाद 2024 में भारत और स्विट्जरलैंड के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को नई गति मिली। इसके साथ ही, स्विट्जरलैंड और अन्य ईएफटीए देश भारत के साथ मुक्त व्यापार करार (एफटीए) करने वाले पहले यूरोपीय भागीदार बन गए। इस ऐतिहासिक समझौते को लागू करने के तरीकों पर चर्चा करने के उद्देश्य से, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने 14-15 जुलाई को स्विट्जरलैंड का आधिकारिक दौरा किया।

तुर्किए

विदेश मंत्री ने 27 जुलाई को विएंतिमाने में 57^{वां} आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान तुर्किए के विदेश मंत्री हकन फिदान के साथ द्विपक्षीय बैठक की।

विदेश मंत्री हकन फिदान ने 17 अगस्त को वीडियो संदेश भेजकर वीओजीएसएस के तीसरे संस्करण के विदेश मंत्रियों के सत्र में वर्चुअल रूप से भाग लिया। तुर्की के ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन उप मंत्री अहमत बेरात कोनकर ने 17 अगस्त को वीडियो संदेश भेजकर वीओजीएसएस के तीसरे संस्करण के ऊर्जा मंत्रियों के सत्र में भाग लिया।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री ने 17 सितंबर को अमेरिका के ह्यूस्टन में गैसटेक 2024 सम्मेलन के दौरान तुर्किए के ऊर्जा मंत्री अलपसलान बायराक्तर से मुलाकात की।



विंतिगाने, लाओस में 57^{वीं} आसियान बैठक के अवसर पर विदेश मंत्री, तुर्किए के विदेश मंत्री हुकन फिदान के साथ। जुलाई 2024

सचिव (पश्चिम) ने सितंबर में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान तुर्की के उप विदेश मंत्री डॉ. नुह यिलमाज के साथ द्विपक्षीय बैठक की थी।

सीआईआई इंडिया-मेडिटेरेनियन बिजनेस कॉन्क्लेव

विदेश मंत्रालय ने सीआईआई के साथ मिलकर 6 सितंबर को नई दिल्ली में प्रथम सीआईआई इंडिया-मेडिटेरेनियन बिजनेस कॉन्क्लेव का आयोजन किया। यह कार्यक्रम व्यवसायों के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है, जहाँ वे विचारों का आदान-प्रदान कर सकते हैं, साझेदारी की संभावनाएँ तलाश सकते हैं और सरकारी स्तर पर उद्योग-विशिष्ट सिफारिशें प्रदान कर सकते हैं। कॉन्क्लेव ने बहुमूल्य व्यावसायिक संबंधों को सुगम बनाया। विदेश मंत्री ने समापन सत्र में "भारत- मेडिटेरेनियन भविष्य का मार्ग: भविष्य के लिए भागीदारी बनाना" शीर्षक से मुख्य भाषण दिया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने पूर्ण सत्र में वक्तव्य दिया, इसमें सीरियाई अरब गणराज्य की अर्थव्यवस्था एवं विदेश व्यापार उप मंत्री रानिया अहमद और साइप्रस गणराज्य के अनुसंधान, नवाचार एवं डिजिटल नीति उप मंत्री डॉ. निकोडेमोस दामियानौ ने भाग लिया। कॉन्क्लेव में व्यापार और निवेश, प्राकृतिक संसाधन, भविष्य की तकनीक और बुनियादी ढाँचे सहित विभिन्न विषयों पर सत्र आयोजित किए गए। जिन विषयों को शामिल किया गया उनमें औद्योगिक रक्षा, डिजिटल परिवर्तन, समुद्री सहयोग, विनिर्माण नवाचार और शहरी बुनियादी ढाँचा शामिल थे।

यूरोप पश्चिम

एंडोरा

मार्च में भारत और एंडोरा के बीच राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा अपेक्षाओं में छूट पर एक द्विपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। 2022-23 में भारत और एंडोरा के बीच द्विपक्षीय व्यापार 3.28 मिलियन अमरीकी डॉलर रहा, जिसमें लगभग सारा व्यापार एंडोरा को भारतीय निर्यात (3.27 मिलियन अमरीकी डॉलर) था, जिसमें मुख्य रूप से कपड़ा तथा परिधान, चमड़े के उत्पाद एवं जूते, लोहा और इस्पात तथा कीमती एवं अर्ध-कीमती पत्थर शामिल हैं।

एंडोरा में करीब 140 भारतीय/भारतीय मूल के निवासी रहते हैं। भारतीय समुदाय 1970 के दशक से एंडोरा में इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचने वाले व्यवसायी के रूप में काम कर रहा है और बाद में अन्य क्षेत्रों में भी फैल गया।

बेल्जियम

भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंध हैं जो साझा समानताओं और विधि के शासन, संघवाद और बहुलतावाद के प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित हैं। बेल्जियम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की आकांक्षा का समर्थन करता है।

प्रधानमंत्री ने 26 मार्च को बेल्जियम के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डी क्रू के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, परिषद की बेल्जियम की अध्यक्षता के तहत भारत-यूरोपीय संघ साझेदारी को आगे ले जाने और क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर सहयोग पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

विदेश मंत्री ने 17 फरवरी को म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के अवसर पर बेल्जियम के विदेश मंत्री हादजा लाहबीब से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों तथा यूरोपीय संघ परिषद की बेल्जियम की अध्यक्षता के दौरान मिलकर काम करने पर चर्चा की।

विदेश मंत्री ने सितम्बर में न्यूयॉर्क में 79^{वीं} संयुक्त राष्ट्र महासभा के अवसर पर बेल्जियम के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डी क्रू से मुलाकात की।

10 अप्रैल को नई दिल्ली में सचिव (पश्चिम) और विदेश मंत्रालय में बोर्ड के महासचिव और अध्यक्ष थियोडोरा जेंट्जिस की अगुवाई में विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया गया। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। जेंट्जिस ने विदेश मंत्री से भी मुलाकात की।

18^{वीं} भारत-बेल्जियम-लक्जमबर्ग-आर्थिक संघ संयुक्त आयोग बैठक (भारत बीएलईयू जेसीएम) अप्रैल 2024 में नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस अवसर पर द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग सहित कई मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई।



विदेश मंत्री ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन, फरवरी 2024 के अवसर पर बेल्जियम के विदेश मंत्री हादजा लाहबीब के साथ मुलाकात की

परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव ने 21 मार्च को ब्रुसेल्स में बेल्जियम सरकार और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित प्रथम परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन में भाग लिया।

बेल्जियम, भारतीय उत्पादों के लिए 18^{वें} सबसे महत्वपूर्ण गंतव्य के रूप में स्थान रखता है और भारत, बेल्जियम के मुख्य व्यापार भागीदारों में 19^{वें} स्थान पर है। जनवरी - सितंबर 2024 के दौरान वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार 8.16 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा, जिसमें से भारतीय निर्यात 4.83 बिलियन अमरीकी डॉलर और बेल्जियम का निर्यात 3.34 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा। सितंबर 2024 तक बेल्जियम से कुल एफडीआई 3,941.03 मिलियन अमरीकी डॉलर था। नवीनतम अनुमानों के अनुसार, बेल्जियम में लगभग 24,732 भारतीय प्रवासी हैं।

यूरोपीय संघ

विशाल जीवंत लोकतंत्रों, खुले बाजार अर्थव्यवस्थाओं और बहुलतावादी समाजों के उदाहरण भारत और यूरोपीय संघ ने 2024 में अपनी रणनीतिक साझेदारी की 20^{वीं} वर्षगांठ मनाई। इस वर्ष नियमित रूप से उच्च स्तरीय वार्ताएं हुईं और व्यापार एवं निवेश, उभरती प्रौद्योगिकियों, नवाचार, हरित परिवर्तन, सुरक्षा और प्रवासन एवं आवाजाही के क्षेत्रों में सहयोग और अधिक गहन हुआ।

यूरोपीय परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने 10 अक्टूबर को वियनतियाने में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री के साथ अलग से बैठक की। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन

ने 19 नवंबर को रियो डी जेनेरियो में जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री से संक्षिप्त मुलाकात की। उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने प्रधानमंत्री को 6 जून को उनके पुनः निर्वाचित होने पर फोन कॉल करके बधाई दी।

नियमित रूप से मंत्रिस्तरीय वार्ताएं होती रही। विदेश मंत्री ने 2024 में तत्कालीन यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि और उपाध्यक्ष जोसेप बोरेल से दो बार मुलाकात की, पहली बार जुलाई में विएंटियाने में आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान और फिर फरवरी में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में। विदेश मंत्री ने सितंबर में न्यूयॉर्क में यूपएनजीए के दौरान जलवायु कार्रवाई के लिए यूरोपीय आयुक्त वोपके होकेस्ट्रा से मुलाकात की। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने जुलाई में विला सैन जियोवानी में जी7 व्यापार मंत्रियों की बैठक के दौरान तत्कालीन यूरोपीय आयोग के कार्यकारी उपाध्यक्ष वाल्डिस डोम्ब्रोव्स्की से मुलाकात की। बजट और प्रशासन संबंधी यूरोपीय आयुक्त जोहान्स हैन ने अक्टूबर में अपनी भारत यात्रा के दौरान वित्त मंत्री से मुलाकात की।

2024 के दौरान जिन संस्थागत संवाद तंत्रों की बैठक हुई, उनमें ब्रुसेल्स में रणनीतिक साझेदारी समीक्षा बैठक, ब्रुसेल्स में विदेश नीति तथा सुरक्षा परामर्श बैठक और नवंबर में ब्रुसेल्स में ऊर्जा पैनल शामिल हैं। सितंबर में ब्रुसेल्स में विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचालन समिति की बैठक हुई। प्रवासन एवं आवाजाही पर उच्च स्तरीय वार्ता नवंबर में ब्रुसेल्स में और जलवायु पर अक्टूबर में नई दिल्ली में हुई। पर्यावरण पर संयुक्त कार्य समूह की बैठक नई दिल्ली में और जल मंच बैठक सितंबर में नई दिल्ली में हुई। ऊर्जा दक्षता मंच मई में वर्चुअली आयोजित किया गया था। कृषि और समुद्री उत्पाद बैठक फरवरी में वर्चुअल रूप से आयोजित की गई थी। पादप स्वास्थ्य और

पशु स्वास्थ्य संबंधी तकनीकी कार्य समूह की बैठक अक्टूबर में वर्चुअल रूप से आयोजित की गई थी और आयुर्वेद बैठक सितंबर में वर्चुअली आयोजित की गई थी।

भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद (टीटीसी) तंत्र के तहत सेमीकंडक्टर, उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग, बैटरी प्रौद्योगिकी, समुद्री प्लास्टिक कूड़े और अपशिष्ट से ऊर्जा जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। हरित और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों पर भारत-यूरोपीय संघ टीटीसी के कार्य समूह-2, स्टार्ट-अप को लक्षित करके इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी रीसाइक्लिंग प्रौद्योगिकियों पर एक मैचमेकिंग कार्यक्रम जून में आयोजित किया गया था, जिसके बाद सितंबर और अक्टूबर में दोनों पक्षों की ओर से बाजार में गहनता बनाने संबंधी यात्राएं हुईं। मुक्त व्यापार करार पर नौ दौर की वार्ता, निवेश संरक्षण करार पर पांच दौर की वार्ता और भौगोलिक संकेत (जीआई) संरक्षण करार पर छह दौर की वार्ता अब तक हो चुकी है। भारत-यूरोपीय संघ स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु साझेदारी के चरण III (2025-28) के लिए एक कार्य कार्यक्रम नवंबर में अंगीकार किया गया था। मार्च में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और यूरोपीय संघ कानून प्रवर्तन सहयोग एजेंसी (यूरोपोल) के बीच एक कार्य व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए गए थे। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) और इसरो के बीच चंद्रयान-3 और आदित्य-एल1 सहित भारत के मिशनों के लिए परस्पर समर्थन व्यवस्था की गई थी।

यूरोपीय संघ, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है जबकि भारत यूरोपीय संघ का 9^{वां} सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। जनवरी-सितंबर से वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार 85.43 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा, जिसमें भारतीय निर्यात 36.09 बिलियन अमरीकी डॉलर और यूरोपीय संघ

का निर्यात 49.27 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा। 2023 में सेवाओं में भारत-यूरोपीय संघ का द्विपक्षीय व्यापार 53.14 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा, जिसमें 23.32 बिलियन अमरीकी डॉलर का भारतीय निर्यात और 29.81 बिलियन अमरीकी डॉलर का आयात शामिल है। फेडरेशन ऑफ यूरोपियन बिजनेस इन इंडिया (एफईबीआई), जो भारत में यूरोपीय संघ का आधिकारिक चैंबर ऑफ कॉमर्स है, 11 अक्टूबर को शुरू किया गया और इसका उद्देश्य भारत और यूरोप के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देना है।

फ्रांस

पिछले दशकों के दौरान, और विशेष रूप से 1998 में रणनीतिक साझेदारी की घोषणा के बाद से, भारत और फ्रांस ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, संप्रभुता एवं रणनीतिक स्वायत्तता में दृढ़ विश्वास, बहुध्रुवीय विश्व के लिए साझा प्रतिबद्धता, विधि के शासन और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के आधार पर असाधारण विश्वास तथा आत्मविश्वास, स्थिरता और दृढ़ता वाली भागीदारी विकसित की है। 2024 में, भारत और फ्रांस ने अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत किया।

14 जुलाई 2023 को फ्रांसीसी राष्ट्रीय दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा के बाद, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों भारत के 75^{वें} गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में भारत की राजकीय यात्रा पर आए। दोनों नेताओं का क्रमशः एक दूसरे के राष्ट्रीय दिवसों पर मुख्य अतिथि बनना भारत-फ्रांस संबंधों में एक उच्च स्थिति को दर्शाता है।



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, भारत की राजकीय यात्रा के दौरान यूपीआई-भुगतान ऐप का उपयोग करते हुए, जनवरी 2024

राष्ट्रपति मैक्रों के साथ एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था जिसमें सशस्त्र सेना, संस्कृति, यूरोपीय और विदेश मामलों के मंत्री, साथ ही फ्रांसीसी सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और कुछ सीईओ और अग्रणी उद्योगपति शामिल थे। फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष सेना के तीन विमानों ने भारतीय वायु सेना के एक विमान के साथ मिलकर कर्तव्य पथ पर उड़ान भरी। फ्रांसीसी सैन्य दल ने गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया, जो पेरिस में 14 जुलाई को फ्रांसीसी राष्ट्रीय दिवस पर भारतीय त्रि-सेवा दल और एक लड़ाकू विमान की भागीदारी का प्रतिफल था।

माननीय राष्ट्रपति जी ने परंपरा से हटकर गणतंत्र दिवस की संध्या को गणमान्य अतिथि के सम्मान में भोज का आयोजन किया। राष्ट्रपति मैक्रों राष्ट्रपति भवन में आयोजित 'एट-होम' रिसेप्शन में माननीय राष्ट्रपति जी के साथ शामिल हुए। द्विपक्षीय कार्यक्रमों के अलावा, राष्ट्रपति मैक्रों ने जयपुर की यात्रा की और राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, कला और शिल्प का अनुभव किया। प्रधानमंत्री ने गुलाबी नगरी में फ्रांसीसी राष्ट्रपति के लिए रात्रिभोज का आयोजन किया।

दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति के साथ-साथ जुलाई 2023 में दोनों पक्षों के बीच सहमत होराइजन 2047 रोडमैप की नियमित समीक्षा की है। 14 जून को प्रधानमंत्री ने इटली में जी7 शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इससे पहले, राष्ट्रपति मैक्रों ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उनके फिर से चुने जाने पर 6 जून को प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए फोन किया था। 18 नवंबर को दोनों नेताओं ने ब्राजील में जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात की।

26 जनवरी को विदेश मंत्री ने फ्रांस के तत्कालीन विदेश मंत्री स्टीफन सेजॉन से मुलाकात की और कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री ने 24 सितंबर को न्यूयॉर्क में यूएनजीए के दौरान और 25 नवंबर को रोम मेडिटेरेनियन डायलॉग 2024 के दौरान फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैरोट से मुलाकात की।

30 सितंबर को, एनएसए ने पेरिस में राजनयिक सलाहकार के साथ 37^{वाँ} भारत-फ्रांस रणनीतिक वार्ता की सह-अध्यक्षता की। यात्रा के दौरान, एनएसए ने फ्रांसीसी विदेश मंत्री जीन नोएल बरोट, सशस्त्र बल मंत्री सेबेस्टियन लेकॉर्नु से भी वार्ता की और राष्ट्रपति मैक्रों से मुलाकात की। वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री ने 24 अक्टूबर को वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक और आईएमएफ की वार्षिक बैठक के दौरान फ्रांस के अर्थव्यवस्था, वित्त और उद्योग मंत्री एंटोनी आर्मंड से मुलाकात की। पर्यटन मंत्री ने 6 नवंबर को लंदन में विश्व यात्रा बाजार के दौरान पर्यटन अर्थव्यवस्था के लिए फ्रांसीसी मंत्री प्रतिनिधि ओलिविया ग्रेगोइरे से मुलाकात की। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने 10-14 अक्टूबर को डिजॉन, फ्रांस की यात्रा की और 45^{वाँ} विश्व वाइन कांग्रेस के आयोजन से पहले मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भाग लिया तथा फ्रांसीसी कृषि, खाद्य संप्रभुता और वानिकी मंत्री एनी जेनेवार्ड से मुलाकात की। कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री ने 9-12 सितंबर को ल्योन, फ्रांस की यात्रा की और विश्व कौशल प्रतियोगिता 2024 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री ने 25 अक्टूबर को ब्राजील में जी20 व्यापार और औद्योगिक मंत्रियों की बैठक के दौरान विदेश व्यापार के लिए फ्रांसीसी मंत्री प्रतिनिधि सोफी प्राइमास से मुलाकात की।

विदेश व्यापार और विदेश में फ्रांसीसी नागरिकों के लिए मंत्री प्रतिनिधि सोफी प्राइमास ने 27-29 नवंबर को भारत की यात्रा की और भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री से मुलाकात की। दोनों मंत्रियों ने नई दिल्ली में फ्रांसीसी विदेश व्यापार सलाहकारों के एशिया-प्रशांत फोरम (एपीएसी) 2024 को संबोधित किया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने एपीएसी फोरम को प्रधानमंत्री का संदेश पढ़ा। दोनों मंत्रियों ने द्विपक्षीय सीईओ फोरम में भी हिस्सा लिया, जो नई दिल्ली में एक साथ आयोजित किया गया था। ये कार्यक्रम भारत और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारतीय और फ्रांसीसी कंपनियों के बीच व्यापार के अवसरों और सहयोग पर केंद्रित थे।

भारत-फ्रांस एफओसी 5 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसकी सह-अध्यक्षता तत्कालीन विदेश सचिव और फ्रांस के यूरोप एवं विदेश मामलों के मंत्रालय की महासचिव (एसजी) ऐनी-मैरी डेस्कोटेस ने की थी।

संसदीय दौरे

2024 में दोनों देशों की संसदों के बीच आदान-प्रदान को एक नई गति मिली और इसने भारत-फ्रांस संबंधों में योगदान दिया। फ्रांसीसी सीनेट के अध्यक्ष जेराई लार्चर ने पांच सीनेटरों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ 19 और 20 फरवरी को भारत का आधिकारिक दौरा किया। यह फ्रांसीसी सीनेट के अध्यक्ष की भारत की पहली आधिकारिक यात्रा थी। यात्रा के दौरान, उन्होंने अपने समकक्ष, भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति और विदेश मंत्री से मुलाकात की। लार्चर ने भारत में मौजूद फ्रांसीसी कंपनियों के व्यापारिक नेताओं से भी मुलाकात की और "मेक इन इंडिया" और "स्किल इंडिया" में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली फ्रांसीसी कंपनियों के कार्यस्थलों की यात्रा की। उन्हें नए संसद भवन का निर्देशित दौरा भी कराया गया।

रक्षा सहयोग

वर्ष 2024 में द्विपक्षीय सैन्य क्षमता और क्षमता विकास दोनों क्षेत्र में अभूतपूर्व गतिविधियाँ देखी गईं। चल रहे प्रमुख रक्षा सौदों में पी-75 स्कॉर्पिन कार्यक्रम और 26 राफेल-एम विमानों की खरीद शामिल है। भारत और फ्रांस के बीच 26 जनवरी को रक्षा अंतरिक्ष साझेदारी को गहन करने के लिए एक आशय पत्र (एलओआई) पर हस्ताक्षर किए गए, जो रक्षा के साथ-साथ अंतरिक्ष के क्षेत्र में बढ़ते रणनीतिक सहयोग का प्रमाण है। रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी के एक सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 3 से 6 मार्च को फ्रांस के टूलूज़ में एस्टरएक्स-24 अभ्यास में सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया। बढ़ते विश्वास के संकेत के रूप में, मार्च 2025 में आगामी एस्टरएक्स अभ्यास के लिए भागीदारी की स्थिति को 'पर्यवेक्षक' से बढ़ाकर 'भागीदार स्तर' कर दिया गया है।

07-08 नवंबर को दिल्ली में सेना से सेना स्टाफ वार्ता का 20^{वाँ} संस्करण आयोजित किया गया। नौसेना से नौसेना स्टाफ वार्ता का 17^{वाँ} दौर 06-07 फरवरी को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। द्विपक्षीय सेना अभ्यास शक्ति 2024 13-26 मई को भारत के मेघालय के उमरोई में

आयोजित किया गया। यह पहली बार था जब अभ्यास में वायु सेना और नौसेना पर्यवेक्षकों की भागीदारी देखी गई। फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल (एफएएसएफ) और आईएफएफ वर्ष 2023 तक द्विपक्षीय अभ्यास गरुड़ में भाग ले रहे हैं। 2024 में, भारतीय वायुसेना ने अभ्यास गरुड़ के बदले एक नए अभ्यास 'तरंग शक्ति' के रूप में कई देशों को आमंत्रित करके दायरे का विस्तार किया। 02 से 05 सितंबर तक फ्रांस के टूलॉन तट पर नौसैन्य अभ्यास वरुण 2024 का समुद्री चरण आयोजित किया गया। अभ्यास वरुण 2024 में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना के P-8I (समुद्री गश्ती और टोही विमान) के बेड़े को 01 से 04 सितंबर तक फ्रांस के इस्ट्रेस में तैनात किया गया था। फ्रांसीसी विमान अटलांटिक-2 ने विशाखापत्तनम के तट पर बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2024 में भाग लिया।

वर्ष के दौरान कई बंदरगाहों पर तैनाती की गई। आईएनएस तबर ने 29 अगस्त से 2 सितंबर तक टूलॉन में बंदरगाह पर तैनाती की। बंदरगाह पर तैनाती में अभ्यास वरुण 2024 का बंदरगाह चरण भी शामिल था। आईएनएस तलवार ने 27 से 29 अक्टूबर तक ला रीयूनियन में ऑपरेशनल टर्नअराउंड (ओटीआर) किया।

लिपक्षीय सहयोग

भारत और फ्रांस की क्रमशः ऑस्ट्रेलिया और यूएई के साथ मजबूत लिपक्षीय संस्थागत आदान-प्रदान व्यवस्था हैं। तीसरी भारत-फ्रांस-ऑस्ट्रेलिया लिपक्षीय फोकल प्वाइंट बैठक 19 जून को हुई और दूसरी भारत-फ्रांस-यूएई लिपक्षीय फोकल प्वाइंट बैठक 9 जुलाई को हुई।

अंतरिक्ष सहयोग

भारत और फ्रांस की इसरो और उसके फ्रांसीसी समकक्ष सेंटर नेशनल डी'एचूडस स्पैटियल्स (सीएनईएस) के माध्यम से अंतरिक्ष के क्षेत्र में छह दशकों से अधिक समय तक सहयोग और सहभागिता की समृद्ध विरासत है। चल रही सहयोग गतिविधियों में संयुक्त उपग्रह मिशन तृष्णा (उच्च-रिज़ॉल्यूशन प्राकृतिक संसाधन आकलन के लिए थर्मल इंफ्रा-रेड इमेजिंग सैटेलाइट), समुद्री डोमेन जागरूकता प्रणाली, पेलोड व्यवस्था, ग्राउंड स्टेशन समर्थन, मानव अंतरिक्ष उड़ान और पेशेवर आदान-प्रदान शामिल हैं। इसरो वाणिज्यिक आधार पर अपने भारी संचार उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए एरियनस्पेस की लॉन्च सेवाओं का उपयोग कर रहा है।

दूसरा भारत-फ्रांस रणनीतिक अंतरिक्ष संवाद 4 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसका नेतृत्व तत्कालीन विदेश सचिव और यूरोप एवं विदेश मंत्रालय की महासचिव ऐनी-मैरी डेस्कोटेस ने किया था। भारत और फ्रांस ने पहले भारत-फ्रांस रणनीतिक अंतरिक्ष संवाद के बाद से हुई प्रगति की समीक्षा की और अंतरिक्ष क्षेत्र में चल रहे मजबूत द्विपक्षीय जुड़ाव पर चर्चा की। उन्होंने जी2जी और वाणिज्यिक क्षेत्रों में आगे सहयोग के अवसरों की खोज की, साथ ही रक्षा-अंतरिक्ष सहयोग, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, अंतरिक्ष आदान-प्रदान और रक्षा-अंतरिक्ष औद्योगिक सहयोग पर योजना के कार्यान्वयन पर भी चर्चा की।

आर्थिक सहयोग

यूरोपीय संघ के भीतर, नीदरलैंड, जर्मनी, बेल्जियम और इटली के बाद फ्रांस, भारत का सातवां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना हुआ है। वर्ष 2024-25 के लिए, अप्रैल और अक्टूबर के बीच फ्रांस को भारतीय निर्यात 4.69 बिलियन अमरीकी डॉलर था। भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले दशक में दोगुना से अधिक बढ़कर 2023-24 में 15.11 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है, जो 2009-10 में 6.4 बिलियन अमरीकी डॉलर था।

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2000 से मार्च 2024 तक 10.94 बिलियन अमरीकी डॉलर के संचयी निवेश के साथ फ्रांस भारत में 11^{वां} सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है, जो भारत में कुल एफडीआई प्रवाह का 1.61 प्रतिशत है। शीर्ष 5 एफडीआई इक्विटी प्रवाह इस प्रकार हैं: सेवा क्षेत्र (17.87 प्रतिशत), सीमेंट और जिप्सम उत्पाद (8.91 प्रतिशत), हवाई परिवहन (हवाई माल ढुलाई सहित) (7.31 प्रतिशत), विविध उद्योग (7.04 प्रतिशत) और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (6.81 प्रतिशत)। ये पांच क्षेत्र अप्रैल 2000 से मार्च 2024 तक फ्रांस से कुल इक्विटी प्रवाह का 47.93 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं।

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) और लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड टेक सर्विसेज (एलटीटीएस) सहित कई भारतीय कंपनियों ने संयुक्त प्रौद्योगिकी विकास के लिए फ्रांस में अपने नवाचार केंद्र खोले हैं। फ्रांसीसी प्रौद्योगिकियों, विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा, स्थायी विनिर्माण और शहरी बुनियादी ढांचे के विकास को भारत में एकीकृत किया जा रहा है।

भारत और फ्रांस द्वारा 2024 में आर्थिक कूटनीति के लिए पहचाने गए पांच प्रमुख क्षेत्र हैं, डिजिटल प्रौद्योगिकी और नवाचार को आगे बढ़ाना, स्वच्छ ऊर्जा सहयोग, अनुसंधान एवं विकास, स्मार्ट विनिर्माण तथा रक्षा सहित महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियां, फ्रांस को भारत का निर्यात बढ़ाना और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला स्थानांतरण पहल।

डिजिटल सहयोग

यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) को कार्यशील करने की प्रक्रिया सफल रही है। जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री की पेरिस यात्रा के दौरान, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (एनआईपीएल) और फ्रांस के लाइरा कलेक्ट ने फ्रांस और यूरोप में यूपीआई को लागू करने के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किए। 26 जनवरी को राष्ट्रपति मैक्रोन की भारत यात्रा के दौरान यूपीआई को स्वीकार करने वाले फ्रांस के पहले व्यापारिक स्थल के रूप में एफिल टॉवर पर भुगतान प्रणाली लाइव हो गई। इसके बाद, 3 जुलाई को गैलरी लाफायेट में यूपीआई भुगतान लॉन्च किए गए। एक खुली, मुक्त, लोकतांत्रिक और समावेशी डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं और डिजिटल समाजों के विकास के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) दृष्टिकोण की शक्ति में एक साझा विश्वास के साथ, भारत और फ्रांस ने इनफ्रास्ट्रक्चरस (भारत फ्रांस संरचनाएं) और इनफाइनिटि (सूचना प्रौद्योगिकी में भारत फ्रांस नवाचार) प्लेटफार्मों के माध्यम से बहु-हितधारक आदान-प्रदान को आगे बढ़ाया है।

संस्कृति और पर्यटन

जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री की पेरिस यात्रा के दौरान नए राष्ट्रीय संग्रहालय और संग्रहालय विज्ञान में सहयोग पर हस्ताक्षरित आशय पत्र के बाद, दोनों देशों ने राष्ट्रीय संग्रहालय और फ्रांस संग्रहालय विकास के बीच एक विस्तृत करार पर प्रगति की है। फ्रांस भारत की “युगयुगीन भारत” राष्ट्रीय संग्रहालय परियोजना के साथ काम कर रहा है। पेरिस में 17-19 सितंबर को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय और फ्रांसीसी यात्रा बाजार (आईएफटीएम) टॉप रेसा पर्यटन मेले में एक ‘भारत मंडप’ स्थापित किया गया था। वहां केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश पर्यटन बोर्डों के राज्य मंडप थे।

असैन्य परमाणु सहयोग

भारत के 75^{वां} गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति मैक्रों की भारत की राजकीय यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मैक्रों ने इस बात पर जोर दिया कि ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और न्यून कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए परमाणु ऊर्जा ऊर्जा मिश्रण का एक अनिवार्य हिस्सा है। दोनों नेताओं ने विशेष रूप से जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र परियोजना के संबंध में भारत-फ्रांस असैन्य परमाणु संबंधों और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर सहयोग के प्रयासों को स्वीकार किया। वे भारत-फ्रांस रणनीतिक वार्ता के ढांचे में परमाणु ऊर्जा पर एक विशेष टास्क फोर्स तैयार करने पर सहमत हुए।

समुद्री अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग

अक्टूबर 2023 में पेरिस में आयोजित पहली द्विपक्षीय बैठक के दौरान लिए गए निर्णयों के आधार पर, समुद्री अर्थव्यवस्था और महासागर अभिशासन पर भारत-फ्रांस अनुवर्ती वार्ता 21 फरवरी को नीति आयोग, नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व नीति आयोग के सीईओ ने किया और फ्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ध्रुवीय और समुद्री मुद्दों के राजदुत ओलिवियर पोइवर डी'आवॉर ने किया। अनुवर्ती चर्चाओं के दौरान दोनों पक्षों ने सहयोग क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा की और उनकी पहचान की।

भारत-फ्रांस संयुक्त कार्य समूह की चौथी बैठक 10 जुलाई को आयोजित की गई। पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और प्रदूषण में द्विपक्षीय सहयोग की समृद्धि को याद करते हुए, दोनों पक्षों ने तटीय पारिस्थितिकी तंत्र और सेवाओं, समुद्री और तटीय नियोजन और तटीय पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्रों में ब्लू इकोनॉमी वार्ता के तहत काम करने पर सहमति व्यक्त की।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग

18 जनवरी को संयुक्त विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति की दूसरी बैठक हुई। संयुक्त समिति की दूसरी बैठक में चर्चा किए गए विषयों में शामिल थे: (i) ऊर्जा: ग्रीन हाइड्रोजन, ऊर्जा संरक्षण और भंडारण, (ii) जलवायु परिवर्तन

और संधारणीय शहर: कार्बन कैप्चर और उपयोग एव भंडारण तकनीक, पृथक्करण, (iii) डिजिटल तकनीक: संधारणीयता के लिए एआई, स्वायत्त नेविगेशन, (iv) क्वांटम तकनीक: क्वांटम कंप्यूटिंग, सेंसिंग और मेट्रोलॉजी, सामग्री और उपकरण, (v) स्वास्थ्य: कैंसर अनुसंधान और नवाचार, नवीन चिकित्सा विज्ञान, उभरती बीमारियों का जल्दी पता लगाने के लिए नवीन निदान, स्वास्थ्य सेवा में एआई का अनुप्रयोग, उभरती संक्रामक बीमारियों की मेजबान-रोगजनक अनुक्रिया आदि। (vi) महासागर, और (vi) अनुप्रयुक्त गणित।

18 जनवरी को नई दिल्ली में संयुक्त समिति की दूसरी बैठक के दौरान डीएसटी और एजेंस नेशनल डे ला रिसर्च (एएनआर) फ्रांस के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता ज्ञापन के तहत कार्रवाई के लिए चुने गए दो क्षेत्र हैं: (i) डीकार्बोनेटेड हाइड्रोजन (ii) डिजिटल एआई के लिए अनुप्रयुक्त गणित।

डीएसटी के सचिव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम कर रहे फ्रांसीसी संस्थानों के साथ विभिन्न द्विपक्षीय बैठकों की और 25 अप्रैल को पेरिस में सीईएफआईपीआरए (उन्नत अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए भारत-फ्रांसीसी केंद्र) के शासी निकाय की 37^{वां} बैठक की सह-अध्यक्षता भी की। एक अन्य परिणाम जिसे शासी बोर्ड ने मंजूरी दी, वह था स्वास्थ्य मुद्दों पर भारत-फ्रांस वर्चुअल नोड (आईएलबीएस-आईएनएसईआरएम) का शुभारंभ, जिसके तहत, भारत-फ्रांसीसी नोड “लिवर और मेटाबोलिक रोग नेटवर्क (इनफ्लिमेन)” को 04 जुलाई को नई दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज (आईएलबीएस) में विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री द्वारा पेश और उसका उद्घाटन किया गया।

प्रवासी भारतीय

फ्रांस की मुख्य भूमि और उसके विदेशी भू-क्षेत्रों में भारतीय प्रवासियों की बड़ी संख्या मौजूद है। अनुमान है कि मुख्य भूमि फ्रांस में 1,19,000 भारतीय हैं। फ्रांस में करीब 10,000 भारतीय छात्र हैं।

जर्मनी

7^{वां} भारत-जर्मनी अंतर-सरकारी परामर्श (आईजीसी) 25 अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसमें व्यापार, निवेश और सतत विकास जैसे सहयोग के पारंपरिक क्षेत्रों पर जोर दिया गया, साथ ही रक्षा और सुरक्षा जुड़ाव तथा नई और उभरती प्रौद्योगिकियों में नवाचार पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया गया।

प्रधानमंत्री और जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज़ ने 7^{वां} आईजीसी की सह-अध्यक्षता की। जर्मन चांसलर के साथ एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया था जिसमें उप-कुलपति और आर्थिक मामलों और जलवायु कार्रवाई के संघीय मंत्री रॉबर्ट हैबेक, संघीय विदेश मंत्री एनालेना बैरबॉक, संघीय श्रम एवं सामाजिक मामलों के मंत्री ह्यूबर्टस हील और तत्कालीन संघीय शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री बेटीना स्टार्क-वाटज़िंगर शामिल थे।



अक्टूबर 2024 में नई दिल्ली में जर्मनी संघीय गणराज्य के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज़ के साथ प्रधानमंत्री

सुरक्षा, हरित ऊर्जा, शहरी आवाजाही, स्टार्ट-अप, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा, कौशल विकास, श्रम और स्वास्थ्य जैसे विविध क्षेत्रों में कई करारों पर हस्ताक्षर किए गए। महत्वपूर्ण परिणामों में आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता संधि (एमएलएटी) और वर्गीकृत सूचनाओं के आदान-प्रदान और पारस्परिक संरक्षण पर करार शामिल है। इस दौरान नवाचार और प्रौद्योगिकी पर रोडमैप की प्रस्तुति के साथ-साथ ग्रीन हाइड्रोजन रोडमैप का शुभारंभ भी हुआ।

दोनों पक्षों ने अफ्रीका और पूर्वी एशिया पर मौजूदा तंतों के अलावा पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका (डब्ल्यूएएनए) पर परामर्श तंतों की स्थापना के माध्यम से आपसी हित के वैश्विक मुद्दों पर चर्चा को मजबूत करने का भी फैसला किया। इस तरह का पहला परामर्श 27 नवंबर को आयोजित किया गया था।

7^{वीं} आईजीसी के अलावा, प्रधानमंत्री और चांसलर स्कोल्ज़ ने 14 जून को इटली के अपुलिया में आयोजित जी7 शिखर सम्मेलन के दौरान भी बातचीत की।

अन्य उच्च स्तरीय आदान-प्रदान

दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय वार्ताओं के माध्यम से और मजबूत हुए हैं।

विदेश मंत्री 10-11 सितंबर को 2 दिवसीय यात्रा पर बर्लिन गए। यात्रा के दौरान, विदेश मंत्री ने चांसलर स्कोल्ज़ से मुलाकात की और विदेश मंत्री बैरबॉक, संघीय रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस, चांसलर के विदेश और सुरक्षा

नीति सलाहकार जेन्स प्लोटनर के साथ-साथ संसद सदस्यों (बुंडेस्टैग) से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण-आयामों पर चर्चा की। विदेश मंत्री, जर्मन विदेश कार्यालय में आयोजित जर्मन मिशन के प्रमुखों के सम्मेलन में मुख्य अतिथि भी थे। उन्होंने जर्मन राजदूतों, महावाणिज्य दूतों और व्यापार एवं उद्योग जगत में अग्रणी लोगों को संबोधित किया। 16-18 फरवरी को 60^{वां} म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में, विदेश मंत्री ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटी ब्लिंकन और जर्मन विदेश मंत्री एनालेना बैरबॉक के साथ "ग्रीडिंग द पाई: सीजिंग शेयर्ड ऑपच्युनिटीज" पर एक पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया। विदेश मंत्री ने अर्जेन्टीना की विदेश मंत्री डायना मोंडिनो, तत्कालीन यूके विदेश सचिव डेविड कैमरन और पेरू के विदेश मंत्री जेवियर गोंजालेज-ओलाचेआ और बुल्गारिया की विदेश मंत्री मारिया गेब्रियल सहित कई समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं। विदेश मंत्री ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन और ओआरएफ द्वारा आयोजित चुनिंदा जर्मन निर्णय-निर्माताओं और प्रमुख विदेश और सुरक्षा नीति विशेषज्ञों के साथ एक गोलमेज चर्चा 'बर्लिन में एमएससी' में मुख्य वक्ता के रूप में भी भाग लिया।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (एमएनआरई) ने 6-9 अक्टूबर को हैम्बर्ग और बर्लिन की यात्रा की, जिसके दौरान उन्होंने हैम्बर्ग स्थिरता सम्मेलन में भाग लिया और कुलपति हेबेक से मुलाकात की। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ने 21-22 नवंबर को बर्लिन और स्टटगार्ट की यात्रा की, जहाँ उन्होंने क्रमशः अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल संवाद सम्मेलन और न्यूज़9 ग्लोबल समिट में भाग लिया। रेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने भी न्यूज़9 ग्लोबल समिट में भाग लेने के लिए 21-22 नवंबर को स्टटगार्ट की यात्रा की। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से सभा को संबोधित किया।

जर्मनी की ओर से संघीय आर्थिक सहयोग एवं विकास मंत्री स्वेनजा शुल्जे ने 16-18 सितंबर को गांधीनगर में आयोजित एमएनआरई के प्रमुख कार्यक्रम के चौथे संस्करण री-इन्वेस्ट 2024 में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया। जर्मनी इस कार्यक्रम का भागीदार देश था, जिसमें 'वैश्विक स्तर पर अक्षय ऊर्जा में निवेश के लिए भारत-जर्मनी मंच' का शुभारंभ भी हुआ।

चांसलर के विदेश एवं सुरक्षा नीति सलाहकार, जैन्स प्लोटनर भी अक्टूबर में भारत आए थे और उन्होंने एनएसए तथा विदेश मंत्री से मुलाकात की थी।

विदेश सचिव और जर्मन विदेश कार्यालय (जीएफओ) के स्टेट सेक्रेटरी थॉमस बैगर की सह-अध्यक्षता में एफओसी का आयोजन 15 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में किया गया।

भारत और जर्मनी के प्रबुद्ध मंडलों और नीति निर्माताओं के बीच ट्रैक 1.5 स्तर पर चौथा वार्ता तंत्र 20 नवंबर को बर्लिन में आयोजित की गई। भारत की ओर से इसमें भारतीय वैश्विक परिषद (आईसीडब्ल्यूए), विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (आरआईएस) और विदेश मंत्रालय ने हिस्सा लिया, जबकि जर्मनी की ओर से जर्मन इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल एंड एरिया स्टडीज (जीआईजीए), जर्मन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल एंड सिस्वोरिटी अफेयर्स (एसडब्ल्यूपी) और जर्मन विदेश कार्यालय ने हिस्सा लिया।

बहुपक्षीय सहयोग

भारत और जर्मनी बहुपक्षीय प्रणाली को सुदृढ़ बनाने और उसमें सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तथा समूह-4 (जी-4) के सदस्य के रूप में दोनों देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्यता के विस्तार के लिए एक-दूसरे का समर्थन करते हैं।

7^{वीं} आईजीसी में भारत और जर्मनी ने एक ऐसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए अपना आह्वान दोहराया जो कुशल, प्रभावी, पारदर्शी और 21^{वीं} सदी को प्रतिबिंबित करने वाली हो। दोनों देशों ने अंतर-सरकारी वार्ता (आईजीएन) में एक 'निश्चित समय-सीमा' के साथ पाठ-आधारित वार्ता का आह्वान किया। विदेश मंत्रियों के स्तर पर जी4 की पिछली बैठक सितंबर में 79^{वीं} यूएनजीए के दौरान आयोजित की गई थी। भारत और जर्मनी के बीच संयुक्त राष्ट्र पर कार्य-स्तरीय परामर्श तंत्र अप्रैल में बर्लिन में आयोजित किया गया था।

भारत और जर्मनी एक दूसरे से परामर्श करते हैं और जलवायु परिवर्तन, सतत विकास और साइबर सुरक्षा जैसे वैश्विक मुद्दों पर जी-20 और संयुक्त राष्ट्र सहित बहुपक्षीय मंचों पर अपनी स्थितियों को समन्वित करते हैं। जर्मनी, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए), इंडो-पैसिफिक महासागर पहल (आईपीओआई) और आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (सीडीआरआई) जैसी भारतीय बहुपक्षीय पहलों का भी हिस्सा है।

आर्थिक सहयोग

वित्तीय वर्ष 2023-24 में जर्मनी भारत का 12^{वां} सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। वित्त वर्ष 2023-24 में वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार 26.48

बिलियन अमेरिकी डॉलर था। वित्त वर्ष 2024-25 (सितंबर 2024 तक) के दौरान द्विपक्षीय व्यापार 13.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें निर्यात 5.07 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसमें 4.67 प्रतिशत की वृद्धि दर थी। आयात 8.73 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में 3.33 प्रतिशत की कमी दर्शाता है।

जर्मनी भारत का 9^{वां} सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक है, वित्त वर्ष 2023-24 में कुल जर्मन एफडीआई के साथ, भारत में जर्मन एफडीआई 507 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। वर्तमान में भारत में 2,000 से अधिक जर्मन कंपनियां और 600 से अधिक संयुक्त उद्यम सक्रिय हैं। जर्मन कंपनियों ने भारत में महत्वपूर्ण निवेश किया है। जनवरी में, मर्सिडीज-बेंज ने पुणे में अपने ऑटोमोटिव विनिर्माण का विस्तार करने के लिए 24 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया। फ्लिक्सबस ने फरवरी में अपनी बस सेवाएं शुरू कीं। फरवरी में ही, वैश्विक बायोमेडिकल लीडर मिल्टेन्यी बायोटेक ने हैदराबाद में सेलुलर और जीन थेरेपी के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की। शिपिंग कंपनी हैपग-लॉयड ने कंटेनर टर्मिनलों और औद्योगिक पार्कों में 295 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अगस्त में, ज़ेडएफ़ ग्रुप ने वैश्विक ऑटोमोटिव और औद्योगिक प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं के लिए भारत में सामग्री प्रापण बढ़ाने के लिए 2030 तक 2.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की अपनी योजना की घोषणा की, साथ ही अपनी कोयंबटूर पवन ऊर्जा इकाई का 52 मिलियन अमेरिकी डॉलर का विस्तार भी किया। सितंबर में, स्कोडा ऑटो वोक्सवैगन इंडिया ने चाकन में एक नई विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर आवंटित किए। जर्मन सरकारी स्वामित्व वाले विकास बैंक क्रेडिटनस्टाल्ट फर विडेरॉफ़बाउ (केएफडब्ल्यू) की विकास वित्त संस्थान (डीईजी) इकाई ने भारत के ऊर्जा और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अपने निवेश को दोगुना करके 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर करने का संकल्प लिया।

“नवाचार, आवाजाही और स्थिरता के साथ मिलकर आगे बढ़ना” के आदर्श वाक्य के तहत, 7^{वां} आईजीसी ने प्रौद्योगिकी एवं नवाचार, हरित एवं स्थायी विकास तथा पेशेवरों के कौशल विकास एवं आवाजाही पर विशेष जोर दिया। 7^{वां} आईजीसी के दौरान, दोनों देशों ने रोजगार और श्रम पर एक संयुक्त आशय घोषणा (जेडीआई), भारत-जर्मनी हरित शहरी आवाजाही भागीदारी पर एक जेडीआई, भारत-जर्मनी प्रबंधकीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (आईजीएमटीपी) पर एक जेडीआई और कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

18^{वां} एशिया-प्रशांत जर्मन बिजनेस सम्मेलन (एपीके) 25-26 अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिससे द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत हुई। आईजीसी और एपीके के दौरान भारत-जर्मनी सीईओ फोरम और रक्षा उद्योग गोलमेज सम्मेलन का भी आयोजन किया गया।

भारत में कार्यरत जर्मन कंपनियों की चिंताओं/शिकायतों के समाधान के लिए डीपीआईआईटी और जर्मन संघीय आर्थिक मामले एवं जलवायु कार्रवाई मंत्रालय (बीएमडब्ल्यूके) द्वारा स्थापित फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म की बैठक 27 मार्च को हुई, जिसकी अध्यक्षता सचिव (डीपीआईआईटी) और भारत में जर्मनी के राजदूत डॉ. फिलिप एकरमैन ने की।

विकास सहयोग

जर्मनी 2024 में भी भारत के लिए एक महत्वपूर्ण विकास सहयोग भागीदार बना रहा। विकास सहयोग पर वार्षिक भारत-जर्मन वार्ता 20 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित की गई, जिसके दौरान जर्मन सरकार ने नई परियोजनाओं के लिए 1,149.07 मिलियन अमरीकी डॉलर देने की प्रतिबद्धता जताई। इसमें वित्तीय सहयोग के लिए 1,109.44 मिलियन अमरीकी डॉलर, तकनीकी सहायता के लिए 2.92 मिलियन अमरीकी डॉलर और कृषि और खाद्य प्रणालियों को बदलने के लिए 95.11 मिलियन अमरीकी डॉलर शामिल हैं। भारत-जर्मन विकास सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में ऊर्जा, सतत आर्थिक विकास, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन शामिल हैं। ऊर्जा (नवीकरणीय, हरित हाइड्रोजन, हरित ऊर्जा गलियारे), सतत शहरी विकास (जल और स्वच्छता, जलवायु अनुकूल शहरी आवाजाही और स्मार्ट शहर) और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में कई परियोजनाएँ शुरू की जा रही हैं। दोनों पक्षों के लिए एक प्रमुख प्रेरणा स्त्रोत त्रिकोणीय विकास सहयोग (टीडीसी) की बढ़ती भूमिका है, जो अफ्रीका, एशिया और उससे भी आगे के क्षेत्रों में एसडीजी और जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति का समर्थन करने के लिए तीसरे देशों में स्थायी, व्यवहार्य और समावेशी परियोजनाओं की पेशकश करने के लिए आपसी सामर्थ्य और अनुभवों को एक साथ लाता है। दोनों पक्षों ने 2024 में कैमरून (कृषि), मलावी (महिला उद्यमिता) और घाना (बागवानी) के साथ टीडीसी प्रायोगिक परियोजनाओं को पूर्ण पैमाने पर शुरू करने पर सहमति व्यक्त की। इसके अलावा, दोनों पक्षों ने इथियोपिया और मेडागास्कर में श्रीअन्न से संबंधित प्रायोगिक परियोजनाएँ शुरू कीं। भारत और जर्मनी ने टीडीसी के तहत संयुक्त पहलों की निगरानी के लिए एक संयुक्त संचालन समिति और एक संयुक्त कार्यान्वयन समूह की भी स्थापना की।

प्रवासन और आवाजाही

भारत, जर्मनी में भारतीय छात्रों और कुशल कामगारों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने, जर्मन मानकों के अनुसार भारतीय छात्रों के लिए दोहरे व्यावसायिक प्रशिक्षण पर सहयोग और रोजगार के उद्देश्यों के लिए निष्पक्ष प्रवास को बढ़ावा देने पर उच्च प्राथमिकता देता है। 16 अक्टूबर को, जर्मन सरकार ने 'कुशल श्रम रणनीति: भारत' जारी की, जो भारत से कुशल कामगारों की भर्ती पर जर्मनी के ध्यान केंद्रण को स्पष्ट करती है। भारत पहला देश है जिसके लिए जर्मनी ने ऐसी रणनीति की घोषणा की है। फरवरी में, नोर्का -गैर-निवासी केरलवासियों के मामलों के विभाग की नोर्का रूट्स (केरल की सरकारी स्वामित्व वाली भर्ती एजेंसी) और संघीय रोजगार एजेंसी, बंडेसगैटूर फर आर्बिट (बीए) ने जर्मनी में केरल से नर्सों की नियुक्ति के लिए मौजूदा करार के दायरे का विस्तार किया। तेलंगाना की सरकारी स्वामित्व वाली भर्ती एजेंसी तेलंगाना ओवरसीज मैनपावर कंपनी (टॉमकॉम) ने नर्सों के लिए बीए के साथ इसी तरह के प्लेसमेंट समझौते पर हस्ताक्षर किए। महाराष्ट्र और बाडेन वुर्टेम्बर्ग स्टेट ने भी फरवरी में कौशल और प्रवासन पर सहयोग के लिए एक संयुक्त घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किए।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग

भारत और जर्मनी ने 'वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी विकास में सहयोग' पर अंतर-सरकारी करार के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग की 50^{वीं} वर्षगांठ मनाई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) और जर्मन संघीय शिक्षा और अनुसंधान मंत्रालय (बीएमबीएफ) समग्र समन्वय के लिए नोडल एजेंसियां हैं। भारत-जर्मन विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग के 50 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए स्वर्ण जयंती समारोह मई में जर्मनी के डार्मस्टाट और अक्टूबर में नई दिल्ली में मनाया गया।

7^{वां} आईजीसी में, इंडो-जर्मन विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र (आईजीएसटीसी) के तहत उन्नत सामग्रियों के लिए 2+2 कॉल संबंधी एक जेडीआई पर हस्ताक्षर किए गए। 7^{वां} आईजीसी में मैक्स-प्लैंक गेसेलशाफ्ट और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के बीच दो समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए गए। उन्नत विनिर्माण, एम्बेडेड सिस्टम और आईसीटी, जैव प्रौद्योगिकी, जैव-अर्थव्यवस्था, जल, स्मार्ट शहर आदि जैसे राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में कुल 49 परियोजनाओं (38 पूर्ण और 11 चालू) का समर्थन किया गया है।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, अगस्त में पहली बार भारत-जर्मन संयुक्त मास्टर डिग्री की शुरुआत हुई। "वाटर सिक्वोरिटी एंड ग्लोबल चेंज" में, एक सहयोगात्मक कार्यक्रम में टेक्नीश यूनिवर्सिटी ड्रेसडेन (ड्रेसडेन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी), राइनिश-वेस्टफेलिश टेक्नीश होचस्युले आचेन (टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ आचेन) और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास (आईआईटीएम) शामिल हैं। 24 अक्टूबर को शिक्षण, अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से टीयू ड्रेसडेन और आईआईटीएम के बीच एक नई "ट्रांसकैपस" पहल तैयार की गई।

7^{वां} भारत-जर्मन आईजीसी के दौरान उच्च शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए 13 करार संपन्न हुए। नवाचार के मामले में भारत और जर्मनी ने एक दूरदर्शी पहल की शुरुआत की है, जिसका नाम है "भारत-जर्मनी नवाचार और प्रौद्योगिकी भागीदारी रोडमैप"। दोनों देशों ने एंटी-प्रोटॉन और आयन अनुसंधान (एफएआईआर) सुविधा और ड्यूश इलेक्ट्रोनेन सिंक्रोट्रॉन (डीईएसवाई) के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

25 नवंबर को यूनिवर्सिटी लीपज़िग ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और नई दिल्ली स्थित जीनोमिक्स और इंटीग्रेटिव बायोलॉजी संस्थान को निःशुल्क मोबाइल सूटकेस लैब की तकनीक हस्तांतरित करने की पेशकश की। यह तकनीक विशेष रूप से ग्रामीण भारत में सीमित संसाधनों वाली परिस्थितियों में डेंगू, तपेदिक, जीका, साल्मोनेला आदि जैसे संक्रामक रोगों और रोगजनकों के त्वरित निदान में सहायता करती है। दो भारतीय फर्मों ने भारत में किट बनाने के लिए समझौता किया है।

रक्षा सहयोग

7^{वां} आईजीसी बैठक के दौरान चांसलर स्कॉल्ज़ के नेतृत्व में एक जर्मन प्रतिनिधिमंडल ने गोवा में जर्मन लड़ाकू सहायता जहाज 'फ्रैंकफर्ट एम मेन' के पार्ट कॉल के दौरान उसका दौरा किया। 24 अक्टूबर को नई दिल्ली में

एशिया प्रशांत जर्मन व्यापार सम्मेलन (एपीके) 2024 के अवसर पर रक्षा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया जिसका उद्देश्य भारत और जर्मनी के बीच रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ाना था।

जनवरी में जर्मन संघीय रक्षा मंत्रालय के राजनीतिक निदेशक जैस्पर वीक के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली का दौरा किया। उन्होंने डिप्टी एनएसए, रक्षा सचिव और नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख सहित अन्य लोगों से मुलाकात की। जर्मन रक्षा स्टेट सेक्रेटरी निल्स हिल्मर ने अक्टूबर में भारत का दौरा किया और भारतीय रक्षा सचिव की सह-अध्यक्षता में रक्षा सचिव स्तर की वार्ता में भाग लिया। फरवरी में विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित अभ्यास मिलन 2024 में जर्मन नौसेना के दो अधिकारियों ने पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया।

रक्षा वार्ता तंत्र में रक्षा सचिव स्तर पर उच्च रक्षा समिति की बैठकें, सैन्य सहयोग उप-समूह बैठक और रक्षा तकनीकी उप-समूह समिति की बैठक शामिल थी। रक्षा सचिव और स्टेट सेक्रेटरी के बीच 11^{वीं} उच्च रक्षा समिति (एचडीसी) की बैठक 27 फरवरी को बर्लिन में हुई। 2025 के लिए वार्षिक कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए 17^{वीं} सैन्य सहयोग उप-समूह बैठक 1-2 अक्टूबर को बर्लिन में हुई।

जर्मन वायु सेना ने 7 से 14 अगस्त को तमिलनाडु के सुलूर में भारतीय वायु सेना के साथ अपने पहले द्विपक्षीय अभ्यास तरंग शक्ति- I में भाग लिया। जर्मन पक्ष ने इन क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों को इंडो-पैसिफिक डिप्लॉयमेंट 2024 और पैसिफिक स्काईज -2024 जैसे अपने वायु सेना अभ्यासों के रूप में संदर्भित किया।

एयर चीफ मार्शल ने तीन अधिकारियों के साथ 6 जून को बर्लिन एक्सपोजे सेंटर एयरपोर्ट पर द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय वैमानिकी प्रदर्शनी, ILA बर्लिन 2024 में भाग लिया, उसके बाद जर्मन वायुसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इंगो गेरहार्ड के साथ लागे एयर फोर्स बेस से यूरोफाइटर उड़ान भरी। एनडीसी, नई दिल्ली से 64^{वाँ} राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज पाठ्यक्रम प्रतिनिधिमंडल ने अपने विदेशी अध्ययन दौरे (एफसीएसटी) के हिस्से के रूप में 2-7 जून को जर्मनी का दौरा किया। राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के कमांडेंट ने पांच विदेशी अधिकारियों सहित 16 अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

आईएनएस तबर ने 17-20 जुलाई को हैम्बर्ग में अपना पोर्ट कॉल किया, जिसके बाद जर्मन नौसेना के साथ एक पैसेज एक्सरसाइज या पासेक्स का आयोजन किया गया। मई-नवंबर तक, जर्मन फ्रिगेट 'बैडेन-वुर्टेम्बर्ग' की इंडो-पैसिफिक यात्रा, एक कॉम्बैट सपोर्ट शिप 'फ्रैंकफर्ट एम मेन' के साथ जून-अगस्त से अमेरिका में रिम ऑफ द पैसिफिक (रिमपैक) अभ्यास में भाग लिया, और डीपीआरके पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को लागू करने के लिए अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर पैसिफिक सिक्योरिटी मैरीटाइम एक्सचेंज (पीएसएमएक्स) में भाग लिया। इसके बाद भारत में एक स्टॉपओवर, 21-23 अक्टूबर को भारतीय महासागर में आईएनएस दिल्ली के साथ एक संयुक्त अभ्यास और 26-29 अक्टूबर को गोवा में एक पोर्ट कॉल। जहाज पर उच्च स्तरीय दौरे और रक्षा प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया।



भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस तबर जर्मनी के हैम्बर्ग में बंदरगाह पर उतरा, जिसके बाद जर्मन नौसेना के साथ पासेक्स अभ्यास किया गया, जुलाई 2024

सांस्कृतिक सहयोग

बर्लिन में भारतीय दूतावास के टैगोर सेंटर ने बर्लिनले के 74^{वें} संस्करण के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें कई राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता मनोज बाजपेयी के साथ 'वैश्विक संदर्भ में भारतीय सिनेमा' पर बातचीत की गई। टैगोर सेंटर के 30 साल पूरे होने और अलेक्जेंडर वॉन ज़ेमलिंस्की की लिрикल सिम्फनी की शताब्दी के उपलक्ष्य में डुइसबर्ग फिलहारमोनी में संगीत कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की गई, जो रवींद्रनाथ टैगोर की कविता 'द गार्डनर' पर आधारित है।

मार्च 2024 में, हिल्डेशाइम विश्वविद्यालय में भारतीय संगीत की आईसीसीआर पीठ की स्थापना संबंधी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

प्रवासी भारतीय

जर्मनी में लगभग 1.93 लाख एनआरआई/भारतीय पासपोर्ट धारक और लगभग 52,864 भारतीय मूल के लोग हैं।

भारतीय प्रवासियों में मुख्य रूप से पेशेवर, शोधकर्ता तथा वैज्ञानिक, व्यवसायी, नर्स और छात्र शामिल हैं। जर्मनी में लगभग 49,483 (2024) भारतीय छात्र अध्ययन कर रहे हैं, यह संख्या पिछले 4 वर्षों में दोगुनी हो गई है। भारतीय छात्र जर्मन विश्वविद्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का सबसे बड़ा समूह हैं, जिनमें से कई विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में मास्टर और डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रहे हैं। आईटी, बैंकिंग और वित्त के क्षेत्रों में अर्हता प्राप्त भारतीय पेशेवरों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

आयरलैंड

भारत और आयरलैंड के संबंधों की विशेषता मजबूत राजनीतिक संबंध हैं, जो उनके स्वतंत्रता संग्राम आंदोलनों और बढ़ते आर्थिक एवं लोगों के मध्य आपसी संबंधों पर आधारित हैं।

14 मार्च को विदेश मंत्री ने आयरलैंड के तत्कालीन उद्यम, व्यापार और रोजगार मंत्री साइमन कोवेनी से मुलाकात की, जो सेंट पैट्रिक दिवस समारोह के लिए भारत आए थे। मंत्री साइमन कोवेनी ने भारत यात्रा के दौरान तत्कालीन एमओएस (एमएल) और तत्कालीन नागर विमानन राज्य मंत्री से भी मुलाकात की।

22-25 अक्टूबर को आयरलैंड के चुनाव आयोग की अध्यक्ष न्यायमूर्ति मैरी बेकर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल भारत आया और मुख्य चुनाव आयुक्त से मिला। उन्होंने चुनाव सुधारों, चुनावी अखंडता के क्षेत्रों में सहयोग और ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ाने पर चर्चा की और संसदीय चुनावों को कराने में भारत के अनुभव के विषय में चर्चा की।

आयरलैंड के विदेश विभाग के महासचिव जो हैकेट 9 जनवरी को दिल्ली आए और सचिव (पश्चिम) से मुलाकात की।

वित्त वर्ष 2023-2024 के दौरान भारत और आयरलैंड के बीच वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार 6.3 बिलियन अमरीकी डॉलर था। आयरलैंड को भारत

का निर्यात 702.73 मिलियन अमरीकी डॉलर और आयरलैंड से आयात 5.6 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा।

आयरलैंड के अग्रणी विद्युत आपूर्ति बोर्ड (ईएसबी) और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी लिमिटेड) ने जनवरी में हरित ईंधन/रसायनों में अनुसंधान एवं विकास, ज्ञान साझा करने और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में संयुक्त प्रायोगिक परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक गैर-बाध्यकारी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

आयरलैंड में लगभग 80,000 भारतीय प्रवासी रहते हैं, जिनमें से अधिकांश स्वास्थ्य सेवा, आईटी, इंजीनियरिंग और वरिष्ठ प्रबंधन पदों पर कार्यरत हैं।

आयरलैंड, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक भारतीय छात्रों (लगभग 10,000) के लिए भी एक महत्वपूर्ण गंतव्य बन गया है, विशेष रूप से इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा और प्रबंधन के क्षेत्रों में स्नातकोत्तर, डॉक्टरेट और पोस्टडॉक्टरेट छात्रों के लिए।

इटली

भारत-इटली संबंधों में उच्च स्तरीय राजनीतिक वार्ता जारी रही तथा सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए गए। जून में पुगलिया में जी7 आउटरीच लीडर्स समिट में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री की इटली यात्रा मुख्य आकर्षण थी। भारत और इटली के प्रधानमंत्रियों ने 18 नवंबर को रियो डी जेनेरियो में द्विपक्षीय संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना की घोषणा की। इसका उद्देश्य रणनीतिक साझेदारी से ठोस परिणाम सुनिश्चित करना है।

प्रधानमंत्री ने इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर आउटरीच पार्टनर के रूप में जी7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 13 और 14 जून को इटली की यात्रा की। तीसरे कार्यकाल के लिए चुने जाने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा थी। भारत के प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री मेलोनी ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक के परिणामों में, अन्य बातों के साथ-साथ, ऊर्जा परिवर्तनशीलता में सहयोग के लिए एक आशय पत्र और औद्योगिक संपदा अधिकारों पर एक समझौता ज्ञापन शामिल थे। प्रधानमंत्रियों ने 18 नवंबर को जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान रियो डी जेनेरियो में फिर से मुलाकात की, जहां उन्होंने 2025-29 के लिए एक संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना का समर्थन किया, जो एक पांच वर्षीय रोडमैप है जिसमें व्यापार एवं निवेश, रक्षा, अंतरिक्ष, स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तनशीलता, नवाचार और आवाजाही जैसे प्रमुख क्षेत्रों में बढ़ी हुई भागीदारी की परिकल्पना की गई है। कार्य योजना का उद्देश्य सह-उत्पादन, औद्योगिक साझेदारी और नवाचार को सुविधाजनक बनाकर ठोस परिणाम सुनिश्चित करना है।

24-26 नवंबर को विदेश मंत्री ने जी7 विदेश मंत्रियों की बैठक (एफएमएम) में भाग लेने के लिए इटली की यात्रा की। जी7 एफएमएम के दौरान विदेश मंत्री ने इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी से मुलाकात की। उन्होंने इतालवी विदेश मंत्रालय के सहयोग से इतालवी अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अध्ययन संस्थान द्वारा आयोजित भूमध्यसागरीय (एमईडी) वार्ता में भाग



जून 2024 में इटली में आयोजित जी-7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री और प्रतिभागी वैश्विक नेतागण

लिया। विदेश मंत्री ने विदेश मंत्रालय के महासचिव, सीनेटर गुइलियो टेरज़ी, भारत-इटली संसदीय मैत्री समूह के अध्यक्ष और अन्य इतालवी गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में रोम में दूतावास के नए चांसरी भवन का उद्घाटन किया। विदेश मंत्री ने भारतीय सामुदायिक संघों के प्रतिनिधियों और इटली में रहने वाले भारतीय प्रवासियों के एक वर्ग से भी बातचीत की।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने 16 और 17 जुलाई को इटली के रेजियो कैलाब्रिया में जी7 व्यापार एवं निवेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। उन्होंने द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश, औद्योगिक सह-उत्पादन तथा स्वच्छ प्रौद्योगिकियों में सहयोग पर चर्चा करने के लिए उप-प्रधानमंत्री एवं विदेश मामलों एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री एंटोनियो तजानी से मुलाकात की।

पर्यटन राज्य मंत्री ने 13-15 नवंबर को फ्लोरेंस में जी7 पर्यटन मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया और अपने इतालवी समकक्ष से मुलाकात की।

जी7 संस्कृति मंत्रियों की बैठक, जी7 उद्योग बैठक और जी7 स्वास्थ्य बैठक में वरिष्ठ अधिकारी स्तर पर भारतीय प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व रहा।

आर्थिक सहयोग

इटली यूरोपीय संघ में भारत का छठा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जिसका वित्त वर्ष 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार 14.56 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जिसमें से 8.77 बिलियन अमेरिकी डॉलर भारत के निर्यात हैं। व्यापार संतुलन 2.97 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ भारत के पक्ष में है।

इटली के उद्यम मंत्री एडोल्फो उर्सो 29 नवंबर से 2 दिसंबर तक भारत आए। उनकी यात्रा इतालवी नौसेना के जहाज आईटीएस अमेरिगो वेस्पुची के मुंबई बंदरगाह पर पहुंचने के अवसर पर हुई, जो उसके इंडो-पैसिफिक दौरे का हिस्सा था। मंत्री उर्सो ने केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग

मंत्री, अंतरिक्ष राज्य मंत्री, कोयला एवं खान मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री से मुलाकात की और दिल्ली में सीआईआई भागीदारी शिखर सम्मेलन में भाग लिया।

सचिव (अंतरिक्ष) और इसरो के अध्यक्ष ने 13-17 अक्टूबर को मिलान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस (आईएसी) में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। उन्होंने इटली के उद्यम और मेड इन इटली मंत्री एडोल्फो उर्सो के साथ द्विपक्षीय बैठक में भाग लिया। जहां भारत और इटली अंतरिक्ष अन्वेषण और वाणिज्यिक सहयोग में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। आईएनएसपेस के तत्वावधान में आईएसी प्रदर्शनी में भारत मंडप में 17 भारतीय अंतरिक्ष कंपनियों और स्टार्टअप ने भाग लिया। यात्रा के दौरान, उपग्रह सेवाओं और ग्राउंड स्टेशन समाधान के क्षेत्रों में भारतीय और इतालवी अंतरिक्ष स्टार्टअप के बीच तीन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।

रक्षा सहयोग

भारत और इटली के रक्षा संबंधों को मार्च में संयुक्त रक्षा समिति की बैठक के आयोजन से गति मिली, यह बैठक रक्षा सचिव और इतालवी रक्षा मंत्रालय के महासचिव लेफ्टिनेंट जनरल लुसियानो प्रोटोलानो के नेतृत्व में हुई।

इटालवी नौसेना के जहाजों द्वारा भारतीय बंदरगाहों की यात्रा से भारत-इटली समुद्री सहयोग को बढ़ावा मिला है। इंडो-पैसिफिक पर इटली के निरंतर ध्यान-केंद्रण के हिस्से के रूप में, आईटीएस कैवोर और आईटीएस एल्पिनो जहाजों से युक्त एक इतालवी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने 1-4 अक्टूबर को गोवा में पोर्ट कॉल किया। इस अवधि के दौरान पैसाक्स अभ्यास आयोजित किया गया। सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैनुफैक्चरर्स (एसआईडीएम) और इटैलियन इंडस्ट्रीज फेडरेशन फॉर एयरोस्पेस, डिफेंस एंड सिविलियरीटी (एआईएडी) के प्रतिनिधियों ने 2 और 3 अक्टूबर को एक इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किया। इतालवी नौसेना के प्रशिक्षण जहाज, आईटीएस अमेरिगो

वेस्पुची ने अपने विश्व दौरे और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की यात्रा के हिस्से के रूप में 28 नवंबर-2 दिसंबर को मुंबई में पोर्ट कॉल किया।

भारत और इटली के बीच प्रथम साइबर वार्ता 25 अक्टूबर को नई दिल्ली में हुई। दोनों पक्षों ने साइबर खतरे के परिदृश्य, राष्ट्रीय साइबर रणनीतियों/नीतियों, महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की सुरक्षा, क्षमता निर्माण पहलों के लिए तंत्रों और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोगात्मक अवसरों के संबंध में विचारों का आदान-प्रदान किया।

सांस्कृतिक संबंध

अगस्त में, आईसीसीआर द्वारा उपहार स्वरूप दी गई महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण बंदरगाह शहर ब्रिंडिसि में भारत के राजदूत और ब्रिंडिसि के मेयर गुइसेप्पे मार्चियोना द्वारा किया गया था, यह वही स्थान है जहां से गांधीजी 1932 में ब्रिंडिसि के लिए जहाज पर चढ़े थे।

सितंबर में, मिलान विश्वविद्यालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) के बीच 2025 के मध्य से हिंदी पीठ की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

प्रवासी भारतीय

इटली में लगभग 2,00,000 भारतीय प्रवासी रहते हैं, जो इटली में विदेशी नागरिकों का 3.25 प्रतिशत है और देश में छठा सबसे बड़ा विदेशी समुदाय है। इतालवी विश्वविद्यालयों में भारतीय विश्वविद्यालय के छात्रों की संख्या बढ़ रही है, वर्तमान में 6000 से अधिक छात्र इंजीनियरिंग, फैशन और डिजाइन, प्रबंधन, अर्थशास्त्र और चिकित्सा में नामांकित हैं।

बहुपक्षीय संबंध

भारत, विश्व खाद्य सुरक्षा समिति के अलावा खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ), विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) और अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष (आईएफएडी) की रोम स्थित तीन संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के शीर्ष शासी निकायों और समितियों में भारत का महत्व और उपस्थिति बढ़ाने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहा है। भारत को 2025-2027 तक 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (ईसीओएसओसी) के माध्यम से डब्ल्यूएफपी कार्यकारी बोर्ड के सदस्य के रूप में फिर से चुना गया; 2024 में आईएफएडी के कार्यकारी बोर्ड में एक और तीन वर्ष की अवधि अर्थात् 2024-2026 के लिए और 3 वर्ष की अवधि के लिए आईएफएडी की मूल्यांकन समिति के सदस्य के रूप में चुना गया।

वर्ष के दौरान, भारत को सर्वसम्मति से खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के तहत दो प्रमुख तकनीकी उप-समितियों का प्रथम उपाध्यक्ष चुना गया, जो दो वर्ष की अवधि के लिए है। इनमें 2024-2025 के लिए मत्स्य प्रबंधन पर मत्स्य पालन समिति (सीओएफआई) उप-समिति और 2024-2026 के लिए पशुधन पर कृषि समिति (सीओएजी) उप-समिति शामिल हैं। इन

समितियों में भारत का चुनाव मत्स्य प्रबंधन और पशुधन विकास में इसकी वैश्विक स्थिति और योगदान का प्रमाण है। भारत को कृषि में जल की कमी पर वैश्विक ढांचे संबंधी संचालन समिति (डब्ल्यूएएसएजी) के सदस्य के रूप में चुना गया।

खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ)

अंतर्राष्ट्रीय श्रीअन्न वर्ष (आईवाईएम) का समापन समारोह 29 मार्च को एफएओ मुख्यालय, रोम में आयोजित किया गया, जिसमें एफएओ के वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों, स्थायी प्रतिनिधियों, सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों/संस्थाओं के प्रतिनिधियों, किसानों, रसोइयों, उद्योगपतियों, छात्रों, शोधकर्ताओं आदि ने भाग लिया।

भारत सरकार के कई उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडलों ने एफएओ, रोम में प्रमुख बैठकों में भाग लिया। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव ने 14-16 अक्टूबर को विश्व खाद्य मंच के दौरान एफएओ हैड-इन-हैड पहल फोरम और संयुक्त राष्ट्र पारिवारिक खेती दशक के वैश्विक पारिवारिक कृषक फोरम के उच्च स्तरीय उद्घाटन समारोह में भाग लिया। एफएओ में बैठकों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के दौरो में 8-12 जुलाई को मत्स्य पालन विभाग के सचिव का एफएओ मत्स्य पालन समिति की बैठक के लिए दौरा, एफएओ-वानिकी समिति की बैठक के लिए वन महानिदेशक और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के विशेष सचिव का दौरा, कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग की कार्यकारी समिति के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का दौरा और पशु स्वास्थ्य नवाचार पर एफएओ वैश्विक सम्मेलन के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग के सचिव की यात्रा शामिल थी।

भारत ने आयरलैंड के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस घोषित करने के प्रस्ताव को सह-प्रायोजित किया। 30 सितंबर-4 अक्टूबर को आयोजित कृषि संबंधी एफएओ समिति के 29^{वाँ} सत्र में इसका समर्थन किया गया। इस अनुमोदन से 2024 में एफएओ परिषद और 2025 में एफएओ सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अनुमोदन का मार्ग प्रशस्त हुआ।

लक्समबर्ग

भारत और लक्समबर्ग के बीच मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, जो द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तरों पर आपसी समझ और सहयोग के उच्च स्तर पर आधारित हैं। भारत और लक्समबर्ग के बीच राजनयिक संबंध 1948 में स्थापित हुए थे।

प्रधानमंत्री को लगातार तीसरी बार फिर से चुने जाने पर 22 जुलाई को लक्समबर्ग के प्रधानमंत्री ल्यूक फ्रीडेन से बधाई संदेश मिला। वार्ता के दौरान, दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, सतत वित्त व्यवस्था, औद्योगिक विनिर्माण, स्वास्थ्य, बाहरी अंतरिक्ष और लोगों से लोगों के बीच संपर्कों सहित विविध क्षेत्रों में द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने पर जोर दिया।

भारत-लक्जमबर्ग के बीच दूसरे दौर की एफओसी वार्ता 9 अप्रैल को नई दिल्ली में हुई। नवंबर 2020 में भारत और लक्जमबर्ग के प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के परिणामस्वरूप इस परामर्श को संस्थागत रूप दिया गया।

18^{वाँ} भारत-बेल्जियम लक्जमबर्ग आर्थिक संघ संयुक्त आयोग की बैठक (भारत बीएलईयू जेसीएम) अप्रैल में नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस अवसर पर द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग सहित कई मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई।

व्यापार और निवेश भारत लक्जमबर्ग संबंधों का एक महत्वपूर्ण तत्व है। भारत और लक्जमबर्ग के बीच दोहरा कराधान अपवंचन संधि (डीटीएए), एक सामाजिक सुरक्षा करार और एक नागरिक उड्डयन समझौता है, जो द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापार सहयोग को बढ़ाने के लिए बुनियादी आधार तैयार करता है।

लक्जमबर्ग भारत के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है। जनवरी-सितंबर 2024 तक वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार 6.70 मिलियन अमरीकी डॉलर रहा, जिसमें से भारतीय निर्यात 2.37 मिलियन अमरीकी डॉलर और लक्जमबर्ग का निर्यात 4.23 मिलियन अमरीकी डॉलर रहा।

अप्रैल 2000 से मार्च 2024 तक लक्जमबर्ग से भारत में एफडीआई प्रवाह 4.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जिससे यह भारत में 14^{वाँ} सबसे बड़ा निवेशक बन गया।

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) और लक्जमबर्ग के वित्तीय नियामक के बीच 2022 में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, कमीशन डी सर्विलांस डू सेक्टर फाइनेंसर (सीएसएसएफ), अध्यक्ष आईएफएससीए के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने फरवरी में लक्जमबर्ग का दौरा किया और विभिन्न वित्तीय सेवा एजेंसियों के साथ बैठकें कीं।

मोनाको

भारत और मोनाको के 2007 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए तथा पेरिस में भारत के राजदूत को मोनाको रियासत का भी राजदूत नियुक्त किया गया।

भारत-मोनाको सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में व्यापार, पर्यटन और कर मामले शामिल हैं जो भारत और मोनाको के बीच समग्र सकारात्मक संबंधों को समृद्ध करते हैं। दोनों पक्ष सांस्कृतिक संबंधों, समुद्री जैव विविधता और स्वच्छ ऊर्जा पर सहयोग सहित अन्य क्षेत्रों में भी सहयोग का प्रयास कर रहे हैं।

नीदरलैंड

भारत और नीदरलैंड के बीच लंबे समय से मैत्रीपूर्ण और बहुआयामी संबंध हैं, जिनमें लोकतंत्र, विधि के शासन और वैश्विक एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर बढ़ती एकमतता के साझा मूल्यों द्वारा चिह्नित सहयोग का व्यापक एजेंडा शामिल

है। इस वर्ष दोनों देशों के बीच सहयोग के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में विभिन्न मंत्रालय-स्तरीय बातचीत और प्रतिनिधिमंडल-स्तरीय आदान-प्रदान के साथ जुड़ाव की सक्रिय व्यवस्था देखी गई।

उच्च स्तरीय आदान-प्रदान

भारत में लोकसभा चुनावों के बाद, जुलाई में नीदरलैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री मार्क रूट ने प्रधानमंत्री को टेली वार्ता द्वारा बधाई दी। दोनों नेताओं ने भारत-नीदरलैंड द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की, जिसमें जल के लिए रणनीतिक साझेदारी और कृषि, स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी एवं सेमीकंडक्टर और स्वच्छ ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग शामिल है। जुलाई में नीदरलैंड में प्रधानमंत्री डिक शूफ के नेतृत्व में नई सरकार के सत्ता में आने पर, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने अपने समकक्षों को बधाई दी।

2024 में रायसीना वार्ता में नीदरलैंड के दो वरिष्ठ मंत्री शामिल हुए। नीदरलैंड के तत्कालीन विदेश मंत्री हैके ब्रुन्स स्लॉट और तत्कालीन रक्षा मंत्री काजसा ओलोग्रेन फरवरी में रायसीना वार्ता में वक्तव्य देने के लिए भारत आए थे। स्लॉट ने इस दौरान विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की। यह रायसीना वार्ता में डच रक्षा मंत्री की पहली भागीदारी थी। तत्कालीन रक्षा मंत्री ओलोग्रेन ने रक्षा मंत्री से भी मुलाकात की और समुद्री सुरक्षा और औद्योगिक सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर विचार-विमर्श किया।



विदेश मंत्री, सितंबर 2024 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अवसर पर नीदरलैंड के विदेश मंत्री कैस्पेर वेल्डकैप के साथ

जुलाई में पदभार ग्रहण करने वाले डच विदेश मंत्री कैस्पर वेल्डकैंप ने सितंबर में 79^{वाँ} यूएनजीए के दौरान विदेश मंत्री से मुलाकात की। रणनीतिक सहयोग, जल प्रबंधन, कृषि, व्यापार और निवेश तथा अन्य क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर व्यापक चर्चा हुई। वित्त स्टेट सेक्रेटरी मार्निक्स वैन रिज ने 14 मार्च को नई दिल्ली में आर्थिक कार्य विभाग के सचिव से मुलाकात की। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कराधान मामलों पर विचारों का आदान-प्रदान किया और दोहरे कराधान से बचने के लिए द्विपक्षीय समझौते पर लंबे समय से चली आ रही सहमति को दोहराया।

अन्य द्विपक्षीय आदान-प्रदान

भारत और नीदरलैंड के बीच 12^{वाँ} विदेश कार्यालय परामर्श बैठक 2 मई को हेग में आयोजित की गई थी, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा की गई थी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व तत्कालीन सचिव (पश्चिम) ने किया था। 14 अक्टूबर को नीदरलैंड के विदेश मंत्रालय में राजनीतिक मामलों के महानिदेशक मार्सेल डी विंक ने भारत का दौरा किया और सचिव (पश्चिम) तथा उप एनएसए से मुलाकात की।

इंडो-पैसिफिक के प्रति डच प्रतिबद्धता के अनुरूप, डच फ्रिगेट हिज नीदरलैंड मैजेस्टीज शिप (एचएनएलएमएस) "ट्रॉम्प" इंडो-पैसिफिक के लिए रवाना हुआ और अप्रैल में मुंबई बंदरगाह पर रुका। तत्कालीन विदेश व्यापार और विकास सहयोग मंत्री लीजे श्रेनेमेकर ने पोर्ट कॉल में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया। यात्रा के दौरान, उन्होंने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री से मुलाकात की और जल, कृषि और ऊर्जा परिवर्तनशीलता के क्षेत्रों में डच कंपनियों के लिए अवसरों पर चर्चा की।

वर्ष के दौरान कई अन्य महत्वपूर्ण वार्ता तंत्रों की बैठकें और यात्राएँ हुईं। 7 नवंबर को वीजा, कौंसली और पारस्परिक कानूनी सहायता संधियों (एमएलएटी)/प्रत्यर्पण मामलों पर चर्चा करने के लिए हेग में पहली बार भारत-नीदरलैंड कौंसली वार्ता आयोजित की गई। 7 नवंबर को, हेग में तीसरी भारत-नीदरलैंड साइबर नीति वार्ता आयोजित की गई। 10 जुलाई को, हेग में प्रस्तावित द्विपक्षीय प्रवासन और आवाजाही भागीदारी करार और राजनयिक वीजा छूट करार पर भारत और नीदरलैंड के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई।

आर्थिक संबंध

नीदरलैंड दुनिया में भारत का 11^{वाँ} सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और यूरोपीय संघ में सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वित्त वर्ष 2023-2024 के दौरान नीदरलैंड के साथ कुल सामग्री व्यापार 27.335 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। नीदरलैंड के साथ भारत का व्यापार अधिशेष 17.403 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। वित्त वर्ष 2023-2024 में भारत ने नीदरलैंड को 22.369 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का माल निर्यात किया और 4.966 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का माल आयात किया।

वित्त वर्ष 2023-2024 के दौरान एफडीआई इक्विटी प्रवाह 4.924 बिलियन अमरीकी डॉलर का था। अप्रैल 2000 से मार्च 2024 तक, नीदरलैंड भारत में निवेश करने वाला चौथा सबसे बड़ा निवेशक था, इसका कुल निवेश सकल निवेश का 7 प्रतिशत था, जिसमें 48.683 बिलियन

अमरीकी डॉलर का संचयी एफडीआई इक्विटी प्रवाह था। इसी अवधि के दौरान, नीदरलैंड, भारतीय कंपनियों द्वारा 25.031 बिलियन अमरीकी डॉलर के विदेशी निवेश (विदेशी प्रत्यक्ष निवेश-ओडीआई) के साथ चौथा सबसे बड़ा गंतव्य था, जो निवेश का 8.27 प्रतिशत था। वित्त वर्ष 2023-2024 में, नीदरलैंड 1.098 मिलियन अमरीकी डॉलर के निवेश के साथ भारत से ओडीआई के लिए पाँचवाँ सबसे बड़ा गंतव्य था।

अन्य क्षेत्रों में सहयोग

वर्ष के दौरान जल संबंधी भारत-नीदरलैंड रणनीतिक साझेदारी को आगे विस्तारित किया गया। 2023 में भारत में आयोजित भारत-नीदरलैंड रणनीतिक जल साझेदारी पर पहली मंत्रिस्तरीय बैठक के बाद, नीदरलैंड की जल दूत मीके वैन गिन्नेकेन ने जुलाई में भारत का दौरा किया। उन्होंने जल शक्ति मंत्री से मुलाकात की और दिल्ली में अन्य प्राधिकरणों और प्रबुद्ध मंडलों के साथ वार्ता की। उन्होंने केरल का भी दौरा किया और तटीय संरक्षण पर चर्चा की और जल से लाभ उठाने संबंधी पहल की प्रगति का जायजा लिया। 15 जुलाई को, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण (डी.ओ.डब्ल्यू.आर., आर.डी.एण्ड.जी.आर.) विभाग, पश्चिम बंगाल और केरल राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों वाले 10-सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने डच अवसररचना एवं जल प्रबंधन मंत्रालय के महानिदेशक जाप स्लोटमेकर से मुलाकात की तथा और अधिक सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की।

स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में, सचिव (स्वास्थ्य) ने नीदरलैंड का दौरा किया और डिजिटल स्वास्थ्य, एंटी-माइक्रोबियल रिसर्च (एएमआर), जलवायु परिवर्तन, चिकित्सा पर्यटन और फार्मा क्षेत्र में और अधिक सहयोग पर चर्चा करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य महानिदेशक मार्जोलिजन सोनेमा से मुलाकात की। भारत और नीदरलैंड के बीच स्वास्थ्य पर 5^{वाँ} संयुक्त कार्य समूह की बैठक 15 फरवरी को हुई। दोनों पक्षों ने महामारी की तैयारी, संक्रामक रोगों और डेटा संचालित रोग निगरानी प्लेटफार्मों पर संरचित सहयोग के अवसरों का पता लगाने पर सहमति व्यक्त की। वे विश्व स्वास्थ्य सभा (डब्ल्यूएचए), यूएनजीए जैसे बहुपक्षीय मंचों पर एएमआर पर एक साथ काम करने और आपूर्ति श्रृंखला और अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में आगे सहयोग करने पर भी सहमत हुए।

कृषि सहयोग पर 7^{वाँ} भारतीय-डच संयुक्त कार्य समूह की बैठक 10 अप्रैल को नीदरलैंड के हेग में हुई, जिसमें जैव विविधता बहाली में स्थायी व्यापार मॉडल, जैव विविधता अभिसमय पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, भारतीय बागवानी का विकास, प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि, फसल विविधीकरण और उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की प्रक्रिया और कार्यप्रणाली में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। वर्तमान में भारत में 9 सीओई हैं, जो डच डिजाइन के साथ ग्रीनहाउस का निर्माण कर रहे हैं, जिन्हें भारत में बनाया जाएगा। नीदरलैंड के कृषि मंत्रालय के महासचिव जान कीस गोएट ने नवंबर में लखनऊ में सीआईआई कृषि भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एक डच प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, जहां नीदरलैंड एक भागीदार देश था। इस यात्रा के दौरान गोएट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, कृषि मंत्रालय के सचिव और मत्स्य मंत्रालय के सचिव से मुलाकात की।

भारत के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) और डच जलवायु नीति एवं हरित विकास मंत्रालय के बीच 12 सितंबर को नई दिल्ली में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापन में पवन ऊर्जा, बायोमास, जैव ऊर्जा और अपशिष्ट से ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया, सौर ऊर्जा, ऊर्जा भंडारण और आपसी हित के किसी भी अन्य वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के क्षेत्रों में सहयोग की परिकल्पना की गई है। एमएनआरई सचिव के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 12-17 अप्रैल को रोटटरडैम में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी में पहली बार 'प्रदर्शक' के रूप में भाग लिया। 7 फरवरी को, आर्थिक मामलों और जलवायु नीति मंत्रालय के ऊर्जा दूत फ्रेडरिक विलेल्म ने गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह में डच भागीदारी का नेतृत्व किया, जहां उन्होंने 'मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों में परिवहन ईंधन के रूप में एलएनजी' शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। 23 अप्रैल को, विद्युत मंत्रालय के सचिव ने विश्व ऊर्जा कांग्रेस में भाग लेने के लिए नीदरलैंड का दौरा किया। सम्मेलन में कई भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों और सीआईआई की निजी क्षेत्र की कंपनियों ने भाग लिया। कांग्रेस में एक भारतीय मंडप भी स्थापित किया गया, नीदरलैंड के उप प्रधानमंत्री रॉब जेटन और रॉटरडैम के मेयर अहमद अबाउतालेब ने इसका दौरा किया।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग

डच रिसर्च काउंसिल (एनडब्ल्यूओ) और भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) ने भारत (डीएसटी)-नीदरलैंड सहयोग अनुसंधान कार्यक्रम के तहत तीन नई परियोजनाओं को वित्त पोषित किया। ये परियोजनाएं भारत और नीदरलैंड में बाढ़ और सूखे के प्रबंधन में चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करेंगी। तीनों परियोजनाओं को 'जल आपदा प्रबंधन' पर संयुक्त प्रस्ताव के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है, जिसका उद्देश्य भारत और नीदरलैंड दोनों में बाढ़ और सूखे से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए वैज्ञानिक समझ, तकनीकी समाधान, अभिशासन और सामाजिक अभिस्वीकृति विकसित करना है।

29 मई को, डच सरकार द्वारा आयोजित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी-केंद्रित नवाचार मिशन ने नीदरलैंड का दौरा किया, जिसमें भारतीय अंतरिक्ष कंपनियों और भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) जैसे संस्थान शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने विभिन्न डच अंतरिक्ष कंपनियों, ट्वेंटे विश्वविद्यालय और डेलफ्ट विश्वविद्यालय का दौरा किया और अंतरिक्ष क्षेत्र में संभावित द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। इसरो, रेल मंत्रालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं और उद्योग के प्रतिनिधियों से युक्त भारत के एक प्रतिनिधिमंडल ने 13-16 मई को हेग में चार दिवसीय भू-स्थानिक विश्व मंच में भाग लिया।

लोगों से लोगों के आपसी संबंध

भारत के 3,500 से अधिक छात्र (शोधकर्ताओं को छोड़कर) वर्तमान में नीदरलैंड के विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्ययन कर रहे हैं। अक्टूबर

में "शेपिंग टुमॉरो: भारत-नीदरलैंड शैक्षणिक सहयोग पर एक संवाद" विषय पर एक सेमिनार आयोजित किया गया था, जिसमें डच शिक्षा, संस्कृति एवं विज्ञान मंत्रालय ने 13 आईआईटी के डीन/निदेशकों और डच विश्वविद्यालयों के संकाय सदस्यों के साथ भाग लिया था। इस अवसर पर आईआईटी रुड़की और व्रीजे विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। आईआईटी के डीन/निदेशकों ने भविष्य में सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए डच विश्वविद्यालयों का दौरा किया। संस्कृति और लोगों के बीच आपसी सहयोग के क्षेत्र में भारत-नीदरलैंड सहयोग को और मजबूत किया गया। भारत ने 26 सितंबर 2024 से 12 जनवरी 2025 के बीच प्रदर्शन के लिए रिजक्स म्यूजियम (नीदरलैंड का राष्ट्रीय संग्रहालय) द्वारा एशियाई कांस्य प्रदर्शनी के लिए 4 कलाकृतियाँ (एक राष्ट्रीय संग्रहालय से और 3 बिहार संग्रहालय से) उधार दी हैं। प्रदर्शनी में 75 एशियाई कांस्य कृतियाँ प्रदर्शित की जा रही हैं और यह यूरोप में अपनी तरह की पहली प्रदर्शनी है।

प्रवासी भारतीय

नीदरलैंड में यूरोप में दूसरा सबसे बड़ा भारतीय प्रवासी समुदाय (यूके के बाद) तथा मुख्य भूमि यूरोप में सबसे बड़ा भारतीय प्रवासी समुदाय है, जिसकी कुल संख्या लगभग 2,60,000 है, जिसमें 60,000 भारतीय और 2,00,000 भारतीय मूल के सूरीनामी-हिंदुस्तानी समुदाय के लोग शामिल हैं।

नीदरलैंड भारतीय छात्रों के लिए एक लोकप्रिय शिक्षा गंतव्य है, खासकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। टीयू डेलफ्ट, लीडेन यूनिवर्सिटी और मास्ट्रिच यूनिवर्सिटी जैसे कई डच विश्वविद्यालयों का भारतीय विश्वविद्यालयों के साथ लंबे समय से सहयोग है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है और वर्तमान में 3500 से अधिक भारतीय छात्र नीदरलैंड में अध्ययन कर रहे हैं।

पुर्तगाल

ऐतिहासिक समुद्री संबंधों, सांस्कृतिक और प्रवासी जुड़ाव पर आधारित भारत और पुर्तगाल के बीच द्विपक्षीय संबंध 2024 में भी आगे बढ़ते रहे। वर्ष 2025 में राजनयिक संबंधों की पुनः स्थापना की 50^{वीं} वर्षगांठ है।

10 मार्च को हुए संसदीय चुनावों के बाद अप्रैल में पुर्तगाल में नई सरकार का गठन हुआ। डॉ. लुइस मोन्टेनेग्रो ने 2 अप्रैल को पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला।

प्रधानमंत्री ने नवंबर में रियो डी जेनेरियो में जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री लुइस मोन्टेनेग्रो से मुलाकात की। बैठक में पुर्तगाल के विदेश मंत्री पाउलो रंगेल और भारतीय विदेश मंत्री भी मौजूद थे, जिसमें आर्थिक संबंधों, रक्षा सहयोग और लोगों के बीच संबंधों के संवर्धन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत और पुर्तगाल के बीच दीर्घकालिक संबंधों पर चर्चा की गई। यह दोनों नेताओं के बीच पहली बैठक और नई सरकार के साथ पहली उच्च स्तरीय बातचीत थी।



नवंबर 2024 में रियो डी जेनेरियो में जी20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर पुर्तगाल के प्रधान मंत्री लुइस मोंटेनेग्रो के साथ प्रधानमंत्री

वैश्विक और क्षेत्रीय संघर्षों और वैश्विक व्यापार पर बाहरी झटकों के बावजूद, द्विपक्षीय व्यापार में लगातार वृद्धि हुई है, जो 2023 में 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। व्यापार संतुलन भी भारत के पक्ष में बना हुआ है। पुर्तगाल में 2023 में 26.5 मिलियन पर्यटक आए, जिनमें से 86,200 भारतीय थे।

संस्थागत तंत्र के तहत नियमित संवाद और आदान-प्रदान ने कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों में निरंतर प्रगति में योगदान दिया है। इनमें जनवरी में आयोजित चौथी एफओसी और सितंबर में लिस्बन में आयोजित रक्षा संबंधी संयुक्त कार्य समूह की तीसरी बैठक शामिल है। विदेश मंत्री की पुर्तगाल यात्रा के दौरान की गई घोषणा के अनुरूप नवंबर में लिस्बन में पहली भारत-पुर्तगाल कौंसली वार्ता आयोजित की गई थी।

उच्च स्तरीय आदान-प्रदान

प्रधानमंत्री ने 18 नवंबर को रियो डी जेनेरियो में जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो से मुलाकात की। व्यापार एवं निवेश, रक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यटन, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संबंधों के साथ-साथ क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मंचों में सहयोग के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने आईटी एवं डिजिटल प्रौद्योगिकी, हरित ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, स्टार्टअप एवं नवाचार तथा पेशेवरों और कुशल श्रमिकों की आवाजाही जैसे नए और उभरते क्षेत्रों में सहयोग की बढ़ती संभावनाओं को भी रेखांकित किया। दोनों नेताओं ने 2025 में भारत और पुर्तगाल के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की आगामी 50^{वीं} वर्षगांठ को संयुक्त रूप से मनाने पर सहमति व्यक्त की।

चौथी विदेश कार्यालय परामर्श बैठक 31 जनवरी को नई दिल्ली में हुई, जिसकी सह-अध्यक्षता सचिव (पश्चिम) और पुर्तगाल के विदेश मंत्रालय में विदेश नीति के तत्कालीन महानिदेशक राजदुत रुई विंहास ने की। बैठक में द्विपक्षीय सहयोग के संपूर्ण पहलुओं की समीक्षा की गई, जिसमें अक्टूबर 2023 में विदेश मंत्री की पुर्तगाल यात्रा के दौरान हुई वार्ताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया।

भारत-पुर्तगाल संयुक्त रक्षा कार्य समूह की तीसरी बैठक 17 सितंबर को लिस्बन में आयोजित की गई। इस बैठक की सह-अध्यक्षता रक्षा मंत्रालय और पुर्तगाल के संयुक्त सचिव (अंतर्राष्ट्रीय सहयोग) तथा पुर्तगाल के रक्षा नीति महानिदेशक मेजर जनरल नूनो लेमोस पिरिस ने की।

दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय मुद्दों और सैन्य संबंधों को बढ़ाने के कदमों पर चर्चा की तथा रक्षा औद्योगिक सहयोग के अवसरों पर वार्ता की।

पहली भारत-पुर्तगाल कौंसली वार्ता 5 नवंबर को लिस्बन में आयोजित की गई। बैठक की सह-अध्यक्षता संयुक्त सचिव (कौंसली, पासपोर्ट और वीजा) और पुर्तगाल के विदेश मंत्रालय के कौंसली मामलों और पुर्तगाली समुदाय की महानिदेशालय मार्टा क्राउलिंग ने की। दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से कौंसली, वीजा और अन्य मामलों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।

आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए द्विपक्षीय व्यापार 1.36 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था, जिसमें भारतीय निर्यात 1.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर और पुर्तगाल से आयात 178 मिलियन अमेरिकी डॉलर का था। प्रमुख भारतीय निर्यातों में खनिज ईंधन, लोहा और इस्पात, कपास, कार्बनिक रसायन, प्लास्टिक तथा संबद्ध उत्पाद, विद्युत मशीनरी, समुद्री उत्पाद, परिधान और वस्त्र, मशीनरी, जूते, रबर तथा संबद्ध उत्पाद एवं कॉफी और चाय शामिल थे।

पुर्तगाल से आयातित प्रमुख वस्तुओं में लकड़ी की लुगदी, मशीनरी एवं यांत्रिक उपकरण, कार्बनिक रसायन और विद्युत मशीनरी शामिल हैं। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में पुर्तगाल का स्थान 52^{वां} है, सितंबर तक कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 125.93 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। पुर्तगाल में भारतीय निवेश लगभग 475 मिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है।

इस दौरान भारत से कई वाणिज्यिक प्रतिनिधिमंडल पुर्तगाल गए। इसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के संयुक्त सचिव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल का दौरा भी शामिल था, जिसने 19 अप्रैल को विश्व खाद्य भारत 2024 को बढ़ावा देने के लिए लिस्बन का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल ने पुर्तगाली सरकार के हितधारकों से मुलाकात की, बी2बी बैठकों में भाग लिया और लिस्बन में खाद्य वितरण केंद्र मर्काडो अबास्टेसडोर दा रेगियो डी लिस्बोआ (एमएआरएल) का दौरा किया।

भारतीय निर्यात संगठन महासंघ (एफआईआईओ) के एक प्रतिनिधिमंडल ने 26 और 27 सितंबर को पुर्तगाल का दौरा किया और लिस्बन और पोर्टो में नेटवर्किंग बी2बी कार्यक्रमों में भाग लिया। इन कार्यक्रमों में कई क्षेत्रों की कंपनियों और व्यापार संघों ने भाग लिया।

नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज (नैसकॉम) के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 8 नवंबर को लिस्बन का दौरा किया। उन्होंने स्थानीय आईटी, नवाचार और स्टार्ट-अप क्षेत्रों के हितधारकों के साथ नेटवर्किंग सत्र आयोजित किए, जिसमें वेब समिट के आयोजक और प्रशासन के आधुनिकीकरण संबंधी एजेंसी शामिल थी।

अंतरिक्ष विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने 14-15 मई को लिस्बन में आयोजित बाह्य अंतरिक्ष गतिविधियों के प्रबंधन और स्थिरता सम्मेलन में भाग लिया और भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य प्रस्तुत किया। यह सम्मेलन पुर्तगाली अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र बाह्य अंतरिक्ष मामलों के कार्यालय द्वारा आयोजित किया गया था।

राजदूत ने 26-27 नवंबर को पुर्तगाल के कास्केस में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सभ्यता गठबंधन (यूएनएओसी) के 10^{वां} वैश्विक फोरम में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

पुर्तगाल में भारतीय मूल के लोगों की संख्या लगभग 1,20,000 है, जिसमें 44,051 भारतीय नागरिक और लगभग 90,000 भारतीय मूल के लोग शामिल हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हैं। पुर्तगाल में भारतीय नागरिक, चौथा सबसे बड़ा विदेशी समुदाय है।

सैन मारिनो

सैन मैरिनो के साथ संबंध सौहार्दपूर्ण और मैत्रीवत रहे। दोनों देशों ने विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, साथ ही साझा हितों के मुद्दों पर द्विपक्षीय स्तर पर भी लाभकारी सहयोग स्थापित किया है।

सैन मैरिनो गणराज्य ने यूनिटिड गवर्निंग काउंसिल 2024-28 सहित विभिन्न संयुक्त राष्ट्र निकायों में भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया है। अपर सचिव (एलएंडटी) को रोम स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ (यूनिटिड) की गवर्निंग काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संगठन परिषद श्रेणी-बी, 2024-25 और विश्व स्वास्थ्य संगठन बाहरी लेखा परीक्षा, 2024-27 के लिए चुना गया।

वित्त वर्ष 2023-24 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 9.26 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 0.59 मिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया। सैन मैरिनो को भारत का निर्यात बढ़कर 0.52 मिलियन अमरीकी डॉलर हो गया जबकि सैन मैरिनो से आयात 0.07 मिलियन अमरीकी डॉलर रहा।

स्पेन

1956 में राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद से भारत-स्पेन द्विपक्षीय संबंध सौहार्दपूर्ण रहे हैं। इस वर्ष के दौरान, स्पेन सरकार के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज ने 28 और 29 अक्टूबर को भारत की यात्रा की। यह 18 वर्षों में किसी स्पेनिश शासनाध्यक्ष की पहली यात्रा थी। यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सांचेज ने संयुक्त रूप से सी295 एयरक्राफ्ट फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन किया। भारत और स्पेन ने रेल परिवहन के क्षेत्र में सहयोग और सीमा शुल्क मामलों में सहयोग संबंधी करारों



अक्टूबर 2024 में वडोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस में स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज के साथ प्रधानमंत्री

पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने बेंगलुरु में एक स्पेनिश वाणिज्य दूतावास की स्थापना और बार्सिलोना में भारत के महावाणिज्य दूतावास के संचालन की घोषणा की। उन्होंने 2026 को भारत-स्पेन संस्कृति, पर्यटन और एआई वर्ष के रूप में भी नामित किया।

विदेश मंत्री ने सितम्बर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अवसर पर न्यूयॉर्क में स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अलबरेसे से मुलाकात की, जहां उन्होंने आपसी हित के वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की।

तीसरे उप राष्ट्रपति (उप प्रधानमंत्री) और पारिस्थितिकी परिवर्तन एवं जनसांख्यिकी चुनौती मंत्री टेरेसा रिबेरा 7-9 फरवरी को भारत की यात्रा पर आईं। अपने स्पेनिश समकक्ष के निमंत्रण पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने अप्रैल में स्पेन का दौरा किया।

रक्षा सहयोग

‘आत्मनिर्भर भारत’ के लिए एक उल्लेखनीय कदम उठाते हुए, राष्ट्रपति सांचेज और प्रधानमंत्री मोदी ने अक्टूबर में वडोदरा में एयरबस स्पेन के सहयोग से टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा निर्मित सी-295 विमान के फाइनल असेंबली लाइन प्लांट का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस संयंत्र से 2026 में भारत में निर्मित होने वाले कुल 40 विमानों में से पहला ‘मेड इन इंडिया’ सी295 विमान तैयार होने की उम्मीद है। एयरबस स्पेन भारत को ‘फ्लाई-अवे’ स्थिति में 16 विमान भी डिलीवर कर रहा है।

रक्षा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अम्पारो वलकार्से ने मार्च में स्पेन की रक्षा कंपनियों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान स्पेन की रक्षा कंपनियों के संघ (टीईडीआई) और उसके भारतीय समकक्ष, भारतीय रक्षा निर्माता सोसायटी (एसआईडीएम) के बीच सहयोग संबंधी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

भारतीय नौसेना के जहाज स्पेन के तटों पर अक्सर पैसेज अभ्यास (पासेक्स) और पोर्ट कॉल में भाग लेते हैं, इनमें सबसे ताजा उदाहरण अगस्त में आईएनएस तबर का अभ्यास था।

आर्थिक सहयोग

भारत और स्पेन के बीच 2023 में द्विपक्षीय व्यापार 9.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 4.2 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। अप्रैल 2000 और जून 2024 के बीच 4.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के संघयी एफडीआई स्टॉक के साथ स्पेन भारत में 16^{वां} सबसे बड़ा निवेशक है। भारत में 230 से अधिक स्पेनिश कंपनियां और स्पेन में लगभग 80 भारतीय कंपनियां हैं। अक्टूबर में राष्ट्रपति सांचेज की भारत यात्रा के दौरान, भारत और स्पेन में आपसी निवेश की सुविधा के लिए डीपीआईआईटी इंडिया में और स्पेन के अर्थव्यवस्था, व्यापार और व्यवसाय मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं निवेश महानिदेशालय में फास्ट ट्रेक मैकेनिज्म की स्थापना संबंधी एक करार पर हस्ताक्षर किए गए थे।

सांस्कृतिक सहयोग

राष्ट्रपति सांचेज की भारत यात्रा के दौरान, भारत स्पेन ऑडियो-विजुअल सह-निर्माण करार के तहत एक संयुक्त तंत्र स्थापित किया गया था। भारत, मैड्रिड में समकालीन कला की फेरा डे आर्टे इंडिपेंडिएंटे एन मैड्रिड (एफएआईएम) कला प्रदर्शनी में अतिथि देश था, और जून में एलिकांटे शहर में फेस्टिवल डी होगुएरस में थीम देश भी था।

छात्र आदान-प्रदान और अंतर-विश्वविद्यालय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय विश्वविद्यालय संघ और स्पेनिश विश्वविद्यालयों के रेक्टरों के संयोजन के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

स्पेन में लगभग 75,000 भारतीय प्रवासी रहते हैं। वहां लगभग 1,000 भारतीय छात्र हैं।

यूनाइटेड किंगडम (यू.के.)

पिछले कुछ वर्षों में भारत-ब्रिटेन के संबंध मजबूत, बहुआयामी और पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंधों में तब्दील हो गए हैं। 2021 में वर्चुअल शिखर सम्मेलन में रोडमैप-2030 को अपनाने के साथ-साथ संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी स्तर तक उन्नत किया गया।

दोनों देशों के बीच नियमित उच्च स्तरीय यात्राओं और वार्ताओं से द्विपक्षीय संबंध मजबूत होते रहे हैं। जुलाई में हुए आम चुनाव में ब्रिटेन की लेबर पार्टी

सत्ता में आई। प्रधानमंत्री ने 6 जुलाई को तत्कालीन निर्वाचित प्रधानमंत्री और अब प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर को टेलीफोन पर बधाई दी और उन्हें शीघ्र ही भारत आने का निमंत्रण दिया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने 18 नवंबर को ब्राजील में जी-20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात की। ब्रिटेन और भारत के प्रधानमंत्रियों ने मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता फिर से शुरू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने बेलफास्ट और मैनचेस्टर में यूनाइटेड किंगडम में भारत के दो नए महावाणिज्य दूतावासों की स्थापना की घोषणा की। तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने 14 जून को इटली में जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री से मुलाकात की और रोडमैप 2030 के कार्यान्वयन का आकलन किया, भारत-ब्रिटेन साझेदारी को मजबूत करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने 12 मार्च को भी फोन पर बात की और मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता की प्रगति पर चर्चा की।

विदेश सचिव डेविड लैमी ने कार्यभार संभालने के बाद के पहले ही महीने जुलाई में भारत का दौरा किया। उनकी यात्रा के दौरान प्रौद्योगिकी और सुरक्षा पहल (टीएसआई) पर हस्ताक्षर किए गए।

साउथेम्प्टन विश्वविद्यालय ने ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा कि वह राष्ट्रीय शैक्षिक नीति (एनईपी) के अंतर्गत भारत में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करेगा।

द्विपक्षीय यात्राएं

रक्षा मंत्री ने 8-10 जनवरी को ब्रिटेन की यात्रा की और अपने ब्रिटिश समकक्ष, तत्कालीन रक्षा सचिव ग्रांट शैप्स के साथ द्विपक्षीय वार्ता की, जिसमें रक्षा, सुरक्षा और औद्योगिक सहयोग के कई मुद्दों पर चर्चा की गई। उन्होंने तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और तत्कालीन विदेश सचिव डेविड कैमरन से भी मुलाकात की, ब्रिटिश रक्षा उद्योग के सीईओ और उद्योग जगत के अग्रणी लोगों से बातचीत की और भारतीय समुदाय से भी मिले।

25 सितंबर को विदेश मंत्री ने न्यूयॉर्क में 79^{वां} संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के दौरान यूके के विदेश मंत्री डेविड लैमी से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने 25 नवंबर को जी7 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान रोम में यूके के विदेश मंत्री डेविड लैमी से फिर मुलाकात की। 16-17 जुलाई को इटली में जी7 व्यापार मंत्रियों की बैठक में, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने ब्रिटेन के व्यापार और व्यवसाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जोनाथन रेनॉल्ड्स से मुलाकात की और जनवरी 2022 में शुरू हुई मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) वार्ता को आगे बढ़ाने पर चर्चा की।

विधि एवं न्याय राज्य मंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने विधि वर्ष 2024 के उद्घाटन समारोह में भाग लेने, तथा भारत-यूके विधिक सेवा समिति और संयुक्त परामर्शदात्री समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए 30 सितंबर-3 अक्टूबर तक यूके की यात्रा की।

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने लंदन में आयोजित विश्व यात्रा बाजार 2024 कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 3-7 नवंबर तक ब्रिटेन की यात्रा की।

तत्कालीन विदेश सचिव ने 16^{वीं} भारत-यूके एफओसी के लिए 16 और 17 मई को यूके की यात्रा की। अपनी यात्रा के दौरान, उन्होंने सर फिलिप बार्टन, लॉर्ड तारिक अहमद, जेम्स कार्टलिज, यूके के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, मुख्य व्यापार वार्ताकार और यूके के प्रधानमंत्री के अन्य सलाहकारों सहित वरिष्ठ यूके अधिकारियों से मुलाकात की।

दूसरी 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता 3-4 दिसंबर को दिल्ली में आयोजित की गई। इस वार्ता की सह-अध्यक्षता संयुक्त सचिव (ईडब्ल्यू) और संयुक्त सचिव (आईसी), रक्षा मंत्रालय तथा यू.के. के उनके समकक्षों ने की। नीति आयोग के सीईओ के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल यू.के.-भारत इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज (यूकेआईआईएफबी) बैठकों में भाग लेने के लिए 4-6 सितंबर को लंदन गया। 18 और 19 नवंबर को सह-अध्यक्षों और कार्य समूह के सदस्यों की बैठकें दिल्ली में आयोजित की गईं।

भारत-ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए ब्रिटेन की इंडो-पैसिफिक मंत्री कैथरीन वेस्ट 18-19 नवंबर को भारत आईं। इस दौरान उन्होंने राज्य मंत्री (पीएम) से मुलाकात की।

ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी ने 24-25 जुलाई को भारत की यात्रा की, जहां उन्होंने विदेश मंत्री और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं और प्रधानमंत्री से मुलाकात की। बैठकों का मुख्य आकर्षण ब्रिटेन-भारत प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल का शुभारंभ था, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच प्रौद्योगिकी सुरक्षा और नवाचार पर सहयोग को मजबूत करना है।

मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिण एशिया, राष्ट्रमंडल और संयुक्त राष्ट्र के लिए ब्रिटेन के तत्कालीन राज्य मंत्री लॉर्ड (तारिक) अहमद ऑफ विंबलडन, विदेश मंत्री के निमंत्रण पर रायसीना वार्ता में भाग लेने के लिए 21-24 फरवरी को भारत आए।

ब्रिटेन की तत्कालीन शैडो उप प्रधानमंत्री एंजेला रेनर ने रायसीना वार्ता 2024 में भाग लेने के लिए 18-25 फरवरी तक भारत की यात्रा की। नई दिल्ली में इस कार्यक्रम के दौरान, उन्होंने विदेश मंत्री के साथ बैठक की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संवाद और सहयोग के महत्व पर बल दिया गया और उन्होंने उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात की।

यूके लेबर पार्टी के तत्कालीन शैडो विदेश सचिव डेविड लेमी ने तत्कालीन शैडो व्यापार और व्यापार सचिव जोनाथन रेनॉल्ड्स के साथ यूके-भारत व्यापार वार्ता पर चर्चा करने और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए 05-07 फरवरी को भारत की यात्रा की। उन्होंने सहयोग बढ़ाने के लिए विदेश मंत्री सहित वरिष्ठ भारतीय नेताओं से मुलाकात की।

आर्थिक संबंध

2024 में भारत-यूके द्विपक्षीय व्यापार लगातार बढ़ा है। भारत-यूके द्विपक्षीय व्यापार (वस्तुएं और सेवाएं) 2024 की दूसरी तिमाही के अंत तक 52.30 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया, जबकि 2023 की दूसरी तिमाही के अंत में यह 49.68 बिलियन अमरीकी डॉलर था, अर्थात्

12.4 प्रतिशत या 5.47 बिलियन अमरीकी डॉलर की वृद्धि। वर्ष 2024 (जनवरी से नवंबर) के लिए भारत का यूके को निर्यात 13.09 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 15.58 प्रतिशत अधिक है। 2024 की दूसरी तिमाही के अंत तक भारत का यूके को निर्यात 31.34 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया, जो 11.3 प्रतिशत की वृद्धि है। प्रमुख निर्यातों में खनिज ईंधन, मशीनरी, कीमती पत्थर, फार्मास्यूटिकल्स, परिधान, लोहा और इस्पात तथा रसायन शामिल थे, जिनका कुल निर्यात में 68.72 प्रतिशत योगदान रहा। एफटीए वार्ता के कई दौर हो चुके हैं, जो 2022 से शुरू हुई है। नवंबर में जी20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री स्टारमर के बीच द्विपक्षीय बैठक के दौरान एफटीए वार्ता को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया।

शिक्षा

शिक्षा, भारत-यू.के. संबंधों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। 2024 के यू.के. गृह कार्यालय के अध्ययन वीजा डेटा से पता चलता है कि जून 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में भारतीय नागरिक मुख्य आवेदकों की 110,006 प्रायोजित अध्ययन वीजा अनुदान दिए गए थे (जो समग्र का 25 प्रतिशत थे)। हाल के डेटा से पता चलता है कि अधिकांश (81 प्रतिशत) भारतीय छात्र मास्टर्स स्तर पर अध्ययन करने के लिए यू.के. गए थे।

भारत ने एक और उपलब्धि तब हासिल की जब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भारत में किसी विदेशी विश्वविद्यालय का पहला अपतटीय परिसर स्थापित करने के लिए साउथेम्प्टन विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह परिसर गुरग्राम में होगा और जुलाई 2025 तक शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू होने की आशा है।

रक्षा सहयोग

रक्षा मंत्री ने जनवरी में ब्रिटेन की यात्रा की थी। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और ब्रिटेन के रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला के बीच अगली पीढ़ी की क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक व्यवस्थापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

भारतीय नौसेना के लिए इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम के डिजाइन एवं विकास पर सहयोग के लिए तथा समुद्री प्रोपल्शन डिजाइन और विनिर्माण के क्षेत्र में दीर्घकालिक संबंध और रणनीतिक साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने के लिए भारत और ब्रिटेन के बीच नवंबर में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे।

ब्रिटेन के लिटोरल रिसांस ग्रुप ने भारत का दौरा किया और मार्च में भारतीय नौसेना के साथ समुद्री अभ्यास किया। आईएनएस तबर ने 07-11 अगस्त को लंदन में बंदरगाह पर पोर्ट कॉल किया। रॉयल एयर फोर्स ने अगस्त में अभ्यास तरंग शक्ति में भारतीय वायु सेना के साथ भाग लिया।

भारतीय पश्चिमी वायु कमान के एयर मार्शल ने 17-19 जुलाई को यूके का दौरा किया और ग्लोबल एयर एंड स्पेस चीफ्स कॉन्फ्रेंस (जीएएससीसी) और रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू 2024 में भाग लिया।

मित्र देशों के 4 अधिकारियों सहित एनडीसी के 64^{वाँ} पाठ्यक्रम के 16 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय के कमांडेंट के नेतृत्व में 3-7 जून को विदेशी अध्ययन दौरे पर ब्रिटेन की यात्रा की। रक्षा प्रबंधन महाविद्यालय, सिकंदराबाद से उच्च रक्षा प्रबंधन पाठ्यक्रम (एचडीएमसी-19) के एक प्रतिनिधिमंडल ने मित्र देशों के एक अधिकारी सहित 21 अधिकारियों के साथ 5-9 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय सामरिक प्रबंधन दौरे पर ब्रिटेन की यात्रा की।

भारतीय नौसेना बेड़े के परिचालन मानक और प्रशिक्षण दल ने पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग के नेतृत्व में, समुद्री सुरक्षा में सहयोग के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए रॉयल नेवी के साथ बैठक के लिए 12-16 मार्च को ब्रिटेन की यात्रा की।

ब्रिटेन के युवा और कैडेट प्रतिनिधिमंडल ने भारत का दौरा किया और 16-29 जनवरी तक गणतंत्र दिवस शिविर 2024 में भाग लिया। भारत से

राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) के 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 1-19 जुलाई तक ब्रिटेन का दौरा किया।

भारतीय सेना और ब्रिटिश सेना के बीच 13^{वाँ} सेना कार्यकारी संचालन समूह (ईएसजी) वार्ता 1 और 2 मई को लंदन में आयोजित की गई। भारतीय नौसेना और ब्रिटिश नौसेना के बीच 16^{वाँ} नौसेना ईएसजी बैठक 22-24 अक्टूबर को लंदन और पोर्ट्समाउथ में आयोजित की गई।

प्रवासी भारतीय

2021 की जनगणना के अनुसार, अनुमानतः 1.864 मिलियन प्रवासी भारतीय यूके में रहते हैं। यह यूके की कुल जनसंख्या का लगभग 2.6 प्रतिशत है, जो कि 2022 में अनुमानित रूप से 68 मिलियन थी।

अध्याय

9

अमेरिका

उत्तरी अमेरिका

संयुक्त राज्य अमेरिका

भारत-अमेरिका व्यापक रणनीतिक वैश्विक साझेदारी साझा मूल्यों और भविष्योन्मुखी सहयोग के प्रति एक दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करती है। लोकतंत्र, स्वतंत्रता, कानून के शासन, मानवाधिकारों, बहुलवाद और समान अवसरों पर आधारित यह साझेदारी वैश्विक चुनौतियों का मिलकर समाधान करते हुए अधिक परिपूर्ण संघों के रूप में विकसित होने की दोनों देशों की साझा आकांक्षाओं को दर्शाती है।

भारत और अमेरिका के बीच अभूतपूर्व स्तर का विश्वास और सहयोग वैश्विक कल्याण के लिए एक महत्वाकांक्षी एजेंडा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण रहा है। शीर्ष नेतृत्व के संपर्कों, जैसे कि अमेरिका के विलमिंगटन, डेलावेयर में छठी क्वाड लीडर्स समिट के दौरान तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जोसेफ आर. बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री की बैठक ने द्विपक्षीय संबंधों को और गहन करने के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान किया है। मंत्रिस्तरीय और आधिकारिक संपर्कों में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जिससे आपसी प्राथमिकताओं को मजबूती मिली है।

विदेश नीति, रक्षा, व्यापार, वित्त, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य और अंतरिक्ष सहित विविध क्षेत्रों में पचास से अधिक संवाद तलों के साथ-साथ दोनों देशों की साझेदारी ने उल्लेखनीय गहराई और व्यापकता का प्रदर्शन

किया है। ये संवाद दोनों देशों के विकास और वैश्विक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निरंतर जुड़ाव और प्रगति सुनिश्चित करते हैं।

व्यापार और निवेश प्रवाह में वृद्धि के साथ आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध भी मजबूत हुए हैं। रक्षा सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जिसमें सह-उत्पादन, सह-विकास, उद्योग भागीदारी और संयुक्त सैन्य अभ्यास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ये पहल रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करती हैं और दोनों देशों की सुरक्षा संरचनाओं को मजबूत बनाती हैं।

महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए पहल (आईसीईटी) ने अत्याधुनिक क्षेत्रों में भारत-अमेरिका रणनीतिक सहयोग को और मजबूत किया है। सेमीकंडक्टर, उन्नत दूरसंचार, एआई, क्वांटम प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा, जैव प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिजों और एसटीईएम में सहयोग नवाचार और सतत विकास के लिए साझा प्रतिबद्धता का उदाहरण है।

लोगों के बीच आपसी संबंधों की जीवंतता इस साझेदारी की आधारशिला बनी हुई है। अमेरिका भारतीय छात्रों, पेशेवरों और यात्रियों के लिए एक शीर्ष गंतव्य बना हुआ है, जो गहरी आपसी समझ और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देता है।

आशावाद और अग्रगामी गति से प्रेरित यह व्यापक साझेदारी आने वाले दशकों में और भी अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचने की आशा उत्पन्न करती है, तथा वैश्विक समुदाय के लाभ के लिए साझा प्राथमिकताओं को पूरा करती है।



प्रधानमंत्री और अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जोसेफ आर. बिडेन ने सितंबर 2024 में विलमिंगटन में छठे क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक की।

उच्च स्तरीय यात्राएं

प्रधानमंत्री ने छठे क्वाड लीडर्स समिट में भाग लेने के लिए 21-23 सितंबर को अमेरिका के विलमिंगटन, डेलावेयर की यात्रा की, जिसमें अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बाइडेन, जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीस शामिल थे। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री ने क्वाड लीडर्स समिट के दौरान तत्कालीन राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा आयोजित क्वाड कैंसर मूनशॉट कार्यक्रम में भी भाग लिया। यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की और तत्कालीन प्रधानमंत्री किशिदा और प्रधानमंत्री अल्बानीस के साथ अलग-अलग द्विपक्षीय बैठकें कीं। भारत-अमेरिका द्विपक्षीय वार्ता के दौरान, दोनों पक्षों ने भारत-अमेरिका औषधि नीति ढांचे से संबंधित समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान किया और भारत ने पिलर III (स्वच्छ अर्थव्यवस्था), पिलर IV (निष्पक्ष अर्थव्यवस्था) और व्यापक समझौते के तहत इंडो-पैसिफिक आर्थिक ढांचे (आईपीईएफ) करारों से संबंधित अनुसमर्थन दस्तावेज प्रस्तुत किए। दोनों पक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने, वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ावा देने, रक्षा सहयोग में विविधता लाने और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने के माध्यम से द्विपक्षीय संबंधों को और आगे बढ़ाने पर भी सहमत हुए। दोनों नेताओं ने अन्य परिणामों के अतिरिक्त सुरक्षित और संरक्षित वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए अमेरिका-भारत रोडमैप की घोषणा की।

22 सितंबर को प्रधानमंत्री ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) में आयोजित भविष्य सम्मेलन के शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र में अपना

मुख्य भाषण दिया। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) द्वारा संचालित टेक सीईओ राउंडटेबल में भी भाग लिया, जिसमें उन्होंने सेमीकंडक्टर, फार्मास्युटिकल और बायोटेक्नोलॉजी कंपनियों के सीईओ के साथ बातचीत की। इसके अतिरिक्त, उन्होंने लॉन्ग आइलैंड में भारतीय प्रवासियों के सदस्यों की एक बड़ी सभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने बोस्टन और लॉस एंजिल्स में क्रमशः दो वाणिज्य दूतावास खोलने के भारत सरकार के फैसले की घोषणा की।

18 नवंबर को, प्रधानमंत्री ने रियो डी जेनेरियो में जी-20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया और तत्कालीन राष्ट्रपति बाइडेन से संक्षिप्त मुलाकात की।

मंलिस्तरीय बैठकें और द्विपक्षीय वार्ता

रक्षा मंत्री ने 22-25 अगस्त को अमेरिका की चार दिवसीय यात्रा की। उन्होंने 23 अगस्त को तत्कालीन अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों पक्षों ने आपूर्ति सुरक्षा व्यवस्था (एसओएसए) और संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) जेक सुलिवन से भी मुलाकात की और अमेरिकी रक्षा उद्योग के नेताओं से बातचीत की। नवंबर में, रक्षा मंत्री ने लाओस में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस (एडीएमएम-प्लस) के दौरान तत्कालीन रक्षा सचिव ऑस्टिन से मुलाकात की।

विदेश मंत्री और तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पूरे वर्ष नियमित संपर्क में रहे। मंत्रियों ने 16 फरवरी को जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन (एमएससी) के मौके पर मुलाकात की। दोनों मंत्रियों ने 28 जुलाई को टोक्यो में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के मौके पर द्विपक्षीय बैठक भी की। विदेश मंत्री ने 30 सितंबर-01 अक्टूबर को वाशिंगटन डीसी की यात्रा की और तत्कालीन सचिव ब्लिंकन, तत्कालीन वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडो, तत्कालीन एनएसए जेक सुलिवन, उपराष्ट्रपति फिलिप गॉर्डन के तत्कालीन एनएसए के साथ-साथ अन्य राजनीतिक और प्रबुद्ध नेताओं के साथ चर्चा की।

विदेश मंत्री और विदेश सचिव ने दिसंबर में अमेरिका की यात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री ने तत्कालीन एनएसए सुलिवन, तत्कालीन विदेश मंत्री ब्लिंकन और वर्तमान एनएसए माइकल वाल्ट्ज सहित प्रमुख वार्ताकारों से मुलाकात की। इसके अतिरिक्त, विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की अंतरिम टीम के कई सदस्यों से मुलाकात की। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच निरंतर संवाद सुनिश्चित करना, आपसी मुद्दों को आगे बढ़ाना और संबंधों को मजबूत करना था।



विदेश मंत्री ने अक्टूबर 2024 में वाशिंगटन डीसी में तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने तत्कालीन ऊर्जा सचिव जेनिफर ग्रैनहोम के साथ भारत-अमेरिका रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी (एससीईपी) मंत्रिस्तरीय बैठक की सह-अध्यक्षता करने के लिए 16 सितंबर को वाशिंगटन डीसी की यात्रा की। बैठक के बाद, मंत्री ने 17-18 सितंबर को गैसटेक सम्मेलन में भाग लेने के लिए ह्यूस्टन, टेक्सास की यात्रा की।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (सीआईएम) ने 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक वाशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क की यात्रा की। उन्होंने 2 अक्टूबर को दूसरे पुनर्गठित भारत-अमेरिका सीईओ फोरम और 3 अक्टूबर को तत्कालीन अमेरिकी वाणिज्य सचिव रायमोंडो के साथ छठी भारत-अमेरिका वाणिज्यिक वार्ता की सह-अध्यक्षता की। मंत्री ने व्यापार नीति फोरम के तहत चल रहे सहयोग पर चर्चा करने और दोनों देशों के बीच दोतरफा व्यापार को और बढ़ाने के तरीकों पर विचार-विमर्श करने के लिए वाशिंगटन डीसी में तत्कालीन अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) राजदूत कैथरीन ताई से भी मुलाकात की। मंत्री की अमेरिका यात्रा के दौरान 'महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं का विस्तार और विविधता लाने' संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

वित्त और कॉर्पोरेट मामले मंत्री ने 20-26 अक्टूबर को वाशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क की यात्रा की। वाशिंगटन डीसी में, मंत्री महोदय ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ)-विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों में भाग लिया। उन्होंने यूनाइटेड किंगडम, स्विट्जरलैंड और जर्मनी के अपने समकक्षों के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें भी कीं; इसके अतिरिक्त विश्व बैंक (डब्ल्यूबी), एशियाई विकास बैंक (एडीबी), यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (ईवीआरडी) के प्रमुखों के साथ-साथ बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों के सीईओ के साथ वैयक्तिक बैठकें कीं। न्यूयॉर्क में, मंत्री महोदय ने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में आयोजित पेंशन फंड राउंडटेबल, ग्लोबल सॉवरेन डेट राउंडटेबल (जीएसडीआर) के साथ-साथ कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर (सीडीआरआई) और सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज (सीएसआईएस) द्वारा आयोजित चर्चाओं में भाग लिया। मंत्री ने व्हार्टन स्कूल, पेन्सिलवेनिया विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों के साथ भी बातचीत की।

तत्कालीन यूएसटीआर राजदूत कैथरीन ताई ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के साथ 14^{वें} भारत-अमेरिका व्यापार नीति फोरम की सह-अध्यक्षता करने के लिए 12 जनवरी को नई दिल्ली की यात्रा की। मंत्रियों ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में साझा प्राथमिकताओं पर एक साथ काम करने की अपनी इच्छा, लंबित द्विपक्षीय कृषि मुद्दों को सुलझाने की अपनी प्रतिबद्धता और अमेरिका और भारत के बीच व्यापार संबंधों को बढ़ाने के नए तरीकों पर चर्चा की। राजदूत ताई और सीआईएम ने सितंबर में नई दिल्ली में आयोजित भारत-संयुक्त राज्य व्यापार नीति फोरम (टीपीएफ) अंतर-संघीय बैठकों के दौरान सकारात्मक चर्चाओं का भी उल्लेख किया और द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को प्रभावित करने वाले अतिरिक्त मुद्दों के समाधान के लिए टीपीएफ को शीघ्रता से मंत्रिस्तरीय स्तर पर फिर से बुलाने पर सहमति व्यक्त की। सीआईएम ने डब्ल्यूटीओ के 13^{वें} मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के दौरान मार्च में अबू धाबी में राजदूत कैथरीन ताई से भी मुलाकात की।

प्रतिनिधि माइकल मैककॉल (आर-टेक्सास); स्पीकर एमेरिका नैन्सी पेलोसी (डी-सीए); प्रतिनिधि ग्रेगरी डब्ल्यू. मीक्स (डी-एनवाई); प्रतिनिधि जिम मैकगवर्न (डी-एमए); प्रतिनिधि एमी बेरा (डी-सीए); प्रतिनिधि मैरिएनेट मिलर-मीक्स (आर-आईए); और प्रतिनिधि निकोल मैलियोटाकिस (आर-एनवाई) सहित 7 सदस्यीय द्विदलीय अमेरिकी कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने 16-21 जून को भारत की यात्रा की। यात्रा के दौरान, कांग्रेस के



प्रतिनिधि अमी बेरा (डी-सीए), प्रतिनिधि माइकल मैककॉल (आर-टीएक्स), प्रतिनिधि मैरिपुनेट मिलर-मीक्स (आर-आईए) और स्पीकर एमेरिटा नैन्सी पेलोसी (डी-सीए) सहित सात सदस्यीय द्विदलीय अमेरिकी कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने जून 2024 में नई दिल्ली में प्रधान मंत्री से मुलाकात की।

प्रतिनिधिमंडल को प्रधानमंत्री से मिलने का अवसर मिला। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने प्रधानमंत्री को तीसरे लगातार ऐतिहासिक कार्यकाल के लिए उनके चुनाव पर बधाई दी। उन्होंने भारत में हाल ही में संपन्न दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक चुनाव अभ्यास के पैमाने, निष्पक्षता और पारदर्शिता के लिए गहरी प्रशंसा व्यक्त की। प्रतिनिधिमंडल ने भारत-अमेरिका संबंधों को सबसे महत्वपूर्ण बताया और व्यापार, नई और उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, लोगों के बीच आदान-प्रदान सहित सभी क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक

वैश्विक साझेदारी को और गहरा करने के लिए अपना दृढ़ समर्थन व्यक्त किया। प्रतिनिधिमंडल ने विदेश मंत्री के साथ भी बैठक की। विदेश मंत्री ने भारत-अमेरिका संबंधों को आगे बढ़ाने में अमेरिकी कांग्रेस के लगातार और द्विदलीय समर्थन द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला, जो साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, कानून के शासन के सम्मान और लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित हैं।



विदेश मंत्री ने जनवरी 2024 में नई दिल्ली में आयोजित 14^{वें} अमेरिकी व्यापार नीति फोरम के अवसर पर तत्कालीन अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत कैथरीन ताई से मुलाकात की।

तत्कालीन अमेरिकी एनएसए जेक सुलिवन ने 17 जून को महत्वपूर्ण और उभरती हुई प्रौद्योगिकी (आईसीईटी) पर भारत-अमेरिका पहल की वार्षिक समीक्षा बैठक के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मिलने के लिए भारत की यात्रा की। नेताओं ने अंतरिक्ष, सेमी कंडक्टर, उन्नत दूरसंचार, एआई, क्वांटम, एसटीईएम, जैव प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिजों और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग को गहरा करने और विस्तारित करने की दिशा में भारत और अमेरिका द्वारा की गई महत्वपूर्ण प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने दोनों देशों के बीच गहन प्रौद्योगिकी सहयोग सहित क्षेत्रों में अपार अप्रयुक्त क्षमता को भी मान्यता दी।

भारत की अन्य यात्राओं में 18-20 फरवरी और 17-22 अगस्त को तत्कालीन प्रबंधन एवं संसाधन उप-सचिव रिचर्ड वर्मा, 17-18 जून को तत्कालीन विदेश उप-सचिव कर्ट कैम्बेल, 21-23 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय जलवायु नीति के लिए राष्ट्रपति के वरिष्ठ सलाहकार जॉन पोडेस्टा, 21-23 अगस्त को तत्कालीन ऊर्जा उप-सचिव डेविड टर्क तथा जुलाई में अमेरिकी राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन (एनएसएफ) के निदेशक सेतुरामन पंचनाथन की यात्राएं शामिल थी।

विदेश सचिव ने 09-14 अप्रैल को वाशिंगटन डीसी की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने तत्कालीन उप विदेश मंत्री कर्ट कैम्बेल, तत्कालीन प्रबंधन एवं संसाधन उप विदेश मंत्री रिचर्ड वर्मा, तत्कालीन वाणिज्य उप सचिव डॉन ग्रेक्स, तत्कालीन ऊर्जा उप सचिव डेविड तुर्क, तत्कालीन रक्षा उप सचिव कैथलीन हिक्स, तत्कालीन प्रधान उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार

(पीडीएनएसए) जॉन फाइनर, तत्कालीन अवर विदेश मंत्री उजरा जेया आदि से मुलाकात की।

विदेश सचिव ने 24-27 सितंबर को वाशिंगटन डीसी की यात्रा की और तत्कालीन उप विदेश मंत्री कैम्बेल, तत्कालीन प्रबंधन एवं संसाधन उप विदेश मंत्री वर्मा, तत्कालीन रक्षा उप सचिव हिक्स, तत्कालीन पीडीएनएसए फाइनर, तत्कालीन कार्यवाहक उप गृह सुरक्षा मंत्री क्रिस्टी कैनेगैलो से मुलाकात की तथा वाशिंगटन डीसी स्थित प्रबुद्ध मंडलों के साथ बातचीत की। 23-28 दिसंबर को वाशिंगटन डीसी की अपनी यात्रा के दौरान विदेश सचिव ने तत्कालीन उप विदेश मंत्री कैम्बेल, तत्कालीन पीडीएनएसए फाइनर और तत्कालीन प्रबंधन उप सचिव वर्मा से मुलाकात की तथा आपसी हितों के क्षेत्रों पर चर्चा की।

अफ्रीका पर भारत-अमेरिका वार्ता का दूसरा दौर 14-15 मई को वाशिंगटन डीसी में आयोजित किया गया। इस वार्ता का उद्देश्य विचारों और दृष्टिकोणों को साझा करना तथा अफ्रीका में साथ मिलकर काम करने के लिए संस्थागत, तकनीकी और द्विपक्षीय तालमेल विकसित करने के तरीकों की खोज करना था। इस वार्ता ने अफ्रीका में विकास परियोजनाओं और सहयोग के कार्यक्रमों की पहचान करने में भी मदद की, जिससे अफ्रीकी प्राथमिकताओं के अनुसार भारत और अमेरिका की ताकत का लाभ उठाया जा सके। भारत की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ (एयू) को जी-20 के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किए जाने के बाद, यह भारत और अमेरिका के बीच अफ्रीका पर पहली ऐसी वार्ता थी। इसके अतिरिक्त, तत्कालीन लघु



अमेरिका में भारत के राजदूत और विदेश सचिव ने दिसंबर 2024 में वाशिंगटन डीसी में तत्कालीन उप विदेश मंत्री कर्ट कैम्बेल और तत्कालीन प्रबंधन उप मंत्री रिचर्ड वर्मा से मुलाकात की।

व्यवसाय प्रशासन (एसबीए) प्रशासक इसाबेल कैसिलास गुज़मैन ने 13 अगस्त को भारत का दौरा किया और एमएसएमई सचिव के साथ छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

रक्षा सहयोग

भारत और अमेरिका के बीच व्यापक और दूरदर्शी रक्षा साझेदारी है, जिसमें उच्च स्तरीय सहभागिता, नीतिगत वार्ता, रक्षा खरीद, सह-उत्पादन और सह-विकास, संयुक्त सैन्य अभ्यास और क्षमता निर्माण शामिल हैं।

21 सितंबर को प्रधानमंत्री और अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जोसेफ आर. बाइडेन ने विलमिंगटन में द्विपक्षीय बैठक की, जिसमें अमेरिका-भारत रक्षा औद्योगिक सहयोग रोडमैप के तहत उल्लेखनीय प्रगति को मान्यता दी गई, जिसमें जेट इंजन, युद्ध सामग्री और ग्राउंड मोबिलिटी सिस्टम के लिए प्राथमिकता वाली सह-उत्पादन व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए चल रहे सहयोग शामिल हैं। नेताओं ने रक्षा औद्योगिक साझेदारी का विस्तार करने के प्रयासों का भी स्वागत किया और रक्षा वस्तुओं और सेवाओं की पारस्परिक आपूर्ति को और सक्षम बनाने के लिए भारत और अमेरिका की संबंधित रक्षा खरीद प्रणालियों को संरेखित करने पर चल रही चर्चाओं को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।

नेताओं ने लॉकहीड मार्टिन और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड के बीच सी-130जे सुपर हरक्यूलिस विमान पर टीमिंग समझौते की भी सराहना की, भारत-अमेरिका रक्षा त्वरण पारिस्थितिकी तंत्र (इंडस-एक्स) पहल द्वारा सरकारों, व्यवसायों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच बढ़ते रक्षा नवाचार सहयोग की सराहना की और रक्षा मंत्रालय (एमओडी) के रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (आईडीईएक्स) और अमेरिकी रक्षा विभाग (यूएस डीओडी) की रक्षा नवाचार इकाई (डीआईयू) के बीच बढ़े हुए सहयोग का स्वागत किया, जिसे 09-10 सितंबर को सिलिकॉन वैली शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के माध्यम से सुगम बनाया गया।

प्रधानमंत्री और तत्कालीन राष्ट्रपति बाइडेन ने राष्ट्रीय सुरक्षा, अगली पीढ़ी के दूरसंचार और हरित ऊर्जा अनुप्रयोगों के लिए उन्नत संवेदन, संचार और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पर केंद्रित एक नया सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण व्यवस्था की भी सराहना की। इन्फ्रारेड, गैलियम नाइट्राइड और सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर के निर्माण के उद्देश्य से स्थापित इस फैब को भारत सेमीकंडक्टर मिशन के समर्थन के साथ-साथ भारत सेमी, तीसरा आईटेक और यूएस स्पेस फोर्स के बीच रणनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदारी से भी बल मिलेगा।

अगस्त में रक्षा मंत्री की अमेरिका यात्रा के दौरान दो प्रमुख द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए - आपूर्ति व्यवस्था की सुरक्षा (एसओएसए) और अमेरिकी कमांडों में संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में समझौता ज्ञापन। यात्रा के बाद, सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीएस) ने अक्टूबर में अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स से 31 एमक्यू-9बी प्रोड्यूसर ड्रोन के अधिग्रहण को मंजूरी दी।



अमेरिकी इंडो-पैसिफिक कमांड (यूएस इंडोपैकोम) के तत्कालीन कमांडर एडमिरल जॉन सी. एक्विलिनो ने फरवरी 2024 में नई दिल्ली में आयोजित भारत-अमेरिका रक्षा त्वरण पारिस्थितिकी तंत्र (इंडस-एक्स) शिखर सम्मेलन के दौरान विदेश मंत्री से मुलाकात की।

फरवरी में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ (सीओएएस) ने अमेरिका की यात्रा की और वाशिंगटन डीसी तथा सैन फ्रांसिस्को में बैठकें कीं। तत्कालीन यूएस इंडोपैकोम कमांडर एडमिरल जॉन सी. एक्विलिनो ने फरवरी में भारत की यात्रा की और अपने समकक्षों, वरिष्ठ भारतीय अधिकारियों के साथ बातचीत की तथा रायसीना वार्ता में भाग लिया। तत्कालीन यूएस कमांडर साइबर कमांड जनरल टिमोथी डी. हॉग ने मई में द्विपक्षीय बातचीत के लिए भारत की यात्रा की।

सेना, वायुसेना और नौसेना के लिए कार्यकारी संचालन समूह की बैठकें क्रमशः अप्रैल (नई दिल्ली), मई (हवाई) और सितंबर (नई दिल्ली) में आयोजित की गईं, ताकि सैन्य-से-सैन्य सहयोग को और गहरा किया जा सके। भारत-अमेरिका एडवांस्ड डोमेन डिफेंस वार्ता मई में वाशिंगटन डीसी में आयोजित किया गया था, जबकि कमांड एंड कंट्रोल कम्पेटिबिलिटी बोर्ड (सीसीसीबी) की बैठकें क्रमशः जून (नई दिल्ली) और दिसंबर (हवाई) में आयोजित की गईं।

विदेश एवं रक्षा मंत्रालयों तथा अमेरिकी विदेश एवं रक्षा विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की अगुवाई में द्विपक्षीय 2+2 अंतर-सत्रीय बैठक 16 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित की गई।

भारत-अमेरिका संयुक्त प्रौद्योगिकी समूह (जेटीजी) की 23^{वाँ} बैठक, जिसकी सह-अध्यक्षता अमेरिकी रक्षा अनुसंधान एवं इंजीनियरिंग अंडर सेक्रेटरी कार्यालय (ओयूएसडी) और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा की गई, अक्टूबर माह में वाशिंगटन डी.सी. में आयोजित की गई।



औद्योगिक आधार नीति के लिए अमेरिकी प्रधान उप सहायक रक्षा सचिव विक रामदास और रक्षा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक (अधिग्रहण) ने अगस्त 2024 में वाशिंगटन डीसी में आपूर्ति सुरक्षा व्यवस्था (एसओएसए) पर हस्ताक्षर किए।

भारत-अमेरिका सैन्य सहयोग समूह (एमसीजी) की 21^{वीं} बैठक नवंबर में नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस बैठक की सह-अध्यक्षता एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख और अमेरिकी इंडो-पैसिफिक कमांड के डिप्टी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जोशुआ एम. रुड ने की।

इस वर्ष भारत और अमेरिका ने कई संयुक्त रक्षा अभ्यास किए। भारतीय नौसेना ने जनवरी में गुआम में आयोजित अमेरिकी नेतृत्व वाले बहुपक्षीय अभ्यास 'सी ड्रैगन' और फरवरी में सेशेल्स में आयोजित कटलैस एक्सप्रेस 2024 में भाग लिया। अमेरिकी प्रशांत बेड़े ने फरवरी में विशाखापत्तनम में आयोजित भारत के नेतृत्व वाले बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2024 में भाग लिया।

मार्च में तीनों सेनाओं का जल-थल-स्थल अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ आईएनएस जलाश्व पर आयोजित किया गया था। उसी महीने के दौरान, भारतीय तटरक्षक बल और अमेरिकी तटरक्षक बल ने पोर्ट ब्लेयर में एक व्यापक समुद्री सुरक्षा अभ्यास 'सी डिफेंडर्स 2024' आयोजित किया।

अप्रैल में संयुक्त टास्क फोर्स 150 के हिस्से के रूप में समुद्री सुरक्षा संचालन के लिए भारतीय नौसेना के पोतों को पश्चिमी अरब सागर में तैनात किया गया था। भारतीय नौसेना ने 27 जून से 01 अगस्त तक हवाई में आयोजित अमेरिका के नेतृत्व वाले अभ्यास 'रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज' (रिमपैक) में भी भाग लिया। जून में, भारतीय वायु सेना (आईएएफ) ने

अलास्का में अभ्यास रेड फ्लैग में भाग लिया। भारतीय नौसेना के पोतों ने जुलाई में अरब सागर में अमेरिकी नौसेना कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास (एमपीएक्स) में भाग लिया।

सितंबर में, राजस्थान में युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया था, जिसमें सैन्य शक्ति और उपकरणों के संदर्भ में संयुक्त अभ्यास के दायरे और विशेषज्ञता में उल्लेखनीय वृद्धि की गई थी। अक्टूबर में विशाखापत्तनम में मालाबार अभ्यास का 28^{वां} संस्करण आयोजित किया गया था, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के निर्देशित मिसाइल विध्वंसक, बहुउद्देश्यीय फ्रिगेट, पनडुब्बियां, फिक्स्ड विंग एमआर, लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टरों ने भाग लिया था। विशेष बल अभ्यास 'वज्र प्रहार' का 15^{वां} संस्करण नवंबर में अमेरिका के इडाहो में आयोजित किया गया था। भारतीय नौसेना मरीन कमांडो फोर्स (माकोस) और अमेरिकी नौसेना समुद्र, वायु और भूमि टीमों (सील) द्वारा आयोजित अभ्यास संगम का 9^{वां} संस्करण नवंबर में गोवा में आयोजित किया गया था।

एक वाणिज्यिक अनुबंध के तहत, अमेरिकी सैन्य समुद्री परिवहन कमान (एमएससी) जहाज यूएसएनएस चार्ल्स डू की 23 सितंबर से 12 नवंबर तक कट्टपल्ली स्थित एलएंडटी शिपयार्ड में मरम्मत की गई।

व्यापार और आर्थिक सहयोग

कैलेंडर वर्ष 2023-24 के लिए, माल और सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार 190 बिलियन अमेरिकी डॉलर दर्ज किया गया है। भारत ने अमेरिका को 120.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात किया, जबकि इसका आयात 70.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापारिक संबंधों को ऊर्जा, रक्षा, विनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे उद्योगों में तेजी से वृद्धि द्वारा आगे बढ़ाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र, विशेष रूप से मोबाइल फोन और सौर पैनल, समुद्री उत्पाद और फार्मास्यूटिकल्स में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। दोनों देशों की अपनी-अपनी ताकत का लाभ उठाते हुए, यह आर्थिक संबंध सतत विकास, नवाचार और आपसी समृद्धि के लिए आधारशिला बना हुआ है।

निवेश के मोर्चे पर, भारत और अमेरिका के बीच दोतरफा निवेश के साथ उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अमेरिका भारत में तीसरा सबसे बड़ा निवेशक है, जिसका अप्रैल 2000 से मार्च तक एफडीआई निवेश 65.19 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। अनुमान के मुताबिक, भारत में 2000 से अधिक अमेरिकी कंपनियां हैं।

7^{वां} भारत-अमेरिका विमानन शिखर सम्मेलन 24-26 जून को वाशिंगटन डीसी में आयोजित हुआ। इसमें हवाई क्षेत्र की क्षमता, कार्गो और सुरक्षा से लेकर प्रौद्योगिकी में उन्नति तक के विषयों पर समर्पित सत्रों के साथ, शिखर सम्मेलन ने नागरिक विमानन पर अमेरिकी और भारतीय विशेषज्ञों के बीच संवाद को सुगम बनाया गया और भारत की प्रमुख विमानन और हवाई अड्डा परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए उन्नत अमेरिकी प्रौद्योगिकी, उपकरण, सेवाओं और सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रदर्शन किया गया।



अमेरिकी तटरक्षक कटर (यूएससीजीएस) बर्थॉल्फ (सामने) और भारतीय तटरक्षक (आईसीजी) के अपतटीय गश्ती पोत सीजीएस शौर्य (पीछे) ने मार्च 2024 में पोर्ट ब्लेयर में द्विपक्षीय अभ्यास सी डिफेंडर्स के एक भाग के रूप में संयुक्त अभ्यास किया।



भारतीय और अमेरिकी सैनिकों ने सितंबर 2024 में राजस्थान में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास 'युद्ध अभ्यास' के 20^{वें} संस्करण में भाग लिया।

ऊर्जा एवं जलवायु सहयोग

प्रधानमंत्री और तत्कालीन राष्ट्रपति बाइडेन ने सितंबर में अमेरिका की अपनी यात्रा के दौरान सुरक्षित और संरक्षित वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए भारत-अमेरिका रोडमैप की घोषणा की। रोडमैप ने भारत और अमेरिका में स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और घटकों के विनिर्माण द्वारा समर्थित सुरक्षित और संरक्षित स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं के विस्तार में तेजी लाने के लिए एक नई पहल शुरू की। इस पहल के तहत, दोनों देश प्रारंभिक चरण में 1 बिलियन अमरीकी डालर के बहुपक्षीय वित्तपोषण को अनलॉक करने के लिए मिलकर काम करेंगे, ताकि अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा भंडारण, पावर ग्रिड और ट्रांसमिशन प्रौद्योगिकियों, उच्च दक्षता वाले शीतलन प्रणालियों, शून्य उत्सर्जन वाहनों और अन्य उभरती हुई स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के लिए स्वच्छ ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में परियोजनाओं का समर्थन किया जा सके।

22 अगस्त को नई दिल्ली में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव और तत्कालीन अमेरिकी ऊर्जा विभाग के उप सचिव डेविड तुर्क की संयुक्त अध्यक्षता में नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी कार्य मंच (आरईटीएपी) की संचालन समिति की बैठक आयोजित की गई। दोनों देश भारत में हाइड्रोजन सुरक्षा के लिए एक नया राष्ट्रीय केंद्र स्थापित करने पर भी सहयोग कर रहे हैं।

अंतरिक्ष, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा आईटी सहयोग

इसरो और नासा ने अंतरिक्ष अन्वेषण में अपनी साझेदारी को गहरा करने और 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक संयुक्त प्रयास शुरू करने के लिए जनवरी में एक संयुक्त आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसके अतिरिक्त, दोनों संगठनों ने मार्च में मानव अंतरिक्ष उड़ान में सहयोग के लिए रणनीतिक ढांचे के लिए एक कार्यन्वयन व्यवस्था (आईए) पर हस्ताक्षर किए। आईए रोबोटिक और मानव अंतरिक्ष उड़ान गतिविधियों, जमीन आधारित अनुसंधान, कर्मियों के आदान-प्रदान, उन्नत प्रशिक्षण, प्रणालियों और मानकों की अंतर-संचालन क्षमता और प्रौद्योगिकियों पर सहयोग में संभावित भागीदारी के प्रति जिम्मेदारियों की पहचान करता है। अगस्त में, दो भारतीय अंतरिक्ष यानों ने नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर में प्रशिक्षण शुरू किया।

इसरो द्वारा निर्मित न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) का भारत का उच्च श्रृंखला संचार उपग्रह जीसैट-एन2 (जीएसएटी-20), 19 नवंबर को अमेरिका के केप कैनावेरल से फाल्कन-9 द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया।

प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने वाशिंगटन डी.सी. में स्टेट डिपार्टमेंट में आयोजित क्वांटम समन्वय तंत्र पर दूसरी द्विपक्षीय बैठक में भाग लेने के लिए 25 अगस्त-01 सितंबर को अमेरिका का दौरा किया। उन्होंने राष्ट्रीय मानक और प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएसटी), शिकागो क्वांटम एक्सचेंज और लॉरेंस बर्कले विश्वविद्यालय का भी दौरा किया और शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों के साथ बैठकें कीं।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव ने 08-13 जनवरी को अमेरिका की यात्रा की। उन्होंने हवाई के हिलो में टीएमटी इंटरनेशनल टीम के साथ एक बहुराष्ट्रीय सहयोगात्मक खगोलीय परियोजना यानी 30 मीटर दूरबीन को आगे बढ़ाने के लिए चर्चा की; और एनएसएफ के निदेशक डॉ. सेथुरमन पंचनाथन सहित प्रमुख अधिकारियों से मुलाकात की।

पृथ्वी विज्ञान सचिव ने 06-07 मार्च को अमेरिका की यात्रा की। उन्होंने नौसेना अनुसंधान कार्यालय (ओएनआर) के प्रमुख, राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय एजेंसी (एनओए) के तत्कालीन प्रशासक डॉ. रिचर्ड स्पिनरैड और एनएसएफ निदेशक डॉ. पंचनाथन के साथ चर्चा की।

जून में, एनएसएफ निदेशक डॉ. पंचनाथन ने आईसीईटी की पहली वार्षिक समीक्षा बैठक के लिए भारत की यात्रा की और अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एएनआरएफ) के साथ समझौता ज्ञापन के संबंध में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव के साथ बैठकें कीं। उन्होंने एनएसएफ के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की संभावना तलाशने और एनएसएफ के साथ नए आईए के तहत सहयोगी अनुसंधान के लिए चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए सचिव, एमईआईटीवाई; सचिव, खनन; सचिव, जैव प्रौद्योगिकी विभाग और सचिव, पृथ्वी विज्ञान के साथ अलग-अलग बैठकें भी कीं।

17 अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजित भारत-अमेरिका सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कार्य समूह की बैठक की सह-अध्यक्षता एमईआईटीवाई सचिव ने की। इस बैठक में अंतर्राष्ट्रीय संचार एवं सूचना नीति के लिए अमेरिकी समन्वयक राजदूत स्टीव लैंग भी शामिल थे। दोनों पक्षों ने डिजिटल और दूरसंचार क्षेत्रों में साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई और आवाजाही, डेटा प्रवाह, सीमा पार भुगतान और रिपोर्टिंग (सीबीपीआर), एआई, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण और दूरसंचार क्षेत्र में चल रहे सहयोग पर चर्चा की।

महत्वपूर्ण और उभरती हुई प्रौद्योगिकी पर अमेरिका-भारत पहल (आईसीईटी)

तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एपीएनएसए) जेक सुलिवन ने 17 जून को आईसीईटी समीक्षा बैठक की सह-अध्यक्षता करने के लिए नई दिल्ली की यात्रा की। यात्रा के दौरान, उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और अन्य लोगों के अतिरिक्त विदेश मंत्री और एनएसए से भी मुलाकात की। यात्रा के दौरान आईसीईटी की समीक्षा बैठक की सह-अध्यक्षता एनएसए और तत्कालीन एपीएनएसए सुलिवन ने की। उन्होंने अंतरिक्ष, सेमी कंडक्टर, उन्नत दूरसंचार, एआई, क्वांटम, एसटीईएम, जैव प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिजों और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग को गहरा करने और विस्तारित करने की दिशा में भारत और अमेरिका द्वारा की गई महत्वपूर्ण प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने दोनों देशों के बीच गहन प्रौद्योगिकी सहयोग सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपार अग्रयुक्त क्षमता को भी पहचाना। इस अवसर पर आईसीईटी पर एक संयुक्त भारत-अमेरिका तथ्य पत्रक जारी किया गया।



तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने जून 2024 में नई दिल्ली में आयोजित आईसीईटी समीक्षा बैठक के दौरान प्रधानमंत्री से मुलाकात की।

जी2जी आईसीईटी बैठक के अतिरिक्त, एनएसए और तत्कालीन एपीएनएसए सुलिवन ने सीआईआई के माध्यम से 18 जून को एक उद्योग गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें दोनों देशों के उद्योग जगत के अग्रणी लोगों को एक साथ लाया गया, क्योंकि भारत और अमेरिका रणनीतिक प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के निवेश और भागीदारी को बढ़ाना चाहते हैं। अमेरिकी उद्योग का प्रतिनिधित्व थायर महन, जनरल एटॉमिक्स, जेह एयरोस्पेस, होल्टेक, कर्मिस, एल्सीम एनर्जी और एक्सिओम स्पेस जैसी कंपनियों ने किया। दूसरी ओर, भारतीय उद्योगों में तृतीय आईटेक, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल), भारत फोर्ज, भारती एयरटेल, भुखनवाला इंडस्ट्रीज, सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स, लार्सन एंड टूब्रो (एलएंडटी), टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स, टाटा पावर और तेजस नेटवर्क के उद्योगपति शामिल थे। उद्योगों ने दोनों एनएसए को अपने द्विपक्षीय सहयोग, सहयोग को आगे बढ़ाने के तरीके के बारे में अपने दृष्टिकोण, साथ ही उन विशिष्ट क्षेत्रों के बारे में अपने अब तक के अनुभवों से अवगत कराया, जहां सरकारी सुविधा आगे के सहयोग को बढ़ाने में बाधाओं को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

14 नवंबर को, भारत के सरकारी और उद्योग प्रतिनिधियों तथा अमेरिका के सरकारी अधिकारियों ने नई दिल्ली में आयोजित आईसीईटी एडवांस्ड मैटेरियल्स आरएंडडी फोरम के अंतर्गत प्रथम ट्रेक 1.5 संवाद में भाग लिया।

स्वास्थ्य सहयोग

भारत के जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने 05-06 अगस्त को नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी में भारत-अमेरिका कैंसर संवाद की मेजबानी की। इस संवाद ने एआई-सक्षम निदान और नवाचार, नवीन चिकित्सा, लागत-प्रभावी उपचार और उत्तरजीविता देखभाल सहित विभिन्न क्षेत्रों में कैंसर अनुसंधान सहयोग में एक महत्वपूर्ण प्रगति को चिह्नित किया।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) और अमेरिकी राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान, आयुष मंत्रालय और अमेरिकी स्वास्थ्य एवं मानव सेवा विभाग के साथ-साथ वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) और अमेरिकी शैक्षणिक संस्थानों के बीच कई सहयोगात्मक कार्यक्रम चल रहे हैं।

मादक पदार्थ निरोधक सहयोग

भारत-अमेरिका काउंटर नारकोटिक्स वर्किंग ग्रुप की 5^{वाँ} बैठक 23-24 अक्टूबर को नई दिल्ली में हुई, जिसकी सह-अध्यक्षता तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति कार्यालय के निदेशक डॉ. राहुल गुप्ता और भारत के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के महानिदेशक ने की। यह चर्चा भारत-अमेरिका ड्रग पॉलिसी फ्रेमवर्क के तीन प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित थी, अर्थात्- प्रीकर्सर केमिकल्स सहित अवैध ड्रग उत्पादन और तस्करी का मुकाबला करना, एक स्थायी सार्वजनिक स्वास्थ्य साझेदारी को आगे बढ़ाना और एक सुरक्षित एवं आगे बढ़ती दवा आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करना।

सुरक्षा एवं आतंकवाद-रोध सहयोग

तत्कालीन गृह सचिव और अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग की कार्यवाहक उप सचिव क्रिस्टी कैनेगेलो ने 27 फरवरी को नई दिल्ली में भारत-अमेरिका गृह सुरक्षा वार्ता के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की सह-अध्यक्षता की।

अमेरिका-भारत जेडब्ल्यूजी-सीटी की 20^{वाँ} बैठक और छठी डेजिग्रेसन वार्ता 5 मार्च को वाशिंगटन डीसी में आयोजित की गई।

शिक्षा, सांस्कृतिक सहयोग और लोगों के बीच आदान-प्रदान

अमेरिका में भारतीय प्रवासियों की संख्या वर्तमान में 4.4 मिलियन है। 22 सितंबर को प्रधानमंत्री ने न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में भारतीय समुदाय के एक बड़े समूह को संबोधित किया, जिसमें बोस्टन और लॉस एंजिल्स में दो नए भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की योजना की घोषणा की गई, साथ ही ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में तमिल अध्ययन के लिए तिरुवल्लुवर पीठ की भी घोषणा की गई। सिएटल में भारतीय वाणिज्य दूतावास, जो 2023 में खोला गया, ने 12 जुलाई को सिएटल और बेलोव्यू, वाशिंगटन डीसी में दो वीज़ा आवेदन केंद्र (आईवीसी) खोले।

11^{वाँ} भारत-अमेरिका कौंसली वार्ता, जिसकी सह-अध्यक्षता तत्कालीन अमेरिकी कौंसली मामलों की सहायक विदेश मंत्री रेना बिटर और संयुक्त सचिव (सीपीवी) ने की, 23 फरवरी को नई दिल्ली में आयोजित की गई, जिसमें कमजोर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए सहयोग, अंतर-

देशीय दत्तकग्रहण, प्रवासी नागरिकों को कौशल सेवाओं का प्रावधान, प्रत्यर्पण और यात्रा की सुविधा सहित आपसी हित के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

इस वर्ष, भारत और अमेरिका ने शिक्षा के क्षेत्र में अपने मजबूत द्विपक्षीय आदान-प्रदान को जारी रखा। वर्तमान में 360,000 से अधिक भारतीय छात्र अमेरिकी उच्च शिक्षण संस्थानों (एचईआई) में कार्यक्रमों में अध्ययन कर रहे हैं।

शिक्षा और कौशल विकास पर भारत-अमेरिका कार्य समूह की दूसरी बैठक फरवरी में आयोजित की गई थी, जो शिक्षा और कौशल विकास क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसमें चार उप-समितियों का गठन किया गया था, जो निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान देंगी - अमेरिकी और भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच तालमेल, निजी क्षेत्र के साथ जुड़ाव, कौशल और व्यावसायिक शिक्षा, तथा प्रमाणन एवं मान्यता।

नवंबर में, पड़र्यू विश्वविद्यालय ने भारत में शिक्षा और सहभागिता के लिए अपने केंद्र की स्थापना की घोषणा की, साथ ही सेमीकंडक्टर में यूएस-इंडिया उत्कृष्टता केंद्र (सीईएस) की भी स्थापना की। इन केंद्रों की स्थापना भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), हैदराबाद के सहयोग से की गई है और इन्हें अमेरिका और भारत सरकार का समर्थन प्राप्त है।

संस्कृति के मोर्चे पर, दोनों देशों ने 26 जुलाई को भारत से अमेरिका में प्राचीन वस्तुओं की अवैध तस्करी को रोकने और उस पर अंकुश लगाने के लिए पहले सांस्कृतिक संपत्ति करार पर हस्ताक्षर किए। सितंबर में प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के दौरान, अमेरिका ने भारत से चुराई गई या तस्करी की गई 297 प्राचीन वस्तुओं की वापसी में मदद की।

समझौता ज्ञापन/करार

- स्वच्छ अर्थव्यवस्था, निष्पक्ष अर्थव्यवस्था पर इंडो-पैसिफिक आर्थिक रूपरेखा (आईपीईएफ) करार और व्यापक करार।
- महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं के विस्तार और विविधता के लिए समझौता ज्ञापन
- आपूर्ति सुरक्षा व्यवस्था (एसओएसए)
- भारत और अमेरिका के बीच संपर्क अधिकारियों की तैनाती के संबंध में समझौता ज्ञापन
- सांस्कृतिक संपत्ति करार (भारत की पुरातात्विक और नृवंशविज्ञान सामग्री की श्रेणियों पर आयात प्रतिबंध लगाने के संबंध में अमेरिकी सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच करार)
- लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन

क्वाड संपर्क

भारत और अमेरिका ने पूरे वर्ष क्वाड के ढांचे के तहत अपने उच्च स्तरीय संपर्क और कार्य समूह की बैठकें जारी रखीं। 21 सितंबर को विलमिंगटन में आयोजित छठे क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन के दौरान, नेताओं ने भू-राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की, पिछले एक वर्ष में क्वाड द्वारा की गई प्रगति का आकलन किया और आने वाले वर्ष के लिए एक महत्वाकांक्षी एजेंडा निर्धारित किया, जिसका समापन 2025 में भारत द्वारा क्वाड समिट की मेजबानी के साथ होगा। विलमिंगटन शिखर सम्मेलन में, नेताओं ने चार दस्तावेजों को अंगीकार किया - 'विलमिंगटन घोषणा', क्वाड संयुक्त वक्तव्य फैक्टशीट, क्वाड कैसर मूनशॉट फैक्टशीट और डिजिटल सार्वजनिक अवसरचना (डीपीआई) के विकास और परिनियोजन के लिए क्वाड सिद्धांत।



विदेश मंत्री ने जुलाई 2024 में टोक्यो में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया।

शिखर सम्मेलन के दौरान हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण पहलों की घोषणा की गई, जिसमें इंडो-पैसिफिक में रोगियों और उनके परिवारों पर सर्वाइकल कैंसर के प्रभाव को रोकने, पता लगाने, इलाज करने और कम करने के लिए अभिनव रणनीतियों को लागू करने हेतु क्राइड कैंसर मूनशॉट पहल; इंडो-पैसिफिक भागीदारों को इंडो-पैसिफिक समुद्री क्षेत्र जागरूकता (आईपीएमडीए) और अन्य क्राइड भागीदार पहलों के माध्यम से प्रदान किए गए साधनों के अधिकतम उपयोग के लिए इंडो-पैसिफिक में प्रशिक्षण के लिए समुद्री पहल (मैली), अपने जल की निगरानी और सुरक्षा करने, कानूनों को लागू करने और गैरकानूनी व्यवहार को रोकने में सक्षम बनाना शामिल है।

शिखर सम्मेलन में तटरक्षक बल की अंतर-संचालनीयता में सुधार लाने और समुद्री सुरक्षा को आगे बढ़ाने के लिए क्राइड-एट-सी शिप ऑब्जरवर मिशन जैसी पहलों की घोषणा भी हुई; प्राकृतिक आपदाओं के लिए नागरिक प्रतिक्रिया में सहायता करने के लिए चार देशों के बीच साझा एयरलिफ्ट क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए क्राइड इंडो-पैसिफिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क पायलट परियोजना; टिकाऊ और लचीले बंदरगाह बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन करने के लिए क्राइड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप; उच्च दक्षता वाली किफायती शीतलन प्रणालियों की तैनाती और विनिर्माण के माध्यम से ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए क्राइड प्रयास; इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति; चरम मौसम की घटनाओं और जलवायु प्रभावों की निगरानी में सहायता के लिए मॉरीशस के लिए अंतरिक्ष-आधारित वेब पोर्टल और साथ ही इंडो-पैसिफिक देशों में 2 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य की ऑफ-ग्रिड सौर परियोजनाएं।

नेताओं के शिखर सम्मेलन से पहले, क्राइड विदेश मंत्रियों ने 29 जुलाई को टोक्यो में आयोजित क्राइड विदेश मंत्रियों की बैठक (क्यूएफएमएम) में भाग लिया और क्राइड पहलों और कार्य समूहों की प्रगति की समीक्षा की। मंत्रियों ने सार्वजनिक वस्तुओं की डिलीवरी के माध्यम से क्षेत्र की समकालीन प्राथमिकताओं को संबोधित करके एक स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र के साझा दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों और भविष्य के सहयोग पर चर्चा की। इस अवसर पर एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया।

समृद्धि के लिए हिंद-प्रशांत आर्थिक ढांचा (आईपीईएफ)

समृद्धि के लिए हिंद-प्रशांत आर्थिक ढांचा (आईपीईएफ) 2024 की पहली मंत्रिस्तरीय बैठक 14 मार्च को बैकॉक में हुई। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री और तत्कालीन अमेरिकी वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडो इस बैठक में वर्चुअल रूप से शामिल हुईं। 2024 की दूसरी आईपीईएफ मंत्रिस्तरीय बैठक 05-06 जून को सिंगापुर में हुई। वाणिज्य सचिव और तत्कालीन अमेरिकी वाणिज्य सचिव रायमोंडो ने व्यक्तिगत रूप से बैठक में भाग लिया।

सितंबर में प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा से पहले, भारत ने आईपीईएफ से संबंधित तीन करारों पर हस्ताक्षर किए थे, जो आईपीईएफ स्तंभ III (स्वच्छ अर्थव्यवस्था), आईपीईएफ स्तंभ IV (निष्पक्ष अर्थव्यवस्था) और आईपीईएफ व्यापक करार पर आधारित थे। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने 24 सितंबर को आयोजित आईपीईएफ की वर्चुअल मंत्रिस्तरीय बैठक

में भाग लिया। मंत्री ने अन्य आईपीईएफ मंत्रियों के साथ मिलकर 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर और 11 अक्टूबर को क्रमशः स्वच्छ अर्थव्यवस्था करार, निष्पक्ष अर्थव्यवस्था करार और आईपीईएफ पर व्यापक करार के लागू होने का स्वागत किया और चल रहे सहयोग के माध्यम से आईपीईएफ करारों के तहत आर्थिक सहयोग को और गहरा करने और ठोस लाभ प्रदान करने के महत्वपूर्ण अवसरों पर जोर दिया।

कनाडा

भारत-कनाडा संबंध पारंपरिक रूप से लोगों से लोगों के प्रगाढ़ संबंधों और मजबूत आर्थिक संबंधों पर आधारित हैं।

प्रधानमंत्री ने 14 जून को इटली के अपुलिया में जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से संक्षिप्त मुलाकात की।

आपसी समझ, एक-दूसरे की चिंताओं के प्रति सम्मान, साथ ही कनाडा सरकार का भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के प्रति अटूट सम्मान, कनाडा के साथ स्थिर द्विपक्षीय संबंधों के लिए आवश्यक शर्तें हैं। इस संबंध में, भारत सरकार ने कनाडा सरकार से बार-बार आग्रह किया है कि वह अपनी धरती से सक्रिय सभी भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करे।



विदेश मंत्री ने फरवरी 2024 में म्यूनिख में आयोजित म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली से मुलाकात की।

द्विपक्षीय आदान-प्रदान

द्विपक्षीय संबंधों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, शीर्ष नेतृत्व स्तर की यात्राएं और द्विपक्षीय तंत्र बैठकें 2024 में नहीं हो सकी।

विदेश मंत्री ने 17 फरवरी को म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन (एमएससी) के दौरान विदेश मंत्री मेलानी जोली से मुलाकात की। दोनों मंत्रियों ने 27 जुलाई को लाओस में आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान भी मुलाकात की।

ऑटारियो प्रांत के आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और व्यापार मंत्री विक्टर फेडेली ने एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ 11-16 फरवरी को मुंबई और बेंगलुरु की यात्रा की। कनाडा के सस्केचेवान प्रांत के प्रमुख स्कॉट मो ने 20-23 फरवरी को कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर सहित एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत की यात्रा की। कनाडा के सांसद चंद्र आर्य ने 12 अगस्त को भारत की यात्रा की और प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से मुलाकात की।

खान सचिव ने 03-06 मार्च को टोरंटो में प्रॉस्पेक्ट्स एंड डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ कनाडा (पीडीएसी) में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। नागर विमानन सचिव ने मॉन्ट्रियल में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ) नवाचार सम्मेलन में भाग लेने के लिए 12-14 मार्च को कनाडा की यात्रा की। सितंबर में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने आधिकारिक तौर पर टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (टीआईएफएफ) में भाग लिया।

व्यापार और आर्थिक सहयोग

व्यापार और निवेश संबंध भारत और कनाडा द्विपक्षीय साझेदारी के प्रमुख घटक हैं। जनवरी-अगस्त के बीच भारत का कनाडा को निर्यात 2.68 बिलियन अमरीकी डॉलर का था और कनाडा से आयात 3.03 बिलियन अमरीकी डॉलर का था। जनवरी-अगस्त के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार 5.71 बिलियन अमरीकी डॉलर का था। कनाडा से भारत में पोर्टफोलियो निवेश 55 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक है। भारत की आर्थिक विकास क्षमता के कारण यह राशि और बढ़ने की संभावना है। अप्रैल 2000 से मार्च 2023 के बीच भारत में कनाडा का प्रत्यक्ष निवेश 3.31 बिलियन अमरीकी डॉलर था। 600 से अधिक कनाडाई कंपनियों ने भारत में अपनी उपस्थिति स्थापित की है और लगभग 1000 कनाडाई कंपनियां भारत में व्यापार के अवसरों की तलाश कर रही हैं।

शिक्षा, सांस्कृतिक सहयोग और लोगों के बीच आदान-प्रदान

कनाडा में भारतीय समुदाय विदेशों में सबसे बड़े भारतीय प्रवासियों में से एक है, जिसमें लगभग 1.8 मिलियन भारतीय-कनाडाई और 1 मिलियन अनिवासी भारतीय हैं, जो इसकी कुल आबादी का 7.3% है। प्रवासी, मुख्य रूप से ग्रेटर टोरंटो एरिया, ग्रेटर वैंकूवर एरिया, मॉन्ट्रियल (क्यूबेक), कैलगरी और एडमोंटन (अल्बर्टा), ओटावा (ऑटारियो) और विनीपेग

(मैनिटोबा) सहित विभिन्न क्षेत्रों में केंद्रित हैं, जिन्होंने कनाडाई अर्थव्यवस्था और समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने का समर्थन करने वाले कई व्यवसाय और प्रवासी संगठन मौजूद हैं।

कनाडा भारतीय छात्रों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभरा है, जिनकी वर्तमान संख्या लगभग 4,27,000 है। कनाडा में भारतीय छात्रों के सामने आने वाले सभी मुद्दों पर नियमित रूप से चर्चा की जाती है और उन्हें कनाडाई प्राधिकारियों के साथ उठाया जाता है। भारत सरकार कनाडा में शिक्षा प्राप्त करने वाले भारतीय छात्रों की कल्याण को उच्च प्राथमिकता देती है।

लातिन अमेरिका और कैरेबियन

हाल के वर्षों में भारत और लैटिन अमेरिका तथा कैरेबियन (एलएसी) देशों के बीच अभूतपूर्व संबंध देखने को मिले हैं। भौगोलिक दृष्टि से अलग-अलग होने के बावजूद, लंबे समय से स्थापित भारत-एलएसी संबंध एक नए पथ पर आगे बढ़े हैं, जिससे देशों के बीच विविध संपर्कों का लाभ मिल रहा है। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान राजनीतिक संपर्कों ने एलएसी देशों के साथ भारत के संबंधों को और अधिक गति प्रदान की है।

प्रधानमंत्री 19 नवंबर को रियो डी जेनेरियो में जी-20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के लिए ब्राजील गए। जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान उन्होंने ब्राजील, अर्जेंटीना और चिली के राष्ट्रपतियों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने इससे पहले इटली में जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान ब्राजील के राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री ने नवंबर में गुयाना की अपनी यात्रा के दौरान गुयाना के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की थी।

प्रधानमंत्री ने 19-21 नवंबर तक गुयाना की राजकीय यात्रा की। उन्होंने गुयाना के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद इरफान अली के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। स्टेट हाउस में आयोजित एक समारोह में, प्रधानमंत्री को गुयाना के राष्ट्रपति द्वारा गुयाना के सर्वोच्च पुरस्कार 'ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस' से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने 20 नवंबर को गुयाना के जॉर्जटाउन में दूसरे भारत-कैरिबियन शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया। उन्होंने ग्रेनेडा के प्रधानमंत्री डिकॉन मिशेल के साथ शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता की, जो वर्तमान में कैरिबियन के अध्यक्ष भी हैं। शिखर सम्मेलन के दौरान, प्रधानमंत्री ने एंटीगुआ और बारबुडा के प्रधानमंत्री, बहामास के प्रधानमंत्री, बारबाडोस के प्रधानमंत्री, सेंट लूसिया के प्रधानमंत्री, डोमिनिका राष्ट्रमंडल के प्रधानमंत्री, ग्रेनेडा के प्रधानमंत्री, त्रिनिदाद एवं टोबैगो के प्रधानमंत्री और सूरीनाम के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं। जॉर्जटाउन में आयोजित एक समारोह में, डोमिनिका राष्ट्रमंडल के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार- "डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर" से सम्मानित किया।

गुयाना के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद इरफान अली फरवरी में भारत आए थे। उन्होंने माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय उपराष्ट्रपति से मुलाकात की और विदेश मंत्री तथा विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री के साथ बैठकें कीं। त्रिनिदाद एवं टोबैगो के प्रधानमंत्री कीथ रोली ने मई में



विदेश मंत्री ने सितंबर 2024 में न्यूयॉर्क में आयोजित भारत-सीईएलएसी विदेश मंत्रियों की बैठक की सह-अध्यक्षता की।

मुंबई और जामनगर की यात्रा की। जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस ने अक्टूबर में भारत का आधिकारिक दौरा किया और माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात की। वेनेजुएला के कार्यकारी उपाध्यक्ष डेल्सी रोड्रिगेज ने 24-28 अक्टूबर को भारत में एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया और 25 अक्टूबर को माननीय उपराष्ट्रपति और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री से मुलाकात की।

विदेश मंत्री ने पनामा, ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना और सेंट किट्स एंड नेविस के विदेश मंत्रियों की अगुवानी की। यूएनजीए के दौरान, उन्होंने गुयाना, बोलीविया, मैक्सिको, क्यूबा, अल साल्वाडोर, निकारागुआ, पनामा, डोमिनिका, ग्रेनेडा, त्रिनिदाद एवं टोबैगो, सूरीनाम और वेनेजुएला के अपने समकक्षों के साथ-साथ सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाईस के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। उन्होंने युगांडा में एनएएम शिखर सम्मेलन के दौरान कोलंबिया, बोलीविया और वेनेजुएला के विदेश मंत्रियों से भी मुलाकात की, गुयाना में कैरीकॉम शिखर सम्मेलन के दौरान जमैका के विदेश मंत्री से मुलाकात की और कतर में दोहा फोरम के दौरान होंडुरास के विदेश मंत्री के साथ बातचीत की। इसके अलावा, विदेश मंत्री और होंडुरास के विदेश मामलों की सचिव एनरिक रीना ने 27 सितंबर को न्यूयॉर्क में आयोजित भारत-सीईएलएसी विदेश मंत्रियों की बैठक की सह-अध्यक्षता की। बैठक के दौरान, भारत और सीईएलएसी ने भारत-सीईएलएसी संयुक्त आयोग की स्थापना करके सहयोग को संस्थागत बनाने का निर्णय लिया।

तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री (वीएम) ने जी-20 विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए फरवरी में ब्राजील की यात्रा की। विदेश राज्य मंत्री (पीएम) ने डोमिनिकन गणराज्य, ग्वाटेमाला, अल साल्वाडोर, पनामा, त्रिनिदाद एवं टोबैगो, मैक्सिको, ग्रेनेडा, बारबाडोस और एंटीगुआ तथा बारबुडा का

आधिकारिक दौरा किया। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री ने सीओपी16 बैठक में भाग लेने के लिए कैली, कोलंबिया की यात्रा की।

कोलंबिया, उरुग्वे और अर्जेंटीना के साथ विदेश कार्यालय परामर्श (एफओसी) आयोजित किए गए। पेरू के साथ सचिव स्तर पर संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित की गई।

सितंबर में ला पाज़, बोलीविया में एक नया मिशन खुलने के साथ ही अब एलएसी क्षेत्र में भारत के 17 रेजीडेंट मिशन हो गए हैं।

भारत ने मार्च-अप्रैल में ऑपरेशन इंद्रावती के तहत हैती से 17 भारतीय नागरिकों को निकाला था।

अब तक सात देशों (सूरीनाम, एंटीगुआ एवं बारबुडा, त्रिनिदाद एवं टोबैगो, क्यूबा, कोलंबिया, सेंट किट्स एंड नेविस तथा जमैका) ने इंडिया स्टैक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। यूपीआई के संदर्भ में, पेरू एलएसी क्षेत्र में भारत के साथ वाणिज्यिक करार करने वाला पहला देश है, उसके बाद त्रिनिदाद एवं टोबैगो है।

दक्षिण अमेरिका

अर्जेंटीना

भारत और अर्जेंटीना ने 03 फरवरी को अपने राजनयिक संबंधों की 75^{वीं} वर्षगांठ मनाई। दोनों देशों ने वर्ष के दौरान उच्च स्तरीय आदान-प्रदान और बातचीत के माध्यम से अपने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाए रखा।

24 अप्रैल को मिशन और अर्जेटीना के सबसे प्रमुख थिंकटैंक, कॉन्सेजो अर्जेटीनो पैरा लास रिलोकियोनेस इंटरनेशनल (सीएआरआई) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक कार्यक्रम में अर्जेटीना की उपराष्ट्रपति विक्टोरिया विलारुएल ने सीएआरआई में 'भारत कार्य समूह' का शुभारंभ किया।

प्रधानमंत्री ने 19 नवंबर को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 19^{वां} जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान अर्जेटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली से मुलाकात की। यह दोनों नेताओं के बीच पहली द्विपक्षीय बैठक थी।

अर्जेटीना की तत्कालीन विदेश मंत्री डायना मोडिनो ने 16 फरवरी को जर्मनी में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में विदेश मंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्री मोडिनो ने 05-09 अक्टूबर को नई दिल्ली की यात्रा की और 08 अक्टूबर को विदेश मंत्री के साथ 7^{वां} संयुक्त आयोग बैठक (जेसीएम) की सह-अध्यक्षता की। विदेश मंत्री मोडिनो ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री से भी मुलाकात की। उनके साथ एक अधिकारी के साथ-साथ खनन, कृषि, फार्मास्यूटिकल्स, जैव प्रौद्योगिकी और परमाणु ऊर्जा सहित विविध क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाला 17-सदस्यीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी था। प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय व्यापार और उद्योग के प्रमुखों के साथ एक व्यापारिक कार्यक्रम में भी भाग लिया, जिसका आयोजन सीआईआई द्वारा किया गया था और जिसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री मोडिनो और वाणिज्य एवं उद्योग और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने की थी।

राजनयिक संबंधों की 75^{वां} वर्षगांठ मनाने के लिए दूतावास ने भारत-अर्जेटीना व्यापार परिषद (आईएबीसी) के साथ मिलकर 29 फरवरी को भारत-अर्जेटीना व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में अर्जेटीना के रक्षा मंत्री लुइस पेटी और कैटामार्का के गवर्नर राउल जलील ने भाग लिया, जबकि तत्कालीन विदेश मंत्री मोडिनो शिखर सम्मेलन के मुख्य अतिथि थीं।

अर्जेटीना की मानव पूंजी मंत्री सैंद्रा पेटोवेलो और ऊर्जा सचिव एडुआर्डो चिरिलो ने 17 अगस्त को वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट (वीओजीएसएस) के तीसरे संस्करण में वर्चुअल रूप से भाग लिया। अर्जेटीना के तत्कालीन वायु सेना प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल फर्नांडो लुइस मेंगो ने 10-13 सितंबर को अभ्यास तरंग शक्ति में भाग लिया। उन्होंने 14 सितंबर को मेसर्स हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल), बेंगलुरु का भी दौरा किया।

7^{वां} विदेश कार्यालय परामर्श (एफओसी) 13 सितंबर को ब्यूनस आयर्स में आयोजित किया गया। एफओसी का नेतृत्व सचिव, पूर्व और अर्जेटीना के विदेश मंत्रालय के तत्कालीन सचिव लियोपोल्डो साहोरेस ने किया।

खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड (एक भारतीय सार्वजनिक उपक्रम) और कैमयेन (कैटामार्का प्रांत का एक सार्वजनिक उपक्रम) ने 15 जनवरी को कैटामार्का प्रांत में पांच लिथियम ब्लॉक हासिल करने के लिए करार पर हस्ताक्षर किए।

भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग की एक घटक इकाई, हैवी वॉटर बोर्ड (एचडब्ल्यूबी), मुंबई और मेसर्स न्यूक्लियोइलेक्ट्रिका अर्जेटीना एसए (नासा) ने 04 नवंबर को वर्चुअल रूप में एक करार पर हस्ताक्षर किए।

बोलीविया

भारत और बोलीविया ने अपने द्विपक्षीय संबंधों में गति को आगे बढ़ाया। भारत ने 17 सितंबर को ला पाज़ में अपना रेजिडेंट मिशन खोला।

विदेश मंत्री ने इस वर्ष दो बार बोलीविया की विदेश मंत्री सेलिंडा सोसा लुंडा से मुलाकात की - पहली बार जनवरी में, युगांडा में गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन (एनएएम) के अवसर पर और सितंबर में, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अवसर पर; जिससे द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति को बल मिला।



सितंबर 2024 में न्यूयॉर्क में 79^{वां} यूएनजीए के मौके पर बोलीविया की विदेश मंत्री सेलिंडा सोसा लुंडा से मुलाकात की।

बोलीविया के पर्यावरण एवं जल मंत्रालय के वन विकास और प्रबंधन महानिदेशक फिलोमोन हिनोजोसा टोर्रिफो ने 17 अगस्त को वर्चुअल रूप में आयोजित तीसरे वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के पर्यावरण मंत्रियों के सत्र में भाग लिया।

ब्राजील

प्रधानमंत्री ने इस वर्ष दो बार ब्राजील के राष्ट्रपति लुईज़ इनासियो लूला दा सिल्वा से मुलाकात की, जून में इटली में आयोजित जी7 शिखर सम्मेलन के दौरान और नवंबर में रियो डी जेनेरियो में आयोजित जी20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भी। दोनों नेताओं ने वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर सहयोग पर जोर देते हुए कृषि, रक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, जैव ईंधन और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में भारत-ब्राजील रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने पर चर्चा की। जी20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान, प्रधानमंत्री ने “सामाजिक समावेशन और भूख और गरीबी के विरुद्ध लड़ाई” और



नवंबर 2024 में रियो डी जनेरियो में आयोजित जी20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा से मुलाकात की।

“सतत विकास और ऊर्जा परिवर्तनशीलता” पर महत्वपूर्ण सलों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने गरीबी और भूख के विरुद्ध वैश्विक गठबंधन स्थापित करने की ब्राजील की पहल की भी प्रशंसा की और उन्हें भारत के दृढ़ समर्थन से अवगत कराया।

भारत और ब्राजील के बीच 9^{वाँ} संयुक्त आयोग बैठक (जेसीएम) 27 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस बैठक की सह-अध्यक्षता विदेश मंत्री और ब्राजील के विदेश मंत्री मौरो विएरा ने की। मंत्रियों ने व्यापार एवं निवेश, जैव ईंधन ऊर्जा, कृषि एवं पशुधन, स्वास्थ्य एवं पारंपरिक चिकित्सा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, डिजिटल अर्थव्यवस्था, रक्षा, आतंकवाद-रोध और कौंसली तथा कानूनी मामलों सहित कई मुद्दों पर चर्चा की।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री ने भारतीय तेल एवं गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ सितंबर में ब्राजील की यात्रा की और ब्राजील के खान एवं ऊर्जा मंत्री एलेक्जेंडर सिल्वेरा, पेट्रोब्रास के अध्यक्ष मैग्डा चैम्ब्रियार्ड, विदेश मंत्री माउरो विएरा और राष्ट्रपति के सलाहकार सेल्सो अमोरिम के साथ बैठकें कीं; तथा जैव ईंधन, अपतटीय अन्वेषण और महत्वपूर्ण खनिजों सहित ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की।

वाणिज्य एवं उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी राज्य मंत्री ने सितंबर में ब्राजील की यात्रा की और ब्राजील के उपराष्ट्रपति गेराल्डो अल्कमिन से मुलाकात की तथा स्वच्छ ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, जैव ईंधन, डिजिटल प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा और कृषि में सहयोग के अवसरों की पर बात की। सितंबर में नई दिल्ली में वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) और

ब्राजील के कृषि एवं पशुधन मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

पराना के गवर्नर कार्लोस मासा रतिन्हो जूनियर ने अप्रैल में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत की यात्रा की और पराना के सरकारी संस्थानों और भारत के उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र (सी-डैक) के बीच साझेदारी के माध्यम से उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग पर विशेष ध्यान देते हुए नवाचार और प्रौद्योगिकी में सहयोग के अवसरों का पता लगाया। प्रतिनिधिमंडल ने टाटा समूह के मुख्यालय का भी दौरा किया, जहाँ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) ने पराना के लोंड्रिना में एक नए डिलीवरी सेंटर की स्थापना की घोषणा की।

ब्राजील के संघीय सर्वोच्च न्यायालय के अध्यक्ष, मंत्री लुइस रॉबर्टो बरोसो ने सितंबर में भारत की यात्रा की और भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश तथा विधि एवं न्याय मंत्री के साथ बैठकें कीं।

राज्य सभा के उपसभापति के नेतृत्व में 6 सदस्यीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने 06-09 नवंबर को ब्रासीलिया में 10^{वाँ} जी-20 संसदीय अध्यक्षों (पी-20) शिखर सम्मेलन में भाग लिया और ब्राजील के सीनेट के अध्यक्ष सीनेटर रोड्रिगो पचेको के साथ बैठक की।

भारत और ब्राजील के बीच पहली बार राजनीतिक और सैन्य (2+2) वार्ता मार्च में नई दिल्ली में हुई। इस वार्ता की सह-अध्यक्षता भारत की ओर से विदेश मंत्रालय के अपर सचिव (एलएसी), रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव (अंतर्राष्ट्रीय सहयोग) ने की, जबकि ब्राजील की ओर से विदेश मंत्रालय के निदेशक मार्सेलो कैमारा और रक्षा मंत्रालय की ओर से रियर एडमिरल फर्नांडो डी लुका मार्क्स डी ओलिवेरा ने प्रतिनिधित्व किया।

यह वर्ष रक्षा प्रतिनिधिमंडलों के उच्च स्तरीय आदान-प्रदान और रक्षा उद्योगों के दौरो के लिए उल्लेखनीय रहा। ब्राजील की नौसेना ने 19-27 फरवरी को पूर्वी नौसेना कमान के तत्वावधान में विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास- मिलन 2024 के 12^{वें} संस्करण में भाग लिया। एफएबी के कमांडर के नेतृत्व में ब्राजील की वायु सेना (एफएबी) के एक प्रतिनिधिमंडल ने विशिष्ट आगंतुक (डीवी) दिवस और स्वदेशी रक्षा उद्योग प्रदर्शनी में भाग लिया। ब्रिगेडियर जनरल रोचा लीमा ने 17-23 मार्च को भारत में ब्राजील के सेना प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। ब्राजील के नौसेना कमांडर एडमिरल मार्कोस सम्पाइओ ओलसेन ने 19-24 अगस्त को भारत की यात्रा की। एफएबी के कमांडर लेफ्टिनेंट ब्रिगेडियर मार्सेलो कानिन्हा दमास्केनो 10-13 सितंबर को भारत आए। भारतीय नौसेना ने रियो डी जेनेरियो में 10-15 अक्टूबर को ब्राजील की नौसेना की 79^{वाँ} सेलिंग रेगाटा में भाग लिया।

मई में, इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद (ईईपीसी), भारत के क्षेत्रीय निदेशक (पश्चिमी क्षेत्र) और निदेशक (विपणन और बिक्री) के नेतृत्व में 19 भारतीय इंजीनियरिंग निर्यातकों ने साओ पाउलो में आयोजित एफईआईएमईसी 2024 में इंडिया पैवेलियन में भाग लिया, जिसमें भारत की इंजीनियरिंग क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया और इस प्रतिष्ठित औद्योगिक कार्यक्रम के दौरान लैटिन अमेरिकी बाजार में व्यापार के अवसरों की खोज की गई। उसी महीने, ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसीएमए) के 20-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल और रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी) के 10-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने ब्राजील की यात्रा की। जुलाई में, केमेक्सिल के 8-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने साओ पाउलो में आयोजित 44^{वाँ} डाई+केम ब्राजील एक्सपो के साथ-साथ प्रमुख टूर ऑपरेटर्स और ट्रेवल एजेंटों के साथ भारत पर्यटन प्रचार कार्यक्रम में भाग लिया।

25 जुलाई को आर्थिक संबंध सचिव और कुइबा के मेयर इमैनुएल पिनहेरो ने कुइबा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया, जो ब्राजील और भारत के बीच सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने का प्रतीक है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सी-डैक) के 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने अगस्त में ब्राजील की यात्रा की और सार्वजनिक सेवा नवाचार पर ब्राजील के समकक्षों के साथ सहयोग पर बात की।

17-30 अक्टूबर को आयोजित 48^{वाँ} साओ पाउलो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारत ने 'फोकस कंट्री' के रूप में भाग लिया। इस महोत्सव में भारतीय सिनेमा पर विशेष ध्यान दिया गया और समकालीन भारतीय फिल्मों की एक श्रृंखला प्रदर्शित की गई, जिसमें नए निर्देशकों और स्थापित फिल्म निर्माताओं दोनों को शामिल किया गया।

विश्व विद्या गुरुकुलम के विद्यार्थियों ने जोनास मसेट्टी (आचार्य विश्वनाथ) के नेतृत्व में 19 नवंबर को रियो डी जेनेरियो में प्रधानमंत्री की उपस्थिति में 'रामायण' की प्रस्तुति दी।

चिली

चिली के राष्ट्रपति गेब्रियल बोरिक फॉन्ट ने 17 अगस्त को तीसरे वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के नेताओं के सत्र में भाग लिया और

पुनर्गठित यूएनएससी में भारत के लिए चिली के समर्थन को दोहराया। प्रधानमंत्री ने नवंबर में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति फॉन्ट के साथ द्विपक्षीय बैठक की।

चिली के विदेश मंत्री अल्बर्टो वैन क्लावेरेन स्टॉर्क ने अगस्त में भारत की यात्रा की और विदेश मंत्री के साथ मिलकर भारत-चिली संयुक्त आयोग की बैठक की सह-अध्यक्षता की। कृषि मंत्री एस्टेबन वेलेज़ुएला वैन ट्रीक ने भी इसी अवधि के दौरान भारत की यात्रा की और संबंधित भारतीय अधिकारियों के साथ बैठकें कीं।

अप्रैल में खान सचिव ने चिली में एक उच्चस्तरीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया और खनन क्षेत्र के प्रमुख हितधारकों के साथ चर्चा की। भारत और चिली ने 18 अक्टूबर को चिकित्सा उत्पाद विनियमन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

फार्मास्युटिकल निर्यात संवर्धन परिषद (फार्मिक्सिल) ने फरवरी में सैंटियागो में 'इंटरनेशनल एग्जीबिशन फॉर फार्मा एंड हेल्थकेयर'- लैटिन अमेरिका (आईपीएचईएक्स लैटम): इंडिया-चिली फार्मा बिजनेस मीट' का आयोजन किया। मार्च में, हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीएच) ने सैंटियागो में हस्तशिल्प प्रदर्शनी और क्रेता-विक्रेता बैठक का आयोजन किया। रेलवे में चिली के साथ व्यावसायिक सहयोग की संभावना तलाशने के लिए रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकनॉमिक सर्विस (राइट्स) लिमिटेड की एक टीम ने सितंबर में चिली की यात्रा की। भारतीय निर्यात संगठन महासंघ (एफआईईओ) ने अक्टूबर में 20 सदस्यीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, जो चिली के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय निर्माण क्षेत्र मेले, एडिफिका मेले में भाग लेने गया।

कोलंबिया

वर्ष 2024 में भारत और कोलंबिया के बीच राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे हो गए। इस दौरान भारत और कोलंबिया ने उच्च स्तरीय बैठकों और संपर्कों के माध्यम से अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती प्रदान करना जारी रखा।

20 जनवरी को, विदेश मंत्री ने कंपाला में आयोजित गुटनिरपेक्ष आंदोलन (एनएएम) के 19^{वाँ} शिखर सम्मेलन के मौके पर कोलंबिया के तत्कालीन विदेश मंत्री अल्वारो लेवा दुरान से मुलाकात की। कोलंबिया के तत्कालीन सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) मंत्री मौरिसियो लिज़कानो ने 15-17 फरवरी को भारत की आधिकारिक यात्रा की। मंत्री लिज़कानो ने तत्कालीन राज्य मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमआईटीवाई) से मुलाकात की, और भारत और कोलंबिया के बीच आईसीटी सहयोग को मजबूत करने पर द्विपक्षीय वार्ता की। यात्रा के दौरान, 'डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या स्तर पर कार्यान्वित सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के क्षेत्र में सहयोग' अर्थात 'इंडिया स्टैक' के लिए एमआईटीवाई और कोलंबिया के आईसीटी मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। कोलंबिया के विदेश मंत्री लुइस गिल्बर्टो मुरिलो ने 17 अगस्त को वर्चुअल रूप से आयोजित तीसरे वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के विदेश मंत्रियों के सत्र में भाग लिया।

भारत-कोलंबिया विदेश कार्यालय परामर्श (एफओसी) का 10^{वाँ} दौर 15 अक्टूबर को नई दिल्ली में हुआ। भारतीय और कोलंबियाई पक्षों का नेतृत्व क्रमशः सचिव, पूर्व (एमईए) और कोलंबिया के विदेश मामलों के उप मंत्री जॉर्ज रोजास रोड्रिगेज ने किया। परामर्श के दौरान, दोनों देशों के बीच एक ऑडियो-विजुअल सह-निर्माण करार पर हस्ताक्षर किए गए।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री ने 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक कोलंबिया के कैली में आयोजित जैव विविधता पर अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की 16^{वाँ} बैठक (सीबीडी सीओपी-16) के उच्च स्तरीय खंड में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।



विदेश राज्य मंत्री (केवीएस) ने अक्टूबर 2024 में नई दिल्ली में कोलंबिया गणराज्य के विदेश उप मंत्री जॉर्ज एनरिक रोजास रोड्रिगेज के साथ शिष्टाचार बैठक की।

वर्ष के दौरान फार्मेक्सिल, रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी) और हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीएच) जैसी विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल कोलंबिया गए, जिससे द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को और अधिक बढ़ावा मिला।

इक्वाडोर

22-30 मई को इक्वाडोर के कुएनका में कुएनका विश्वविद्यालय संग्रहालय और टैगोर गार्डन में रवींद्रनाथ टैगोर जयंती मनाई गई। सप्ताह भर चलने वाले समारोह के दौरान, लगभग 1500 मेहमानों ने विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों में भाग लिया। 27-29 सितंबर को इक्वाडोर के ग्वायाकिल में एस्पिरिटु सैंटो विश्वविद्यालय (यूईईएस) में भारतीय फिल्म महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया।

पराग्वे

पराग्वे जून में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100^{वाँ} देश बन गया।

इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद (ईएससी) के 14 सदस्यों वाले पहले भारतीय आईटी प्रतिनिधिमंडल ने 07 मार्च को पराग्वे की यात्रा की। इस कार्यक्रम में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्री (एमआईटीआईसी) गुस्तावो विलाटे भी शामिल हुए। ईएससी और सिसॉफ्ट ने सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

वित्त मंत्रालय के केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के आयुक्त के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 23-29 नवंबर को कर उद्देश्यों के लिए पारदर्शिता और सूचना के आदान-प्रदान पर वैश्विक फोरम की 17^{वाँ} पूर्ण बैठक और संबद्ध बैठकों में भाग लेने के लिए पराग्वे की यात्रा की।

पेरू

इस वर्ष भारत और पेरू के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60^{वाँ} वर्षगांठ मनाई गई। पेरू की राष्ट्रीय डाक सेवा सर्पास्ट ने मार्च में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया और पेरू के विदेश मंत्रालय ने द्विपक्षीय संबंधों के छह दशकों को चिह्नित करने के लिए मंत्रालय में एक फोटो प्रदर्शनी आयोजित की।

27 अक्टूबर को आयोजित अपने मन की बात संबोधन में, प्रधान मंत्री ने भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए हर्लिंगा गार्सिया और मारिया लौरा की उपलब्धियों की सराहना की।

पेरू के तत्कालीन विदेश मंत्री जेवियर गोंजालेज-ओलाचेया ने 17 अगस्त को आयोजित तीसरे वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के विदेश मंत्रियों के दूसरे सत्र में वीडियो संदेश के माध्यम से भाग लिया। शिखर सम्मेलन वर्चुअल रूप में आयोजित किया गया था।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय के 20 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत-पेरू मुक्त व्यापार करारों (एफटीए) के छठे दौर की वार्ता के लिए फरवरी में पेरू की यात्रा की, जबकि द्विपक्षीय एफटीए वार्ता का सातवां दौर 10-13 अप्रैल को नई दिल्ली में आयोजित किया गया।

सितंबर में सचिव, पूर्व (विदेश मंत्रालय) ने पेरू में आयोजित संयुक्त आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। पेरू पक्ष का नेतृत्व विदेश मंत्री के उप मंत्री पीटर कैमिनो ने किया। अपनी यात्रा के दौरान सचिव, पूर्व ने सामाजिक समावेशन मंत्री जूलियो डेमार्टिनी और स्वास्थ्य उप मंत्री एरिक पेना सांचेज़ से बातचीत की।

भारत और पेरू ने मार्च में भारत के वैश्विक परमाणु ऊर्जा साझेदारी केंद्र (जीसीएनईपी) और पेरूवियन इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी (आईपीईएन) के बीच परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अप्रैल में पेरू के विदेश व्यापार और पर्यटन मंत्रालय के 12-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली



वेनेजुएला की कार्यकारी उपाध्यक्ष डेलसी रोड्रिगज ने अक्टूबर 2024 में अपनी नई दिल्ली यात्रा के दौरान माननीय उपराष्ट्रपति से मुलाकात की।

की यात्रा की। 04 जून को, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (एनआईपीएल) ने पेरू में यूपीआई जैसा भुगतान प्लेटफॉर्म बनाने के लिए पेरू सेंट्रल रिजर्व बैंक (बीसीआरपी) के साथ अनुबंध किया।

सुप्रीम कोर्ट और लीमा तथा आस-पास के विभिन्न सुपीरियर कोर्ट के 15 न्यायाधीश/मजिस्ट्रेट 22 जुलाई से 9 अगस्त तक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सीडीएसी), नोएडा द्वारा आयोजित स्पेनिश में “आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस” पर विशेष पाठ्यक्रम में शामिल हुए। 18 सितंबर को दूतावास ने आईटीईसी नेटवर्क दिवस मनाया जिसमें आईटीईसी कार्यक्रम के तहत भारत आए सौ से अधिक पूर्व छात्रों ने भाग लिया। पेरू के सुप्रीम कोर्ट के 15 न्यायाधीशों और 2 अधिकारियों तथा नई दिल्ली में पेरू के दूतावास के एक अधिकारी सहित 18 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 04-08 नवंबर को राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल में मानव तस्करी और नागरिक सुरक्षा पर एक विशेष पाठ्यक्रम में भाग लिया।

उरुग्वे

उरुग्वे के राष्ट्रपति लुइस लैकेले पोउ और सामाजिक विकास मंत्रालय के उप मंत्री एंड्रिया ब्रुगमैन ने 17 अगस्त को आयोजित तीसरे वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट (वीओजीएसएस) के क्रमशः शीर्ष नेताओं के सत्र और युवा मामलों के मंत्रियों के सत्र में वीडियो-मैसेज के माध्यम से भाग लिया। एजीईएसआईसी के कार्यकारी निदेशक हेबर्ट पगुआस ने शिखर सम्मेलन के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रियों के सत्र में उरुग्वे का प्रतिनिधित्व किया।

भारत और उरुग्वे के बीच छठी विदेश कार्यालय वार्ता 16 सितंबर को मोंटेवीडियो, उरुग्वे में आयोजित की गई जिसका नेतृत्व सचिव, पूर्व और

उरुग्वे के विदेश मामलों के उप मंत्री निकोलस अल्बर्टोनी ने किया। 16 सितंबर को भारत और उरुग्वे ने राजनयिकों के संबंधियों के लिए लाभकारी रोजगार पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

वेनेजुएला

भारत और वेनेजुएला ने अक्टूबर में राजनयिक संबंधों की स्थापना की 65^{वीं} वर्षगांठ मनाई।

वेनेजुएला की कार्यकारी उपाध्यक्ष डेलसी रोड्रिगज ने 24-28 अक्टूबर को एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए भारत की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान, उन्होंने माननीय उपराष्ट्रपति से मुलाकात की और 25 अक्टूबर को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री से वार्ता की। इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय ऊर्जा सहयोग को बढ़ाना था।

वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने इस वर्ष दो बार विदेश मंत्री से मुलाकात की, जनवरी में कंपाला में आयोजित गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन के दौरान और सितंबर में न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान। बैठकों के दौरान, उन्होंने आर्थिक, ऊर्जा एवं विकास सहयोग तथा आपसी हित के अन्य मुद्दों पर चर्चा की। 11 जून को रूस में आयोजित विकासशील देशों के साथ ब्रिक्स मंत्रिस्तरीय वार्ता के दौरान, विदेश मंत्री गिल ने आर्थिक संबंध सचिव के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और द्विपक्षीय सहयोग, विशेष रूप से व्यापार, ऊर्जा और बहुपक्षीय सहयोग के मुद्दों पर चर्चा की।

वेनेजुएला के पेट्रोलियम मंत्रालय के गैस उप मंत्री जुआन सैन्ताना ने 06-09 फरवरी को गोवा में आयोजित भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 में भाग

लिया। इको-सोशलिज्म मंत्रालय के पर्यावरण प्रबंधन सेवा के उप मंत्री हर्नान गेब्रियल टोरो हर्नांडेज़ ने 17 अगस्त को आयोजित तीसरे वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के पर्यावरण सत्र में भाग लिया। अक्टूबर में, वेनेजुएला ने औपचारिक रूप से भारत के नेतृत्व वाले गठबंधन, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने की अपनी रुचि व्यक्त की। विद्युत ऊर्जा मंत्रालय के विद्युत क्षेत्र विकास और उद्योग उप मंत्री कार्लोस अल्फ्रेडो गोंजालेज़ ने 03-06 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) की सभा के 7^{वें} सत्र में भाग लिया।

उत्तर और मध्य अमेरिका

बेलीज़

बेलीज़ के विदेश एवं विदेश व्यापार मंत्री फ्रांसिस फोंसेका ने 20 नवंबर को गुयाना में आयोजित दूसरे भारत-कैरिबियन शिखर सम्मेलन में बेलीज़ का प्रतिनिधित्व किया।

शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डियान कैस्टिलो माहिया ने 17 अगस्त को वर्चुअल रूप में आयोजित तीसरे वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के शिक्षा मंत्रियों के सत्र में भाग लिया।

कोस्टा रिका

जून में, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव ने सैन जोस, कोस्टा रिका में 'महासागर संरक्षा संबंधी उच्च स्तरीय कार्यक्रम (एचएलईओए): इमर्सेड इन चेंज' में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। प्रतिनिधियों में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र और मत्स्य पालन विभाग के विशेषज्ञ शामिल थे। चर्चाओं में महासागर संरक्षण के महत्व पर जोर दिया गया और इसमें कोस्टा रिका के पर्यावरण मंत्री फ्रांज़ टैटनबैक के साथ-साथ फ्रांस, नॉर्वे और ब्राजील के प्रतिनिधियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें शामिल थीं।

कोस्टा रिका के बहुपक्षीय मामलों के उप मंत्री एलेजांद्रो सोलानो ने 17 अगस्त को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के उप मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित तीसरे वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के पर्यावरण मंत्रियों के सत्र में भाग लिया।

अल साल्वाडोर

अल साल्वाडोर के उपराष्ट्रपति फेलिक्स उलोआ हिजो और शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जोस मौरिसियो पिनेडा ने 17 अगस्त को वर्चुअल रूप में आयोजित तीसरे वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के क्रमशः नेताओं के सत्र और शिक्षा मंत्रियों के सत्र में वीडियो संदेशों के माध्यम से भाग लिया।

विदेश मंत्री ने 28 सितंबर को न्यूयॉर्क में आयोजित 79^{वें} संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सप्ताह के अवसर पर अल साल्वाडोर की विदेश मंत्री एलेक्जेंद्रा हिल टिनोको से मुलाकात की।

19-20 अगस्त को राज्य मंत्री (पीएम) ने अल साल्वाडोर की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान, उन्होंने अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले से मुलाकात की और विदेश मंत्री टिनोको, राष्ट्रपति बुकेले के सलाहकार, नवाचार सचिव डैनियल मेडेज़, परिवहन और लोक निर्माण मंत्री रोमियो रोड्रिगेज़, आवास मंत्री मिशेल सोल, अर्थव्यवस्था मंत्री मारिया लुइसा हेयम और शिक्षा मंत्री जोस मौरिसियो पिनेडा रोड्रिगेज़ से वार्ता की। 20 अगस्त को राज्य मंत्री (पीएम) की इस देश की यात्रा के दौरान सैन साल्वाडोर में साइबर सुरक्षा पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।



राज्य मंत्री (पीएम) ने अगस्त 2024 में सैन साल्वाडोर में अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले से मुलाकात की।

राष्ट्रपति के सलाहकार इब्राहिम बुकेले ने 14-22 अप्रैल को एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए भारत की यात्रा की, ताकि प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त किया जा सके तथा विभिन्न संभावित परियोजनाओं के संचालन की देखरेख की जा सके, जिन पर अल साल्वाडोर और भारत सहयोग कर सकते हैं।

भारत ने जून में उष्णकटिबंधीय तूफान से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए अल साल्वाडोर को 50 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) सामग्री दान की। दिसंबर में, भारत ने अल साल्वाडोर के साथ त्वरित प्रभाव परियोजनाओं (क्यूआईपी) के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जो दोनों देशों की साझेदारी की बढ़ती ताकत को दर्शाता है।

ग्वाटेमाला

राज्य मंत्री (पीएम) ने 17-19 अगस्त को ग्वाटेमाला गणराज्य की आधिकारिक यात्रा की। यात्रा के दौरान, उन्होंने ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति सेसर बर्नाडो एरेवलो डी लियोन से मुलाकात की और विदेश मंत्री कार्लोस रामिरो मार्टिनेज अल्वाराडो से वार्ता की।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव के नेतृत्व में चार सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 03-06 मई को ग्वाटेमाला की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान, भारत और ग्वाटेमाला ने 'बाघ (पैंथेरा टाइग्रिस) और जगुआर (पैंथेरा ओनका) के संरक्षण' पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। विदेश मंत्री अल्वाराडो ने 17 अगस्त को एक वीडियो संदेश के माध्यम से तीसरे वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के विदेश मंत्रियों के सत्र में भाग लिया। शिखर सम्मेलन वर्चुअल रूप में आयोजित किया गया था।

14 मार्च को भारतीय दूतावास ने ग्वाटेमाला शहर में स्वास्थ्य मंत्रालय में आयोजित एक समारोह में ग्वाटेमाला सरकार को भारत में निर्मित दवाओं की दस लाख से अधिक खुराकें दान कीं। ये दवाइयाँ तपेदिक, मिर्गी और टाइप-2 मधुमेह के इलाज के लिए थीं।

होंडुरस

दिसंबर में, विदेश मंत्री ने कतर में दोहा फोरम के दौरान होंडुरस के विदेश मामलों एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री एडुआर्डो एनरिक रीना के साथ बैठक की। होंडुरस के शिक्षा मंत्री डैनियल स्पोंडा ने 17 अगस्त को आयोजित तीसरे वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट (वीओजीएसएस) के शिक्षा मंत्रियों के सत्र में एक वीडियो संदेश के माध्यम से भाग लिया।

दिसंबर में, भारत ने होंडुरस के साथ त्वरित प्रभाव परियोजनाओं (क्यूआईपी) के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जो उस देश के साथ प्रगति और आपसी सहयोग के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

मेक्सिको

विदेश मंत्री ने 29 सितंबर को न्यूयॉर्क में 79^{वाँ} संयुक्त राष्ट्र महासभा के अवसर पर मैक्सिको की तत्कालीन विदेश मंत्री एलिसिया बारसेना से मुलाकात की।

वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री ने 16-20 अक्टूबर को मैक्सिको में एक आधिकारिक एवं व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। यात्रा के दौरान, उन्होंने मैक्सिको के वित्त एवं सार्वजनिक ऋण मंत्री रोजेलियो रामिरेज़ डे ला ओ और मैक्सिकन सीनेट की विदेश संबंध समिति सहित विभिन्न संसदीय समितियों के प्रमुखों से मुलाकात की। उन्होंने मैक्सिको सिटी और मैक्सिको स्टेट के वित्त एवं अर्थव्यवस्था मंत्रियों के साथ भारत-मेक्सिको निवेश शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने मैक्सिको के

प्रमुख उद्योगपतियों और व्यवसायियों के चुनिंदा समूह के साथ एक विशेष बैठक भी की। ग्वाडालजारा में, उन्होंने एक टेक लीडर्स फोरम को संबोधित किया और जलिसको स्टेट के गवर्नर पाब्लो लेमुस नवारो के साथ द्विपक्षीय बैठक की।

ऊर्जा परिवर्तनशीलता और योजना उप मंत्री हेबर्टो कैस्टिलो और उच्च शिक्षा उप मंत्री लुसियानो कोंचेइरो बोरकेज़ ने 17 अगस्त को वर्चुअल रूप में आयोजित वीओजीएसएस के तीसरे संस्करण के ऊर्जा मंत्रियों के सत्र और शिक्षा मंत्रियों के सत्र में भाग लिया।

मेक्सिको के राष्ट्रपति के रूप में डॉ. क्लाउडिया शिनबाम के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए राज्य मंत्री (पीएम) ने 30 सितंबर-02 अक्टूबर को मेक्सिको की यात्रा की।

भारत और मैक्सिको ने मार्च में मैक्सिको सिटी के एल कोलेजियो डी मैक्सिको में भारतीय अध्ययन की ऑक्टैवियो पाज़ पीठ को पुनर्जीवित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के एक प्रतिनिधिमंडल ने 11-14 मार्च को मैक्सिको की यात्रा की।

मैक्सिको के 25 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के एक समूह ने भारत के आईटीईसी कार्यक्रम के अंतर्गत 25 जून से 5 जुलाई तक राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, गांधीनगर में विशेष रूप से आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लिया।

मैक्सिकन राष्ट्रीय वानिकी आयोग (सीओएनएएफओआर) और मैक्सिकन अंतरिक्ष एजेंसी (ईईएम) के बुनियादी ढांचे, संचार और परिवहन सचिवालय (एसआईसीटी) के समन्वय में इसरो द्वारा 26-28 अगस्त को “वन अग्रे प्रबंधन के लिए अंतरिक्ष प्रणालियों के उपयोग” पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था।

10^{वाँ} अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मैक्सिको में कई स्थानों पर मनाया गया, इन स्थानों में मैक्सिकन संसद, मैक्सिको में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, यूनेस्को, पुलिस अकादमी आदि शामिल हैं।

निकारागुआ

विदेश मंत्री ने 29 सितंबर को आयोजित 79^{वाँ} संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अवसर पर निकारागुआ के विदेश मंत्री वाल्ट्ज़ेक जैन्ट्स्के से मुलाकात की।

पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन उप मंत्री जेवियर एंटोनियो गुटिरेज़ रामिरेज़ ने 17 अगस्त को वर्चुअल रूप में आयोजित वीओजीएसएस के तीसरे संस्करण के पर्यावरण मंत्रियों के सत्र में भाग लिया। सत्र जलवायु रक्षण कार्रवाई और सतत विकास पर केंद्रित था।

फरवरी में, भारत और निकारागुआ ने फार्माकोपिया सहयोग संबंधी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जो दवाओं के विनियमन पर केंद्रित था। निकारागुआ, भारत फार्माकोपिया को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश बन गया। अगस्त में निकारागुआ के स्वास्थ्य मंत्रालय के दो अधिकारियों ने भारत में नीति निर्माता और नियामक विशेषज्ञों के

दौरे में भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में नियामक मानकों को बढ़ाना और सहयोग को गहरा करना था। दिसंबर में, भारत और निकारागुआ ने त्वरित प्रभाव परियोजनाओं (क्यूआईपी) के लिए एक सर्व-समावेशी करार पर हस्ताक्षर किए। इस करार का लक्ष्य बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छता जैसे क्षेत्रों में स्थानीय समुदायों के लिए ठोस लाभ प्राप्त करना है।

पनामा

फरवरी में, पनामा की तत्कालीन विदेश मंत्री जनैना तेवानी ने रायसीना वार्ता 2024 में भाग लिया और विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। विदेश मंत्री जेवियर मार्टिनेज-आचा वास्केज़ ने 17 अगस्त को विदेश मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस के तीसरे संस्करण के विदेश मंत्रियों के सत्र में भाग लिया। विदेश मंत्री मार्टिनेज-आचा वास्केज़ ने सितंबर में द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करने के लिए 79^{वाँ} संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के दौरान भी विदेश मंत्री से मुलाकात की।

अगस्त में, राज्य मंत्री (पीएम) ने पनामा की यात्रा की। उन्होंने पनामा के राष्ट्रपति जोस राउल मुलिनो से मुलाकात की और पनामा के विदेश मंत्री और अन्य उच्च-स्तरीय अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक की, जिसमें पनामा के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, विदेश मामलों एवं स्वास्थ्य उप मंत्री, राष्ट्रीय आव्रजन सेवा के महानिदेशक, पनामा पैसिफिको के विशेषज्ञ और विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार संबंधी राष्ट्रीय सचिवालय के प्रतिनिधि शामिल थे।

फरवरी में, भारत ने अवैध तम्बाकू व्यापार पर पक्षकारों की तीसरी बैठक (एमओपी) की अध्यक्षता की तथा पनामा में आयोजित पक्षकारों के सम्मेलन (सीओपी10) में भाग लिया।

मार्च में पनामा ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) का अनुसमर्थन किया और वह इसका 97^{वाँ} सदस्य बन गया।

अप्रैल में, पनामा ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन संबंधी आधारभूत दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए। उसी महीने, एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने पनामा में खाद्य पदार्थों में संदूषकों पर 17^{वाँ} कोडेक्स समिति (सीसीसीएफ) में भाग लिया। भारत के प्रतिनिधिमंडल में वाणिज्य मंत्रालय, एपीडा, एफएसएसएआई और मसाला बोर्ड के अधिकारी शामिल थे।

अगस्त में लैटिन अमेरिकी बाजार में अवसरों का पता लगाने के लिए 19 भारतीय कंपनियों ने लैटिन टायर एक्सपोजे में भाग लिया।

अक्टूबर में, बायोलॉजिकल ई. लिमिटेड के एक प्रतिनिधिमंडल ने पनामा के साथ वैक्सीन सहयोग के अवसरों का पता लगाने के लिए पनामा की यात्रा की। नवंबर में, पनामा के सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश मारिया यूजेनिया लोपेज़ एरियास ने भारत के लखनऊ में दुनिया के मुख्य न्यायाधीशों के 25^{वाँ} अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (आईसीसीजेडब्लू) में भाग लिया। उसी महीने पनामा के मैरीटाइम चैंबर के अध्यक्ष जोस डिगेरोनिमो ने नई दिल्ली में सागरमंथन संवाद में भाग लिया।

कैरेबियाई देश

कैरीकॉम

दूसरे भारत-कैरिबियन शिखर सम्मेलन के साथ भारत-कैरिबियन संबंधों में गति आई। प्रधानमंत्री ने कैरिबियन के वर्तमान अध्यक्ष और ग्रेनेडा के प्रधानमंत्री डिकॉन मिशेल के साथ शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता की। शिखर सम्मेलन में कैरिबियन की महासचिव कार्ला बार्नेट के अतिरिक्त 11 सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया। भारत-कैरिबियन संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने कैरिबियन के सदस्य देशों के समक्ष “कैरिबियन” के रूप में सात स्तंभों का प्रस्ताव रखा, जिसमें “सी का अर्थ है क्षमता निर्माण, ए का अर्थ है कृषि और खाद्य सुरक्षा, आर का अर्थ है अक्षय ऊर्जा एवं जलवायु परिवर्तन, आई का अर्थ है नवाचार, प्रौद्योगिकी एवं व्यापार, सी का अर्थ है क्रिकेट एवं संस्कृति, ओ का अर्थ है महासागर अर्थव्यवस्था एवं समुद्री सुरक्षा, और एम का अर्थ है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा।”

भारत-कैरिबियन शिखर सम्मेलन के बाद, प्रधानमंत्री ने डोमिनिका, सूरीनाम, लिनिदाद एवं टोबैगो, बारबाडोस, बहामास, एंटीगुआ और बारबुडा, सेंट लूसिया और ग्रेनेडा के शासनाध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं।

भारत-सीओएफसीओआर (भारत-कैरिबियन विदेश मंत्रिस्तरीय) बैठक 27 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान आयोजित की गई।

प्रधानमंत्री की गुयाना यात्रा से पहले, 06 नवंबर को वर्चुअल रूप में भारत-कैरिबियन संयुक्त आयोग की दूसरी बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान प्रतिभागियों ने भारत और कैरिबियन के बीच संबंधों के संपूर्ण आयाम की समीक्षा की।

एंटीगुआ और बारबुडा

दूसरे भारत-कैरिबियन शिखर सम्मेलन के अवसर पर प्रधानमंत्री ने गुयाना के जॉर्जटाउन में एंटीगुआ और बारबुडा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन के साथ वार्ता की।

राज्य मंत्री (पीएम) ने 06-08 अक्टूबर को एंटीगुआ और बारबुडा की यात्रा की। इस दौरान उन्होंने गवर्नर जनरल रॉडनी विलियम्स, प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन, विदेश मंत्री ईपी चेट ग्रीन और पर्यटन एवं निवेश मंत्री चार्ल्स फर्नांडीस से मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री की 'एक पेड़ मां के नाम' पहल के स्मरण में एंटीगुआ में अमेरिकी विश्वविद्यालय के परिसर में ताड़ का पौधा लगाया।

सचिव, पश्चिम (विदेश मंत्रालय) ने 27-30 मई को आयोजित लघु द्वीप और विकासशील राष्ट्रों (एसआईडीएस) के चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए एंटीगुआ और बारबुडा की यात्रा की।

बहामास

बहामास के प्रधानमंत्री फिलिप डेविस ने 20 नवंबर को जॉर्जटाउन, गुयाना में आयोजित दूसरे भारत-कैरिबियन शिखर सम्मेलन में देश के प्रतिनिधिमंडल

का नेतृत्व किया। प्रधानमंत्री ने भारत-कैरिबिअन शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री डेविस के साथ द्विपक्षीय बैठक की।

बहामास के शिक्षा और तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण मंत्री ग्लेनिस मार्गरेट ई. ह्यूना-मार्टिन ने 17 अगस्त को वर्चुअल रूप में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस के तीसरे संस्करण में भाग लिया।

बारबाडोस

20 नवंबर को प्रधानमंत्री ने गुयाना के जॉर्जटाउन में दूसरे भारत-कैरिबिअन नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान बारबाडोस की प्रधानमंत्री मिया अमोर मोटली से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोटली ने कोविड-19 महामारी के विरुद्ध लड़ाई में उनके नेतृत्व और भारत तथा बारबाडोस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री को 'बारबाडोस की स्वतंत्रता का मानद आदेश' प्रदान करने के अपनी सरकार के फैसले की घोषणा की।



प्रधानमंत्री ने नवंबर 2024 में गुयाना में आयोजित दूसरे भारत-कैरिबिअन शिखर सम्मेलन के दौरान बारबाडोस की प्रधानमंत्री मिया अमोर मोटली से मुलाकात की।

बारबाडोस की उद्योग, नवाचार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री मार्शा के.ए. कैडल, एम पी ने 17 अगस्त को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस के तीसरे संस्करण के वित्त मंत्रियों के सत्र में अपने देश का प्रतिनिधित्व किया।

विदेश राज्य मंत्री (पीएम) ने कैरिबियन के अपने आधिकारिक दौरे के तहत 05-06 अक्टूबर को बारबाडोस की यात्रा की। अपनी यात्रा के दौरान, उन्होंने विदेश मंत्री केरी डूराई साइमंड्स के साथ अनौपचारिक चर्चा की और भारतीय प्रवासी सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने व्हीन एलिजाबेथ अस्पताल का भी दौरा किया और इन्वेस्ट बारबाडोस और एक्सपोर्ट बारबाडोस के अधिकारियों से मुलाकात की।

अपर सचिव (लैटिन अमेरिकी और कैरिबियन) ने 08 मई को सूरीनाम में कैरिबियन राष्ट्र संघ (एसीएस) की बैठक के दौरान बारबाडोस के शिक्षा राज्य मंत्री से मुलाकात की।

डोमिनिका राष्ट्रमंडल

डोमिनिका राष्ट्रमंडल के राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने प्रधानमंत्री को उनकी शासन-पारंगता और और कोविड महामारी के दौरान डोमिनिका को दिए गए समर्थन तथा भारत-डोमिनिका संबंधों को मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार "डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर" से सम्मानित किया। यह समारोह 20 नवंबर को गुयाना के जॉर्जटाउन में आयोजित दूसरे भारत-कैरिबिअन शिखर सम्मेलन के अवसर पर आयोजित किया गया था।

डोमिनिका के प्रधानमंत्री रूजवेल्ट स्केरिट 25-28 अक्टूबर को निजी यात्रा पर भारत आए। राज्य मंत्री (पीएम) ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री स्केरिट से मुलाकात की, जिसके दौरान उन्होंने भारत और डोमिनिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने पर विचारों का आदान-प्रदान किया। प्रधानमंत्री स्केरिट ने 20 नवंबर को जॉर्जटाउन में आयोजित भारत-कैरिबिअन शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया; जहां उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की।

विदेश, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वाणिज्य एवं ऊर्जा मंत्री विन्स हेंडरसन ने 27 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान आयोजित भारत-कैरिबिअन विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री से मुलाकात की।

डोमिनिका के शिक्षा मंत्री ऑक्टोविया अल्फ्रेड ने 17 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंस के तीसरे संस्करण के शिक्षा मंत्रियों के सत्र में भाग लिया।

भारत की ओर से अनुदान परियोजना 'कैलिनागो क्षेत्र में सतत आजीविका और प्रतिरोधक्षमता को सुदृढ़ बनाने' संबंधी महत्वपूर्ण परियोजना जनवरी में डोमिनिका में पूरी हो गई।

क्यूबा

भारत और क्यूबा ने पूरे वर्ष बहुपक्षीय मंचों पर एक-दूसरे के प्रति ऐतिहासिक समर्थन बनाए रखा। विदेश मंत्री ने 25 सितंबर को 79^{वाँ} संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के दौरान न्यूयॉर्क में क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिगज से मुलाकात की।

संचार उप-मंत्री विल्फ्रेडो रोड्रिगज ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोजे/इंडिया सॉफ्ट एक्सपोजे में भाग लेने के लिए जनवरी में भारत की यात्रा की और "डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या स्तर पर कार्यान्वित सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के क्षेत्र में सहयोग" पर 'इंडिया स्टैक' - समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

सिविल डिफेंस नेशनल स्टाफ के उप प्रमुख (सचिव स्तर) प्रथम कर्नल लुइस एंजेल मैकारेनो वेलिज़ के नेतृत्व में तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 24-25

अप्रैल को नई दिल्ली में आपदा रोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया।

भारत ने अगस्त में क्यूबा को 11 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की सक्रिय दवा सामग्री (एपीआई) दान करके सहायता की। इन एपीआई ने क्यूबा के दवा निर्माताओं को अगले छह महीने से एक वर्ष तक सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के लिए एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनाने में सक्षम बनाया। विदेश मंत्री रोड्रिगेज ने 17 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंस के तीसरे संस्करण के विदेश मंत्रियों के सत्र में एक वीडियो संदेश भी दिया।

डोमिनिकन गणराज्य

विदेश राज्य मंत्री (पीएम) ने डोमिनिकन गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचन पर राष्ट्रपति लुइस अबिनादर के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए 15-17 अगस्त को डोमिनिकन गणराज्य की आधिकारिक यात्रा की। उन्होंने विदेश मंत्री रॉबर्टो अल्वारेज़ से भी मुलाकात की और द्विपक्षीय हितों के मुद्दों पर चर्चा की। विदेश राज्य मंत्री (पीएम) ने दूतावास परिसर में भारतीय प्रवासी लोगों से भी बातचीत की।

डोमिनिकन गणराज्य के विदेश मंत्रालय और भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के बीच संयुक्त आर्थिक और व्यापार सहयोग (जेटको) संबंधी समझौता ज्ञापन पर 12 मार्च को हस्ताक्षर किए गए, ताकि दोनों देशों के बीच व्यापारिक, आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध बढ़ाए जा सकें। मौसम विज्ञान के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) और डोमिनिकन गणराज्य के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान कार्यालय (ओएनएमईटी) के बीच 24 अप्रैल को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

सरकार के सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कार्यालय (ओजीटीआईसी), एमआईआईएक्स, उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमआईएससीआईटी) और केंद्रीय बैंक के 12 सरकारी अधिकारियों ने 01-12 जुलाई को सीडैक दिल्ली में उत्तरदायी कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर विशेष पाठ्यक्रम में भाग लिया।

डोमिनिकन गणराज्य के ऊर्जा एवं खान मंत्रालय की मेजबानी में लैटिन अमेरिका और कैरिबियन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) क्षेत्रीय समिति की छठी बैठक 09-11 सितंबर को सैंटो डोमिंगो में आयोजित की गई। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में ऊर्जा मंत्री जोएल सैंटोस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) के महानिदेशक और 23 सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन परिषद (सीएनसीसीएमडीएल) के कार्यकारी उपाध्यक्ष मैक्स पुइग के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 03-05 नवंबर को नई दिल्ली में आईएसए की 7^{वीं} सभा में भाग लिया।

ग्रेनेडा

ग्रेनेडा के प्रधानमंत्री डिकॉन मिशेल और प्रधानमंत्री ने 20 नवंबर को गुयाना में आयोजित दूसरे भारत-कैरिबिअन शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता की।

दोनों नेताओं ने शिखर सम्मेलन के दौरान एक अलग द्विपक्षीय बैठक की और आपसी हितों के कई मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री ने 27 सितंबर को न्यूयॉर्क में भारत-कैरिबिअन विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान अपने ग्रेनेडियन समकक्ष जोसेफ एंडल से मुलाकात की। मंत्री एंडल ने 17 अगस्त को वर्चुअल रूप में आयोजित तीसरे वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के विदेश मंत्रियों के सत्र में भाग लिया।

जलवायु प्रतिरोधकता, पर्यावरण और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री केरीन जेड. जेम्स ने 03-06 नवंबर को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) की 7^{वीं} सभा में भाग लिया। एलएसी क्षेत्र के लिए आईएसए के दो उपाध्यक्षों में से एक ग्रेनेडा को चुना गया।

विदेश राज्य मंत्री (पीएम) ने 03-05 अक्टूबर को ग्रेनेडा का आधिकारिक दौरा किया, जिसके दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मिशेल और विदेश मामलों, व्यापार एवं निर्यात विकास मंत्री जोसेफ एंडल से मुलाकात की। विदेश राज्य मंत्री (पीएम) ग्रेनेडा की संसद के तीसरे सत्र के औपचारिक उद्घाटन में भी उपस्थित रहे और गवर्नर-जनरल सेसिल ला ग्रेनेड और अन्य नेताओं के साथ बातचीत की। विदेश राज्य मंत्री (पीएम) ने ग्रेनेडा में रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी बातचीत की।

ग्रेनेडा ने वर्ष के दौरान भारत में अपना पहले गैर-आवासीय उच्चायुक्त, गीता किशोर कुमार पसुपुलेटी को नियुक्त किया, जिन्होंने 25 नवंबर को माननीय राष्ट्रपति जी को अपना परिचय-पत्र प्रस्तुत किया।

गुयाना

गुयाना के प्रधानमंत्री ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) मार्क फिलिप्स 06-11 फरवरी को भारत आए। उन्होंने माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री तथा विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री से मुलाकात की। उन्होंने नई दिल्ली में टीईआरआई द्वारा आयोजित विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में मुख्य वक्ता के रूप में भाग लिया।

प्रधानमंत्री ने 19-21 नवंबर को गुयाना की सफल राजकीय यात्रा की, जहां उन्होंने गुयाना के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद इरफान अली के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। प्रधानमंत्री को गुयाना के राष्ट्रपति द्वारा गुयाना के सर्वोच्च पुरस्कार 'ऑर्डर ऑफ़ द एक्सीलेंस' से सम्मानित किया गया और उन्होंने गुयाना की नेशनल असेंबली के साथ-साथ भारतीय समुदाय और प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अली ने स्टेट हाउस में 'एक पेड़ मां के नाम' पहल के तहत एक पौधा लगाया। यात्रा के दौरान, दोनों देशों ने कुल दस करारों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें हाइड्रोकार्बन एवं ऊर्जा, स्वास्थ्य एवं फार्मास्यूटिकल्स, कृषि, डिजिटल सहयोग, संस्कृति और रक्षा एवं सुरक्षा अध्ययन जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

प्राकृतिक संसाधन मंत्री विक्रम भरत 07 फरवरी को गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह के दौरान ग्लोबल साउथ एनर्जी मिनिस्ट्रीयल राउंडटेबल के लिए भारत आए। उन्होंने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री से मुलाकात की। आवास एवं जल मंत्री कोलिन क्रोल सितंबर में भारत जल सप्ताह में भाग लेने के लिए दिल्ली आए और कार्यक्रम के दौरान जल शक्ति मंत्री से मिले।

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ब्रिगेडियर उमर खान 04-09 नवंबर तक भारत दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने रक्षा सचिव, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल, सेना प्रमुख जनरल, नौसेना प्रमुख एडमिरल और वायु सेना प्रमुख के साथ बैठकें कीं। उन्होंने पुणे, कानपुर और दिल्ली में विभिन्न रक्षा विनिर्माण सुविधाओं का भी दौरा किया।

विकास साझेदारी के अंतर्गत भारत ने मार्च माह में गुयाना को दो एचएएल-228 डोर्नियर विमान सफलतापूर्वक सौंपे।

गुयाना ने सितंबर में आयोजित अभ्यास तरंग शक्ति और 23 सितंबर से 5 अक्टूबर तक एनडीसी, नई दिल्ली में आयोजित इन-स्टेप स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट कार्यक्रम में भाग लिया।

2023-24 में, आई.टी.ई.सी. कार्यक्रम के तहत, गुयाना के अधिकारियों के लिए तीन अनुकूलित पाठ्यक्रम अर्थात; चावल मिलिंग और चावल मूल्य संवर्धन, फॉरेसिक जांच में शारीरिक साक्षात्कार तकनीक और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड/पीएसओसी-पीएस आयोजित किए गए। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय फॉरेसिक विज्ञान विश्वविद्यालय, गांधीनगर के दो प्रोफेसरों ने पॉलीग्राफी में प्रशिक्षण देने के लिए गुयाना का दौरा किया और जन सूचना विभाग के 15 सदस्यीय मीडिया पेशेवरों की एक टीम ने मीडिया ट्रेलिंग के लिए भारत का दौरा किया।

हैती

हैती के पर्यावरण मंत्रालय के महानिदेशक जोसेफ इमैनुएल फिलिप ने 17 अगस्त को तीसरे वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के पर्यावरण मंत्रियों के सत्र में भाग लिया।

हैती के पर्यावरण मंत्रालय में निदेशक व्लादिमीर चेरी ने 03-05 नवंबर को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) की 7^{वीं} सभा में भाग लिया।

हैती में सुरक्षा की स्थिति खराब होने और हैती से आने-जाने वाली सभी वाणिज्यिक उड़ानों के निलंबन के कारण, हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए मंत्रालय ने 22 मार्च को ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया था। मार्च और अप्रैल में कुल 17 भारतीय नागरिकों को डोमिनिकन गणराज्य पहुंचाया गया।

अगस्त में, भारत सरकार ने हैती के सार्वजनिक स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्रालय के राष्ट्रीय रक्तआधान सुरक्षा कार्यक्रम को सहायता प्रदान करने के लिए लगभग 83,000 अमेरिकी डॉलर मूल्य की 9 टन रक्तआधान संबंधी आवश्यक सामग्री, इम्यूनोहेमेटोलॉजी के लिए अभिकर्मक, त्वरित परीक्षण, एलिसा और अन्य वस्तुएं दान कीं।

जमैका

जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस ने प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक भारत का आधिकारिक दौरा किया। यह जमैका

के किसी प्रधानमंत्री की भारत की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। यात्रा के दौरान, उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और माननीय राष्ट्रपति जी और माननीय उपराष्ट्रपति से भेंट की। उन्होंने नई दिल्ली में "जमैका मार्ग" के रूप में नव नामित सड़क का उद्घाटन किया, जो दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता का प्रतीक है। सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम, खेल, डिजिटल भुगतान प्रणाली और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्र में चार समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। उन्होंने सारनाथ तथा राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय और वाराणसी में दशाश्वमेध घाट का दौरा किया। यह यात्रा भारत-जमैका द्विपक्षीय संबंधों में एक नए युग की शुरुआत है।

विदेश मामले एवं विदेश व्यापार मंत्री कामिना जॉनसन स्मिथ और शिक्षा मंत्री फेवल विलियम्स ने 17 अगस्त को भारत द्वारा आयोजित तीसरे वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन में क्रमशः विदेश मंत्रियों और शिक्षा मंत्रियों के सत्रों में भाग लिया। मंत्री जॉनसन स्मिथ ने जॉर्जटाउन, गुयाना में आयोजित दूसरे भारत-कैरिबियन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जमैका के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी किया और शिखर सम्मेलन के दौरान विदेश मंत्री से मुलाकात की।

मिशन ने 13 दिसंबर को "भारत जमैका व्यापार अवसर: 2047 तक विकसित भारत की ओर: विकसित भारत" शीर्षक से एक व्यावसायिक कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में जमैका के 250 कैबिनेट मंत्रियों, जमैका प्रमोशन कॉरपोरेशन (जैमप्रो) के सदस्यों, संसद सदस्यों, व्यापारिक समुदाय और मीडिया के सदस्यों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में गुरुदेव श्री श्री रविशंकर, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन द्वारा जमैका के व्यापारिक समुदाय के साथ संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापार और नैतिकता संवाद सत्र भी शामिल था।

सेंट किट्स एंड नेविस

सेंट किट्स एंड नेविस के विदेश मंत्री डेन्ज़िल डगलस ने 04-09 अगस्त को भारत का दौरा किया, जो सेंट किट्स एंड नेविस से भारत की पहली विदेश मंत्री स्तरीय यात्रा थी। मंत्री डगलस ने विदेश मंत्री से मुलाकात की और स्वास्थ्य, आईटी, खेल, वाणिज्य, उपभोक्ता मामले, कृषि और खाद्य सुरक्षा में दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। विदेश मंत्री डगलस ने स्वास्थ्य, उपभोक्ता मामले, युवा एवं खेल मंत्री और वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री से भी मुलाकात की। प्रमुख परिणाम के रूप में, यात्रा के दौरान तीन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए, अर्थात् - खेल सहयोग पर समझौता ज्ञापन, इंडिया स्टैक पर करार और विदेश कार्यालय परामर्श पर समझौता ज्ञापन।

सेंट लूसिया

प्रधानमंत्री ने 20 नवंबर को जॉर्जटाउन, गुयाना में द्वितीय भारत-कैरिबियन नेताओं के शिखर सम्मेलन के अवसर पर सेंट लूसिया के प्रधानमंत्री फिलिप जे. पियरे के साथ द्विपक्षीय चर्चा की।

सेंट लूसिया के शिक्षा, सतत विकास, नवाचार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण मंत्री शॉन ए. एडवर्ड ने 17 अगस्त को शिक्षा मंत्री द्वारा आयोजित तीसरे वॉयस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन में शिक्षा मंत्रियों के सत्र में भाग लिया।

लैटिन अमेरिकी और कैरिबियन (एलएसी) के अपर सचिव ने 07 मई को पारामारिबो में कैरिबियन राष्ट्र संघ (एसीएस-ईसीसी) मंत्रिस्तरीय बैठक के अवसर पर सेंट लूसिया के विदेश मंत्री, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं नागरिक उड्डयन मंत्री अल्वा आर. बैपटिस्ट से मुलाकात की।

भारत-यूएनडीपी कोष के तहत, "कमजोर स्थिति वाले युवाओं के लिए प्रभावशाली व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सेंट लूसिया की क्षमता को उन्नत करना" नामक परियोजना सफलतापूर्वक पूरी की गई। 16 अप्रैल को सेंट लूसिया और भारत के बीच राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट करार पर हस्ताक्षर किए गए।

सेंट विसेंट एवं ग्रेनेडाइंस (एसवीजी)

सेंट विसेंट एवं ग्रेनेडाइंस के प्रधानमंत्री राल्फ एवार्ड गोंजाल्विस ने 20 नवंबर को जॉर्जटाउन में आयोजित दूसरे भारत-कैरिबिअन शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने की। 26 सितंबर को विदेश मंत्री ने एल-69 और सी-10 समूहों की संयुक्त मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान 79^{वें} यूएनजीए के अवसर पर प्रधानमंत्री राल्फ ई. गोंजाल्विस से मुलाकात की।

पूर्वी कैरेबियाई राष्ट्रों के संगठन (ओईसीएस) के अध्यक्ष और सेंट विसेंट एवं ग्रेनेडाइंस सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री रेने मर्सिडीज बैपटिस्ट मार्च में विशिष्ट आगंतुक कार्यक्रम पर भारत आए।

भारत ने सेंट विसेंट एवं ग्रेनेडाइंस में 01 जुलाई को आए तूफान बेरिल के विनाशकारी प्रभावों के प्रत्युत्तर में सेंट विसेंट एवं ग्रेनेडाइंस को मानवीय सहायता प्रदान की। 27 सितंबर को 10 टन राहत सामग्री लेकर एक विमान एसवीजी पहुंचा और लगभग 50 टन अतिरिक्त आपूर्ति समुद्री मार्ग से भेजी गई।

भारत से कृषि प्रसंस्करण मशीनरी की आपूर्ति के माध्यम से लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई) के विकास के लिए 30 अक्टूबर को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास भागीदारी निधि के तहत एरोरूट उद्योग आधुनिकीकरण परियोजना संपन्न हुई। इसका उद्देश्य जलवायु प्रतिरोधकता बनाना और स्वदेशी समुदायों के लिए स्थायी आजीविका को बढ़ावा देना है।

एसवीजी में अन्य विकास पहलों को सुविधाजनक बनाने के लिए त्वरित प्रभाव परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक नए व्यापक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। भारत ने एसवीजी में चार त्वरित प्रभाव परियोजनाओं (क्यूआईपी) को सफलतापूर्वक लागू किया, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे सहित विभिन्न क्षेत्रों को लाभ हुआ।

सूरीनाम

05 जून को, सूरीनाम ने पारामारिबो में भारतीय अप्रवासी लोगों के आगमन की 151^{वीं} वर्षगांठ पर कई कार्यक्रम आयोजित किए। सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिकाप्रसाद संतोखी ने अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ मिलकर सूरीनाम के विकास में उनके योगदान को याद करते हुए पहले भारतीय अप्रवासियों को पुष्पांजलि अर्पित की। जून में प्रधानमंत्री के मन की बात संबोधन में इसका विशेष उल्लेख किया गया।

17 अगस्त को राष्ट्रपति संतोखी ने वीडियो संदेश के माध्यम से तीसरे वॉयस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के नेताओं के सत्र में भाग लिया और पर्यावरण एवं स्थानिक नियोजन मंत्री मार्सियानो दासई ने शिखर सम्मेलन के पर्यावरण मंत्रियों के सत्र में भाग लिया। शिखर सम्मेलन वर्चुअल रूप में आयोजित किया गया था।

प्रधानमंत्री ने 20 नवंबर को जॉर्जटाउन, गुयाना में द्वितीय भारत-कैरिबिअन नेताओं के शिखर सम्मेलन के अवसर पर राष्ट्रपति संतोखी से मुलाकात की।

विदेश मंत्री ने 27 सितंबर को 79^{वें} संयुक्त राष्ट्र महासभा के अवसर पर भारत-कैरिबिअन विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान सूरीनाम के विदेश मंत्री अल्बर्ट रामदीन से मुलाकात की।

सूरीनाम की नेशनल असेंबली के चेयरमैन मैरिनस बी के नेतृत्व में एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल 04-08 फरवरी को भारत आया। प्रतिनिधिमंडल ने लोकसभा अध्यक्ष के साथ-साथ राज्यसभा के सभापति से भी मुलाकात की। यह अयोध्या में राम मंदिर का दौरा करने वाला पहला विदेशी प्रतिनिधिमंडल था।

अपर सचिव, एलएसी ने 06-09 मई को पारामारिबो में कैरेबियाई देशों के संगठन (एसीएस) की बैठकों में विदेश मंत्री का प्रतिनिधित्व किया। प्रतिनिधिमंडल ने ग्रेटर कैरिबियन के 16^{वें} बिजनेस फोरम, 8^{वें} अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सम्मेलन और एसीएस की मंत्रिस्तरीय परिषद की 29^{वीं} साधारण बैठक के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। उन्होंने सूरीनाम के विदेश मंत्री अल्बर्ट रामदीन के साथ अलग से द्विपक्षीय बैठक भी की।

सूरीनाम के सशस्त्र बलों के प्रमुख कर्नल कियो ए. सेन ने सितंबर में भारत में आयोजित तरंग शक्ति अभ्यास में भाग लिया।

लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई) के विकास के लिए 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान के तहत द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

लिनिदाद और टोबैगो (टीएंडटी)

लिनिदाद और टोबैगो (टीएंडटी) के प्रधानमंत्री कीथ रोले ने व्यापार और निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए मई में मुंबई का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री रोले ने महाराष्ट्र के राज्यपाल से भी मुलाकात की।

प्रधानमंत्री रोले ने 20 नवंबर को जॉर्जटाउन, गुयाना में दूसरे भारत-कैरिबिअन शिखर सम्मेलन में भाग लिया और प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर

चर्चा की। उन्होंने निनिदाद और टोबैगो में एकीकृत स्वचालित फल और सब्जी प्राथमिक प्रसंस्करण गतिविधियों की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान किया।

विदेश एवं कैरीकॉम मामलों के मंत्री अमेरी ब्राउन ने 27 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान आयोजित भारत-कैरीकॉम विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री से मुलाकात की।

डिजिटल परिवर्तन के क्षेत्र में चल रहे द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए डिजिटल परिवर्तन मंत्री हासेल बाक्स ने 23-29 जनवरी को भारत में दूसरे तकनीकी मिशन का नेतृत्व किया। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (एनआईपीएल) ने 26 सितंबर को पोर्ट ऑफ स्पेन में टीएंडटी के डिजिटल परिवर्तन मंत्रालय के साथ तकनीकी लाइसेंस करारका आदान-प्रदान किया, जिससे टीएंडटी, कैरीकॉम क्षेत्र में यूपीआई अपनाने वाला पहला देश बन गया।

विदेश राज्य मंत्री (पीएम) ने 23-24 अगस्त को निनिदाद और टोबैगो का आधिकारिक दौरा किया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री कीथ रोले से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा करने के लिए मंत्री ब्राउन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस यात्रा के दौरान राजनयिक

मिशन या कौंसली केंद्र के सदस्यों के आश्रितों के लिए लाभकारी रोजगार में नियोजन हेतु प्राधिकार के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। विदेश राज्य मंत्री (पीएम) ने सीनेट के अध्यक्ष निगेल डी फ्रीटस और प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष ब्रिजिड एनीसेट-जॉर्ज से भी मुलाकात की। इसके अतिरिक्त, उन्होंने एक समारोह में देश में रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी बातचीत की।

डिजिटल परिवर्तन मंत्रालय के स्थायी सचिव कोरी बेलफोंट ने 17 अगस्त को तीसरे वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन में भाग लिया।

भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता से, भारत-यूएनडीपी कोष के तहत 'उच्च एवं निम्न प्रौद्योगिकी लाने (एचएएलटी)' की प्रमुख परियोजना 17 अगस्त को टीएंडटी के स्वास्थ्य मंत्री टेरेस देयालसिंह को 6 स्वास्थ्य सेवा रोबोट सौंपे जाने के बाद पूरी हो गई।

मिशन द्वारा भारत और कैरेबियाई क्षेत्र के विद्वानों की भागीदारी के साथ 06-08 सितंबर को पोर्ट ऑफ स्पेन में एक अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय हिंदी सम्मेलन (आईआरएचसी) का आयोजन किया गया।

अध्याय

10

भारत-प्रशांत

भारत-प्रशांत के लिए भारत के दृष्टिकोण में एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम-आधारित भारत-प्रशांत पर ध्यान केंद्रित किया गया है। भारत क्षेत्र के सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान, सभी देशों की समानता, विवादों के शांतिपूर्ण समाधान, बल के उपयोग या उपयोग की धमकी से बचने और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, नियमों और विनियमों का पालन करने पर बल देता है। भारत का उद्देश्य क्षेत्र के सभी देशों और इसमें रुचि रखने वाले देशों के साथ बहुआयामी जुड़ाव है, जिसमें राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक एवं सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्र शामिल हैं, इसका उद्देश्य क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास (सागर) है।

वर्ष 2024 में एक्ट ईस्ट नीति का एक दशक पूरा होने जा रहा है। भारत-प्रशांत ढांचे के तहत विभिन्न तलों में भारत की भागीदारी में लगातार वृद्धि देखी गई है, जिसमें अन्यो के साथ-साथ दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान), पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस), हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (आईओआरए), एशिया-यूरोप बैठक (एएसईएम), मेकांग-गंगा सहयोग (एमजीसी), हिंद महासागर आयोग (आईओसी), अयेयावाडी-चाओ फ्राया-मेकांग आर्थिक सहयोग रणनीति (एसीएमईसीएस) और इंडोनेशिया-मलेशिया-थाईलैंड प्रगति त्रिकोण (आईएमटी-जीटी) शामिल हैं।

दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान)

आसियान के साथ भारत का संबंध इसकी विदेश नीति का एक प्रमुख स्तंभ है और इसकी एक्ट ईस्ट नीति तथा उसके बाद इस पर निर्मित भारत-

प्रशांत दृष्टिकोण की आधारशिला है। भारत भारत-प्रशांत में विकसित हो रही संरचना में आसियान की एकता और केंद्रीयता का समर्थन करता है। आसियान के साथ भारत का औपचारिक जुड़ाव 1992 में क्षेत्रीय वार्ता भागीदार के रूप में और उसके बाद 1996 में वार्ता भागीदार के रूप में शुरू हुआ, जिसे 2002 में शिखर सम्मेलन स्तर, 2012 में रणनीतिक साझेदारी और 2022 में व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक उन्नत किया गया।

भारत और आसियान के बीच सभी स्तरों पर व्यापक भागीदारी है, जिसमें सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में आधिकारिक स्तर की वार्ताओं के अतिरिक्त विदेश, वाणिज्य, पर्यटन, कृषि, डिजिटल और रक्षा क्षेत्रों में छह मंलिस्तरीय भागीदारी शामिल हैं।

आसियान के साथ जुड़ाव एक बहुस्तरीय संपर्क प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के शीर्ष पर वार्षिक भारत-आसियान शिखर सम्मेलन है, जिसे भारत-आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक और भारत-आसियान वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक द्वारा समर्थित किया जाता है। प्रधानमंत्री, 10 अक्टूबर को लाओ पीडीआर के वियनतियाने में आयोजित 21^{वें} भारत-आसियान शिखर सम्मेलन में भारत-आसियान व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा करने और सहयोग की भविष्य की दिशा निर्धारित करने के लिए आसियान नेताओं के साथ सम्मिलित हुए। यह प्रधानमंत्री की आसियान नेताओं के साथ 11^{वें} मुलाकात थी। इस अवसर पर दो संयुक्त वक्तव्य जारी किए गए: (i) भारत की एक्ट ईस्ट नीति (एईपी) की सहायता से भारत-प्रशांत पर आसियान दृष्टिकोण (एओआईपी) के संदर्भ में क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए भारत-आसियान व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना (ii)



पहला भारत-आसियान महिला वैज्ञानिक सम्मेलन अप्रैल 2024 में सिंगापुर में आयोजित किया गया।

डिजिटल परिवर्तनशीलता को आगे बढ़ाना। विदेश मंत्री ने भारत-आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक और तत्पश्चात मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए 25-27 जुलाई को वियनतियाने की यात्रा की।

भारत और आसियान के बीच गहन सभ्यतागत संबंधों को विभिन्न पहलों के माध्यम से और मजबूत किया गया है, जिसमें पांच आसियान देशों में साझा सांस्कृतिक विरासत की बहाली और विभिन्न जन-केंद्रित कार्यक्रमों का आयोजन शामिल है। लोगों के बीच आपसी जुड़ाव की दिशा में कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में 24-26 अप्रैल को सिंगापुर में आयोजित भारत-आसियान महिला वैज्ञानिक सम्मेलन, 06-08 नवंबर को मुंबई में वार्षिक राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड बैठक के लिए आसियान के कैंसर विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं की यात्रा थी।

सिंगापुर में 07-08 नवंबर को भारत-आसियान प्रबुद्ध मंडल नेटवर्क का 8^{वां} गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। आसियान के साथ भारत के जुड़ाव की अन्य मुख्य बातों में 29 नवंबर से 01 दिसंबर तक नई दिल्ली में आयोजित तीसरा भारत-आसियान संगीत समारोह; 03-05 जुलाई को बाली, इंडोनेशिया में भारत-आसियान स्केल-हब; 28-30 नवंबर को आयोजित चौथा भारत-आसियान स्टार्टअप महोत्सव; भारत-आसियान मीडिया एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत भारतीय मीडिया प्रतिनिधिमंडल का थाईलैंड और लाओ पीडीआर का दौरा और आसियान मीडिया प्रतिनिधिमंडल का भारत का दौरा तथा नालंदा विश्वविद्यालय में आसियान के लिए मास्टर्स छात्रवृत्ति स्लॉट को दोगुना करना शामिल हैं। पहली भारत-आसियान साइबर नीति वार्ता और डिजिटल भविष्य के लिए भारत-आसियान कोष की शुरुआत इस वर्ष की अन्य प्रमुख पहलें थीं।



विदेश मंत्री ने नवंबर 2024 में सिंगापुर में भारत-आसियान प्रबुद्ध मंडल नेटवर्क के 8^{वें} गोलमेज सम्मेलन में मुख्य वक्तव्य दिया।

आसियान एक प्रमुख व्यापार भागीदार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और पर्यटक प्रवाह के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत और गंतव्य के रूप में उभरा है। कुछ आसियान सदस्य देश महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी साझेदार के रूप में भी उभरे हैं। आसियान के साथ संपर्क में सुधार करना भारत का फोकस रहा है। वर्तमान में सात सदस्य देशों के लिए सीधी उड़ानें हैं। उभरते हुए फिनटेक सहयोग और डिजिटल कनेक्टिविटी से आसियान के साथ साझेदारी और मजबूत होगी।

सहयोग को और बढ़ाने के लिए भारत-आसियान वस्तु व्यापार करार की समीक्षा की जा रही है, जबकि समुद्री, साइबर सुरक्षा, डिजिटल अर्थव्यवस्था के साथ-साथ नए और उभरते क्षेत्रों सहित कई क्षेत्रों में व्यावहारिक सहयोग बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, 21^{वें} भारत-आसियान शिखर सम्मेलन में की गई घोषणाओं में वर्ष 2025 को भारत-आसियान पर्यटन वर्ष के रूप में मनाना और नई भारत-आसियान कार्य योजना (2026-2030) को अंतिम रूप देना शामिल है, जो भारत-आसियान व्यापक रणनीतिक साझेदारी की पूरी क्षमता का उपयोग करने में दोनों पक्षों का मार्गदर्शन करेंगी।

पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस)

2005 में स्थापित, शीर्ष नेताओं के अगुवाई वाला ईएएस प्रारूप, मुख्य रूप से इस क्षेत्र में रणनीतिक विश्वास का माहौल बनाने में योगदान देने के कारण आसियान के नेतृत्व वाले ढांचे का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत ईएएस को एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी, पारदर्शी, नियम-आधारित, शांतिपूर्ण और समृद्ध भारत-प्रशांतक्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए तार्किक मंच के रूप में देखता है।

ईएएस के साथ भारत की भागीदारी एक बहुस्तरीय बातचीत प्रक्रिया है, जिसके शीर्ष तंत्र में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन है, जिसके साथ ईएएस विदेश मंत्रियों की बैठक (ईएएस एफएमएम) और ईएएस वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक (ईएएस एसओएम) आयोजित की जाती हैं।

11 अक्टूबर को, प्रधानमंत्री ने 19^{वें} पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जिसकी अध्यक्षता आसियान अध्यक्ष के रूप में लाओ पीडीआर ने की। प्रधानमंत्री ने आसियान की केंद्रीयता के लिए भारत के समर्थन को रेखांकित किया और एक स्वतंत्र, खुले और नियम-आधारित भारत-प्रशांतक्षेत्र को सुनिश्चित करने का आह्वान किया। ईएएस तंत्र के महत्व को दोहराते हुए और इसे और मजबूत करने के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि करते हुए, प्रधानमंत्री ने नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार पर ईएएस भागीदार देशों से प्राप्त समर्थन का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर नालंदा विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले उच्च शिक्षा प्रमुखों के सम्मेलन के लिए ईएएस देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने भारत-प्रशांतक्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को प्रभावित करने वाले क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया। विकासशील देशों पर संघर्षों के गंभीर प्रभाव को रेखांकित करते हुए, प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि दुनिया में संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए मानवीय दृष्टिकोण पर आधारित संवाद और कूटनीति का रास्ता अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने आगे दोहराया कि युद्ध के मैदान में इन मुद्दों का कोई समाधान नहीं है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि साइबर और समुद्री चुनौतियों के साथ-साथ आतंकवाद, वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है, इसलिए देशों को इसका मुकाबला करने के लिए एकजुट होना चाहिए।



भारत-आईओआरए कूज पर्यटन सम्मेलन जून 2024 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया।



प्रधानमंत्री ने अक्टूबर 2024 में विएतियाम में आयोजित 19^{वें} पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लिया।

हिंद महासागर आयोग (आईओसी)

2020 में भारत, हिंद महासागर आयोग का पर्यवेक्षक सदस्य बन गया। भारत आईओसी में पश्चिमी हिंद महासागर के देशों के साथ पर्यवेक्षक के रूप में जुड़ाव जारी रखे हुए है।

हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (आईओआरए)

1997 में आईओआरए की स्थापना के बाद से ही भारत, इसका संस्थापक सदस्य है। भारत 2023-25 की अवधि के लिए हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के उपाध्यक्ष की भूमिका में है। भारत इस अवधि के दौरान समुद्री सुरक्षा तथा संरक्षा तथा समुद्री अर्थव्यवस्था संबंधी कार्य समूह का नेतृत्व भी कर रहा है। इन निर्णयों की घोषणा अक्टूबर 2023 में कोलंबो में आयोजित मंत्रिपरिषद् की बैठक के दौरान की गई थी, जिसमें विदेश मंत्री ने भाग लिया था। लिया। भारत ने 2023 भारत-प्रशांत पर आईओआरए के दृष्टिकोण की तैयारी में भी अग्रणी रहा और इसे लागू करने के लिए एक रोडमैप पर काम कर रहा है।

भारत-प्रशांत महासागर पहल (आईपीओआई)

01 जून 2018 को, प्रधानमंत्री ने सिंगापुर में सांगरी ला वार्ता में दिए गए अपने वक्तव्य में भारत-प्रशांत क्षेत्र के लिए भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित किया। भारत, भारत-प्रशांत क्षेत्र में एक स्वतंत्र, खुली और समावेशी व्यवस्था का आह्वान करता है, जो सभी देशों की संप्रभुता और

क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान, बातचीत के माध्यम से विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और अंतर्राष्ट्रीय नियमों एवं कानूनों के पालन पर आधारित हो। भारत-प्रशांत क्षेत्र के बारे में भारत की अवधारणा की प्रकृति समावेशी है, और एक ऐसे दृष्टिकोण का समर्थन करती है जो अंतरराष्ट्रीय समुद्रों में सभी के लिए नेविगेशन तथा उड़ान की स्वतंत्रता के अधिकार का सम्मान करता है। भारत का दृष्टिकोण क्षेत्र में साझा चुनौतियों के लिए साझा प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता को देखते हुए सहयोग और सहभागिता पर आधारित है, और यह 'आसियान-केंद्रीयता' के सिद्धांत पर आधारित है।

04 नवंबर 2019 को, प्रधानमंत्री ने बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित 14^{वें} पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत-प्रशांत महासागर पहल (आईपीओआई) का शुभारंभ किया। एक खुली वैश्विक पहल के रूप में आईपीओआई, समुद्री सुरक्षा; समुद्री पारिस्थितिकी; समुद्री संसाधन; क्षमता निर्माण और संसाधन साझाकरण; आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन; विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं शैक्षणिक सहयोग; और व्यापार संपर्क एवं समुद्री परिवहन के क्षेत्रों के लिए परिकल्पित सात केंद्रीय स्तंभों पर ध्यान केंद्रित करने हेतु मौजूदा क्षेत्रीय सहयोग संरचना और तंत्रों पर आधारित है।

आईपीओआई ढांचे के भीतर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए भारत के निमंत्रण पर प्रतिक्रिया देते हुए, कई देशों ने विभिन्न स्तंभों में नेतृत्वकारी भूमिका निभाई है। ब्रिटेन ने समुद्री सुरक्षा स्तंभ का सह-नेतृत्व करने पर सहमति व्यक्त की है; ऑस्ट्रेलिया समुद्री पारिस्थितिकी स्तंभ के शीर्ष पर है; फ्रांस और इंडोनेशिया ने संयुक्त रूप से समुद्री संसाधन स्तंभ का नेतृत्व करने पर सहमति व्यक्त की है; जर्मनी ने क्षमता निर्माण और संसाधन साझाकरण स्तंभ का नेतृत्व करने पर सहमति व्यक्त की है; सिंगापुर और इटली विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शैक्षणिक सहयोग स्तंभ का सह-नेतृत्व कर रहे हैं; और



सचिव (पूर्व) सितंबर-अक्टूबर 2024 में नई दिल्ली में आईएमटी-जीटी के साथ भारत की विकास साझेदारी के तहत "कंप्यूटर नेटवर्किंग प्रौद्योगिकी पर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण" संबंधी प्रशिक्षण मॉड्यूल के प्रतिभागियों के साथ।

जापान एवं अमेरिका व्यापार संपर्क और समुद्री परिवहन स्तंभ का सह-नेतृत्व कर रहे हैं।

2024 में थाईलैंड, समुद्री पारिस्थितिकी स्तंभ की सह-नेतृत्वकारी भूमिका के साथ आईपीओआई में शामिल हो गया और बांग्लादेश ने भारत के साथ आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन स्तंभ का सह-नेतृत्व करने का निर्णय किया। ग्रीस भी आईपीओआई का सदस्य बन गया है।

मेकांग गंगा सहयोग (एमजीसी)

2000 में स्थापित, मेकांग-गंगा सहयोग (एमजीसी) मेकांग उप-क्षेत्र में सबसे पुराना उप-क्षेत्रीय तंत्र है। 2024 में, भारत ने शिक्षा कार्य समूह और जल संसाधन प्रबंधन कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित की, जिसका वह अध्यक्ष है। सहयोग के दस चिन्हित क्षेत्रों के लिए दस कार्य समूह हैं। 2024 में एमजीसी व्यापार परिषद की भी स्थापना की गई।

एमजीसी के तहत, भारत कई छोटी अवधि की, उच्च प्रभाव वाली परियोजनाओं को लागू करता है जिन्हें त्वरित प्रभाव परियोजनाएं (क्यूआईपी) कहा जाता है। एक वर्ष तक की सामान्य अवधि वाली ये परियोजनाएं स्थानीय समुदायों को सीधे लाभान्वित करती हैं, जिनके परिणाम तत्काल और दृश्यमान होते हैं। इस योजना के तहत, प्रत्येक सीएलएमवी (कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम) देश को वर्तमान में प्रति वर्ष अधिकतम 10 परियोजनाएं शुरू करने की पेशकश की जाती है, जिसकी

लागत प्रति परियोजना 50,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक नहीं होगी। 2016 से अब तक ऐसी 121 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। क्षमता निर्माण के लिए, भारत 2005 से एमजीसी देशों के छात्रों को इतिहास एवं संस्कृति, पर्यटन, आईटी, व्यावसायिक प्रशिक्षण, इंजीनियरिंग, प्रबंधन, शिक्षक प्रशिक्षण, फिल्म निर्देशन आदि में डिप्लोमा और डिग्री पाठ्यक्रम करने के लिए प्रति वर्ष 50 एमजीसी छात्रवृत्ति प्रदान कर रहा है।

इंडोनेशिया-मलेशिया-थाईलैंड प्रगति त्रिकोण (आईएमटी-जीटी)

इंडोनेशिया-मलेशिया-थाईलैंड प्रगति त्रिकोण (आईएमटी-जीटी) उप-क्षेत्रीय सहयोग की स्थापना 2005 में की गई थी, जिसका उद्देश्य इस उप-क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य के अधिक एकीकरण के माध्यम से भाग लेने वाले देशों में आर्थिक विकास को गति देना और सुविधाजनक बनाना था। भारत, सितंबर 2022 में आईएमटी-जीटी के पहले विकास भागीदार के रूप में शामिल हुआ। “कंप्यूटर नेटवर्किंग प्रौद्योगिकी पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण”, नामक पहला अर्ली हावैस्ट प्रोजेक्ट (ईएचपी), भारत द्वारा 23 सितंबर से 04 अक्टूबर तक नई दिल्ली में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ़ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सी-डैक) में आयोजित किया गया था, जो 2024-25 के लिए आईएमटी-जीटी के साथ भारत की विकास भागीदारी के तहत अर्ली हावैस्ट प्रोजेक्ट्स (ईएचपी) का हिस्सा है।

अध्याय

11

बिस्स्टेक और सार्क

बिस्स्टेक

बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग पहल (बिस्स्टेक), बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और आसन्न क्षेत्रों में स्थित सात सदस्य राष्ट्रों का समूह है। यह संगठन 6 जून 1997 को 'बैंकॉक घोषणापत्र' के माध्यम से अस्तित्व में आया। अब तक पांच बिस्स्टेक शिखर सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं - 2004 (बैंकॉक), 2008 (नई दिल्ली), 2014 (ने प्पी ताओ), 2018 (काठमांडू) और 2022 (कोलंबो-वर्चुअल)। भारत ने अक्टूबर 2016 में गोवा में बिस्स्टेक आउटरीच शिखर सम्मेलन और लीडर्स रिट्रीट की मेजबानी की। 5^{वां} बिस्स्टेक शिखर सम्मेलन 30 मार्च 2022 को कोलंबो, श्रीलंका में आयोजित किया गया। नेताओं ने शिखर सम्मेलन में वर्चुअल रूप से भाग लिया।

शिखर सम्मेलन में नेताओं ने बिस्स्टेक चार्टर को अंगीकार किया, जो बिस्स्टेक के एक समूह से एक क्षेत्रीय संगठन में परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। बिस्स्टेक चार्टर 20 मई को लागू हुआ। छठा बिस्स्टेक शिखर सम्मेलन 4 सितंबर को बैंकॉक में आयोजित होने वाला था, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया।

महत्वपूर्ण बैठकें

भारत ने 11 और 12 जुलाई को नई दिल्ली में बिस्स्टेक विदेश मंत्रियों की दूसरी रिट्रीट की मेजबानी की। भारत ने 27 सितंबर को न्यूयॉर्क में यूएनजीए के 79^{वें} सत्र के दौरान बिस्स्टेक विदेश मंत्रियों की पहली अनौपचारिक

बैठक की मेजबानी की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने म्यांमार में 24-26 जुलाई को आयोजित चौथी बिस्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों (बीएनएससी) बैठक में भाग लिया। भारत ने 11 सितंबर को नई दिल्ली में बंगाल की खाड़ी में समुद्री सुरक्षा सहयोग पर विशेषज्ञ समूह की तीसरी बैठक की मेजबानी की। बिस्स्टेक के भविष्य की दिशा पर बिस्स्टेक प्रख्यात व्यक्तियों के समूह की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

भारत द्वारा 5-10 फरवरी को नई दिल्ली में बिस्स्टेक युवा जल क्रीड़ा 2024 का आयोजन किया गया। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के साथ साझेदारी में पहला बिस्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन 06-08 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारत ने मुंबई, भारत में राष्ट्रीय कैसर ग्रिड (एनसीजी) की वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए बिस्स्टेक देशों के कैसर देखभाल पेशेवरों के लिए एक एक्सपोजर यात्रा की मेजबानी की।

सचिव (पूर्व) ने 19 दिसंबर 2024 को थाईलैंड द्वारा वर्चुअल रूप से आयोजित बिस्स्टेक वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक के 24^{वें} सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

सार्क

भारत सार्क का संस्थापक सदस्य है। सार्क के साथ भारत की भागीदारी इसकी 'पड़ोस प्रथम' नीति के अनुरूप है।

सार्क प्रोग्रामिंग समिति की 59^{वीं} बैठक लगभग तीन वर्षों के बाद 06 और 07 मार्च 2024 को काठमांडू में आयोजित की गई।



केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री ने नई दिल्ली में पहली बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। फरवरी 2024।

सार्क महासचिव श्री मोहम्मद गुलाम सरवर 11-15 मई को भारत आए और तत्कालीन राज्य मंत्री (आरआरएस), विदेश सचिव और सचिव (पूर्व) से मुलाकात की। उन्होंने 11-13 नवंबर को भी नई दिल्ली का दौरा किया

और विदेश मंत्रालय के सचिव (पूर्व) से मुलाकात की।

भारत ने वर्ष के दौरान विशेषज्ञ स्तर पर कई सार्क बैठकों में भाग लिया।

अध्याय

12

संयुक्त राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन

संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79^{वाँ} सत्र

कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री फिलेमोन यांग को 06 जून को महासभा (पीजीए) के 79^{वें} सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। महासभा (यूएनजीए) का 79^{वाँ} सत्र 10 सितंबर को शुरू हुआ। सत्र का विषय था "हर जगह और सभी

के लिए शांति, सतत विकास और मानवीय गरिमा को आगे बढ़ाने के लिए एकता और विविधता।" भारत ने इस सत्र में सक्रिय रूप से भाग लिया और वैश्विक दक्षिण को प्रभावित करने वाले मुद्दों सहित अन्य प्रासंगिक मुद्दों पर सत्र में अपनी स्थिति को प्रभावी ढंग से व्यक्त किया।



प्रधानमंत्री ने सितंबर 2024 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के भविष्य के शिखर सम्मेलन में अपना भाषण दिया



विदेश मंत्री ने सितंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79^{वें} सत्र में भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य दिया

इस वर्ष के यूएनजीए सत्र का मुख्य आकर्षण 'भविष्य का शिखर सम्मेलन' था, जो सितंबर में 79^{वें} यूएनजीए के उच्च स्तरीय सप्ताह के दौरान आयोजित एक उच्च स्तरीय कार्यक्रम था, जिसमें विभिन्न विश्व नेता एक मंच पर आए। प्रधान मंत्री ने शिखर सम्मेलन को संबोधित किया और सतत विकास के लिए भारत के मानव-केंद्रित दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। प्रधान मंत्री ने वैश्विक दक्षिण के देशों के साथ एकजुटता भी व्यक्त की और प्रौद्योगिकी के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देने के लिए संतुलित नियमों का आह्वान किया। उन्होंने उल्लेख किया कि भारत व्यापक सार्वजनिक भलाई के लिए अपने डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को साझा करने के लिए तैयार है। प्रधान मंत्री ने जोर देकर कहा कि "सुधार प्रासंगिकता की कुंजी है" और "वैश्विक कार्रवाई, वैश्विक महत्वाकांक्षा के अनुरूप होनी चाहिए"।

इस शिखर सम्मेलन में 5 कार्य बिंदुओं के साथ "भविष्य के लिए समझौता" को अंगीकार किया गया। ये थे, सतत विकास और विकास के लिए वित्तपोषण, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा; विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार एवं डिजिटल सहयोग, युवा और भविष्य की पीढ़ियाँ, और वैश्विक शासन में बदलाव। इस समझौते के अलावा, दो अन्य दस्तावेज़, वैश्विक डिजिटल कॉम्पैक्ट और भविष्य की पीढ़ियों के लिए घोषणा संबंधी समझौते को शामिल किया गया।

प्रधानमंत्री ने नेपाल के प्रधानमंत्री और कुवैत के क्राउन प्रिंस सहित अनेक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी कीं। उन्होंने फिलिस्तीन, वियतनाम और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों से भी मुलाकात की।

विदेश मंत्री ने 79^{वें} सत्र में उच्च स्तरीय सप्ताह के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया और 28 सितंबर को न्यूयॉर्क में 79^{वें} यूएनजीए के उच्च

स्तरीय खंड की आम बहस को संबोधित किया। विदेश मंत्री ने अपने वक्तव्य में विश्व के सामने आने वाली अभूतपूर्व चुनौतियों और डिजिटल नवाचार, जन-केंद्रित नीतियों और वंचित समूहों के सशक्तिकरण की परिवर्तनकारी क्षमता का लाभ उठाने में भारत की उपलब्धियों का उल्लेख किया। विदेश मंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि आधुनिक संयुक्त राष्ट्र को सहयोग, समान विकास और संघर्ष के समाधान को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि कोई भी पीछे न छूटे और बेहतर भविष्य का निर्माण हो सके।

यूएनजीए के अवसर पर विदेश मंत्री ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री से मुलाकात की और अल्जीरिया, बोलीविया, बांग्लादेश, बेलारूस, बुरुंडी, क्यूबा, साइप्रस, डेनमार्क, मिस्र, इथियोपिया, अल साल्वाडोर, फ्रांस, ग्रीस, जॉर्डन, माल्टा, मोटेनेग्रो और लिक्टेनस्टीन के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं। उन्होंने गुयाना, इराक, मोल्दोवा, मोरक्को, निकारागुआ, नीदरलैंड, उत्तरी मैसेडोनिया, पनामा, रोमानिया, रूस, तुर्कमेनिस्तान, सीरिया, स्वीडन, सोमालिया, स्लोवेनिया, सिंघापोर, स्विट्जरलैंड, यूएई, यूके, उज्बेकिस्तान, वेनेजुएला और यमन के विदेश मंत्रियों के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें कीं।

विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और पीजीए फिलोमेन यांग से भी मुलाकात की। विदेश मंत्री ने इस यात्रा के दौरान जी4, जी20, आईबीएसए, ब्रीक्स, कैरिकोम, सीईएलपीसी, एल69 + सी-10 और बिमस्टेक के विदेश मंत्रियों की बहुपक्षीय बैठकों में भी भाग लिया। इसके अतिरिक्त विदेश मंत्री ने उच्च स्तरीय सप्ताह के दौरान ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और एशिया सोसाइटी द्वारा आयोजित कार्यक्रमों को संबोधित किया।



विदेश मंत्री सितंबर 2024 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अवसर पर बिम्स्टेक देशों के विदेश मंत्रियों के साथ

विचार विमर्श और प्रक्रियाएँ

भारत ने बहस, वार्ता और प्रक्रियाओं में अपनी सक्रिय भागीदारी की। भारत के लिए विकास के मुद्दे, यूएनएससी सुधारों सहित बहुपक्षीय सुधार, भारत के फोकस और गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहे। भारत ने ऋण स्थिरता और सभी के लिए सामाजिक-आर्थिक समानता, विकास के लिए वित्तपोषण (एफएफडी4), सतत विकास के लिए आईसीटी, गरीबी उन्मूलन, कृषि विकास, खाद्य सुरक्षा और पोषण, समुद्र के स्तर में वृद्धि से उत्पन्न अस्तित्व संबंधी जोखिम जैसे प्रमुख मुद्दों पर अपने एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए चर्चाओं को आगे बढ़ाया। भारत की स्थिति मुख्य रूप से वैश्विक दक्षिण की विकास प्राथमिकताओं से प्रेरित थी और इसने एक अग्रणी दक्षिण-दक्षिण विकास भागीदार के रूप में हमारी बढ़ती स्थिति को प्रस्तुत करने का मार्ग प्रशस्त किया।

इस दौरान महिलाओं, बच्चों, जनसंख्या और शहरीकरण से संबंधित सामाजिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। शांति, सुरक्षा और राजनीतिक आयामों पर बहस में भारत की भागीदारी ने इन क्षेत्रों में भारत की पारंपरिक स्थिति को सुदृढ़ किया। सितंबर में उच्च स्तरीय सप्ताह के दौरान समुद्र के स्तर में वृद्धि से उत्पन्न अस्तित्व संबंधी जोखिमों पर आयोजित कार्यक्रम में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को प्रमाणित किया और जलवायु समानता और न्याय पर हमारे विचारों को रेखांकित किया। इसने जलवायु परिवर्तन पर हमारे नेतृत्व के विचार भी स्पष्ट हुए, जिसमें लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट (लाईफ) आंदोलन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए), सीडीआरआई और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन

(जीबीए) शामिल हैं। जलवायु वित्त के मुद्दों पर भारत ने हमारे प्रयासों के माध्यम से, वैश्विक दक्षिण की चिंताओं को दूर करने के लिए साझा लेकिन भिन्न-भिन्न जिम्मेदारी के सिद्धांत को भी स्पष्ट किया।

इसके अतिरिक्त फिलीस्तीन, गाजा जैसे प्रमुख भू-राजनीतिक मुद्दों पर बहस के दौरान बातचीत और कूटनीति पर भारत के पक्ष को महत्व दिया।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार

भारत ने अंतर-सरकारी वार्ता (आईजीएन) प्रक्रिया सहित सक्रिय भागीदारी द्वारा सुधारित बहुपक्षवाद, विशेष रूप से यूएनएससी सुधारों पर जोर दिया। भारत ने वैश्विक शासन में परिवर्तन करने से संबंधित भविष्य के लिए समझौते में पांचवें क्लस्टर पर भी ध्यान केंद्रित किया।

जी4, एल.69 और सी-10 जैसे सुधारोन्मुख समूहों के साथ भारत की पहुंच और समन्वय जारी है। विदेश मंत्री ने उच्च स्तरीय सप्ताह के दौरान न्यूयॉर्क में जी4 की मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। मंत्रियों ने पाठ-आधारित वार्ता के माध्यम से यूएनएससी सुधारों को तत्काल शुरू करने की आवश्यकता पर जोर दिया। एल.69 और सी-10 की पहली संयुक्त मंत्रिस्तरीय बैठक भी न्यूयॉर्क में आयोजित की गई। विदेश मंत्री ने समयबद्ध तरीके से ठोस परिणामों पर जोर देते हुए स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में व्यापक यूएनएससी सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया।



विदेशमंली ने सितंबर 2024 में न्यूयॉर्क में 79^{वाँ} यूएनजीए के अवसर पर एल-69 और सी-10 राष्ट्र समूहों की संयुक्त मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया।



10^{वाँ} अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, “स्वयं और समाज के लिए योग” थीम पर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, न्यूयॉर्क में जून 2024 में मनाया गया

भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79^{वाँ} सत्र के दौरान आईजीएन प्रक्रिया में अपनी स्थिति की दृढ़ता से पुष्टि की। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया ताकि वह वर्तमान वैश्विक चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना कर सके। इसने परिषद की स्थायी श्रेणी में विशेष रूप से अधिक प्रतिनिधित्व का आह्वान किया। आईजीएन प्रक्रिया पर ही भारत ने समयबद्ध तरीके से पाठ-आधारित वार्ता और परिणाम-केंद्रित दृष्टिकोण का आह्वान किया।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 21 जून को “स्वयं और समाज के लिए योग” विषय पर 10^{वाँ} अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। उप महासचिव अमीना जे मोहम्मद के साथ संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों तथा भारतीय समुदाय के सदस्यों सहित संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के स्थायी प्रतिनिधियों (पीआर) और प्रतिनिधियों ने योग दिवस समारोह में भाग लिया।

गुटनिरपेक्ष आंदोलन

गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य के रूप में भारत ने इस समूह में अपनी भागीदारी जारी रखी है। विदेश मंत्री ने 17 से 20 जनवरी को कंपाला में एनएएम शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। सितंबर 2024 में न्यूयॉर्क में एनएएम मंत्रिस्तरीय बैठक में, विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) ने इस बात पर जोर दिया कि एनएएम इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त है, जो समकालीन वास्तविकताओं को दर्शाता है, जिससे यह संगठन युवाओं के लिए अधिक आकर्षक हो गया है।

शांति रक्षक

भारत 1950 से अब तक लगभग 2,90,000 सैन्यकर्मियों के साथ सबसे बड़ा सैन्य योगदानकर्ता देश (टीसीसी) बना हुआ है। कुल 180 भारतीय शांति सैनिकों ने अपने कर्तव्य के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। वर्तमान में, भारत चौथा सबसे बड़ा योगदानकर्ता है, जिसके 11 संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में से 09 में 5000 से अधिक शांति सैनिक तैनात हैं।



भारतीय सेना की मेजर राधिका सेन को मई 2024 में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा 'यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर' सम्मान से नवाजा गया।

अपने संपर्कों के दौरान भारत ने शांति स्थापना के मिशनों के लिए अधिदेश तैयार करने में टीसीसी को शामिल करने आह्वान किया। भारत ने शांति स्थापना में रणनीतिक संचार की आवश्यकता पर बल दिया ताकि अधिदेश के लिए सभी सहभागियों के बीच स्पष्टता हो सके। भारत ने शांति स्थापना अभियानों पर हमारे सहयोग के भाग के रूप में यथार्थ और स्पष्ट निकास रणनीतियों पर जोर दिया। भारत ने विभिन्न मंचों पर इस बात पर भी प्रकाश डाला कि शांति सैनिकों को न केवल उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपितु प्रभावी अधिदेश उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित और वित्तपोषित किया जाना चाहिए। भारत ने शांति स्थापना में प्रौद्योगिकी संचार की पहल की, क्योंकि हम इसके व्यापक अनुकूलन की दिशा में "यूनाइट अवेयर" पहल जैसी प्रणालियों का समर्थन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं।

शांति स्थापना में महिलाओं की अधिक भागीदारी का समर्थन करने और शांति स्थापना के लिए कार्रवाई के साथ तालमेल बिठाने में भारत पहला देश है जिसने 2007 से 2016 तक एक शांति मिशन - लाइबेरिया में संयुक्त राष्ट्र मिशन (यूएनएमआईएल) में एक पूरी तरह से महिला पुलिस इकाई तैनात की है। 2019 से, भारतीय सेना की महिला सैनिकों वाली एक पूरी तरह से महिला नियुक्ति वाली टीम (एफईटी) को कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन (एमओएनयूससीओ), अवेई के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल (यूएनआईएसएफए), सूडान और हाल ही में जुलाई 2024 में दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन (यूएनएमआईएसएस) में तैनात किया गया है।

मार्च 2023 से अप्रैल 2024 तक पूर्वी डीआरसी में मोनुस्को शांति सेना के साथ काम करने वाली मेजर राधिका सेन को उनके कार्य के लिए वर्ष का संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट सम्मान दिया गया। भारत ने न्यूयॉर्क में डब्ल्यूपीएस सप्ताह के दौरान जर्मनी और स्विटजरलैंड के साथ एक कार्यक्रम की सह-मेजबानी के साथ महिला, शांति और सुरक्षा (डब्ल्यूपीएस) एजेंडे का भी समर्थन किया। भारतीय सेना में चिकित्सा सेवा महानिदेशक (डीजीएमएस) ने इस कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

भारत शांति सैनिकों के विरुद्ध अपराधों के लिए जवाबदेही और कानून के शासन को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है। भारत, शांति सैनिकों के विरुद्ध अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए मित्र समूह के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में शांति सैनिकों के लिए एक मेमोरियल वॉल की स्थापना में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

नवंबर 2024 में शांति स्थापना के लिए भारत-संयुक्त राष्ट्र सामरिक वार्ता आयोजित की गई, जिसमें शांति स्थापना और शांति निर्माण के सभी पहलुओं पर भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच सहयोग बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त किया गया।

शांति स्थापना

भारत ने अपने संपर्कों के दौरान, शांति निर्माण प्रयासों का समर्थन करते हुए, यह भी उल्लेख किया कि शांति निर्माण में विभिन्न राष्ट्रों की संप्रभुता को

ध्यान में रखते हुए संघर्ष के बाद की स्थिति के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। भारत ने मेजबान राष्ट्र की भागीदारी और सहमति सुनिश्चित करते हुए संघर्ष की रोकथाम के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया।

भारत ने शांति स्थापना आयोग (पीबीसी) की बैठकों में अपनी सलाहकारी और संबंध सुधार करने की भूमिकाओं के निर्वहन में सक्रिय रूप से भाग लिया है। भारत ने शांति स्थापना कार्यों के सतत और पूर्वानुमानित वित्तपोषण का स्वागत किया और शांति स्थापना कोष के माध्यम से वित्तपोषित परियोजनाओं और विकास कार्यों द्वारा राष्ट्रीय स्वामित्व के केंद्रीय सिद्धांत को बनाए रखा। भारत ने शांति स्थापना कार्यों के लिए लचीले और सतत वित्तपोषण द्वारा शांति स्थापना कोष में 50 मिलियन अमरीकी डॉलर के निर्धारित योगदान का स्वागत किया और उचित पारदर्शिता और निरीक्षण तंत्र को प्रोत्साहित किया। भारत शीर्ष टीसीसी में से एक के रूप में 2025-2026 तक दो वर्ष की एक और अवधि के लिए शांति स्थापना आयोग का सदस्य बना रहेगा।

आतंकवाद से निपटना

संयुक्त राष्ट्र में भारत की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक आतंकवाद रोध (सीटी) है, जहां भारत ने आतंकवाद से निपटने के लिए व्यापक बहुपक्षीय कार्रवाई करने, सदस्य राष्ट्रों की क्षमता निर्माण सहायता का प्रावधान करने, संयुक्त राष्ट्र सीटी से संबंधित प्रतिबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के साथ-साथ आतंकवाद के विरुद्ध सामूहिक कार्रवाई करने का समर्थन किया है।

भारत ने संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद रोध कार्यालय (यूएनओसीटी) के क्षमता निर्माण प्रयासों का सक्रिय रूप से समर्थन किया है तथा इसकी और अधिक स्वायत्तता के आह्वान का समर्थन करता रहा है। भारत ने आतंकवाद के वित्तपोषण मानकों को बढ़ावा देने और लागू करने, आतंकवादी उद्देश्यों के लिए नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग का मुकाबला करने तथा सीमा पार आतंकवाद के पीड़ितों के लिए 'न्याय के अधिकार' की वकालत करने के लिए यूएनओसीटी एजेंसियों तथा एफएटीएफ जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों के बीच अधिक तालमेल बनाए रखने पर भी जोर दिया। इन मंचों के बीच घनिष्ठ वार्ता से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने संबंधी कन्वेंशन (सीसीआईटी) को शीघ्र अंतिम रूप देने तथा अपनाने में सुविधा होगी, जिससे 'अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद' की कानूनी परिभाषा प्रदान की जा सकेगी। 2024 में, भारत ने आतंकवाद रोध के लिए संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड में 500,000 अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया।

भारत ने 25 सितंबर को आयोजित 23^{वाँ} समन्वय समिति की बैठक और 27 सितंबर को न्यूयॉर्क में आयोजित वैश्विक आतंकवाद रोध मंच (जीसीटीएफ) की 14^{वाँ} मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया। भारत ने 25 सितंबर को आयोजित की गई, आतंकवाद के पीड़ितों के मिला समूह (जीओएफवीओटी) की मंत्रिस्तरीय बैठक में भी भाग लिया। भारत ने 25 मार्च को आयोजित सऊदी अरब की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद रोध केंद्र (यूएनसीसीटी) के सलाहकार बोर्ड की आवधिक बैठकों में भी भाग लिया।

आतंकवाद के मुद्दों पर अपनी प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए भारत ने 08-09 अक्टूबर को स्पेन के विटोरिया में आयोजित आतंकवाद के पीड़ितों

के लिए वैश्विक सम्मेलन में भाग लिया। मैड्रिड में भारत के राजदूत ने इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया और "पीड़ितों और बचे लोगों को उनके अधिकार प्रदान करने और उनकी ज़रूरत के समय सहायता सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत कार्रवाई" संबंधी पैनल चर्चा में सहभागिता की।

विशेष राजनीतिक और गैर उपनिवेशीकरण संबंधी चौथी समिति

भारत चौथी समिति की बहसों में उपनिवेशवाद के विरुद्ध लड़ाई में सबसे आगे रहा है। भारत ने उपनिवेशवाद के उन्मूलन के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण का समर्थन किया, जिससे 17 गैर-स्वशासित क्षेत्रों के लोगों की वैध इच्छाओं की पूर्ति हो सके। भारत ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि विशेष राजनीतिक मिशनों की बहस में राष्ट्रीय स्वामित्व सभी राजनीतिक समाधानों के लिए महत्वपूर्ण है।

सूचना समिति

सूचना समिति का 46^{वाँ} सत्र 29 अप्रैल से 07 मई तक आयोजित किया गया। भारत ने डिजिटल विभाजन को सफलतापूर्वक पाटने में अपनी भूमिका को रेखांकित किया और इस बात पर बल दिया कि "सूचना लोकतंत्र की मुद्रा है।" भारत ने संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं के अलावा अन्य भाषाओं में वैश्विक पहुंच बढ़ाने का आह्वान किया और व्यापक दर्शकों तक पहुंच बनाने के लिए हिंदी में सूचना के अधिक सक्रिय प्रसार की वकालत की। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने में संयुक्त राष्ट्र के समर्थन की सराहना की, जिससे इस प्राचीन परंपरा के बारे में वैश्विक जागरूकता को बढ़ावा मिला है। समिति ने सर्वसम्मति से दो प्रस्ताव पारित किए अर्थात् 'मानवता की सेवा के लिए सूचना' और 'संयुक्त राष्ट्र वैश्विक संचार नीतियां और क्रियाकलाप'। भारत ने 21 दिसंबर को 'विश्व ध्यान दिवस' घोषित करने वाले संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को सह-प्रायोजित किया जो 06 दिसंबर को अपनाया गया था।

संयुक्त राष्ट्र में हिंदी

संयुक्त राष्ट्र में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए 2017 में संयुक्त राष्ट्र के साथ जिस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, उसे मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है। अब तक भारत ने संयुक्त राष्ट्र के चैनलों के माध्यम से हिंदी में समाचारों के प्रसार के लिए स्वैच्छिक योगदान के रूप में 6.45 मिलियन अमरीकी डॉलर की राशि का योगदान दिया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में बहुभाषिकता का समर्थन करने के लिए बहुभाषिकता संबंधी प्रस्ताव का सह-प्रायोजन भी किया है, जिसे 06 सितंबर को भारी बहुमत से अपनाया गया। संयुक्त राष्ट्र के सार्वजनिक संचार (संयुक्त राष्ट्र समाचार, संयुक्त राष्ट्र रेडियो संबंधी साप्ताहिक ऑडियो बुलेटिन और संयुक्त राष्ट्र सोशल मीडिया) में हिंदी का प्रयोग मार्च 2018 में शुरू हुआ और इसमें सोशल मीडिया भी शामिल है। संयुक्त राष्ट्र समाचार की हिंदी वेबसाइट अक्टूबर 2019

में शुरू हुई जिसमें संयुक्त राष्ट्र समाचार हिंदी सोशल मीडिया अकाउंट आदि शामिल हैं। सोशल मीडिया हैंडल पर हर महीने औसतन 240 से अधिक पोस्ट डाले जाते हैं। संबंधित विषयों में स्वास्थ्य, विकास, पर्यावरण, मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, संयुक्त राष्ट्र मामले, सामान्य मामले आदि शामिल हैं।

हिंदी में यूएन न्यूज़ की न्यूज़लेटर सदस्यता सेवा और आरएसएस फ़ीड भी उपलब्ध है। यूएन ने यूएन न्यूज़ ऐप (आईओएस और एंड्रॉइड पर उपलब्ध) पर हिंदी एक्सटेंशन विकसित किया है। हिंदी@यूएन सोशल मीडिया अकाउंट्स - [ट्विटर 51,800+ फ़ॉलोअर्स], इंस्टाग्राम (29,700+ फ़ॉलोअर्स) और फेसबुक (6.1 मिलियन ग्लोबल पेज)] की सोशल मीडिया पहुंच में भी वृद्धि हुई है।

भारतीय मिशन ने 22 नवंबर को न्यूयॉर्क में हिंदी दिवस की हीरक जयंती समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में भारत के सांसदों और 40 से अधिक देशों के पीआर और उप पीआर के बहुपक्षीय प्रतिनिधिमंडल, संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारियों, शिक्षाविदों, प्रवासियों सदस्यों और कार्यक्रम के हिंदी प्रतियोगिताओं के विजेताओं ने भाग लिया।

वित्तीय योगदान

संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के रूप में भारत नियमित रूप से संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट में पूर्ण और समय पर योगदान देता है, जो बहुपक्षवाद के प्रति इसकी मजबूत प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। पिछले वर्षों की तरह, 2024 में भी भारत ने अपना निर्धारित अंशदान पूर्ण रूप से अदा किया और परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र के 2024 'ऑनर रोल' में शामिल हो गया, जिसमें उन सदस्य देशों की सूची होती है जो संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट के लिए अपने वित्तीय दायित्वों को पूर्ण रूप से और समय पर पूरा करते हैं।

राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्ष बैठक (सीएचओजीएम)

राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक (सीएचओजीएम) 24-26 अक्टूबर को समोआ के अपिया में आयोजित की गई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामले मंत्री ने किया। राष्ट्राध्यक्षों ने घाना की तत्कालीन विदेश मंत्री शिले बोचवे को राष्ट्रमंडल का अगला महासचिव चुना। वे 01 अप्रैल 2025 को पदभार ग्रहण करेंगी। एंटीगुआ और बारबुडा 2026 में अगले सीएचओजीएम की मेज़बानी करेंगे।

मानवाधिकार, मानवीय और सामाजिक मामले

महासभा की तीसरी समिति ने मानवाधिकारों के मामलों की जांच पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा और महत्वपूर्ण सामाजिक विकास के मामलों पर विचार किया। समिति ने यूएनजीए के 79^{वें} सत्र में 03 अक्टूबर से 22 नवंबर तक बैठकें कीं। इसने तस्करी, ड्रग्स और अपराध, विकलांगता, महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध हिंसा, धर्म की स्वतंत्रता, मानवाधिकारों का प्रचार

और संरक्षण, सामाजिक विकास और देश-विशिष्ट प्रस्तावों जैसे विषयों को शामिल करते हुए कुल 48 प्रस्तावों को अपनाया। भारत ने 18 प्रस्तावों का सह-प्रायोजन किया।

सामाजिक विकास आयोग का 62^{वां} सत्र 05-14 फरवरी को आयोजित किया गया। भारत ने आयोग के 62^{वें} सत्र की अध्यक्षता की। 1975 के बाद यह पहली बार है जब भारत ने यह पद संभाला है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सचिव ने भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य दिया। महिलाओं की स्थिति हेतु आयोग का 68^{वां} सत्र 11-22 मार्च को आयोजित किया गया। पीआर ने भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य दिया। भारत 2021 से 2025 तक के लिए इस आयोग का सदस्य है। जनसंख्या और विकास संबंधी 57^{वां} आयोग 29 अप्रैल से 03 मई तक आयोजित किया गया। भारत ने जनसंख्या, शिक्षा और सतत विकास के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण प्रगति पर प्रकाश डाला।

22 सितंबर को न्यूयॉर्क में भविष्य के शिखर सम्मेलन में भावी पीढ़ियों के लिए घोषणापत्र को अपनाया गया। भविष्य के लिए समझौते से जुड़ी यह घोषणापत्र भारत की मुख्य प्राथमिकताओं से निकटता से जुड़ी है जिसमें : गरीबी उन्मूलन, विकास का अधिकार, महिलाओं के प्रति समानता, समावेशी विकास, जलवायु न्याय और युवा सशक्तिकरण शामिल हैं। भारत का समर्थन सतत विकास और समानता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, जो एक दूसरे से जुड़ी दुनिया में भावी पीढ़ियों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा के लिए वैश्विक प्रयासों का समर्थन करता है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा में कानूनी मामले

02 अक्टूबर से 22 नवंबर को आयोजित किए गए, यूएनजीए के 79^{वें} सत्र के दौरान, भारत ने छठी समिति (कानूनी) में प्रमुख भूमिका निभाई और कानूनी मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए एक विचारशील और रचनात्मक दृष्टिकोण का प्रदर्शन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के कानूनी निकायों में अधिक समावेशिता और विकासशील देशों के बढ़े हुए प्रतिनिधित्व की वकालत की। भारत ने मानवता के विरुद्ध अपराधों पर बहस में सक्रिय रूप से भाग लिया और विभिन्न एजेंडा मदों पर राष्ट्रीय बयान पेश किए, जिसमें "अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को खत्म करने के उपाय" के एजेंडा पर विशेष ध्यान दिया गया। भारत ने लगातार प्रयासों से महासभा द्वारा एक प्रस्ताव को अपनाने में योगदान दिया, जिसने आतंकवादी गतिविधियों को रोकने और दबाने में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। भारत ने आतंकवाद से निपटने के अलावा, अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रणाली में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को मजबूत बनाने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून को बढ़ाने और मूल कानूनी सिद्धांतों को कायम रखने की चर्चाओं में भाग लिया।

भारत का योगदान विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों तक रहा है जिसमें संयुक्त राष्ट्र के पदाधिकारियों की आपराधिक जवाबदेही और कानून का शासन शामिल हैं। भारत ने सार्वभौमिक अधिकार क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आयोग के कार्य, आपदाओं के दौरान व्यक्तियों की सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) की भूमिका और समुद्री कानून से संबंधित मुद्दों की चर्चा में भी योगदान दिया। भारत ने अपनी सक्रिय भागीदारी के

माध्यम से वैश्विक कानूनी मानदंडों को आगे बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय कानून में विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का समाधान करने के लिए अपने समर्पण को रेखांकित किया।

आर्थिक एवं सामाजिक मुद्दे

यूएनजीए की आर्थिक और वित्त समिति (दूसरी समिति) ने 7 अक्टूबर को विभिन्न एजेंडा मदों पर अपनी आम बहस और चर्चा शुरू की, जो यूएनजीए के 79^{वें} सत्र के उच्च स्तरीय सप्ताह के दौरान 22-23 सितंबर को आयोजित भविष्य के शिखर सम्मेलन के परिणामों पर आधारित थी। उच्च स्तरीय सप्ताह के अन्य महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय कार्यक्रमों में समुद्र-स्तर में वृद्धि और रोगाणुरोधी प्रतिरोध के लिए उच्च स्तरीय बैठकें शामिल थीं। समिति ने चतुर्भुज व्यापक नीति समीक्षा (क्यूसीपीआर) को भी अपनाया जो संयुक्त राष्ट्र विकास प्रणाली को रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए हर चार वर्ष में एक बार अपनाया जाने वाला एक संकल्प है।

यूएनजीए के 79^{वें} सत्र के दौरान, द्वितीय समिति ने 03 अक्टूबर से 27 नवंबर तक मुख्य सत्र के लिए अपनी बैठकें आयोजित कीं, जिसमें कुल 15 कार्यसूची मदों पर विचार किया गया, जिसमें 39 प्रस्ताव, एक निर्णय और अगले सत्र के कार्य का एक मसौदा कार्यक्रम शामिल था। 39 प्रस्तावों में से 5 पर मतदान हुआ। भारत ने सभी प्रस्तावों के पक्ष में मतदान किया। द्वितीय समिति की आम बहस में, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों, विशेष रूप से सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिक्रिया पर प्रकाश डाला। इनमें महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाना, डिजिटल तकनीक का उपयोग करना, दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देना और जलवायु कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है।

तृतीय दक्षिण शिखर सम्मेलन

तृतीय दक्षिण शिखर सम्मेलन 21-22 जनवरी को युगांडा के कंपाला में आयोजित किया गया था, जिसका विषय था 'किसी को पीछे न छोड़ना'। यह शिखर सम्मेलन 18 वर्षों के अंतराल के बाद हुआ और इसका उद्देश्य जी-77 के 134 सदस्य देशों और चीन के बीच नई गतिशीलता लाना था। तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री (वीएम) ने इस शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया और राष्ट्रीय वक्तव्य दिया।

एसआईडीएस4 सम्मेलन

लघु द्वीपीय विकासशील राष्ट्रों हेतु दस वर्षीय चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (एसआईडीएस4) 27 से 30 मई तक एंटीगुआ और बारबुडा में आयोजित किया गया, जिसका विषय था 'लचीली समृद्धि की दिशा में मार्ग तैयार करना'। दस वर्ष में एक बार होने वाला लघुद्वीप विकासशील राष्ट्र हेतु चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (एसआईडीएस4) 27 से 30 मई तक एंटीगुआ और बारबुडा में आयोजित किया गया, जिसका विषय था 'लचीली समृद्धि की दिशा के लिए मार्ग तैयार करना'। इस सम्मेलन में एसआईडीएस के लिए एंटीगुआ और बारबुडा एजेंडा (एबीएस), एसआईडीएस के लिए एक दस

वर्षीय कार्यक्रम को अपनाया गया, जो 2014 में अपनाए गए एसआईडीएस त्वरित कार्रवाई के तौर-तरीकों का अनुवर्ती कार्यक्रम है। भारत ने इस सम्मेलन के आयोजन के लिए 300,000 अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया। सचिव (पश्चिम) ने भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। भारत ने 'एसआईडीएस के लिए संसाधन जुटाने' हेतु यूएनएसजी के नेतृत्व वाली उच्च स्तरीय बैठक में भी भाग लिया और 'एसआईडीएस में लचीले भविष्य के लिए डेटा और डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना और प्रभावी संस्थानों का निर्माण' पर परस्पर वार्ता में भाग लिया

ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट

महासभा ने सितंबर 2024 में भविष्य के शिखर सम्मेलन में भविष्य के लिए समझौते के अनुल्लङ्घ्य के रूप में वैश्विक डिजिटल समझौते को अंगीकार किया। यह समझौता सभी के लिए एक खुले और सुरक्षित डिजिटल भविष्य के लिए सदस्य देशों के बीच सहयोग के लिए एक व्यापक रूपरेखा निर्धारित करता है। इस समझौते में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा गवर्नेंस और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) पर जोर देना, इन क्षेत्रों में भारत की आकांक्षाओं को पूरा करता है।

सतत विकास के लिए एचएलपीएफ

ईसीओएसओसी के तत्वावधान में सतत विकास संबंधी उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम (एचएलपीएफ) 08-17 जुलाई को आयोजित किया गया, जबकि मंत्रिस्तरीय खंड 15-17 जुलाई के बीच आयोजित किया गया। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने किया। 2024 एचएलपीएफ, 2023 एसडीजी शिखर सम्मेलन के बाद ईसीओएसओसी के तत्वावधान में पहला मंच था, जिसे सितंबर 2023 में महासभा द्वारा आयोजित किया गया था। 2024 एचएलपीएफ ने 2030 एजेंडा और एसडीजी को आगे बढ़ाने के लिए एसडीजी शिखर सम्मेलन के राजनीतिक घोषणापत्र और अन्य परिणामों के कार्यान्वयन का समर्थन किया। 36 देशों ने 2030 एजेंडा पर अपनी प्रगति रिपोर्ट साझा करते हुए अपनी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा (वीएनआर) प्रस्तुत की। भारत के स्थायी मिशन (पीएमआई) न्यूयॉर्क ने एचएलपीएफ के अवसर पर दो कार्यक्रम आयोजित किए। पहला, फ्रांस और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के स्थायी मिशन के साथ "सौर दमक: सार्वभौमिक ऊर्जा पहुंच के साथ जीवन को सशक्त बनाना" पर। दूसरा कार्यक्रम नीति आयोग, यूएनडीपी और यूएन इंडिया के साथ "किसी को पीछे न छोड़ना: एसडीजी में तेजी लाने में भारत का अनुभव" के संबंध में आयोजित किया गया।

विकास के लिए वित्तपोषण

2024 ईसीओएसओसी विकास के लिए वित्तपोषण (एफएफडी) फोरम 22-25 अप्रैल को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित किया गया। एफएफडी फोरम हर वर्ष में अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा में निर्धारित अपने अधिदेश के अनुरूप आयोजित किया जाता है, ताकि एक्शन एजेंडा में निर्धारित उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जा सके। इस फोरम के इस संस्करण



विदेश मंत्री ने सितंबर 2024 में न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार की सीमा से बाहर अन्य क्षेत्रों में जैव विविधता करार पर हस्ताक्षर किए

में सतत विकास वित्तपोषण से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों विशेष रूप से 2025 के लिए निर्धारित विकास के लिए वित्तपोषण पर चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (एफएफडी 4) की तैयारी के लिए पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस दौरान विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए ऋण प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय कर सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता के अलावा एक प्रमुख विषय था।

समुद्र तल से वृद्धि

पीजीए ने महासभा के 79^{वाँ} सत्र के उच्च स्तरीय सप्ताह के दौरान समुद्र के बढ़ते स्तर से उत्पन्न अस्तित्वगत जोखिमों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय पूर्ण बैठक आयोजित की। इस उच्च स्तरीय बैठक का समग्र विषय था "समुद्र के बढ़ते स्तर से उत्पन्न जोखिमों से निपटना"। भारत का प्रतिनिधित्व सचिव (पश्चिम) ने किया, जिन्होंने अपने तटीय क्षेत्रों में इस चुनौती से निपटने के लिए भारत के दृष्टिकोण को साझा किया।

भारत-यूएनडीपी और आईबीएसए निधि

भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी कोष की स्थापना 2017 में 150 मिलियन अमरीकी डॉलर के बजट के साथ की गई थी। यह कोष सामान्य और राष्ट्रमंडल विंडोज के तहत काम करता है और भारत से ग्लोबल साउथ के देशों को स्वैच्छिक निधि मुहैया कराता है, जिसमें एसआईडीएस (लघु द्वीप विकासशील राज्य), एलडीसी (सबसे कम विकसित देश), एलएलडीसी (भूमि से घिरे विकासशील देश) और आपदा से प्रभावित देशों पर जोर दिया जाता है। यह कोष शुरू से अंत तक समर्थन प्रदान करता है: मेजबान सरकार एक क्षेत्रीय आवश्यकता की पहचान करती है और संयुक्त राष्ट्र अनुरोधकर्ता सरकार की प्राथमिकताओं और दृष्टिकोणों के अनुसार परियोजना निर्माण

और कार्यान्वयन में सहायता प्रदान की जाती है। अब तक, इस कोष से 57 देशों में 68 मिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य की 84 परियोजनाओं के लिए सहयोग किया गया।

भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका (आईबीएसए) कोष की स्थापना के बाद, लिपक्षीय भागीदारी 2006 में पूरी तरह से शुरू हो गई, ताकि वैश्विक दक्षिण में भागीदार देशों को उनके व्यापक विकास उद्देश्यों की आम उद्देश्यों के लिए मदद मिल सके। आईबीएसए कोष द्वारा 34 देशों में 47 परियोजनाओं का समर्थन किया गया है, जिसके लिए 51.57 मिलियन अमेरिकी डॉलर आवंटित किए गए हैं। आईबीएसए कोष और भारत-संयुक्त राष्ट्र कोष ने मई में एंटीगुआ और बारबुडा में एसआईडीएस संबंधी चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान एक अतिरिक्त कार्यक्रम आयोजित किया। भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका (आईबीएसए-एफएमएम) के विदेश मंत्रियों ने 26 सितंबर को उच्च स्तरीय सप्ताह के दौरान मुलाकात की और स्थिति का जायजा लिया।

संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संबंधी सम्मेलन (यूएनसीएलओएस)

विदेश मंत्री ने 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में "राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र की सीमा से बाहर अन्य क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संबंधी सम्मेलन (यूएनसीएलओएस) के तहत करार" या "बीबीएनजे करार" पर हस्ताक्षर किए। इस करार का प्राथमिक आशय और उद्देश्य राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र सीमा से बाहर अन्य क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग को सुनिश्चित करना है। यह करार समुद्री कानून के संहिताकरण में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र की सीमा से बाहर अन्य क्षेत्रों में समुद्री जैव विविधता

के संरक्षण और सतत उपयोग का समाधान करता है। भारत द्वारा बीबीएनजे करार पर हस्ताक्षर करना यह सुनिश्चित करने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि महासागर स्वस्थ और रेजीलेंट बने रहें।

अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस

पीएमआई न्यूयॉर्क ने 02 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में “अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस” मनाया। इस कार्यक्रम में स्थायी प्रतिनिधियों, वरिष्ठ संयुक्त राष्ट्र अधिकारियों और भारतीय समुदाय के सदस्यों ने भाग लिया।

अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन (आईएलओ)

अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन (112 आईएलसी) का 112^{वाँ} सत्र 03-14 जून को जिनेवा में आयोजित किया गया। श्रमिकों, नियोक्ताओं और सरकार के प्रतिनिधियों वाले भारतीय लिपक्षीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्रमिक और रोजगार मंत्रालय के सचिव ने किया। सचिव (श्रम एवं रोजगार) ने “नए सामाजिक अनुबंध की दिशा में” विषय पर 112 आईएलसी पूर्ण सत्र को संबोधित किया; आईएलओ के महानिदेशक गिल्बर्ट हुंगबो और वरिष्ठ आईएलओ अधिकारियों से मुलाकात की और इस कार्यक्रम के दौरान अनेक द्विपक्षीय बैठकें की। सम्मेलन के दौरान आईएलओ महानिदेशक की प्रमुख पहल वैश्विक सामाजिक न्याय गठबंधन के उद्घाटन मंच को चिह्नित किया। श्रमिकों के लाभ के लिए भारत की मौजूदा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को प्रदर्शित करने के लिए 04 जून को पीएमआई में भारत के ई-श्रम पोर्टल पर एक साइट इवेंट आयोजित की गई।

सचिव (श्रम एवं रोजगार) ने मार्च, जून और अक्टूबर-नवंबर में आयोजित आईएलओ अभिशासी निकाय (जीबी) के 350^{वें}, 351^{वें} और 352^{वें} सत्रों में भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। व्यवसायों के वर्गीकरण संबंधी एक अंतरराष्ट्रीय संदर्भ ढांचे की व्यवहार्यता अध्ययन की घोषणा, जो 2023 में भारत की जी20 प्रेसीडेंसी के तहत रोजगार कार्य समूह का एक प्रमुख परिणाम है, 352^{वें} जीबी सत्र के दौरान की गई।

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ)

भारत को द्विवार्षिक 2024-25 के लिए श्रेणी बी (अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सबसे बड़ी रुचि रखने वाले देश) के अंतर्गत आईएमओ परिषद में पुनः निर्वाचित किया गया है, तथा यह विभिन्न बैठकों और चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लेता रहा है।

भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस विशाखापत्तनम के कप्तान और चालक दल को मार्शल द्वीप ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाज मार्लिन लुआंडा जिसमें जनवरी में लाल सागर में आग लग गई थी, की आग बुझाने के प्रयासों में शामिल होने के कारण उनके उल्लेखनीय साहस और दृढ़ संकल्प के लिए आईएमओ से प्रशंसा पत्र प्राप्त हुआ।

पोत परिवहन, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के सचिव की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने डीजी शिपिंग के साथ क्रमशः 08-12 जुलाई और 18-22 नवंबर को लंदन में आईएमओ के मुख्यालय में आयोजित आईएमओ परिषद के 132^{वें} और 133^{वें} सत्र में भाग लिया। विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, भारतीय नौसेना और एनएससीएस के अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल 01-03 अक्टूबर को लंदन की यात्रा की और महासचिव आईएमओ, जिबूती आचार संहिता (डीसीओसी) सदस्य देशों और डीसीओसी मित्र देशों के साथ वार्ता की। भारत ने नाविकों के मुद्दों और मानवीय तत्व की पहचान करने और उनका समाधान करने के लिए तीसरे संयुक्त आईएलओ/आईएमओ लिपक्षीय कार्य समूह (जेटीडब्ल्यूजी) के आठ सदस्यों में से एक के रूप में भी भाग लिया।

अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (आईओएम)

भारत ने 26-28 नवंबर को आईओएम परिषद के 115^{वें} सत्र में भाग लिया, जिसमें उच्च स्तरीय खंड में सचिव (सीपीवी और ओआईए) का एक वीडियो वक्तव्य भी शामिल था।

मई में भारत ने दो वर्ष की अवधि के लिए कोलंबो प्रक्रिया (सीपी) की अध्यक्षता संभाली। विदेश मंत्रालय के सचिव (सीपीवी एवं ओआईए) ने सीपी अध्यक्ष के रूप में भारत का कार्यभार संभालने के बाद पहली सीपी बैठक का नेतृत्व करने के लिए 28 जून को जिनेवा की यात्रा की और सीपी के लिए भारत की कार्ययोजना की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसमें नियमित प्रवास मार्गों, प्रवासी संपर्क, भारतीय कुशल कामगारों की सामाजिक सुरक्षा पोर्टेबिलिटी और उनके नियमित प्रवास को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर चर्चा शामिल थी।

संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय (यूएनडीआरआर)

भारत के उम्मीदवार कमल किशोर को मार्च में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव (एसआरएसजी) के विशेष प्रतिनिधि के रूप में नियुक्ति द्वारा सहायक महासचिव और यूएनडीआरआर का प्रमुख बनने के लिए चुना गया।

सीडीआरआई महानिदेशक ने 19 मार्च को पीएमआई द्वारा सीडीआरआई और यूएनडीआरआर के सहयोग से जिनेवा में आयोजित एक कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के पीआर को सीडीआरआई के कार्यों के बारे में जानकारी दी।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ)

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) महानिदेशक के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 10-14 जून को जिनेवा में डब्ल्यूएमओ कार्यकारी परिषद की बैठक में भाग लिया। आईएमडी के प्रतिनिधिमंडल ने 15-19 अप्रैल को जिनेवा में डब्ल्यूएमओ के अवलोकन, अवसंरचना और सूचना प्रणाली

आयोग (आईएनएफसीओएम) की बैठकों के तीसरे सत्र में भाग लिया। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के एक प्रतिनिधिमंडल ने 06-07 जून को जिनेवा में डब्ल्यूएमओ की वित्तीय सलाहकार समिति (एफआईएनएसी 44) की 44^{वीं} बैठक में भाग लिया।

यूएनईपी

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) के अपर सचिव के नेतृत्व में भारत के प्रतिनिधिमंडल ने छठी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (यूएनईए-6) में भाग लिया, जो 26 फरवरी से 01 मार्च तक केन्या के नैरोबी में आयोजित किया गया था। भारत ने "सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना" शीर्षक से एक प्रस्ताव पेश किया, जिसे सर्वसम्मति से यूएनईए-6 में अंगीकार किया गया। यह प्रस्ताव, जो भारत की वैश्विक पहल- पर्यावरण के लिए जीवन शैली (लाईफ) के अनुरूप था, संयुक्त राष्ट्र के किसी निकाय द्वारा अपनाया गया पहला ऐसा प्रस्ताव था। यूएनईए-6 ने 15 प्रस्तावों को अपनाया, जो धातुओं, खनिज संसाधनों, रसायनों और अपशिष्ट, जल नीतियों, महासागर और समुद्र, अत्यधिक खतरनाक रसायनों, भूमि क्षरण, सशस्त्र संघर्ष के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

समुद्री पर्यावरण सहित प्लास्टिक प्रदूषण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन विकसित करने के लिए अंतर-सरकारी वार्ता समिति (आईएनसी-4) का चौथा सत्र 21-29 अप्रैल को ओटावा में आयोजित किया गया था। अंतर-सरकारी वार्ता समिति (आईएनसी-5) का पांचवां सत्र 25 नवंबर से 01 दिसंबर तक दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित किया गया। इन सम्मेलनों में भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अपर सचिव ने किया।

भारत 2024-2026 की अवधि के लिए यूएनईपी में 10-वर्षीय सतत रूपरेखा कार्यक्रम (10वाईपी) का बोर्ड सदस्य बन गया है।

रामसर कन्वेंशन के महासचिव मुसोंडा मुंबा ने 30-31 जनवरी को दिल्ली और 01-03 फरवरी को इंदौर की यात्रा की, ताकि मध्य प्रदेश के सिरपुर में विश्व वेटलैंड्स दिवस (डब्ल्यूडब्ल्यूडी) में भाग लिया जा सके, जो रामसर द्वारा मान्यता प्राप्त स्थल है। यह पहली बार था जब रामसर कन्वेंशन के किसी अनुबंधकारी पक्ष ने विश्व वेटलैंड्स दिवस की मेजबानी की। डब्ल्यूडब्ल्यूडी का विषय "वेटलैंड्स और मानव कल्याण" था। रामसर महासचिव ने 31 जनवरी को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री से मुलाकात की और वेटलैंड संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक सहयोग संबंधी क्षेत्रों पर चर्चा की।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावास

यूएन-हैबिटेट के 36 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड के सदस्य के रूप में भारत ने बोर्ड के 06-08 मई के प्रथम सत्र तथा 04-06 दिसंबर के इसके दूसरे सत्र में भाग लिया। भारत ने राष्ट्रीय/स्थानीय स्मार्ट सिटी विनियमन, योजना और रणनीति विकसित करने के लिए एक गैर-बाध्यकारी ढांचे के रूप में जन-केंद्रित स्मार्ट शहरों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय दिशानिर्देश विकसित करने के लिए स्थापित 30 सदस्यीय विशेषज्ञ कार्य समूह में संयुक्त सचिव और मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटी मिशन, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को नामित किया है।

चुनाव

संयुक्त राष्ट्र और संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के चुनावों में भारत का प्रदर्शन नीचे सूचीबद्ध किया गया है:

- भारत की उम्मीदवार सुश्री जगजीत पवाडिया ने सरकारी श्रेणी में 2025-30 के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड (आईएनसीबी) का चुनाव जीत लिया।
- भारत को अप्रैल 2024 में 2025-2029 की अवधि के लिए महिलाओं की स्थिति संबंधी आयोग (सीएसडब्ल्यू) के लिए चुना गया।
- भारत को अप्रैल में 2025-2027 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) के कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना गया।
- भारत को अप्रैल में 2025-2027 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) और संयुक्त राष्ट्र परियोजना सेवा कार्यालय (यूएनओपीएस) के कार्यकारी बोर्डों के लिए चुना गया।
- भारत को अप्रैल में 2025-2027 की अवधि के लिए महिलाओं के प्रति समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र इकाई के कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना गया।
- भारत को 29 जुलाई से 2 अगस्त तक किंगस्टन, जमैका में आयोजित आईएसए के 29^{वें} सत्र के दौरान 'ग्रुप बी' के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समुद्रतल प्राधिकरण (आईएसए) परिषद के लिए पुनः चुना गया।
- राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज), हैदराबाद के महानिदेशक को 2024-28 की अवधि के लिए एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास केंद्र (सीआईआरडीएपी) के महानिदेशक के रूप में चुना गया। सीआईआरडीएपी की 24^{वीं} अभिशासी परिषद की बैठक के दौरान इसके लिए 6 जून को बैंकॉक, थाईलैंड में चुनाव संपन्न हुए। सीआईआरडीएपी एक क्षेत्रीय, अंतर-सरकारी और स्वायत्त संगठन है, जिसमें 15 सदस्य देश शामिल हैं।
- केंद्रीय रेशम बोर्ड, बैंगलोर के सदस्य सचिव को 10-12 अक्टूबर के दौरान बुखारेस्ट, रोमानिया में आयोजित चुनाव के दौरान लगातार 5^{वीं} बार, 2025-27 की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय रेशम आयोग (आईएससी), बैंगलोर, भारत के महासचिव के रूप में चुना गया।
- ऑस्ट्रिया के विएना में 24-27 सितंबर को आयोजित चुनावों के दौरान भ्रष्टाचार रोधी कानून प्रवर्तन प्राधिकरणों के वैश्विक परिचालन नेटवर्क (ग्लोबई नेटवर्क) की संचालन समिति के सदस्य के रूप में चुना गया।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी)

भारत ने 2022-2024 की अवधि के लिए यूएनएचआरसी के सदस्य राष्ट्र के रूप में, इस वर्ष यूएनएचआरसी सत्रों में एवं संबंधित मानवाधिकार तंत्रों और प्रक्रियाओं में अपनी भागीदारी जारी रखी। भारत, विकास के अधिकार



विदेश मंत्री ने सितंबर 2024 में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क से मुलाकात की



विदेश मंत्री ने सितंबर 2024 में नए भवन का उद्घाटन किया, जिसमें संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन और सीडी में भारत का स्थायी मिशन, साथ ही जिनेवा में भारतीय कौंसलावास भी स्थित होंगे।

सहित मानवाधिकारों के वैश्विक संवर्धन और संरक्षण के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के बीच तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण सहयोग के लिए अपने समर्थन प्रदान करता रहा है।

विदेश मंत्री ने 12-13 सितंबर को जिनेवा, स्विटजरलैंड की यात्रा की। विदेश मंत्री ने अपनी यात्रा के दौरान जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नेतृत्व से वार्ता की, जिसमें संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क और

विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम गेब्रेयसस शामिल थे। विदेश मंत्री ने जिनेवा में पीएमआई के एक नवनिर्मित अत्याधुनिक भवन का उद्घाटन किया। विदेश मंत्री ने पीएमआई में भीमराव अंबेडकर की एक प्रतिमा समर्पित की। इसके अलावा, विदेश मंत्री ने यूडीएचआर के प्रारूपण में हंसा मेहता के योगदान की स्मृति में पीएमआई के बहुउद्देशीय हॉल को समर्पित किया।

भारत ने 26 फरवरी-05 अप्रैल, 18 जून-12 जुलाई और 09 सितंबर-11 अक्टूबर को आयोजित क्रमशः 55^{वाँ}, 56^{वाँ} और 57^{वाँ} यूएनएचआरसी सत्रों में सक्रिय रूप से भाग लिया। भारत ने विकास के अधिकार, मानवाधिकार और एकपक्षीय दमनकारी उपायों के लिए यूएनएचआरसी प्रस्तावों का सह-प्रायोजन किया। भारत यूएनएचआरसी सत्रों में विभिन्न देशों के समूहों के संयुक्त वक्तव्यों में भी शामिल हुआ, जिसमें स्वास्थ्य, महिलाएँ और बच्चे, स्थानीय शासन आदि जैसे महत्वपूर्ण विषयगत मुद्दे शामिल थे।

भारत ने 57^{वाँ} यूएनएचआरसी सत्र के दौरान, 19 सितंबर को बच्चों के विकास के अधिकार संबंधी एक अतिरिक्त कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें विकास के अधिकार पर विशेष प्रतिवेदक भी शामिल थे, जिसे अच्छी प्रतिक्रिया मिली और इसमें अनेक सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया।

भारत ने 15-16 जुलाई को जिनेवा में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वाचा की मानवाधिकार समिति द्वारा अपनी चौथी आवधिक समीक्षा सफलतापूर्वक पूरी की। भारत के अटॉर्नी जनरल और भारत के सॉलिसिटर जनरल के सह-नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय; सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय; इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय; अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय; विदेश मंत्रालय; जनजातीय मामले मंत्रालय; गृह मंत्रालय; और अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल के कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। इस समीक्षा के दौरान, भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने नागरिक और राजनीतिक अधिकारों से संबंधित मुद्दों की एक व्यापक श्रृंखला पर मानवाधिकार समिति के सदस्यों के साथ सार्थक वार्ता की और इन क्षेत्रों में भारत की प्रतिबद्धता, कार्यों और उपलब्धियों को साझा किया।

भारत ने यूडीएचआर को अंगीकार करने की 76^{वीं} वर्षगांठ के अवसर पर, जिसे विश्व भर में मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, 09 दिसंबर को जिनेवा में अपने स्थायी मिशन के हंसा मेहता हॉल में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उप उच्चायुक्त, संयुक्त राष्ट्र विशेष प्रक्रिया अधिदेश धारकों और जिनेवा में मौजूद राजनयिक समुदाय ने भाग लिया, जिसमें यूडीएचआर के प्रारूपण में हंसा मेहता के महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डाला गया।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) के सचिव के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 27 मई से 01 जून को जिनेवा में 77^{वाँ} विश्व स्वास्थ्य सभा (डब्ल्यूएचए 77) में भाग लिया। सचिव (एमओएचएफडब्ल्यू) ने डब्ल्यूएचए 77 की दो मुख्य समितियों में से एक की अध्यक्षता की।

- एक ऐतिहासिक निर्णय में, विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचए) 77 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (आईएचआर) 2005 में संशोधनों को अपनाया। भारत

ने आईएचआर संशोधनों के प्रारूपण में, विशेष रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए एक न्यायसंगत प्रतिक्रिया के संचालन के प्रावधानों के संबंध में, एक रचनात्मक भूमिका निभाई।

- भारत ने वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए डब्ल्यूएचओ के साथ सहयोग किया। भारत सरकार और डब्ल्यूएचओ ने 31 जुलाई को एक डोनर करार पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत भारत गुजरात के जामनगर में डब्ल्यूएचओ ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर के संचालन का समर्थन करेगा। डब्ल्यूएचए 77 के दौरान, भारत ने 31 मई को जिनेवा में अपने स्थायी मिशन में "पारंपरिक चिकित्सा: आगे की राह" के संबंध में एक अन्य कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें आयुष मंत्रालय के वक्ता शामिल थे।
- भारत ने अंतर-सरकारी वार्ता निकाय (आईएनबी) की 2024 की बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लिया, जो डब्ल्यूएचओ महामारी संबंधी करार पर वार्ता कर रहा है, जहाँ भारत वैश्विक दक्षिण की चिंताओं और प्राथमिकताओं, विशेष रूप से समानता से संबंधित प्रावधानों पर आवाज़ उठाता रहा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधिमंडल ने क्रमशः 19 फरवरी-01 मार्च, 18-28 मार्च, 09-20 सितंबर और 04-15 नवंबर को जिनेवा में आयोजित 8^{वाँ}, 9^{वाँ}, 11^{वाँ} और 12^{वाँ} आईएनबी बैठकों में भाग लिया।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के एक प्रतिनिधिमंडल ने 25-27 जून को जिनेवा में एचआईवी/एड्स संबंधी संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम (यूएनएड्स) के कार्यक्रम समन्वय बोर्ड की 54^{वाँ} बैठक और 24 जून को यूएनएड्स वैश्विक लक्ष्य टास्क टीम की बैठक में भाग लिया।
- अपर सचिव और निदेशक के नेतृत्व में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का एक प्रतिनिधिमंडल 04-05 जुलाई को जिनेवा में मातृ, नवजात और बाल स्वास्थ्य के लिए साझेदारी बोर्ड की 33^{वाँ} बैठक में शामिल हुआ।
- भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 18-22 नवंबर को जिनेवा में कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग (सीएसी) की कार्यकारी समिति के 87^{वाँ} सत्र और 25-30 नवंबर को सीएसी के 47^{वाँ} सत्र में भाग लिया।

अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू)

प्रधानमंत्री ने 14-24 अक्टूबर को नई दिल्ली में भारत द्वारा आयोजित आईटीयू की विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा (डब्ल्यूटीएसए) का उद्घाटन किया। यह पहली बार था कि डब्ल्यूटीएसए, जो प्रति 4 वर्ष में आयोजित की जाती है, एशिया-प्रशांत क्षेत्र में आयोजित की गई। इस महत्वपूर्ण वैश्विक कार्यक्रम में 160 से अधिक देशों के दूरसंचार, डिजिटल और आईसीटी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले उद्योग जगत के नेताओं, नीति-निर्माताओं और तकनीकी विशेषज्ञों सहित 3700 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जो डब्ल्यूटीएसए में अब तक की सबसे अधिक भागीदारी है।



प्रधानमंत्री ने अक्टूबर 2024 में नई दिल्ली में आईटीयू-विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया

नई दिल्ली डब्ल्यूटीएसए ने उभरते दूरसंचार क्षेत्रों के लिए आठ प्रस्तावों को अपनाया, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीपीआई, सतत डिजिटल परिवर्तन, मेटावर्स मानकीकरण को बढ़ावा देना और मजबूत बनाना, और आपातकालीन संचार के लिए हैडसेट-व्युत्पन्न कॉलर स्थान की जानकारी का प्रावधान शामिल है।

भारत ने आईटीयू दूरसंचार मानकीकरण क्षेत्र (आईटीयू-टी) में अब तक के सबसे अधिक नेतृत्व पदों को प्राप्त किया है। भारतीय विशेषज्ञों को 10 आईटीयू-टी अध्ययन समूहों और शब्दावली संबंधी मानक समिति में चुना गया। डब्ल्यूटीएसए में 15 से अधिक उच्च स्तरीय साइड इवेंट आयोजित किए गए, जिनमें एआई4गुडइंडिया इम्पैक्ट, नेटवर्क फॉर वीमेन, केलिडोस्कोप, रेगुलेटर्स कॉन्फ्रेंस, यूएन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कॉन्फ्रेंसिंग, आईटीयू-डब्ल्यूएचओ सेफ लिसनिंग और हैकाथॉन शामिल हैं।

वर्ष 2024 में आईटीयू के मानक-निर्धारण विचार-विमर्श तंत्र जैसे कि कार्यदल और अध्ययन समूह की 57 बैठकें हुईं। इनमें से 46 बैठकें जिनेवा में और 11 कंबोडिया, चीन, फ्रांस, भारत, जापान, कजाकिस्तान, माल्टा और यूके में हुईं। भारत ने दूरसंचार विभाग के विशेषज्ञ-स्तरीय प्रतिनिधिमंडलों के साथ सभी 57 बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लिया।

संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास (यूएनसीटीएडी)

भारत ने 12-14 जून को जिनेवा में आयोजित यूएनसीटीएडी की 60^{वीं} वर्षगांठ समारोह में भाग लिया, जिसमें उच्च स्तरीय वैश्विक नेतृत्व फोरम

ने विभिन्न देशों के समक्ष आने वाली बहुआयामी चुनौतियों, सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र 2030 एजेंडा को आगे बढ़ाने की रणनीतियों तथा लचीलेपन, आर्थिक विकास और सतत विकास को बढ़ावा देने वाले नवीन समाधानों की आवश्यकता पर चर्चा की।

अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति (आईसीआरसी)

भारत ने 28-31 अक्टूबर को जिनेवा में आयोजित रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट के 34^{वें} अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। हर चार वर्ष में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में जिनेवा सम्मेलनों के 191 राष्ट्र दुलों के साथ-साथ 186 राष्ट्रीय समाज, आईसीआरसी और रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटीज के अंतर्राष्ट्रीय महासंघ ने भाग लिया, जिससे वैश्विक मानवीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच उपलब्ध हुआ।

इस सम्मेलन में सर्वसम्मति से पांच प्रस्ताव पारित किए गए, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून, सशस्त्र संघर्ष के दौरान आईसीटी क्रियाकलापों की संभावित मानवीय लागत, आपदा जोखिम प्रशासन को सुदृढ़ बनाना, सैद्धांतिक मानवीय कार्यवाई में स्थानीय नेतृत्व, क्षमता और क्रियान्वयन को सक्षम बनाना, तथा अत्यधिक जलवायु और मौसम संबंधी घटनाओं के मानवीय प्रभाव शामिल थे।

भारत के स्थायी प्रतिनिधि की अध्यक्षता में भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल के अतिरिक्त, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया। भारतीय वायु सेना की एक टीम ने अत्याधुनिक, मेड-इन-इंडिया पोर्टेबल प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री भीषण क्यूब का प्रदर्शन करते हुए एक स्टॉल लगाया, जिसमें आपातकालीन और आपदा क्षेत्रों में तेजी से तैनाती के लिए डिज़ाइन किए गए चिकित्सा उपकरण और आवश्यक वस्तुएं शामिल रही। भारत इस सम्मेलन में स्टॉल लगाने वाला एकमात्र देश था।

इस सम्मेलन के दौरान भारत ने जिनेवा सम्मेलनों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और इसके पूर्ण अनुपालन की बात कही। भारत ने विश्व भर में चलाए गए मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियानों पर भी प्रकाश डाला।

शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर)

भारत ने 14-18 अक्टूबर के दौरान जिनेवा में यूएनएचसीआर की कार्यकारी समिति के 75^{वें} वार्षिक सत्र में भाग लिया। इस समिति ने पिछले वर्ष के कार्यों की समीक्षा की और अगले वर्ष के लिए अपने कार्यक्रम का निर्धारण किया, साथ ही 2025 के लिए यूएनएचसीआर की वित्तीय आवश्यकताओं की जांच की और वार्षिक कार्यक्रम बजट को स्वीकृति प्रदान की। भारत ने यूएनएचसीआर के अधिदेश को पूरा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत किया और इस दृष्टिकोण को दोहराया कि विस्थापित व्यक्तियों और शरणार्थियों की उनके घरों में सुरक्षित, त्वरित और सतत वापसी शरणार्थियों की आगम का समाधान करने का बेहतर दीर्घकालिक समाधान है।

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ)

भारत ने इस वर्ष डब्ल्यूआईपीओ की बैठकों और स्थायी समिति की बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लिया। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के एक प्रतिनिधिमंडल ने सचिव (डीपीआईआईटी) के नेतृत्व में जिनेवा में 09-17 जुलाई को 65^{वाँ} डब्ल्यूआईपीओ आम सभा (जीए 65) में भाग लिया। जीए 65 के दौरान, भारत ने बौद्धिक संपदा (आईपी) में भारत की उपलब्धियों को साझा करते हुए "क्रिएटिव इंडिया: इनोवेटिव इंडिया" पर एक मंडप तैयार किया। सचिव (डीपीआईआईटी) और डब्ल्यूआईपीओ महानिदेशक ने भारतीय मंडप के उद्घाटन समारोह के दौरान अनेक भारतीय भाषाओं में भारतीय अनुकूलन पर आईपी डायग्नोस्टिक टूल को संयुक्त रूप से लॉन्च किया।

डब्ल्यूआईपीओ के सदस्य देशों ने 13-24 मई को जिनेवा में आयोजित राजनयिक सम्मेलन के दौरान आनुवंशिक संसाधनों और संबद्ध पारंपरिक ज्ञान के संबंध में 2024 में दो संधियों पर हस्ताक्षर किए; और 11-22 नवंबर को रियाद में डिजाइन कानून पर हस्ताक्षर किए। डीपीआईआईटी के नेतृत्व में भारतीय अंतर-मंत्रालयी प्रतिनिधिमंडलों ने दोनों संधियों संबंधी वार्ता में सक्रिय रूप से भाग लिया और संबंधित राजनयिक सम्मेलनों में उनके पारित होने हेतु शामिल हुए।

डब्ल्यूआईपीओ का वैश्विक नवाचार सूचकांक (जीआईआई) राजनीतिक वातावरण, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और ज्ञान सृजन पर उपायों सहित लगभग 80 संकेतकों वाले नवाचार मापदंडों पर अर्थव्यवस्थाओं को रैंक प्रदान करता है। जीआईआई 2024 ने दुनिया भर की 133 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया, जिसमें भारत, मध्य और दक्षिणी एशिया की 10 अर्थव्यवस्थाओं में पहले स्थान पर था; 38 निम्न-मध्यम आय समूह अर्थव्यवस्थाओं में पहले स्थान पर था; और अपनी समग्र रैंकिंग में सुधार करते हुए 39^{वाँ} स्थान पर पहुंच गया है।

डीपीआईआईटी का एक प्रतिनिधिमंडल 18-20 मार्च 2024 को जिनेवा में ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन और भौगोलिक संकेत कानून संबंधी स्थायी समिति के 47^{वाँ} सत्र में शामिल हुआ। डीपीआईआईटी के प्रतिनिधिमंडल ने 17-19 अप्रैल 2024 को जिनेवा में कॉपीराइट और संबंधित अधिकारों पर स्थायी समिति के 45^{वाँ} सत्र भाग लिया।

अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग के एक प्रतिनिधिमंडल ने 01-03 मई को जिनेवा में विकास और बौद्धिक संपदा संबंधी डब्ल्यूआईपीओ की समिति की बैठक में भाग लिया। पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक कार्यालय के एक प्रतिनिधिमंडल ने 07-11 अक्टूबर को जिनेवा में मार्क के अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण के लिए मैड्रिड प्रणाली के कानूनी विकास संबंधी कार्य समूह के 22^{वाँ} सत्र में भाग लिया।

9-10 अक्टूबर को जिनेवा में आयोजित 2024 डब्ल्यूआईपीओ बौद्धिक संपदा न्यायाधीश फोरम में भारत के सर्वोच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने भाग लिया।

संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (यूएनआईटीएआर)

यूएनआईटीएआर के अनुरोध पर भारत ने सितंबर में भारतीय वायु सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी को एक वर्ष की अवधि के लिए यूएनआईटीएआर में टीम लीडर, मिलिटरी पिलर के रूप में नियुक्त किया।

यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (यूपीयू)

यूपीयू ने 9 अक्टूबर को 150^{वाँ} वर्षगांठ मनाई। भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने बर्न में आयोजित वर्षगांठ स्मारक समारोह में भाग लिया।

डाक विभाग के सचिव ने यूपीयू की प्रशासन परिषद और डाक संचालन परिषद की बैठकों में भाग लेने के लिए 06-08 नवंबर को स्विट्जरलैंड की यात्रा की।

भारत सरकार ने यूपीयू में एक वरिष्ठ भारतीय डाक सेवा अधिकारी को नियुक्त किया, जो 07 अक्टूबर को यूपीयू में शामिल हुए।

यूएनईएससीएपी

भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने यूएनईएससीएपी (80सीएस) के 80^{वाँ} आयोग सत्र में सक्रिय रूप से भाग लिया, जो 22 से 26 अप्रैल तक बैंकॉक के यूएन कॉन्फ्रेंस सेंटर में आयोजित किया गया था। इस सत्र का विषय था "एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सतत विकास के लिए डिजिटल नवाचार का लाभ उठाना"। भारत ने यूएनईएससीएपी द्वारा आयोजित डिजिटल नवाचार मेले में भी भाग लिया और मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए कार्यक्रम के तहत अपनाए गए एकीकृत नियोजन के परिवर्तनकारी दृष्टिकोण को प्रदर्शित करने के लिए "पीएम-गति शक्ति" पहल का प्रदर्शन किया। साथ ही इस अवधि के दौरान यूएनईएससीएपी की विभिन्न अंतर-सरकारी बैठकों में भी भाग लिया।

यूनेस्को

यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधिमंडल ने यूनेस्को में भारत के हितों को सक्रियता से आगे बढ़ाया। यूनेस्को के मूल्यों के अनुरूप शिक्षा और सांस्कृतिक संरक्षण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला गया।

भारत ने अपनी विरासत को प्रदर्शित करते हुए 46^{वाँ} विश्व धरोहर समिति सत्र की मेज़बानी की और असम के अहोम राजवंश के प्राचीन दफ़न टीलों, मोइदुम को 43^{वाँ} विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया। भारत ने वैश्विक संरक्षण प्रयासों के लिए 1 मिलियन अमरीकी डॉलर देने का संकल्प लिया। भारतीय मिशन ने मुक्त विज्ञान और भू-पाकों पर यूनेस्को-एड कार्यक्रम आयोजित किए और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जैसे सांस्कृतिक अवसरों का आयोजन किया। इसके अतिरिक्त, पेरिस में भारत के स्थायी



प्रधानमंत्री मोदी यूनेस्को की महानिदेशक ऑड्रे अज़ोले के साथ नई दिल्ली में जुलाई 2024 में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में विदेश से लौटी कलाकृतियों की समीक्षा करते हुए

प्रतिनिधिमंडल ने यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें शिक्षा, विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुम्बकम् पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें सांस्कृतिक मूल्यों और नैतिकता के महत्व पर जोर दिया गया। विश्व हिंदी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस और ऐसे अन्य अवसर भी नियमित रूप से मनाए गए।

वर्ष 2024 की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

1. विश्व धरोहर समिति का 46^{वाँ} सत्र, नई दिल्ली: प्रधानमंत्री ने विश्व धरोहर समिति के 46^{वाँ} सत्र का उद्घाटन किया, जो 21-31 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह पहली बार था जब भारत ने इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम की मेज़बानी की। भारत मंडपम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र में आयोजित यह बैठक न केवल अपने विचार-विमर्श के लिए अपितु वैश्विक मंच पर भारत की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए भी महत्वपूर्ण रही। भारत ने विकासशील देशों में संरक्षण प्रयासों का समर्थन करने के लिए यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र को 1 मिलियन अमरीकी डॉलर प्रदान करने की प्रतिबद्धता जताई। इस बैठक में युवा पेशेवरों और साइट प्रबंधकों के लिए मंचों सहित अनेक अन्य कार्यक्रम शामिल थे, जिनका उद्देश्य ज्ञान साझा करना और विरासत संरक्षण में सर्वोत्तम परिपाटियों पर ध्यान केंद्रित करना था।

2. अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियां/घटनाएं:

- क) कलाकृतियों की वापसी: सांस्कृतिक संपत्ति को उसके मूल देश में वापस लौटाने या अवैध विनियोग के मामले में उसकी वापसी को बढ़ावा देने के लिए अंतर-सरकारी समिति (आईसीपीआरसीपी) के 24^{वाँ} सत्र में 29 से 31 मई 2024 तक भारत ने चोल युग की ताम्र प्लेटों (वर्तमान में लीडेन विश्वविद्यालय, नीदरलैंड में) की वापसी की मांग की।
- ख) आई.सी.एच. में भागीदारी: भारत ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु कन्वेंशन (आई.सी.एच.) के सदस्य देशों की महासभा के 10^{वाँ} सत्र में भाग लिया।
- ग) वैज्ञानिक सहयोग: भारत ने पेरिस में यूनेस्को के साथ मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन की सह-मेजबानी की, जिसमें मुक्त विज्ञान और ज्ञान साझाकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया। गोलमेज सम्मेलन की परिकल्पना और लॉन्चिंग 2023 में भारत की जी20 अध्यक्षता के दौरान शेरपा-ट्रैक पहल के रूप में की गई थी। इस कार्यक्रम में 29 देशों और 06 अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
- घ) क्षमता निर्माण: यूनेस्को ग्लोबल जियोपाक्स पर पहली क्षमता निर्माण प्रशिक्षण-सह-कार्यशाला का आयोजन नई दिल्ली में किया

गया, जिसका उद्देश्य भारतीय संदर्भ में यूनेस्को ग्लोबल जियोपार्क्स की अवधारणा को प्रस्तुत करना और उसका अन्वेषण करना था। इस कार्यक्रम का आयोजन यूनेस्को के सहयोग से खनन मंत्रालय के नेटवर्क द्वारा किया गया।

ड) भारत ने विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क (डब्ल्यूएनबीआर) में प्रवेश के लिए बांधवगढ़ क्षेत्र (मध्य प्रदेश) और देहांग-देबांग बायोस्फीयर रिजर्व (अरुणाचल प्रदेश) के नामांकन प्रस्तुत किए।

च) मुंबई ने 2026 में XVIII यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क (यूसीसीएन) वार्षिक सम्मेलन का मेजबान बनने का प्रस्ताव करते हुए आवेदन प्रस्तुत किया।

छ) अंतर्राष्ट्रीय महासागरीय आयोग (आईओसी): भारत यूनेस्को के महासागर विज्ञान दशक (2021-2030) में अपना योगदान करता रहा है। आईओसी ने "दशकीय कार्रवाइयों" की एक नई श्रृंखला का समर्थन किया, जिसमें महासागर संरक्षण के संबंध में वैज्ञानिक सहयोग और पहल शामिल हैं। भारत इस क्षेत्र के अंतर्गत परियोजनाओं में सक्रिय रहा है, जो समुद्री जैव विविधता, जलवायु लचीलापन और सतत महासागर प्रबंधन जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती हैं।

ज) इस वर्ष यूनेस्को के 3 सम्मेलनों के लिए 86,162 अमेरिकी डॉलर की राशि आवंटित की गई थी। ये हैं (i) विश्व विरासत निधि; (ii) आईसीएच की सुरक्षा के लिए निधि; और (iii) सांस्कृतिक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय निधि (आईएफसीडी)।

झ) यूनेस्को पीठ:

क. भारत के कालीकट विश्वविद्यालय में सामुदायिक आधारित विकलांगता प्रबंधन और पुनर्वास अध्ययन के संबंध में यूनेस्को पीठ संबंधी करार का 30 जून 2028 तक नवीनीकरण।

ख. महिलाओं के प्रति समानता और महिला सशक्तिकरण के संबंध में यूनेस्को पीठ, अमृता विश्व विद्यापीठम, भारत से संबंधित करार का दिसंबर 2028 तक नवीनीकरण।

ग. सतत नवाचार और विकास के लिए अनुभवात्मक शिक्षा के संबंध में यूनेस्को पीठ, अमृता विश्व विद्यापीठम, भारत से संबंधित करार का 30 जून 2028 तक नवीनीकरण।

3. उच्च स्तरीय यात्राएं

भारत से अन्य देशों की

क) 23 मार्च - गुजरात के गृह, उद्योग, संस्कृति मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री ने, आईसीएच सूची के लिए "गुजरात के गरबा" का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पेरिस की यात्रा की। यूनेस्को में भारत के राजदूत/पीआर के साथ गुजरात के प्रतिनिधिमंडल ने यूनेस्को के महानिदेशक से मुलाकात की।

ख) 03 मई - सचिव (खेल) ने पक्षकारों के एंटी-डोपिंग अभिसमय के सम्मेलन (सीओपी9) की असाधारण बैठक में भाग लिया।

ग) 09 - 14 जून - भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक ने 46^{वाँ} विश्व धरोहर सम्मेलन के संबंध में सूचना सत्र में भाग लेने के लिए 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

घ) 11-15 सितम्बर - मेघालय के कला एवं संस्कृति मंत्री ने यूनेस्को अभिलेखागार की कार्यप्रणाली को समझने के लिए 8 सदस्यीय इनटैक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए यूनेस्को की यात्रा की।

अन्य देशों से भारत की

क) 21-22 जुलाई: यूनेस्को के महानिदेशक ने दिल्ली में आयोजित 46^{वाँ} विश्व धरोहर समिति (डब्ल्यूएचसी) की बैठक के लिए भारत की यात्रा की। इस कार्यक्रम में यूनेस्को के संस्कृति के सहायक महानिदेशक और यूनेस्को के विश्व धरोहर केंद्र के निदेशक भी शामिल हुए।

खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ)

2024 के दौरान, भारत सरकार के अनेक आधिकारिक प्रतिनिधिमंडलों ने एफएओ, रोम में प्रमुख बैठकों में भाग लिया।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव ने 14-16 अक्टूबर 2024 तक को आयोजित विश्व खाद्य मंच के दौरान एफएओ हैंड-इन-हैंड इनिशिएटिव फोरम और संयुक्त राष्ट्र दशक के पारिवारिक खेती के वैश्विक पारिवारिक किसान फोरम के उच्च स्तरीय उद्घाटन समारोह में भाग लिया। उन्होंने डब्ल्यूएफपी के महानिदेशक और कार्यकारी निदेशक तथा प्रमुख विकासशील देशों के प्रतिनिधिमंडल प्रमुखों और स्थायी प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सचिव (डीएएफडब्ल्यू) ने आरबीए में कार्यरत भारतीयों और इटली में कृषि फार्मों में काम करने वाले भारतीय नागरिकों के साथ वार्ता की।

08-12 जुलाई के मत्स्य पालन संबंधी एफएओ समिति के लिए मत्स्य पालन विभाग के सचिव ने वानिकी के संबंध में एफएओ समिति के लिए वन महानिदेशक और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के विशेष सचिव के साथ, कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग की कार्यकारी समिति के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और पशु स्वास्थ्य नवाचार पर एफएओ वैश्विक सम्मेलन के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग के सचिव के साथ बैठक की।

2024 में, भारत को सर्वसम्मति से दो वर्ष की अवधि के लिए एफएओ के भीतर दो प्रमुख तकनीकी उप-समितियों के पहले उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। इनमें 2024-2025 के लिए मत्स्य प्रबंधन के संबंध में मत्स्य पालन उप-समिति और 2024-2026 के लिए पशुधन संबंधी कृषि उप-समिति समिति शामिल हैं। भारत का चुनाव मत्स्य प्रबंधन और पशुधन विकास में इसकी वैश्विक स्थिति और योगदान का प्रमाण है। भारत को 2024 में कृषि में जल की कमी के संबंध में वैश्विक ढांचे के संबंध में संचालन समिति (डब्ल्यूएएसएजी) के सदस्य के रूप में चुना गया।

भारत ने आयरलैंड के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस घोषित करने के प्रस्ताव को सह-प्रायोजित किया, जिसका 30 सितंबर से 04 अक्टूबर तक आयोजित कृषि संबंधी एफएओ समिति के 29^{वाँ} सत्र में समर्थन किया गया। इस समर्थन से 2024 में एफएओ परिषद और 2025 में एफएओ सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अनुमोदन का मार्ग प्रशस्त होता है।

अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष (आईवाईएम) का समापन समारोह 29 मार्च को एफएओ मुख्यालय, रोम में आयोजित किया गया, जिसमें एफएओ के वरिष्ठ प्रबंधन, स्थायी प्रतिनिधियों, सरकारों के प्रतिनिधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों/संस्थाओं, किसानों, रसोइयों, उद्योग, छात्रों, शोधकर्ताओं आदि ने भाग लिया।

एफएओ के मत्स्य पालन प्रभाग के निदेशक ने 21 नवंबर को नई दिल्ली में विश्व मत्स्य पालन दिवस 2024 को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने दक्षिण-दक्षिण और त्रिकोणीय सहयोग ढांचे द्वारा संचालित मत्स्य पालन और जलीय कृषि में भारत और एफएओ के बीच रणनीतिक साझेदारी पर प्रकाश डाला।

विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी)

भारत को 2024 में, 2025-2027 तक 3 साल के कार्यकाल के लिए ईसीओएसओसी के माध्यम से डब्ल्यूएफपी कार्यकारी बोर्ड के सदस्य के रूप में फिर से चुना गया। डब्ल्यूएफपी में भारत के समृद्ध योगदान को देखते हुए, डब्ल्यूएफपी कार्यकारी बोर्ड में इसकी उपस्थिति ग्लोबल साउथ के हितों के लिए महत्वपूर्ण है। भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास भागीदारी कोष ने लाओ पीडीआर में लागू किए जाने वाले चावल फोर्टिफिकेशन कार्यक्रम के लिए डब्ल्यूएफपी को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान किए।

डब्ल्यूएफपी के सहायक कार्यकारी निदेशक ने अगस्त में भारत की यात्रा की और डब्ल्यूएफपी इंडिया के साथ साझेदारी में लागू किए गए भारत के सफल खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों के बारे में अधिक जानने के लिए वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों से मुलाकात की। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और डब्ल्यूएफपी के बीच शुष्क भूमि क्षेत्रों में छोटे किसानों, विशेष रूप से महिलाओं की क्षमता निर्माण के लिए एक क्षेत्रीय अनुकूलन परियोजना के संबंध में एक करार पर हस्ताक्षर किए गए। भारत को अप्रैल में 2025-2027 के कार्यकाल के लिए डब्ल्यूएफपी के कार्यकारी बोर्ड के लिए भी चुना गया।

कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष (आईएफएडी)

भारत का आईएफएडी के अभिशासी निकायों के माध्यम से इसके साथ व्यापक नीतिगत संपर्क रहा है। भारत को 2024 में आईएफएडी के कार्यकारी बोर्ड में तीन साल की एक और अवधि अर्थात् 2024-2026 के लिए फिर से चुना गया और 3 साल की अवधि के लिए इसकी मूल्यांकन समिति के सदस्य के रूप में भी चयन किया गया।

अप्रैल 2024 में, भारतीय मिशन ने जम्मू और कश्मीर के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना के लिए आईएफएडी बोर्ड की मंजूरी प्राप्त की, जिसका नाम है "जम्मू और कश्मीर में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धात्मकता सुधार", जिसकी परियोजना लागत 217.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर है और आईएफएडी ऋण घटक 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर है।

विश्व खाद्य सुरक्षा (सीएफएस) के संबंध में संयुक्त राष्ट्र समिति ने भारत को शहरीकरण और ग्रामीण परिवर्तन के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा और पोषण प्राप्त करने के लिए शहरी और अर्ध-शहरी खाद्य प्रणालियों को मजबूत बनाने के संबंध में सीएफएस नीति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिवेदक के रूप में चुना है। सीएफएस एक महत्वपूर्ण अंतर-सरकारी निकाय है जिसका काम रोम स्थित तीन एजेंसियों के बीच फैला हुआ है।

भारत ने इथियोपिया, गिनी और डोमिनिकन गणराज्य के साथ मिलकर 52^{वां} सीएफएस के दौरान “खाद्य सुरक्षा एवं पोषण के लिए भोजन का अधिकार और सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र की भूमिका” के संबंध में एक अन्य कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा और पोषण को बढ़ावा देने एवं एसडीजी 2 अर्थात् भूख समाप्त, को प्राप्त करने में सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र की भूमिका और प्रभाव का आकलन करना था। इस दौरान नीति आयोग के सदस्य ने मुख्य भाषण दिया, जबकि एफएओ, डब्ल्यूएफपी, इथियोपिया और डोमिनिकन गणराज्य से आमंत्रित लोगों ने कार्यक्रम के दौरान चर्चा की। इस कार्यक्रम को बेहतर प्रतिक्रिया मिला, जिसमें बड़ी संख्या में अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों से आए लोगों ने भाग लिया।

अंतर संसदीय संघ (आईपीयू)

148^{वां} और 149^{वां} आईपीयू सभाएं क्रमशः 23-27 मार्च और 13-17 अक्टूबर को जिनेवा में आयोजित की गईं। दोनों आईपीयू सभाओं में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया।

148^{वां} आईपीयू सभा में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राज्य सभा के उपसभापति ने किया और इसमें राज्य सभा सचिवालय के महासचिव, राज्य सभा के 5 सांसद और लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय के 8 अधिकारी शामिल थे। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 148^{वां} आईपीयू सभा के पूर्ण अधिवेशन और पैनल चर्चाओं में भाग लेने के अतिरिक्त आईपीयू के अध्यक्ष, तंजानिया की नेशनल असेंबली की स्पीकर तुलिया एकसन और आर्मेनिया, सर्बिया, थाईलैंड और ट्यूनीशिया के प्रतिनिधिमंडलों के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं।

149^{वां} आईपीयू सभा में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लोकसभा अध्यक्ष ने किया और इसमें राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के 5 सांसद, राज्यसभा के 3 सांसद, लोकसभा और राज्यसभा सचिवालयों के महासचिव और लोकसभा एवं राज्यसभा सचिवालयों के 11 अधिकारी शामिल थे। 149^{वां} आईपीयू सभा के पूर्ण सत्र और पैनल चर्चाओं में भाग लेने के अतिरिक्त, भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने आईपीयू के अध्यक्ष, तंजानिया की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष के साथ-साथ अल्जीरिया, आर्मेनिया, मालदीव, नामीबिया, ओमान, सेशेल्स, स्विट्जरलैंड, नेपाल, भूटान और थाईलैंड के प्रतिनिधिमंडलों के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं। अध्यक्ष ने जिनेवा के एरियाना पार्क में गांधीजी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और भारत के स्थायी मिशन के हंसा मेहता हॉल में आयोजित सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया।

अंटार्कटिक और आर्कटिक मामले

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में भारत ने 20-30 मई को कोच्चि में 46^{वाँ} अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक (एटीसीएम-46) और 26^{वाँ} पर्यावरण संरक्षण समिति (सीईपी-26) की बैठक आयोजित की। अंटार्कटिक मामलों के संबंध में वैश्विक बैठक के दौरान 56 देशों के 400 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। एटीसीएम-46 का उद्घाटन पृथ्वी विज्ञान और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने किया। विदेश मंत्रालय की ओर से सचिव (पश्चिम) ने उद्घाटन सत्र में भाग लिया। भारत द्वारा आयोजित 46^{वाँ} एटीसीएम में पहली बार

अंटार्कटिका में पर्यटन को नियमित करने के लिए एक समर्पित कार्य समूह तैयार किया गया।

भारत ने दिसंबर 2023 से स्वालबार्ड, नॉर्वे के न्यू एलेसंड में स्थित भारत के आर्कटिक अनुसंधान केंद्र, हिमाद्री में शीतकालीन अभियान शुरू किया और 2024 से पूरे वर्ष स्वालबार्ड में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। भारत ने 19-21 अक्टूबर को रेक्जाविक में आयोजित 2024 आर्कटिक सर्कल असेंबली बैठक में भी भाग लिया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के संयुक्त सचिव ने किया।

अध्याय

13

जी20

जी-20 2023 में अपनी सफल की अध्यक्षता के बाद, भारत 2024 में ब्राजील की जी-20 अध्यक्षता के दौरान एक प्रभावशाली ट्रोइका (भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका) सदस्य के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखेगा। भारत की अध्यक्षता के दौरान किए गए कार्यों के आधार पर, ब्राजील ने तीन प्राथमिकताओं की पहचान की:

- (i) सामाजिक समावेशन और भूख और गरीबी के विरुद्ध लड़ाई।
- (ii) ऊर्जा परिवर्तन और इसके आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय आयामों में सतत विकास को बढ़ावा देना; तथा
- (iii) 'एक न्यायपूर्ण विश्व और एक संपोषणीय ग्रह का निर्माण' की व्यापक थीम के अंतर्गत वैश्विक शासन संस्थाओं में सुधार।

सक्रिय भागीदारी के साथ, भारत ने भू-राजनीति, जलवायु परिवर्तन आदि जैसे विवादास्पद मुद्दों पर एक पुल निर्माता के रूप में काम किया, जो ब्राजील के जी-20 अध्यक्षता की सफलता के लिए महत्वपूर्ण थे। साथ ही, भारत ने यह सुनिश्चित करने में ब्राजील का समर्थन किया कि विकास एजेंडा केंद्र में रहे और जी-20 में वैश्विक दक्षिण के हितों को बढ़ावा मिले।

प्रमुख घटनाक्रम

ब्राजील की जी20 अध्यक्षता 2024

ट्रोइका के एक भाग के रूप में, ब्राजील के जी20 अध्यक्षता के दौरान भारत की ओर से परिणामों में सार्थक योगदान देने के लिए उच्च स्तर की भागीदारी देखी गई। मंत्रिस्तरीय बैठकों में विदेश मंत्री, वित्त मंत्री और संस्कृति,

पर्यटन, वाणिज्य और उद्योग, शिक्षा, कृषि और किसान कल्याण, तथा श्रम और रोजगार जैसे विभागों के अन्य मंत्रियों की महत्वपूर्ण भागीदारी देखी गई।



विदेश मंत्री ने अक्टूबर 2024 में न्यूयॉर्क में 79^{वां} यूएनजीए के अवसर पर जी-20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया



नवंबर 2024 में रियो डी जेनेरियो में नेताओं के शिखर सम्मेलन में अन्य जी20 नेताओं के साथ प्रधानमंत्री

विदेश मंत्री ने 25 सितंबर को आयोजित दूसरी जी20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भी भाग लिया, जो 79^{वें} संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सप्ताह के साथ-साथ आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान, एक ऐतिहासिक "वैश्विक शासन सुधार पर कार्रवाई का आह्वान" अपनाया गया। तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री (वीएम) ने रियो डी जेनेरियो में 21-22 फरवरी को आयोजित पहली जी20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया।

भारत के जी-20 शेरपा ने ब्राजील में आयोजित तीन शेरपा बैठकों में भाग लिया और एक अन्य वर्चुअल रूप से आयोजित की गई। सचिव (ईआर) ने 22-23 जुलाई को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित जी-20 विकास मंत्रियों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। बैठक के दौरान दो परिणाम दस्तावेज़- (i) असमानताओं को कम करने के लिए जी-20 विकास मंत्रियों की घोषणा; और (ii) पेयजल, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने पर कार्रवाई के लिए मंलिस्तरीय आह्वान को अपनाया गया।

ब्राजील ने जी-20 प्रक्रिया में व्यापक हितधारक और सामाजिक भागीदारी के लिए 13 सहभागिता समूहों की बैठकें भी आयोजित कीं। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) ने 12-14 मई को रियो डी जेनेरियो में आयोजित न्यायपालिका 20 के शिखर सम्मेलन में भाग लिया। राज्य सभा के उपसभापति ने 06-08 नवंबर को ब्रासीलिया में आयोजित संसद 20 शिखर सम्मेलन में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने 16-18 जून को बेलेम में सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों (एसएआई 20) की बैठक में भाग लिया।

प्रधानमंत्री ने 18-19 नवंबर को रियो डी जेनेरियो में आयोजित 19^{वें} जी20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। अपने भाषणों में उन्होंने बहुआयामी गरीबी

को कम करने और जन-केंद्रित नीतियों के माध्यम से सामाजिक सेवाएं प्रदान करने में भारत की सफलता पर प्रकाश डाला, साथ ही वैश्विक दक्षिण के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने विकासशील देशों में एआई के बढ़ते प्रभाव और किफायती ऊर्जा संक्रमण के महत्व पर भी प्रकाश डाला। विकसित और विकासशील देशों के बीच उनकी टिप्पणियों की व्यापक रूप से सराहना की गई क्योंकि वे मानव-केंद्रित, रचनात्मक और विकासोन्मुख थीं। यह पहला जी20 शिखर सम्मेलन था जिसमें भारत की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को शामिल किए जाने के बाद एक स्थायी सदस्य के रूप में भाग लिया।

ब्राजील के जी20 अध्यक्षता का प्रमुख कार्य भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन था, जिसे रियो शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के दौरान लॉन्च किया गया था। भारत संस्थापक सदस्य के रूप में गठबंधन में शामिल हुआ। शिखर सम्मेलन के दौरान अपनाए गए रियो जी20 नेताओं के घोषणापत्र ने भारत की जी20 परम्परा का समर्थन किया, जिसमें नई दिल्ली शिखर सम्मेलन के कई संदर्भ दिए गए। इसके अलावा, नई दिल्ली नेताओं के घोषणापत्र के प्रमुख परिणामों को आगे बढ़ाया गया, जिसमें पर्यावरण के लिए जीवनशैलीको मुख्यधारा में लाना, एसडीजीपर जी20 वाराणसी कार्य योजना में तेजी लाना, विकास के लिए डीपीआईआई और डेटा का लाभ उठाना, महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देना और पारंपरिक चिकित्सा को महत्व देना शामिल है। नई दिल्ली शिखर सम्मेलन के जनादेश पर निर्माण करते हुए, बेहतर, बड़े और अधिक प्रभावी बहुपक्षीय विकास बैंकों के लिए रोडमैप को रियो में नेताओं द्वारा अनुमोदित किया गया। भारत ने जलवायु वित्त को अरबों से खरबों डॉलर तक बढ़ाने की महत्वाकांक्षा को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया और जलवायु वित्त पर एक सफल नया सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (एनसीक्यूजी) प्राप्त किया।

इसके अलावा, विभिन्न कार्य समूह की बैठकों के दौरान, प्रमुख भारतीय प्राथमिकताओं पर साइड इवेंट आयोजित किए गए। रियो डी जेनेरियो में विकास मंत्रियों की बैठक से पहले और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में दूसरे विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान पर्यावरण के लिए जीवनशैली के महत्व पर प्रकाश डालने वाले साइड इवेंट भी आयोजित किए गए। अंत में, रियो शिखर सम्मेलन के दौरान, भारत ने डीपीआई, एआई और डेटा फॉर अभिशासन पर एक साइड-इवेंट की मेजबानी की। प्रधानमंत्री के साथ इटली, स्पेन, पुर्तगाल, नॉर्वे और सिंगापुर के प्रधानमंत्री, संयुक्त राष्ट्र महासचिव, मैक्सिको के ऊर्जा मंत्री और विश्व बैंक, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ और डब्ल्यूएचओ के प्रमुख शामिल हुए। इस कार्यक्रम में संयुक्त ट्रोइका घोषणा का समर्थन भी किया गया।

दक्षिण अफ्रीका की जी20 अध्यक्षता 2025

दक्षिण अफ्रीका ने 01 दिसंबर को जी20 की अध्यक्षता संभाली। 9-11 दिसंबर को आयोजित पहली शेरपा बैठक में, दक्षिण अफ्रीकी अध्यक्षता ने अफ्रीका के विकास एजेंडे, अफ्रीका और वैश्विक दक्षिण की विकासशील

अर्थव्यवस्थाओं के लिए समर्थन जुटाने और इंडोनेशियाई, भारतीय और ब्राजील के जी20 अध्यक्षता की सफलताओं पर निर्माण करने पर अपने व्यापक ध्यान को रेखांकित किया। 'एकजुटता, समानता, स्थिरता' के समग्र विषय के अंतर्गत, दक्षिण अफ्रीका ने तीन अस्थायी कार्य बल स्थापित किए हैं:

- (i) समावेशी आर्थिक विकास, औद्योगीकरण, रोजगार और असमानता में कमी,
- (ii) खाद्य सुरक्षा, और
- (iii) उच्च स्तरीय परिणाम प्रदान करने के लिए सतत विकास हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा शासन और नवाचार पर विचार किया जाएगा तथा विकासशील देशों में पूंजी की उच्च लागत के मुद्दे के समाधान के लिए पूंजी लागत आयोग का गठन किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, दक्षिण अफ्रीकी अध्यक्षता प्रथम चक्र में जी-20 के कार्यों की समीक्षा करेगी तथा इस चक्र की अध्यक्षता 2025 में समाप्त होने पर विचार-विमर्श करेगी।

अध्याय

14

बहुपक्षीयआर्थिक संबंध

ब्रिक्स

16^{वां} ब्रिक्स शिखर सम्मेलन

‘न्यायसंगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को सुदृढ़ बनाना’ विषय पर 16^{वां} ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 22-24 अक्टूबर को कज़ान में रूस की अध्यक्षता में आयोजित किया गया।

प्रधानमंत्री ने 23 अक्टूबर को शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। विदेश मंत्री ने 24 अक्टूबर को शिखर सम्मेलन के ‘ब्रिक्स प्लस/आउटरीच’ सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। शिखर सम्मेलन के दौरान, नेताओं ने ‘16^{वां} ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कज़ान घोषणा’ को अपनाया और ‘ब्रिक्स भागीदार देश श्रेणी की रूपरेखा’ और ‘संभावित ब्रिक्स भागीदार देशों की सूची’ को अंतिम रूप दिया गया।

ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक और अंतर्राष्ट्रीय संबंध

विदेश मंत्री ने 26 सितंबर को न्यूयॉर्क में 79^{वां} यूएनजीए के दौरान ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 10-11 जून को निज़नी नोवगोरोड में रूस द्वारा ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की एक स्वतंत्र बैठक आयोजित की गई। इसके अतिरिक्त, इसमें ‘विकासशील देशों के साथ ब्रिक्स संवाद’ शीर्षक से एक मंत्रिस्तरीय सत्र भी आयोजित किया गया।

सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने भी बैठक में भाग लिया।

ब्रिक्स ढांचे के अंतर्गत कई मंत्रिस्तरीय बैठकें आयोजित की गईं। परिवहन मंत्रियों की बैठक 6-7 जून को सेंट पीटर्सबर्ग में हुई। पर्यटन मंच और पर्यटन मंत्रियों की बैठक 20-21 जून को मास्को में हुई। खेल मंत्रियों की बैठक 22 जून को कज़ान में हुई। पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 28 जून को हुई, जिसमें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और एमओईएस (एमओईएफसीसी) ने वर्चुअली भाग लिया। चौथी ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक 28 जून को मास्को में हुई। आपदा प्रबंधन के लिए ब्रिक्स मंत्रियों की बैठक 10-11 जुलाई को हुई। 10^{वां} ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन और युवा मंत्रियों की बैठक 22-26 जुलाई को उल्यानोवस्क में हुई, जिसमें युवा मामले और खेल राज्य मंत्री ने भाग लिया। बैठक के दौरान ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन घोषणा को अपनाया गया। 14^{वां} ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक 26 जुलाई को मास्को में हुई। 16 अगस्त को निज़नी नोवगोरोड में 8^{वां} ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। 30 अगस्त को वर्चुअल मोड में जलवायु परिवर्तन पर एक उच्च स्तरीय वार्ता आयोजित की गई, जिसमें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने भाग लिया।

श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक 9-10 सितंबर को सोची में हुई। संस्कृति मंत्रियों की बैठक 11 सितंबर को सेंट पीटर्सबर्ग में हुई। न्याय मंत्रियों की बैठक 18 सितंबर को वर्चुअली हुई। महिला मामलों पर मंत्रिस्तरीय बैठक 20 सितंबर को सेंट पीटर्सबर्ग में हुई। संचार मंत्रियों की बैठक 23-27 सितंबर को इनोपोलिस में हुई। 9^{वां} ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक 26



विदेश मंत्री ने सितंबर 2024 में न्यूयॉर्क में 79^{वाँ} यूएनजीए के अवसर पर ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया

सितंबर को मॉस्को में हुई, जिसमें एमओएस (विद्युत मंत्रालय) ने वर्चुअली भाग लिया। इस बैठक में 9^{वाँ} ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक का एक विज्ञापित जारी की गई। 12^{वाँ} ब्रिक्स विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्रिस्तरीय बैठक 27 सितंबर को मॉस्को में हुई। ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रिस्तरीय बैठक 10-11 अक्टूबर को हुई। ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक 11 अक्टूबर को हुई। 10^{वाँ} ब्रिक्स संसदीय मंच 11-12 जुलाई को सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित किया गया, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ने भाग लिया। बैठक में 10^{वाँ} ब्रिक्स संसदीय मंच पर एक संयुक्त वक्तव्य और ब्रिक्स संसदीय मंच के समझौता-ज्ञापन के लिए एक प्रोटोकॉल को अपनाया गया। सुरक्षा मुद्दों के लिए उत्तरदायी ब्रिक्स उच्च-स्तरीय प्रतिनिधियों की बैठक 10-12 सितंबर को सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित की गई।

भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका वार्ता मंच (आईबीएसए)

आईबीएसए विदेश मंत्रियों की बैठक

न्यूयॉर्क में 79^{वाँ} यूएनजीए के दौरान, विदेश मंत्री ने आईबीएसए विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री (वीएम) ने 22 फरवरी को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आईबीएसए विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इस बैठक के दौरान एक मंत्रिस्तरीय घोषणा को अपनाया गया।



विदेश मंत्री ने ब्राजील के विदेश मंत्री मौरो विप्रा और दक्षिण अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोग मंत्री रोनाल्ड लामोला के साथ सितंबर 2024 में न्यूयॉर्क में 79^{वाँ} यूएनजीए के दौरान आईबीएसए विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया।

आईबीएसएएमएआर अभ्यास 2024

आईबीएसएएमएआर अभ्यास का 8^{वाँ} संस्करण 6-18 अक्टूबर को दक्षिण अफ्रीका के तट पर आयोजित किया गया। भारतीय नौसेना के स्टील्थ फ्रिगेट, आईएनएस तलवार ने अभ्यास में भाग लिया।



विदेश मंत्री ने नवंबर 2024 में फिउग्गी में जी7 विदेश मंत्रियों की बैठक के आउटरीच सत्र में भाग लिया

एशिया सहयोग वार्ता (एसीडी)

19^{वाँ} एसीडी मंत्रिस्तरीय बैठक

सचिव (ईआर) ने 24 जून को तेहरान में 19^{वाँ} एसीडी मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। बैठक के दौरान एशिया सहयोग वार्ता की प्रक्रिया के नियम, एसीडी सचिवालय के कामकाज के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और तेहरान घोषणा को अपनाया गया।

तीसरा एसीडी शिखर सम्मेलन

एमओएस (केवीएस) ने कतर में 2-3 अक्टूबर को तीसरे एसीडी शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। बैठक के दौरान दोहा घोषणा को अपनाया गया।

जी7

50^{वाँ} जी7 शिखर सम्मेलन 2024

प्रधानमंत्री ने इटली की अध्यक्षता में 14 जून को अपुलिया में 50^{वाँ} जी7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में भाग लिया। इस सत्र में एआई, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागर पर ध्यान केंद्रित किया गया। इटली ने 11 आउटरीच देशों-

अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ब्राजील (जी20 ट्रोइका), होली सी, भारत (जी20 ट्रोइका), जॉर्डन, केन्या, मॉरिटानिया (एयूअध्यक्ष), ट्यूनीशिया, तुर्किये, संयुक्त अरब अमीरात और अफ्रीकी विकास बैंक (एएफडीबी), अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी), विश्व बैंक (डब्ल्यूबी), और संयुक्त राष्ट्र (यूएन) सहित पाँच अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया। जी7 शिखर सम्मेलन के दौरान, प्रधानमंत्री ने जी7 के नेताओं, अन्य आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ द्विपक्षीय बैठकें और चर्चाएँ कीं।

भारत ने कई जी7 मंत्रिस्तरीय बैठकों में भाग लिया। विदेश मंत्रियों की बैठक का आउटरीच सत्र 26 नवंबर को फिउग्गी में आयोजित किया गया था। भारत को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया था, और विदेश मंत्री ने बैठक में भाग लिया।

जी7 व्यापार मंत्रिस्तरीय का आउटरीच सत्र 16-17 जुलाई को जियोवानी रेजियो कैलाब्रिया में आयोजित किया गया था, जिसमें वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने भाग लिया था। संस्कृति मंत्रियों की बैठक 20-21 सितंबर को नेपल्स में आयोजित की गई थी, जिसमें सचिव (संस्कृति मंत्रालय) ने भाग लिया था। नवाचार और प्रौद्योगिकी मंत्रियों की बैठक 10 अक्टूबर को रोम में आयोजित की गई थी, जिसमें सचिव (एमआईआईटीवाई) ने भाग लिया था। स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक 9-11 अक्टूबर को इटली में आयोजित की गई थी, जिसमें सचिव (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय) ने भाग लिया था। पर्यटन मंत्रियों की बैठक 13-15 नवंबर को फ्लोरेंस में आयोजित की गई थी, जिसमें एमओएस (पर्यटन मंत्रालय) ने भाग लिया था।

अध्याय

15

निरस्त्रीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामले

वर्ष 2024 में भारत ने निरस्त्रीकरण, अप्रसार और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित बहुपक्षीय मंचों में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा क्षेत्र में अपने राष्ट्रीय सुरक्षा हितों और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा गया। वर्ष के दौरान भारत ने द्विपक्षीय बैठकें भी कीं और इन मुद्दों पर क्षेत्रीय मंचों पर अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत किए। भारत के योगदान ने सार्वभौमिक और गैर-भेदभावपूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण के लक्ष्य के प्रति अपनी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को रेखांकित किया और अंतरिक्ष, समुद्री और सामूहिक विनाश के हथियारों के अप्रसार जैसे क्षेत्रों में वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए समर्थन दिया, जबकि विभिन्न देशों द्वारा विकसित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा वातावरण और पहलों को संबोधित किया।

संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) की पहली समिति

भारत ने रचनात्मक रूप से भाग लिया और 07 अक्टूबर से 08 नवंबर तक न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) की पहली समिति के 79^{वाँ} सत्र में निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों पर अपने सैद्धांतिक पदों और विचारों को प्रस्तुत किया।

79^{वाँ} यूएनजीए प्रथम समिति ने चार प्रस्तावों को अपनाया जिन्हें भारत द्वारा हर वर्ष प्रस्तुत किया जाता है। “आतंकवादियों को सामूहिक विनाश के हथियार हासिल करने से रोकने के उपाय” और “अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और निरस्त्रीकरण के संदर्भ में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका” पर प्रस्तावों को समिति द्वारा फिर से सर्वसम्मति से अपनाया गया। प्रथम समिति में भारत के दो अन्य प्रस्ताव, “परमाणु हथियारों के उपयोग के निषेध पर सम्मेलन”-

जो परमाणु हथियारों के उपयोग या उपयोग की धमकी को प्रतिबंधित करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन पर चर्चा करने का आह्वान करता है- और “परमाणु खतरे को कम करना”- जो परमाणु हथियारों के जानबूझकर या आकस्मिक उपयोग के जोखिम को कम करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान करता है- को भी संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के व्यापक समर्थन से अपनाया गया।

निरस्त्रीकरण सम्मेलन (सीडी)

भारत निरस्त्रीकरण सम्मेलन (सीडी) के 2024 सत्र के छह अध्यक्षों में से पहला था, जिसने परमाणु निरस्त्रीकरण, परमाणु युद्ध की रोकथाम और सभी संबंधित मामलों, बाहरी अंतरिक्ष में हथियारों की दौड़ की रोकथाम, सामूहिक विनाश के नए प्रकार के हथियारों और हथियारों में पारदर्शिता सहित सीडी के सभी मुख्य एजेंडा मदों पर अपनी स्थिति प्रस्तुत की। एक महत्वपूर्ण सफलता में, सीडी जून 2024 में कार्य के कार्यक्रम पर आम सहमति तक पहुँचने में सक्षम थी, जो काफी हद तक वर्ष की शुरुआत में प्रस्तुत भारतीय प्रस्ताव पर आधारित थी।

भारत ने वर्ष के दौरान परमाणु निरस्त्रीकरण सत्यापन (एनडीवी) पर 25-सदस्यीय सरकारी विशेषज्ञों के समूह (जीजीई) के सत्रों में भी भाग लिया। भारत ने अन्य मंचों पर निरस्त्रीकरण से संबंधित मुद्दों पर बैठकों में भाग लिया, जिनमें संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण अनुसंधान संस्थान (यूएनआईडीआईआर) और अन्य थिंक टैंक द्वारा आयोजित बैठकें शामिल हैं।

संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग (यूएनडीसी)

यूएनडीसी ने 2024 के लिए अपना वार्षिक मूल सत्र 01-19 अप्रैल तक न्यूयॉर्क में आयोजित किया, जिसमें इस वर्ष एक नया 3-वर्षीय चक्र शुरू हो रहा है। दोनों कार्य समूह परमाणु निरस्त्रीकरण और उदीयमान प्रौद्योगिकियों के सुरक्षा निहितार्थों के विषयों पर चर्चा करेंगे। भारत ने यूएनडीसी की बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लिया।

रासायनिक हथियार सम्मेलन (सीडब्ल्यूसी)

रासायनिक हथियार निषेध संगठन (ओपीसीडब्ल्यू) में, भारत ने रासायनिक हथियार विनाश, उद्योग सत्यापन, राष्ट्रीय उपायों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संदर्भ में रासायनिक हथियार सम्मेलन (सीडब्ल्यूसी) के कार्यान्वयन पर काम किया। भारत ने हेग में राज्य दलों के 29^{वाँ} सम्मेलन में रचनात्मक रूप से भाग लिया, जिसमें सम्मेलन के कार्यान्वयन और पिछले वर्ष के दौरान ओपीसीडब्ल्यू की गतिविधियों का मूल्यांकन किया गया और ओपीसीडब्ल्यू के लिए भविष्य की प्राथमिकताएँ निर्धारित की गईं। भारत ने सम्मेलन और इसके कार्यान्वयन से संबंधित मामलों, विशेष रूप से उद्योग सत्यापन और निरीक्षण व्यवस्था पर अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत किए।

भारत ने वर्ष के दौरान सम्मेलन के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा किया और भारत में रासायनिक सुविधाओं के अनुसूचित निरीक्षणों के सुचारु संचालन के लिए ओपीसीडब्ल्यू को समर्थन दिया। भारत ने ओपीसीडब्ल्यू तकनीकी सचिवालय के सहयोग से हैदराबाद में भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी) द्वारा आयोजित विश्लेषणात्मक और प्रयोगशाला कौशल विकसित करने पर पाठ्यक्रमों के माध्यम से ओपीसीडब्ल्यू की क्षमता निर्माण गतिविधियों में योगदान दिया। भारत ने सीडब्ल्यूसी के कार्यान्वयन की दिशा में केन्या के लिए क्षमता निर्माण सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ओपीसीडब्ल्यू प्रायोजित मेंटरशिप कार्यक्रम में भाग लिया। भारत ने 25-26 अक्टूबर को ओपीसीडब्ल्यू और मोरक्को द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित सीडब्ल्यूसी कार्यान्वयन में एआई पर पहले वैश्विक सम्मेलन में भी भाग लिया।

2024 ओपीसीडब्ल्यू हेग पुरस्कार 25 नवंबर 2024 को भारतीय रासायनिक परिषद (आईसीसी) को प्रदान किया गया। यह पहली बार था जब पुरस्कार ने किसी रासायनिक उद्योग निकाय के प्रयासों को मान्यता दी। इस पुरस्कार ने भारत में रासायनिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, सम्मेलन के अनुपालन और उद्योग-व्यापी सुरक्षा प्रथाओं को बढ़ाने में आईसीसी द्वारा निभाई गई भूमिका को मान्यता दी।

जैविक एवं विषैले हथियार सम्मेलन (बीटीडब्ल्यूसी)

भारत ने 09-13 अगस्त और 02-13 दिसंबर को बीटीडब्ल्यूसी को सुदृढ़ करने पर कार्य समूह की बैठकों और 16-18 दिसंबर को बीटीडब्ल्यूसी के सदस्य देशों की वार्षिक बैठक में सक्रिय रूप से भाग लिया। बैठकों के दौरान, भारत ने सम्मेलन को सुदृढ़ करने, राष्ट्रीय कार्यान्वयन को बढ़ाने,

प्रतिक्रिया और तैयारियों के प्रयासों को बढ़ावा देने, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय विकास की समीक्षा करने, सामान्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सहायता, और बीटीडब्ल्यूसी के अंतर्गत वैज्ञानिक समीक्षा तंत्र की स्थापना सहित अपनी प्राथमिकताओं को रेखांकित किया।

भारत ने विश्वास-निर्माण उपायों (सीबीएम) के हिस्से के रूप में बीटीडब्ल्यूसी को अपनी वार्षिक प्रस्तुतियाँ भी जारी रखीं और विशिष्ट मुद्दों पर अन्य देशों के साथ रचनात्मक रूप से चर्चा की।

पारंपरिक हथियारों पर फोरम

भारत ने 04-08 मार्च और 26-30 अगस्त को जिनेवा में आयोजित कुछ पारंपरिक हथियारों (सीसीडब्ल्यू) पर कन्वेंशन के अंतर्गत घातक स्वायत्त हथियार प्रणालियों (जीजीई ऑन एलएडब्ल्यूएस) के क्षेत्र में उदीयमान प्रौद्योगिकियों पर सरकारी विशेषज्ञों के समूह की बैठकों में भाग लिया, जहां इसने एलएडब्ल्यूएस की साझा और आम समझ की आवश्यकता पर जोर दिया और इस विषय पर आगे की प्रगति के लिए सीसीडब्ल्यू फोरम के महत्व को दोहराया। भारत ने युद्ध के विस्फोटक अवशेषों से संबंधित प्रोटोकॉल वी के उच्च अनुबंध पक्षों के 17^{वाँ} सम्मेलन (02 सितंबर) और खानों, आईईडी और बूबी ट्रैप से संबंधित संशोधित प्रोटोकॉल II के 25^{वाँ} वार्षिक सम्मेलन (03-04 नवंबर) में भी भाग लिया। एक साइड इवेंट में, भारत ने 'सुरक्षित दुनिया के लिए मानवीय खान कार्रवाई' की दिशा में होराइजन समूह द्वारा किए गए योगदान को प्रदर्शित किया।

भारत ने 18-20 जून को जिनेवा, स्विट्जरलैंड में एंटी-पर्सनल माइन बैन कन्वेंशन-अंतर-संघीय बैठकों और पांचवें समीक्षा सम्मेलन के लिए पहली तैयारी बैठक में एक पर्यवेक्षक के रूप में भी भाग लिया। भारत ने इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के प्रावधानों के प्रति अपना सम्मान और उचित विचार दोहराया और विभिन्न देशों के डि-माइनिंग और क्षमता निर्माण पर प्रशिक्षण के लिए अपने योगदान को रेखांकित किया।

इसके अतिरिक्त, भारत ने 23-24 जनवरी को काठमांडू, नेपाल में दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए क्षेत्रीय तैयारी बैठक में भाग लिया। इसके बाद, भारत ने 12-16 फरवरी और 17-28 जून को न्यूयॉर्क में यूएनपीओए, एसएलडब्ल्यू की तैयारी समिति और अंतिम समीक्षा सम्मेलन-4 में भाग लिया। बैठक में एक परिणाम दस्तावेज को अपनाया गया जिसका उद्देश्य एसएलडब्ल्यू की अवैध तस्करी के खिलाफ कार्रवाई के कार्यक्रम के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय ट्रेसिंग इंस्ट्रूमेंट (आईटीआई) के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करना है।

भारत ने 04-05 दिसंबर को काठमांडू, नेपाल में आयोजित एशिया और प्रशांत क्षेत्र में शांति और निरस्त्रीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय केंद्र की बैठक में भाग लिया। इस बैठक में पारंपरिक गोला-बारूद प्रबंधन, एशिया और प्रशांत क्षेत्र पर वैश्विक रूपरेखा (जीएफए) के कार्यान्वयन पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में, दो भारतीय महिला आयुध और गोला-बारूद तकनीकी अधिकारियों ने गोला-बारूद प्रबंधन के क्षेत्र में भारत की श्रेष्ठता

का प्रदर्शन किया और अन्य देशों की महिलाओं को जीएफए के उद्देश्यों की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित किया।

सैन्य क्षेत्र में एआई

भारत ने 09-10 सितंबर को सियोल में कोरिया गणराज्य, नीदरलैंड, यूके, सिंगापुर और केन्या द्वारा सह-आयोजित द्वितीय सैन्य क्षेत्र में उत्तरदायी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आरईएआईएम) शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जिसमें सैन्य अनुप्रयोगों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास और उपयोग का मार्गदर्शन करने के लिए मानदंडों और सिद्धांतों पर चर्चा करने के लिए सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, उद्योग, शिक्षा और नागरिक समाज के हितधारकों को एक साथ लाया गया।

अप्रसार मामले और सामरिक निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाएं

भारत ने सामूहिक विनाश के हथियारों के अप्रसार और सीरिया, डीपीआरके तथा अन्य यूएनएससी समितियों और पैनलों से संबंधित संबंधित घटनाक्रमों से संबंधित विशिष्ट मामलों पर संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिक समितियों के साथ चर्चा की।

भारत के सामूहिक विनाश के हथियारों के अधिनियम 2005 और उसके नियमों के अंतर्गत, विभिन्न सलाहकार समितियों ने वर्ष के दौरान नीति, कार्यान्वयन और अन्य प्रासंगिक मुद्दों से संबंधित अपनी समीक्षा बैठकें कीं।

भारत सामूहिक विनाश के हथियारों और उनकी वितरण प्रणालियों, संबंधित सामग्रियों, उपकरणों और प्रौद्योगिकियों के अप्रसार के लक्ष्यों की दिशा में बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं के सदस्य के रूप में शामिल हुआ। इसमें निर्यात नियंत्रण के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं या कार्यान्वयन के अनुभवों को साझा करना, निर्यात नियंत्रण के लिए दिशा-निर्देशों के विकास/संशोधन में भागीदारी और मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (एमटीसीआर), वासेनार व्यवस्था (डब्ल्यूए) और ऑस्ट्रेलिया समूह (एजी) के अंतर्गत विनियमित सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकियों की सूची, और भारत की राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण सूची या विशेष रसायन, जीव, सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकियों (एससीओएमईटी) को इन व्यवस्थाओं और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) के साथ सुसंगत बनाना शामिल है।

भारत ने बर्लिन में ऑस्ट्रेलिया समूह (एजी) अंतर-सलीय बैठक (जनवरी-फरवरी) और पेरिस में एजी पूर्ण बैठक (जून) में भाग लिया; विना में डब्ल्यूए के विशेषज्ञ समूह और सामान्य कार्य समूह की बैठकें (अप्रैल, मई, सितंबर और अक्टूबर); हेग में एमटीसीआर तकनीकी विशेषज्ञ बैठक (मार्च), संबंधित निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं की नियंत्रण सूचियों और सर्वोत्तम अभ्यास दिशानिर्देशों को विकसित करने के परामर्श के साथ-साथ कार्यान्वयन के अनुभवों, तकनीकी विकास, प्रसार प्रवृत्तियों और इन मुद्दों के उभरने पर उनका समाधान करने पर सूचना का आदान-प्रदान किया।

भारत के वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) पारस्परिक मूल्यांकन (जो 2023 में शुरू हुआ) का समापन जून में सिंगापुर में एफएटीएफ प्लेनरी के साथ हुआ, जिसमें एफएटीएफ की सिफारिशों से संबंधित प्रसार वित्त-पोषण (पीएफ) पर भारत के विधिक ढांचे और नियामक/कार्यान्वयन प्रणाली के मूल्यांकन से संबंधित हमारी एफएटीएफ पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया। एफएटीएफ प्लेनरी ने निष्कर्ष निकाला कि भारत एफएटीएफ आवश्यकताओं के साथ तकनीकी अनुपालन के उच्च स्तर पर पहुंच गया है, और इसकी एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग, काउंटर टेरर फाइनेंसिंग और काउंटर प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग (सीपीएफ) व्यवस्था अच्छे परिणाम प्राप्त कर रही है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इसके सीपीएफ उपाय भी शामिल हैं। पीएफ से संबंधित एफएटीएफ अनुशंसाओं और तत्काल परिणामों पर, भारत को 'काफी हद तक अनुपालन करने वाला' और 'काफी हद तक प्रभावी' माना गया है।

विदेश मंत्रालय ने भारत की एससीओएमईटी सूची के अंतर्गत निर्यात नियंत्रित दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) के नेतृत्व में अंतर-मंत्रालयी कार्य समूह (आईएमडब्ल्यूजी) की निर्यात लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं में योगदान देना जारी रखा; एससीओएमईटी की श्रेणी 6 (युद्ध सामग्री सूची) सैन्य वस्तुओं के निर्यात के लिए रक्षा उत्पादन विभाग (डीडीपी) द्वारा; और परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा परमाणु-संबंधित वस्तुओं के निर्यात के लिए योगदान दिया।

विदेश मंत्रालय अन्य बातों के अलावा निर्यात, अंतिम उपयोग, अंतिम उपयोगकर्ता और गंतव्य की वस्तु को ध्यान में रखते हुए दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं की कुछ श्रेणियों के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और लाइसेंसिंग प्रक्रिया के बेहतर डिजिटलीकरण और संबंधित एजेंसियों के साथ एकीकरण की दिशा में आगे बढ़ने पर डीजीएफटी के साथ काम कर रहा है। विदेश मंत्रालय हमारे राष्ट्रीय अप्रसार उद्देश्यों के संदर्भ में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) और उसके संगठनों सहित प्रवर्तन तंत्रों और एजेंसियों के साथ भी जुड़ा हुआ है।

विदेश मंत्रालय ने अपने साझेदारों जैसे डीजीएफटी, डीडीपी, सीबीआईसी, विभिन्न उद्योग मंडलों और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर पूरे वर्ष भारत के सामरिक निर्यात नियंत्रणों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आउटरीच गतिविधियों में भाग लिया। पिछले कुछ वर्षों में जारी क्षेत्र-विशिष्ट और क्षेत्र-विशिष्ट आउटरीच कार्यक्रमों पर ध्यान देने के साथ-साथ, प्रासंगिक संगठनों के माध्यम से स्टार्ट-अप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों आदि तक पहुंचने पर भी जोर दिया गया।

जनवरी में, विदेश मंत्रालय ने डीजीएफटी और भारत सरकार की अन्य एजेंसियों के साथ नई दिल्ली में सामरिक व्यापार नियंत्रण (एनसीएसटीसी) पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने में भागीदारी की, जिसमें भारत की सामरिक व्यापार नियंत्रण प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया, ताकि दोहरे उपयोग और सैन्य वस्तुओं और प्रौद्योगिकियों के निर्यात से संबंधित अनुपालन को और अधिक सक्षम बनाया जा सके। जबकि पहले चार ऐसे राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं एनसीएसटीसी को एक नए प्रारूप में तैयार किया गया है जिसमें बड़ी अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी (विदेशी प्रतिनिधि और विशेषज्ञ), और विभिन्न

सरकारी संगठनों, संबंधित क्षेत्रों में उद्योग हितधारकों, शिक्षाविदों और अनुसंधान संस्थानों की व्यापक भागीदारी शामिल है, जिसमें कुल 550 से अधिक प्रतिभागी हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1540 समिति के अध्यक्ष और मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (एमटीसीआर) के अध्यक्ष ने मुख्य वक्ता के रूप में 2024 एनसीएसटीसी में भाग लिया।

वर्ष के दौरान आयोजित एससीओएमईटी और निर्यात नियंत्रण अनुपालन और विनियमों पर अतिरिक्त आउटरीच कार्यक्रमों में जुलाई में हैदराबाद में एक कार्यक्रम और नवंबर में मुंबई में एक कार्यक्रम शामिल था, जो एयरोस्पेस, आईटी, बायोटेक, रसायन, रक्षा और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों से इन क्षेत्रों में और इसके आसपास के उद्योगों पर केंद्रित था।

अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए)

भारत ने 16 से 20 सितंबर तक वियना में आयोजित आईएईएमहासम्मेलन के 68^{वां} सत्र में भाग लिया, साथ ही मार्च, जून, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में आयोजित शासी मंडल की बैठकों में भी भाग लिया। इन बैठकों में, भारत ने परमाणु सुरक्षा मुद्दों, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग, तकनीकी सहयोग और परमाणु सुरक्षा और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों से संबंधित विचार-विमर्श में योगदान दिया। भारत और आईएईएने प्रमुख आईएईएकार्यक्रमों के माध्यम से परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग को गहरा करने पर काम किया।

भारत का वैश्विक परमाणु ऊर्जा भागीदारी केंद्र (जीसीएनईपी) नियमित आधार पर उन्नत परमाणु ऊर्जा प्रणालियों, परमाणु सुरक्षा, रेडियोआइसोटोप और विकिरण प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग, रेडियोलॉजिकल सुरक्षा, परमाणु सामग्री लक्षण वर्णन आदि जैसे क्षेत्रों में क्षमता निर्माण के लिए आईएईएऔर विभिन्न भागीदार देशों के साथ सहयोग करता है।

असैन्य परमाणु सहयोग

भारत ने परमाणु ऊर्जा उत्पादन और परमाणु ऊर्जा के अन्य शांतिपूर्ण उपयोगों, जैसे कि चिकित्सा के क्षेत्र में रेडियो आइसोटोप अनुप्रयोगों के क्षेत्र में विभिन्न देशों के साथ काम किया है। परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में सहयोग के लिए जीसीएनईपीने मार्च में पेरू के साथ एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और सितंबर में फ्रांस के साथ समझौता-ज्ञापन का नवीनीकरण किया।

भारत ने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए विभिन्न भागीदारों को शामिल करने वाली परियोजनाओं में भी योगदान देना जारी रखा। यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन (सीईआरएन) के एक सहयोगी सदस्य के रूप में भारत ने सीईआरएनपरिषद और समितियों के सत्रों में भाग लिया।

वर्ष 2005 से अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर (आईटीईआर) के पूर्ण भागीदार के रूप में, भारत ने आईटीईआरपरिषद की बैठकों में भाग लिया और इसके निर्माण में योगदान देना जारी रखा। भारत ने स्कायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी और लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल-वेव

ऑब्जर्वेटरी (एलआईजीओ) और प्रोटॉन इम्प्रूवमेंट प्लान-II परियोजनाओं पर अमेरिका के साथ अपना सहयोग जारी रखा।

बाह्य अंतरिक्ष मामले

भारत ने निरस्तीकरण सम्मेलन में बाह्य अंतरिक्ष से संबंधित मामलों पर सक्रिय रूप से भाग लेना और अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत करना जारी रखा, साथ ही बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर संयुक्त राष्ट्र समिति और उसके सहायक निकायों की बैठकों में भी भाग लिया। बाह्य अंतरिक्ष गतिविधियों की दीर्घकालिक स्थिरता पर कार्य समूह के अध्यक्ष के रूप में, भारत ने बाह्य अंतरिक्ष के सुरक्षित और उत्तरदायी उपयोग के लक्ष्य को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य समूह की बैठकों के दौरान संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के साथ निकटता से जुड़ना जारी रखा।

एक भारतीय विशेषज्ञ बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ की रोकथाम के लिए आगे के व्यावहारिक उपायों पर सरकारी विशेषज्ञों के 25-सदस्यीय समूह का हिस्सा था, जिसे 2022 में यूएनजीएसकल्प 77/383 द्वारा स्थापित किया गया था, जो 05-16 अगस्त को अपने दूसरे सत्र के लिए मिला था। इसने सर्वसम्मति से काम किया और बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ की रोकथाम पर एक अंतरराष्ट्रीय विधिक रूप से बाध्यकारी साधन के पर्याप्त तत्वों पर आगे विचार करने की सिफारिश करते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

भारत ने हेग आचार संहिता (एचसीओसी) के प्रावधानों को लागू करना जारी रखा, जैसे कि भारत के बैलिस्टिक मिसाइल और अंतरिक्ष प्रक्षेपणों की पूर्व-प्रक्षेपण अधिसूचनाएँ और व्यवस्था के लिए वार्षिक घोषणाएँ प्रस्तुत करना। भारत ने 11-12 अप्रैल को वियना में आयोजित एचसीओसीकी 23^{वां} वार्षिक नियमित बैठक में भाग लिया।

समुद्री सुरक्षा मामले

भारत-प्रशांत क्षेत्र और वैश्विक स्तर पर समुद्री सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण हितधारक के रूप में, भारत ने देशों और बहुपक्षीय संगठनों के साथ सक्रिय जुड़ाव बनाए रखा है। भारत ने सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र (आईएफसी-आईओआर) में जुड़ाव का विस्तार किया, जहाँ विभिन्न देशों ने समुद्री क्षेत्र में आपसी समझ और सहयोग बढ़ाने की दिशा में वर्ष के दौरान अपने संपर्क अधिकारियों को तैनात किया।

भारत ने नवंबर में तंजानिया में जिबूती आचार संहिता-जेद्दा संशोधन (डीसीओसी-जेए) की उच्च-स्तरीय बैठक में भाग लिया, जहाँ डीसीओसी-जेएसदस्य राज्यों के साथ भारत के बढ़ते जुड़ाव के अवसरों पर चर्चा की गई। एक बहु-मंजूर प्रतिनिधिमंडल ने 01-03 अक्टूबर को लंदन में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, डीसीओसीके मिलों और डीसीओसी-जेए के सदस्य राज्यों के साथ द्विपक्षीय रूप से चर्चा की। भारत ने एक क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा रणनीति (आरएमएसएस) के विकास में सहायता करने के

लिए प्रतिबद्धता जताई और 11-21 नवंबर तक सऊदी अरब के जेद्दा में आरएमएसएसपर पहली डीसीओसीकार्यशाला की सुविधा प्रदान की।

भारत ने इटली के रोम में 01-03 दिसंबर तक गिनी की खाड़ी के मित्तों (जी7++ एफओजीजी) की पूर्ण बैठक में भाग लिया, जिसमें 2022 और 2023 में गिनी की खाड़ी में अपनी लंबी नौसैनिक तैनाती के साथ-साथ क्षमता विकास की दिशा में विभिन्न पहलों का प्रदर्शन किया गया। भारत ने 05 सितंबर को अवैध समुद्री गतिविधियों पर संपर्क समूह (सीजीआईएमए) की दूसरी पूर्ण बैठक में भी आभासी रूप से भाग लिया।

भारत ने सिंगापुर स्थित एशिया में जहाजों के खिलाफ समुद्री डकैती और सशस्त्र डकैती का प्रतिकार करने पर क्षेत्रीय सहयोग समझौते (आरईसीएपी) के साथ भी जुड़ना जारी रखा। भारतीय उम्मीदवार को 2025-2028 की अवधि के लिए आरईसीएपीसूचना साझाकरण केंद्र के अगले कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया।

उपरोक्त के अलावा, भारत ने क्राइ समुद्री सुरक्षा कार्यकारी समूह (क्यूएमएसडब्ल्यूजी) के माध्यम से समुद्री लचीलेपन के निर्माण और बढ़ाने की दिशा में भारत-प्रशांत क्षेत्र को भी शामिल करना जारी रखा। भारत ने 06-07 जून को सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में क्यूएमएसडब्ल्यूजी बैठक में भाग लिया, जिसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए क्राइ भागीदारों के सहयोगात्मक प्रयासों की दिशा में विभिन्न पहलों का प्रस्ताव रखा। भारत समुद्री डोमेन जागरूकता (आईपीएमडीए) आईओआर कार्यक्रम के लिए हिंद-प्रशांत भागीदारी का नेतृत्व करता है और इसे जल्द ही चालू करने की आशा कर रहा है। भारत ने Q1/2025 के लिए मैती (भारत-प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए समुद्री पहल) का पहला कार्यक्रम भी निर्धारित किया है।

अन्य देशों के साथ संवाद

भारत ने वर्ष के दौरान ऑस्ट्रेलिया (13 अगस्त), वियतनाम (16 अगस्त) और फिलीपींस (13 दिसंबर को उद्घाटन संवाद) के साथ अलग-अलग समुद्री सुरक्षा संवाद आयोजित किए, ताकि समुद्री स्थितियों के आकलन, रुचि के क्षेत्रों में विकास के बारे में दृष्टिकोण, सहयोग के अवसरों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करने के बारे में विचार-विमर्श किया जा सके।

आसियान क्षेत्रीय मंच (एआरएफ) और आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस (एडीएमएम प्लस)

सचिव (पूर्व) ने 07-08 जून को वियनतियाने, लाओ पीडीआर में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक (ईएसएसओएम) और आसियान क्षेत्रीय मंच के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक (एआरएफ एसओएम) में भारत का प्रतिनिधित्व किया। प्रतिभागियों ने मई में इंडोनेशिया और अमेरिका के साथ समुद्री सुरक्षा पर 15^{वीं} एआरएफ

अंतर-संघीय बैठक की भारत द्वारा सह-अध्यक्षता की सराहना की। भारत ने फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनी और अमेरिका के साथ अंतर्राष्ट्रीय जहाज और बंदरगाह सुविधा सुरक्षा (आईएसपीएस) कोड पर प्रशिक्षण मॉड्यूल का भी नेतृत्व किया।

भारत ने समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद और अंतरराष्ट्रीय अपराध, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, अप्रसार और निरस्त्रीकरण, आपदा राहत आदि पर एआरएफ गतिविधियों और पहलों में सक्रिय रूप से भाग लेना जारी रखा। 2024 में, भारत ने अमेरिका, फिलीपींस और पापुआ न्यू गिनी के साथ 23-25 अप्रैल को पापुआ न्यू गिनी में जानबूझकर जहाज और बंदरगाह सुविधा सुरक्षा (आईएसपीएस) कोड पर एआरएफ प्रशिक्षण श्रृंखला और सर्वोत्तम अभ्यास मैनुअल के तीसरे भाग की सह-अध्यक्षता की।

इस वर्ष, भारत ने मलेशिया के साथ एडीएमएम + में सीटी (आतंकवाद का प्रतिकार) पर विशेषज्ञ कार्य समूह की सह-अध्यक्षता संभाली। रक्षा मंत्री ने 20-22 नवंबर तक लाओ पीडीआर के वियनतियाने में 11^{वीं} एडीएमएम+ बैठक में भारत की भागीदारी का नेतृत्व किया, जिसमें उन्होंने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर एक व्याख्यान दिया।

भारत ने 13 नवंबर को लाओ पीडीआर के वियतनाम में 12^{वां} विस्तारित आसियान समुद्री फोरम में भाग लिया, जिसमें समुद्री संपर्क और क्षमता निर्माण, आधारभूत संरचना और उपकरणों के उन्नयन, नाविकों के प्रशिक्षण, समुद्री पर्यावरण, पूर्वी एशिया में पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देने और एक स्थायी समुद्री अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्र से संबंधित समुद्री मुद्दों पर चर्चा की गई। भारत ने 04-05 जुलाई को मुंबई में समुद्री सुरक्षा सहयोग पर पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन रूपरेखा सम्मेलन के 6^{वां} संस्करण की मेजबानी की।

एशिया में सहभागिता और विश्वास निर्माण उपायों पर सम्मेलन (सीआईसीए)

सीआईसीएके महासचिव कैरेट सरयबे ने 20 फरवरी को भारत का दौरा किया और तत्कालीन एमओएस (एमएल) और संयुक्त सचिव (डीएंडआईएसए) से मुलाकात की। भारत सीआईसीएका एक सदस्य राज्य है, और बैठकों के दौरान, सीआईसीएके एक क्षेत्रीय अंतरराष्ट्रीय संगठन में प्रस्तावित क्रमिक परिवर्तन के साथ-साथ सीआईसीएकी विभिन्न पहलों के साथ भारत की भागीदारी पर चर्चा हुई। भारत ने 17 दिसंबर को अज़रबैजान द्वारा आयोजित वर्चुअल सीआईसीएमंत्रिस्तरीय परिषद की बैठक में भाग लिया।

भारत ने सीआईसीएके विभिन्न कार्यक्रमों जैसे पर्यावरण मुद्दों पर सीआईसीएमंत्रिस्तरीय सम्मेलन (अगस्त); सीआईसीएदेशों के स्वयंसेवी आंदोलन नेताओं की रैली और सीआईसीएयुवा परिषद की बैठक (अक्टूबर); और सीआईसीएव्यापार परिषद और व्यापार मंच की बैठकों (नवंबर) में भाग लिया और अपने दृष्टिकोण साझा किए।

निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों पर फेलोशिप कार्यक्रम

निरस्त्रीकरण, अप्रसार और शस्त्र नियंत्रण शिक्षा को बढ़ावा देने तथा युवा राजनयिकों को इन क्षेत्रों में ज्ञान और कौशल से लैस करने की भारत की प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में, सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान ने डी एंड आईएसए प्रभाग के सहयोग से 22 जनवरी से 09 फरवरी तक

विदेशी राजनयिकों के लिए निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों की फेलोशिप के चौथे संस्करण का आयोजन किया। इसमें 24 देशों के राजनयिकों ने भाग लिया। यह पहल यूएनजीए संकल्प 'निरस्त्रीकरण और अप्रसार शिक्षा पर संयुक्त राष्ट्र अध्ययन' के अधिदेश को पूरा करती है और यह संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निरस्त्रीकरण एजेंडे 'हमारे साझा भविष्य को सुरक्षित करना' में 'निरस्त्रीकरण शिक्षा' पर ध्यान केंद्रित करने के अनुरूप है।

अध्याय

16

आर्थिक कूटनीति

आर्थिक कूटनीति (ईडी) प्रभाग भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की एक आर्थिक शाखा है जो विदेश में भारतीय मिशनों/पोस्टों, विदेश मंत्रालय के क्षेत्रीय प्रभागों, भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों और भारत में विदेशी मिशनों/पोस्टों के साथ समन्वय में काम करती है ताकि विदेशी निवेश प्रवाह को सक्षम बनाया जा सके और द्विपक्षीय व्यापार, पर्यटन, प्रौद्योगिकी, शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। यह स्वास्थ्य सेवा, ऊर्जा सुरक्षा, अनाज कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए), आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन (सीडीआरआई), भारत, इजरायल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका (आई2यू2) के बीच साझेदारी, सामाजिक सुरक्षा समझौते (एसएसए) आदि से संबंधित मामलों को भी संभालता है।

व्यापार और निवेश

व्यापार, पर्यटन और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने पर जोर देने के लिए, ईडी प्रभाग ने इन तीन मापदंडों की निगरानी के लिए ईजी और आईटी प्रभाग के साथ एक व्यापक डैशबोर्ड बनाया। यह डैशबोर्ड विदेश में स्थित मिशनों को व्यापार, प्रौद्योगिकी और पर्यटन से संबंधित डेटा और प्रगति की रिपोर्टिंग करने में सुविधा प्रदान करता है, साथ ही इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए की गई गतिविधियों की भी जानकारी देता है। यह बदले में मंत्रालय को व्यापार, पर्यटन और प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने में मिशनों के प्रदर्शन का आकलन करने में सक्षम बनाता है। डैशबोर्ड तक

पहुंच सभी संबंधित मंत्रालयों और विभागों को प्रदान की गई है, जिसमें वाणिज्य विभाग (डीओसी), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), और पर्यटन मंत्रालय (एमओटी) शामिल हैं। वाणिज्य विभाग (डीओसी) के सहयोग से ईडी प्रभाग ने व्यापारिक निर्यात प्रयासों का समर्थन करने के लिए विदेश में स्थित भारतीय मिशनों के साथ काम किया। इन संयुक्त पहलों ने वर्ष के दौरान उल्लेखनीय प्रगति हासिल करने में योगदान दिया।

आई2यू2 (भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और यूएसए)

भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका से मिलकर बना आई2यू2 इन देशों के बीच सामरिक साझेदारी का प्रतीक है। यह पहल छह महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोगी निवेश पर जोर देती है: जल, ऊर्जा, परिवहन, बाहरी अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा। इसका प्राथमिक उद्देश्य आधारभूत संरचना को विकसित करने, औद्योगिक कार्बन उत्सर्जन को कम करने, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने और उदीयमान और हरित प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता और संसाधनों का उपयोग करना है। नवाचार, प्रौद्योगिकी, कुशल श्रम और उद्यमिता में साझा शक्तियों का लाभ उठाकर, आई2यू2 सदस्य देशों में सतत विकास को आगे बढ़ाना चाहता है।

जुलाई 2022 में, प्रधानमंत्री इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और यूएसए के अपने समकक्षों के साथ आई2यू2नेताओं के उद्घाटन वर्चुअल शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिखर सम्मेलन के दौरान चर्चा भारत में दो प्रमुख परियोजनाओं पर केंद्रित थी: खाद्य पार्क और नवीकरणीय ऊर्जा पहल। फूड पार्क परियोजना में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। जनवरी में वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के दौरान संयुक्त अरब अमीरात और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) के बीच एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके अतिरिक्त, 9 सितंबर को गुजरात सरकार और अबू धाबी डेवलपमेंटल होल्डिंग कंपनी पीजेएससी (एडीक्यू) के बीच एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे भारत में खाद्य पार्क विकास को बढ़ावा मिला। ईडी प्रभाग आई2यू2 उद्देश्यों को आगे बढ़ाने और अपनी पहलों के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए हितधारकों के साथ अपनी सहभागिता जारी रखता है।

विदेश में उच्च शिक्षा संस्थान (एचईआई)

ईडीप्रभाग शिक्षा मंत्रालय और आईआईटीपरिषद् के साथ समन्वय करके नई शिक्षा नीति (एनईपी) के भाग के रूप में विदेशों में आईआईटीकी स्थापना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है। संयुक्त अरब अमीरात और आईआईटीदिल्ली (दुबई में परिसर चालू है) और तंजानिया और आईआईटीमद्रास के बीच समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसने ज़ांजीबार में परिचालन शुरू कर दिया है। जुलाई में, ईडीप्रभाग ने मलेशिया में एक आईआईटीपरिसर खोलने के लिए मलेशिया में भारतीय मिशन के साथ एक आभासी बैठक आयोजित की। मंत्रालय द्वारा अन्य स्वीकृत देशों में अधिक आईआईटीपरिसर स्थापित करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

विदेश में महत्वपूर्ण खनिजों का अधिग्रहण

ईडी प्रभाग खान मंत्रालय के सहयोग से विदेश में महत्वपूर्ण खनिजों के अधिग्रहण से संबंधित मामलों पर समन्वय करता है। यह खोजे गए भंडारों, निवेश के अवसरों और विदेशों में भारतीय मिशनों द्वारा रिपोर्ट की गई संभावित संसाधन सहयोग पर जानकारी का समय पर साझाकरण सुनिश्चित करता है। सक्रिय भागीदारी के माध्यम से, ईडी प्रभाग ने विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों तक पहुँच सुनिश्चित करने, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम) जैसी पहलों का समर्थन करने और अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे प्रमुख क्षेत्रों के साथ साझेदारी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

भारतीय रुपये (आईएनआर) में भुगतान का निपटान

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने निर्यात/आयात के चालान, भुगतान और निपटान के लिए अतिरिक्त व्यवस्था के रूप में वस्तुओं और सेवाओं

के निर्यात और/या आयात के लिए आईएनआर में व्यापार के अंतर्राष्ट्रीय निपटान की अनुमति दी है। विदेश मंत्रालय ने अपने राजनयिक मिशनों के साथ घनिष्ठ समन्वय में विभिन्न देशों के साथ आईएनआर में व्यापार निपटान की सुविधा के लिए आईएनआर नामित विशेष वोस्ट्रो खाता (एसवी खाता) खोलने को प्रोत्साहित करने के लिए ठोस प्रयास किए हैं। वर्तमान में, आरबीआई ने 22 देशों के भागीदार बैंकों के 99 विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते खोलने की अनुमति दी है। इसके अलावा, कुवैत, मॉरीशस और वियतनाम के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली (एलसीएसएस) के लिए समझौता-ज्ञापन शुरू किए गए हैं। तंजानिया और नाइजीरिया के साथ भी इसी तरह की व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है। एलसीएसएस ढाँचे में व्यापक कवरेज है और इसमें भागीदार देशों के बीच सभी चालू खाता और अनुमेय पूंजी खाता लेनदेन शामिल हैं। एलसीएसएस व्यवस्था में प्रवेश करने से आईएनआर के और अधिक अंतर्राष्ट्रीयकरण में मदद मिलेगी।

पर्यटन विस्तार गतिविधियाँ

ईडी प्रभाग ने राज्य पर्यटन विभागों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सफलतापूर्वक पहल की है। 28 जून को, भारत में बौद्ध सर्किट को बढ़ावा देने के लिए बोधि यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली में 15 विदेशी मिशनों का प्रतिनिधित्व करने वाले गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया, जिन्होंने अपने-अपने देशों में सर्किट को बढ़ावा देने में गहरी रुचि दिखाई। इसके अतिरिक्त, कुंभ मेला 2025 के लिए एक पर्दा उठाने वाला कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें इसके सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डाला गया। इन प्रयासों ने वैश्विक जागरूकता और जुड़ाव को प्रभावी ढंग से बढ़ाया है, जिससे भारत की स्थिति एक प्रमुख सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पर्यटन स्थल के रूप में सुदृढ़ हुई है।

एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई)

ईडीप्रभाग अन्य देशों में अंतर-संचालनीय मोबाइल भुगतान समाधान, यूपीआईको बढ़ावा देने के लिए एक इंटरफ़ेस के रूप में काम करता है। इस संबंध में, प्रभाग भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम-(एनपीसीआई) अंतर्राष्ट्रीय भुगतान लिमिटेड (एनआईपीएल) को सुविधा प्रदान कर रहा है, जो आरबीआईकी एक पहल है, ताकि हमारे मिशनों के माध्यम से संबंधित देशों के केंद्रीय बैंकों के साथ चर्चा की जा सके। एनआईपीएलउन देशों के साथ अवसरों की तलाश कर रहा है, जो वास्तविक समय भुगतान प्रणाली और पारंपरिक कार्ड भुगतान रेल के विकल्प की स्थापना करना चाहते हैं। ऐसे मामलों में एनआईपीएलने ऑनलाइन भुगतान प्रणाली, बैंक-ऑफिस सिस्टम, भारत इंटरफ़ेस फॉर मनी (भीम) ऐप या सभी को सरकार से सरकार या केंद्रीय बैंक से केंद्रीय बैंक व्यवस्था के अंतर्गत स्रोत कोड के हस्तांतरण के माध्यम से पूरी तरह से संप्रभु तरीके से लाइसेंस प्रदान करने का प्रस्ताव दिया है।

स्वास्थ्य और चिकित्सा यात्रा

भारत में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ाने के लिए, हमारे मिशन अपने देशों में पर्यटकों की क्षेत्-विशिष्ट मांग पर स्वास्थ्य मंत्रालय को मूल्यवान मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ईडी प्रभाग ने नवंबर के महीने में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में भारत-सऊदी अरब निवेश और निर्यात पर बैठकों का समन्वय किया। अलग-अलग, विभिन्न देशों में भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता दिलाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने गांधीनगर में भारत की जी 20 अध्यक्षताके अंतर्गत मेडिकल वैल्यू ट्रेवल (एमवीटी) के लिए भारत के आधिकारिक हील इन इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया। यह एक "वन-स्टॉप" पोर्टल है जो विदेश से भारत में चिकित्सा उपचार का लाभ उठाने के इच्छुक लोगों को जानकारी प्रदान करने की सुविधा और आसानी के लिए विकसित किया गया है। पोर्टल भारत में अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा यात्रियों की जानकारी और रोगी यात्रा को सुव्यवस्थित करने में मदद करता है।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए)

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी, वित्त और क्षमता के संदर्भ में सौर ऊर्जा की व्यापक तैनाती में मुख्य आम बाधाओं के लिए सामूहिक प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए देशों को एक साथ लाने में पेरिस जलवायु समझौते के कार्यान्वयन में योगदान देना है।

27 अगस्त को फ्रेमवर्क समझौते पर लेबनान द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के साथ, 120 देशों ने आईएसए के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें से 104 देशों ने फ्रेमवर्क समझौते की पुष्टि भी की है, अमेनिया 15 अक्टूबर को पुष्टि करने और जमा करने वाला नवीनतम देश है। ईडी प्रभाग ने सौर ऊर्जा की तैनाती को बढ़ाने के लिए सौर कंपनियों, इनक्यूबेटर्स और त्वरक के लिए, राष्ट्रों के प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ अपनी तरह के एक सौर महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव के सफल आयोजन की सुविधा प्रदान की।

आईएसए का डिपॉजिटरी होने के नाते ईडी प्रभाग ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) (नोडल मंत्रालय) और आईएसए सचिवालय के साथ समन्वय किया। इसने 4 नवंबर को नई दिल्ली में आईएसए की 7^{वां} आम सभा के आयोजन की सुविधा प्रदान की। सभा के दौरान, भारत को 2024-2026 तक लगातार चौथी बार आईएसए महासभा के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया। ईडी प्रभाग ने आईएसए के महानिदेशक के पद के लिए भारत के उम्मीदवार के लिए प्रचार किया, जिसे भारी बहुमत से इस पद (2025-29) के लिए चुना गया।

आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन (सीडीआरआई)

सीडीआरआई एक समावेशी बहु-हितधारक भागीदारी के रूप में कार्य करता है, जहाँ आधारभूत ढाँचे के आपदा रोधी के विभिन्न पहलुओं पर ज्ञान

उत्पन्न और आदान-प्रदान किया जाता है। ईडी प्रभाग और सीडीआरआई के बीच समन्वय प्रयासों का उद्देश्य विभिन्न भौगोलिक और सामाजिक-आर्थिक संदर्भों, आपदा जोखिम प्रोफाइल के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन और आपदाओं को कम करने और अनुकूलन करने की क्षमताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त सदस्यों, देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को शामिल करना है।

29 नवंबर तक, गठबंधन की सदस्यता चालीस राष्ट्रीय सरकारों और सात अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तक बढ़ गई है। वियतनाम सीडीआरआई में शामिल होने वाला नवीनतम देश है। आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन (सीडीआरआई) के सह-अध्यक्ष के रूप में भारत और फ्रांस ने अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया के 14 देशों को गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हुए संयुक्त ज्ञापन दिया है।

वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन (जीबीए)

वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, एक अद्वितीय बहु हितधारक गठबंधन, भारत की जी20 अध्यक्षता के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा 9 सितंबर 2023 को अर्जेंटीना, बांग्लादेश, ब्राजील, इटली, मॉरीशस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात और यूएसए जैसे 8 अन्य देशों के नेताओं के साथ अध्यक्ष की पहल के रूप में लॉन्च किया गया था।

3 अक्टूबर को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेजबान देश समझौते (एचसीए) पर हस्ताक्षर और अनुसमर्थन को मंजूरी दी। 11 अक्टूबर को, भारत सरकार और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन (जीबीए) ने एचसीए पर हस्ताक्षर किए। एचसीए/जीबीए को भारत में गठबंधन का भौतिक सचिवालय स्थापित करने की सुविधा प्रदान करता है, जिसमें भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों कर्मचारी शामिल होते हैं, जिससे जीबीए अपने इच्छित उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम होता है। इसके अलावा, एचसीए/जीबीए को आवश्यक विधिक दर्जा प्रदान करेगा, जिसमें संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा) अधिनियम, 1947 के अंतर्गत प्रतिरक्षा और विशेषाधिकार शामिल हैं, जिससे भारत के कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुसार अपने कार्यों और कार्यक्रमों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करने में सक्षम होगा। दोनों पक्षों द्वारा आंतरिक विधिक प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद एचसीए हाल ही में 23 नवंबर को लागू हो गया है।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग (यूएनसीआईटीआरएएल)

ईडी प्रभाग ने यूएनसीआईटीआरएएल के आयोग सत्र में भाग लिया, जहाँ संयुक्त सचिव (ईडी) ने भारत सरकार की ओर से वक्तव्य दिया। प्रभाग यूएनसीआईटीआरएएल के छह कार्य समूहों में अपने इनपुट प्रदान करके सक्रिय रूप से भाग ले रहा है।

वेयरहाउस रसीदों पर कार्य समूह I के अंतर्गत, यूएनसीआईटीआरएएल आयोग ने वेयरहाउस रसीदों पर यूएनसीआईटीआरएएल-अंतर्राष्ट्रीय निजी

कानून एकीकरण संस्थान (यूएनआईडीआरओआईटी) मॉडल कानून को अंतिम रूप दिया और अपनाया, तथा अधिनियमन के लिए मसौदा मार्गदर्शिका को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी।

विवाद निपटान पर कार्य समूह II, जो विशेषीकृत एक्सप्रेस विवाद समाधान (एसपीईडीआर) पर यूएनसीआईटीआरएल मॉडल क्लॉज पर विचार-विमर्श कर रहा है, ने मसौदा व्याख्यात्मक नोटों के साथ इसे अंतिम रूप दिया और दो दिवसीय संगोष्ठी आयोजित की, जिसके बाद कार्य समूह ने प्रारंभिक रूप से इलेक्ट्रॉनिक पुरस्कारों की मान्यता और प्रवर्तन के विषय पर विचार किया।

निवेशक-राज्य विवाद निपटान सुधार पर कार्य समूह III ने अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवादों के समाधान के लिए एक स्थायी तंत्र के मसौदा कानून पर अपने विचार-विमर्श को जारी रखा और निवेशक-राज्य विवाद निपटान (आईएसडीएस) सुधार पर प्रक्रियात्मक और क्रॉस-कटिंग मुद्दों के साथ-साथ एक बहुपक्षीय साधन पर भी विचार किया।

इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पर कार्य समूह IV ने यूएनसीआईटीआरएल द्वारा अपने पचपनवें सत्र में दिए गए अधिदेश के अंतर्गत डेटा प्रावधान अनुबंधों पर डिफॉल्ट नियमों के निर्माण पर अपना काम जारी रखा। कार्य समूह ने स्वचालित अनुबंध पर यूएनसीआईटीआरएल मॉडल कानून के अधिनियमन के लिए मार्गदर्शिका की भी समीक्षा की।

दिवालियापन कानून पर कार्य समूह V ने दिवालियापन कार्यवाही में परिसंपत्ति अनुरेखण और वसूली पर एक पाठ के दूसरे और तीसरे मसौदे और दिवालियापन कार्यवाही में त्वरित परिसंपत्ति अनुरेखण और वसूली के लिए एक मसौदा टूलकिट की अपनी समीक्षा पूरी कर ली है। इसके अलावा, कार्य समूह 2025 में अपने पचपनवें सत्र में आयोग द्वारा विचार और अंतिम रूप देने के लिए संशोधित दोनों पाठों को प्रेषित करेगा।

परक्राम्य कार्यों दस्तावेजों पर कार्य समूह VI ने परक्राम्य कार्यों दस्तावेजों पर एक साधन के लिए संशोधित प्रारंभिक मसौदा प्रावधानों की अपनी लेख-दूर-लेख समीक्षा जारी रखी।

स्थायी मध्यस्थता न्यायालय

स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (पीसीए) एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसका भारत 1950 से सदस्य है। हेग में मुख्यालय वाले पीसीए ने भारत-संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) के अंतर्गत रास अल खैमाह निवेश प्राधिकरण (आरएकेआईए) मामले में अंतिम सुनवाई की है; भारत-मॉरीशस बीआईटी के अंतर्गत जीपीआईएक्स मामले में केस मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस (सीएमसी) की सुनवाई, भारत-मलेशिया बीआईटी के अंतर्गत मैक्सिस कम्युनिकेशंस बरहाद और भारत-मॉरीशस बीआईटी के अंतर्गत ग्लोबल कम्युनिकेशन सर्विसेज होल्डिंग्स लिमिटेड सहित अन्य।

भारत ने भारत में एक स्थायी सुविधा स्थापित करने के लिए 2008 में पीसीए के साथ एक एचसीए पर हस्ताक्षर किए थे। इस वर्ष, पीसीए ने अपनी स्थापना के 125 वर्ष पूरे किए। इस अवसर को मनाने के लिए, पीसीए ने

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के साथ समन्वय में “अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और कानून का शासन” पर एक सम्मेलन आयोजित किया, जो 13-15 सितंबर को सर्वोच्च न्यायालय के सभागार में आयोजित किया गया था। सम्मेलन के समापन समारोह के दौरान, पीसीए इंडिया कार्यालय, जिसे पीसीए इंडिया होस्ट कंट्री एग्रीमेंट (2008) के अंतर्गत स्थापित करने पर विचार किया गया था, का शुभारंभ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया गया। इस समारोह में सचिव (ईआर) और भारत के अटॉर्नी जनरल मौजूद थे।

ऊर्जा सुरक्षा

ईडी प्रभाग, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) और अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी (आईआरईएनए) सहित संबंधित मंत्रालयों और ऊर्जा एजेंसियों के बीच संबंधों को सुगम बनाने वाली प्राथमिक संस्था के रूप में कार्य करता है। बहुपक्षीय मंच पर भारत की ऊर्जा भागीदारी को सुगम बनाने के अलावा, ईडी प्रभाग, संबंधित मंत्रालयों के समूह का भी हिस्सा है, जो द्विपक्षीय ऊर्जा संवादों को आगे बढ़ाने और विभिन्न देशों के साथ संस्थागत संबंधों को बेहतर बनाने में शामिल है। ईडी प्रभाग, विद्युत मंत्रालय और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ समन्वय में भारत की आईईए सदस्यता प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहा है।

बाजार विस्तार गतिविधियाँ

व्यापार, पर्यटन और प्रौद्योगिकी के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने और भारतीय व्यापार और उद्योग की वैश्विक दृश्यता बढ़ाने के लिए, मंत्रालय “बाजार विस्तार गतिविधियों” बजट के अंतर्गत विदेशों में अपने मिशनों और पोस्टों के माध्यम से वित्तीय संसाधन आवंटित करता है। ये निधियाँ मिशनों को नियमित व्यापार और निवेश पूछताछ को संबोधित करने, अपने मेजबान देशों में आर्थिक और व्यावसायिक स्थितियों का मूल्यांकन करने और बाजार सर्वेक्षण करने में सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त, संसाधन सेमिनार आयोजित करने और स्थानीय चैंबर्स ऑफ कॉमर्स, उद्योग प्रतिनिधियों और व्यापार संघों के साथ जुड़ने में सहायता करते हैं। वर्तमान अवधि के लिए, ईडी प्रभाग ने वैश्विक स्तर पर विभिन्न मिशनों और पोस्टों में इन गतिविधियों के लिए 9 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

वेबसाइट और संसाधनों का वैश्विक मानचित्रण

विदेश मंत्रालय के ईडी प्रभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.indbiz.gov.in को 16 दिसंबर 2020 को विदेश मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया। यह प्लेटफॉर्म सूचना के व्यापक भंडार के रूप में कार्य करता है, जो राज्य-विशिष्ट डेटा, निवेश के अवसर, सामान्य तथ्य, सांख्यिकी और भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विस्तृत जानकारी शामिल करने वाले संसाधनों का खजाना प्रदान करता है। वेबसाइट का उद्देश्य आधुनिक, समावेशी तरीके से 'ब्रांड



माननीय राष्ट्रपति जी ने अक्टूबर 2024 में अल्जीरिया में आयोजित भारतीय सामुदायिक स्वागत समारोह में भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया और बच्चों से चर्चा की।

इंडिया' को प्रदर्शित करना और भारतीय व्यवसायों और विदेशी उद्यमों के बीच सूचनाओं के दो-तरफ़ा आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करना है।

वेबसाइट की प्रमुख विशेषताओं में से एक 'विश्व संसाधन बंदोबस्ती और अवसर' शीर्षक वाला खंड है, जो खनिजों, व्यापार, कृषि निर्यात और बहुत कुछ पर जानकारी सहित वैश्विक संसाधन आपूर्ति और मांग की गतिशीलता पर एक संपूर्ण डेटाबेस प्रदान करता है। साइट को नियमित रूप से व्यापार से संबंधित डेटा और विदेशों में भारतीय मिशनो द्वारा किए गए बाजार सर्वेक्षणों के साथ अपडेट किया जाता है, जिससे व्यवसायों को उभरते व्यापार अवसरों की पहचान करने में मदद मिलती है।

निवेश संधियाँ

ईडी प्रभाग निवेश संधि वार्ताओं में सक्रिय रूप से भाग लेता है और इन वार्ताओं के समन्वय में शामिल रहा है तथा नीति/राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से और अंतर्राष्ट्रीय कानून के परिप्रेक्ष्य से अपेक्षित इनपुट प्रदान करता रहा है। भारत 2015 के नए मॉडल बीआईटी के आधार पर निवेश संधियों पर चर्चा करने में विभिन्न देशों के साथ सक्रिय रूप से शामिल है। विदेश मंत्रालय एक अंतर्राष्ट्रीय विपणन समूह का सदस्य है और बीआईटी वार्ताओं का एक अभिन्न अंग है तथा अपेक्षित इनपुट भी प्रदान करता है। अन्य देशों के साथ बीआईटी के बारे में पलाचार, मंत्रालय के माध्यम से नोट वर्बल्स आदि के द्वारा ईडी प्रभाग के माध्यम से किया जाता है जो निवेश संधि और संबंधित ऐसे मामलों के लिए मंत्रालय में नोडल प्रभाग है।

भारत के सामने करीब 40 निवेश संधि दावे हैं, जिनमें दावों की संख्या राशि 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। मामले विभिन्न चरणों में हैं, जिनमें कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें पंचाट दिए जा चुके हैं। अब तक निवेशकों द्वारा भारत के खिलाफ करीब 40 विवाद नोटिस दिए गए हैं, जिनमें से भारत ने 06 मध्यस्थता मामलों में जीत प्राप्त की जीती है, 05 मध्यस्थता हारी है, 02 विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया गया है और वर्तमान में 06 से अधिक सक्रिय विवाद हैं। भारत सरकार के अंतर-मंत्रालयी समूह के एक हिस्से के रूप में ईडी प्रभाग आवश्यक इनपुट प्रदान करके, सुनवाई की सुविधा प्रदान करके और विदेशी अधिकार क्षेत्र में इन मामलों में अन्य संबंधित कार्रवाइयों का समन्वय करके विवाद के हर चरण में सक्रिय रूप से शामिल है। ये मामले विदेश में स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरणों के समक्ष हैं और इनमें अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रश्न शामिल हैं जहां मंत्रालय की सलाह मांगी जाती है।

2023 में, भारत गणराज्य के खिलाफ दो नए विवाद दायर किए गए; भारत-यूके बीआईटी के अंतर्गत इंडो गोल्ड बनाम भारत गणराज्य और वेदांता बनाम भारत गणराज्य। पहले मामले में, इंडो-गोल्ड का दावा है कि भारत सरकार ने 2021 में खान और खनिज अधिनियम में संशोधन के माध्यम से भुक्तियां में उसके निवेश को जब्त कर लिया। वेदांता बनाम भारत गणराज्य, मामला भारत सरकार द्वारा शेयर खरीद समझौते के कथित उल्लंघन में वेदांता के पक्ष में हिंदुस्तान जिंक में अपने 30 प्रतिशत शेयर बेचने से इनकार करने से संबंधित है।

औद्योगिक आउटरीच और निवेश संवर्धन और प्रचार

13-15 अक्टूबर तक माननीय राष्ट्रपति जी की अल्जीरिया की राजकीय यात्रा के दौरान, ईडी प्रभाग ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) के सहयोग से व्यापार कार्यक्रम के लिए रक्षा, ऑटोमोबाइल, खाद्य प्रसंस्करण, ऊर्जा, आधारभूत संरचना सहित विविध क्षेत्रों से 25 सदस्यीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल भेजा।



मालदीव के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद मुइज्जू ने भारत की राजकीय यात्रा के दौरान एसोचैम, सीआईआई और फिक्की के साथ कार्यक्रमों में, अक्टूबर 2024 में भाग लिया

माननीय राष्ट्रपति जी की 17-19 अक्टूबर तक मलावी की राजकीय यात्रा के दौरान, ईडी प्रभाग ने एसोचैम, सीआईआई और फिक्की के सहयोग से 36 सदस्यीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल भेजा।

मालदीव गणराज्य के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद मुइज्जू की 6-10 अक्टूबर की राजकीय यात्रा के दौरान, एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम), भारतीय उद्योग परिषद (सीआईआई) और फिक्की के सहयोग से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में व्यावसायिक कार्यक्रम आयोजित किए गए।

ईडी प्रभाग ने पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) के सहयोग से 11-15 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह 2024 के दूसरे संस्करण का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में खाद्य, ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कौशल विकास, पर्यटन आदि जैसे प्रमुख क्षेत्रों में साझेदारी की नई संभावनाओं की खोज पर ध्यान केंद्रित किया गया।

ईडी प्रभाग ने दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद (टीईपीसी) के सहयोग से 29 जुलाई को रक्षा क्षेत्र आईसीटी कॉन्क्लेव का आयोजन किया। यह कार्यक्रम अफ्रीकी देशों के रक्षा क्षेत्र में आईसीटी उपकरणों और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था।

ईडी प्रभाग ने मिलेनियल इंडिया इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर (एमआईआईसीसीआईए) के सहयोग से 05 अगस्त को नॉर्डिक और बाल्टिक देशों में अवसरों पर एक व्यापार सम्मेलन का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य नॉर्डिक बाल्टिक क्षेत्र में उपयुक्त आर्थिक अवसरों की खोज करना और भारतीय व्यापार और उद्योग के लिए विश्वसनीय व्यापार भागीदार ढूंढना था।

ईडी प्रभाग ने पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई), नेशनल पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल (एफसीसी) के साथ मिलकर 28-30 अगस्त तक ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (जीएफएफ)-2024 का आयोजन किया। जीएफएफ ने वैश्विक नीति निर्माताओं, नियामकों, केंद्रीय बैंकों, उद्योग प्रमुखों, विचारकों, शिक्षाविदों और वरिष्ठ उद्योग पेशेवरों के लिए फिनटेक इकोसिस्टम से संबंधित मुद्दों पर चर्चा और बहस करने के लिए एक मंच के रूप में काम किया।

ईडी प्रभाग ने पॉवरजेन इंटरनेशनल इंडिया के साथ मिलकर 4-6 सितंबर तक भारतीय उपयोगिता सप्ताह 2024 का आयोजन किया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य वैश्विक ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र के हितधारकों को भारत के उभरते ऊर्जा मिश्रण द्वारा प्रस्तुत किए गए अवसरों का पता लगाने, सहयोग करने और उन तक पहुंचने के लिए एक मंच प्रदान करना था।

ईडी प्रभाग ने सीआईआई के साथ मिलकर 19 नवंबर को ऊर्जा सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ एक संपोषणीय और कम कार्बन भविष्य को सुरक्षित करने के लिए विशिष्ट रणनीतियों के साथ आने के लिए व्यापक चर्चा को सुविधाजनक बनाना था।

नागरिक उड्डयन

आर्थिक कूटनीति प्रभाग विदेश मंत्रालय में विदेशी देशों/एयरलाइंस के साथ हवाई सेवा समझौतों से संबंधित सभी मामलों के लिए नोडल प्रभाग है और इन मामलों पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय (एमओसीए) के साथ मिलकर काम करता है। प्रभाग इन मुद्दों पर और पर्यटन को बढ़ावा देने और द्विपक्षीय/बहुपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए उड़ान संचालन या कोड शेयरिंग की आवश्यकताओं पर इनपुट भी प्रदान करता है।

अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ) की भागीदारी

विदेश मंत्रालय की ओर से ईडी प्रभाग दीर्घावधि आकांक्षात्मक लक्ष्य (एलटीएजी) और अंतर्राष्ट्रीय विमानन के लिए कार्बन ऑफसेटिंग और



प्रधानमंत्री ने सितंबर 2024 में भारत मंडपम, नई दिल्ली में नागरिक उड्डयन पर दूसरे एशिया-प्रशांत (एपीएसी) मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भाग लिया।

न्यूनीकरण योजना (सीओआरएसआईए) आदि जैसे आईसीएओके मुद्दों पर इनपुट प्रदान करता है।

अगस्त के अंतिम सप्ताह में आयोजित आईसीएओलेखापरीक्षा भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। विदेश मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करते हुए, ईडीप्रभाग ने लेखापरीक्षा के दौरान उठाए गए सभी प्रश्नों के व्यापक उत्तर सुनिश्चित किए। अंतर्राष्ट्रीय मानकों और प्रथाओं से संबंधित प्रमुख मुद्दों को संबोधित किया गया, और वैश्विक विमानन मानदंडों को पूरा करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने के लिए ठोस प्रयास किए गए। लेखापरीक्षा के सफल समापन ने आईसीएओकी आवश्यकताओं के साथ तालमेल बिठाने के लिए भारत की तत्परता को रेखांकित किया, जिससे वैश्विक विमानन समुदाय में हमारी स्थिति और सुदृढ़ हुई। भारत ने वैश्विक औसत (72.36) और एशिया-प्रशांत क्षेत्र (एपीएसी) औसत (64.91) को महत्वपूर्ण अंतर से हराकर सफलतापूर्वक 82 अंक प्राप्त किए।

11 से 12 सितंबर को आयोजित 2018 एशिया-प्रशांत (एपीएसी) मंत्रिस्तरीय परिषद ने नागरिक उड्डयन में क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास को चिह्नित किया। समन्वय समिति के हिस्से के रूप में, ईडी प्रभाग ने भाग लेने वाले अधिकारियों के लिए वीजा प्राप्त करने में विदेश मंत्रालय की सहायता की और अपने क्षेत्रों में इस कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए विदेशी मिशन के साथ मिलकर काम किया। परिषद ने हवाई यातायात बढ़ाने, कनेक्टिविटी बढ़ाने और विमानन क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए सहयोगी पहलों पर जोर दिया। यह कार्यक्रम एशिया-प्रशांत क्षेत्र

में भारत की नेतृत्व भूमिका को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण था, विशेष रूप से प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में दिल्ली घोषणा को अपनाने के साथ।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 21 से 25 अक्टूबर तक कुआलालंपुर में मलेशियाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरण द्वारा आयोजित 16^{वें} आईसीएओवायु सेवा वार्ता (आईसीएएन2024) में भाग लिया। विभिन्न देशों में द्विपक्षीय बैठकें आयोजित की गईं। भारतीय एयरलाइनों द्वारा अधिक कॉल पॉइंट, कोड-शेयरिंग व्यवस्था सहित वायु सेवा व्यवस्था के उदारीकरण के लिए भी चर्चा हुई। एमओसीएके सहयोग से ईडीप्रभाग भारत और अन्य देशों के बीच संचालन के लिए राष्ट्रीय और विदेशी वाहकों के पदनाम में भी शामिल है।

मध्यस्थता प्रकोष्ठ

विदेश मंत्रालय का आर्थिक कूटनीति प्रभाग विभिन्न विधिक मुद्दों को संभालता है, जिसमें निवेश संधि विवाद और संबंधित अदालती कार्यवाही, निवेश संधि वार्ता, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग (यूएनसीआईटीआरएल) और स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (पीसीए) से संबंधित कार्य सहित कई मध्यस्थता और मुकदमेबाजी को संभालना शामिल है। इसके अलावा, प्रभाग विभिन्न अन्य वाणिज्यिक विधिक मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) और आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (सीडीआरआई) से संबंधित विधिक पहलुओं को भी संभालता है।

आज की तारीख में 40 से अधिक विवाद हैं, जिनमें भारत को प्रतिवादी राष्ट्र बनाया गया है और भारत से जुड़े ये निवेश संधि विवाद विभिन्न चरणों में हैं, जिनमें कुछ मामले मध्यस्थ न्यायाधिकरणों के समक्ष लंबित हैं और कुछ अन्य मामले जो दुनिया भर के विभिन्न न्यायालयों में मध्यस्थ पुरस्कारों के प्रवर्तन के बहुत उन्नत चरण में हैं।

इन मामलों में दांव बड़े हैं और समयबद्ध कार्रवाई के साथ एक समय दृष्टिकोण और निरंतर निगरानी और रिपोर्टिंग की आवश्यकता है। इनमें से कुछ मामलों की निगरानी प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और कैबिनेट सचिव द्वारा की जाती है और नियमित बैठकें और मामले की सुनवाई होती है जिसमें इस प्रभाग के प्रतिनिधियों को भाग लेना होता है। ये सुनवाई भारत और विदेशों में अदालतों में और विदेशों में मध्यस्थ न्यायाधिकरणों के समक्ष भी होती है। इसके समानांतर, भारत 30 से अधिक देशों के साथ निवेश संधियों पर भी चर्चा कर रहा है।

मध्यस्थता प्रकोष्ठ द्वारा संभाले बहिर्गमन विषय नीचे दिए गए हैं:

विभिन्न बोर्डों/समितियों को इनपुट

सदस्य के रूप में, ईडी प्रभाग विभिन्न बोर्डों और समितियों में कार्य करता है, जिसमें भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ), इन्वेस्ट इंडिया, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी), इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद (ईईपीसी), परियोजना निर्यात संवर्धन परिषद (पीईपीसी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के साथ निर्यातमुख इकाइयों (ईओयू) और विशेष आर्थिक क्षेत्रों (ईओयू और एसईजेड-ईपीसीईएस के लिए निर्यात संवर्धन परिषद) के लिए निर्यात संवर्धन परिषद शामिल हैं।

सचिवों का क्षेत्रीय समूह (एसजीओएस)

एसजीओएस समूह 3 और 7, जो संसाधन और वाणिज्य एवं उद्योग से संबंधित हैं, तथा जिनका प्रतिनिधित्व क्रमशः सचिव (पूर्व) और सचिव (ईआर) करते हैं, को ईडी प्रभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है। समूहों का मुख्य लक्ष्य भौतिक संपर्क में वृद्धि, प्रतिस्पर्धी अनुमोदन, निवेशक-अनुकूल नीतियों, बढ़े हुए निर्यात और आयात पर निर्भरता को कम करके भारत के निवेश माहौल को बेहतर बनाना है।

सामाजिक सुरक्षा समझौता (एसएसए)

सामाजिक सुरक्षा समझौते (एसएसए) भारत और अन्य देशों के बीच द्विपक्षीय समझौते हैं, जिनका उद्देश्य सीमा पार करने वाले श्रमिकों के हितों

की रक्षा करना है। ये समझौते विदेश में काम करने वाले भारतीय नागरिकों और भारत में कार्यरत विदेशी नागरिकों पर लागू होते हैं, जिनका प्राथमिक उद्देश्य “कोई कवरेज नहीं” या “दोहरा कवरेज” के मुद्दों को खत्म करना और दोनों देशों में श्रमिकों के लिए समान व्यवहार सुनिश्चित करना है। एसएसए विदेशों में भारतीय पेशेवरों और कुशल श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करते हैं, जैसे दोहरे सामाजिक सुरक्षा योगदान के भुगतान से बचना, लाभों की निर्यात क्षमता को सक्षम करना और लाभों के नुकसान को रोकने के लिए दोनों देशों में योगदान अवधि को एकत्रित करना। विदेश मंत्रालय इन समझौतों पर चर्चा करने के लिए “सक्षम प्राधिकारी” के रूप में कार्य करता है, जबकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) एसएसए प्रावधानों के प्रबंधन और कवर किए गए प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को कवरेज प्रमाणपत्र (सीओसी) जारी करने के लिए उत्तरदायी संपर्क एजेंसी के रूप में कार्य करता है। नवंबर में, भारत ने पोलैंड के साथ एक एसएसए पर हस्ताक्षर किए, जिससे सामाजिक सुरक्षा समझौतों की कुल संख्या 21 हो गई।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

ईडी प्रभाग एफडीआई मामलों को संसाधित करने के लिए विदेश मंत्रालय में नोडल प्रभाग है। एफडीआई मामले उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होते हैं। मामलों को उनके विचारों/टिप्पणियों के लिए संबंधित मिशनो और क्षेत्रीय प्रभागों को भेजा जाता है। प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर, ईडी प्रभाग सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद निर्धारित समय के भीतर, जहां भी आवश्यक हो, डीपीआईआईटी और संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों को अपने इनपुट बताता है। ईडी प्रभाग लंबित एफडीआई प्रस्तावों की समीक्षा के लिए नियमित आधार पर डीपीआईआईटी द्वारा आयोजित एफडीआई बैठकों में भी भाग लेता है। आम तौर पर, ये बैठकें मासिक आधार पर आयोजित की जाती हैं।

डीपीआईआईटी द्वारा प्रदान की गई एफडीआई फैक्ट शीट के अनुसार, भारत ने वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही की तुलना में वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही के दौरान एफडीआई प्रवाह में 47.8 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि देखी, जो 16.178 मिलियन अमरीकी डॉलर थी।

अध्याय

17

आतंकवाद का प्रतिकार

भारत ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के लिए भागीदारों के साथ चर्चा जारी रखी है। भारत के 26 देशों के साथ आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी-सीटी) हैं।

भारत आतंकवाद के खिलाफ बिस्स्टेक, जी20, आसियानक्षेत्रीय मंच, एससीओ, ब्रिक्स, ईयू, एफएटीएफ और क्वाडफोरम जैसे क्षेत्रीय और बहुपक्षीय निकायों के साथ भी चर्चा कर रहा है।

द्विपक्षीय सहभागिता (जेडब्ल्यूजी-सीटी)

वर्ष के दौरान, आतंकवाद निरोध पर संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी-सीटी) की बैठकें यूएसए (4-5 मार्च), कजाकिस्तान (8 अप्रैल), फ्रांस (15 अप्रैल), यूरोपीय संघ (7 मई), यूके (21 मई), जापान (29 मई), ऑस्ट्रेलिया (12 अगस्त), इंडोनेशिया (23 अगस्त) और सऊदी अरब (3 अक्टूबर), रूस (19-20 दिसंबर) के साथ आयोजित की गईं।

क्षेत्रीय सहभागिताएँ

आरएटीएस-एससीओ

भारत ने 16-19 जनवरी को बीजिंग, चीन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (आरएटीएस एससीओ) परिषद के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे

के विधिक विशेषज्ञों के समूह (जीएलई) की बैठक में भाग लिया, तथा उसके बाद 8-11 सितंबर को बैठक हुई।

आसियान

अंतरराष्ट्रीय अपराध पर 11^{वीं} आसियान वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक (एसओएमटीसी)+भारत परामर्श 27 और 28 जून को वियनतियाने, लाओ पीडीआर में आयोजित किया गया।

ब्रिक्स

ब्रिक्स आतंकवाद निरोधी कार्य समूह की 9^{वीं} वार्षिक पूर्ण बैठक और इसके उप-समूहों की बैठक 22-24 जुलाई को मास्को, रूस में आयोजित की गई।

बिस्स्टेक

भारत ने 19-20 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित नारकोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक पदार्थों और प्रीकर्सर रसायनों की अवैध तस्करी की रोकथाम पर बिस्स्टेक उप-समूह की 8^{वीं} बैठक में भाग लिया।

बहुपक्षीय भागीदारी

भारत ने वर्ष के दौरान विभिन्न बहुपक्षीय निकायों के साथ भागीदारी की। भारत ने पुनर्वास और पुनः एकीकरण रणनीतियों को बढ़ाने के लिए अच्छे



आतंकवाद निरोध पर भारत-रूस संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की 13^{वीं} बैठक (सीटी) और संयुक्त राष्ट्र से संबंधित मुद्दों पर भारत-रूस परामर्श का छठा दौर। दिसंबर 2024।

अभ्यासों को साझा करने पर क्षेत्रीय कार्यशाला में भाग लिया, जिसका आयोजन 13-15 फरवरी को कोलंबो, श्रीलंका में श्रीलंका सरकार के सहयोग से यूएनओडीसी द्वारा किया गया था।

एफएटीएफ

एफएटीएफकार्य समूह की बैठक और पूर्ण अधिवेशन 23-28 जून को सिंगापुर में आयोजित किया गया था। इस पूर्ण अधिवेशन के दौरान भारत की पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट को अपनाया गया, जिसमें भारत को "नियमित अनुवर्ती" श्रेणी में रखा गया। यह स्थिति दर्शाती है कि भारत ने एफएटीएफअनुशंसाओं और तत्काल परिणामों के अनुपालन का उच्च स्तर हासिल किया है। भारत ने अक्टूबर में एफएटीएफके कार्य समूहों और पूर्ण अधिवेशन में भी भाग लिया था।

जीसीटीएफ

भारत ने 26-29 फरवरी को केन्या के नैरोबी में आयोजित वैश्विक आतंकवाद निरोधी फोरम (जीसीटीएफ) ट्रांस-क्षेत्रीय समूह बैठक और 23^{वीं} समन्वय समिति की बैठक में भाग लिया, तथा 25-27 सितंबर को न्यूयॉर्क में आयोजित जीसीटीएफ की 24^{वीं} समन्वय समिति की बैठक और मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया।

ईएजी

भारत ने 29-31 मई को बिश्केक, किर्गिज गणराज्य में आयोजित मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त-पोषण पर यूरेशियन समूह (ईएजी) की 40^{वीं} पूर्ण बैठक में भाग लिया।

दुशांबे प्रक्रिया

भारत ने 4-5 नवंबर को कुवैत शहर में आयोजित 'दुशांबे प्रक्रिया उच्च स्तरीय सम्मेलन-कुवैत चरण' में भाग लिया।

क्वाड

भारत ने 4-6 नवंबर को सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में सी-डब्ल्यूएमडी खतरों पर क्वाड तकनीकी आदान-प्रदान और कार्यशाला में भाग लिया।

क्वाड आतंकवाद निरोधी कार्य समूह की दूसरी बैठक और 5^{वां} क्वाड टेबल टॉप अभ्यास 20-22 नवंबर को टोक्यो, जापान में आयोजित किया गया।

अध्याय

18

विकास सहयोग

डीपीए I

विकास साझेदारी भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। ग्लोबल साउथ के नेता के रूप में, भारत अपने साझेदार देशों की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है।

भारत की विकास परियोजनाएं एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन और प्रशांत द्वीप समूह में फैली हुई हैं। वे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, जल, ऊर्जा, संपर्क, निर्माण, रक्षा और सुरक्षा आदि सहित कई क्षेत्रों को कवर करती हैं।

क्रेडिट लाइन्स (एलओसी), जो साझेदार देशों को दिए बहिर्गमन रियायती ऋण हैं, वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (आईडीईएएस) द्वारा शासित हैं, जिसे अंतिम बार 2022 में संशोधित किया गया था।

2024 में पूरी होने वाली कुछ प्रमुख ऋण परियोजनाओं में बुरुंडी के काबू में 20 मेगावाट की जलविद्युत परियोजना, जिम्बाब्वे और तंजानिया में जल आपूर्ति प्रणालियों का उन्नयन, श्रीलंका में रेलवे ट्रैक उन्नयन परियोजना और गुयाना को विमानों की आपूर्ति शामिल हैं।

इस अवधि में भारत द्वारा आईडीईएएसपहल के अंतर्गत परियोजना वित्त-पोषण के लिए पहली बार रुपया मूल्यवर्गित ऋण दिया गया। ऋण रेखा 487.60 करोड़ रुपये की है और इसे मॉरीशस में जल पाइपलाइन प्रतिस्थापन परियोजना के लिए बढ़ाया गया था। तेल रिफाइनरी परियोजना

के पैकेज-IV के वित्त-पोषण के लिए जनवरी में मंगोलिया को 700 मिलियन अमरीकी डॉलर की अतिरिक्त ऋण रेखा पर हस्ताक्षर किए गए थे।

भारत आर्थिक संकट में फंसे देशों को ऋण राहत प्रदान करने का प्रयास कर रहा है। 2024 में, भारत श्रीलंका और जाम्बिया के साथ अपने ऋण का पुनर्गठन करने पर सहमत हुआ। भारत श्रीलंका के साथ ऋण पुनर्गठन वार्ता में आधिकारिक ऋणदाता समिति का सह-अध्यक्ष भी था।

दिसंबर 2024 में श्रीलंका के राष्ट्रपति की भारत की राजकीय यात्रा के दौरान, श्रीलंका में सात पूर्ण हो चुकी लाइन-ऑफ-क्रेडिट परियोजनाओं से संबंधित भुगतानों को निपटाने के लिए 20.66 मिलियन अमरीकी डॉलर की अनुदान सहायता दी गई। इसके अलावा, उत्तरी प्रांत में कांकेसथुराई बंदरगाह के पुनर्वास (61.5 मिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य) और श्रीलंका रेलवे के महो अनुराधापुरा खंड के संबंध में सिग्नलिंग सिस्टम परियोजना (14.9 मिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य) के लिए अनुदान सहायता बढ़ाई गई। लाइन ऑफ क्रेडिट परियोजनाओं के बदले अनुदान का विस्तार ऋण के बोझ को कम करने और श्रीलंका की सतत आर्थिक सुधार में सहायता करने के लिए किया गया था।

क्रेडिट लाइनें गुणक प्रभाव पैदा करने में सक्षम रही हैं, और भागीदार देशों को अपने विकास पथ पर आगे बढ़ने में मदद की है। उन्होंने 'मेक-इन-इंडिया' पहल के लिए सुदृढ़ प्रवर्तक के रूप में काम किया है; भारत के माल और सेवाओं के निर्यात में वृद्धि की है, और भारतीय उद्योग को वैश्विक बनाने की प्रक्रिया को सुगम बनाया है।

वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चीन्ह की 31 जुलाई से 1 अगस्त तक भारत की राजकीय यात्रा के दौरान भारत और वियतनाम के बीच 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

गुयाना के चेड्डी जगन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सौर पीवी बिजली संयंत्र की स्थापना के लिए 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर 29 फरवरी को हस्ताक्षर किए गए।

पूर्ण परियोजनाएँ

भारत ने दुनिया भर के साझेदार देशों में कई आधारभूतसंरचना परियोजनाएँ पूरी की हैं। वर्ष 2024 में पूरी की जाने वाली कुछ प्रमुख क्रेडिट लाइनपरियोजनाएँ इस प्रकार हैं:

मॉरीशस: मॉरीशस में दो नई क्रेडिट लाइनपरियोजनाएँ शुरू की गईं- एक फोरेंसिक साइंस लैब का निर्माण (जिसका मूल्य 13.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर है) और राष्ट्रीय अभिलेखागार और राष्ट्रीय पुस्तकालय का निर्माण (जिसका मूल्य 13 मिलियन अमेरिकी डॉलर है) क्रमशः मार्च और अक्टूबर में।

टोगो: टोगो में 46 दूरदराज के गाँवों/इलाकों को कवर करने वाली एक ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना (जिसका मूल्य 5.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर है) जून में शुरू की गई थी, जिसके लिए इकोवासबैंक फॉर इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट (ईबीआईडी) को 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की क्रेडिट लाइन दी।

बुरुंडी: बुरुंडी के राष्ट्रपति इवारिस्टे नदिशिमीये की उपस्थिति में 25 अक्टूबर को काबू में 20 मेगावाट की एक जलविद्युत परियोजना बुरुंडी सरकार को सौंपी गई। इसे 80 मिलियन अमेरिकी डॉलर के क्रेडिट लाइनके अंतर्गत बनाया गया था। यह बुरुंडी में सबसे बड़ी बिजली उत्पादन परियोजना है और इसने बुरुंडी की बिजली उत्पादन क्षमता को लगभग 30 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है।

जिम्बाब्वे: जिम्बाब्वे के डेका में पाइपलाइन निर्माण और जल आपूर्ति परियोजना अगस्त में पूरी हुई। यह परियोजना हांगे थर्मल पावर प्लांट को पानी उपलब्ध कराती है, जो जिम्बाब्वे का सबसे बड़ा बिजली संयंत्र है, और हांगे टाउनशिप को सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करती है, जो लगभग 40,000 लोगों की सेवा करती है। इस परियोजना को 48.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर के भारतीय ऋण के माध्यम से वित्त-पोषित किया गया है।

तंजानिया: जंजीबार में करीब 1 लाख लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराने वाली एक जलापूर्ति परियोजना अगस्त में पूरी हुई। परियोजना की लागत करीब 92.18 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिसे क्रेडिट लाइनके अंतर्गत वित्त-पोषित किया गया है।

गुयाना: हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड से गुयाना सरकार को दो हिंदुस्तान 228-201 विमानों की आपूर्ति के लिए 23.37 मिलियन अमेरिकी डॉलर के क्रेडिट लाइन पर 15 मार्च को हस्ताक्षर किए गए। ये विमान 1 अप्रैल को गुयाना को सौंप दिए गए।

गुयाना के भीतरी इलाकों के समुदायों में करीब 30,000 घरों के लिए सौर प्रकाश व्यवस्था की खरीद और स्थापना का काम जनवरी में 7.29 मिलियन अमेरिकी डॉलर के क्रेडिट लाइनके अंतर्गत पूरा हुआ।

श्रीलंका: माहो से ओमथाई तक करीब 130 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक का उन्नयन सितंबर में पूरा हुआ। 91.26 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत वाली इस परियोजना को श्रीलंका को क्रेडिट लाइनके अंतर्गत वित्त-पोषित किया गया है। पिछले 100 वर्षों में इस ट्रैक का यह पहला उन्नयन है।

सेशेल्स: 60 बसों की आपूर्ति के लिए सेशेल्स सरकार को 2.83 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया गया। बसों की आखिरी खेप दिसंबर में सौंपी गई।

कार्यान्वयनाधीन परियोजनाएँ

भारत वैश्विक दक्षिण के देशों के लिए एक सुदृढ़ विकास भागीदार के रूप में अपनी भूमिका को और सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। 2025-2026 तक पूरी होने वाली कुछ प्रमुख परियोजनाओं में मालदीव में हवाई अड्डों का उन्नयन; निकारागुआ, टोगो, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में बिजली परीक्षण परियोजनाएँ; बेनिन और कोटे डी आइवर में सिंचाई और जल आपूर्ति परियोजनाएँ और नेपाल में सड़क परियोजनाएँ शामिल हैं।

डीपीए II

भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) के माध्यम से क्षमता निर्माण

डीपीए II प्रभाग प्रमुख आईटीईसी योजना सहित विभिन्न क्षमता निर्माण पहलों का प्रबंधन करता है। पिछले कुछ वर्षों में, आईटीईसी योजना न केवल भारत की द्विपक्षीय कूटनीति का एक दृश्यमान साधन बन गई है, बल्कि वैश्विक क्षमता निर्माण परिदृश्य में एक मान्यता प्राप्त नाम भी बन गई है।

एक समृद्ध घरेलू प्रशिक्षण परिदृश्य के साथ, आईटीईसी कृषि और उद्यमिता जैसे पारंपरिक विकास विषयों से लेकर एआई, जैव प्रौद्योगिकी और साइबर जैसे उन्नत प्रौद्योगिकी उन्मुख विषयों तक के पाठ्यक्रम प्रदान करने में सक्षम है। जनसंख्या-स्तरीय समाधानों को लागू करने और जी20 जैसे वैश्विक मंचों पर उनके कारणों की वकालत करने के भारत के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए, सुशासन, विकास के लिए डेटा और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना से संबंधित पाठ्यक्रमों में गहरी रुचि रही है। चुनाव आयोग और न्यायपालिका जैसी भारतीय संस्थाओं की ताकत को वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त है और ऐसे संस्थानों द्वारा समझौता-ज्ञापन-संचालित प्रशिक्षण भी आईटीईसी के अंतर्गत कवर किया जा रहा है।

आईटीईसी योजना वैश्विक दक्षिण देशों के सरकारी पेशेवरों-नागरिक, रक्षा और अर्धसैनिक- के लिए प्रतिष्ठित भारतीय प्रशिक्षण संस्थानों में पूरी तरह से वित्त-पोषित प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करती है। नागरिक पक्ष में, इन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को लघु अवधि, आवासीय, गहन पाठ्यक्रमों के रूप

में डिजाइन किया गया है, जिसमें कक्षा और अनुभवात्मक दोनों तरह की सामग्री है, जो भारत के जीवंत सांस्कृतिक परिदृश्य के सांस्कृतिक प्रदर्शन के साथ पूरक है। आईटीईसीप्रशिक्षण का लाभ उठाने में रुचि रखने वाले सरकारी पेशेवर भारतीय दूतावासों के माध्यम से आवेदन करते हैं, लेकिन इन पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए उन्हें अपनी सरकारों द्वारा नामांकित होना आवश्यक है। पाठ्यक्रम बहु-देशीय आधार पर और साथ ही देश-विशिष्ट अनुकूलित आधार पर प्रस्तुत किए जाते हैं। रक्षा पक्ष में, तीनों सशस्त्र बलों की विशेष प्रशिक्षण सुविधाओं में पाठ्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं, साथ ही प्रतिष्ठित अधिकारी प्रशिक्षण सुविधाओं में उच्च रक्षा प्रबंधन पाठ्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाते हैं। आईटीईसीप्रशिक्षण का एक उभरता हुआ पहलू आईटीईसी-सुरक्षा की एक समर्पित पद्धति के अंतर्गत, विशेष रूप से पड़ोसी देशों के लिए पुलिस और सशस्त्र अर्धसैनिक बलों को प्रदान किया जाने वाला प्रशिक्षण है।

आईटीईसीके अंतर्गत नागरिक प्रशिक्षण

चालू वित्त वर्ष में कुल 216 मेनू-आधारित/बहु-देशीय और 100 से अधिक एकल-देशीय और अनुकूलित पाठ्यक्रमों को कार्यान्वयन के लिए मंजूरी दी गई है। दिसंबर 2024 तक, इनमें से आधे से अधिक पाठ्यक्रम पूरे हो चुके हैं और 4200 से अधिक विदेशी सरकारी पेशेवरों ने इन पाठ्यक्रमों का लाभ उठाया है। पिछले वर्ष की तुलना में, यह एक स्वस्थ वृद्धि की प्रवृत्ति को दर्शाता है। सागर अमृत (प्रशांत द्वीप देशों के लिए), क्राड इंफ्रास्ट्रक्चर फेलोशिप (भारत-प्रशांत देशों के लिए) और एलएसीदेशों जैसे विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों के लिए सुनिश्चित क्षमता निर्माण सहायता प्रदान करने वाले विशिष्ट पैकेज कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

चालू वित्त वर्ष के दौरान, डीपीए II ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों के वितरण में नवाचारों को शामिल करने का प्रयास किया। इसमें वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के लिए अभ्यास-उन्मुख पाठ्यक्रम देने के लिए कोएलेशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर (सीडीआरआई) और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (आईबीसीए) जैसे अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों के साथ साझेदारी करना शामिल था। सुशासन और मानवाधिकारों के बीच संबंधों के प्रति वैश्विक समुदाय को संवेदनशील बनाने के लिए एक विशिष्ट पाठ्यक्रम भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) द्वारा पाठ्यक्रमों की एक श्रृंखला के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। साइट-विशिष्ट प्रकृति और वन्यजीव संरक्षण पर एक अनूठा पाठ्यक्रम पहली बार किसी प्रशिक्षण संस्थान में नहीं, बल्कि एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय उद्यान में संचालित किया जा रहा है। चालू वर्ष में कार्यान्वित किया गया एक अन्य नवाचार आईटीईसी-प्रोफेशनल की नई पद्धति के अंतर्गत चार्टर्ड पेशेवरों के लिए तकनीकी पाठ्यक्रमों का संचालन है; इसके अंतर्गत भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा भारतीय लेखांकन कहानी को साझा करने पर पहला पाठ्यक्रम संचालित किया गया। चालू वित्त वर्ष में आईटीईसी कार्यक्रम की एक विशेष विशेषता लैंगिक प्रासंगिक विषयों पर केवल महिलाओं के लिए पाठ्यक्रमों का कार्यान्वयन रहा है।

चालू वर्ष में संचालित पाठ्यक्रमों में से कुछ मुख्य हैं, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी (एनजेए), भोपाल में भूतानी न्यायपालिका के लिए पाठ्यक्रम; हैदराबाद में

मैनेज में इंडोनेशिया के लिए एग्रीटेक स्टार्टअप पर पाठ्यक्रम; राष्ट्रीय जल अकादमी (एनडब्ल्यूए), पुणे में नेपाल के लिए बाढ़ पूर्वानुमान पाठ्यक्रम; वियतनाम, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका और गुयाना के लिए मीडिया पेशेवर पाठ्यक्रम; वित्तीय खुफिया/धन शोधन विरोधी (एएमएल)/आतंकवाद के वित्त-पोषण का प्रतिकार (सीएफटी) पर पाठ्यक्रम; मिस्र के वाणिज्यिक प्रतिनिधियों के लिए ई-कॉमर्स कराधान और प्रेरण प्रशिक्षण पर पाठ्यक्रम; महात्मा गांधी शांति और सतत विकास शिक्षा संस्थान (एमजीआईईपी) और भारत द्वारा स्थापित यूनेस्को केंद्र के साथ साझेदारी में डिजिटल शिक्षाशास्त्र और प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा पर पाठ्यक्रम; और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टीआईएसएस), मुंबई में विकलांग बच्चों से निपटने वाले म्यांमार के सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रम।

एनटीपीसी स्कूल ऑफ बिजनेस, राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू), राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आरआरयू) और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग (सी-डैक) द्वारा ग्रिड प्रबंधन से लेकर ईवी तकनीक तक बिजली क्षेत्र के विषयों से संबंधित बड़ी संख्या में पाठ्यक्रम, फोरेंसिक विज्ञान से संबंधित विषय, डेटा और कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित विषय संचालित किए गए। अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय (ईएफएलयू) द्वारा 08 पाठ्यक्रमों के माध्यम से अंग्रेजी भाषा का प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जो देश-विशिष्ट और बहु-देशीय अनुरोधों को पूरा करता है और पेशेवर शिक्षकों के साथ-साथ प्रशासकों दोनों की जरूरतों को पूरा करता है। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) ने बांग्लादेश, कंबोडिया, तंजानिया और अन्य देशों के सिविल सेवकों के लिए मध्य-करियर प्रशिक्षण के लिए 13 पाठ्यक्रम संचालित किए।

वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के लिए नीति-उन्मुख पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए, डीपीए II प्रभाग नियमित रूप से आईटीईसी-कार्यकारी पद्धति के अंतर्गत उच्च मूल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करता है। अब तक, चालू वित्तीय वर्ष में 06 पाठ्यक्रम आयोजित किए गए हैं, और मार्च 2025 तक अन्य 06-08 पाठ्यक्रम आयोजित किए जाने की संभावना है। कुछ अधिक महत्वपूर्ण पाठ्यक्रमों में शामिल हैं: भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), इंदौर द्वारा आधारभूत संरचना में वैश्विक रुझान; आपदा रोधी आधारभूत संरचना के लिए गठबंधन (सीडीआरआई) द्वारा बिजली क्षेत्र का लचीलापन; राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सामरिक जुड़ाव कार्यक्रम (आईएनएसटीईपी); राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान और विकास संस्थान (एनआईएलईआरडी) द्वारा विकास के लिए डेटा, और भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) द्वारा मानवाधिकार।

सुधार प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, ऑनलाइन पोर्टल में कई सुधार लागू किए जा रहे हैं जो प्रतिभागियों के पंजीकरण से लेकर बिलिंग तक पूर्ण-चक्र स्वचालन को सक्षम बनाता है। तीन प्रमुख आईटीईसीहितधारकों-प्रतिभागी, प्रशिक्षण संस्थान और मिशन में आईटीईसीसमन्वयक-को एक-दूसरे के साथ सहजता से चर्चा करने और व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करने में सक्षम बनाने के लिए एक ऐप विकसित किया जा रहा है। वेबसाइट (www.itecgoi.in) को एक लाइव डैशबोर्ड के साथ अपग्रेड किया गया है जो योजना के प्रदर्शन को ग्राफिक रूप से प्रदर्शित करता है।



आईटीईसी वेबसाइट के उन्नत अनुभाग में एक लाइव डैशबोर्ड है जिसमें मिशन में भागीदार, प्रशिक्षण संस्थान और आईटीईसी समन्वयक के बीच निर्बाध चर्चा के प्रावधान हैं।

देश में आयोजित पाठ्यक्रमों के अलावा, डीपीए II ऑनसाइट मोड में क्षमता निर्माण सहायता भी प्रदान करता है। मेसर्स एजुकेशनल कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (ईडीसीआईएल) के माध्यम से फिजी के प्रवासी स्कूलों को तमिल भाषा के शिक्षक उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी तरह, नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी (एनएफएसयू) ने गुयाना के पुलिस संगठनों को फोरेंसिक उपकरणों के संचालन के लिए ऑनसाइट प्रशिक्षण प्रदान किया। इस तरह का समर्थन आईटीईसी-विशेषज्ञ पद्धति के अंतर्गत व्यक्तिगत विशेषज्ञों को तैनात करने के हमारे पिछले अनुभव के अनुरूप है, जब आयुष विषयों, मत्स्य पालन और पादप विज्ञान में नागरिक विशेषज्ञों को विदेशी प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है।

आईटीईसी के अंतर्गत रक्षा प्रशिक्षण

रक्षा-आईटीईसी पद्धति के अंतर्गत मित देशों (एफएफसी) के लिए रक्षा संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। 2014 से, सेना, नौसेना, वायु सेना और तटरक्षक बल के 100 से अधिक रक्षा प्रशिक्षण संस्थानों में करीब 12,000 रक्षा कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है। चालू वर्ष में, 79 एफएफसी को 3316 स्लॉट प्रदान किए जा रहे थे। विशेष रूप से, राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज (एनडीसी), नई दिल्ली में "राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक अध्ययन" पर एक वर्ष के पाठ्यक्रम के लिए 30 देशों को 41 स्लॉट की पेशकश की गई है। इसी तरह के उच्च-मूल्य/रक्षा प्रबंधन पाठ्यक्रम कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट, सिकंदराबाद; डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज (डीएसएससी) वेलिंगटन; और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए), पुणे जैसे संस्थानों में भी प्रदान किए जाते हैं।

इन प्रशिक्षणों को बहु-वर्षीय आधार पर विदेशों में रक्षा प्रशिक्षण टीमों की तैनाती द्वारा पूरक बनाया जाता है। 2014 से, विदेश मंत्रालय द्वारा 20 से

अधिक देशों में करीब 200 भारतीय रक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है।

डीपीए द्वितीय प्रभाग ने पुलिस और अर्धसैनिक बलों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आईटीईसी-सिक्वोरिटी नामक एक समर्पित पद्धति विकसित की है। इस पद्धति के अंतर्गत, पाठ्यक्रम के प्रशासन को भागीदारी की आसानी के लिए सरल बनाया गया है, और सुरक्षा प्रोटोकॉल को पूरा करने के लिए अनुकूलित किया गया है। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) जैसे संस्थानों में उच्च पाठ्यक्रम आपदा राहत, खुफिया, जासूसी प्रशिक्षण, फोरेंसिक विश्लेषण और सीमा प्रबंधन को पूरा करने वाले प्रशिक्षण संस्थानों में सामरिक पाठ्यक्रमों के साथ प्रदान किए जाते हैं। सामरिक/संचालन विषयों के साथ-साथ एएमएल/सीएफटी, आर्थिक खुफिया, क्रिप्टो, साइबर धोखाधड़ी और मोबाइल फोरेंसिक जैसे प्रौद्योगिकी उन्मुख विषयों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत के बाद से, इस पद्धति के अंतर्गत 50 से अधिक पाठ्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें 800 से अधिक रक्षा बल कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया है। चालू वित्त वर्ष में, लगभग 800 कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए करीब 45 पाठ्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, डीपीए II प्रभाग आईटी उत्कृष्टता केंद्र (सीईआईटी) परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक प्रभाग है, जिसके अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसी सी-डैक विदेशों में आईटी प्रशिक्षण केंद्र संचालित करती है; और "मानवता के लिए भारत" योजना, जिसके अंतर्गत कृत्रिम अंग फिटमेंट शिविरों के संचालन के लिए कार्यान्वयन एजेंसी भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति (बीएमवीएसएस) को धन उपलब्ध कराया जाता है।

आज तक 47 देशों में कुल 58 सीईआईटी परियोजनाएं क्रियान्वित की गई हैं, जिनमें करीब 2 लाख प्रशिक्षुओं को हाई परफॉरमेंस कंप्यूटिंग,

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/मशीन लर्निंग (एआई/एमएल) और बिग डेटा जैसे विषयों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। फिलहाल वानुअतु, सोलोमन द्वीप और अर्जेंटीना में सीईआईटी परियोजनाएं चालू हैं। जॉर्डन और तंजानिया के केंद्रों के लिए प्रशिक्षण सहायता प्रदान की जा रही है। सी-डैक कजाकिस्तान में स्थापित सीईआईटी के उन्नयन में भी सहयोग कर रहा है।

अब तक 21 देशों में कुल 30 'इंडिया फॉर ह्यूमैनिटी' शिविर आयोजित किए जा चुके हैं, जिसके परिणामस्वरूप 16,500 से अधिक कृत्रिम अंग लगाए गए हैं। चालू वित्त वर्ष में इथियोपिया, मंगोलिया, श्रीलंका, मलावी और मेडागास्कर में शिविर आयोजित किए गए हैं। इस पहल को मिली तीव्र सराहना को देखते हुए प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि प्रशांत द्वीप देशों और कैरिबियन देशों में क्षेत्रीय आधार पर ऐसे शिविर आयोजित किए जाएंगे। तदनुसार, भविष्य में मोजाम्बिक, तंजानिया और निकारागुआ के अलावा पापुआ न्यू गिनी, तिमोर-लेस्ते और टोबैगो में भी शिविर लगाने की योजना है।

भारतीय प्रशिक्षण संस्थानों की गहनता और सीमा को देखते हुए, विकसित देशों द्वारा अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए उनकी मांग बढ़ रही है। इस प्रवृत्ति के हिस्से के रूप में, डीपीए II प्रभाग भारत-अमेरिका त्रिकोणीय विकास साझेदारी को लागू करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएसएआईडी) के साथ साझेदारी कर रहा है। इस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, तीसरे देशों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम साझेदारी में डिजाइन किए जा रहे हैं और भारतीय संस्थानों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे हैं। फिलीपींस और फिजी (मनोवैज्ञानिक-सामाजिक देखभाल और टेलीमेडिसिन पर), इंडोनेशिया (संपोषणीय कॉफी बागान प्रथाओं पर) और तंजानिया (पावरग्रिड प्रबंधन पर) के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। विचाराधीन अतिरिक्त

कार्यक्रम थाईलैंड और और तंजानिया के साथ नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित विषयों के लिए इंडोनेशिया के साथ आपदा लचीलापन पर ज्ञान साझा करने की गतिविधियाँ हैं।

डीपीए III

‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ के दर्शन से प्रेरित होकर, भारत के अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग ने हाल के वर्षों में अपनी भौगोलिक पहुंच के साथ-साथ सहयोग के क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय रूप से विस्तार किया है। यह स्वाभाविक है कि भारत की अधिकांश महत्वपूर्ण विकास साझेदारियों में पड़ोसी देश शामिल हैं, क्योंकि भारत की बाहरी भागीदारी का ध्यान ‘पड़ोस पहले’ और ‘एक्ट ईस्ट’ नीतियों द्वारा समर्थित अपने निकटतम और विस्तारित पड़ोस पर है। भारत की विकास साझेदारियों की एक और उल्लेखनीय विशेषता इसकी मांग-आधारित प्रकृति और भागीदार देशों की प्राथमिकताओं के साथ घनिष्ठ संरेखण रही है।

विदेश मंत्रालय की विकास साझेदारी प्रशासन (डीपीए) शाखा ने पिछले कुछ वर्षों में अनुभव प्राप्त किया है, इसलिए परियोजनाओं की स्थिरता, परियोजना वितरण और कार्यान्वयन के अलावा, अधिक ध्यान दिया गया है। भारत के विकास साझेदारी मॉडल को इसकी मांग-संचालित प्रकृति और विदेशों में निष्पादित परियोजनाओं के केंद्र में भागीदार देश की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को रखने पर ध्यान केंद्रित करने के कारण अपने भागीदारों से उच्च स्तर की स्वीकृति मिली है।



भारत और मलावी के बीच फार्माकोपिया सहयोग पर समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर। अक्टूबर 2024



अगस्त 2024 में भारत से बीएचआईएसएचएमक्यूब के पहले बैच के साथ प्रधानमंत्री और यूक्रेन के राष्ट्रपति।

भारत की विकास साझेदारी डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) और स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक परिवहन, नवीकरणीय ऊर्जा, लघु और मध्यम उद्यमों जैसे नए क्षेत्रों में विस्तारित हुई है, जो भागीदार देशों की प्राथमिकताओं पर आधारित है। इसके अलावा, भारत की विकास साझेदारी पोर्टफोलियो पड़ोस में नई परियोजनाओं के साथ तीव्र होती जा रही है, और अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र, पश्चिम एशिया और ओशिनिया तक भी फैली हुई है।

इसके अलावा, डीपीए निम्नलिखित माध्यमों से विकसित हुआ है- (I) विदेशों में परियोजनाओं के निष्पादन के लिए भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (पीएसयू) के साथ अधिक साझेदारी; और (ii) परियोजना निगरानी और तकनीकी मार्गदर्शन में पेशेवर विशेषज्ञता को प्रभावित करने के लिए एक परियोजना प्रबंधन इकाई की शुरुआत।

भारत की विकास सहायता साझेदार देशों में रेलवे लिंक, सड़क और पुल, जलमार्ग, सीमा से संबंधित आधारभूत संरचना, ट्रांसमिशन लाइनों, बिजली उत्पादन, जल विद्युत आदि जैसे बहुत जरूरी आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए एक प्रमुख उत्प्रेरक रही है और यह स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और आवास जैसे सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों तक भी फैली हुई है।

अफगानिस्तान

गंभीर सुरक्षा चुनौतियों के बावजूद भारत अफगानिस्तान में पुनर्निर्माण और विकास प्रयासों में एक दृढ़ भागीदार रहा है। अफगानिस्तान को भारत की विकास सहायता का मुख्य जोर अफगान नागरिकों और उसके संस्थानों की शासन और सार्वजनिक सेवा प्रदान करने की क्षमता का निर्माण करना,

सामाजिक-आर्थिक आधारभूत संरचना का विकास करना, जीवन को सुरक्षित करना और आजीविका को बढ़ावा देना रहा है।

अफगानिस्तान में कुछ प्रमुख भारतीय परियोजनाएँ काबुल में संसद भवन (2015) और अफगान-भारत मैत्री बांध हैं, जिसे पहले सलमा बांध (2016) के नाम से जाना जाता था, जो एक एकीकृत, लोकतांत्रिक और समृद्ध अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। दोनों देशों ने अफगानिस्तान को भारत की विकास सहायता को और बढ़ाने के लिए सितंबर 2017 में एक साथ 'नई विकास साझेदारी' शुरू की।

भारत ने अनुदान सहायता बढ़ाकर अफगानिस्तान के सभी 34 प्रांतों में फैले उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं (एचआईसीडीपी) का समर्थन किया। 2005 से, भारतीय अनुदानों द्वारा वित्त-पोषित और कृषि, शिक्षा, श्रम, ग्रामीण विकास और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों को कवर करने वाले समुदाय-आधारित परियोजनाओं के तीन चरणों को अफगान सरकारी एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित किया गया है, इस प्रकार परियोजना प्रबंधन की दिशा में स्थानीय क्षमता का निर्माण हुआ है। 2005-2009 के दौरान कार्यान्वित किए गए चरण I और II के अंतर्गत 116 परियोजनाओं के लिए 20 मिलियन अमरीकी डॉलर प्रदान किए गए थे। 2012 में शुरू किए गए चरण III के अंतर्गत 420 परियोजनाओं के लिए 100 मिलियन अमरीकी डॉलर का वित्त-पोषण प्रदान किया गया, जिनमें से 350 पूरे हो चुके हैं। नवंबर 2020 में जिनेवा में आयोजित 2020 अफगानिस्तान सम्मेलन में, विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान में लगभग 100 नई परियोजनाओं को लागू करने के लिए 80 मिलियन अमरीकी डॉलर की अनुदान सहायता के साथ एचआईसीडीपी के चरण-IV के शुभारंभ की घोषणा की।

शिक्षा और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के लिए समर्थन अफगानिस्तान के साथ भारत की विकास साझेदारी का एक महत्वपूर्ण पहलू है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) द्वारा प्रशासित अफगान नागरिकों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना (एसएसएसएएन) के अंतर्गत, भारत भर के विश्वविद्यालयों और संस्थानों में अध्ययन करने के लिए अफगान छात्रों को 1000 वार्षिक छात्रवृत्ति स्लॉट प्रदान किए जाते हैं। 2006 से, इस योजना के अंतर्गत 10,000 से अधिक अफगान छात्रों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके अलावा, अफगान राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा बलों के शहीदों के बच्चों/आश्रितों के लिए 500 अन्य छात्रवृत्ति स्लॉट और कृषि अध्ययन के लिए 614 फेलोशिप प्रदान की जाती हैं, जिन्हें कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। भारत ने अफगान छात्रों के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के माध्यम से कंधार में अफगानिस्तान राष्ट्रीय कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एएनएसटीयू) की स्थापना का भी समर्थन किया जो अफगानिस्तान में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय है।

वर्तमान राजनीतिक और सुरक्षा स्थिति के कारण, अफगानिस्तान में अनुदान सहायता परियोजनाएं रुकी हुई हैं। हालांकि, भारत वर्तमान में भारतीय विश्वविद्यालयों में नामांकित छात्रों को छात्रवृत्ति कार्यक्रमों का समर्थन देता है।

म्यांमार

भारत म्यांमार में दो प्रमुख सड़क संपर्क परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य म्यांमार और भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों के बीच सड़क नेटवर्क का निर्माण करके क्षेत्रीय संपर्क को सुदृढ़ करना है। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (केएमएमटीटीपी) परियोजना के अंतर्गत, म्यांमार के सित्तवे में एक अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह बनाया गया है। सित्तवे पोर्ट को पलेतवा से जोड़ने वाली कलादान नदी के खंड को नेविगेशन के लिए विकसित किया गया है और पलेतवा में एक अंतर्देशीय जल टर्मिनल

स्थापित किया गया है। सित्तवे बंदरगाह का उद्घाटन मई 2023 में किया गया था और अब यह चालू है। हालांकि, चल रही सुरक्षा स्थिति के कारण, सित्तवे से पलेतवा तक अंतर्देशीय जलमार्ग चालू नहीं हैं। सित्तवे पोर्ट पर संचालन और रखरखाव (ओएंडएम) का काम वर्तमान में अप्रैल से पोर्ट, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (आईपीजीएल) द्वारा किया जा रहा है। भारत-म्यांमार सीमा पर पलेतवा और ज़ोरिनपुरई के बीच सड़क बनाने का काम भी चल रहा है। भारत ने भारत-म्यांमार-थाईलैंड (आईएमटी) त्रिपक्षीय राजमार्ग के कार्यान्वयन और कलेवा-यार्गी सड़क खंड के उन्नयन का समर्थन किया है। पूरा हो जाने पर, त्रिपक्षीय राजमार्ग भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को म्यांमार, थाईलैंड और अन्य आसियान देशों के साथ निर्बाध संपर्क प्रदान करेगा और माल और यातायात की आवाजाही को सुविधाजनक बनाएगा। इसके अलावा, संपर्क परियोजना भारत के आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को भी सुविधाजनक बनाएगी और दक्षिण पूर्व एशियाई पड़ोसियों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करेगी।

भारत ने म्यांमार में क्षमता निर्माण परियोजनाओं के लिए भी समर्थन प्रदान किया है, अर्थात् मांडले में म्यांमार सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एमआईआईटी), यांगून में भारत म्यांमार आईटी कौशल संवर्धन केंद्र (आईएमसीआईआईटीएस) और नेपीडॉ के पास कृषि अनुसंधान और शिक्षा के लिए उन्नत केंद्र (एसीएआरई) की स्थापना। भारत सरकार (जीओआई) 2008 से यांगून में आईएमसीआईआईटीएस की स्थापना और संचालन के लिए म्यांमार संघ गणराज्य (जीओएम) की सरकार की सहायता कर रही है। इसकी स्थापना के बाद से, 2839 छात्रों ने आईएमसीआईआईटीएस से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, जिससे इस क्षेत्र को कुशल जनशक्ति बनाने और रोज़गार सृजन के लिए क्षमता निर्माण में लाभ हुआ है। इसके अलावा, आईएमसीआईआईटीएसने स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों कंपनियों द्वारा नियोजित उद्योग-तैयार आईटीविशेषज्ञों का उत्पादन करके एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। स्नातक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियर, मोबाइल डेवलपर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, मल्टीमीडिया विशेषज्ञ, ऑपरेशन/प्रोजेक्ट



ऑपरेशन सद्भाव: तूफान यागी के बाद म्यांमार को एचएडीआरसहायता। सितंबर 2024



भारत से नेपाल को एचएडीआर सहायता आपूर्ति, जून 2024।

मैनेजर जैसे पदों पर हैं। इस परियोजना को इसके सकारात्मक प्रभाव और लाभों के लिए जीओएमके साथ-साथ आबादी द्वारा भी सराहा गया है, जैसा कि ऊपर बताया गया है।

नेपाल

भारत-नेपाल विकास साझेदारी परियोजनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला तक फैली हुई है, जिसमें रेलवे, सड़क, बिजली पारेषण लाइनें, पुलिस प्रशिक्षण और व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में आधारभूतसंरचना परियोजनाएं शामिल हैं। भारत लोगों और माल की आवाजाही को आसान बनाने के लिए नेपाल के साथ रेल संपर्क विकसित कर रहा है। पहले चरण के अंतर्गत, जयनगर-बरदीबास रेल लिंक (68.72 किमी) और जोगबनी-विराटनगर रेल लिंक (18.60 किमी) का विकास लगभग 10.8 मिलियन अमरीकी डॉलर की अनुमानित लागत से किया जा रहा है।

भारत ने व्यापार और माल और यातायात की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत-नेपाल सीमा पर नेपाल में बीरगंज, विराटनगर और नेपालगंज में तीन एकीकृत चेक-पोस्ट (आईसीपी) का निर्माण पूरा कर लिया है। इन्हें क्रमशः 2018, 2020 और 2024 में नेपाल सरकार को सौंप दिया गया था। आईसीपी भैरहवा का विकास वर्तमान में चल रहा है और आशा है कि 2025 में इसे पूरा करके नेपाल सरकार को सौंप दिया जाएगा। दोधारा चंदानी में भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पांचवें आईसीपी का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है।

भारत सरकार 752 मिलियन अमरीकी डॉलर की अनुदान सहायता के साथ नेपाल के पनौती में एक राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एनपीए) की स्थापना को

वित्त-पोषित कर रही है। एनपीए भारत सरकार द्वारा अनुदान सहायता के अंतर्गत पूरी तरह से वित्त-पोषित होने वाली सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) के रूप में नियुक्त किया गया था और परियोजना जुलाई 2022 में शुरू हुई और 2025 तक पूरी होने की आशा है। भारत नेपाल को 20 इलेक्ट्रिक बसें भी आपूर्ति करने की प्रक्रिया में है।

श्रीलंका

भारत-श्रीलंका विकास साझेदारी के अंतर्गत जाफना में एक आधुनिक सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण किया गया है। सांस्कृतिक केंद्र में 2 मंजिला संग्रहालय, 12 मंजिला लर्निंग टॉवर, एक ऑडिटोरियम ब्लॉक, एक सार्वजनिक चौक और सांस्कृतिक प्रदर्शन के लिए एक तैरता हुआ मंच शामिल है। इस परियोजना का उद्घाटन मार्च 2022 में विदेश मंत्री द्वारा किया गया था।

भारत श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के तीसरे और चौथे चरण को भी लागू कर रहा है। तीसरे चरण के अंतर्गत भारत के मध्य, उवा और दक्षिणी प्रांतों में समुदाय संचालित दृष्टिकोण के अंतर्गत 4,000 घरों का निर्माण किया जा रहा है। चौथे चरण के अंतर्गत उत्तर-पश्चिम, मध्य, उवा, दक्षिणी, पश्चिमी और अन्य प्रांतों में कुल 10,000 घर बनाने का प्रस्ताव है। भारतीय आवास परियोजना का समग्र उद्देश्य आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों और भारतीय मूल के तमिलों को संपोषणीय घर उपलब्ध कराना है।

मालदीव

भारत और मालदीव के बीच विकास साझेदारी बढ़ रही है, जिसमें अनुदान और ऋण सहायता दोनों शामिल हैं। भारत मालदीव के लिए रक्षा मंत्रालय के नए भवन के निर्माण में सहायता कर रहा है, जिसके 2025 तक पूरा होने की आशा है। मालदीव में नेशनल कॉलेज फॉर पुलिसिंग एंड लॉ एनफोर्समेंट (एनसीपीएलई) (पूर्व में आईएसएलईएस) का निर्माण पूरा हो चुका है और इस परियोजना का उद्घाटन मार्च 2022 में विदेश मंत्री द्वारा किया गया था। भारत ने माफ़ीलाफ़ुशी द्वीप पर भारत की सहायता से निर्मित समग्र प्रशिक्षण केंद्र में अतिरिक्त सुविधाओं के निर्माण के लिए अनुदान प्रदान किया।

100 मिलियन अमरीकी डॉलर के अनुदान और 400 मिलियन अमरीकी डॉलर के ऋण सहायता के माध्यम से भारत समर्थित ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट (जीएमसीपी) का निर्माण कार्य जारी है। प्रधानमंत्री और मालदीव के तत्कालीन राष्ट्रपति ने संयुक्त रूप से अगस्त 2022 में इस परियोजना की आधारशिला रखी थी। जीएमसीपी में माले के साथ विलिंगली, गुलहिफालू और थिलाफ़ुशी द्वीपों के बीच पुल और सड़क संपर्क का निर्माण शामिल है और इसके सितंबर 2026 तक पूरा होने की आशा है। यह परियोजना देश में शुरू की जाने वाली सबसे बड़ी आधारभूतसंरचना परियोजना है और एक बार पूरा हो जाने पर, यह मालदीव के लिए एक आर्थिक जीवन रेखा और एक बल-गुणक बन जाएगी।

मॉरीशस

भारत मॉरीशस को आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा और क्षमता निर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकास सहायता प्रदान कर रहा है। इस वर्ष शुरू की गई कुछ महत्वपूर्ण आधारभूतसंरचना और क्षमता निर्माण परियोजनाओं

में ईएनटी अस्पताल का निर्माण और मॉरीशस में प्राथमिक विद्यालयों के लिए शिक्षण सहायक सामग्री प्रदान करने के लिए ई-टैबलेट परियोजना शामिल है।

भारत पोर्ट लुइस में एक सिविल सेवा कॉलेज के निर्माण के लिए अनुदान सहायता भी प्रदान कर रहा है जो पूरा होने वाला है। एक अन्य परियोजना में फ़ॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए भारतीय अनुदान सहायता शामिल है जिसके 2025 में पूरा होने की आशा है। ग्रैंड बोइस में मेडी-क्लिनिक का उद्घाटन 17 जुलाई को किया गया था और यह रोगी सेवा के लिए सफलतापूर्वक चल रहा है। न्यू ग्रोव और कैप माल्हेरेक्स में क्षेत्रीय स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण क्रमशः 15 अक्टूबर और 28 अक्टूबर को पूरा हुआ। भारत सरकार की 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता के अंतर्गत मॉरीशस के जवाहर लाल नेहरू अस्पताल में रीनल ट्रांसप्लांट यूनिट की स्थापना का काम चल रहा है और 2025 की शुरुआत में इसके पूरा होने की संभावना है।

भारत मॉरीशस को अनुदान के आधार पर 100 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने और आपूर्ति करने की प्रक्रिया में भी है। डिलीवरी 2025 में पूरी होने की आशा है।

जाम्बिया

भारत सरकार जाम्बिया सरकार को अनुदान सहायता के माध्यम से 9.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के चिकित्सा उपकरण आपूर्ति कर रही है। चिकित्सा उपकरण जनवरी 2025 में जाम्बिया पहुंचने की आशा है। भारत जाम्बिया को उपहार के रूप में 600 सिलाई मशीनें भी आपूर्ति करने की प्रक्रिया में है।



मॉरीशस के तत्कालीन प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ के साथ विदेश मंत्री ने मॉरीशस में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। अक्टूबर 2024।



भारत द्वारा मेडागास्कर के स्वतंत्र राष्ट्रीय चुनाव आयोग को तीन 9-टन ट्रक दान किए गए। दिसंबर 2024

दक्षिण अफ्रीका

युवा लोगों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं और दक्षिण अफ्रीका की कारीगर कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गुणवत्तापूर्ण व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, जुलाई 2018 में प्रधानमंत्री की दक्षिण अफ्रीका यात्रा के दौरान भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच गांधी मंडेला कारीगर कौशल विशेषज्ञता केंद्र (जीएमसीओएस) की स्थापना के लिए एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। समझौता-ज्ञापन में दक्षिण अफ्रीका में उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना शामिल है। दक्षिण अफ्रीका सरकार ने गांधी-मंडेला केंद्र के पहले स्थान के रूप में प्रिटोरिया में त्वावने दक्षिण तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (टीवीईटी) कॉलेज की पहचान की। भारतीय सहायता के अंतर्गत, दक्षिण अफ्रीका में मांग के अंतर्गत कौशल में मशीनरी और उपकरण, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, बाह्य उपकरण और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएं प्रदान की गई हैं। टीवीईटी कॉलेज में जीएमसीओएस अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया था। परियोजना की उपयोगिता को देखते हुए, दक्षिण अफ्रीका सरकार ने परियोजना के विस्तार का अनुरोध किया है जिस पर भारत ने सहमति व्यक्त की है। सुविधा का वार्षिक रखरखाव भी चल रहा है।

मंगोलिया

भारत उलानबटार में भारत-मंगोलिया मैत्री माध्यमिक विद्यालय के निर्माण के लिए सहायता प्रदान कर रहा है। रक्षा मंत्री ने सितंबर 2022 में इस परियोजना की आधारशिला रखी थी। 17 मई 2015 को प्रधानमंत्री की मंगोलिया यात्रा के दौरान इस परियोजना के लिए एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। मंगोलियाई पक्ष से आवश्यक मंजूरी मिलने के बाद, साइट पर खुदाई का काम अक्टूबर 2024 में शुरू हुआ। इस परियोजना के 2026 तक पूरा होने की आशा है।

मेडागास्कर

भारत ने दिसंबर में मेडागास्कर में स्वतंत्र राष्ट्रीय चुनाव आयोग (आईएनईसी) को तीन 09-टन ट्रक उपहार में दिए।

कोमोरोस

भारत कोमोरोस को बसों, एम्बुलेंस और पिकअप वैन सहित सार्वजनिक परिवहन वाहनों की आपूर्ति में सहायता कर रहा है, जिसका उद्देश्य कोमोरोस के लोगों के लिए आवागमन की सुविधा में सुधार करना है। यह आपूर्ति 2025 में पूरी होने की आशा है।

एलएसई देश

भारत कैरेबियन समुदाय (कैरिकॉम) और सेंट्रल अमेरिकन इंटीग्रेशन सिस्टम (एसआईसीएस) देशों को संपोषणीय और व्यवहार्य उद्यमों के निर्माण/विकास के लिए प्रति परियोजना लगभग 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर (अनुदान सहायता के आधार पर) की लागत से लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) के विकास के लिए मशीनरी की आपूर्ति कर रहा है। परियोजना के प्रारंभिक चरण में सूरीनाम, सेंट वीसेंट और ग्रेनेडाईस, त्रिनिदाद और टोबैगो, सेंट किट्स और नेविस, डोमिनिकन गणराज्य और बारबाडोस के लिए लघु और मध्यम आकार के उद्यम (एसएमई) प्रस्तावों पर काम किया जा रहा है।

सूरीनाम

भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की विस्तारित निधि सुविधा के अंतर्गत सूरीनाम सरकार के एकीकृत सामाजिक कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन का समर्थन कर रही है, जिसमें 6 महीने की अवधि के लिए 28 विभिन्न खाद्यान्नों की खरीद और आपूर्ति की जाएगी। 425 मीट्रिक टन की पहली खेप 17 नवंबर को भारत से रवाना हुई।

प्रशांत द्वीपीय देश (पीआईसी)

भारत 9 प्रशांत द्वीपीय देशों को 16 समुद्री एम्बुलेंस की आपूर्ति की प्रक्रिया में कर रही है, जो 22 मई 2023 को पोर्ट मोरेस्बी, पापुआ न्यू गिनी में आयोजित भारत-प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच (एफआईपीआईसी) III शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा घोषित की गई सेवाओं में से एक है। समुद्री एम्बुलेंस का उद्देश्य प्रशांत द्वीपीय देशों में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं में सुधार करना है, जो अक्सर अपने दूरस्थ स्थानों और

समय पर चिकित्सा देखभाल तक पहुँच की कमी के कारण चुनौतियों का सामना करते हैं। यह प्रतिबद्धता मानवीय सहायता और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रशांत द्वीपीय देशों के लिए प्रमुख विकास भागीदार के रूप में भारत की भूमिका को रेखांकित करती है।

फिजी

भारत सरकार फिजी गणराज्य की सरकार के साथ मिलकर सुवा में एक नया 100 बिस्तरों वाला सुपर स्पेशियलिटी कार्डियोलॉजी अस्पताल विकसित करने के लिए काम कर रही है, जो भारत सरकार की अनुदान सहायता परियोजना है, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने 2023 में तीसरे एफआईपीआईसीशिखर सम्मेलन में की थी। इस संबंध में, फिजी सरकार के परामर्श से सरकार से सरकार (जी2जी) समझौता-ज्ञापन का मसौदा अंतिम रूप दिया जा रहा है।

पलाऊ

भारत पलाऊ को 12 भारी ड्यूटी, उच्च तापमान प्रतिरोधी पानी के टैंक की आपूर्ति करने की प्रक्रिया में है। अनुबंध प्रदान किया जा चुका है और माल पलाऊ के लिए पारगमन में है।

क्वाड

अपनी चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता (क्वाड) प्रतिबद्धताओं को पूरा करते हुए, भारत सरकार ने भारत-प्रशांत क्षेत्र में कोमोरोस, फिजी, मेडागास्कर और सेशेल्स को सौर शीत भंडारण, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का सौरीकरण और सौर जल पंपिंग प्रणाली प्रदान करने के लिए लगभग 2 मिलियन अमरीकी डॉलर की प्रतिबद्धता जताई है।

डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना

भारत यूपीआई, आधार या मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म (एमओएसआईपी), डिजिलॉकर, ईसंजीवनी आदि डिजिटल पेशकशों के

माध्यम से दुनिया भर में, विशेष रूप से ग्लोबल साउथ के देशों में भारत में विकसित डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को बढ़ावा दे रहा है। यह 2023 और 2024 में आयोजित वॉयस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट्स के अंतर्गत विचार-विमर्श से निकला है। डीपीआई के लिए भारत का जोर भारत और विदेशी देशों दोनों में डिजिटल परिवर्तन को आगे बढ़ाने और पारिस्थितिकी तंत्र-केंद्रित डिजिटल पहलों (जैसे इंडिया स्टैक) में सहयोग बढ़ाने के लिए है। विदेशी सरकारों के साथ इंडियास्टैक डीपीआई को बढ़ावा देने के सरकारी प्रयासों ने सतह समझौता-ज्ञापनों में फलित किया है।

विदेशों में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के निर्यात/प्रचार के लिए, आरबीआई और मेजबान देशों-गुयाना, पेरू, उरुग्वे, नामीबिया, फिजी और नाइजीरिया के सेंट्रल बैंक के बीच छह एलओआई पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (एनआईपीएल) और उनके समकक्षों के बीच नामीबिया, पेरू, त्रिनिदाद और टोबैगो और बांग्लादेश के लिए वाणिज्यिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जबकि यूपीआई पर आगे सहयोग के लिए गुयाना, जमैका और मालदीव के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

भारत सरकार भारत की अनुदान सहायता के साथ श्रीलंका यूनिट डिजिटल आइडेंटिटी प्रोग्राम के कार्यान्वयन में सहायता कर रही है। परियोजना के कार्यान्वयन से सरकारी सेवाओं की अधिक प्रभावी और कुशल डिलीवरी और सामाजिक-आर्थिक समावेशन में वृद्धि होगी। इसके अलावा, म्यांमार सरकार के साथ उनकी आबादी के लिए डिजिटल पहचान के लिए एक समान परियोजना चल रही है जिसे भारत सरकार पायलट आधार पर शुरू करेगी।

डीपीए IV

डीपीए IV प्रभाग को विरासत स्थलों के जीर्णोद्धार और संरक्षण की परियोजनाओं से निपटने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो भारत की सांस्कृतिक



फिजी सरकार को चिकित्सा आपूर्ति सौंपी गई, और फिजी में भारत की राजनयिक उपस्थिति के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया गया। अप्रैल 2024।



संहिता के अंतर्गत 1100 भारतीय पांडुलिपियों के डिजिटल संग्रह/सूची की वेबसाइट

कूटनीति पहुंच के एक हिस्से के रूप में भागीदार देशों के सांस्कृतिक परिदृश्य को परिभाषित करते हैं। जबकि इन परियोजनाओं को संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत नामित तकनीकी एजेंसी एएसआई द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, इनका समन्वय और वित्त-पोषण विदेश मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह प्रभाग भित्ति चित्रों, पांडुलिपियों आदि जैसी अमूर्त विरासत परिसंपत्तियों के जीर्णोद्धार और संरक्षण से संबंधित परियोजनाओं को लागू करने के लिए अन्य संगठनों के साथ भी सहयोग करता है।

विरासत स्थलों की तीनों चल रही जीर्णोद्धार परियोजनाओं में काम जोरों पर चल रहा है। इनमें कंबोडिया (ता प्रोहम और ग्रीह विहियर) और लाओ पीडीआर (वैट फोउ) की परियोजनाएं शामिल हैं। वियतनाम में दो नई परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं।

ता प्रोहम मंदिर, कंबोडिया: यह विदेश मंत्रालय की सबसे पुरानी परियोजना है, जो फरवरी, 2004 में शुरू हुई थी। परियोजना का मौजूदा दस वर्ष लंबा चरण III नवंबर 2026 में पूरा होने की संभावना है। चालू वित्त वर्ष के दौरान, हॉल ऑफ ड्राइंग जैसे प्रमुख खंडों के लिए संरक्षण कार्य पूरा हो गया है, जिससे समग्र भौतिक प्रगति 70 प्रतिशत से अधिक हो गई है।

ग्रीह विहियर मंदिर, कंबोडिया: यह विदेश मंत्रालय द्वारा शुरू की गई नवीनतम परियोजना और कंबोडिया में दूसरी परियोजना है। 2020 में स्वीकृत इस परियोजना के 10 वर्षों में पूरा होने की संभावना है। चालू वित्त वर्ष के दौरान, आधारभूत आकलन, वैज्ञानिक अध्ययन और पर्यटक पहुंच सुविधाओं के निर्माण के साथ परियोजना गतिविधियों के कार्यान्वयन में तेजी आई है। कुल प्रगति 20 प्रतिशत से कम है।

वट फौ मंदिर, लाओ पीडीआर: पहला चरण (मई 2007-मई 2017) सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद यह परियोजना वर्तमान में अपने दूसरे चरण में है। 10वर्ष लंबा दूसरा चरण नवंबर 2018 में शुरू हुआ। कोविड के वर्षों में व्यवधान के बाद, काम की गति बहाल हो गई है और केंद्रीय औपचारिक मार्ग और उसके परिचर चतुर्भुज पर काम किया गया, जिससे कुल भौतिक प्रगति 20 प्रतिशत के करीब पहुंच गई। 2024 में वट फौ यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पर एएसआई द्वारा किए गए काम के 15वर्ष पूरे हो जाएंगे।

एएसआई द्वारा प्रकाशित वट फौ के जीर्णोद्धार और संरक्षण कार्य पर एक विशेष प्रकाशन का शुभारंभ 4 नवंबर को लाओस के गृह मंत्री विलायवोंग बौडाखम और शिक्षा और खेल संघ के मंत्री फाउट सिम्मालावोंग ने किया।

22 दिसंबर 2022 को इस परियोजना को औपचारिक रूप से माई सन प्रबंधन बोर्ड को सौंप दिया गया। इसके बाद, मंदिरों के "ई" और "एफ" समूहों का संरक्षण शुरू किया गया है। संरक्षण कार्य शुरू करने के लिए दिसंबर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की टीम को साइट पर भेजा गया था।

कंबोडिया के वाट राजा बो पैगोडा में भित्ति चित्रों का संरक्षण: इस परियोजना को अनुदान सहायता के रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसमें एएसआई कंबोडियाई अधिकारियों को पर्यवेक्षी और तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान कर रहा है। जीर्णोद्धार कार्य चल रहा है, और अनुदान राशि की दो किस्तें जारी की जा चुकी हैं।

नई परियोजनाएं

माई सन साइट पर मंदिरों के "एफ" और "ई" समूह के अलावा, डोंग डुओंग बौद्ध मठ का संरक्षण और नहान टॉवर का संरक्षण भी वियतनाम में विचाराधीन है। इन परियोजनाओं की घोषणा प्रधानमंत्री ने दिसंबर 2020 में आयोजित भारत-वियतनाम वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान की थी।

भाषा, अनुष्ठान, प्रथाओं, प्रदर्शन और अन्य ललित कलाओं जैसी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की संस्थागत तरीके से बहाली और पुनरुद्धार को बढ़ावा देने के प्रयास के अंतर्गत, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (आईआईसी), नई दिल्ली ने यूके, डेनमार्क और नेपाल में विभिन्न स्थानों पर रखी गई भारतीय पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए एक शोध परियोजना शुरू की। परिणामों को 'दक्षिण एशियाई पांडुलिपि इतिहास और पाठ्य संग्रह' (संहिता) के रूप में सार्वजनिक डोमेन में रखा गया है, जो सूचीबद्ध और डिजिटल प्रारूप में 1100 भारतीय पांडुलिपियों को प्रदर्शित करता है। इस परियोजना का दूसरा चरण, जिसका लक्ष्य 8 देशों और रिपॉजिटरी में 3000 पांडुलिपियों को सूचीबद्ध और डिजिटल बनाना है, विचाराधीन है।

अध्याय

19

नीति नियोजन एवं अनुसंधान

नीति नियोजन एवं अनुसंधान, विदेश नीति में विशेषज्ञता रखने वाले सामरिक, थिंकटैंक और अकादमिक समुदाय तक मध्यम अवधि की नीति नियोजन, अनुसंधान और आउटरीच से संबंधित पहलों के लिए मंत्रालय का नोडल प्रभाग है, साथ ही नीति नियोजन संवादों पर द्विपक्षीय साझेदार

देशों को शामिल करता है। नीति नियोजन प्रभाग सरकार की वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट (वीओजीएसएस) पहल और मंत्रालय में भारत की पड़ोस प्रथम नीति के समन्वय के लिए भी नोडल प्रभाग है।



विदेश मंत्री ने अगस्त 2024 में 'वैश्विक दक्षिण के लिए एक अद्वितीय प्रतिमान तैयार करना' विषय पर तीसरे/तीसरे वीओजीएसएस के पहले विदेश मंत्रियों के सत्र को वर्चुअली संबोधित किया।



विदेश मंत्री ने अगस्त 2024 में 'वैश्विक दक्षिण के लिए एक अद्वितीय प्रतिमान तैयार करना' विषय पर तीसरे वीओजीजीएस के पहले विदेश मंत्रियों के सत्र को वर्चुअली संबोधित किया।

वर्ष के दौरान, वीओजीजीएसका तीसरा संस्करण 17 अगस्त को वर्चुअल प्रारूप में आयोजित किया गया था, जिसका व्यापक विषय था, "एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त वैश्विक दक्षिण"। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया और उद्घाटन नेताओं के सत्र की मेजबानी की। उद्घाटन सत्र के बाद 10 मंत्रिस्तरीय सत्र हुए, जिनमें दो विदेश मंत्रियों के सत्र और स्वास्थ्य, वित्त, ऊर्जा, शिक्षा, वाणिज्य, आईटी, युवा, शिक्षा और पर्यावरण मंत्रालयों द्वारा आयोजित एक-एक सत्र शामिल थे। शिखर सम्मेलन में वैश्विक दक्षिण के 123 देशों के 173 गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया, जिनमें 21 राष्ट्राध्यक्ष/सरकार प्रमुख, 34 विदेश मंत्री और 118 मंत्री और उप मंत्री शामिल थे।

वर्ष के दौरान, प्रभाग ने जापान, फ्रांस, नॉर्वे के विदेश मंत्रालयों के समकक्ष नीति नियोजन प्रभागों/ब्यूरो के साथ और ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के क्वाड सदस्य-राज्यों के साथ संयुक्त रूप से नीति नियोजन वार्ता आयोजित की। इस अवधि के दौरान एक संयुक्त भारत-जापान-कोरिया लिपक्षीय नीति नियोजन वार्ता भी आयोजित की गई।

प्रभाग प्रमुख थिंक टैंकों और शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से अपनी चार प्रमुख पहलों रायसीना डायलॉग, हिंद महासागर सम्मेलन, एशिया आर्थिक वार्ता और वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के माध्यम से भारत की विदेश नीति की पहुंच का नेतृत्व करता है। यह भारत-अमेरिका फोरम, भारत-जापान फोरम सहित कई उच्च प्रभाव वाली सामरिक वार्ताओं का भी आयोजन करता है, जो वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भारत की भागीदारी को सुदृढ़ करता है।

9^{वां} रायसीना डायलॉग, "चतुरंग: संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग, सृजन" विषय पर 21-23 फरवरी को नई दिल्ली में ऑब्जरर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित किया गया था। इस वर्ष के संस्करण में 115 देशों

के 2500 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिससे यह विदेश नीति चिकित्सकों और विशेषज्ञों की सबसे बड़ी वैश्विक सभाओं में से एक बन गई।



फरवरी 2024 को नई दिल्ली में 9^{वां} रायसीना डायलॉग में ग्रीस के प्रधानमंत्री क्यारिाकोस मिस्तोताकिस के साथ प्रधानमंत्री।



फरवरी 2024 को नई दिल्ली में 9^{वें} रायसीना डायलॉग के उद्घाटन सत्र को विदेश मंत्री ने संबोधित किया।



विदेश मंत्री ने फरवरी 2024 में पर्थ में सातवें/7^{वें} हिंद महासागर सम्मेलन में मुख्य भाषण दिया।

सातवां हिंद महासागर सम्मेलन 9 और 10 फरवरी को पर्थ में आयोजित किया गया था, जिसे ऑस्ट्रेलिया सरकार के विदेश मामलों और व्यापार विभाग, एस राजारत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, सिंगापुर और

ऑस्ट्रेलिया में पर्थ-यूएस एशिया सेंटर के सहयोग से आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का विषय “एक स्थिर और संपोषणीय हिंद महासागर की ओर” था।



विदेश मंत्री के साथ श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉंग और सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन फरवरी 2024 में पर्थ में सातवें हिंद महासागर सम्मेलन के दौरान।



विदेश मंत्री ने फरवरी 2024 में पुणे में आयोजित 8^{वें} एशिया-आर्थिक वार्ता 2024 को वर्चुअली संबोधित किया।

एशिया आर्थिक वार्ता 29 फरवरी-02 मार्च को पुणे में आयोजित की गई थी, जिसका आयोजन पुणे अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के सहयोग से किया गया था। इस शिखर सम्मेलन के 7^{वें} संस्करण का विषय "प्रवाह के युग में भू-आर्थिक चुनौतियाँ" था।

वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन नवाचार वार्ता का उद्घाटन संस्करण 8-9 अक्टूबर को बैंगलोर में आयोजित किया गया था, जिसका आयोजन

कार्नेगी इंडिया के सहयोग से किया गया था। इसने डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) पर तकनीक-केंद्रित चर्चाएँ आयोजित कीं, जिसमें इस बात पर ध्यान केंद्रित किया गया कि ये प्रौद्योगिकियाँ कैसे समावेशी विकास को बढ़ावा दे सकती हैं, शासन में सुधार कर सकती हैं, सतत विकास का समर्थन कर सकती हैं और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी बना सकती हैं।



7^{वाँ} भारत-अमेरिका फोरम में विदेश मंत्री, नई दिल्ली, जनवरी 2024

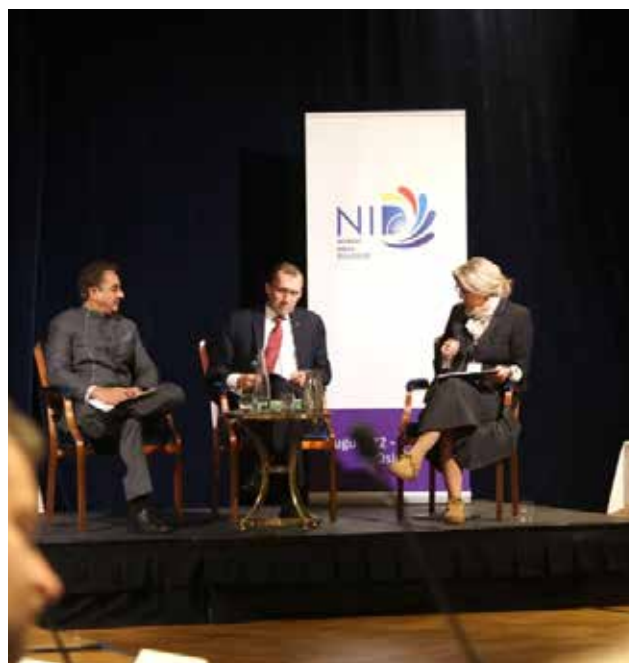
7^{वाँ} भारत-अमेरिका फोरम 27-29 जनवरी को दिल्ली में अनंत एस्पेन सेंटर के सहयोग से आयोजित किया गया था।

पहला भारत-नॉर्डिक ट्रैक 1.5 संवाद 22-23 अगस्त को नॉर्वे के ओस्लो में अनंत एस्पेन सेंटर के सहयोग से आयोजित किया गया था। संवाद में चर्चाएँ भू-राजनीति और सुरक्षा; उदीयमान हुई प्रौद्योगिकियाँ; आर्कटिक; हरित संक्रमण के विषयों पर केंद्रित रहीं।

भारत-यूरोपीय संघ ट्रैक 1.5 संवाद 21-22 अक्टूबर को नई दिल्ली में अनंत सेंटर के सहयोग से आयोजित किया गया था। इसने भारत-यूरोप संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए नए विचारों और अवसरों का पता लगाने के लिए नीति निर्माताओं, व्यापारिक नेताओं, थिंक-टैंक विशेषज्ञों और शिक्षाविदों को एक साथ लाया। चर्चाएँ क्षेत्रीय और वैश्विक भू-राजनीतिक मुद्दों, भारत-यूरोपीय संघ साझेदारी के भविष्य; भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी और सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित रहीं।

23^{वाँ} भारत कोरिया वार्ता 13-14 नवंबर को दिल्ली में अनंत एस्पेन सेंटर के सहयोग से आयोजित की गई।

7^{वाँ} भारत जापान भारत-प्रशांत फोरम 18-19 नवंबर को दिल्ली में आयोजित की गई, जिसका आयोजन दिल्ली पॉलिसी ग्रुप के सहयोग से किया गया। इस संस्करण का विषय था "भारत और जापान: एशियाई स्थिरता और प्रगति के लिए साझेदार"।



अगस्त 2024 में ओस्लो में प्रथम भारत-नॉर्डिक ट्रैक 1.5 संवाद के उद्घाटन भाषण में नॉर्वे के विदेश मंत्री एस्पेन बार्थ ईंडे के साथ विदेश राज्य मंत्री (केवीएस)।

तीसरा भारत जापान फोरम 6-7 दिसंबर को दिल्ली में अनंत एस्पेन सेंटर के सहयोग से आयोजित किया गया था।

इसके अलावा, विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुरूप, "भारत की नीति नियोजन और आईसीडब्ल्यूए और आरआईएस के विशेष संदर्भ में थिंक टैंक की भूमिका" पर अपनी 24th रिपोर्ट में, प्रभाग ने देश के विभिन्न हिस्सों में विदेश नीति की पहुंच का विस्तार किया और देश भर के विभिन्न राज्यों में कई ट्रैक 1.5/ट्रैक 2.0 संवाद आयोजित किए।

ऐसे ट्रैक 1.5/2.0 संवादों के माध्यम से, प्रभाग ने पूरे वर्ष विभिन्न भारतीय राज्यों में थिंक-टैंक और शैक्षणिक संस्थानों के साथ संस्थागत जुड़ाव का विस्तार करना जारी रखा। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के सहयोग से 28-29 फरवरी को गांधीनगर में एशियाई अफ्रीकी संधि कानून और व्यवहार सम्मेलन आयोजित किया गया; यूएसएस फाउंडेशन के सहयोग से 22-23 मार्च को उदयपुर में तीसरा महाराणा प्रताप वार्षिक भूराजनीति संवाद आयोजित किया गया; राष्ट्रीय उन्नत अध्ययन संस्थान के सहयोग से 30-31 अगस्त को बेंगलुरु में पहला ट्रैक 1.5 ध्रुवीय संवाद आयोजित किया गया; गेटवे हाउस के सहयोग से 23-24 सितंबर को मुंबई में पहला भारत-इंडोनेशिया ट्रैक 1.5 संवाद आयोजित किया गया; मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी के सहयोग से 21-23 नवंबर को कर्नाटक के मणिपाल में चीन अध्ययन पर 17th अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया; द एनर्जी फोरम के सहयोग से 14-15 दिसंबर को भुवनेश्वर में पूर्वोदय परिप्रेक्ष्य पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया।

प्रभाग ने विदेश नीति के रूझानों और अंतर्राष्ट्रीय विकास को कवर करते हुए कई शोध-पत्र और नीति संक्षिप्त तैयार किए। शोध आउटपुट का उपयोग मंत्रालय और विदेशों में भारतीय मिशनों द्वारा किया जाता है। इन पत्रों का फोकस तात्कालिक प्रतिक्रिया विकल्पों से लेकर उभरते मुद्दों, दुनिया में मध्यम और दीर्घकालिक रूझानों और विकास और इस सामरिक क्षितिज पर भारत की उदीयमान भूमिका और हितों तक था। प्रभाग ने कई प्रकाशन तैयार किए, जिनमें विदेश नीति दैनिक रिपोर्ट, नीति श्रृंखला, थिंक टैंक संग्रह, मंत्रिमंडल का मासिक सारांश और मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट शामिल हैं।

वर्ष के दौरान, प्रभाग ने नीति शक्ति पहल की कल्पना की और उसे क्रियान्वित किया जिसके तहत मंत्रालय में प्रभाग देश भर के थिंक टैंकों और शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से रुचि के किसी भी विषय पर अल्पकालिक अध्ययन/शोध परियोजनाएं शुरू कर सकते हैं। नीति शक्ति पहल के अंतर्गत कई प्रासंगिक शोध प्रस्ताव प्रक्रियाधीन हैं।

भारतीय वैश्विक परिषद (आईसीडब्ल्यूए)

यह प्रभाग भारतीय वैश्विक परिषद (आईसीडब्ल्यूए) से संबंधित सभी मामलों के लिए मंत्रालय में प्रशासनिक और नोडल प्रभाग है। वर्ष 2024 के दौरान, आईसीडब्ल्यूए ने भारतीय विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के अध्ययन को बढ़ावा देने के साथ-साथ भू-राजनीतिक और भू-सामरिक रूझानों और विकास का विश्लेषण करने के उद्देश्य से अपनी अनिवार्य गतिविधियों को जारी रखा। इन गतिविधियों में अनुसंधान, प्रकाशन, चर्चाएँ और विदेश

नीति आउटरीच पहल शामिल थीं। आईसीडब्ल्यूए ने 87 अंक संक्षिप्त, 78 दृष्टिकोण और 17 विशेष रिपोर्टों के रूप में अपने शोध आउटपुट प्रकाशित किए। परिषद ने 4 सप्रू हाउस पेपर्स भी प्रकाशित किए जो विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर चयनित विषयों पर व्यापक भविष्योन्मुखी नीति शोध-पत्र हैं। आईसीडब्ल्यूए की पत्रिका 'इंडिया क्वार्टरली' अंग्रेजी और हिंदी दोनों में नियमित रूप से प्रकाशित की गई। इसने वैश्विक और क्षेत्रीय विकास, व्यापार, संस्कृति, सभ्यता, एसडीजी और ग्रे ज़ोन अभिशासन पर 16 पुस्तकें [9 एकल लेखक पुस्तकें, 5 संपादित पुस्तकें और 2 अनुवाद] प्रकाशित कीं। इसने 16 विशेष प्रकाशन और अतिथि स्तंभ भी प्रकाशित किए, जिनमें विभिन्न विषयों पर प्रख्यात विशेषज्ञों के शोधपत्र शामिल थे। इसने अपने प्रकाशनों का हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने का प्रयास जारी रखा।

आईसीडब्ल्यूए ने द्विपक्षीय संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के मुद्दों पर जानकारी दर्शकों के साथ चर्चा करने के लिए उन्हें एक मंच देने के उद्देश्य से विदेशी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा सप्रू हाउस व्याख्यान की मेजबानी की। वियतनाम और मलेशिया के प्रधानमंत्री, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष, आसियान के महासचिव और थाईलैंड के विदेश मामलों के उप मंत्री उन विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में शामिल थे जिन्होंने 2024 में सप्रू हाउस व्याख्यान दिए। परिषद ने 'भविष्य के संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन' पर एक 'कर्टन रेजर' सेमिनार का आयोजन किया, और समकालीन प्रासंगिकता और महत्व के विभिन्न विषयों पर केंद्रित कई पैनल चर्चाएँ कीं।

परिषद ने विभिन्न ट्रैक 2 और ट्रैक 1.5 संवाद, सेमिनार, सम्मेलन, पुस्तक चर्चाएँ आयोजित कीं। कुछ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय ट्रैक 2 संवाद ईरान, रूस, दक्षिण कोरिया और वियतनाम में आईसीडब्ल्यूए के समझौता-ज्ञापन भागीदारों के साथ आयोजित किए गए थे; और ट्रैक 1.5 संवाद जर्मनी में भागीदार के साथ आयोजित किया गया था।

परिषद ने कई विश्वविद्यालयों के साथ समझौता-ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए, जिसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रहे छात्रों को आईसीडब्ल्यूए में इंटर्नशिप करने का अवसर दिया जाता है। 2024 में, आईसीडब्ल्यूए ने 42 शोध प्रशिक्षुओं-16 सशुल्क प्रशिक्षु (6 महीने की अवधि) और 26 गैर-सशुल्क प्रशिक्षु (2 महीने की अवधि) के नामांकन के साथ अपने युवा जुड़ाव कार्यक्रमों के पैमाने और दायरे का विस्तार किया। इसने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में आईसीडब्ल्यूए संकाय द्वारा व्याख्यान भी आयोजित किए और छात्रों को आईसीडब्ल्यूए कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया।

1955 से कार्यरत, आईसीडब्ल्यूए पुस्तकालय, जिसे सप्रू हाउस पुस्तकालय के नाम से जाना जाता है, पिछले सात दशकों में भारतीय और विदेशी विद्वानों के लिए एक प्रमुख संसाधन केंद्र के रूप में उभरी है। विदेश नीति के विशिष्ट क्षेत्रों में शोध गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने और विद्वानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पुस्तकालय संग्रह में सामयिक महत्व की नई पुस्तकें जोड़ी गईं। हिंदी विद्वानों, छात्रों और पाठकों की सुविधा के लिए हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर अधिक पुस्तकें प्राप्त करने पर विशेष ध्यान दिया गया।

विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली (आरआईएस)

पीपीएंडआर विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली (आरआईएस) से संबंधित सभी मामलों के लिए नोडल प्रभाग है। आरआईएस एक स्वायत्त नीति अनुसंधान संस्थान है जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विकास, व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी से संबंधित मुद्दों में विशेषज्ञता रखता है। यह वैश्विक और क्षेत्रीय आर्थिक मुद्दों पर विकासशील देशों के बीच नीति संवाद और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देता है। इसका प्राथमिक ध्यान दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने और विभिन्न मंचों पर बहुपक्षीय वार्ता में विकासशील देशों के साथ सहयोग करने पर है।

आरआईएस में स्थित, ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (दक्षिण) ग्लोबल साउथ के देशों के लिए क्षमता निर्माण और स्थायी समाधान विकसित करने के लिए ज्ञान साझा करने और परस्पर अभिग्रहण को बढ़ावा देता है। दक्षिण ने कृषि, स्वास्थ्य और डिजिटल सार्वजनिक आधारभूत संरचना पर कई कार्यशालाओं का आयोजन किया है। इसने ग्लोबल साउथ के साझेदार थिंक टैंकों के साथ भी सहयोग किया है और उनके साथ कई संवादात्मक सत्र आयोजित किए हैं।

आरआईएस ने 11-13 जनवरी को नई दिल्ली में "ग्लोबल कॉन्क्लेव 2024: एडवांसिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इन ग्लोबल साउथ" शीर्षक से एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस प्रमुख सम्मेलन में लगभग 350 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों, विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं, विकास चिकित्सकों और अन्य हितधारकों ने भाग लिया।

27 फरवरी को आयुष मंत्रालय और आरआईएस ने भारतीय पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में अकादमिक सहयोग बढ़ाने और अनुसंधान, नीति संवाद और प्रकाशनों को सुविधाजनक बनाने के लिए एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

आरआईएस ने 7-8 नवंबर को सिंगापुर में आसियान-भारत थिंक टैंक नेटवर्क (एआईएनटीटी) के 8^{वें} गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। गोलमेज सम्मेलन का विषय था "परिवर्तनशील दुनिया में आगे बढ़ना: आसियान-भारत सहयोग का एजेंडा।" इस कार्यक्रम में भारत और आसियान सदस्य देशों के 100 से अधिक विद्वान, नीति निर्माता और विशेषज्ञ वैश्विक और क्षेत्रीय बदलावों के बीच आसियान-भारत संबंधों को बढ़ाने पर विचार-विमर्श करने के लिए एक साथ आए।

आरआईएस ने 20 नवंबर को टोक्यो में "भारत-जापान आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करना: बदलती वैश्विक व्यवस्था के संदर्भ में अवसर और चुनौतियाँ" शीर्षक से एक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का भी आयोजन किया। संगोष्ठी में 500 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

आरआईएस ने क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किए हैं जो दक्षिण-दक्षिण सहयोग का एक महत्वपूर्ण तरीका बन गए हैं। 2024 में, आरआईएस ने पड़ोसी देशों के प्रतिभागियों के लिए दो क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें शिक्षाविदों, विकास सहयोग के अभ्यासकर्ताओं, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व किया गया।

विदेश मंत्रालय की पुस्तकालय

मंत्रालय का पुस्तकालय मुख्यालय में विदेश मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ-साथ विदेशों में भारतीय मिशनो और पोस्टों के उपयोग के लिए एक संसाधन और सूचना केंद्र के रूप में कार्य करता है। यह पुस्तकालय वर्तमान में दिल्ली में पटियाला हाउस और जवाहरलाल नेहरू भवन (जेएनबी) में स्थित है। पुस्तकालय में एक लाख से अधिक पुस्तकें, समृद्ध संसाधन सामग्री और मानचित्रों, माइक्रोफिल्मों और आधिकारिक दस्तावेजों का एक बड़ा संग्रह है। यह नीति, योजना और अनुसंधान का समर्थन करने के लिए आधुनिक सुविधाओं से भी सुसज्जित है।

अध्याय

20

विधिक एवं संधि प्रभाग

विधिक एवं संधि प्रभाग मंत्रालय के विधिक मामलों की देखरेख करता है, तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के परिप्रेक्ष्य से सलाह देता है। वर्ष 2024 में, प्रभाग मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा समग्र रूप से संभाले बहिर्गमन प्रमुख मुद्दों पर सलाह देना जारी रखेगा, तथा अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं में भाग लेने के अलावा, अनेक द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संधियों की जाँच और अनुसमर्थन में सहायता करेगा।

संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ जुड़ाव

संयुक्त राष्ट्र

संयुक्त राष्ट्र महासभा की छठी समिति

संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) की छठी समिति, जिसे विधिक समिति के रूप में भी जाना जाता है, विधिक मामलों को संबोधित करने, अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास को बढ़ावा देने और विभिन्न विधिक प्रश्नों को हल करने के लिए समर्पित है। यह अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग की रिपोर्टों की समीक्षा करती है और महत्वपूर्ण विधिक मुद्दों पर सिफारिशें तैयार करती है, जिन्हें फिर विचार और कार्रवाई के लिए महासभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। ऐतिहासिक रूप से, एक सुसंगत और प्रगतिशील अंतर्राष्ट्रीय विधिक ढांचे

को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए समिति के काम की सराहना की गई है।

2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79^{वें} सत्र के दौरान, भारत ने छठी समिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संयुक्त राष्ट्र के विधिक निकायों में विकासशील देशों की बढ़ती भागीदारी की वकालत करके, भारत ने एक संतुलित और रचनात्मक दृष्टिकोण का प्रदर्शन किया, जिसमें समावेशिता और प्रतिनिधित्व पर जोर दिया गया। भारत ने मानवता के खिलाफ अपराधों पर चर्चा में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय और अपराधियों की जवाबदेही के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता को उजागर किया।

इसके अलावा, भारत की सक्रिय भागीदारी कई अन्य एजेंडा मदों तक भी फैली, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को खत्म करने के उपाय, आतंकवादी कृत्यों को रोकने और दबाने में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करना। अपनी भागीदारी के माध्यम से, भारत ने विधिक सिद्धांतों को बनाए रखने और न्याय सुनिश्चित करने के महत्व को रेखांकित किया, वैश्विक विधिक परिदृश्य को आकार देने में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में अपनी भूमिका का प्रदर्शन किया।

अंतर्राष्ट्रीय विधि सप्ताह

भारत, सह-आयोजकों में से एक के रूप में, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय विधि सप्ताह के दौरान 21-22 अक्टूबर को आयोजित विधिक सलाहकारों की 34^{वाँ} अनौपचारिक बैठक में शामिल हुआ। पैनल

चर्चा के लिए रखे गए विषयगत मुद्दों में अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग की 75^{वाँ} वर्षगांठ का स्मरणोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान और नौवहन की स्वतंत्रता की प्रासंगिकता शामिल थी। 23 अक्टूबर को, भारत ने द हेग अकादमी ऑफ इंटरनेशनल लॉ द्वारा आयोजित एक साइड-इवेंट का सह-प्रायोजन भी किया, जिसका विषय था, 'क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून एक बेबल का टॉवर है'।

यूएनसीआईटीआरएल

1966 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग (यूएनसीआईटीआरएल), संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक सहायक निकाय के रूप में कार्य करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून के लिए समर्पित संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर प्राथमिक विधिक इकाई के रूप में खड़ा है। यूएनसीआईटीआरएलका मुख्य लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने वाले नियमों का आधुनिकीकरण और सामंजस्य स्थापित करना है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिले।

अपनी स्थापना के बाद से, विधिक और संधि प्रभाग यूएनसीआईटीआरएलकार्य समूहों में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है, सत्रों में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इस वर्ष भी, प्रभाग ने अपनी निरंतर भागीदारी बनाए रखी, चयनित कार्य समूह गतिविधियों का बारीकी से पालन किया और मूल्यवान इनपुट प्रदान किए। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून को आकार देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और यूएनसीआईटीआरएलके भीतर इसकी प्रभावशाली भूमिका को उजागर करता है। 2024 में यूएनसीआईटीआरएल कार्य समूहों के नवीनतम विकास इस प्रकार हैं:

- कार्य समूह I (वेयरहाउस रसीदें): यह कार्य समूह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए वेयरहाउस रसीदों के लिए एक विधिकसंरचना विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। समूह का प्राथमिक उद्देश्य वेयरहाउस रसीदों से संबंधित कानूनों का आधुनिकीकरण और सामंजस्य स्थापित करना है, जिससे व्यवसायों के लिए इन रसीदों को वित्त-पोषण के लिए संपार्श्विक के रूप में उपयोग करना आसान हो जाता है।
- कार्य समूह II (विवाद निपटान) प्रौद्योगिकी से संबंधित विवाद समाधान और विशेष एक्सप्रेस विवाद समाधान के लिए मॉडल खंडों से संबंधित है।
- कार्य समूह III (निवेशक-राज्य विवाद निपटान सुधार) निवेशक-राज्य विवाद निपटान (आईएसडीएस) में सुधार करने पर काम करता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवादों को हल करने के लिए एक स्थायी तंत्र का विकास और आईएसडीएससुधार पर एक बहुपक्षीय साधन शामिल है।
- कार्य समूह IV (इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स) इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से संबंधित मुद्दों को संबोधित करता है, जिसमें स्वचालित अनुबंध और डेटा प्रावधान अनुबंधों के लिए डिफॉल्ट नियम शामिल हैं।

- कार्य समूह V (दिवालियापन कानून) दिवालियेपन कार्यवाही में सिविल संपत्ति का पता लगाने और वसूली तथा दिवालियेपन कार्यवाही में लागू कानून पर ध्यान केंद्रित करता है।
- कार्य समूह VI (परक्राम्य कार्गो दस्तावेज) परक्राम्य कार्गो दस्तावेजों पर एक साधन के लिए मसौदा प्रावधानों पर काम करता है, जो परक्राम्यता से संबंधित मसौदा लेखों पर ध्यान केंद्रित करता है।

समुद्री कानून

भारत ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मंचों में सक्रिय भागीदारी का प्रदर्शन किया। 15-17 मई को आयोजित संयुक्त राष्ट्र मछली स्टॉक समझौते (आईसीएसपी17) के राज्य दलों के अनौपचारिक परामर्श में भाग लेते हुए। भारत ने स्थायी मत्स्य प्रबंधन के लिए सहयोगी प्रयासों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। 10-14 जून को आयोजित संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन के राज्य दलों की 34^{वाँ} बैठक में भारत की सक्रिय भागीदारी को स्वीकार किया गया और उसकी सराहना की गई, जिसमें सम्मेलन के अंतर्गत भारतीय संस्थानों के सराहनीय कार्य पर प्रकाश डाला गया।

भारत की प्रतिबद्धता परिषद के 29^{वाँ} सत्र और अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण की विधानसभा बैठक तक विस्तारित हुई, जहाँ खनिज संसाधन दोहन के लिए मसौदा विनियमों पर चर्चा केंद्रित थी। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण की वित्त समिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए, भारत ने विधानसभा को प्रस्तुत समिति की रिपोर्ट तैयार करने में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसमें उत्तरदायी और संपोषणीय समुद्री संसाधन प्रबंधन पर जोर दिया गया। महासागरों और समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र की खुली अनौपचारिक परामर्श प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए, भारत ने 18-21 जून को अपनी 24^{वाँ} बैठक के दौरान "स्थायी भोजन के स्रोत के रूप में महासागर" पर चर्चा की।

भारत ने जून में समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के राष्ट्र पक्षों की 34^{वाँ} बैठक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संपूर्ण महासभा के तदर्थ कार्य समूह में भारत की भागीदारी, विशेष रूप से 20^{वाँ} और 21^{वाँ} बैठकों में, सामाजिक-आर्थिक पहलुओं सहित समुद्री पर्यावरण की स्थिति की वैश्विक रिपोर्टिंग और आकलन के लिए नियमित प्रक्रिया का जायजा लेने पर केंद्रित थी। इसके अलावा, भारत ने महासागरों और समुद्र के कानून पर अनौपचारिक परामर्श के दौरान पर्याप्त योगदान दिया, जिसमें इसका सर्वव्यापी संकल्प भी शामिल था।

सीओपी 29 वार्ता

भारत ने 11-24 नवंबर को बाकू, अजरबैजान में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के 29^{वाँ} सम्मेलन (सीओपी29) में भाग लिया। अन्य बातों के अलावा, जलवायु वित्त पर एक नए सामूहिक मातात्मक लक्ष्य (एनसीक्यूजी) पर एक बड़ा निर्णय अपनाया गया। इस निर्णय का उद्देश्य जलवायु कार्रवाई के लिए वित्त-पोषण में उल्लेखनीय वृद्धि करना है, यह सुनिश्चित करना कि जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित देशों के लिए वित्तीय संसाधन सुलभ हों।

इसके अतिरिक्त, प्रभाग ने पेरिस समझौते के अंतर्गत अनुकूलन, शमन, अनुपालन तंत्र, प्रतिक्रिया उपायों और पेरिस समझौते की प्रतिबद्धताओं के कार्यान्वयन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा में योगदान दिया।

वैज्ञानिक और तकनीकी सलाह के लिए सहायक निकाय

विधि और संधि प्रभाग ने 03-13 जून को बॉन, जर्मनी में आयोजित वैज्ञानिक और तकनीकी सलाह के लिए सहायक निकाय (एसबीएसटीए) के 60^{वें} सत्र में भाग लिया। सत्र में जलवायु परिवर्तन से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें वैश्विक स्टॉक-टेकिंग प्रक्रिया, अनुकूलन उपाय और पर्यावरण की दृष्टि से ध्वनि प्रौद्योगिकियों का विकास और हस्तांतरण शामिल है।

प्लास्टिक प्रदूषण पर अंतर्राष्ट्रीय विधिक रूप से बाध्यकारी साधन, जिसमें समुद्री पर्यावरण वार्ता भी शामिल है।

प्लास्टिक प्रदूषण पर अंतर-सरकारी वार्ता समिति (आईएनसी) की स्थापना मार्च 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (यूएनईए-5.2) में एक प्रस्ताव के बाद की गई थी, जिसका उद्देश्य समुद्री पर्यावरण सहित प्लास्टिक प्रदूषण पर एक विधिक रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय साधन विकसित करना था। आईएनसीने अपनी स्थापना के बाद से पाँच सत्र आयोजित किए हैं, जिसकी शुरुआत नवंबर 2022 में पुंटा डेल एस्ते, उरुग्वे में पहले सत्र से हुई, उसके बाद पेरिस, नैरोबी, ओटावा और हाल ही में नवंबर में बुसान, दक्षिण कोरिया में सत्र हुए।

भारत ने प्राथमिक प्लास्टिक पॉलिमर के उत्पादन को विनियमित करने का विरोध किया है, यह तर्क देते हुए कि ऐसे उपाय भारत के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। बुसान में 5^{वें} सत्र के दौरान, भारत ने इस बात पर जोर दिया कि साधन को पॉलिमर उत्पादन विनियमन तक विस्तारित किए बिना केवल प्लास्टिक प्रदूषण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भारत ने साधन के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए विकासशील देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता देने का भी आह्वान किया।

बाह्य अंतरिक्ष

विभाग ने 15-26 अप्रैल को वियना में बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर विधिक उप-समिति के 63^{वें} सत्र में भाग लिया। बैठक में बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण अन्वेषण और उपयोग से संबंधित विभिन्न विधिक प्रश्नों पर चर्चा की गई। विधिक उप-समिति के एजेंडे में निम्नलिखित विषय शामिल थे: बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण अन्वेषण और उपयोग से संबंधित राष्ट्रीय कानून; अंतरिक्ष कानून से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय अंतर-सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों की गतिविधियाँ; अंतरिक्ष मलबे के शमन और उपचार उपायों से संबंधित विधिक तंत्र; बाह्य अंतरिक्ष पर गैर-विधिक रूप से बाध्यकारी संयुक्त राष्ट्र के साधन; अंतरिक्ष यातायात प्रबंधन के विधिक पहलू; छोटे-उपग्रह गतिविधियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून का अनुप्रयोग; और अंतरिक्ष संसाधनों के अन्वेषण, दोहन और उपयोग में गतिविधियों के लिए संभावित विधिक मॉडल।

एशियाई-अफ्रीकी विधिक परामर्श संगठन (एएएलसीओ)

एशियाई-अफ्रीकी विधिक परामर्श संगठन (एएएलसीओ) एक अंतर-सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और जो अपने सदस्य देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र में एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है तथा आम चिंता के विधिक मामलों में एशियाई-अफ्रीकी सहयोग के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। भारत एएएलसीओके अधिदेश में सक्रिय रूप से योगदान देता है और 8-13 सितंबर को बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित एशियाई-अफ्रीकी विधिक परामर्श संगठन (एएएलसीओ) के 62^{वें} वार्षिक सत्र में भाग लिया।

भारत ने एएएलसीओके 60^{वें} वार्षिक सत्र की अध्यक्षता की, जिसमें अवर सचिव (एलएंडटी) अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। भारत की अध्यक्षता में संपर्क अधिकारियों की एक खुली उप-समिति ने एएएलसीओके वैधानिक नियमों की समीक्षा की और उन्हें संशोधित किया, जिसका अद्यतन संस्करण इस सत्र में अपनाया गया।

सामान्य वक्तव्य प्रस्तुत करने के अलावा, भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने विभिन्न एजेंडा विषयों पर वक्तव्य दिए, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग, समुद्र का कानून, साइबरस्पेस में अंतर्राष्ट्रीय कानून, बाह्य अंतरिक्ष में विधिक मुद्दे, परिसंपत्ति पुनर्प्राप्ति, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून और सतत विकास, तथा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद शामिल हैं। भारत की व्यापक भागीदारी ने एएएलसीओमंच पर चर्चा को आकार देने और वैश्विक दक्षिण एजेंडे को आगे बढ़ाने में इसकी सक्रिय भूमिका को रेखांकित किया।

प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ (एचसीसीएच) पर हेग सम्मेलन

वर्ष के दौरान, विधिक एवं संधि प्रभाग ने हेग कॉन्फ्रेंस ऑन प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ (एचसीसीएच) के साथ अपनी सक्रिय भागीदारी जारी रखी, जो एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसका कार्य निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों के क्रमिक एकीकरण का कार्य है। प्रभाग ने एचसीसीएचकी विभिन्न परियोजनाओं और पहलों में योगदान दिया, जिसमें सेवा और साक्ष्य सम्मेलनों, पेरेंटेज और अंतर्राष्ट्रीय सरोगेसी व्यवस्थाओं और निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत न्याय तक पहुँच जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

भारत ने पेरेंटेज/सरोगेसी पर कार्य समूह और सामान्य मामलों और नीति परिषद (सीजीएपी-2024) की बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लिया। इन भागीदारी का उद्देश्य विधिक पेरेंटेज पर एक नए अंतर्राष्ट्रीय साधन के विकास का समर्थन करना था, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सरोगेसी व्यवस्थाओं के परिणामस्वरूप पेरेंटेज शामिल है। कार्य समूह के प्रयास माता-पिता के अधिकारों की मान्यता, बच्चों और भावी माता-पिता के बीच विधिक संबंध और सरोगेट माताओं की भलाई की सुरक्षा के लिए स्पष्ट, सुसंगत नियम स्थापित करने पर केंद्रित हैं। इसके अतिरिक्त, प्रभाग एचसीसीएच की गतिविधियों का समन्वय करने वाला एक राष्ट्रीय अंग होने के नाते, 2-5 जुलाई को हेग में आयोजित सेवा सम्मेलन, साक्ष्य सम्मेलन और न्याय तक पहुँच सम्मेलनों पर विशेष आयोग में भाग लिया। इस आयोग ने देश के प्रोफाइल को अद्यतन और परिष्कृत करने और सेवा और साक्ष्य सम्मेलनों

के लिए पुस्तिकाओं को संशोधित करने पर ध्यान केंद्रित किया ताकि उनके आवेदन में अधिक स्पष्टता और स्थिरता को बढ़ावा दिया जा सके। इन प्रयासों का उद्देश्य अनुबंधित राज्यों के लिए परिचालन मार्गदर्शन को बढ़ाना और अधिक प्रभावी सीमा पार न्यायिक सहयोग सुनिश्चित करना है।

एचसीसीएच के महासचिव ने 24 अक्टूबर को भारत का दौरा किया और वरिष्ठ मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की और एचसीसीएच के साथ भारत के जुड़ाव को और गहरा करने के तरीकों और साधनों पर चर्चा की। इसके अलावा, इस बात पर भी चर्चा हुई कि भारत एचसीसीएच की ई-एपीपी परियोजना के अंतर्गत भारत में ई-एपोस्टिल्स के संभावित जारीकरण को किस प्रकार बढ़ावा दे सकता है और उसका समर्थन कर सकता है।

अंटार्कटिक संधि प्रणाली

अंटार्कटिक संधि प्रणाली में विधिक और संधि प्रभाग की भागीदारी अंटार्कटिका के द्वितीय पर्यावरण को संरक्षित करने और क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने पर केंद्रित थी।

विभाग ने 46^{वीं} अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक और कोच्चि, केरल में पर्यावरण संरक्षण समिति की 26^{वीं} बैठक में भाग लिया। इसमें *वसुधैव कुटुम्बकम्* की थीम के अंतर्गत शांति, वैज्ञानिक सहयोग और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया। मुख्य चर्चाओं में एक नए अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन, मैली-II की स्थापना, जलवायु परिवर्तन के निहितार्थ और एक पर्यटन ढांचे का विकास शामिल था।

अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून (आईएचएल) को आगे बढ़ाने वाली संगोष्ठी और कार्यक्रम

15 मई को, विधिक एवं संधि प्रभाग ने सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा पर एएलसीओ-आईसीआरसी वेबिनार में भाग लिया, जिसमें महत्वपूर्ण मानवीय चुनौतियों पर चर्चा की गई और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून पर व्यापक चर्चा में योगदान दिया गया।

इसके बाद 12 अगस्त को, जिनेवा कन्वेंशन की 75^{वीं} वर्षगांठ मनाने के लिए रेड क्रॉस (आईसीआरसी) क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में, एएस (एलएंडटी) ने '75^{वां} जिनेवा कन्वेंशन: मानवता की साझा विरासत' विषय पर विशेष भाषण दिया।

विभाग ने 28 से 31 अक्टूबर को जिनेवा में आयोजित 34^{वां} आईसीआरसी और रेड क्रॉस मूवमेंट में सक्रिय रूप से भाग लिया और सम्मेलन द्वारा आईएचएल पर अपनाए गए प्रस्ताव पर भारत के दृष्टिकोण से वार्ता में योगदान दिया,

आपराधिक मामलों और प्रत्यर्पण में पारस्परिक विधिक सहायता

विधिक और संधि प्रभाग आपराधिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता संधियों (एमएलएटी) और प्रत्यर्पण संधियों और अनुरोधों की जांच करता

है। एमएलएटी मामलों की देखरेख करने वाले केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में, गृह मंत्रालय ने विधिक जांच के लिए मसौदा संधियों के व्यापक पाठ प्रदान किए। ये मसौदे फिलीपींस, गुयाना, तुर्कमेनिस्तान, ब्रुनेई, लिथुआनिया, बोत्सवाना, नाइजीरिया और पेरू सहित कई देशों से संबंधित हैं।

इसके अतिरिक्त, विधिक और संधि प्रभाग ने भारत और कंबोडिया के बीच प्रत्यर्पण संधि वार्ता में भी भाग लिया और प्रत्यर्पण और एमएलएटी से संबंधित कई प्रश्नों की जांच की, जिसमें प्रत्यर्पण संधियों में "अस्वीकृति के आधार" से संबंधित प्रश्न भी शामिल थे। भारत और विदेशी देशों से उत्पन्न होने वाले कई नागरिक और आपराधिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता और प्रत्यर्पण अनुरोधों की विधिक और संधि प्रभाग में सावधानीपूर्वक जांच की गई और व्यापक विधिक राय प्रदान की गई।

सूचना प्रौद्योगिकी कानून

साइबर सुरक्षा/साइबर अपराध से संबंधित समझौता-ज्ञापनों/समझौतों की जांच के अलावा, विधिक एवं संधि प्रभाग ने संयुक्त राष्ट्र तदर्थ समिति (यूएन एएचसी) की वार्ता में भी भाग लिया, जिसका उद्देश्य "आपराधिक उद्देश्यों के लिए आईसीटी के उपयोग का प्रतिकार करने के लिए व्यापक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन" को विस्तृत करना था, जो संपन्न हुआ और 29 जुलाई से 9 अगस्त तक न्यूयॉर्क में आयोजित पुनः आयोजित सत्र के दौरान एएचसी द्वारा पाठ को अपनाया गया।

व्यापार और निवेश

आईपीईएफ वार्ता: मई 2022 में शुरू की गई समृद्धि के लिए भारत-प्रशांत आर्थिक रूपरेखा (आईपीईएफ), जिसमें भारत सहित 14 देश शामिल हैं, का उद्देश्य आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करना और भारत-प्रशांत क्षेत्र में 21^{वीं} सदी की आर्थिक चुनौतियों से निपटना है। रूपरेखा चार प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है: व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला, स्वच्छ अर्थव्यवस्था और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था, साथ ही व्यापक रूपरेखा समझौता। भारत व्यापार से संबंधित स्तंभ I को छोड़कर सभी समझौतों का हिस्सा है। विधिक और संधि प्रभाग ने आईपीईएफ समझौतों की चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लिया और विधिक जांच और हस्ताक्षर प्रक्रिया में भी शामिल रहा।

विधिक और संधि प्रभाग ने भारत और ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते की चर्चा में भाग लिया, जो भारत गणराज्य सरकार और ऑस्ट्रेलिया सरकार के बीच भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (इंडोस एक्टा) को प्रतिस्थापित करेगा। विधिक और संधि प्रभाग ने भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौते की चर्चा में भी भाग लिया। विधिक एवं संधि प्रभाग भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच व्यापार एवं आर्थिक भागीदारी समझौते (टीईपीए) के समापन में शामिल रहा। इस पर 10 मार्च को हस्ताक्षर किए गए। विधिक एवं संधि प्रभाग ने भारत और संयुक्त अरब अमीरात; कुवैत; यूके; सऊदी अरब और अन्य देशों के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि वार्ता में भाग लिया।

अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू विवाद निपटान

i. निवेश मध्यस्थता मामले

विधिक और संधि प्रभाग द्विपक्षीय निवेश संधियों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए भारत सरकार के खिलाफ दायर मध्यस्थता मामलों पर विभिन्न मंत्रालयों को सलाह प्रदान करता है।

ii. आईटीएलओएस के समक्ष जलवायु परिवर्तन मामला

समुद्र के कानून के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण (आईटीएलओएस) ने यूएनसीएलओएस के पक्षकारों और अन्य को “जलवायु परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय कानून पर छोटे द्वीप राज्यों के आयोग द्वारा प्रस्तुत सलाहकार राय के लिए अनुरोध” मामले में सलाहकार राय के लिए न्यायाधिकरण को प्रस्तुत प्रश्नों पर लिखित बयान प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया। प्रभाग ने लिखित बयान की तैयारी में सहायता की, और प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संयुक्त सचिव (एलएंडटी) ने किया, जिन्होंने समुद्री पारिस्थितिकी प्रणालियों पर जलवायु प्रभावों को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर जोर देते हुए भारत का पक्ष प्रस्तुत किया।

iii. जलवायु परिवर्तन पर आईसीजे का मामला

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संकल्प ए/आरईएस/77/276 के माध्यम से संदर्भित “जलवायु परिवर्तन के संबंध में राज्यों के दायित्व” पर सलाहकार राय में अपनी सुनवाई शुरू की। अनुरोध वानुअतु द्वारा शुरू किया गया था और कई देशों द्वारा समर्थित था। यह जलवायु प्रणाली की रक्षा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत राज्यों के दायित्व और ऐसा करने में विफल रहने वालों के परिणामों पर सलाहकार राय चाहता है। प्रभाग ने कार्यवाही में भाग लिया और तर्क दिया कि विकसित देश जो ऐतिहासिक रूप से मानवजनित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में सबसे बड़े योगदानकर्ता रहे हैं, उन्हें जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। भारत ने विकसित देशों द्वारा उत्सर्जन में कमी और जलवायु वित्त पर अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

iv. सिंधु जल संधि पर तटस्थ विशेषज्ञ

भारत और पाकिस्तान के बीच इस बात पर असहमति है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में स्थित किशनगंगा (2018 में पूरी हुई) और रतले (निर्माणाधीन) जलविद्युत परियोजनाओं की तकनीकी डिजाइन विशेषताएँ सिंधु जल संधि का उल्लंघन करती हैं या नहीं। भारत और पाकिस्तान के स्थायी आयुक्तों से मिलकर बने स्थायी सिंधु आयोग स्तर पर मतभेद के मुद्दे को सुलझाया नहीं जा सका। 13 अक्टूबर 2022 को, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आईबीआरडी) ने सिंधु जल संधि 1960 के अनुच्छेद IX और अनुलग्नक चके अनुसार, और प्रत्येक पक्ष के साथ परामर्श के बाद, श्री मिशेल लिनो को इन कार्यवाहियों (पीसीए द्वारा प्रशासित) में तटस्थ विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया।

अब तक, तटस्थ विशेषज्ञ ने दोनों परियोजनाओं के संबंध में पक्षों के साथ दो बैठकें और एक साइट का दौरा (पक्षों के साथ) किया है। विधिक और संधि प्रभाग ने इस मामले पर अपनी सलाह और विधिक सहायता प्रदान की।

v. घरेलू न्यायालय के मामले

विधिक एवं संधि प्रभाग की घरेलू न्यायालयों में मंत्रालय द्वारा या उसके विरुद्ध दायर मुकदमों में प्रमुख भूमिका होती है। मंत्रालय से जुड़े सभी न्यायालय मामलों के लिए नोडल बिंदु के रूप में, यह हलफनामों की गहन जांच और विभिन्न प्रभागों के विरुद्ध दायर याचिकाओं के जवाब तैयार करने सहित व्यापक विधिक सहायता प्रदान करता है। प्रभाग न्यायालय में मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाले पैनल अधिवक्ताओं के साथ भी संपर्क करता है, जिससे मंत्रालय से संबंधित मुद्दों पर विधिक प्रतिनिधित्व और सहायता सुनिश्चित होती है। पूरे वर्ष के दौरान, प्रभाग ने ऐसे कई मामलों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित किया और मंत्रालय के विधिक हितों की रक्षा की।

संधि अभ्यास और ऑनलाइन संधि डेटाबेस

विधिक और संधि प्रभाग भारत की ओर से संधियों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत की ओर से संधियों पर हस्ताक्षर करने के लिए, प्रभाग ने पूर्ण शक्ति के साधन जारी किए, जैसा कि **अनुलग्नक-I** में विस्तृत है। इसी तरह, हस्ताक्षरित द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संधियों का कार्यान्वयन अनुसमर्थन के साधन जारी करने के माध्यम से प्राप्त किया गया था, जो विधिक और संधि प्रभाग द्वारा संचालित एक प्रक्रिया है, जिसकी सूची **अनुलग्नक-II** में उपलब्ध है।

भारत की ओर से हस्ताक्षरित सभी संधियों के भंडार के रूप में अपनी क्षमता में, प्रभाग पहुंच और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। **अनुलग्नक-III** वर्ष के दौरान भारत द्वारा हस्ताक्षरित गैर-वर्गीकृत समझौतों/संधि की एक विस्तृत सूची प्रदान करता है। विधिक और संधि प्रभाग इन संधियों के पाठ को भारतीय संधि डेटाबेस में अनुक्रमित और अपलोड करके अपनी सेवा प्रदान करता है, जिसे लगातार अपडेट किया जाता है। यह व्यापक डेटाबेस, जिसे वेब लिंक <https://www.mea.gov.in/TreatyList.htm?1> के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, में 1950 से 2024 तक की संधियाँ, 4000 से अधिक समझौते शामिल हैं और यह जनता के लिए खुला है, जो पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्धता पर बल देता है और भारत की अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों में मूल्यवान ऐतिहासिक और समकालीन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

विधिक दस्तावेजों की जांच/सत्यापन

विधिक और संधि प्रभाग ने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय विधिक दस्तावेजों की जांच की है, जिसमें समझौता-ज्ञापन (एमओयू), संधियाँ/समझौते, साथ ही विभिन्न विषयों पर कैबिनेट नोट हैं, ये दस्तावेज कई क्षेत्रों में हैं, जो भारत की अंतरराष्ट्रीय भागीदारी की बहुमुखी प्रकृति को दर्शाते हैं। उल्लेखनीय श्रेणियों में संस्कृति, कार्मिक प्रबंधन, श्रमिकों का रोजगार और प्रत्यावर्तन,

जांच के क्षेत्र में सहायता, लाभकारी रोजगार, ज्ञान भागीदारी, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क, पेट्रोलियम अवसंरचना, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, निवेश और नवाचार संबंध, भ्रष्टाचार का प्रतिकार, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण, वित्तीय सेवाएं, कृषि और वन, चिकित्सा, द्विपक्षीय निवेश और नवाचार संबंध, हवाई सेवाएं, स्थानीय मुद्रा निपटान तंत्र, वर्गीकृत सूचनाओं की सुरक्षा, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां, अंतरिक्ष, सीमा पार व्यापार, प्रवासन गतिशीलता भागीदारी, ऑडियो-विजुअल सहयोग, ओजोन-क्षयकारी पदार्थ, पर्यटन, ट्विनिंग/सिस्टर सिटी समझौते, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा, सौर गठबंधन, विदेशी देशों में कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाएं और रक्षा सहयोग पर संधियां, समझौते, एमओयू आदि शामिल हैं। इस प्रकार, विधिक और संधि प्रभाग के काम ने विधिक और कूटनीतिक मुद्दों के व्यापक स्पेक्ट्रम को संबोधित करने, वैश्विक स्तर पर सहयोग और सहभागिता को सुविधाजनक बनाने में मदद की।

विधिक राय और विधिक शोध

इस वर्ष, प्रभाग ने ओजोन-क्षयकारी पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर विधिक राय प्रस्तुत की। इसकी विधिक राय स्थानीय कर्मचारी मामलों, अंतर-देशीय दत्तक-ग्रहण, बाल प्रत्यावर्तन, कोंसली, प्रतिरक्षा और विशेषाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार और मानवीय कानून मामलों, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कानून और विधिक सहायता के मामलों को शामिल करते हुए क्षेत्रों के व्यापक क्षेत्रों तक है। इसके अतिरिक्त, प्रभाग ने सजा पाए व्यक्तियों के स्थानांतरण, अंतरिक्ष और वायु कानून से लेकर अंतरिक्ष वस्तुओं की वापसी से जुड़े मामलों में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुप्रयोग तक के विषयों पर अंतर्दृष्टि प्रदान की है। उल्लेखनीय रूप से, प्रभाग ने पर्यावरण मामलों, सिंधु जल संधि के मुद्दों, अदालती मामलों, निविदा दस्तावेजों और भारत सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न अन्य विधिक साधनों को संबोधित करने में योगदान दिया है।

अध्याय

21

ई-अभिशासन और सूचना प्रौद्योगिकी (ईजीएंडआईटी)

ई-अभिशासन और सूचना प्रौद्योगिकी (ईजीएंडआईटी) प्रभाग मंत्रालय की विभिन्न ई-अभिशासन पहलों के डिजाइन, विकास, कार्यान्वयन और रखरखाव से जुड़ा हुआ है। प्रभाग मंत्रालय और विदेश स्थित मिशन/केंद्रों को सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) से संबंधित सभी मामलों में संपूर्ण सहायता भी प्रदान करता है, जैसे कि आईटी अवसंरचना की खरीद और रखरखाव।

जनवरी से दिसंबर की अवधि के दौरान, ईजीएंडआईटी प्रभाग ने मंत्रालय और विदेश स्थित सभी मिशन/केंद्रों में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन की दिशा में कई कदम उठाए हैं, ताकि एक पारदर्शी, सुरक्षित, सुलभ और सहभागी आईटी पारिस्थितिकी तंत्र बनाया जा सके। मंत्रालय में कामकाज के सभी स्तरों पर तालमेल हासिल करने और सरकारी अधिकारियों को कुशल आईटी सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वचालन और नेटवर्क का उपयोग उपकरण के रूप में किया जा रहा है।

वर्ष 2024 के दौरान ई-अभिशासन एवं आईटी प्रभाग द्वारा की जाने वाली प्रमुख पहलें इस प्रकार हैं:

(i) सरकारी पहलों की पहुंच और दक्षता में सुधार के लिए ई-अभिशासन समाधानों का उपयोग करने के व्यापक दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में, मंत्रालय के पोर्टलों की संख्या को सुव्यवस्थित और युक्तिसंगत बनाने की कवायद शुरू की गई है।

- विदेश मंत्रालय की ऑनलाइन कार्य प्रणाली (एमईएडीओडब्ल्यूएस) में कई नए उपयोगिता मॉड्यूल जोड़े गए हैं, जैसे इंटरनेट मॉड्यूल,

इंडक्शन कोऑर्डिनेशन अपडेशन मॉड्यूल और कर्मयोगी प्रमाणन पर मॉड्यूल।

- ग्लोबल एस्टेट मैनेजमेंट (जीईएम) प्रभाग के लिए एक इन-हाउस एप्लिकेशन डैशबोर्ड विकसित किया गया है, जो भारत के भीतर विदेश मंत्रालय की अन्य परियोजनाओं के अलावा विदेशों में हमारे मिशन/पोस्टों की परियोजनाओं/संपत्तियों का विवरण दर्शाता है।
- समन्वय प्रभाग की आवश्यकताओं के अनुसार ईजीएंडआईटी प्रभाग द्वारा आगंतुक आगंतुकों (सम्मेलन से संबंधित कार्यक्रम) के लिए ई-राजनीतिक मंजूरी के लिए एक अलग पोर्टल विकसित किया गया है।

(ii) प्रभाग ने समय-समय पर सरकारी अधिकारियों के लिए साइबर सुरक्षा और साइबर स्वच्छता के मूल सिद्धांतों पर कई व्याख्यान/सेमिनार आयोजित किए हैं, जिसका उद्देश्य मंत्रालय और विदेश में स्थित मिशन/केंद्रों के अधिकारियों के बीच साइबर सुरक्षा की आधारभूत अवधारणाओं के बारे में जागरूक करना है। इस संबंध में, हर महीने के पहले बुधवार को 'साइबर जागरूकता दिवस' मनाया जाता है। इसके अलावा, नए भर्ती किए गए अधिकारियों के प्रेरण प्रशिक्षण और पदोन्नति संबंधी प्रशिक्षण और विदेश में पोस्टिंग पर बहिर्गमन अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण में विशेष साइबर जागरूकता/स्वच्छता-सत्र शामिल किए जाते हैं।

अध्याय

22

कोंसली, पासपोर्ट और वीज़ा सेवाएँ

कोंसली, पासपोर्ट और वीज़ा (सीपीवी) प्रभाग भारत और विदेशों में भारतीय प्रवासियों सहित भारतीय नागरिकों और विदेशियों को कोंसली और वीज़ा सेवाएँ प्रदान करने वाला नोडल प्रभाग है।

कोंसली सेवाएँ

विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए कल्याणकारी उपायों के एक अभिन्न अंग के रूप में, हमारे मिशन और केंद्र विभिन्न कोंसली सेवाएँ प्रदान करते हैं, जिनमें दस्तावेजों का सत्यापन, विवाह का पंजीकरण और अनुष्ठान, तथा भारतीय नागरिकों के जन्म और मृत्यु का पंजीकरण शामिल है। इसके अतिरिक्त, वे मृतक भारतीयों के पार्थिव शरीर को ले जाने और भारतीय न्यायालयों से प्राप्त समन को विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों को तामील करने की सुविधा प्रदान करते हैं। विदेश में गिरफ्तार या कैद किए गए भारतीय नागरिकों के लिए, मिशन और केंद्र जेलों में उनसे मिलने और उनके कल्याण का पता लगाने के लिए कोंसली पहुँच प्रदान करते हैं। अधिकांश मिशन और केंद्र विभिन्न स्थानों पर नियमित रूप से ओपन हाउस और कोंसली कैप आयोजित करते हैं। इसके अलावा, खाड़ी देशों और मलेशिया में हमारे मिशन और केंद्रों में इन क्षेत्रों में भारतीय नागरिकों द्वारा सामना किए बहिर्गमन रोजगार संबंधी मुद्दों को संबोधित करने के लिए विशेष सामुदायिक कल्याण और श्रम शाखाएँ हैं।

भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों और भारत में विदेशी राजनयिक मिशनों के परामर्श से, सीपीवी प्रभाग भारत में विदेशी

नागरिकों के कोंसली मामलों को भी देखता है, जो मुख्य रूप से भारत में उनकी सुरक्षा और संरक्षा से संबंधित मुद्दों से संबंधित होते हैं।

कोंसली संवाद तंत्र

कोंसली संवाद तंत्र का उद्देश्य विदेशों में भारतीय प्रवासियों द्वारा सामना किए बहिर्गमन मुद्दों पर चर्चा करने और उन्हें हल करने के उद्देश्य से संबंधित कोंसली, वीज़ा और प्रवासी-संबंधी मामलों पर चर्चा करना है। भारत ने अब तक 33 से अधिक देशों के साथ द्विपक्षीय कोंसली संवाद तंत्र स्थापित किया है। 2024 के दौरान, बांग्लादेश, बेलारूस, इजराइल, इटली, नीदरलैंड, नाइजीरिया, फिलीपींस, पुर्तगाल, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात, यूके, यूएसए, यूक्रेन के साथ कोंसली संवाद/परामर्श आयोजित किए गए। बेलारूस, पुर्तगाल और नीदरलैंड के साथ बैठकें उद्घाटन संवाद थीं।

वीज़ा-छूट समझौते

भारत ने अब तक 135 देशों के साथ राजनयिक और आधिकारिक/सेवा पासपोर्ट धारकों के लिए 'वीज़ा छूट/छूट समझौते' पर हस्ताक्षर किए हैं। इस वर्ष, राजनयिक और/या आधिकारिक/सेवा पासपोर्ट धारकों के लिए वीज़ा छूट/छूट समझौते पर अंडोरा, माइक्रोनेशिया, टोगो, नाउरू और मोल्दोवा की सरकारों के साथ हस्ताक्षर किए गए और उन्हें लागू किया गया।

ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड योजना

मंत्रालय भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ) के भारत में उनकी जड़ों के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने, उन्हें देश की यात्रा करने, निवेश करने और गहरे संबंधों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य के अनुरूप, सीपीवी प्रभाग ने गृह मंत्रालय के साथ घनिष्ठ समन्वय में, ओसीआई कार्ड जारी करने को आसान बनाने के लिए काम किया है। ओसीआई सुविधा को 11 जुलाई को गुआडेलोप और मार्टिनिक के फ्रांसीसी कैरिबियन क्षेत्रों में भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ) और 20 नवंबर को गुयाना में 6^{वीं} पीढ़ी तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके अतिरिक्त, मॉरीशस में भारतीय मूल के पीआईओ के लिए सुविधा का विस्तार करके 7^{वीं} पीढ़ी तक कर दिया गया है।

ओसीआई कार्ड की शुरुआत के बाद से, 5.12 मिलियन से अधिक कार्ड जारी किए गए हैं, इस वर्ष कुल 316,211 कार्ड जारी किए गए हैं।

ई-वीजा योजना

ई-वीजा सुविधा, जिसने काफी लोकप्रियता हासिल की है, अब 172 देशों के नागरिकों के लिए उपलब्ध है, जिससे यात्रियों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए भारत की यात्रा करना अधिक सुविधाजनक हो गया है।

प्रत्यर्पण

विदेश मंत्रालय भारत में प्रत्यर्पण मामलों के लिए केंद्रीय प्राधिकरण है। मंत्रालय अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद, काला धनशोधन, वित्तीय धोखाधड़ी, मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य आपराधिक अपराधों में शामिल अभियुक्तों को वापस लाने के लिए विधिक ढांचे को व्यापक बनाने के लिए द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधियों के लिए विभिन्न देशों के साथ सक्रिय रूप से चर्चा कर रहा है। जहां कोई द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि/व्यवस्था नहीं है, वहां पारस्परिकता के आश्वासन पर प्रत्यर्पण अनुरोध भी किए जाते हैं।

भगोड़े अपराधियों के प्रत्यर्पण की सुविधा के लिए, वर्तमान में 48 प्रत्यर्पण संधियाँ लागू हैं। भारत ने 12 देशों के साथ प्रत्यर्पण व्यवस्था भी की है। मंत्रालय आपराधिक मामलों और नागरिक और वाणिज्यिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता पर समझौतों और सजायाप्राप्त व्यक्तियों के हस्तांतरण पर समझौतों के लिए चर्चा की सुविधा भी देता है। सीपीवी प्रभाग वर्तमान में 1947 से पहले की गई प्रत्यर्पण संधियों को बदलने के लिए संबंधित देशों के साथ चर्चा कर रहा है।

पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम

पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम (पीएसपी) प्रभाग भारत और विदेशों में पासपोर्ट से संबंधित सेवाएँ प्रदान करता है। पासपोर्ट जारी करना मंत्रालय द्वारा प्रदान

की जाने वाली सबसे प्रमुख वैधानिक और नागरिक-केंद्रित सेवाओं में से एक के रूप में उभरा है। एक आरामदायक व्यवस्था में समय पर, पारदर्शी, सुलभ और विश्वसनीय पासपोर्ट वितरण सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय ने सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं और एक समर्पित, प्रशिक्षित और प्रेरित कार्यबल के माध्यम से महत्वपूर्ण मात्रात्मक और गुणात्मक सुधार लागू किए हैं।

विदेश मंत्रालय द्वारा पीएसपीप्रभाग, केंद्रीय पासपोर्ट संगठन (सीपीओ), और इसके 37 पासपोर्ट कार्यालयों, सीपीवीप्रभाग (राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट) और अंडमान और निकोबार द्वीप प्रशासन के माध्यम से भारतीय पासपोर्ट (अन्य यात्रा दस्तावेजों जैसे कि राज्यविहीन व्यक्तियों के लिए पहचान प्रमाणपत्र, भारत लौटने वालों के लिए आपातकालीन प्रमाणपत्र, पुलिस निकासी प्रमाणपत्र, समर्पण प्रमाणपत्र और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा यात्रा परमिट) जारी किए गए थे।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में 93 पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके) हैं और डाक विभाग के सहयोग से 37 पासपोर्ट कार्यालयों की विस्तारित शाखा के रूप में 442 डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीओपीएसके) हैं। दिसंबर तक देश में कार्यरत पासपोर्ट सेवा केंद्रों की कुल संख्या 535 थी, जिसमें पीएसके और पीओपीएसके शामिल हैं। विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए, पासपोर्ट और आपातकालीन प्रमाणपत्र पीएसपी प्रणाली से जुड़े 194 भारतीय मिशन/पोस्टों के माध्यम से प्रदान किए जा रहे हैं।

पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम (पीएसपीसंस्करण 2.0)

आगामी पीएसपी V2.0 देश में नागरिकों और विदेशों में भारतीय मिशनों/पोस्टों के माध्यम से पासपोर्ट से संबंधित सेवाओं का लाभ उठाने वाले प्रवासी लोगों के लिए पासपोर्ट सेवाओं की आसानी को और बढ़ाएगा और बेहतर बनाएगा। सभी पासपोर्ट जारी करने वाले प्राधिकरणों, पीएसके/पीओपीएसके और अन्य हितधारकों (पुलिस, डाक विभाग और भारतीय प्रतिभूति मुद्राणालय नासिक) को कागज रहित और नकद रहित वातावरण में पासपोर्ट से संबंधित सेवाओं के एंड-टू-एंड प्रसंस्करण के लिए एक अत्याधुनिक सुरक्षित डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र से जोड़ा जाएगा।

अप्रैल में, पासपोर्ट संस्करण 2.0 को पायलट आधार पर आरपीओभुवनेश्वर और नागपुर में लॉन्च किया गया था। पीएसपी V2.0 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई)-सक्षम "बॉट" और रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन (आरपीए) द्वारा निर्देशित ऑनलाइन आवेदन दाखिल करने, दस्तावेज अपलोड करने, अपेक्षित शुल्क का भुगतान आदि के लिए एक इंटरैक्टिव पोर्टल प्रदान करता है। पीएसपी V2.0 नागरिक अनुभवों के अगले स्तर को प्रदान करने के लिए उन्नत, उच्च-स्तरीय और उदीयमान हुई तकनीकों का लाभ उठाएगा। पीएसपी V2.0 के अगले वर्ष लाइव होने की आशा है।

भारत में पासपोर्ट सेवाएँ और विदेश में मिशन/पोस्ट

पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम (पीएसपी), एक आईटी-संचालित मिशन-मोड परियोजना है, जिसने देश भर में नागरिकों को कुशल, सुरक्षित, उपयोगकर्ता-अनुकूल, पारदर्शी और जवाबदेह पासपोर्ट सेवाएँ सफलतापूर्वक प्रदान की

हैं। प्रौद्योगिकी के लाभ और फ्रंट ऑफिस संचालन की आउटसोर्सिंग ने बड़ी संख्या में नागरिकों को आसानी से और जल्दी से पासपोर्ट सेवाओं तक पहुँचने में सक्षम बनाया। 2010 में देश में केवल 55 लाख पासपोर्ट जारी किए गए थे, जबकि इस वर्ष जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या 1.30 करोड़ थी।

एम-पासपोर्टसेवामोबाइल ऐप

एम-पासपोर्टसेवा मोबाइल ऐप, पासपोर्ट सेवाओं के लिए आवेदन करने, भुगतान करने और नियोजित भेंटसमय निर्धारित करने की अतिरिक्त सुविधाओं के साथ, एंड्रॉयड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। पासपोर्ट सेवाओं के लिए आवेदन करने के लिए नागरिकों को कंप्यूटर और प्रिंटर तक पहुँच की आवश्यकता नहीं है। एमपासपोर्टसेवा ऐप अब पासपोर्ट सेवाओं के एक उन्नत सेट का समर्थन करता है, जैसे:

1. नया उपयोगकर्ता पंजीकरण
2. पंजीकृत उपयोगकर्ता खाते में साइन इन करें
3. पासपोर्ट और पुलिस अनापत्ति प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने के लिए आवेदन-पत्र दाखिल करना
4. पासपोर्ट सेवाओं के लिए भुगतान
5. नियोजित भेंटसमय-सारणी
6. आवेदन उपलब्धता स्थिति
7. दस्तावेज़ सलाहकार
8. शुल्क गणक

भारत में कहीं से भी आवेदन करना

अब कोई भी आवेदक भारत में कहीं से भी पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकता है। इस पहल से आवेदक पासपोर्ट कार्यालय (पीओ) और इस प्रकार, पीओ के अंतर्गत वांछित पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके)/डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीओपीएसके) चुन सकते हैं, जहां वे अपना आवेदन जमा करना चाहते हैं, भले ही आवेदन-पत्र में निर्दिष्ट वर्तमान आवासीय पता चयनित पीओ के अधिकार क्षेत्र में आता हो या नहीं। पुलिस सत्यापन उस पुलिस स्टेशन द्वारा किया जाएगा जिसके अधिकार क्षेत्र में फॉर्म में उल्लिखित पता आता है, और आवेदक द्वारा आवेदन जमा करने के लिए चुने गए पीओ द्वारा पासपोर्ट भी उसी पते पर मुद्रित और भेजा जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 30 नवंबर तक लगभग 25.2 लाख आवेदन जमा किए गए थे।

नियुक्तियाँ

मंत्रालय ने प्रतिदिन लगभग 85,000 नियुक्तियाँ जारी कीं, जिनमें 442 पीओपीएसके पर लगभग 23,000 नियुक्तियाँ शामिल हैं। पीएसके पर पासपोर्ट आवेदन जमा करने के लिए ऑनलाइन नियुक्तियाँ प्राप्त करना सरल बना दिया गया है। वर्तमान प्रावधान आवेदकों को पासपोर्ट संबंधी

सेवाओं के लिए नियुक्ति निर्धारित करने/पुनर्निर्धारित करने के लिए सबसे पहले उपलब्ध पाँच तिथियों (कार्य दिवसों) में से कोई भी नियुक्ति तिथि चुनने की अनुमति देता है। इसने पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को आसान और तेज़ बना दिया है।

पासपोर्ट सेवाओं की पहुँच

सरकार का उद्देश्य पासपोर्ट की बढ़ती माँग को पूरा करना और पासपोर्ट कार्यालयों से दूर रहने वाले लोगों तक पहुँचना है।

क. पासपोर्ट कार्यालय

(अनुलग्नक: भारत में 37 पासपोर्ट कार्यालयों की सूची अनुलग्नक-V में है)

ख. पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके)

दिसंबर 2024 तक देश में 93 पीएसके कार्यरत हैं। (अनुलग्नक-VI)

ग. डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीओपीएसके)

मंत्रालय ने डाक विभाग (डीओपी) के सहयोग से 24 जनवरी 2017 को देश के मुख्य डाकघरों (एचपीओ)/डाकघरों (पीओ) में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने के लिए एक अभिनव पहल की घोषणा की, जिसे 'डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र' (पीओपीएसके) कहा जाता है। मंत्रालय ने आज तक 442 पीओपीएसके क्रियाशील किए हैं, जिनमें वर्ष के दौरान 08 नए पीओपीएसके स्थापित किए गए हैं। (अनुलग्नक-VII)

आवेदक, जो पासपोर्ट पोर्टल के माध्यम से अपने पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं, वे नियोजित भेंटसमय निर्धारित कर सकते हैं और फिर पासपोर्ट जारी करने से पहले आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए नामित पीओपीएसके पर जा सकते हैं।

घ. विदेश स्थित भारतीय मिशन/पोस्टों का पीएसपी में एकीकरण

विदेश स्थित भारतीय मिशन/पोस्टों को पीएसपी में एकीकृत करने की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है जो अक्टूबर 2018 में शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य विदेश में रहने वाले और पासपोर्ट से संबंधित सेवाओं की मांग करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एकल केंद्रीकृत डेटाबेस पर काम करने वाली एक समान केंद्रीकृत पासपोर्ट जारी करने की आवेदन प्रक्रिया प्रदान करना है। मंत्रालय ने 194 भारतीय मिशन/पोस्टों में पासपोर्ट जारी करने की प्रणालियों को वैश्विक पीएसपी (जीपीएसपी) प्रणाली में सफलतापूर्वक एकीकृत किया है। मंत्रालय यथाशीघ्र विदेश स्थित सभी भारतीय मिशन/पोस्टों के एकीकरण को पूरा करने के लिए काम कर रहा है।

प्रक्रियाओं का सरलीकरण

मंत्रालय ने पासपोर्ट प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कदम उठाए हैं। इसमें पासपोर्ट नियमों का सरलीकरण और पासपोर्ट संबंधी सेवाएं प्रदान करने में लोगों तक पहुँच शामिल है।

1. अंतर्देशीय गोद लिए गए बच्चों को पासपोर्ट जारी करना

गोद लिए गए बच्चों को पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए मंत्रालय ने केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (सीएआरए) के साथ इस मामले को आगे बढ़ाया। तदनुसार, भारत और विदेश में सभी पासपोर्ट जारी करने वाले प्राधिकरणों को गोद लिए गए बच्चों को पासपोर्ट जारी करने के लिए आवश्यक संशोधित दस्तावेजों को निर्धारित करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

2. गोवा मूल के भारतीय नागरिकों द्वारा पासपोर्ट का समर्पण।

पुर्तगाली राष्ट्रीयता प्राप्त करने के बाद भारतीय पासपोर्ट प्राप्त करने वाले गोवा मूल के विदेशी नागरिकों को भारतीय पासपोर्ट के समर्पण प्रमाणपत्र के बदले में निरस्तीकरण आदेश जारी करने के बारे में संदर्भ प्राप्त हुए थे। गृह मंत्रालय के परामर्श से इस मुद्दे की जाँच की गई। उचित विचार-विमर्श के बाद, भारत सरकार ने ऐसे पूर्व भारतीय नागरिकों को ओसीआईके लिए जारी किए गए निरस्तीकरण आदेश को स्वीकार करने का निर्णय लिया।

3. हज यात्रियों को पासपोर्ट जारी करने में प्राथमिकता

हज-2025 पर जाने के इच्छुक तीर्थयात्रियों के पासपोर्ट आवेदनों के प्रसंस्करण में तेजी लाने के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अनुरोध के जवाब में, मंत्रालय ने सभी पासपोर्ट जारी करने वाले प्राधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हज यात्रियों के लिए पासपोर्ट समय पर जारी करने को उच्च प्राथमिकता दें।

ई-पासपोर्ट

ई-पासपोर्ट एक संयुक्त कागज़ और इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट है जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप और इनले के रूप में एक एंटीना लगा होता है। ई-पासपोर्ट का मुख्य लाभ इसके डेटा की अखंडता को बनाए रखने की इसकी बढ़ी हुई क्षमता है, जिससे भारतीय पासपोर्ट में विश्वास का स्तर बढ़ता है। ई-पासपोर्ट भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा को आसान बनाता है, जिससे आब्रजन अधिकारियों के साथ उनका इंटरफ़ेस आसान हो जाता है।

ई-पासपोर्ट परियोजना में एक जटिल तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना शामिल थी, जिसमें सार्वजनिक कुंजी अवसंरचना (पीकेआई), कुंजी प्रबंधन प्रणाली (केएमएस), इंटर-ऑपरेबिलिटी टेस्ट बेड, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पीएमयू), ई-पर्सनलाइजेशन, साथ ही आब्रजन ब्यूरो द्वारा आब्रजन चेक पॉइंट्स पर ई-पासपोर्ट सत्यापन सेटअप का निर्माण शामिल था।

वर्तमान में, भुवनेश्वर और नागपुर स्थित पासपोर्ट कार्यालय 01 अप्रैल से नागरिकों को ई-पासपोर्ट जारी कर रहे हैं। 31 दिसंबर तक कुल लगभग 1,08,125 ई-पासपोर्ट जारी किए जा चुके हैं।

यात्रा दस्तावेजों का सृजन और निजीकरण

भारतीय यात्रा दस्तावेजों का सृजन भारतीय प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक द्वारा किया जाता है, जो भारत प्रतिभूति मुद्रणतथा मुद्रण निर्माण निगम

लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल) के अंतर्गत एक इकाई है। भारत में सभी क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों और विदेशों में चुनिंदा मिशनो/पोस्टों को मशीन-पठनीय पासपोर्ट प्रिंटर प्रदान किए गए हैं। सभी पासपोर्ट जारी करने वाले प्राधिकरण अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ) द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार मशीन-पठनीय पासपोर्ट (एमआरपी) जारी करते हैं।

25 भारतीय मिशनो/केंद्रों पर पासपोर्ट/ओसीआई का मुद्रण स्थानीय स्तर पर किया जाता है। विदेशों में स्थित अधिकांश भारतीय मिशनो/केंद्रों (जहां पासपोर्ट छपाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है) के लिए, मशीन-पठनीय पासपोर्ट और ओसीआई मंत्रालय के पीएसपी प्रभाग, नई दिल्ली के केंद्रीय भारतीय पासपोर्ट मुद्रण प्रणाली (सीआईपीपीएस) में मुद्रित किए जाते हैं।

पहचान प्रमाणपत्र (सीओआई)

पासपोर्ट अधिनियम 1967 में भारत में रहने वाले राज्यविहीन व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से सीओआई जारी करने का प्रावधान है। वर्ष के दौरान कुल 2,521 सीओआई जारी किए गए।

पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 11 के अंतर्गत अपील

पासपोर्ट अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत, पासपोर्ट जारी करने वाले अधिकारियों (पीआईए) के निर्णय के खिलाफ अपील करना प्रभावित व्यक्तियों को दिया गया एक वैधानिक अधिकार है। संयुक्त सचिव (पीएसपी) और मुख्य पासपोर्ट अधिकारी ऐसे मामलों के लिए अपीलीय प्राधिकारी हैं। वर्ष के दौरान, 92 अपीलों पर सुनवाई की गई और उनका निपटारा किया गया।

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों का निरीक्षण

पीएसपी प्रभाग विदेश मामलों की स्थायी समिति के अध्ययन दौरों तथा क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों में राजभाषा के प्रगतिशील प्रयोग पर संसद की राजभाषा संबंधी प्रथम उप-समिति द्वारा क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों के निरीक्षण का समन्वय करता है।

वर्ष के दौरान, संसद की राजभाषा संबंधी प्रथम उप-समिति ने अहमदाबाद (18 अक्टूबर) तथा बरेली (20 नवंबर) में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों का निरीक्षण किया।

2024 क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी सम्मेलन 2024

मंत्रालय द्वारा 22-24 जून को नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी सम्मेलन आयोजित किया गया। सभी 37 क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों और पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम (पीएसपी) के हितधारकों ने पासपोर्ट जारी करने की

प्रणाली के कामकाज, इसकी उपलब्धियों, चुनौतियों और भारत के नागरिकों के लिए प्रक्रिया को सुचारू और अधिक प्रभावी बनाने के लिए भविष्य की पहलों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया।

अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ)

फरवरी 2009 से, भारत आईसीएओके 'ई-पासपोर्ट पर सार्वजनिक कुंजी निर्देशिका (पीकेडी)' का सहभागी सदस्य रहा है, जो मशीन-पठनीय यात्रा दस्तावेजों पर दिशानिर्देशों को लागू कर रहा है। भारत ने नीचे उल्लिखित बैठकों में भाग लिया:

- (क) 16-17 सितंबर को आयोजित यात्री पहचान कार्यक्रम (टीएजी/टीआरआईपी) पर तकनीकी सलाहकार समूह की बैठक और 18-20 सितंबर को कोपेनहेगन, डेनमार्क में आयोजित नई प्रौद्योगिकी कार्य समूह (एनटीडब्ल्यूजी) की बैठक।
- (ख) 31^{वाँ} आईसीएओपीकेडीबोर्ड कार्यशाला और बैठक 24-26 सितंबर को शीआन, चीन में आयोजित की गई।
- (ग) 15-18 अक्टूबर के दौरान सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में 39794-5 एप्लीकेशन प्रोफाइल इंटरऑपरेबिलिटी परीक्षण।

लोक शिकायत निवारण तंत्र

पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत, मंत्रालय ने एक सुदृढ़ शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित की है, जिसके तहत एक बहुभाषी राष्ट्रीय कॉल सेंटर, जिसका टोल-फ्री नंबर (1800-258-1800) है, 17 भाषाओं में और 24 x 7 आधार पर संचालित होता है, शिकायतों से निपटने और नागरिकों की प्रतिक्रिया सहित विभिन्न पासपोर्ट-संबंधी सेवाओं के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए स्थापित किया गया है। पासपोर्ट पोर्टल में एक ईमेल-

आधारित हेल्पडेस्क भी है, जहाँ सुझाव और शिकायतें पोस्ट की जा सकती हैं। नागरिक इस पोर्टल के माध्यम से अपने पासपोर्ट आवेदन/शिकायतों की स्थिति की ऑनलाइन निगरानी भी कर सकते हैं।

संयुक्त सचिव (पीएसपी) और सीपीओ की देखरेख में पीएसपी प्रभाग में एक लोक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (पीजीआरसी) स्थापित किया गया है, जिन्हें केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) के लिए मंत्रालय के लोक शिकायत के प्रभारी अधिकारी के रूप में भी नामित किया गया है। यह आम जनता से सीधे टेलीफोन, ई-मेल और डाक के माध्यम से प्राप्त शिकायतों और विभिन्न सरकारी कार्यालयों जैसे राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय और केंद्रीय सतर्कता आयोग आदि से प्राप्त संदर्भों से निपटता है। लोक शिकायत अधिकारी के नाम और संपर्क विवरण भी आरपीओ/पीएसके और आरपीओ की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाते हैं।

जनवरी-नवंबर की अवधि के दौरान सीपीजीआरएएमएस में 17,865 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 17096 शिकायतों, अर्थात् 95% का निपटारा किया गया।

केंद्रीय पासपोर्ट संगठन

केंद्रीय पासपोर्ट संगठन (सीपीओ) की स्थापना 1959 में मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में की गई थी और इसका नेतृत्व संयुक्त सचिव और मुख्य पासपोर्ट अधिकारी करते हैं, जो पासपोर्ट अधिनियम 1967 के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी के रूप में भी कार्य करते हैं।

सीपीओ कैडर के कर्मचारी देश भर में 37 पासपोर्ट कार्यालयों, 93 पीएसके और 442 पीओपीएसके में तैनात हैं। 01 दिसंबर तक, सीपीओ की स्वीकृत संख्या 2,737 है और कार्यरत संख्या 1,747 है।

अध्याय

23

उत्प्रवास नीति, कल्याण और प्रवासी जुड़ाव

उत्प्रवास नीति और कल्याण प्रभाग

हाल के दिनों में, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रवास गतिशीलता में एक अग्रणी देश है और अपनी जनसांख्यिकीय क्षमता के साथ लाभप्रद रूप से तैयार है। 2030 तक, भारत की कार्यशील आबादी 68.9% पर चरम पर पहुंचने वाली है, जो 1.04 बिलियन लोगों तक पहुंच जाएगी। वर्तमान में, भारत का प्रवासी समुदाय 35 मिलियन से अधिक है और यह वर्ष 2023 में 120 बिलियन अमरीकी डॉलर के बराबर धन प्रेषण के साथ दुनिया में शीर्ष प्रेषण प्राप्त करने वाला देश है। उनकी क्षमता को पहचानते हुए, भारत सरकार श्रमिकों, पेशेवरों और विदेश यात्रा करने वाले नागरिकों की अन्य श्रेणियों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवास को बढ़ावा देने के लिए काम करती है।

गतिशीलता व्यवस्था

प्रवास नीति एवं कल्याण प्रभाग भारतीय श्रमिकों, छात्रों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, व्यवसायियों आदि की वैश्विक गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए संस्थागत तंत्र स्थापित करने की दिशा में काम कर रहा है। मंत्रालय विभिन्न समझौता-ज्ञापनों/समझौतों जैसे कि प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी (एमएमपीए), तथा भागीदार गंतव्य देशों के साथ श्रम गतिशीलता और श्रम कल्याण के माध्यम से भारतीय कार्यबल के लिए गतिशीलता को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है। इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य

विधिक प्रवास के लिए एक सुदृढसंरचना स्थापित करना है। ये समझौते/समझौता-ज्ञापन लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देते हैं, वीजा प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करते हैं, अनियमित प्रवासन को रोकते हैं, द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ करते हैं और कौशल विकास का समर्थन करते हैं। वर्ष के दौरान, डेनमार्क के साथ एमएमपीए पर हस्ताक्षर किए गए तथा ताइवान और मलेशिया के साथ श्रम गतिशीलता समझौते (एलएमए) पर हस्ताक्षर किए गए।

चालू वर्ष के दौरान विभिन्न देशों के साथ हस्ताक्षरित प्रवासन और गतिशीलता/श्रम गतिशीलता समझौतों से संबंधित प्रमुख घटनाक्रम इस प्रकार हैं:

डेनमार्क

भारत और डेनमार्क ने 22 फरवरी को नई दिल्ली में गतिशीलता और प्रवास साझेदारी पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। एमएमपीए पर विदेश मंत्री और डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन ने हस्ताक्षर किए। यह समझौता लोगों के बीच संपर्क और व्यवसायियों, छात्रों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, पेशेवरों, कुशल और स्वरोजगार वाले श्रमिकों की गतिशीलता को बढ़ाने में एक प्रमुख मील का पत्थर है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच अनियमित प्रवास और मानव तस्करी से संबंधित मुद्दों पर सहयोग को सुदृढ करना है।



विदेश मंत्री और मलेशिया के विदेश मंत्री मोहम्मद बिन हसन ने अगस्त 2024 में नई दिल्ली में भारत और मलेशिया के बीच श्रमिकों की भर्ती, रोजगार और प्रत्यावर्तन पर समझौता-ज्ञापन का आदान-प्रदान किया।

इजराइल

भारत और इजराइल के बीच इजराइल के विशिष्ट श्रम बाजार क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों के अस्थायी रोजगार की सुविधा पर समझौता 04 जनवरी से प्रभावी हो गया है।

मलेशिया

भारत और मलेशिया के बीच श्रमिकों की भर्ती, रोजगार और प्रत्यावर्तन पर समझौता-ज्ञापन पर मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की 20 अगस्त को भारत यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए।

ताइवान

ताइवान में भारतीय श्रमिकों के रोजगार की सुविधा पर भारत ताइपे एसोसिएशन (आईटीए) और ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र (टीईसीसी) के बीच समझौता-ज्ञापन पर 16 फरवरी को वीडियो-कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से हस्ताक्षर किए गए, जिसके साक्षी सचिव (सीपीवी और ओआईए) थे।

यू.के.

भारत-यू.के. एम.एम.पी.ए. के अंतर्गत वर्ष 2024 के लिए युवा पेशेवर योजना (वाई.पी.एस.) को लॉन्च करने के लिए 20 फरवरी को अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई, तमिलनाडु में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस योजना को भारत में यू.के. के तत्कालीन उच्चायुक्त द्वारा तमिलनाडु

सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री की उपस्थिति में लॉन्च किया गया था। इस योजना के लिए मतदान/लॉटरी 20-22 फरवरी तक 48 घंटों के लिए खुली थी, जिसमें 3000 स्लॉट उपलब्ध थे। यह योजना 18 से 30 वर्ष की आयु के भारतीय नागरिकों को यू.के. में 2 वर्ष तक रहने और काम करने की अनुमति देती है। मतदान में 3 लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया।

मोल्दोवा

मोल्दोवा के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री की भारत यात्रा के दौरान, 15 दिसंबर को भारत और मोल्दोवा के बीच प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी पर आशय की घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए। हस्ताक्षर के समय विदेश मंत्री मौजूद थे और घोषणा में प्रवासन और गतिशीलता के क्षेत्र में समझ और सहयोग का एक साझा संरचना स्थापित करने और छात्रों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, पेशेवरों और व्यापारियों की गतिशीलता और उनकी वापसी को सुविधाजनक बनाने की परिकल्पना की गई है। घोषणा का उद्देश्य अवैध प्रवासन, मानव तस्करी और मानव तस्करी को रोकने के लिए एक संरचना स्थापित करना भी है।

इसके अलावा, क्रोएशिया, फिनलैंड, ग्रीस, गुयाना, रूस और स्विट्जरलैंड के साथ इसी तरह के समझौतों के संबंध में चर्चा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

एमएमपीए/एलएमए के अंतर्गत विभिन्न देशों के साथ संयुक्त कार्य समूह की बैठकें:

भारत-ब्रिटेन

भारत सरकार के विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों सहित उत्प्रवास नीति एवं कल्याण प्रभाग के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 24-25 अप्रैल को लंदन में आयोजित प्रवासन एवं गतिशीलता भागीदारी पर भारत-ब्रिटेन समझौता-ज्ञापन के अंतर्गत तीसरी भारत-ब्रिटेन संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) बैठक में भाग लिया। जेडब्ल्यूजी बैठक में अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया, जिसमें व्यक्तियों के आवागमन पर समझौता-ज्ञापन का कार्यान्वयन, राजनयिक वीजा छूट समझौता, विधिक प्रवासन एवं गतिशीलता को बढ़ावा देना, भारतीय सरकारी पोर्टलों पर रोजगार के अवसरों की जानकारी का प्रसार, तथा अवैध प्रवासन की रोकथाम एवं उससे निपटने से संबंधित सहयोग शामिल हैं।

भारत-इटली

भारत और इटली के बीच एमएमपीएके अंतर्गत पहली जेडब्ल्यूजीबैठक 27 जून को रोम में आयोजित की गई थी। जेडब्ल्यूजीके बाद, मंत्रालय इटली के भावी विदेशी नियोक्ताओं को ई-मिग्रटपोर्टल पर पंजीकृत करने के लिए मिलकर काम कर रहा है, ताकि फ्लो डिफ्री के अंतर्गत इटली द्वारा आवंटित कोटा के अनुसार मौसमी और गैर-मौसमी श्रमिकों की भर्ती शुरू की जा सके। वर्ष 2023, 2024 और 2025 के लिए मौसमी श्रमिकों के लिए कोटा क्रमशः 3000, 4000 और 5000 है, जबकि इसी अवधि के लिए गैर-मौसमी श्रमिकों के लिए कोटा क्रमशः 5000, 6000 और 7000 है।

भारत-ताइवान

भारत-ताइवान श्रम सहयोग कार्य-स्तरीय पहली बैठक 05-07 नवंबर को ताइपेई, ताइवान में आयोजित की गई, जिसमें ताइवान में भारतीय श्रमिकों के रोजगार की सुविधा पर हाल ही में हस्ताक्षरित समझौता-ज्ञापन के कार्यान्वयन पर चर्चा की गई।

अंतर्राष्ट्रीय/बहुपक्षीय संगठनों के साथ सहयोग

प्रवासन और गतिशीलता तथा श्रम प्रवास पर द्विपक्षीय व्यवस्थाओं के अलावा, ईपीएंडब्ल्यू प्रभाग सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवास मार्गों को बढ़ावा देने में भारत की पहलों के क्षितिज को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय और बहुपक्षीय संगठनों के साथ जुड़ता है।

अबू धाबी वार्ता (एडीडी) का 7^{वां} मंत्रिस्तरीय परामर्श

एडीडी का 7^{वां} मंत्रिस्तरीय परामर्श 10-11 फरवरी को दुबई में आयोजित किया गया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सचिव (सीपीवी और ओआईए) ने किया और उनके साथ विदेश मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के अधिकारी भी थे। एडीडी 2008 से चालू है और यह श्रम मूल के 11 एशियाई देशों और 7 गंतव्य देशों के

बीच एक क्षेत्रीय, स्वैच्छिक और गैर-बाध्यकारी परामर्श प्रक्रिया के रूप में कार्य करता है। यह संविदात्मक श्रम गतिशीलता, सर्वोत्तम अनुभवों को साझा करने और एक-दूसरे के अनुभव से सीखने पर क्षेत्रीय सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। अबू धाबी वार्ता के दौरान, सचिव (सीपीवी और ओआईए) ने संयुक्त अरब अमीरात के मानव संसाधन और अमीरातीकरण मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय प्रवासी श्रमिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए दोनों सरकारों द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों पर चर्चा की गई।

अबू धाबी वार्ता (एडीडी) सलाहकार समिति 2024-2026

अबू धाबी स्थित एडीडीसचिवालय के निमंत्रण पर, भारत ओमान की अध्यक्षता में 2024-26 की अवधि के लिए एडीडीकी सलाहकार समिति में शामिल हुआ। 01 अक्टूबर को आयोजित एडीडीकी सलाहकार समिति की वर्चुअल बैठक में संयुक्त सचिव (ईपीएंडब्ल्यू) ने भाग लिया।

बुडापेस्ट प्रक्रिया

07-08 मई को, ईपीएंडब्ल्यू प्रभाग के प्रतिनिधियों ने इस्तांबुल, तुर्की में बुडापेस्ट प्रक्रिया के अंतर्गत प्रवास के लिए विधिक मार्गों पर विषयगत कार्य समूह की बैठक में भाग लिया। बैठक में 27 यूरोपीय देशों और यूरोपीय आयोग, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ), अंतर्राष्ट्रीय प्रवास संगठन (आईओएम), प्रवास नीति संस्थान, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी), यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन (ओएससीई), अंतर्राष्ट्रीय प्रवास नीति विकास केंद्र (आईसीएमपीडी) और बुडापेस्ट प्रक्रिया सचिवालय के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बुडापेस्ट प्रक्रिया वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक (एसओएम) 27 जून को स्टॉकहोम में आयोजित की गई और इसमें स्टॉकहोम में भारतीय दूतावास के एक प्रतिनिधि ने भाग लिया। यह बैठक बुडापेस्ट प्रक्रिया के 7^{वां} मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के मद्देनजर वरिष्ठ अधिकारी स्तर पर दूसरी तैयारी बैठक के रूप में कार्य करती है। एसओएमके दौरान, मंत्रिस्तरीय पाठ के दोनों मसौदों (अर्थात मसौदा मंत्रिस्तरीय घोषणा और कार्य योजना) की समीक्षा की गई। बुडापेस्ट प्रक्रिया का 7^{वां} मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 12 नवंबर को बुडापेस्ट, हंगरी में आयोजित किया गया। इस बैठक में बुडापेस्ट में हमारे मिशन ने भाग लिया।

प्रवासन पर अंतर्राष्ट्रीय संवाद (आईडीएम)

आईडीएम का पहला सत्र 21-22 मई को न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया। आईडीएम आईओएम सदस्यों और पर्यवेक्षकों राज्यों, अंतर्राष्ट्रीय और गैर-सरकारी संगठनों, निजी क्षेत्रों और अन्य भागीदारों के लिए दुनिया भर में प्रवासन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक खुला मंच है। इस संवाद में सचिव (सीपीवी और ओआईए) ने भाग लिया।

कोलंबो प्रक्रिया (सीपी)

भारत ने 29 मई को अपनी स्थापना के बाद पहली बार 2024-26 के लिए सीपी की अध्यक्षता संभाली। सीपी दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के प्रवासी श्रमिक मूल देशों की एक क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया है। यह विदेशी रोजगार पर सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। भारत प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने तथा सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने 28 जून को जिनेवा में आईओएम मुख्यालय में स्थायी प्रतिनिधि स्तर की बैठक में सीपी के अध्यक्ष के रूप में अपनी पहली बैठक की अध्यक्षता की। भारत ने सीपी को और सुदृढ़ करने के लिए प्रमुख प्राथमिकताओं और पहलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अगले दो वर्षों के लिए एक कार्य योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की।

सीपी (2024-26) के लिए भारत की प्राथमिकताओं में शामिल हैं:

- (क) कोलंबो प्रक्रिया की वित्तीय स्थिरता की समीक्षा करना,
 - (ख) नए सदस्य राज्यों और पर्यवेक्षकों को शामिल करके सदस्यता को व्यापक बनाना,
 - (ग) तकनीकी-स्तरीय सहयोग को फिर से पुनर्निर्धारण करना,
 - (घ) अध्यक्षता के लिए एक संरचित रोटेशन को लागू करना,
 - (ङ) सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन (जीसीएम) के लिए वैश्विक समझौते की क्षेत्रीय समीक्षा करना और;
 - (च) एडीडी और अन्य क्षेत्रीय प्रक्रियाओं के साथ संवाद में शामिल होना।
- सीपी की विषयगत क्षेत्र कार्य समूह बैठकें 26-28 नवंबर को बैंकॉक में हुईं।

अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (आईओएम)

आईओएम परिषद का 115^{वाँ} सत्र 26-28 नवंबर को जिनेवा में आयोजित किया गया था। आईओएम परिषद के सत्र का उद्देश्य नियमित प्रवासन मार्गों को सुदृढ़ करने के लिए समाधानों को लागू करना और उनका संचालन करना था।

प्रवासन और गतिशीलता पर भारत-यूरोपीय संघ उच्च स्तरीय वार्ता (एचएलडीएमएम)

अवर सचिव (ईपीएंडडब्ल्यू) के नेतृत्व में 8^{वाँ} भारत-यूरोपीय संघ एचएलडीएमएम 28 नवंबर को ब्रुसेल्स में आयोजित की गई, साथ ही 29 नवंबर को वापसी और पुनः प्रवेश पर कार्यशाला भी आयोजित की गई। एचएलडीएमएम ने परियोजना सलाहकार समिति के कामकाज की समीक्षा की और प्रवासन और गतिशीलता पर भारत-यूरोपीय संघ साझा एजेंडा (सीएएमएम) के चरण 2 के अंतर्गत 2025 के लिए योजना को मंजूरी दी। 2006 में शुरू किया गया एचएलडीएमएम भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रवासन और गतिशीलता के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है और प्रवासन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है। इसे अब तक आठ बार आयोजित किया जा चुका है।

विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ

सरकार विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण को उच्च प्राथमिकता देती है। भारतीय समुदाय कल्याण कोष, प्रवासी भारतीय बीमा योजना, प्रस्थान-पूर्व अभिविन्यास प्रशिक्षण आदि जैसी कल्याणकारी योजनाएँ इस उद्देश्य की प्राप्ति में महत्वपूर्ण साबित हुई हैं।

भारतीय समुदाय कल्याण कोष (आईसीडब्ल्यूएफ)

2009 में स्थापित, भारतीय समुदाय कल्याण कोष (आईसीडब्ल्यूएफ) का उद्देश्य संकट के समय में सबसे योग्य मामलों में आपातकालीन चिकित्सा सहायता, फंसे हुए भारतीयों को हवाई मार्ग, विधिक सहायता, आपातकालीन चिकित्सा सहायता, बोर्डिंग और लॉजिंग, वैवाहिक समस्याओं का सामना कर रही भारतीय महिलाओं की सहायता और शवों को भारत में स्थानांतरित करके विदेशों में रहने वाले भारतीयों की सहायता करना है। इस योजना को 2017 में संशोधित किया गया है और इसे विदेशों में सभी भारतीय मिशनों और पोस्टों में स्थापित किया गया है। सितंबर 2024 तक 683 करोड़ रुपये के कुल व्यय के साथ विदेशों में संकट की स्थिति में सहायता प्राप्त भारतीय नागरिकों की संख्या 3,53,369 तक पहुँच गई है।

प्रस्थान-पूर्व अभिमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम (पीडीओटी)

पीडीओटी कार्यक्रम को जनवरी 2018 में प्रवासी कौशल विकास योजना (पीकेवीवाई) के अंतर्गत विदेश मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य खाड़ी और अन्य उत्प्रवास जाँच अपेक्षित (ईसीआर) देशों के लिए बहिर्गमन भारतीय प्रवासी श्रमिकों के कौशल को बढ़ाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, प्रवासी श्रमिकों को गंतव्य देश की संस्कृति, भाषा, परंपरा और स्थानीय नियमों और विनियमों को समझने में सक्षम बनाने के लिए निःशुल्क एक दिवसीय अभिमुखीकरण प्रशिक्षण दिया जाता है। अभिमुखीकरण प्रशिक्षण प्रवासी श्रमिकों को सुरक्षित और विधिक प्रवास के मार्गों और उनके कल्याण, सुरक्षा और संरक्षण के लिए विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों जैसे आईसीडब्ल्यूएफ, मदद, पीबीबीवाई आदि के बारे में जागरूक करने में भी मदद करता है। पीडीओटी कार्यक्रम की शुरुआत से लेकर 31 अक्टूबर 2024 तक 41 पीडीओटी केंद्रों के माध्यम से कुल 1,56,659 प्रवासी श्रमिकों को प्रशिक्षण दिया गया है।

प्रवासी भारतीय बीमा योजना (पीबीबीवाई)

प्रवासी भारतीय बीमा योजना (पीबीबीवाई) ईसीआरदेशों में बहिर्गमन सभी ईसीआरश्रेणी के श्रमिकों के लिए एक अनिवार्य बीमा योजना है। यह योजना आकस्मिक मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में आईएनआर 10 लाख का बीमा कवर और आईएनआर 275/- के मामूली बीमा प्रीमियम पर दो वर्ष के लिए या आईएनआर 375/- तीन वर्ष की वैधता के लिए अन्य लाभ प्रदान करती है। इस योजना को 01 अगस्त 2017 से संशोधित

किया गया था, ताकि स्वीच्छिक आधार पर ईसीएनआरश्रेणी के श्रमिकों को शामिल किया जा सके और हमारे श्रमिकों के लाभ के लिए दावों के निपटान को सरल बनाया जा सके और दावों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित किया जा सके। पीबीबीवाईयोजना ने अब तक अक्टूबर, 2024 तक 80,09,035 भारतीय प्रवासी श्रमिकों को बीमा कवर प्रदान किया है।

प्रवासी सहभागिता प्रभाग

प्रवासी सहभागिता प्रभाग, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार, क्षेत्रीय प्रवासी भारतीय दिवस, भारत को जानो कार्यक्रम, प्रवासी बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम, भारत को जानो प्रश्नोत्तरी, प्रवासी रिश्ता पोर्टल और प्रवासी भारतीयों के साथ सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने सहित कई प्रवासी सहभागिता योजनाएं संचालित करता है। प्रभाग प्रवासी भारतीयों से जुड़े वैवाहिक विवादों और बाल हिरासत के मामलों, विदेश में भारतीय छात्रों से संबंधित मुद्दों और प्रवासी भारतीयों से प्राप्त विविध शिकायतों से भी निपटता है।

प्रवासी भारतीय दिवस (पीबीडी) सम्मेलन

प्रवासी भारतीय दिवस (पीबीडी) सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है और भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिह्नित करने और शीर्ष स्तर पर प्रवासी भारतीयों के साथ भारत के जुड़ाव को फिर से जोड़ने और गहन करने के लिए हर दो वर्ष में 09 जनवरी को मनाया जाता है। यह प्रवासी भारतीय समुदाय को विदेशों में भारत को बढ़ावा देने के लिए चिंता के मुद्दों और विचारों को साझा करके भारत सरकार के साथ जुड़ने के लिए एक मंच प्रदान करता है। 17^{वां} पीबीडी सम्मेलन मध्य प्रदेश सरकार के साथ साझेदारी में 08-10 जनवरी 2023 तक इंदौर, मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। पीबीडी सम्मेलन के दौरान, प्रमुख भारतीय प्रवासी सदस्यों को माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा प्रतिष्ठित 'प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार' (पीबीएसए) से सम्मानित किया जाता है। यह एनआरआई, पीआईओ या एनआरआई या पीआईओ द्वारा स्थापित और संचालित किसी संगठन या संस्था को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, जो उनकी उपलब्धियों को मान्यता देता है और भारत और विदेशों में विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदान को सम्मानित करता है।

प्रवासी बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम (एसपीडीसी)

एसपीडीसी की शुरुआत शैक्षणिक वर्ष 2006-07 में भारतीय मूल के लोगों (पीआईओ) और एनआरआई के बच्चों के लिए की गई थी, ताकि वे भारतीय विश्वविद्यालयों/

संस्थानों में स्नातक पाठ्यक्रम कर सकें और भारत को उच्च अध्ययन के केंद्र के रूप में बढ़ावा दे सकें। एसपीडीसी योजना के अंतर्गत, मंत्रालय चिकित्सा और संबंधित पाठ्यक्रमों सहित पेशेवर और गैर-पेशेवर पाठ्यक्रमों में स्नातक स्तर पर 4000 अमेरिकी डॉलर तक की 150 छात्रवृत्तियाँ प्रदान

करता है, जिनमें से 50 सीटें ईसीआर देशों में भारतीय श्रमिकों के बच्चों के लिए आरक्षित हैं। एसपीडीसी का लाभ दुनिया भर के पीआईओ और एनआरआई के बच्चे उठा सकते हैं। एसपीडीसी की स्थापना के बाद से, शैक्षणिक वर्ष 2023-24 तक कुल 1687 छात्रवृत्तियाँ प्रदान की गई हैं।

भारत को जानो कार्यक्रम (केआईपी)

केआईपी भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य प्रवासी भारतीयों के युवाओं को जोड़ना है। इसका उद्देश्य 21-35 वर्ष की आयु के भारतीय मूल के युवाओं का अपनी मातृभूमि से जुड़ाव सुदृढ़ करना है, साथ ही समकालीन भारत में जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में उनकी जागरूकता को बढ़ावा देना और उन्हें देश के भीतर चल रहे सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों के साथ-साथ भारत की कला, विरासत और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। कैलेंडर वर्ष 2024 में, नवंबर 2024 तक केआईपी के 8 संस्करण (71^{वां} से 78^{वां} संस्करण तक) आयोजित किए जा चुके हैं, जिसमें विभिन्न देशों के 310 प्रवासी युवाओं ने भाग लिया। अब तक केआईपी के 81 संस्करण पूरे हो चुके हैं।

प्रवासी भारतीयों के साथ सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना (पीसीटीडी)

पीसीटीडी योजना के अंतर्गत, मंत्रालय विदेशों में भारतीय मिशन/केंद्रों को उनकी पहल का समर्थन करने के लिए अनुदान प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य प्रवासी भारतीय समुदाय के साथ संबंधों को सुदृढ़ करना और उनकी भारतीय विरासत और संस्कृति को संरक्षित, बनाए रखना और प्रदर्शित करना है। इस योजना का उद्देश्य भारत और उसके प्रवासी भारतीयों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को पोषित और सुदृढ़ करना है। भारत में थिंक-टैंक और संगठनों को भी अनुदान प्रदान किया जाता है जो प्रवासी भारतीय समुदाय से संबंधित कार्यक्रम आयोजित करते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में, इस योजना के अंतर्गत विदेशों में 66 भारतीय मिशन/केंद्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

विदेश संपर्क कार्यक्रम

विदेश संपर्क कार्यक्रम की शुरुआत 2017 में विदेश मंत्रालय की एक आउटरीच पहल के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य राज्य सरकारों के भीतर प्रासंगिक हितधारकों के साथ जुड़ना था। विदेश मंत्रालय ने "विदेश संपर्क कार्यक्रम" के अंतर्गत राज्य आउटरीच कार्यक्रम शुरू किए, जो मंत्रालय और राज्य सरकारों के बीच एक गहन संवाद है। विदेश में हमारे नागरिकों के कल्याण और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों के समाधान में सहयोग प्राप्त करने और विदेश में रहने वाले भारतीय समुदाय के जुड़ाव और कल्याण तथा अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाने के लिए विदेश मंत्रालय की पहलों के बारे में राज्य सरकारों को जानकारी देने के लिए राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में राज्य आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वर्ष



विदेश मंत्री ने श्रम एवं रोजगार मंत्री तथा प्रधानमंत्री के साथ मिलकर अक्टूबर 2024 में संशोधित ई-माइग्रेट पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया।

के दौरान, जुलाई में बिहार और त्रिपुरा तथा सितंबर में उत्तराखंड राज्यों के साथ 3 विदेश संपर्क कार्यक्रम आयोजित किए गए।

वैवाहिक समस्याओं से प्रभावित एनआरआई महिलाओं को सहायता

विदेश मंत्रालय को प्रवासी भारतीयों से विवाहित संकटग्रस्त महिलाओं से परित्याग, परित्याग, उत्पीड़न और बाल हिरासत के मामलों सहित वैवाहिक समस्याओं पर शिकायतें प्राप्त होती हैं। पीड़ित महिलाओं को ऐसे मामलों में उचित परामर्श, मार्गदर्शन और विधिक प्रक्रियाओं और तंत्रों के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। मंत्रालय ने इस वर्ष ऐसी 283 शिकायतों का समाधान किया है।

ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल

ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल विदेश में मिशन/पोस्ट के माध्यम से प्रवासी (एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई) को भारत सरकार से जोड़ने के लिए एक ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल है। यह विदेश मंत्रालय, संबंधित मिशन/पोस्ट और प्रवासी समुदाय के बीच एक तीन-तरफ़ा संचार चैनल है। यह सूचना के प्रसार और स्वैच्छिक पंजीकरण के आधार पर हमारे प्रवासी समुदाय का डेटाबेस बनाने में मदद करता है। प्रवासी जुड़ाव (डीई) प्रभाग वर्तमान में ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल सहित अपने सभी मौजूदा पोर्टलों को समेकित करने की प्रक्रिया जारी है। पोर्टल को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है।

छात्र मुद्दे

लगभग 1.33 मिलियन भारतीय छात्र विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। विदेशी विश्वविद्यालयों में नामांकित भारतीय छात्रों से संबंधित कई

मुद्दों को मंत्रालय ने विदेश में संबंधित भारतीय मिशन/केंद्रों के परामर्श से संबोधित किया है।

ओईऔरपीजीई प्रभाग

प्रवास जाँच अपेक्षित (ईसीआर) श्रेणी के पासपोर्ट रखने वाले भारतीयों के प्रवास की प्रक्रिया को प्रवास अधिनियम, 1983 के अंतर्गत विनियमित किया जाता है, जिसे विदेश मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है। रोजगार के लिए 18 अधिसूचित ईसीआरदेश अफगानिस्तान, बहरीन, इंडोनेशिया, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मलेशिया, ओमान, कतर, सऊदी अरब, दक्षिण सूडान, सूडान, सीरिया, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और यमन हैं।

ईसीआर पासपोर्ट धारकों के प्रवास को उत्प्रवास मंजूरी (ईसी) के अनुदान के माध्यम से विनियमित किया जाता है, जो कि प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स (पीओई) कार्यालयों द्वारा दी जाती है। प्रोटेक्टर जनरल ऑफ इमिग्रेंट्स (पीजीई) मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, चंडीगढ़, हैदराबाद, कोचीन, तिरुवनंतपुरम, जयपुर, रायबरेली, पटना, बेंगलुरु, गुवाहाटी, रांची, भुवनेश्वर और अगरतला में स्थित प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स (पीओई) के 16 कार्यालयों की मदद से उत्प्रवास अधिनियम को लागू करता है। पंजीकृत भर्ती एजेंटों (आरए) को विदेश में रोजगार के लिए भर्ती करने से पहले पीजीई से पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) प्राप्त करना आवश्यक है। वर्तमान में, मौजूदा परिस्थितियों के कारण लीबिया और यमन के लिए उत्प्रवास मंजूरी जारी करना निलंबित कर दिया गया है।

संशोधित ईमाइग्रेट V2.0 पोर्टल और ईमाइग्रेटमोबाइल ऐप का शुभारंभ

श्रम और रोजगार, युवा मामले और खेल मंत्री और राज्य मंत्री (पीएम) की उपस्थिति में 14 अक्टूबर को ईएएमद्वारा संशोधित ईमाइग्रेट V2.0 पोर्टल

और ईमाइग्रेटमोबाइल ऐप को औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया था। ईमाइग्रेटपरियोजना 2015 में शुरू की गई थी और इसे ईसीआरश्रेणी के पासपोर्ट धारक श्रमिकों के उत्प्रवास को सुविधाजनक बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। संशोधित ईमाइग्रेट 2.0 पोर्टल विदेशी नियोक्ताओं, भर्ती एजेंटों और प्रवासियों को एक ही मंच पर जोड़ता है, जो डिजिटललॉकरके माध्यम से दस्तावेज़ भंडारण और 5.6 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से उत्प्रवास संबंधी सेवाओं जैसी उन्नत सेवाएँ प्रदान करता है। यह राष्ट्रव्यापी ई-अभिशासन सेवाओं के लिए उमंग, क्षेत्रीय भाषा समर्थन के लिए भाषिणी और बिना किसी लेनदेन शुल्क के डिजिटल भुगतान के लिए एसबीआईके साथ एकीकृत होता है यह ऐप हितधारकों को पोर्टल पर उपलब्ध प्रमुख सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करता है, जिसमें आवेदन की स्थिति पर नज़र रखना, पंजीकृत और अपंजीकृत भर्ती एजेंटों की सूची प्राप्त करना, शिकायत दर्ज करना आदि शामिल हैं। यह पोर्टल प्रवासन को आसान बनाने में एक महत्वपूर्ण तकनीकी पहल है।

2024 में प्रवास के रुझान

हर वर्ष भारत से बहुत से लोग रोजगार के उद्देश्य से विदेश जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत से प्रवासी श्रमिकों का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों में गया है। इस वर्ष ईसीआर देशों में प्रवास करने वाले ईसीआर पासपोर्ट धारकों के लिए ईमाइग्रेट पोर्टल के माध्यम से कुल 3,87,075 उत्प्रवास मंजूरी (ईसी) जारी की गई। इसमें ईसीआर देशों में प्रवास करने वाली नर्सों को जारी की गई 14,570 ईसी शामिल हैं। ईमाइग्रेट पोर्टल ने 9,805 नए विदेशी नियोक्ता (एफई) और 165 नए पंजीकृत भर्ती एजेंट (आरए) भी जोड़े हैं। वर्ष के दौरान, 1,741 नई रोजगार संबंधी शिकायतें (जीआर)



दर्ज की गई और 512 जीआर का समाधान किया गया। दिसंबर 2023 में, मंत्रालय ने भर्ती एजेंसियों (आरए) के लिए मौजूदा बैंक गारंटी प्रणाली के साथ-साथ एक अतिरिक्त विकल्प प्रदान करने के लिए क्रेडिट/सुरक्षा बीमा योजना लागू की, ताकि वे उत्प्रवास अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) प्राप्त करने या नवीनीकृत करने के लिए वित्तीय सुरक्षा आवश्यकता को पूरा कर सकें। अब तक 200 से अधिक आरए इस योजना के अंतर्गत लाभ उठा चुके हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और महाराष्ट्र, 2024 के दौरान जारी किए गए ईसी की संख्या के मामले में शीर्ष 10 राज्य थे।

अध्याय

24

राज्य प्रभाग

राज्य प्रभाग विदेशों में भारतीय मिशनो और पोस्टों के नेटवर्क और विदेश मंत्रालय के शाखा सचिवालयों के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की बाहरी पहुंच को सुगम बनाता है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की कूटनीतिक पहुंच को सुगम बनाने और संघीय स्तर पर आर्थिक कूटनीति को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कदम उठाते हुए इस अधिदेश का सक्रिय रूप से पालन किया गया।

विभिन्न मामलों को सुगम बनाने के लिए दिल्ली में अपने रेजिडेंट कमिश्नरों के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ संपर्क बनाए रखना जारी रहा। व्यापार/निवेश संवर्धन, कौशल विकास, कृषि अनुसंधान, अन्य बातों के अलावा, राज्य सरकारों और उनकी संस्थाओं के बीच विदेशी समकक्षों के साथ कई समझौता-ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रभाग ने भारतीय राज्यों/शहरों के साथ विदेशी प्रांतों/शहरों के बीच मैत्रीपूर्ण और सहकारी संबंध स्थापित करने के लिए सिस्टर सिटी/राज्य समझौतों को भी संसाधित और सुगम बनाया। आयोजित महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का विवरण नीचे दिया गया है।

विदेश में राज्य सुविधा (एसएफए) बजट शीर्ष के अंतर्गत वितरित निधियां

विदेश में भारतीय मिशनो/केंद्रों को “विदेश में राज्य सुविधा” (एसएफए) के अंतर्गत 8 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई। इन निधियों का उपयोग हमारे मिशनो/केंद्रों द्वारा विदेशों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रचार गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया।

राज्य सुविधा और ज्ञान सहायता (एसएफएंडकेएस) बजट शीर्ष के अंतर्गत वितरित निधियां

राज्य प्रभाग ने तीसरे पूर्वोत्तर निर्यात संवर्धन सम्मेलन के लिए शाखा सचिवालय गुवाहाटी को निधियां मंजूर कीं। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की बाहरी पहुंच को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता, हैदराबाद और चेन्नई में शाखा सचिवालयों और त्रिवेन्द्रम, श्रीनगर और जम्मू में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों को भी निधियां मंजूर की गईं।

राज्य प्रभाग द्वारा आयोजित/सुविधायुक्त कार्यक्रम

- (i) प्रभाग ने 10 मई को केरल सरकार के रेजिडेंट कमिश्नर और अन्य अधिकारियों की एक बैठक आयोजित की, ताकि उन्हें विदेश मंत्रालय की कार्यप्रणाली और राज्य की बाहरी भागीदारी को बढ़ावा देने के तरीकों से परिचित कराया जा सके।
- (ii) प्रभाग ने उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो (यूपीआईटीएस) 2024 के दूसरे संस्करण को बढ़ावा देने के लिए 25-29 सितंबर को वेबिनार की मेजबानी की, जिसमें विदेश मंत्रालय मुख्यालय, विदेश में भारतीय मिशन/पोस्ट और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
- (iii) प्रभाग ने उत्कर्ष ओडिशा: मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव '25 की प्रस्तावना के रूप में 03 अक्टूबर को दिल्ली में राजदूतों की बैठक की सुविधा प्रदान की, जिसकी अध्यक्षता ओडिशा के मुख्यमंत्री ने की

और जिसमें भारत में मान्यता प्राप्त कई विदेशी मिशनों के प्रमुखों ने भाग लिया।

(iv) प्रभाग ने 13-19 अक्टूबर तक अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोत्सव के दौरान 18 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में राजदूतों की बैठक आयोजित की, जिसकी अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की और इसमें भारत में मान्यता प्राप्त कई विदेशी मिशनों के प्रमुखों ने भाग लिया।

(v) प्रभाग ने भारतीय वाणिज्य मंडल (आईसीसी), नॉर्थ ईस्ट इनिशिएटिव के सहयोग से 21 नवंबर को गुवाहाटी में तीसरे नॉर्थ ईस्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन मीट (बीएसएम) का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य खरीदारों और विक्रेताओं दोनों के लिए एक मंच तैयार करना था।

विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के दौरे की सुविधा

01 जनवरी से 31 दिसंबर की अवधि के दौरान भारत के विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में नई दिल्ली स्थित 100 से अधिक विदेशी प्रतिनिधि मंडलों/राजदूतों के दौरे की सुविधा प्रदान की गई।

बाहरी एजेंसियों द्वारा वित्त-पोषित पूर्वोत्तर राज्य परियोजनाओं को मंजूरी।

2024 में आईएफएडी, एडीबी, जेआईसीए और एनडीबीजैसी बहुपक्षीय और द्विपक्षीय एजेंसियों द्वारा वित्त-पोषित पूर्वोत्तर राज्यों (असम, सिक्किम, मिजोरम और मणिपुर) में शुरू की जाने वाली 10 बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं को विदेश मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है।

शहरों/राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का जुड़वा होना, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और विदेशी संस्थाओं के बीच समझौता-ज्ञापन

क्र. सं.	समझौता-ज्ञापन/करार	पार्टियाँ	विदेश मंत्रालय की एनओसी तिथि
1.	महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, करनाल, हरियाणा और वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया के बीच समझौता-ज्ञापन।	महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, करनाल, हरियाणा और वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया	18 जनवरी
2.	जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी), बिहार सरकार और डेल्टारेस, नीदरलैंड के बीच समझौता-ज्ञापन।	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार और डेल्टारेस, नीदरलैंड	30 जनवरी
3.	जावनीज़ावोडट्रिगलवस्कीनारोडनी पार्क (ट्रिगलव राष्ट्रीय उद्यान प्राधिकरण), स्लोवेनिया और वैली ऑफ़ फ्लावर्स नेशनल पार्क, उत्तराखंड सरकार, भारत के बीच समझौता-ज्ञापन।	त्रिगलव राष्ट्रीय उद्यान प्राधिकरण, स्लोवेनिया और प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), उत्तराखंड सरकार, भारत।	16 फरवरी
4.	श्रीमंत शंकरदेव यूनिवर्सिटी ऑफ़ हेल्थ साइंसेज (एसएसयूएचएस), असम और नोवो नॉर्डिस्क फाउंडेशन (एनएनएफ), डेनमार्क के बीच समझौता-ज्ञापन।	श्रीमंत शंकरदेव स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, असम और नोवो नॉर्डिस्क फाउंडेशन, डेनमार्क।	28 मई
5.	चंडीगढ़ प्रशासन और मिल्टन कीन्स सिटी काउंसिल, यूके-रेग के बीच समझौता-ज्ञापन।	चंडीगढ़ प्रशासन और मिल्टन कीन्स सिटी काउंसिल, यू.के.	30 मई
6.	सिंगापुर-असम नर्सिंग टैलेंट स्किल्स कोऑपरेशन पर असम के मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च डिपार्टमेंट और सिंगापुर-इंडिया पार्टनरशिप ऑफिस और एमओएच होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच समझौता-ज्ञापन।	सिंगापुर-भारत भागीदारी कार्यालय (एसआईपीओ) और असम सरकार	02 सितम्बर
7.	गोवा तटीय और पर्यावरण प्रबंधन सोसायटी और डेल्टारेस, नीदरलैंड के बीच गोवा कटाव अध्ययन और क्षमता निर्माण के चरण 1 को पूरा करने के लिए समझौता-ज्ञापन।	गोवा तटीय और पर्यावरण प्रबंधन सोसायटी और डेल्टारेस, नीदरलैंड	09 सितम्बर
8.	उत्तराखंड सरकार और मेसर्स वर्क्स, आइसलैंड के बीच भूतापीय ऊर्जा पर समझौता-ज्ञापन	उत्तराखंड राज्य और मेसर्स वर्क्स, आइसलैंड	12 दिसम्बर

अध्याय

25

नई उदीयमान और सामरिक प्रौद्योगिकियाँ (एनईएसटी) और साइबर कूटनीति

एनईएसटी

नई उदीयमान और सामरिक प्रौद्योगिकियाँ (एनईएसटी) प्रभाग भारत की प्रौद्योगिकी कूटनीति को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है। अपनी स्थापना के बाद से, प्रभाग ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित बहुपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों के भीतर प्रौद्योगिकी शासन नियमों, मानकों और वास्तुकला पर वार्ता में भारत की स्थिति को विकसित करने और समन्वय करने के लिए सक्रिय रूप से काम किया है। इसने प्रमुख साझेदार देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ नीति सहयोग को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जबकि भारतीय मिशनों को उदीयमान प्रौद्योगिकियों के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुविधाजनक बनाने में 'फील्ड सिनेप्स' के रूप में कार्य करने के लिए सशक्त बनाया है। इन जुड़ावों ने उदीयमान और सामरिक प्रौद्योगिकियों पर राष्ट्रीय और वैश्विक दृष्टिकोण को आकार देने में एक प्रमुख प्रभावक के रूप में भारत की भूमिका को सुदृढ़ किया है।

2024 के दौरान, भारत सरकार ने विभिन्न देशों के साथ महत्वपूर्ण और उदीयमान प्रौद्योगिकियों में साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए लगातार प्रयास किए। महत्वपूर्ण और उदीयमान प्रौद्योगिकी (आईसीईटी) पर यू.एस.-भारत पहल के अंतर्गत दूसरी समीक्षा बैठक जुलाई में आयोजित की गई

थी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के नेतृत्व में हुई इस बैठक में दोनों देशों की सरकारों, व्यवसायों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सामरिक प्रौद्योगिकी साझेदारी और रक्षा औद्योगिक सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। चर्चा में रक्षा, अंतरिक्ष, क्वांटम कंप्यूटिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अर्धचालक, उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग, उन्नत दूरसंचार, जैव प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों की प्राथमिकता दी गई।

जुलाई में, भारत और यूनाइटेड किंगडम ने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में महत्वपूर्ण और उदीयमान प्रौद्योगिकियों (सीईटी) में ब्रिटिश और भारतीय सरकारों, उद्योग और शिक्षाविदों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक नई प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल (टीएसआई) की घोषणा की। अक्टूबर में, भारत और जर्मनी ने भारत-जर्मनी नवाचार और प्रौद्योगिकी भागीदारी रोडमैप पर हस्ताक्षर किए। सितंबर में, भारत और सिंगापुर उन्नत विनिर्माण जैसी महत्वपूर्ण और उदीयमान प्रौद्योगिकियों में सहयोग की संभावना तलाशने पर सहमत हुए। लचीले सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देने के लिए भारत-सिंगापुर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम साझेदारी पर एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अतिरिक्त, डिजिटल प्रौद्योगिकियों में सहयोग पर एक समझौता-ज्ञापन का भी आदान-प्रदान किया गया। प्रभाग ने इन पहलों के अंतर्गत शामिल प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में भारत की नीति स्थिति

और प्रतिक्रियाओं को तैयार करने, देशों के बीच सहयोग और सहभागिता को सुविधाजनक बनाने और सुदृढ़ करने में संबंधित मंत्रालयों को अपने इनपुट प्रदान किए।

वर्ष के दौरान, प्रभाग ने परिणामी दस्तावेजों की अंतिम वार्ता में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी (जीपीएआई) नई दिल्ली घोषणा 2024, जीपीएआई सर्बिया घोषणा 2024, सतत विकास के लिए सुरक्षित, संरक्षित और भरोसेमंद कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियों के अवसरों को जल करने पर यूएनजीए संकल्प, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की क्षमता निर्माण पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने पर यूएनजीए संकल्प, वैश्विक डिजिटल कॉम्पैक्ट और भविष्य के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि, जिसे सितंबर में संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में अपनाया गया था।

इस प्रभाग ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, फिनटेक, अंतरिक्ष अन्वेषण, दूरसंचार और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में भारत की बढ़ती विशेषज्ञता का लाभ उठाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके और भारत के वैश्विक प्रभाव को बढ़ाया जा सके। इसने वैश्विक भागीदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (जीपीएआई) मध्य-वर्षीय शिखर सम्मेलन, वैश्विक भारत एआई शिखर सम्मेलन, ग्रीन हाइड्रोजन पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, चौथा आईई-इन्वेस्ट 2024, इंडिया मोबाइल कांग्रेस, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ-विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा (आईटीयू-डब्ल्यूटीएसए 2024) और वैश्विक फिनटेक महोत्सव 2024 सहित अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के आयोजन में संबंधित मंत्रालयों की सहायता की।

पिछले एक वर्ष में, प्रभाग ने वैश्विक स्तर पर नई और उदीयमान प्रौद्योगिकियों में विकास की निगरानी और प्रसार करने के लिए एक सक्रिय आउटरीच रणनीति अपनाई है। इन प्रगति का दस्तावेजीकरण करने के लिए मासिक समाचार-पत्र तैयार किए गए, जबकि तकनीकी नवाचारों की जानकारी विदेशों में भारतीय मिशनों और अन्य स्रोतों के माध्यम से एकल की गई।

प्रभाग ने सामरिक और उदीयमान प्रौद्योगिकियों, जैसे सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, फिनटेक और भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों पर चर्चा और ब्रीफिंग सत्र भी आयोजित किए। इन सत्रों में उद्योग प्रतिनिधियों ने भारत में तकनीकी प्रगति पर भारतीय मिशनों को ब्रीफिंग दी और विदेशों में बाजार विस्तार के अवसरों की पहचान की।

प्रभाग भारत के राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाते हुए विदेशी देशों और बहुपक्षीय संस्थानों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सहभागिता और ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए बायोई3 (अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी) नीति के लिए नोडल इकाई के रूप में भी कार्य करता है। इसने नाइजीरिया और रूस के साथ समझौता-ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने सहित कई विदेशी देशों में समकक्ष एजेंसियों के साथ जुड़ाव में भारतीय सर्वेक्षण का भी समर्थन किया।

वर्ष के दौरान, प्रभाग अधिकारियों ने वैश्विक प्रौद्योगिकी-संबंधी कार्यक्रमों में भाग लिया, जैसे कि यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह, वैश्विक डीपीआई शिखर सम्मेलन, जिनेवा विज्ञान और कूटनीति प्रत्याशा (जीईएसडीए) शिखर सम्मेलन, आईटीयू-डब्ल्यूटीएसए 2024, साइबरटेक ग्लोबल इवेंट 2024

का 10^{वां} संस्करण, साइबर और टेक रिट्रीट 2024 का चौथा संस्करण, बेलग्रेड, सर्बिया में जीपीएआई शिखर सम्मेलन 2024, आदि। राष्ट्रीय स्तर पर, उन्होंने ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2024, इंडिया जियोस्पेशियल लीडर समिट 2024, ग्लोबल इंडिया एआईसमिट, ईटी 5G|6G कांग्रेस और इंडिया मोबाइल कांग्रेस जैसे कार्यक्रमों में भाग लिया।

साइबर कूटनीति

मंत्रालय का साइबर कूटनीति प्रभाग अंतरराष्ट्रीय साइबर शासन के मुद्दों से निपटने वाला एक विशेष प्रभाग है और यह संयुक्त राष्ट्र सहित द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर देशों के साथ जुड़ा हुआ है। द्विपक्षीय साइबर वार्ता भारत के साइबर आउटरीच और विभिन्न देशों के साथ कूटनीतिक जुड़ाव के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में काम करती है। इन वार्ताओं ने सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान, संयुक्त क्षमता निर्माण पहल और साइबर अपराधों के खिलाफ सहयोग के माध्यम से साइबर सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भागीदार देशों के साथ सहयोग की सुविधा प्रदान की। क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर, भारत ने संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स और एससीओ जैसे विभिन्न बहुपक्षीय और क्षेत्रीय मंचों के अंतर्गत वैश्विक साइबर शासन विकास और नीतियों में अपने हितों और चिंताओं की सक्रिय रूप से समर्थन किया।

द्विपक्षीय साइबर सहभागिताएँ

वर्ष के दौरान, भारत ने दक्षिण कोरिया, एस्टोनिया, यूनाइटेड किंगडम, आसियान, सिंगापुर, इटली और नीदरलैंड के साथ द्विपक्षीय साइबर वार्ता की।

28 मई को दक्षिण कोरिया में आयोजित द्वितीय भारत-दक्षिण कोरिया साइबर वार्ता, 3 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित छठी भारत-यूके साइबर वार्ता और 6 नवंबर को हेग में आयोजित तीसरी भारत-नीदरलैंड साइबर वार्ता जैसे स्थापित तंत्रों ने साइबर क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, साइबर खतरे के परिदृश्य, राष्ट्रीय साइबर नीतियों और रणनीतियों, और महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की सुरक्षा सहित साइबर सुरक्षा में सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया। इन वार्ताओं ने वैश्विक साइबर शासन और नीतियों में समकालीन विकास पर दृष्टिकोणों के आदान-प्रदान की सुविधा भी प्रदान की, जिससे भागीदार देशों को इन क्षेत्रों में भारत की स्थिति और हितों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली।

भारत ने अपने पहले द्विपक्षीय साइबर संवाद आयोजित किए, जिनमें 17 अक्टूबर को सिंगापुर में आयोजित पहला भारत-सिंगापुर साइबर नीति संवाद, 16 अक्टूबर को सिंगापुर में आयोजित पहला भारत-आसियान साइबर नीति संवाद, 17 जून को तेलिन में आयोजित पहला भारत-एस्टोनिया साइबर संवाद और 25 अक्टूबर को XX सदी में आयोजित पहला भारत-इटली साइबर संवाद शामिल है। पहले भारत-सिंगापुर साइबर नीति संवाद में साइबर अपराधों से निपटने, क्षमता निर्माण और संयुक्त राष्ट्र

साइबर स्पेस विकास पर समन्वय के लिए व्यावहारिक द्विपक्षीय सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया। पहले भारत-आसियान साइबर नीति संवाद ने साइबर क्षमताओं पर आसियान प्राथमिकताओं, साइबर खतरों/अपराधों की चुनौतियों और क्षमता निर्माण सहयोग की संभावनाओं की बेहतर समझ प्रदान की।

इन चार नए संवादों के संस्थागतकरण ने भारत के साइबर जुड़ावों को उन क्षेत्रों सहित खोल दिया, जहाँ साइबर स्पेस पर हितों और विचारों के अभिसरण की खोज की जा सकती है।

क्षेत्रीय और बहुपक्षीय साइबर जुड़ाव

वर्ष के दौरान भारत के प्रमुख साइबर जुड़ावों में आईसीटी अपराधों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को विस्तृत करने के लिए तदर्थ समिति की बैठकें, संयुक्त राष्ट्र के भीतर आईसीटी सुरक्षा पर ओपन-एंडेड वर्किंग ग्रुप और ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट की वार्ताएँ शामिल थीं।

अगस्त में आयोजित तदर्थ समिति की बैठकों के दौरान भारत ने सीमा पार साइबर अपराधों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए भाग लिया और समर्थन किया। इन बैठकों में साइबर अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के मसौदे को अपनाया गया, जिसका उद्देश्य सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रणालियों का उपयोग करके किए गए अपराधों से निपटने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ करना और गंभीर अपराधों के इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को साक्षात् करने की सुविधा प्रदान करना था। कन्वेंशन को अपनाने से साइबर अपराधों से निपटने में वैश्विक सहयोग का समर्थन करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय विधिकसंरचना प्रदान किया गया।

भारत ने आईसीटी के उपयोग और सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र ओपन-एंडेड वर्किंग ग्रुप के 8-12 जुलाई को आयोजित 8^{वें} मूल सत्र और 2-6 दिसंबर को आयोजित 9^{वें} मूल सत्र में भी भाग लिया। सदस्य देश प्रमुख मुद्दों पर चर्चा जारी रखने के लिए सहमत हुए, जिसमें मौजूदा और संभावित खतरों

की पहचान करना और उनका समाधान करना, आईसीटी के उपयोग में उत्तरदायी राज्य व्यवहार के नियम, मानदंड और सिद्धांत विकसित करना, आईसीटी पर अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू करना और विश्वास-निर्माण उपायों को लागू करना शामिल था। इन उपायों में वैश्विक संपर्क बिंदुओं के लिए एक निर्देशिका स्थापित करना, तकनीकी आईसीटी शब्दों और प्रौद्योगिकियों की समझ को बढ़ाना, क्षमता निर्माण और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत एक स्थायी वार्ता तंत्र को संस्थागत बनाना शामिल था। भारत ने देशों के बीच इन मुद्दों पर अंतराल को पाटने और समझ बढ़ाने के लिए एकल-ट्रैक, सदस्य-नेतृत्व वाली प्रक्रिया के माध्यम से दृष्टिकोणों के निरंतर आदान-प्रदान का समर्थन किया।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा सितंबर में ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट को अपनाना सभी के लिए सुरक्षित और संरक्षित डिजिटल भविष्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वार्ता के दौरान भारत के प्रयासों ने एक समान वैश्विक डिजिटल परिदृश्य को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया, जो साइबर सुरक्षा, डेटा संरक्षण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक उपयोग जैसी चुनौतियों का समाधान करते हुए सभी हितधारकों को लाभान्वित करता है। भारत ने डिजिटल विभाजन को पाटने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक सहयोग का समर्थन किया, जिससे एक परिवर्तनकारी, पारदर्शी और विश्वसनीय डिजिटल भविष्य में योगदान मिला।

क्षेत्रीय जुड़ावों पर, भारत ने आईसीटी के उपयोग पर ब्रिक्स कार्य समूह और अंतर्राष्ट्रीय सूचना सुरक्षा पर एससीओ विशेषज्ञ समूह के परामर्श में भाग लिया। इन परामर्शों ने क्षेत्रीय साइबर क्षमता निर्माण के अवसरों की पहचान और साइबरस्पेस में वैश्विक वार्ता और संवादों पर विकासशील देशों के बीच दृष्टिकोणों के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान की। भारत ने आसियान क्षेत्रीय मंच और आईबीएसए ढांचे के भीतर किए गए क्षमता निर्माण पहलों में भी सक्रिय रूप से समर्थन और भागीदारी की।

अध्याय

26

प्रोटोकॉल प्रभाग

विदेश मंत्रालय का प्रोटोकॉल प्रभाग विदेश में भारतीय गणमान्य व्यक्तियों की सभी उच्च-स्तरीय विदेश यात्राओं और उनके विदेशी समकक्षों की भारत यात्राओं को संभालने के लिए उत्तरदायी है। प्रभाग भारत में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और बैठकों के आयोजन के लिए भी सहायता प्रदान करता है और रेजिडेंट डिप्लोमैटिक कोर के कल्याण के लिए उत्तरदायी है, जिसमें उनके विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षा से संबंधित सभी मामले शामिल हैं।

वर्ष के दौरान, प्रभाग ने प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद् के शपथ ग्रहण समारोह और बिम्स्टेक मंत्रिस्तरीय बैठक के आयोजन में सफलतापूर्वक सहायता की। इसके अलावा, वर्ष 2024-25 में, प्रभाग ने 7 राजकीय यात्राओं, सरकार के प्रमुख (एचओजी) और राज्य के प्रमुख (एचओएस) स्तर पर 4 आधिकारिक यात्राओं और भारत में 56 उपराष्ट्रपति/उप प्रधानमंत्री/विदेश मंत्री स्तर की यात्राओं की सुविधा प्रदान की। प्रभाग ने 3 आभासी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के आयोजन के लिए भी सहायता प्रदान की।

इस प्रभाग ने माननीय राष्ट्रपति जी की 7 विदेशी देशों की यात्रा, उपराष्ट्रपति जी की एक विदेशी देश की यात्रा तथा प्रधानमंत्री जी की 16 विदेशी गंतव्यों की यात्रा का आयोजन किया। प्रभाग ने 37 नए मिशन प्रमुखों के लिए परिचय-पत्र प्रस्तुतीकरण समारोह का भी आयोजन किया।

इस अवधि के दौरान, नई दिल्ली में 4 नए निवासी विदेशी मिशन खोले गए, जिससे ऐसे विदेशी मिशनों की कुल संख्या 160 हो गई। इसी अवधि में, 7 नए मानद वाणिज्य दूतावास खोले गए। इस अवधि में भारत में विदेशी राजनयिक कोर में 134 नए राजनयिक पदों को जोड़ा गया।

प्रोटोकॉल प्रभाग विदेशी राजनयिक मिशनों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों (आईओ) की संपत्ति से संबंधित मुद्दों की स्थापना का समन्वय भी करता है और ऐतिहासिक हैदराबाद हाउस के रखरखाव के लिए भी उत्तरदायी है। प्रभाग ने वर्ष के दौरान मिशन के निवासी प्रमुखों के लिए ओडिशा की भ्रमण यात्रा के आयोजन में भी मदद की। प्रभाग ने हवाई अड्डे पर सुविधा के लिए 8600 से अधिक अनुरोधों को सुगम बनाया और एचओएस/एचओजी/मंत्रियों/सचिवों के स्तर पर 400 मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित करने में मदद की।

प्रोटोकॉल-I अनुभाग

प्रोटोकॉल-I अनुभाग, प्रोटोकॉल के उप प्रमुखों (औपचारिक) के प्रभार में, राष्ट्राध्यक्षों/सरकार प्रमुखों/उप-राष्ट्रपतियों और विदेश मंत्रियों की आने वाली यात्राओं, राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की जाने वाली यात्राओं, मनोरंजन (विदेश मंत्रालय की ओर से आधिकारिक लंच, डिनर और स्वागत समारोह) और औपचारिक समारोह, हवाई अड्डे के पास, औपचारिक और आरक्षित लाउंज तक पहुँच आदि को संभालने के लिए अधिकृत है। प्रोटोकॉल-I अनुभाग ने इस अवधि के दौरान हवाई अड्डे के पास, लाउंज (औपचारिक और आरक्षित) और तलाशी से छूट के लिए लगभग 8600 अनुरोधों को सुविधाजनक बनाया। साथ ही, इस अवधि के दौरान एचओएस/एचओजी/मंत्री/सचिवों के स्तर पर 400 मनोरंजन कार्यक्रमों को संभाला गया।

प्रोटोकॉल-III अनुभाग

प्रोटोकॉल-III अनुभाग ने इस अवधि (01 जनवरी-30 नवंबर 2024) के दौरान विभिन्न कर्तव्यों का पालन किया है, जो इस प्रकार हैं:

- (i) मिशन प्रमुखों को उनके पहले आगमन और अंतिम प्रस्थान पर प्रोटोकॉल सुविधाएं प्रदान करना।
- (ii) ऑनलाइन और राष्ट्रपति भवन में परिचय समारोह की व्यवस्था करना, जहां आगंतुक मिशन प्रमुख अपने परिचय-पत्र माननीय राष्ट्रपति जी को सौंपते हैं।
- (iii) गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, संसद के संयुक्त सत्र, भारत के प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह, योग दिवस आदि के दौरान मिशन प्रमुखों और राजनयिकों (जहां भी लागू हो) को सुविधा प्रदान करना।
- (iv) भारत में विदेशी राजनयिक मिशनों/पोस्टों के संबंध में हर वर्ष स्थायी हवाई अड्डा प्रवेश पास की प्रक्रिया करना, जो कि पारस्परिकता के अधीन है, जो विदेशों में हमारे सभी मिशनों/पोस्टों से इनपुट प्राप्त करने और उनकी जांच करने के बाद निर्धारित किया जाता है।
- (v) नए महावाणिज्य दूतावास, उप उच्चायोग, व्यापार कार्यालय और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करने के लिए अनुमोदन।
- (vi) विदेशी देशों के मानद वाणिज्यदूतों, महावाणिज्यदूतों, उप उच्चायोगों (राष्ट्रमंडल देशों के लिए डाक प्रमुख) की नियुक्ति और उसके बाद एकजीक्यूटर्स/राजपत्र अधिसूचना तैयार करना।
- (vii) विदेशी मिशन परिसरों में सैटेलाइट अर्थ स्टेशनों की स्थापना के अनुमोदन की प्रक्रिया।
- (viii) विदेशी देशों द्वारा भारतीय अधिकारियों को दिए बहिर्गमन पुरस्कारों के संबंध में अनुमोदन की प्रक्रिया।
- (ix) विदेशी राजनयिक मिशनों में रक्षा अताशे और रक्षा कर्मियों की नियुक्ति।
- (x) विदेशी राजनयिक मिशनों में नए राजनयिक या आधिकारिक पदों के सृजन के अनुमोदन के लिए प्रक्रिया।
- (xi) भारत में विदेशी मिशनों द्वारा मनाए बहिर्गमन विदेशी देशों के राष्ट्रीय दिवसों के लिए मुख्य अतिथि की व्यवस्था करना और यह

सुनिश्चित करना कि कार्यक्रम स्थल में प्रोटोकॉल दिशानिर्देशों का पालन किया जाए।

- (xii) वीवीआईपी (माननीय राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री) के संदेशों को विदेशी देशों के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों को अग्रेषित करना। विदेशी देशों के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के संदेशों को माननीय राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और भारत सरकार के अधिकारियों को प्रेषित करना।
- (xiii) विदेशी राजनयिक मिशनों और भारतीय स्थानीय कर्मचारियों के बीच भुगतान संबंधी विवादों से संबंधित अदालती मामलों को संभालना।
- (xiv) एचओएम/एचओपी द्वारा शिष्टाचार अनुरोध और सौंपे गए अन्य आधिकारिक कार्य।
- (xv) स्वतंत्रता दिवस के दौरान मिशन के प्रमुख और अन्य राजनयिकों को प्रोटोकॉल बधाई देना और रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर संबंधित परिसरों का प्रबंधन करना।

01 जनवरी से 31 दिसंबर 2024 तक स्वीकृत निवासी मिशन/व्यापार कार्यालय/वाणिज्य दूतावास/उप उच्चायोग/मानद वाणिज्यदूतों की सूची:

- निवासी मिशन: अल्बानिया, तिमोर-लेस्ते, सेंट किट्स और नेविस, मॉरिटानिया और बेनिन
- व्यापार कार्यालय: शून्य
- सांस्कृतिक केंद्र: शून्य
- वाणिज्य दूतावास/उप उच्चायोग: शून्य
- वाणिज्य दूतावास: शून्य
- मानद वाणिज्य दूतावास/मानद वाणिज्यदूतावास:
 1. न्यूजीलैंड-कोलकाता
 2. श्रीलंका-अहमदाबाद
 3. रोमानिया-बेंगलुरु
 4. फिनलैंड-अहमदाबाद
 5. जापान-अहमदाबाद
 6. उरुग्वे-बेंगलुरु
 7. कोस्टा रिका-चेन्नई

जनवरी से 31 दिसंबर 2024 तक भारत में विदेशी राजनयिक मिशनों में नव सृजित पदों की माहवार सूची:

माह	सृजित किए गए पदों
जनवरी	12
फरवरी	04
मार्च	03
अप्रैल	11
मई	10

माह	सृजित किए गए पदों
जून	14
जुलाई	37
अगस्त	25
सितंबर	05
अक्टूबर	03
नवंबर	10
दिसंबर	18
योग	152

प्रोटोकॉल हाउसिंग अनुभाग

प्रोटोकॉल हाउसिंग अनुभाग भारत में विदेशी राजनयिक मिशनों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के स्थापना-संबंधी मामलों को देखता है। इनमें निर्माण, जीर्णोद्धार, संपत्ति की खरीद, बिक्री या पट्टे और राजनयिक परिक्षेत्र में भूमि के आवंटन या पट्टे के लिए मंजूरी शामिल है। यह अनुभाग दिल्ली में आवास विभागों, नगर निगम और नागरिक निकायों जैसे एलएंडडीओ, एनडीएमसी, एमसीडी, डीडीए, जल बोर्ड, बिजली बोर्ड और एमटीएनएल और राज्य सरकारों के साथ विदेशी मिशनों और आईओ के बीच संपर्क के रूप में कार्य

करता है। यह विदेशी मिशनों और भारतीय संपत्ति मालिकों के बीच विवादों और अदालती मामलों के मामलों में भी संपर्क करता है।

यह अनुभाग हैदराबाद हाउस के रखरखाव और रख-रखाव के लिए भी उत्तरदायी है और इसने सीपीडब्ल्यूडी के सिविल, इलेक्ट्रिकल और बागवानी विभागों के साथ समन्वय करके यह काम किया है। इसके अलावा, इस अनुभाग ने हैदराबाद हाउस में संचालन और खानपान के लिए आईटीडीसी के अनुबंध के साथ-साथ एयर फोर्स स्टेशन पालम, नई दिल्ली में वीआईपी रिसेप्टोरियम के रखरखाव के अनुबंध संबंधी दायित्वों को भी प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया है।

अध्याय

27

बाह्य प्रचार और सार्वजनिक कूटनीति

विदेशी प्रचार और सार्वजनिक कूटनीति (एक्सपीडी) प्रभाग ने भारत की स्थिति और भारत की विदेश नीति प्राथमिकताओं को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने के अपने प्रयासों को जारी रखा। यह व्यापक मीडिया जुड़ाव और घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने सार्वजनिक कूटनीति पदचिह्न का विस्तार करके हासिल किया गया है। इन उद्देश्यों को अधिकतम करने में डिजिटल मीडिया और आधुनिक सार्वजनिक कूटनीति और आउटरीच टूल का लाभ उठाना महत्वपूर्ण था। प्रभाग ने प्रेस ब्रीफिंग, प्रेस विज्ञप्ति, सलाह और अन्य जुड़ावों के माध्यम से मीडिया के साथ नियमित रूप से जुड़ाव किया, जिससे विभिन्न विदेश नीति मुद्दों पर सरकार के रुख के बारे में व्यापक जानकारी मिली।

नई पहल

एक्सपीडी प्रभाग ने अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए निम्नलिखित नई पहल की:

विदेश मंत्रालय की डिजिटल उपस्थिति का विस्तार

सोशल मीडिया परिदृश्य के निरंतर विस्तार के साथ तालमेल रखते हुए, मंत्रालय ने 24 जुलाई को एक व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करके अपनी डिजिटल उपस्थिति को सुदृढ़ किया।



विदेश मंत्रालय ने अपनी डिजिटल उपस्थिति को सुदृढ़ करने के लिए जुलाई 2024 में एक नया व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया

क्षेत्रीय मीडिया आउटरीच को सुदृढ़ करना

विदेश नीति पहलों को देश के विभिन्न क्षेत्रों तक ले जाने के लिए, एक्सपीडी प्रभाग ने पिछले वर्ष अपने क्षेत्रीय और स्थानीय मीडिया आउटरीच का विस्तार किया। मीडिया आउटलेट्स को वास्तविक समय के आधार पर क्षेत्रीय भाषाओं में जानकारी साझा की गई। इसके अतिरिक्त, भारतीय मिशन/पोस्टों द्वारा सार्वजनिक कूटनीति के प्रयास और विदेशों में भारत से संबंधित प्रासंगिक कहानियों को क्षेत्रीय मीडिया में प्रसारित किया गया। इस नियमित और समय पर संचार ने क्षेत्रीय मीडिया में विदेश नीति के मुद्दों के प्रति रुचि और कवरेज को बढ़ाया है।

सोशल मीडिया कंटेंट सृजनकर्ताओं को जोड़ना

एक्सपीडी प्रभाग ने विदेशों से कंटेंट सृजनकर्ताओं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर (एसएमआई) को आमंत्रित करके अपने विदेशी मीडिया जुड़ाव का विस्तार किया। इन यात्राओं का मुख्य उद्देश्य भारतीय एसएमआई और उनके अंतरराष्ट्रीय समकक्षों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है, जिससे विदेशों में भारतीयों की आवाज़ को बढ़ावा मिले। जनवरी से नवंबर 2024 की अवधि के लिए, श्रीलंका, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात, यूएसए, मालदीव और पश्चिमी यूरोपीय देशों के कंटेंट सृजनकर्ताओं की 5 यात्राएँ आयोजित की गईं।

भारत को जानिए क्लिज़ का आयोजन

एक्सपीडी प्रभाग ने 5^{वीं} भारत को जानिए (बीकेजे) क्लिज़ का आयोजन किया, जिसमें प्रारूप में नए तत्व शामिल किए गए। 11 नवंबर को भारत के विदेश मंत्री द्वारा वर्चुअली लॉन्च की गई यह क्लिज़ 11 दिसंबर तक एक महीने के लिए खुली रही। लगभग 1.25 लाख प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया, जिसमें 1.09 लाख लोगों ने क्लिज़ में हिस्सा लिया, जिससे पंजीकरण में आठ गुना वृद्धि और प्रतिभागियों में 23 गुना वृद्धि हुई। क्लिज़ पर 4.5 लाख से अधिक बार प्रयास किया गया।

ओटीटी पर एक्सपी डॉक्यूमेंट्रीज

एक्सपीडी प्रभाग ने प्रसार भारत के नए लॉन्च किए गए ओटीटी प्लेटफॉर्म वेक्स पर अगस्त में प्रसारण के लिए प्रभाग द्वारा निर्मित 100 डॉक्यूमेंट्री/लघु फिल्में उपलब्ध कराईं।

मीडिया के साथ जुड़ाव

प्रेस कवरेज

एक्सपीडी प्रभाग ने विदेश नीति के घटनाक्रमों की निरंतर कवरेज सुनिश्चित करने के लिए मीडिया के साथ दैनिक संपर्क बनाए रखा। मीडिया ब्रीफिंग, प्रेस विज्ञप्ति, बयान और सलाह सहित विभिन्न चैनलों के माध्यम से सूचना प्रसारित की गई। अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भारत के रुख के बारे में व्यापक

दर्शकों को सूचित करने के लिए साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग आयोजित की गई। इसके अतिरिक्त, इन ब्रीफिंग को व्यापक दर्शकों तक पहुँचाने के लिए विदेश मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर लाइव-स्ट्रीम किया गया।

प्रभाग ने प्रेस विज्ञप्तियों, पृष्ठभूमि नोटों, मीडिया के सवालियों के जवाब आदि का हिंदी सहित 12 क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद भी प्रदान किया। इन्हें 100 से अधिक क्षेत्रीय मीडिया आउटलेट्स में प्रसारित किया गया।

प्रभाग ने पूरी तरह सुसज्जित मीडिया केंद्रों की स्थापना और संचालन, मीडिया ब्रीफिंग का आयोजन और माननीय राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के अंतराष्ट्रीय दौरों के दौरान मीडिया कवरेज की सुविधा सहित रसद व्यवस्थाओं का समन्वय किया। इसके अतिरिक्त, प्रभाग ने विश्व नेताओं और अन्य विदेशी गणमान्य व्यक्तियों की भारत यात्रा के लिए मीडिया कवरेज की सुविधा भी प्रदान की।

एक्सपीडी प्रभाग ने जनवरी से नवंबर के बीच वीवीआईपी/वीआईपी की 38 आने वाली और 37 जाने वाली यात्राओं को कवर किया। इसके अलावा, चार बहुपक्षीय बैठकों को भी कवर किया गया। इन यात्राओं और चर्चा को प्रभाग द्वारा उचित प्रचार दिया गया। महत्वपूर्ण यात्राओं के मुख्य अंश वीडियो के रूप में तैयार किए गए और विदेश मंत्रालय के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से प्रसारित किए गए। कवर की गई यात्राओं का विवरण अनुलग्नक IX और X में दिया गया है।

विदेशी मीडिया के साथ जुड़ाव

विदेशी मीडिया की सुविधा

एक्सपीडी प्रभाग ने विदेशी पत्रकारों के लिए वीजा, मान्यता और प्रासंगिक परमिट की सुविधा प्रदान की। प्रभाग ने विदेशी मीडिया संगठनों के ओसीआई कार्डधारकों को भारत में पत्रकारिता गतिविधियों को करने के लिए विशेष अनुमति देने की सुविधा भी प्रदान की।

प्रभाग ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा विदेशी मीडिया के लिए ब्रीफिंग की भी व्यवस्था की।

परिचय दौरे

एक्सपीडी प्रभाग ने भारत की सार्वजनिक कूटनीति और मीडिया आउटरीच प्रयासों के एक हिस्से के रूप में विदेशी पत्रकारों के दौरे आयोजित किए। इन यात्राओं का उद्देश्य विदेशी मीडिया के सदस्यों को भारत के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना, देश की प्राथमिकताओं, विकास की कहानी, समकालीन समाज के साथ-साथ इसकी समृद्ध विरासत और जीवंत संस्कृति के बारे में गहरी समझ और जागरूकता को बढ़ावा देना था।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत चालू वर्ष में 91 देशों के कुल 259 पत्रकारों और सामग्री निर्माताओं ने भारत का दौरा किया। इसके अलावा, जुलाई में आसियान-भारत मीडिया एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत 08 भारतीय मीडियाकर्मियों ने लाओ पीडीआर और थाईलैंड का दौरा किया।

डिजिटल आउटरीच

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म

मंत्रालय ने विकसित डिजिटल तकनीकों को अपनाते हुए, सूचना प्रसार और सार्वजनिक जुड़ाव के लिए विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी सुदृढ़ उपस्थिति के साथ मार्ग प्रशस्त किया। विदेश मंत्रालय की विदेश नीति पहलों, वीवीआईपी यात्राओं (आवागमन), द्विपक्षीय और बहुपक्षीय जुड़ाव, सलाह, मीडिया प्रतिक्रियाओं, बयानों और भाषणों पर नियमित और समय पर अपडेट प्रदान किए गए।

मंत्रालय की प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे एक्स (पूर्व में ट्विटर), व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फ्लिकर और साउंडक्लाउड पर प्रभावशाली सोशल मीडिया उपस्थिति है। प्रभाग विदेश मंत्रालय की वेबसाइट का रखरखाव और नियमित रूप से अद्यतन भी करता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह वर्तमान और सूचनात्मक बनी रहे।

एक्स संचार और सूचना के लिए सबसे महत्वपूर्ण माध्यम रहा है। विदेश मंत्रालय के दो एक्स हैंडल हैं-आधिकारिक प्रवक्ता का हैंडल (@MEAIndia) और पब्लिक डिप्लोमेसी हैंडल (@IndianDiplomacy)। @MEAIndia अकाउंट के लगभग 2.3 मिलियन फॉलोअर हैं और @IndianDiplomacy के लगभग 1.5 मिलियन फॉलोअर हैं। @MEAIndia दुनिया भर के सभी विदेश मंत्रालयों के बीच सबसे ज़्यादा फॉलो किए बहिर्गमन एक्स हैंडल में से एक बना हुआ है।

सोशल मीडिया पर लोगों की सक्रियता को बढ़ावा देने की मंत्रालय की नीति के अंतर्गत, 204 भारतीय मिशन/पोस्ट अब एक्स पर हैं, 198 फेसबुक पर, 163 इंस्टाग्राम पर और 117 यूट्यूब पर हैं। इसके अलावा, 35 क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय एक्स से जुड़े हुए हैं। इन प्लेटफॉर्म ने मिशन और पोस्ट को भारतीय समुदाय और प्रवासी समुदाय सहित दुनिया भर के लोगों से प्रभावी ढंग से जुड़ने में सक्षम बनाया है। उन्होंने अपने-अपने देशों में व्यापक सूचना प्रसार के लिए स्थानीय भाषाओं का भी इस्तेमाल किया।

सोशल मीडिया हैंडल ने लक्षित दर्शकों तक त्वरित और कुशल वितरण के लिए रचनात्मक ऑडियो-विजुअल सामग्री (जैसे टेक्स्ट-आधारित, चित्र, लघु वीडियो, रील, इन्फोग्राफिक्स, कोट कार्ड, जीआईएफ और लाइव स्ट्रीमिंग) का उपयोग किया।

प्रेस ब्रीफिंग की लाइव स्ट्रीमिंग और अन्य कार्यक्रमों के वीडियो अपलोड करने के लिए 'एमईएडिआ' यूट्यूबचैनल का उपयोग किया गया। पूर्ण लंबाई वाली डॉक्यूमेंट्री और लघु फिल्मों को इंडियन डिप्लोमेसी यूट्यूबचैनल @IndianDiplomacy के माध्यम से एक विशेष ऑनलाइन उपस्थिति मिली।

विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एमईएके वर्तमान अनुसरणकर्ता (सब्सक्राइबर) हैं:

- फेसबुक-21.6 लाख
- इंस्टाग्राम-9.57 लाख
- लिंक्डइन-73,000

- यूट्यूब एमईए-2.46 लाख
- यूट्यूब इंडियन डिप्लोमेसी-1.56 लाख
- व्हाट्सएप चैनल-27,000

फ्लिकर (एमईएफोटोगैलरी) अकाउंट विदेश मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों, जिनमें विदेश में होने वाले कार्यक्रम भी शामिल हैं, के लिए फोटो संग्रह के रूप में काम करता रहा।

मंत्रालय का मोबाइल एप्लीकेशन (एमईएडिआ) मंत्रालय की नागरिक-केंद्रित सेवाओं और आउटरीच गतिविधियों से संबंधित सभी सूचनाओं के लिए एकल खिड़की स्रोत के रूप में काम करता रहा। यह एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर उपलब्ध है।

मंत्रालय ने विदेश में स्थित मिशनों और पोस्टों के साथ मिलकर विभिन्न सरकारी पहलों और अभियानों पर वैश्विक दर्शकों को जोड़ने के लिए सोशल मीडिया का प्रभावी ढंग से लाभ उठाया। इनमें मन की बात, भारत को जानिए क्विज़, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, एक पेड़ माँ के नाम (प्लांट4मदर), चलो इंडिया और अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस समारोह शामिल थे।

एक्सपीडीप्रभाग ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय सिनेमा को बढ़ावा देना जारी रखा। प्रभाग ने विदेशों में भारत की छवि को सकारात्मक रूप से प्रस्तुत करने के उद्देश्य से वृत्तचित्र भी बनवाए।

विदेश में भारतीय फिल्म समारोह

प्रभाग ने भारतीय मिशनों और पोस्टों द्वारा भारतीय फिल्म समारोहों के आयोजन और विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में इन फिल्मों की स्क्रीनिंग के लिए 34 भारतीय फिल्मों (13 हिंदी, 2 गुजराती, 7 तमिल, 2 कन्नड़, 1 मलयालम, 3 मराठी, 3 पंजाबी, 2 असमिया/बोडो और 1 स्पेनिश/अंग्रेजी) के लिए गैर-वाणिज्यिक स्क्रीनिंग अधिकार हासिल किए। प्रभाग ने जाफना, कोलंबो, ओस्लो और रियाद में फिल्म समारोहों की सुविधा प्रदान की। प्रभाग ने भारतीय फिल्मों और सामग्री की विदेशी भाषाओं में डबिंग, वॉयसिंग और सबटाइटलिंग का समर्थन किया।

प्रभाग ने भारतीय मिशनों/पोस्टों द्वारा भारतीय मीडिया और फिल्म क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय की फिल्मी सामग्री के विकास, संचार और प्रसार या डीसीडीएफसी योजना के प्रभावी कार्यान्वयन की सुविधा भी प्रदान की।

वृत्तचित्र

निम्नलिखित वृत्तचित्र/लघु फिल्में बनाई गईं और आधिकारिक यूट्यूब चैनल 'इंडियन डिप्लोमेसी' पर अपलोड की गईं:

1. भारत-बिम्स्टेक पर लघु फिल्म
2. भारत और अफ्रीका पर लघु फिल्म
3. हाल के आम चुनावों पर लघु फिल्म 'इंडिया वोट्स'।
4. 'नालंदा विश्वविद्यालय' पर लघु फिल्म।

5. 'वट फो में मंदिरों के जीर्णोद्धार' पर लघु फिल्म।
6. 'आसियान देशों में मंदिरों के जीर्णोद्धार' पर लघु फिल्म।
7. यूएसए से 297 पुरावशेषों के प्रत्यावर्तन पर लघु फिल्म 'प्राचीन वस्तुओं की वापसी'।

प्रभाग ने भारत और वैश्विक दक्षिण पर एक वृत्तचित्र भी बनवाया।

लेख

एक्सपीडीप्रभाग ने 78^{वें} स्वतंत्रता दिवस और 75^{वें} गणतंत्र दिवस के अवसर पर विभिन्न विषयों पर लेख आमंत्रित किए। ये लेख सेवानिवृत्त भारतीय राजनयिकों और प्रख्यात विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए थे और इन्हें उनके संबंधित देशों में भारतीय मिशन/पोस्टों द्वारा प्रकाशित किया गया था।

भारत परिप्रेक्ष्य पत्रिका

एक्सपीडीप्रभाग ने मंत्रालय की प्रमुख पत्रिका, भारत परिप्रेक्ष्य को नया रूप देने की पहल की। यह पत्रिका 35वर्ष से भी पहले शुरू की गई थी, जिसका पहला अंक जुलाई 1988 में प्रकाशित हुआ था। तब से यह पत्रिका 16 भाषाओं-अरबी, इंडोनेशियाई भाषा, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, इतालवी, जापानी, पश्तो, फारसी, पुर्तगाली, रूसी, सिंहल, स्पेनिश और तमिल में प्रकाशित हो चुकी है।

'एकपेड़मांकेनाम' (प्लांट4मदर)

'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के नोडल बिंदु के रूप में, एक्सपीडीप्रभाग ने विदेश में मिशन/पोस्टों द्वारा इस अभियान के विश्वव्यापी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया। आज तक, भारत में भारतीय मिशन/केंद्रों के साथ-साथ क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा 27,000 से अधिक पेड़ लगाए जा चुके हैं।

काँफी टेबल बुक्स और बुकलेट

प्रभाग ने संयुक्त राज्य अमेरिका से भारतीय कलाकृतियों के प्रत्यावर्तन पर एक सीमित संस्करण की काँफी टेबल बुक तैयार की है, जिसका शीर्षक है 'प्राचीन वस्तुओं को वापस लाना: भारत की सांस्कृतिक विरासत को पुनः प्राप्त करना'। इस पुस्तक में 2000 ईसा पूर्व से 19^{वीं} शताब्दी तक के भारतीय इतिहास की एक विशाल समयरेखा को शामिल करते हुए 297 प्राचीन वस्तुओं की वापसी की सूची दी गई है, जिन्हें 21-23 सितंबर को प्रधानमंत्री की संयुक्त राज्य अमेरिका यात्रा के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भारत को सौंपा गया था।

प्रभाग ने 'एंगेजिंग द वर्ल्ड' शीर्षक से एक पॉकेट-साइज़ सूचना पुस्तिका तैयार की। इसमें द्विपक्षीय और बहुपक्षीय जुड़ाव, राहत और बचाव मिशन, नागरिक-केंद्रित सेवाओं, विकास साझेदारी और प्रवासी जुड़ाव के क्षेत्र में

वर्ष 2014 से 2024 तक की विदेश नीति उपलब्धियों के एक दशक को शामिल किया गया है।

पुस्तक समिति

44^{वाँ} पुस्तक समिति ने विदेश स्थित मिशन/पोस्टों द्वारा प्रचार-प्रसार के लिए 370 पुस्तकों के शीर्षक चुने। शीर्षकों में भारतीय क्लासिक्स, विदेश नीति और सामरिक मामले, प्रौद्योगिकी और लोकप्रिय विज्ञान, हिंदी और संस्कृत, कला और संस्कृति, धर्म और अध्यात्म, बच्चों की पुस्तकें और राजनीति और अर्थव्यवस्था जैसी श्रेणियां शामिल थीं। 95 मिशन/पोस्टों से इन शीर्षकों की लगभग 37,000 प्रतियों की मांग प्राप्त हुई।

बच्चों की पुस्तकें

युवाओं को जोड़ने और उन्हें कहानी सुनाने के माध्यम से भारतीय इतिहास, कला, संस्कृति और विरासत से परिचित कराने के लिए, एक्सपीडीप्रभाग ने जातक कथाओं और अन्य कहानियों वाली बच्चों की पुस्तकों का विदेशी भाषाओं में अनुवाद करने की भारतीय मिशन/पोस्टों की पहल का समर्थन किया। पाँच अमर चित्र कथा (एसीके) जातक कथाएँ कॉमिक पुस्तकों का नौ विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया। इसके अतिरिक्त, छह एसीकेजातक कथाएँ कॉमिक पुस्तकों का नॉर्वेजियन भाषा में अनुवाद किया जा रहा है।

इंडिया कॉर्नर

एक्सपीडी प्रभाग ने विदेशों में स्कूलों, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और सार्वजनिक पुस्तकालयों में इंडिया कॉर्नर स्थापित करना जारी रखा है। पिछले एक वर्ष में, सियोल, म्यूनिख, अबुजा, एरबिल, सिएटल, अबिदजान, लागोस, बेलग्रेड, जॉर्जटाउन, कैडी, ब्रासीलिया, नोम पेन्ह, मॉस्को, दुबई और हो ची मिन्ह सिटी में 15 भारतीय मिशन/पोस्टों को संबंधित देशों के विभिन्न स्कूलों और विश्वविद्यालयों में 50 से अधिक इंडिया कॉर्नर स्थापित करने के लिए पुस्तकें प्रदान की गईं।

विदेश में सार्वजनिक कूटनीति पहलों का समर्थन करना

- एक्सपीडी प्रभाग ने विदेश में मिशन/केंद्रों की कई सार्वजनिक कूटनीति पहलों का समर्थन करना जारी रखा, जैसे कि
- भारतीय दूतावास सैंटो डोमिंगो द्वारा राजनयिक संबंधों के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में लोगो डिजाइन प्रतियोगिता;
- भारतीय महावाणिज्य दूतावास जोहान्सबर्ग द्वारा गॉर्डन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस साइंस (जीआईबीएस), यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिटोरिया की एक्यूमेन पत्रिका के भारत संस्करण का प्रकाशन;

- भारतीय दूतावास वारसॉ द्वारा राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70^{वीं} वर्षगांठ के अवसर पर कार्यक्रमों का आयोजन;
- भारतीय दूतावास बैंकॉक द्वारा 'थाईलैंड में भारतीय प्रवासियों के मौखिक इतिहास' पर एक अकादमिक शोध परियोजना;
- भारतीय दूतावास अबू धाबी द्वारा भारत मजलिस 3.0 कार्यक्रम की मेजबानी;
- भारतीय दूतावास हेलसिंकी द्वारा राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75^{वीं} वर्षगांठ के अवसर पर कार्यक्रम;
- भारतीय दूतावास मिन्स्क द्वारा मिन्स्क अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 30^{वें} संस्करण "लिस्टापैड" में प्रदर्शनी;
- भारतीय दूतावास, मिन्स्क द्वारा भारतीय मूवी सप्ताह;
- भारतीय दूतावास ब्यूनस आयर्स द्वारा भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्पेनिश भाषा में रेडियो निकेतन कार्यक्रम।

विशिष्ट व्याख्यान श्रृंखला

एक्सपीडी प्रभाग ने विशिष्ट व्याख्यान श्रृंखला (डीएलएस) कार्यक्रम को नया रूप दिया। यह कार्यक्रम भारत के विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक

संस्थानों को देश भर के छात्रों और युवाओं के बीच भारत के विदेशी मामलों, इसकी उपलब्धियों और चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए जोड़ता है। यह कार्यक्रम एक सामरिक संचार उपकरण के रूप में भी काम करता है जिसका उद्देश्य भारतीय विदेश नीति के साथ-साथ मंत्रालय की जन-केंद्रित पहलों के बारे में सकारात्मक आख्यान तैयार करना है।

समीप पहल

एक्सपीडी प्रभाग ने समीप व्याख्यानों का आयोजन जारी रखा। जनवरी 2018 में शुरू किया गया समीप, सेवारत भारतीय राजनयिकों को उनके विद्यालय में आने का समर्थन करता है ताकि वे अपने अनुभव, भारत की विदेश नीति के प्रमुख तत्वों और विदेश मंत्रालय की भूमिका और कार्यों को स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों के साथ साझा कर सकें। समीप व्याख्यान रायपुर (छत्तीसगढ़), बस्ती (उत्तर प्रदेश) और चेन्नई (तमिलनाडु) में आयोजित किए गए।

अध्याय

28

प्रशासन, स्थापना, वैश्विक संपदा प्रबंधन और सूचना का अधिकार

प्रशासन

विदेश मंत्रालय में प्रशासन प्रभाग अपने मुख्यालय और विदेश में भारतीय मिशन/पोस्टों में मानव संसाधन प्रबंधन और क्षमता निर्माण के लिए उत्तरदायी है। इसमें भर्ती, प्रशिक्षण, पोस्टिंग/स्थानांतरण, प्रतिनियुक्ति और कैरियर की प्रगति सहित कैडर प्रबंधन अभ्यासों की देखरेख करना शामिल है। प्रभाग को विदेश में तैनात भारतीय कर्मियों और भारतीय मिशनों और पोस्टों में सेवारत स्थानीय कर्मचारियों से संबंधित नियमों और विनियमों को तैयार करने और संशोधित करने का भी काम सौंपा गया है।

01 दिसंबर तक, मंत्रालय की वर्तमान स्वीकृत जनशक्ति 4772 (परिशिष्ट I) है। इसमें से, 54.2% कार्मिक विदेश में मिशनों और पोस्टों में स्थित हैं। ये पद मंत्रालय के भीतर विभिन्न संवर्गों में हैं, जैसे कि भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस), आईएफएससामान्य संवर्ग, शाखा बी, आशुलिपिक संवर्ग, दुभाषिया संवर्ग और विधिक और संधि संवर्ग, अन्य। मंत्रालय समय-समय पर अपने प्रभागों और उनकी जिम्मेदारियों को पुनर्गठित करता है, ताकि नए विकास और कार्यात्मक प्राथमिकताओं के अनुकूल हो सके।

वर्ष 2024 के दौरान, मंत्रालय ने लातविया, जॉर्जिया, गैबॉन गणराज्य और तिमोर-लेस्ते में नए मिशन खोले हैं। ऑकलैंड (न्यूजीलैंड), बार्सिलोना (स्पेन), बेलफास्ट (यूनाइटेड किंगडम), ब्रिसबेन (ऑस्ट्रेलिया), मैनचेस्टर

(यूनाइटेड किंगडम) और मार्सिले (फ्रांस) में नए वाणिज्य दूतावास खोले गए हैं, जिन्होंने इस वर्ष अपना संचालन भी शुरू कर दिया है। ये मिशन और पोस्ट प्रमुख साझेदार देशों में भारत की उपस्थिति स्थापित करेंगे, राजनयिक पहुंच को सुदृढ़ करेंगे, भारत की विदेश नीति के लक्ष्यों को आगे बढ़ाएंगे और मंत्रालय को भारतीय प्रवासियों के लिए सेवाओं का विस्तार करने में सक्षम बनाएंगे।

प्रशासनिक प्रभाग प्रौद्योगिकी के सक्रिय उपयोग के माध्यम से दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है जैसे कि विदेश मंत्रालय ई-समीक्षा पोर्टल, जो मुख्यालय और मिशनों/पोस्टों के बीच एक ऑनलाइन इंटरफ़ेस प्रदान करता है, विदेश मंत्रालय डिजिटल ऑनलाइन कार्य प्रणाली (एमईएडीओडब्ल्यूएस), जिसका उपयोग स्थानांतरण संबंधी मामलों के लिए किया जाता है, और आधिकारिक कार्य के लिए ई-ऑफिस। यह मंत्रालय के घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी विभिन्न इकाइयों के बीच संचार और समन्वय को अनुकूलित करने के लिए अभिनव दृष्टिकोण को भी दर्शाता है। प्रभाग अपने जनशक्ति और वाहन आपूर्तिकर्ताओं को काम पर रखने के लिए सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) पोर्टल का उपयोग करता है।

यह प्रभाग कर्मियों के क्षमता निर्माण पर भी समर्पित रूप से काम करता है। मंत्रालय की क्षमता निर्माण योजना को 2024 में अपनाया गया और उसे क्रियान्वित किया गया। मंत्रालय के सभी सदस्यों को बहुआयामी

प्रशिक्षण के लिए आईगोटकर्मयोगीपोर्टल पर सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया गया। नए भर्ती किए गए लोगों के लिए प्रस्थान-पूर्व प्रशिक्षण और मेंटरशिप कार्यक्रम संस्थागत रूप से शुरू किए गए हैं ताकि वे अपनी नई भूमिकाओं के अनुकूल बन सकें।

विदेश मंत्रालय का इंटरनशिप कार्यक्रम विदेश नीति को नागरिकों के करीब लाने और विदेश नीति निर्माण और निर्णय लेने में योगदान के लिए युवाओं को शामिल करने का काम जारी रखता है। विदेश मंत्रालय के इंटरनशिप कार्यक्रम को 2024 में उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली और साठ (60) छात्रों को दो कार्यकालों में इंटरनशिप की पेशकश की गई, जो विदेश नीति और कूटनीति में भविष्य की प्रतिभाओं को पोषित करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

विदेश मंत्रालय के अंतर्गत अपने आवश्यक उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए प्रशासन प्रभाग का दृष्टिकोण मानव संसाधनों के कुशल प्रबंधन, राजनयिक सहभागिता के सामरिक विस्तार, जन-केन्द्रित पहलों पर ध्यान केन्द्रित करने तथा आधुनिक प्रौद्योगिकीय उपकरणों को अपनाने पर आधारित है, जो मंत्रालय की उदीयमान प्राथमिकताओं को संबोधित करने में इसकी गतिशील, सक्रिय तथा अग्रगामी रणनीति को प्रदर्शित करता है।

स्थापना

स्थापना प्रभाग मंत्रालय के कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका काम कर्मचारियों को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में दैनिक सहायता प्रदान करना है, जिसमें कार्यालय स्थान, फर्नीचर, उपकरण, स्टेशनरी, टेलीफोन, समाचार-पत्र, आवास, सभी भवनों और उपयोगिताओं का रखरखाव और मरम्मत शामिल है। यह प्रभाग विदेशों में भारतीय मिशनों और पोस्टों को भी सेवाएं प्रदान करता है, जिसमें उनकी स्थापना-संबंधी आवश्यकताएं, वाहनों की खरीद, विभिन्न उपयोगिताओं के लिए अनुबंध और उनके कामकाज के लिए आवश्यक अन्य सेवाएं शामिल हैं। यह प्रभाग मिशनों और पोस्टों को ऑब्जेक्ट डी'आर्ट (ओडी'ए) भी प्रदान करता है और यह प्रधानमंत्री, मंत्रियों और अधिकारियों द्वारा विदेशों से प्राप्त उपहारों का भंडार है।

इन कार्यों के निर्वहन में, स्थापना प्रभाग ने मुख्य रूप से सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पोर्टल से एक पारदर्शी खरीद प्रक्रिया का पालन किया, जिसमें कार्यालय और आवासीय भवनों के रखरखाव के लिए एकीकृत सुविधा प्रबंधन सेवाओं के लिए अनुबंध प्रदान करना शामिल है। मंत्रालय के एकीकृत वित्त प्रभाग (आईएफडी) के परामर्श से इन प्रक्रियाओं और प्रक्रियाओं को और अधिक सुव्यवस्थित किया गया। इसके अलावा, प्रधान लेखा-नियंत्रक के परामर्श से, लगभग 150 लंबित लेखापरीक्षा अनुच्छेदों और टिप्पणियों पर उनके शीघ्र समाधान के लिए चर्चा की गई।

तोशाखाना से, प्रभाग ने ई-नीलामी के लिए वस्तुओं की पहचान की है, जो भारतीय नागरिकों के लिए खुली हैं, और आय को सार्वजनिक या धर्मार्थ कार्यों के लिए देने का प्रस्ताव है। पायलट ई-नीलामी के लिए पोर्टल तैयार है।

स्थापना प्रभाग स्वच्छता मिशन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। 13 सितंबर से 02 अक्टूबर 2024 तक, 'स्वच्छता ही सेवा अभियान' 2024 के अंतर्गत, प्रभाग ने विदेशों में स्थित मिशनों और पोस्टों तथा भारत में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों के साथ मिलकर 1085 'जनभागीदारी' गतिविधियां, 282 स्वच्छता लक्षित इकाइयां, 'सफाई मित्रों' के लिए 81 चिकित्सा शिविर आयोजित किए तथा 'एक पेड़ मां के नाम' वृक्षारोपण अभियान चलाया। प्रभाग पुराने वाहनों सहित निष्प्रयोज्य और अप्रचलित वस्तुओं की नीलामी के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) मेटल स्ट्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन लिमिटेड (एमएसटीसी) के साथ काम कर रहा है।

विदेश सचिव के आधिकारिक आवास का नवीनीकरण किया जा रहा है। अधिकारियों और कर्मचारियों के अल्प प्रवास के लिए पारगमन सुविधाओं का उन्नयन किया जा रहा है। प्रभाग ने चाणक्यपुरी आवासीय परिसर में एक क्रेच सुविधा स्थापित की है। कॉमनवेल्थ गेम्स (सीडब्ल्यूजी) और द्वारका आवासीय परिसरों में भी क्रेच सुविधाएं स्थापित की जा रही हैं। चाणक्यपुरी आवासीय परिसर में एक सीजीएसएसक्लिनिक खोला गया। आपातकालीन उपयोग के लिए विदेश मंत्रालय के भवनों में कई स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा किट लगाई गई हैं।

वैश्विक संपदा प्रबंधन (जीईएम)

वैश्विक संपदा प्रबंधन प्रभाग ने विदेशों में भारतीय मिशनों और पोस्टों, तथा भारत में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों, आईसीसीआर, पीओई और शाखा सचिवालयों के लिए संपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण, पुनर्विकास और नवीनीकरण का काम सक्रिय रूप से किया। मंत्रालय के अधिकारियों के लिए नई दिल्ली में उपलब्ध आवासीय आवास को बढ़ाने की पहल को आगे बढ़ाया गया, ताकि ऐसे आवास की उपलब्धता में मौजूदा कमी को प्रभावी ढंग से संबोधित किया जा सके और दीर्घावधि में आवास आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

रोम (चांसरी के लिए), ओस्लो (चांसरी के लिए) और ज़ाग्रेब (दूतावास निवास के लिए) में निर्मित संपत्तियों का अधिग्रहण सफलतापूर्वक पूरा किया गया। तेल अवीव (ईआर और चांसरी), मार्सिले (चांसरी), सेंट पीटर्सबर्ग (चांसरी) और लिलोंगे (चांसरी), मबाबे (चांसरी और निवास), अकरा (चांसरी), तेहरान (चांसरी), फिज़ी (चांसरी, सांस्कृतिक केंद्र और अन्य निवास) और जॉर्जटाउन में एक भूखंड पर निर्मित संपत्तियों के अधिग्रहण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई।

प्रमुख परियोजनाएं जैसे भारतीय उच्चायोग (एचसीआई), ब्रुनेई के लिए चांसरी, ईआर और कर्मचारी आवासों का निर्माण अगस्त 2023 में पूरा हो गया, और भारतीय दूतावास (ईओआई), अम्मान में ईआर का पुनर्विकास मार्च में पूरा हो गया। अम्मान (पुराने चांसरी का पुनर्विकास), कुआलालंपुर (चांसरी और आवासों का पुनर्विकास), सेशेल्स (चांसरी, संस्कृति केंद्र और आवासों का पुनर्विकास), जकार्ता (चांसरी, ईआर और कर्मचारी आवासों का पुनर्विकास), फुएंत्सोलिंग (चांसरी और आवासों का निर्माण) में चल रही

निर्माण परियोजनाएं संतोषजनक ढंग से आगे बढ़ रही हैं। सीजीआई, जेद्दा में चांसरी सह आवासीय परिसर का निर्माण शुरू होने वाला है।

1 जनवरी 2024 के बाद डिज़ाइन अनुभाग में शुरू की गई प्रमुख परियोजनाएँ एथेंस (इंडिया हाउस का पुनर्विकास), अबुजा (अतिरिक्त आवासों का निर्माण), वाशिंगटन (चांसरी कॉम्प्लेक्स का निर्माण), द हेग (चांसरी बिल्डिंग का पुनर्विकास), हेलसिंकी (बहुउद्देशीय हॉल सह कौंसली क्षेत्र का निर्माण), थिम्पू (चांसरी एनेक्स परियोजना का निर्माण) हैं।

पुनर्विकास और नवीनीकरण के मोर्चे पर उल्लेखनीय उपलब्धियों में जकार्ता (इंडिया हाउस), कंपाला (इंडिया हाउस की चारदीवारी की मरम्मत), कुवैत (चांसरी में ऑडिटोरियम का नवीनीकरण), न्यूयॉर्क (पीएमआई बिल्डिंग के अग्रभाग का नवीनीकरण) और प्रिटोरिया (डीएचसी का निवास) में प्रमुख नवीनीकरण का पूरा होना शामिल है। कोलेबो (चांसरी), कुवैत (चांसरी), मास्को (डीसीएम निवास, चांसरी और दूतावास निवास), न्यूयॉर्क (चांसरी-सह-सीजी निवास), प्राग (दूतावास निवास), प्रिटोरिया (चांसरी भवन का विस्तार), रोम (चांसरी भवन), द हेग (इंडिया हाउस और डीसीएम निवास) और वियना (दूतावास निवास) में प्रमुख मरम्मत/नवीनीकरण परियोजनाएं शुरू की गई हैं और प्रगति पर हैं।

वर्ष के दौरान आरपीओ बेंगलुरु और भुवनेश्वर परिसर का नवीनीकरण पूरा किया गया। कोलकाता, श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर) में नए आरपीओ परिसर और आईएनए, नई दिल्ली में एक आवासीय परिसर के लिए प्रमुख निर्माण परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

मंत्रालय ने वी. के. कृष्ण मेनन भवन (आईएसआईएल भवन), नई दिल्ली की चौथी मंजिल पर एक स्थायी मध्यस्थता न्यायालय की स्थापना भी की है, जिसे कैलेंडर वर्ष के अंत तक पूरा किया जाना है।

सूचना का अधिकार अधिनियम

मंत्रालय का आरटीआई सेल सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रसंस्करण का नेतृत्व करता है। आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 4(बी) का पालन करते हुए मंत्रालय सार्वजनिक डोमेन में अधिकतम जानकारी अपलोड और नियमित रूप से अपडेट करता है। मंत्रालय और विदेशों में इसके 203 मिशन/पोस्ट ऑनलाइन और भौतिक आरटीआई आवेदन स्वीकार कर रहे हैं और समयबद्ध तरीके से उनका निपटान कर रहे हैं।

आरटीआई अधिनियम 2005 के अंतर्गत कुल 3291 आरटीआई आवेदन और 182 प्रथम अपील मंत्रालय में 01 जनवरी से 31 दिसंबर तक संसाधित किए गए। आवेदन विदेशी संबंधों, प्रशासनिक मुद्दों, द्विपक्षीय यात्राओं और अन्य प्रासंगिक विषयों जैसे विषयों में भिन्न थे।

इस अवधि के दौरान, संबंधित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) और प्रभाग के एक प्रतिनिधि ने कुल 83 केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) की सुनवाई में भाग लिया। सभी सुनवाई मामलों का संतोषजनक ढंग से निपटारा किया गया। निर्धारित अवधि के भीतर सीआईसी के साथ तिमाही रिटर्न दाखिल किए गए हैं। सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान (एसएसआईएफएस) के सहयोग से, मंत्रालय और विदेश स्थित मिशनों/केंद्रों ने समयबद्ध तरीके से तृतीय पक्ष लेखापरीक्षा (स्वतः प्रकटीकरण) में भाग लिया।

अध्याय

29

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

भारत सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन हमेशा से मंत्रालय की प्राथमिकता रही है। इसे भारत के साथ-साथ विदेशों में भी हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए एक व्यापक योजना के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

विदेशों में हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए विदेश स्थित भारतीय मिशनों/केंद्रों, पीआईओ और एनआरआई निकायों, स्थानीय गैर सरकारी संगठनों, सांस्कृतिक संगठनों और संघों को शामिल करते हुए एक विस्तृत नेटवर्क बनाया गया है। राजभाषा और भारतीय भाषाविज्ञान, सूचना एवं प्रौद्योगिकी (आरबीबीएंडआईटी) प्रभाग ने हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए विदेश स्थित मिशनों और केंद्रों को शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई। मंत्रालय ने इस अवधि के दौरान हिंदी कक्षाएं संचालित करने के लिए शिक्षकों को नियुक्त करने के लिए विदेश स्थित मिशनों/केंद्रों को लगभग 88.80 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की।

यह प्रभाग केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा में हिंदी का अध्ययन करने के लिए विदेशी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने से संबंधित कार्यों का समन्वय भी करता है। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों (आरपीओ) में हिंदी भाषा के प्रगतिशील उपयोग की निगरानी की जिम्मेदारी भी प्रभाग को सौंपी गई है। वर्ष के दौरान, प्रभाग द्वारा चार आरपीओ निरीक्षण सफलतापूर्वक किए गए, अर्थात् 28-30 मई तक कोच्चि और त्रिवेंद्रम, तथा 11-13 जून 2024 तक चंडीगढ़ और शिमला।

वर्ष के दौरान, संसदीय राजभाषा समिति की प्रथम उप-समिति ने मंत्रालय के स्वायत्त/अधीनस्थ कार्यालयों तथा 4 क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों का निरीक्षण किया। निरीक्षण का उद्देश्य मंत्रालय/अधीनस्थ कार्यालयों के आधिकारिक

कार्यों में हिंदी के प्रगतिशील प्रयोग पर केंद्रित था तथा राजभाषा के प्रयोग को और अधिक बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय सुझाए गए।

विदेश में हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए समय-समय पर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय हिंदी सम्मेलन (आईआरएचसी) आयोजित किए गए। क्षेत्रीय हिंदी सम्मेलनों का आयोजन हमारे विदेश स्थित मिशनों द्वारा हिंदी और भारतीय संस्कृति के प्रचार-प्रसार में लगी स्थानीय संस्थाओं के सहयोग से किया जाता है। 10 जनवरी को हमारे सभी विदेश स्थित मिशनों और केन्द्रों तथा मुख्यालय में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। हिंदी दिवस 2024 के उपलक्ष्य में हिंदी पखवाड़ा आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों तथा विदेश स्थित हमारे मिशन और केन्द्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विश्व हिंदी दिवस के लिए मिशनों/केन्द्रों को 2.4 करोड़ रुपये तथा हिंदी दिवस/हिंदी पखवाड़ा समारोह के लिए 2.2 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई। इस अवसर पर हिंदी निबंध लेखन, हिंदी टिप्पण एवं प्रारूपण, हिंदी कविता प्रतियोगिता, राजभाषा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता और हिंदी वाक्यांश अनुवाद प्रतियोगिता सहित विभिन्न प्रतियोगिताएं और गतिविधियां आयोजित की गईं।

हिंदी और भारतीय संस्कृति के प्रचार-प्रसार में कार्यरत स्थानीय संस्थानों या विश्वविद्यालयों के सहयोग से हमारे मिशनों/केंद्रों द्वारा आईआरएचसी का आयोजन किया गया। इस अवधि के दौरान, चार आईआरएचसी का आयोजन इस प्रकार किया गया: (i) टोक्यो में हमारे मिशन ने टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज के सहयोग से फरवरी में “दक्षिण पूर्व एशिया में हिंदी की स्थिति” पर एक आईआरएचसी का आयोजन किया;

(ii) अस्ताना में हमारे मिशन ने अल-फराबी कजाख राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, अल्माटी के सहयोग से मार्च में “यूरेशिया और भारत में हिंदी: वर्तमान और भविष्य” पर एक आईआरएचसी का आयोजन किया; (iii) पोर्ट ऑफ स्पेन में हमारे मिशन ने सितंबर में लिनिदाद और टोबैगो इंक (हिंदी निधि) के हिंदी फाउंडेशन के सहयोग से एक आईआरएचसी का आयोजन किया और (iv) सिंगापुर में हमारे मिशन ने सितंबर में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ

सिंगापुर (एनयूएस) के सहयोग से एक आईआरएचसी का आयोजन किया।

इस अवधि के दौरान, प्रभाग ने मंत्रालय के मुख्यालय और विदेश में हमारे मिशनों और केन्द्रों के विभिन्न प्रभागों से प्राप्त अनुरोधों के अनुसार, अंग्रेजी से हिंदी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कार्य समय पर किया।

अध्याय

30

वित्त एवं बजट

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए विदेश मंत्रालय को आवंटित कुल बजट अनुमान (बीई) चरण में 22154.67 करोड़ रुपये है।

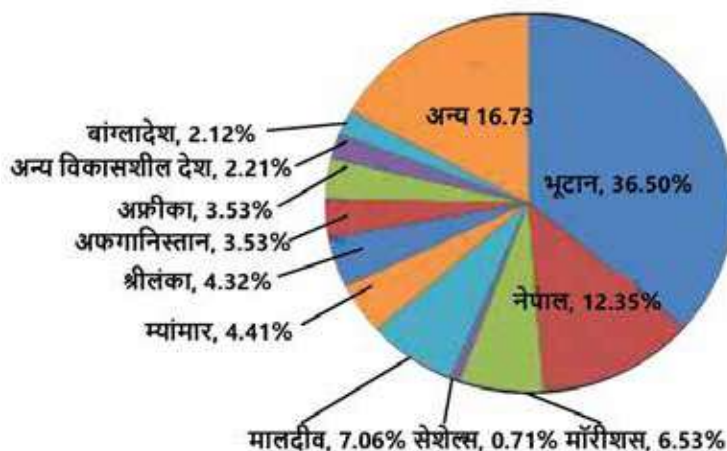
प्रमुख आवंटनों के लिए बजट का क्षेत्रीय वितरण नीचे उल्लिखित है:

क्षेत्र		आवंटन (करोड़ रुपये में)
विदेशी देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग (टीईसी)	अनुदान	4677.86
	ऋण	989.70
	कुलटीईसी	5667.56
विदेश में भारतीय मिशन और पोस्ट		3867.64
विशेष राजनयिक व्यय		4659.01
पासपोर्ट और प्रवास		970.66
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग		659.32
सार्वजनिक निर्माण और आवास पर पूंजीगत व्यय		574.00
विदेश मंत्रालय सचिवालय		789.68
स्वायत्त निकायों और अन्य संस्थानों को सहायता		369.85
आरक्षित निधि (गारंटी मोचन निधि) में स्थानांतरण		4383.40
अन्य		213.55
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कुल बजट अनुमान		22154.67

विकास भागीदारी पोर्टफोलियो (या तकनीकी और आर्थिक सहयोग) जो विभिन्न देशों को भारत की सहायता का गठन करता है, मंत्रालय के बजट में सबसे बड़े आबंटन के साथ फोकस और प्राथमिकता बना हुआ है। वित्त वर्ष 2024-25 में, 22154.67 करोड़ रुपये के कुल बजट में से, तकनीकी और

आर्थिक सहयोग शीर्ष (टीईसी) परिव्यय 25.58% या 5667.56 करोड़ रुपये है, जिसमें से 4677.86 करोड़ रुपये (21.11%) अनुदान कार्यक्रमों के लिए और 989.70 करोड़ रुपये (4.47%) ऋण के लिए हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में टीईसीपरिव्यय का शीर्ष-वार वितरण नीचे दिया गया है:

तकनीकी और आर्थिक सहयोग (टीईसी) प्रमुख		आबंटन (करोड़ रुपये में)	कुल टीईसी आबंटन का %
बांग्लादेश को सहायता		120.00	2.12 %
भूटान	अनुदान	1078.86	36.50 %
	ऋण	989.70	
	कुल भूटान	2068.56	
नेपाल को सहायता		700.00	12.35 %
मॉरीशस को सहायता		370.00	6.53 %
अफगानिस्तान को सहायता		200.00	3.53 %
सेशेल्स को सहायता		40.00	0.71 %
म्यांमार को सहायता		250.00	4.41 %
आईटीईसी कार्यक्रम		160.00	2.82 %
अफ्रीकी देशों को सहायता		200.00	3.53 %
श्रीलंका को सहायता		245.00	4.32 %
चाहबहार बंदरगाह, ईरान		100.00	1.76 %
मालदीव को सहायता		400.00	7.06 %
अन्य विकासशील देशों को सहायता		125.00	2.21 %
निवेश प्रोत्साहन और प्रचार कार्यक्रम		539.00	9.51 %
भारत-प्रशांत सहयोग		50.00	0.88 %
यूरोशियाई देशों को सहायता		20.00	0.35 %
बहुपक्षीय आर्थिक संबंध कार्यक्रम		10.00	0.18 %
लैटिन अमेरिकी देशों को सहायता		30.00	0.53 %
आपदा राहत के लिए सहायता		10.00	0.18 %
सार्क कार्यक्रम		5.00	0.09 %
मंगोलिया को सहायता		5.00	0.09 %
सांस्कृतिक और विरासत परियोजनाओं के लिए सहायता		15.00	0.26 %
क्वाड सहयोग		5.00	0.09 %
कुल			5667.56



मंत्रालय के विकास साझेदारी बजट का बड़ा हिस्सा, जो लगभग 70% है, सरकार की “पड़ोस पहले” नीति के अंतर्गत पड़ोसी देशों को आवंटित किया जाता है, इसके बाद विस्तारित हिंद महासागर क्षेत्र (7.24%), विस्तारित पड़ोस (4%), अफ्रीका (3.53%), लैटिन अमेरिकी देशों (0.53%) को आवंटन किया जाता है, तथा शेष राशि अन्य क्षेत्रों या क्षेत्र-विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए जाती है।

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कुल 22154.67 करोड़ रुपये के बजट में से

स्थापना शीर्षों और गैर-स्थापना शीर्षों के बीच आवंटन का विभाजन क्रमशः 25.52% (5655.46 करोड़ रुपये) और 74.48% (16499.21 करोड़ रुपये) है। मंत्रालय ने स्थापना शीर्षों पर अपने व्यय को लगातार अपने कुल बजट के 30% के भीतर बनाए रखा है।

मंत्रालय पिछले दस वित्तीय वर्षों से वित्तीय वर्ष के संशोधित अनुमान (आरई) चरण में आवंटित धनराशि का इष्टतम उपयोग करता रहा है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	बीई आवंटन	आरई आवंटन	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान के % के रूप में उपयोग	संशोधित अनुमान के % के रूप में उपयोग
	करोड़ रुपये में; पूर्णांकित				
2013-14	11719	11794	11807	101 %	100 %
2014-15	14730	12620	12149	82 %	96 %
2015-16	14967	14967	14541	97 %	97 %
2016-17	14663	13426	12772	87 %	95 %
2017-18	14798	13690	13750	93 %	100 %
2018-19	15011	15582	15526	103%	99%
2019-20	17885	17372	17272	97%	99%
2020-21	17347	15000	14362	83%	96%
2021-22	18155	16000	14174	78%	89%
2022-23	17250	16973	16685	97%	98%
2023-24	18050	29122	29003	161%	99%

वार्षिक रिपोर्ट | 2024

वित्त वर्ष 2023-24 में मंत्रालय को पासपोर्ट सेवाओं (3543.66 करोड़ रुपये), वीजा शुल्क (1396.91 करोड़ रुपये) और अन्य प्राप्तियों (881.59 करोड़ रुपये) से 5822.16 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियां होंगी। वित्त वर्ष 2019-2020 से वित्त वर्ष 2023-2024 तक पिछले पांच वित्तीय वर्षों के लिए राजस्व प्राप्तियां नीचे दी गई हैं:

वर्ष	शीर्ष	राशि (करोड़ रु. में)	प्रतिशत
2019-20	पासपोर्ट	2522.71	49%
	वीजा	1792.11	35%
	अन्य	856.16	17%
	योग	5170.98	
2020-21	पासपोर्ट	583.56	77%
	वीजा	24.85	3%
	अन्य	149.73	20%
	योग	758.14	
2021-22	पासपोर्ट	2332.50	66%
	वीजा	316.93	9%
	अन्य	874.18	25%
	योग	3523.61	
2022-23	पासपोर्ट	3360.03	59%
	वीजा	1440.10	25%
	अन्य	937.89	16%
	योग	5738.02	
2023-24	पासपोर्ट	3543.66	61%
	वीजा	1396.91	24%
	अन्य	881.59	15%
	योग	5822.16	

वर्ष 2023-24 के दौरान, विदेश मंत्रालय के विरुद्ध एक (01) सीएंडएजी पैरा को सीएंडएजी रिपोर्ट संख्या 25/2023 में शामिल किया गया था। वर्ष 2023-2024 के दौरान, विदेश मंत्रालय के विरुद्ध 12 पीएसीअवलोकन/सिफारिशें भी पीएसी (2023-24) 17^{वीं} लोकसभा की 80^{वीं} और 87^{वीं} रिपोर्ट में शामिल की गई। सीएंडएजी पैरा के संबंध में 2018 से कार्रवाई नोट (एटीएन) प्रस्तुत करने की स्थिति और पीएसीपैरा के संबंध में अंतिम कार्रवाई उत्तर प्रस्तुत करने की स्थिति निम्नानुसार है:

वर्ष	सीएंडएजीरिपोर्ट	पैराग्राफ की कुल संख्या	अंतिम एटी-एनप्रस्तुत	प्रक्रियाधीन
2018	2018 की रिपोर्ट संख्या 4	5	5	शून्य
2019	विदेश मंत्रालय के लिए सीएंडएजी-द्वारा कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की गई	-	-	-
2020	2020 की रिपोर्ट संख्या 6	4	4	शून्य
2021	2021 की रिपोर्ट संख्या 2	5	5	दो सीएंडएजीपैरा (5.3 और 5.4) के लिए, लेखापरीक्षा महानिदेशक के कार्यालय ने पैरा को “लेखापरीक्षा द्वारा टिप्पणियों की जांच” से “संसद में रखे गए” श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया क्योंकि पीएसीने अपनी 87 ^{वीं} रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और इसलिए अंतिम एटीएन की आवश्यकता नहीं थी।
2022	2022 की रिपोर्ट संख्या 24	5	5	शून्य
2023	2023 की रिपोर्ट संख्या 25	01	01	शून्य
योग		20	20	शून्य

सीएंडएजी पैरा और पीएसी पैरा का विवरण और स्थिति:

क. सीएंडएजीपैरा:

सीएंडएजी रिपोर्ट संख्या	पैरा नं.	विषय	स्थिति
2021 का 2	5.1	सेवा शुल्क की दर के गलत प्रयोग के कारण अधिक भुगतान हुआ	मंत्रालय द्वारा 14.1.2022 को अंतिम एटीएन प्रस्तुत किया गया
	5.2	दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय द्वारा अनियमित कर छूट के कारण राजस्व की हानि	मंत्रालय द्वारा 26.7.2021 को अंतिम एटीएन प्रस्तुत किया गया
	5.3	एचसीआई लंदन द्वारा मुआवजे की प्राप्ति और उपयोग में अनियमितताएँ	अंतिम एटीएन की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि पीएसी (2023-24) ने अपनी 87 ^{वीं} रिपोर्ट (17 ^{वीं} लोकसभा) प्रस्तुत की थी जिसे 7.2.2024 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया तथा राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया
	5.4	इंडिया हाउस, लंदन में बेसमेंट के जीर्णोद्धार से संबंधित कार्य का घोर अनियमित और हेरफेरपूर्ण पुरस्कार और निष्पादन, जिसके कारण एचसीआई लंदन द्वारा ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुँचाया गया	
	5.5	नालंदा विश्वविद्यालय, राजगीर द्वारा ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुँचाया गया	मंत्रालय द्वारा 13.9.2023 को अंतिम एटीएन प्रस्तुत किया गया।
2022 का 24	2.1	विदेशी नागरिकता कार्ड योजना के लिए शुल्क तय करने में गलत विनियम दर के प्रयोग के कारण शुल्क का कम संग्रह	मंत्रालय द्वारा 14.7.2023 को अंतिम एटीएन प्रस्तुत किया गया
	2.2	वाशिंगटन और पेरिस में भारतीय मिशनों द्वारा भारतीय सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना में अनियमितताएँ	अंतिम एटीएन 19.6.2024 को प्रस्तुत किया गया
2022 में 24	2.3	लागत वृद्धि और ब्याज का परिहार्य भुगतान	मंत्रालय द्वारा 6.11.2023 को अंतिम एटीएन प्रस्तुत किया गया
	2.4	अनुचित निविदा प्रक्रिया को अपनाने से लागत में वृद्धि हुई और साथ ही निविदा के अंतर्गत पहचाने गए कार्य मदों से मनमाने ढंग से विचलन हुआ	मंत्रालय द्वारा 15.11.2023 को अंतिम एटीएन प्रस्तुत किया गया
	2.5	पासपोर्ट त्याग के लिए अतिरिक्त शुल्क लिया गया	मंत्रालय द्वारा 26.5.2023 को अंतिम एटीएन प्रस्तुत किया गया
2023 में 25	3.1	गलत दरों को अपनाने के परिणामस्वरूप निर्माण की अतिरिक्त लागत आई-नालंदा विश्वविद्यालय, राजगीर	मंत्रालय द्वारा 19.06.2024 को अंतिम एटीएन प्रस्तुत किया गया

नोट (i): सचिव (पूर्व) द्वारा 6/4/2022 को सीएंडएजी रिपोर्ट संख्या 2/2021 के पैरा 5.2 पर पीएसी (2021-22) के समक्ष मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। पीएसी (2023-24) ने सीएंडएजीरिपोर्ट संख्या 2/2021 के पैरा 5.2 के आधार पर अपनी 80^{वीं} रिपोर्ट (17^{वीं} लोकसभा) प्रस्तुत की।

नोट (ii): विदेश सचिव द्वारा 10/2/2023 को सीएंडएजीरिपोर्ट संख्या 2/2021 के पैरा 5.3 और 5.4 पर पीएसी (2022-23) के समक्ष मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। पीएसी (2023-24) ने 2021 की सीएंडएजी रिपोर्ट संख्या 2 के सीएंडएजी पैरा 5.3 और 5.4 के आधार पर अपनी 87^{वीं} रिपोर्ट (17^{वीं} लोकसभा) प्रस्तुत की।

ख. 2023-24 के दौरान पीएसी की टिप्पणियाँ/सिफारिशें:

पीएसी रिपोर्ट सं.	पैरा नं.	विषय	स्थिति
दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय (एसएयू) में अनियमित कर छूट के कारण राजस्व की हानि पर 80 ^{वीं} रिपोर्ट (17 ^{वीं} लोकसभा) जो कि 2021 की सीएंडएजी रिपोर्ट संख्या 2 के पैरा 5.2 पर आधारित है।	1	परिचयात्मक:	अंतिम कार्रवाई के जवाब 14 जून 2024 को लोक सभा सचिवालय (पीएसी शाखा) को सौंपे गए

पीएसी रिपोर्ट सं.	पैरा नं.	विषय	स्थिति
	2	मानक संचालन प्रक्रिया की आवश्यकता:	
	3	जवाबदेही तय करना:	
	4	परामर्श और समन्वय	
	5	साझा जिम्मेदारी	
	6	आयकर विभाग द्वारा जांच	
	7	आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र	
	7	आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र	
लंदन के इंडिया हाउस में बेसमेंट के जीर्णोद्धार से संबंधित कार्य के आवंटन और निष्पादन में अनियमितता और हेराफेरी के कारण ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाने पर 87 ^{वीं} रिपोर्ट (17 ^{वीं} लोकसभा) जो कि 2021 की सीए-डब्ल्यूजी रिपोर्ट संख्या 2 के पैरा 5.3 और 5.4 पर आधारित है।	1	आपराधिक मामला/बड़ी सजा	अंतिम कार्रवाई के जवाब 9 अगस्त 2024 को लोक सभा सचिवालय (पीएसी शाखा) को सौंपे गए
	2	जीएफआर 2017 और अन्य प्रासंगिक सरकारी नियमों और विनियमों पर अनिवार्य प्रशिक्षण	
	3	आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र का पुनरुद्धार और सुदृढीकरण	
	4	परियोजनाओं की निगरानी और मिशनों के कामकाज के लिए किए जा रहे उपाय	
	5	भारत के सभी मिशनों में व्यापक जांच	

अध्याय

31

संसद एवं समन्वय प्रभाग

संसद एवं समन्वय प्रभाग की जिम्मेदारी में मुख्य रूप से संसदीय कार्य, मंत्रालय के भीतर और बाहर समन्वय तथा अन्य मंत्रालयों द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियानों में भागीदारी शामिल है। प्रभाग भारत संघ द्वारा अन्य देशों के साथ हस्ताक्षरित समझौता-ज्ञापनों की निगरानी और समीक्षा करने, भारतीय शैक्षणिक संस्थानों में कुछ श्रेणियों के विदेशी छात्रों के प्रवेश और कार्य की डिजिटल निगरानी की सुविधा के लिए विभिन्न डिजिटल पोर्टलों पर मंत्रालय के इनपुट अपलोड करने के लिए भी उत्तरदायी है।

संसद अनुभाग

संसद अनुभाग, संसद के साथ मंत्रालय का इंटरफेस है और मंत्रालय के संसद से संबंधित कार्यों के लिए नोडल बिंदु है। अनुभाग ने संसदीय कार्य के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुपालन में संसद द्वारा उठाए गए मुद्दों पर समय पर प्रतिक्रिया सुनिश्चित की।

कैलेंडर वर्ष 2024 के दौरान, विदेश मामलों पर संसदीय स्थायी समिति ने निम्नलिखित 6 विषयों पर 6 बैठकें कीं:

- इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष
- वर्ष 2024-25 के लिए मंत्रालय की अनुदान मांगों और भारत-चीन संबंध
- एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई और प्रवासी श्रमिकों सहित विदेशों में रहने वाले भारतीय प्रवासी: उनकी स्थिति और कल्याण के सभी पहलू, जिसमें उत्प्रवास विधेयक की स्थिति भी शामिल है

- भारत की विदेश नीति में वर्तमान घटनाक्रम
- ब्राजील में हाल ही में हुए जी20 शिखर सम्मेलन और उसके परिणामों पर संक्षिप्त जानकारी
- भारत-बांग्लादेश संबंधों का भविष्य
- भारत की हिंद महासागर रणनीति का मूल्यांकन

वर्ष 2024 के दौरान संसद में विशेष उल्लेख, नियम 377 और शून्यकाल के अंतर्गत कुल 32 महत्वपूर्ण मामले उठाए गए, जिनमें से 24 मामलों का उत्तर दिया गया। आज तक, 273 स्वीकृत संसद प्रश्नों का उत्तर दिया जा चुका है।

वर्ष के दौरान, भारतीय वैश्विक परिषद, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली और नालंदा विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित खाते संसद में रखे गए।

समन्वय प्रभाग

मंत्रालय ने विदेश स्थित मिशन/केंद्रों के माध्यम से भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों जैसे हर घर तिरंगा, राष्ट्रीय एकता दिवस/सप्ताह, संविधान दिवस, आयुर्वेद दिवस, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जनजातीय गौरव दिवस आदि के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

समन्वय अनुभाग ने भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों, स्वायत्त निकायों और निजी संस्थानों के साथ

मंत्रालय की चर्चा को प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया। अनुभाग ने विदेश यात्राओं, खेल आयोजनों, सम्मेलनों, संगोष्ठियों, प्रदर्शनियों और राजनयिक सैन्य उड़ानों के लिए राजनीतिक मंजूरी की प्रक्रिया की।

कैबिनेट के निर्णय, कैबिनेट की टिप्पणियां, सचिवों की समिति की सिफारिशें, विदेश मंत्रालय का दृष्टिकोण दस्तावेज (एसजीओएस-10) और मंत्रालय द्वारा वित्त-पोषित और प्रशासित प्रगति परियोजनाओं के कार्यान्वयन में हुई प्रगति पर ई-समीक्षा पोर्टल पर लगभग 250 कार्य बिंदुओं की निगरानी की गई और उन्हें मासिक रूप से अद्यतन किया गया। विदेश यात्राओं के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा की गई 23 घोषणाओं को प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) संदर्भ पोर्टल पर नियमित रूप से अद्यतन किया जा रहा है।

लंबित जन शिकायतों, सांसदों, राज्य सरकारों, अंतर-मंत्रालयी परामर्श और संसदीय आश्वासनों आदि के संदर्भों के समय पर और प्रभावी निपटान, स्वच्छता अभियान चलाने और रिकॉर्ड (फाइलों) के प्रबंधन के लिए एक

विशेष अभियान चलाया गया। लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान (एससीडीपीएम) पोर्टल पर आंकड़ों की नियमित रूप से निगरानी की गई और उन्हें अद्यतन किया गया। मंत्रालय ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में स्थित मंत्रालय के कार्यालयों में स्वच्छता पर विशेष अभियान 4.0 चलाया। अभियान 02 अक्टूबर को शुरू हुआ और 31 अक्टूबर तक जारी रहा। अभियान के फोकस क्षेत्रों में जन शिकायतों का प्रभावी निपटान, सांसदों के संदर्भ, संसद आश्वासन, स्वच्छता अभियान, कबाड़ का निपटान और फाइलों को छांटना शामिल था। इस अवधि के दौरान, मंत्रालय ने 779 स्वच्छता अभियान चलाए। 5,30,000 भौतिक फाइलों को छांट दिया गया। कबाड़/अप्रचलित वस्तुओं को हटाकर लगभग 27,482 वर्ग फुट जगह खाली की गई। इसके अलावा, कुल 640 जन शिकायतों का समाधान किया गया और 49 पीएमओ संदर्भों और 95 सांसदों के संदर्भों का समाधान किया गया।

अध्याय

32

सम्मेलन प्रभाग

शिखर सम्मेलन प्रभाग भारत और विदेशों में विदेश मंत्रियों/प्रतिनिधियों की अंतर्राष्ट्रीय और बहुपक्षीय भागीदारी सहित बैठकों, कार्यक्रमों, संगोष्ठियों और सम्मेलनों के आयोजन में मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों को रसद सहायता प्रदान करता है।

शिखर सम्मेलन प्रभाग ने 26^{वाँ} आसियान-भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक (एसओएम) के लिए रसद सहायता प्रदान की, जैसे कि स्थल मानचित्रण, परिवहन, आवास और खानपान व्यवस्था। एसओएम 02-03 मई को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। प्रभाग ने 21 जून को नई दिल्ली में मनाए बहिर्गमन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई) के लिए भी रसद सहायता प्रदान की।

इसके अलावा, सुषमा स्वराज भवन में लगभग 206 आंतरिक बैठकें और अन्य मंत्रालयों/विभागों के बारे में लगभग 91 बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद् की तीन बैठकें शामिल हैं। इसके अलावा, शिखर सम्मेलन प्रभाग सुषमा स्वराज भवन (एसएसबी) के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में भी कार्य करता है। वर्ष के दौरान विदेश मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों/विभागों के कई महत्वपूर्ण बहुपक्षीय/द्विपक्षीय कार्यक्रम एसएसबी में आयोजित किए गए।

अध्याय

33

त्वरित सहायता प्रकोष्ठ

त्वरित सहायता प्रकोष्ठ (आरआरसी) मंत्रालय का नोडल प्रभाग है जो दुनिया भर में सरकार के मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) प्रयासों को अंजाम देता है। आरआरसी की स्थापना 2021 में कोविड-19 से संबंधित जिम्मेदारियों के साथ की गई थी। तब से आरआरसी आपदाओं के बाद एचएडीआर संचालन को अंजाम दे रहा है और दुनिया भर के साझेदार देशों को जरूरत के अनुसार मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। आरआरसी के अधिदेश में संकट से प्रभावित भौगोलिक क्षेत्रों से भारतीय नागरिकों को निकालना भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, आरआरसी विभिन्न पहलों जैसे क्राइ हेल्थ सिव्योरिटी पार्टनरशिप (क्यूएचएसपी), भारत-प्रशांत देशों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य पहल, साझेदार देशों द्वारा भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देना और साझेदार देशों में जन औषधि केंद्र खोलना आदि के माध्यम से मंत्रालय की स्वास्थ्य कूटनीति का विस्तार करने में भी शामिल है।

प्रमुख घटनाक्रम

जनवरी से दिसंबर की अवधि के दौरान, भारत ने आपदाओं के बाद भागीदार देशों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जटिल और तीव्र संचालन किए। भारत का एचएडीआरपदचिह्न अब पड़ोस से आगे बढ़कर अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन और ओशिनिया तक फैल गया है। भारत ने विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों की जरूरतों को प्रभावी ढंग से और जल्दी से पूरा किया।

‘प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता और विश्वसनीय एचएडीआरप्रदाता’ की सुस्थापित प्रतिष्ठा के अनुरूप, भारत ने वर्ष 2024 में तीन प्रमुख संचालन किए, अर्थात् ऑपरेशन इंद्रावती, कुवैत में विशेष मानवीय एयरलिफ्ट ऑपरेशन और ऑपरेशन सद्भाव। वर्ष के दौरान बीस से अधिक देशों को एचएडीआरसहायता भी प्रदान की गई।

ऑपरेशन इंद्रावती

हैती में संकट फरवरी में बढ़ गया था जब सरकारी आधारभूत संरचना जैसे हवाई अड्डों, पुलिस स्टेशनों और जेलों को निशाना बनाकर गिरोहों ने हिंसा की थी। इसके परिणामस्वरूप आपातकाल की घोषणा की गई। मार्च से, अधिकांश एयरलाइनों ने पोर्ट-ऑ-प्रिंस से और पोर्ट-ऑ-प्रिंस के लिए हवाई परिचालन को निलंबित कर दिया।

हैती में रहने वाले भारतीय समुदाय की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, भारत ने हैती से फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए 21 मार्च को ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया। भारत सरकार ने निकासी योजना को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए हैती के स्थानीय अधिकारियों, भारतीय समुदाय संघ, डोमिनिकन गणराज्य की सरकार, विदेशी राजनयिक मिशनों और हैती में एयर चार्टर सेवा प्रदाताओं के साथ समन्वय किया। भारत सरकार ने भारत में भारतीय समुदाय और उनके परिवार और मित्रों की सुविधा के लिए एक 24x7 नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया। निकासी योजना के हिस्से के रूप में, फंसे हुए भारतीय नागरिकों को पहले हैती के अशांत स्थानों से पोर्ट-

ऑ-प्रिंस में एक सभा स्थल पर ले जाया गया। वहां से 17 भारतीय नागरिकों को चार्टर हेलीकॉप्टरों द्वारा हवाई मार्ग से 21 मार्च और 4 अप्रैल को तीन समूहों में जिमानी, डोमिनिकन गणराज्य सुरक्षित पहुंचाया गया।

विशेष मानवीय एयरलिफ्ट ऑपरेशन

भारत ने 12 जून को कुवैत के अल-मंगफ क्षेत्र की एक आवासीय इमारत में हुई भीषण आग की घटना के बाद कुवैत में एक विशेष मानवीय एयरलिफ्ट ऑपरेशन शुरू किया। इस घटना में 45 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई थी। प्रधानमंत्री के निर्देश पर, केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) के राज्य मंत्री भारतीय नागरिकों को दी जा रही चिकित्सा सहायता की देखरेख करने और पार्थिव शरीर को शीघ्र वापस लाने के लिए कुवैत सरकार के साथ समन्वय करने के लिए तुरंत कुवैत पहुंचे। कुवैत में भारतीय दूतावास ने मृतकों और जीवित बचे लोगों के परिवार के सदस्यों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए ताकि वे नवीनतम अपडेट के लिए दूतावास से जुड़ सकें। 13 जून को, भारत सरकार ने 45 मृत भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर वापस लाने के लिए आईएएफसी 130 विमान भेजा। 14 जून को, विमान कोच्चि में उतरा, जहां केरल और आसपास के राज्यों से संबंधित 31 पार्थिव शरीर सौंपे गए। इसके बाद विमान अन्य राज्यों से संबंधित 14 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर सौंपने के लिए दिल्ली चला गया। केन्द्रीय विद्यालय संगठन राज्य मंत्री ने कुवैत से भारत आने वाली भारतीय वायुसेना की उड़ान में यात्रा की।

ऑपरेशन सद्भाव

सितंबर की शुरुआत में तूफान यागी, उसके बाद मूसलाधार बारिश, बाढ़ और भूस्खलन ने दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में तबाही मचाई। संकट के कुछ दिनों के भीतर, भारत ने आपदाग्रस्त देशों के साथ एकजुटता व्यक्त करने और प्रभावित आबादी को तत्काल मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए 15 सितंबर को ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया। आरआरसी प्रभाग ने पूरे ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ (एचक्यूआईडीएस), भारतीय वायु सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ समन्वय किया। यह ऑपरेशन न केवल 'प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता' के रूप में भारत की भूमिका का प्रमाण था, बल्कि भारत की लंबे समय से चली आ रही 'एक्ट ईस्ट' और 'पड़ोसी पहले नीति' के अनुरूप था। ऑपरेशन सद्भाव के अंतर्गत, भारत ने लाओ पीडीआर, वियतनाम और म्यांमार को एचएडीआर सहायता प्रदान की।

लाओ पीडीआर: भारत ने 15 सितंबर को लाओ पीडीआर को आईएएफ सी 17 उड़ान द्वारा लगभग 10 टन मानवीय सहायता प्रदान की। सहायता में जेनसेट्स, जल शोधक, जल शोधन गोलियां और कीटाणुनाशक, स्लीपिंग बैग, कंबल, स्वच्छता किट, मच्छरदानी और मच्छर निरोधक आदि शामिल थे। भारत इस क्षेत्र में एचएडीआर प्रदान करने वाले पहले प्रतिक्रियादाताओं में से एक था।

वियतनाम: भारत ने 15 सितंबर को आईएएफ सी 17 उड़ान द्वारा वियतनाम को लगभग 35 टन मानवीय सहायता प्रदान की। सहायता में जल शोधन सामग्री, पानी के कंटेनर, कंबल, रसोई के बर्तन, सौर लालटेन आदि शामिल थे। यह आपूर्ति उत्तरी वियतनाम में प्रभावित समुदायों तक बढ़ा दी गई, जो प्राकृतिक आपदा से सबसे अधिक प्रभावित थे।

म्यांमार: म्यांमार सरकार से अनुरोध प्राप्त होने के कुछ ही घंटों के भीतर भारतीय नौसेना के जहाज सतपुरा द्वारा लगभग 21 टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी गई। आईएनएससतपुरा ने खाने के लिए तैयार भोजन, टेंट, जनरेटर सेट, रसोई सेट, सौर लैंप, चिकित्सा आपूर्ति, मच्छरदानी और रिपेलेंट्स, जल शोधन गोलियां और कीटाणुनाशक, और अन्य सामग्री के साथ एचएडीआरपैलेट ले गए। 32 टन दवाओं और राहत सामग्री की दूसरी खेप 17 सितंबर को आईएएफआईएल-76 उड़ान द्वारा भेजी गई, जिसमें अस्थायी आश्रय, स्वच्छता किट, एमआरई, जेनसेट, सामान्य दवाएं, जल शोधन आपूर्ति, ब्लीचिंग पाउडर, कीटाणुनाशक आदि शामिल थे।

एचएडीआर प्रयास

नेपाल: भारत ने 03 नवंबर 2023 को नेपाल में आए शक्तिशाली भूकंप के बाद नेपाल को सहायता प्रदान की। तत्काल राहत की पहली खेप 05 नवंबर 2023 को नेपाल को प्रदान की गई और एचएडीआर सहायता की पांचवीं खेप जिसमें टेंट, कंबल, स्लीपिंग बैग और 20 प्रीफैब्रिकेटेड घर शामिल थे, 04 जनवरी को वितरित की गई। पांच खेपों में नेपाल को कुल 4.14 टन दवाइयां और 41 टन राहत सामग्री प्रदान की गई।

भारत ने सितंबर में अभूतपूर्व वर्षा, बाढ़ और भूस्खलन से हुई तबाही के दौरान भी नेपाल को सहायता प्रदान की। नेपाल सरकार से अनुरोध प्राप्त करने के 12 घंटे के भीतर, भारत ने लगभग 36 टन राहत सामग्री प्रदान की। इसके अतिरिक्त, भारत ने बाधित सड़क संपर्क को बहाल करने के लिए नेपाल को 10 बेली ब्रिज भी प्रदान किए।

यूक्रेन: फरवरी 2022 में संघर्ष छिड़ने के बाद, भारत ने मार्च 2022 से जनवरी 2024 तक कई किस्तों में यूक्रेन को एचएडीआर सहायता प्रदान की। राहत की पहली किस्त मार्च 2022 में और एचएडीआर सहायता की पांचवीं किस्त जनवरी 2024 में पहुंचाई गई। एचएडीआर में आवश्यक और जीवनरक्षक दवाएं, चिकित्सा उपकरण और आपदा राहत सामग्री शामिल थी। पांच किस्तों में भारत ने यूक्रेन को लगभग 140 टन चिकित्सा सहायता और आपदा राहत सामग्री की आपूर्ति की।

अगस्त में यूक्रेन सरकार ने भारत सरकार से दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और आधारभूत संरचना के उपकरणों की मानवीय सहायता मांगी थी। यूक्रेन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए भारत सरकार ने 23 अगस्त को प्रधानमंत्री की यूक्रेन यात्रा के दौरान 4 भीष्म क्यूब्स (सहयोग हित और मैली के लिए भारत स्वास्थ्य पहल) और 10 डीजल जनरेटर सेट उपहार में दिए। भीष्म क्यूब भारत में निर्मित, आत्मनिर्भर मोबाइल आपातकालीन देखभाल इकाई है जो उपचार और आघात देखभाल की पहली पंक्ति प्रदान करती है। क्यूब आघात, रक्तस्राव, जलन, फ्रैक्चर आदि जैसे विभिन्न प्रकृति

के 200 मामलों में तत्काल चिकित्सा देखभाल प्रदान कर सकता है।

जाम्बिया: जनवरी-फरवरी में जाम्बिया में हैजा के प्रकोप के मद्देनजर, भारत ने लगभग 3.5 टन की चिकित्सा सहायता प्रदान की, जिसमें जल शोधन आपूर्ति, ओआरएस पाउच आदि शामिल थे।

ग्वाटेमाला: ग्वाटेमाला सरकार के अनुरोध पर, भारत ने मार्च में लगभग 1222 किलोग्राम वजन की एंटी-साइकोटिक, एंटी-डायबिटिक और गर्भावस्था से संबंधित दवाओं के रूप में चिकित्सा सहायता प्रदान की।

फिजी: भारत ने अपने एकीकृत बाल रोग प्रबंधन (आईएमसीआई) टीकाकरण कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के लिए अप्रैल में फिजी को लगभग 7642 किलोग्राम वजन की आवश्यक दवाइयां प्रदान कीं।

केन्या: भारत ने अप्रैल-मई में अचानक आई बाढ़ के बाद केन्या को एचएडीआर सहायता प्रदान की। तत्काल राहत की पहली खेप 10 मई को आईएनएस सुमेधा द्वारा प्रदान की गई थी और लगभग 40 टन आपदा राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता की दूसरी खेप 14 मई को आईएफसी-17 विमान द्वारा केन्या ले जाई गई थी।

पापुआ न्यू गिनी: मई में पापुआ न्यू गिनी के एंगा प्रांत में हुए भूस्खलन के बाद 13 जून को चार्टर्ड फ्लाइट द्वारा पापुआ न्यू गिनी को 6 टन चिकित्सा सहायता भेजी गई।

अल साल्वाडोर: जून में देश में व्यापक बाढ़ और भूस्खलन का असर हुआ। भारत ने हवाई और समुद्री मार्ग से तीन किस्तों में लगभग 50 टन एचएडीआर सहायता प्रदान की। राहत में दवाइयाँ, चिकित्सा उपकरण, परिवहन वेंटिलेटर, महत्वपूर्ण संकेत मॉनिटर, व्हीलचेयर, कंबल, खाने के लिए तैयार भोजन, शिशु और परिवार स्वच्छता उत्पाद आदि शामिल थे।

क्यूबा: क्यूबा सरकार के अनुरोध पर उसके बिगड़ते फार्मसी नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए, भारत ने जुलाई में लगभग 90 टन वजन के 9 मेड-इन-इंडिया एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स (एपीआई) की आपूर्ति की। क्यूबा के दवा निर्माताओं ने पुरानी संक्रामक बीमारियों के इलाज के लिए आवश्यक एंटीबायोटिक दवाओं के निर्माण के लिए एपीआईका उपयोग किया।

हैती: 2024 की शुरुआत में नागरिक अशांति के बाद, हैती एक मानवीय आपदा से जूझ रहा था। भारत ने हैती के राष्ट्रीय आधान सुरक्षा कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए जुलाई-अगस्त में लगभग 9 टन की चिकित्सा सहायता प्रदान की, जिसमें रक्त आधान की आवश्यक वस्तुएं, इम्यूनोहेमेटोलॉजी के लिए अभिकर्मक, रैपिड टेस्ट और ईएलआईएसएआदि शामिल थे।

सेंट वीसेंट और ग्रेनेडाईस: भारत ने तूफान बेरिल के बाद सेंट वीसेंट और ग्रेनेडाईस को सहायता प्रदान की जेनसेट, टेंट, तिरपाल, सोलर लैंप आदि से युक्त दूसरी खेप समुद्र के रास्ते भेजी जा रही है।

चाड: 18 जून को एन'जामेना में सबसे बड़े सैन्य गोला-बारूद डिपो में भीषण आग लग गई, जिससे लगभग 15 नागरिकों की मौत हो गई और 100 लोग घायल हो गए। भारत ने 7 सितंबर को हवाई मार्ग से चाड के लोगों के लिए लगभग 2300 किलोग्राम वजन की आवश्यक जीवन रक्षक एंटीबायोटिक्स और सामान्य दवाओं से युक्त चिकित्सा सहायता प्रदान की।

नाइजीरिया: भारत ने देश में विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए नाइजीरिया को 15 टन मानवीय सहायता प्रदान की। सहायता में खाने के लिए तैयार भोजन (एमआरई), सोने के लिए चटाई, कंबल, जल शोधन आपूर्ति और अन्य राहत सामग्री शामिल थी। दिसंबर में समुद्री मार्ग से लगभग 35 टन की अतिरिक्त सहायता भेजी गई।

जमैका: तूफान बेरिल के बाद, भारत ने दिसंबर में समुद्री मार्ग से जमैका को चिकित्सा उपकरण, डीजल जेनसेट और अन्य उपयोगिताओं के रूप में मानवीय सहायता भेजी।

पीआईसी देशों की स्वास्थ्य-आधारित संरचना की एचएडीआर सहायता: तीसरे एफआईपीआईसी शिखर सम्मेलन में पीआईसी देशों के लिए भारत की प्रतिबद्धता के बाद, पोर्टेबल आरओ इकाइयों के साथ 12 हेमो-डायलिसिस मशीनों की पहली खेप अक्टूबर में पापुआ न्यू गिनी के लिए रवाना हुई। मार्शल द्वीप गणराज्य के लिए पोर्टेबल आरओ इकाइयों के साथ 3 एचडी मशीनों की खेप नवंबर में रवाना हुई। पलाऊ, समोआ, सोलोमन द्वीप और नाउरू में प्रत्येक के लिए एक पोर्टेबल आरओ इकाई के साथ 1 एचडी मशीन नवंबर में समुद्री मार्ग से रवाना हुई। इस आपूर्ति से पीआईसी देशों की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में सुधार होगा।

पश्चिम एशिया के अशांत क्षेत्रों के लिए एचएडीआर प्रतिबद्धता

वर्ष 2024 में, भारत पश्चिम एशिया के अशांत क्षेत्रों में अपनी मानवीय सहायता प्रतिबद्धताओं को पूरा करना जारी रखेगा। सुरक्षा, हवाई क्षेत्र प्रतिबंध, संचार बाधाओं, सीमा शुल्क और आतंकवाद मुद्दों, प्रतिबंधित भूमि आंदोलनों, रसद भागीदारों की अनुपलब्धता आदि से संबंधित कई चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, भारत ने कई एजेंसियों के साथ समन्वय किया और संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के लिए मानवीय सहायता आपूर्ति सफलतापूर्वक पहुंचाई।

भारत ने अगस्त में सीरिया को लगभग 1400 किलोग्राम कैसर रोधी दवाइयों की आपूर्ति की। अक्टूबर में, भारत ने फिलिस्तीन के पश्चिमी तट के लोगों के लिए लगभग 36 टन वजन की आवश्यक जीवन रक्षक और कैसर रोधी दवाओं की आपूर्ति की; भारत ने अक्टूबर-नवंबर में फिलिस्तीन के गाजा को लगभग 30 टन मानवीय सहायता की आपूर्ति करने के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी (यूएनआरडब्ल्यूए) के साथ समन्वय किया। इस वर्ष अक्टूबर-नवंबर में लेबनान को 33 टन चिकित्सा सहायता भेजी गई, जिसमें हृदय संबंधी दवाएं, एनएसएआईडी (गैर-स्टेरायडल एंटी-इंफ्लेमेटरी ड्रग्स), एंटी-इंफ्लेमेटरी एजेंट, एंटीबायोटिक्स और एनेस्थेटिक्स आदि सहित विभिन्न प्रकार के औषधीय उत्पाद शामिल थे।

खाद्यान्न सहायता

भारत ने भागीदार देशों की खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए प्रयास शुरू किए। अफ्रीकी देशों को हाल ही में की गई खाद्यान्न आपूर्ति इस प्रयास का प्रमाण है।



भारत ने ऑपरेशन सद्भाव, सितंबर 2024 के हिस्से के रूप में टाइफून या से हुई व्यापक तबाही के बाद वियतनाम, लाओस और म्यांमार को राहत सामग्री भेजी।

2024 की शुरुआत से अफ्रीका के दक्षिणी भाग में अल-नीनो घटना के कारण होने वाले भयंकर सूखे के कारण, अधिकांश दक्षिणी अफ्रीकी देशों जैसे जाम्बिया, मलावी, जिम्बाब्वे, नामीबिया, लेसोथो आदि ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और भागीदार देशों से सूखे के कारण होने वाली खाद्य कमी और तीव्र कुपोषण को दूर करने के लिए मानवीय सहायता प्रदान करने की अपील की। भारत ने मलावी को 1000 मीट्रिक टन चावल, जिम्बाब्वे को 1000 मीट्रिक टन चावल, जाम्बिया को 2500 मीट्रिक टन मक्का, नामीबिया को 1000 मीट्रिक टन चावल और 1000 मीट्रिक टन मक्का भेजा। भारत ने लेसोथो को भी 1000 मीट्रिक टन चावल भेजा है। 1000 मीट्रिक टन ज्वार की दूसरी खेप जनवरी 2025 की शुरुआत में लेसोथो भेजी जाने की संभावना है। 'एक्ट ईस्ट' और 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति के अनुरूप, भारत ने राजनीतिक अशांति और टाइफून यागी के प्रभाव से खाद्यान्न की कमी का सामना कर रहे म्यांमार को 2200 मीट्रिक टन चावल की आपूर्ति की।

स्वास्थ्य सहयोग

जन औषधि केंद्र: 17 जुलाई को विदेश मंत्री ने मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ की मौजूदगी में मॉरीशस में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। यह परियोजना दोनों देशों के बीच सुदृढ़ द्विपक्षीय संबंधों को दर्शाती है और इसका उद्देश्य मॉरीशस में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा और कल्याण को बढ़ाने के लिए लागत प्रभावी, भारत में निर्मित दवाओं की आपूर्ति करना है।

19-21 नवंबर को प्रधानमंत्री की गुयाना की राजकीय यात्रा के दौरान, पीएमबीजेपी कार्यक्रम के अंतर्गत सस्ती कीमतों पर दवाओं की आपूर्ति के लिए मेसर्स एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड और गुयाना के स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच जन औषधि योजना (पीएमबीजेपी) पर समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

नीति निर्माताओं का दौरा: विदेश मंत्रालय ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और भारतीय फार्माकोपिया आयोग के सहयोग से 19-22 अगस्त को भारत में पहली बार नीति निर्माताओं का दौरा आयोजित किया। उद्घाटन समारोह में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने भाग लिया। इस यात्रा में 15 वैश्विक दक्षिण देशों (बुर्किना फासो, इक्वेटोरियल गिनी, घाना, गुयाना, जमैका, लाओ पीडीआर, लेबनान, मलावी, मोजाम्बिक, नाउरू, निकारागुआ, सीरिया, युगांडा, जाम्बिया और श्रीलंका) के 29 नीति निर्माताओं और दवा नियामकों ने भाग लिया। इस यात्रा में स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारतीय फार्माकोपिया की मान्यता के लाभों, सर्वोत्तम प्रथाओं और गुणवत्ता नियंत्रण पर चर्चा शामिल थी। इस यात्रा में प्रतिभागियों को गाजियाबाद में भारतीय फार्माकोपिया आयोग, आगरा में जन औषधि केंद्र और हैदराबाद में जीनोम वैली में वैक्सीन और दवा निर्माण सुविधाओं और अनुसंधान केंद्रों का भी अनुभव प्राप्त हुआ।

भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देने पर सहमति: 2024 में, भारत सरकार ने निकारागुआ, भूटान, मोजाम्बिक, सोलोमन द्वीप, श्रीलंका, नाउरू, मलावी और गुयाना की सरकारों के साथ फार्माकोपिया सहयोग पर एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इससे भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देने वाले देशों की कुल संख्या तेरह हो गई है।

क्वाड कैंसर मूनशॉट पहल: संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित क्वाड लीडर्स समिट के दौरान, क्वाड देशों ने 21 सितंबर को कैंसर मूनशॉट पहल शुरू की। यह कार्यक्रम सर्वाङ्कल कैंसर स्क्रीनिंग का विस्तार करने, एचपीवी के खिलाफ टीकाकरण बढ़ाने और रोगियों के इलाज पर केंद्रित है। पहल के अंतर्गत, भारत ने भारत-प्रशांत क्षेत्र को 7.5 मिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य के एचपीवी सैंपलिंग किट, डिटेक्शन टूल और सर्वाङ्कल कैंसर के टीके उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता जताई।

क्वाड महामारी की तैयारी: सितंबर में आयोजित क्वाड लीडर्स समिट के दौरान, क्वाड ने भारत-प्रशांत क्षेत्र में स्वास्थ्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से महामारी की तैयारियों पर एक कार्यशाला आयोजित

करेगा और आपातकालीन सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया की रूपरेखा तैयार करने वाला एक श्वेत-पत्र जारी करेगा।

तीसरी क्वाड एचएडीआर कार्य समूह बैठक और टेबल-टॉप अभ्यास: भारत ने क्वाड भागीदारों अर्थात अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मिलकर जापान की अध्यक्षता में 9-11 दिसंबर को टोक्यो, जापान में आयोजित तीसरी क्वाड एचएडीआर कार्य समूह बैठक और टेबल टॉप अभ्यास में भाग लिया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व आरआरसी प्रभाग ने किया, जिसमें लि-सेवाओं, मुख्यालय, एनडीआरएफ, एनडीएमए और टोक्यो में भारतीय दूतावास के अधिकारी शामिल थे। समूह ने भारत-प्रशांत क्षेत्र में क्वाड आपदा राहत सहयोग को सुदृढ़ करने के तरीकों और साधनों पर चर्चा की।

अध्याय

34

सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान

सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान (एसएसआईएफएस) भारत सरकार के 25 केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना 1986 में भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) के नए नियुक्त अधिकारियों को हर वर्ष पेशेवर प्रशिक्षण देने के लिए की गई थी। पिछले कुछ वर्षों में, इसके प्रशिक्षण का दायरा बहुत बढ़ गया है और इसमें विदेश मंत्रालय के अधिकारियों, विदेश मंत्रालय के कर्मियों, अन्य सिविल सेवाओं के सदस्यों और विदेशी राजनयिकों के लिए मिड-कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं। यह विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के अलावा हमारे मिशन और पोस्टों में तैनात अन्य अधिकारियों के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। विदेशी राजनयिकों के लिए पाठ्यक्रम दुनिया भर के देशों, खासकर ग्लोबल साउथ के देशों के साथ दोस्ती और अकादमिक सहयोग के पुल बनाने का एक तरीका है। विदेशी राजनयिकों के लिए पाठ्यक्रम और कार्यक्रम कूटनीति के सिद्धांतों और प्रथाओं, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में वर्तमान और उभरते मुद्दों के परिचय के रूप में काम करने के साथ-साथ भारत के इतिहास, संस्कृति और विदेश नीति के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

एसएसआईएफएस ने क्षमता निर्माण आयोग द्वारा अनिवार्य किए गए विदेश मंत्रालय की वार्षिक क्षमता निर्माण योजना को अंतिम रूप देने में भी योगदान दिया। एसएसआईएफएस ने मंत्रालय के अधिकारियों के लिए अपने प्रशिक्षण मॉड्यूल में एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण (आईजीओटी) प्लेटफॉर्म से स्व-गति ऑनलाइन शिक्षण पाठ्यक्रम जोड़े हैं। सीबीसी टीम द्वारा किए गए दो दिवसीय “ऑन-साइट” मूल्यांकन के बाद 08 मई को एसएसआईएफएस ने क्षमता निर्माण आयोग के “सिविल

सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के राष्ट्रीय मानक” (एनएससीएसटीआई) के साथ अपनी मान्यता प्रक्रिया पूरी की। एसएसआईएफएस मान्यता की प्रक्रिया अगस्त 2022 में शुरू हुई।

आईएफएस अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम

भूटान के दो राजनयिकों के साथ 2023 बैच के आईएफएस अधिकारी-प्रशिक्षुओं का छह महीने का प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम (आईटीपी) 06 नवंबर 2023 को शुरू हुआ और 11 मई 2024 को समाप्त हुआ। आईएफएस अधिकारी प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करने के लिए अपनाए गए शैक्षणिक दृष्टिकोणों में इंटरैक्टिव व्याख्यान, सिमुलेशन, रोल प्ले, फायर-साइड चैट, कार्यशालाएं और केस स्टडी शामिल थे। कक्षा सत्रों में अन्य बातों के अलावा विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और पर्यटन के 3T, विकास साझेदारी और कनेक्टिविटी पहल को शामिल किया गया। अन्य सरकारी अंगों के कामकाज के बारे में जानकारी संलग्नकों और क्षेत्र के दौरे के संयोजन के माध्यम से दी गई। अधिकारी प्रशिक्षुओं ने माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री से पारंपरिक भेंट भी की।

आईटीपी का समापन 11 मई को एक विदाई समारोह के साथ हुआ, जिसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री ने की, जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ अधिकारी प्रशिक्षु



प्रधानमंत्री ने भारतीय विदेश सेवा के 2023 बैच के अधिकारी प्रशिक्षुओं से चर्चा की, अगस्त 2024

को स्वर्ण पदक और सर्वश्रेष्ठ शोध-पत्र के लिए राजदूत बिमल सान्याल मेमोरियल पदक प्रदान किया। एस्पिट डी कॉर्प्स के लिए रजत पदक और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और सर्वश्रेष्ठ समिति के लिए ट्रॉफी भी प्रदान की गई।

एसएसआईएफएस ने 19-23 अगस्त को 2012 बैच के 25 आईएफएस अधिकारियों के लिए एमसीटीपी-1 आयोजित किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान, अधिकारियों ने एसएसआईएफएस में विदेश नीति मॉड्यूल में भाग लिया और अपने आवंटित राज्यों के साथ एक सप्ताह तक काम किया, जिसमें एक आकांक्षी जिले का दौरा भी शामिल था। 2008 बैच के 30 आईएफएस अधिकारियों के लिए एमसीटीपी-II 24-28 जून को आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में एसएसआईएफएस में एक सप्ताह का विदेश नीति मॉड्यूल, आईआईएम (अहमदाबाद) में एक सप्ताह का प्रबंधन मॉड्यूल, ली कुआन यू स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी (एलकेवाईएसपीपी), सिंगापुर में एक सप्ताह का कूटनीति मॉड्यूल और अपने संबंधित राज्यों के साथ एक सप्ताह का काम शामिल है। अवर सचिव स्तर के 31 अधिकारियों के लिए परिवीक्षा संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम 29 जुलाई से 30 अगस्त तक आयोजित किया गया था।

विदेशी राजनयिकों के लिए विशेष पाठ्यक्रम

एसएसआईएफएस साझेदार देशों और क्षेत्रीय समूहों के राजनयिकों के लिए विशेष पाठ्यक्रम आयोजित करता है। 2024 में, एसएसआईएफएस ने कंबोडिया, लाओ पीडीआर, गाम्बिया, मेडागास्कर, मोल्दोवा, श्रीलंका,

कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और नेपाल के राजनयिकों के लिए द्विपक्षीय प्रारूप में विशेष पाठ्यक्रम आयोजित किए। इन विशेष पाठ्यक्रमों में कुल 153 राजनयिकों और अधिकारियों ने भाग लिया। रवांडा, लीबिया और दक्षिण सूडान के राजनयिकों के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम 11-20 दिसंबर को आयोजित किया गया था जिसमें 40 राजनयिकों ने भाग लिया था। एसएसआईएफएस ने 10-19 जुलाई को प्रशांत गठबंधन के चार देशों के लिए पहला विशेष पाठ्यक्रम आयोजित किया जिसमें चिली, कोलंबिया, मैक्सिको और पेरू के 12 राजनयिकों ने भाग लिया। एसएसआईएफएस ने 22 जनवरी से 09 फरवरी तक डी एंड आईएसए प्रभाग के सहयोग से वार्षिक निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों की फेलोशिप के चौथे संस्करण का आयोजन किया, जिसमें दुनिया भर के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के 24 देशों के 24 राजनयिकों ने भाग लिया। 22 अप्रैल से 03 मई तक विदेशी राजनयिकों के लिए 71^{वां} व्यावसायिक पाठ्यक्रम (पीसीएफडी) आयोजित किया गया, जिसमें 30 देशों के 34 राजनयिकों ने भाग लिया। ग्लोबल साउथ यंग डिप्लोमैट्स फोरम (जीएसवाईडीएफ) का दूसरा संस्करण 09-20 सितंबर को आयोजित किया गया, जिसमें ग्लोबल साउथ के 29 देशों के 32 राजनयिकों ने भाग लिया।

समझौता-ज्ञापन

सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान, विदेश मंत्रालय, भारत गणराज्य और डिप्लोमैटिक एकेडमी ऑफ मॉरिटानिया, विदेश मंत्रालय, इस्लामिक



विदेश मंत्री ने 2023 बैच के आईएफएस अधिकारी प्रशिक्षुओं और भूटानी राजनयिकों के विदाई समारोह की अध्यक्षता की, मई 2024

रिपब्लिक ऑफ मॉरिटानिया के बीच 16 अक्टूबर को एक समझौता-ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। 1997 में पेरू से शुरू होकर, एसएसआईएफएस ने अब तक भागीदार देशों के साथ 97 और आईबीएसए, ब्रिक्स और बिम्सटेक सहित बहुपक्षीय संगठनों के साथ 3 समझौता-ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।

प्रतिष्ठित व्याख्यान श्रृंखला

एसएसआईएफएस द्वारा 23 फरवरी को सुषमा स्वराज भवन में आयोजित प्रतिष्ठित व्याख्यान श्रृंखला के दूसरे संस्करण में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार अनवर मोहम्मद गरगाश ने 'पश्चिम एशिया में उभरते भू-सामरिक विकास' पर एक व्याख्यान दिया। विदेश मंत्री ने इस कार्यक्रम में उद्घाटन भाषण दिया, जिसमें लगभग 300 लोगों ने भाग लिया।

विदेश मंत्रालय के अन्य अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

वर्ष के दौरान गैर-प्रतिनिधि ग्रेड (एनआरजी) अधिकारियों (अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव और उससे नीचे) के लिए विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

आयोजित किए गए। ये सीधे भर्ती सहायक अनुभाग अधिकारियों के लिए प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम और अनुभाग अधिकारियों, सहायक अनुभाग अधिकारियों, वरिष्ठ सचिवालय सहायकों, प्रधान निजी सचिवों, निजी सचिवों, निजी सहायकों और आशुलिपिकों के लिए पदोन्नति से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम थे। विदेशों में विभिन्न मिशनों और पोस्टों के अधिकारियों की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए पदोन्नति से संबंधित प्रशिक्षण हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किए गए थे। एनआरजी प्रशिक्षण कार्यक्रमों से कुल 1349 अधिकारियों को लाभ हुआ।

आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत पारदर्शिता लेखापरीक्षा

एसएसआईएफएस को मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक प्राधिकरणों के संबंध में आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा सक्रिय खुलासे की पारदर्शिता लेखापरीक्षा करने का अधिकार दिया गया है। 2024 में, एसएसआईएफएस ने मंत्रालय और विदेशों में भारतीय मिशनों और पोस्टों से 175 सार्वजनिक प्राधिकरणों का सफलतापूर्वक लेखापरीक्षा किया, जिन्होंने इस उद्देश्य के लिए समर्पित सीआईसी (केंद्रीय सूचना आयोग) पोर्टल पर अपना स्व-मूल्यांकन प्रस्तुत किया था।

अध्याय

35

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) ने दुनिया भर में सांस्कृतिक संबंधों और आदान-प्रदान को सुदृढ़ करने की दिशा में अपने प्रयासों में लगातार काम किया है और कई प्रगति की है। परिषद विदेशों में अपने 38 भारतीय सांस्कृतिक केंद्रों के साथ-साथ भारत में 5 क्षेत्रीय कार्यालयों, 4 उप-क्षेत्रीय कार्यालयों और 2 क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ काम करती है।

छात्रवृत्ति

विदेशी नागरिकों के लिए छात्रवृत्ति उन्हें भारतीय कला, विरासत और संस्कृति का अध्ययन करने और उसकी सराहना करने के लिए प्रोत्साहित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह आउटरीच, सद्भावना की भावना पैदा करने और दुनिया भर में भारत के प्रभाव को बढ़ावा देने का एक तरीका भी है। शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में, आईसीसीआरने अपनी 20 छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत विदेशी नागरिकों को 3960 छात्रवृत्ति स्लॉट की पेशकश की, जिसमें ऑनलाइन स्नातक/स्नातकोत्तर (यूजी/पीजी) पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए अफगान नागरिकों के लिए 1000 छात्रवृत्तियाँ शामिल हैं। आईसीसीआरने आईसीसीआरछात्रवृत्ति के माध्यम से अपना पाठ्यक्रम पूरा करने वाले विदेशी छात्रों के लिए “एग्जिट एंगेजमेंट इवनिंग 2024” का आयोजन किया। ये (i) 19 जून को गुवाहाटी में; (ii) 20 जून को कोलकाता; (iii) 29 जून को लखनऊ; विभिन्न मंत्रालयों/विभागों ने कार्यक्रमों में भाग लिया और विदेशी छात्रों को आयुर्वेद, खादी,

भारतीय पर्यटन और आर्थिक सहयोग को दुनिया भर में बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया।

पीठ

आईसीसीआरविश्वविद्यालयों से प्राप्त अनुरोधों और मिशनों द्वारा अनुशंसित दुनिया भर के विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालयों में विभिन्न विषयों (राजनीति विज्ञान, दर्शनशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और बौद्ध अध्ययन, संस्कृत, हिंदी, उर्दू और तमिल (नृत्य और संगीत) पर विदेशों में भारतीय अध्ययन की पीठ स्थापित करने में सहायक है। इस अवधि के दौरान, विभिन्न विश्वविद्यालयों के साथ 10 समझौता-ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं और 04 विद्वानों को विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालयों में आईसीसीआरविजिटिंग प्रोफेसरों के रूप में तैनात किया गया है।

सम्मेलन एवं संगोष्ठियाँ

आईसीसीआरने 21 जून को सुषमा स्वराज भवन में मिशनो के निवासी विदेशी प्रमुखों के लिए 10^{वाँ} अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में विदेश मंत्री, राजनयिक कोर के सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। आईसीसीआरने 27-28 जून को डरबन के क्वाज़ुलु-नताल विश्वविद्यालय के सीनेट चैंबर्स में एस-वीवाईएसएऔर क्वाज़ुलु-नताल



राज्य मंत्री (पीएम) ने नवंबर 2024 को कमानी ऑडिटोरियम, नई दिल्ली में 8^{वें} भारत अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव का उद्घाटन किया

विश्वविद्यालय, दक्षिण अफ्रीका के सहयोग से “स्वयं और समाज के लिए योग” शीर्षक से दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलन का आयोजन किया।

बहिर्गमन सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडल

सांस्कृतिक के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय समझ बनाने के अपने प्रयासों में, आईसीसीआरने इस अवधि के दौरान 54 देशों में सांस्कृतिक प्रदर्शन देने के लिए विभिन्न शैलियों, जैसे कथक, मोनिनीअट्टम, भरतनाट्यम, मणिपुरी, ओडिसी, बॉलीवुड, आदि से 64 सांस्कृतिक मंडलियों और पंजाबी, असमिया, गुजराती और राजस्थान जैसे लोक नृत्य और संगीत समूहों को प्रायोजित किया है।

आगंतुक सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडल

आईसीसीआरने 09-15 मार्च के दौरान नई दिल्ली, अयोध्या और उज्जैन में (i) ‘श्री सत्संग रामायण मंडली’- फिज़ी से रामायण सांस्कृतिक मंडली द्वारा सांस्कृतिक प्रदर्शन आयोजित किए; (ii) 02-03 मई से आयोजित 26^{वें} आसियान-भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक के एक भाग के रूप में आसियान-एसओएम नेताओं और प्रतिनिधियों के सम्मान में ‘मणिपुरी सांस्कृतिक मंडली’ और ‘बेनी एंड द जैज़ कलेक्टिव’ समूह द्वारा जैज़ प्रदर्शन; (iii) विदेश मंत्री द्वारा आयोजित बिम्सटेक विदेश मंत्रियों की रिट्रीट के दौरान 11 जुलाई को नई दिल्ली में मेहताब अली नियाज़ी द्वारा

सितार वादन; (iv) “रामायण के माध्यम से दुनिया को जोड़ना – 2024” के अपने वर्ष भर के उत्सव के भाग के रूप में 29-31 जुलाई तक बेंगलुरु में रामायण पर अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन कला कार्यशाला (चल रही श्रृंखला के अंतर्गत दूसरा संस्करण); और (v) 19-20 नवंबर तक सत्यजीत रे ऑडिटोरियम, आरटीसी, कोलकाता में भारत अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव।

आईसीसीआरने 26-27 नवंबर को कमानी ऑडिटोरियम नई दिल्ली में ‘8^{वें} भारत अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव’ का आयोजन किया। इस महोत्सव में कोलंबिया, श्रीलंका, स्लोवाकिया और इराक के अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक दलों ने भाग लिया। इस महोत्सव का उद्घाटन 26 नवंबर को एमओएस (पीएम) ने किया।

पुरस्कार

पिछले वर्षों में विभिन्न विद्वानों/विशेषज्ञों को दिए गए/प्रदान किए गए पुरस्कार उन्हें 2024 में दिए गए।

रॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ भूटान के कॉलेज ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर स्टडीज के अध्यक्ष श्री लुंगटेन ग्यात्सो को 10 मई को भूटान में भारत मित्र सम्मान-इंडोलांजी 2023 से सम्मानित किया गया।

31 मई को म्यांमार के यांगून में डॉ. आशिन न्यानिसारा, चांसलर, सीतागु इंटरनेशनल बौद्ध अकादमी, म्यांमार को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया।

सुश्री मसाको सातो, कलाकार, कथक नृत्यांगना, कोरियोग्राफर, जापान को 08 नवंबर को जापान में भारत मित सम्मान-विशिष्ट पूर्व छात्र 2022 से सम्मानित किया गया।

आगंतुक कार्यक्रम

परिषद ने विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत यात्राओं की मेजबानी की, जो इस प्रकार हैं:

विशिष्ट आगंतुक कार्यक्रम (डीवीपी): मोल्दोवा, डेनमार्क, ग्वाटेमाला, श्रीलंका और सेंट वीसेंट और ग्रेनेडाईस जैसे पांच देशों के पांच प्रतिनिधियों ने विशिष्ट आगंतुक कार्यक्रम के अंतर्गत जनवरी से मार्च तक भारत का दौरा किया।

शैक्षणिक आगंतुक कार्यक्रम (एवीपी): कजाकिस्तान, ओमान और जाम्बिया जैसे तीन देशों के तीन प्रतिनिधियों ने शैक्षणिक आगंतुक कार्यक्रम के अंतर्गत मार्च-नवंबर में भारत का दौरा किया।

महत्वपूर्ण आगंतुक कार्यक्रम (आईसीसीआर): आईसीसीआर ने महत्वपूर्ण आगंतुक कार्यक्रम के अंतर्गत 14-21 अक्टूबर को ओमान से कैप्टन सलेह बिन सईद अल जाबरी की यात्रा की मेजबानी की।

प्रदर्शनीयाँ

आईसीसीआरने अपने वार्षिक उत्सव “रामायण परंपरा के माध्यम से विश्व को जोड़ने का वर्ष-2024” के हिस्से के रूप में 18-24 जनवरी तक पुराना किला, नई दिल्ली में 7^{वाँ} “भारत अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला-2024” का आयोजन किया। आईसीसीआरके 75^{वाँ} स्थापना दिवस पर, तत्कालीन राज्य मंत्री (संस्कृति) ने 09 अप्रैल को बीकानेर हाउस में अरिंदम-भारतीय अध्याय नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

आईसीसीआरने 23-30 सितंबर तक काठमांडू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र, काठमांडू और नेपाल ललित कला अकादमी के सहयोग से “रामायण प्रतिध्वनि: एक साझा विरासत का जश्न” शीर्षक से एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। नेपाल के संस्कृति, पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्री बट्टी प्रसाद पांडे ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी को 08-15 नवंबर तक म्यांमार के यांगून स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में भी प्रदर्शित किया गया।

प्रतिमाएं एवं मूर्तियाँ

जनवरी से नवंबर की अवधि के दौरान, आईसीसीआरने महात्मा गांधी, हंसा जीवराज मेहता, कस्तूरबा गांधी और भगवान बुद्ध जैसे प्रतिष्ठित नेताओं की 9 प्रतिमाएं एवं मूर्तियाँ विभिन्न देशों जैसे जापान, स्विट्जरलैंड, ब्राजील, कुवैत, इटली, डरबन और श्रीलंका को प्रमुख स्थानों पर स्थापना के लिए भेजीं।

भारतीय संस्कृति केंद्र

आईसीसीआरके दुनिया के विभिन्न हिस्सों में 38 भारतीय सांस्कृतिक केंद्र (आईसीसी) हैं। इसके अतिरिक्त यह स्पेन के वलाडोलिड में कासा डे ला इंडिया को भी सहायता प्रदान करता है। आईसीसीआरने मिशनो/पोस्टों/आईसीसीमें भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, तबला, हिंदुस्तानी और कर्नाटक गायन के विषयों में भारतीय संस्कृति के 48 शिक्षकों और 28 भारत-आधारित प्रदर्शन कला शिक्षकों को तैनात किया है। आईसीसीआरने मिशनो/पोस्टों को योग, भारतीय नृत्य और संगीत के शिक्षकों के रूप में स्थानीय संसाधन व्यक्तियों (एलआरपी) को नियुक्त करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। वर्तमान में विभिन्न मिशनो/पोस्टों/आईसीसीमें कुल 103 एलआरपीतैनात हैं।

भारतीय प्रवासियों और विदेशों में इच्छुक छात्रों के लिए भारतीय प्रदर्शन कला और संगीत के विषयों में ऑनलाइन कक्षाएं और प्रमाणन आयोजित करने के लिए आईसीसीआर, रूट्स2रूट्स (आर2आर) और सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र के बीच एक लिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

हिंदी

आईसीसीआरपिछले 46 वर्षों से देश-विदेश में हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए हिंदी द्विमासिक पत्रिका “गगनांचल” का प्रकाशन कर रहा है। 14 अक्टूबर को नई दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री (प्रधानमंत्री) की उपस्थिति में गगनांचल के विशेष अंक “विदेश में हिंदी” का लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया।

अध्याय

36

नालंदा विश्वविद्यालय

भारत सरकार ने बिहार के राजगीर में प्राचीन शिक्षा केंद्र-नालंदा विश्वविद्यालय-को पुनर्जीवित करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 को अधिनियमित किया। 2007 से इस पुनरुद्धार को पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस) देशों से सुदृढ़ समर्थन मिला है, जिसमें भारत सहित 18 देशों ने विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अंतर-सरकारी समझौता-ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।

19 जून को, माननीय प्रधानमंत्री ने बिहार सरकार द्वारा प्रदान की गई 455 एकड़ भूमि में फैले नालंदा विश्वविद्यालय के नेट ज़ीरो ग्रीन कैम्पस का उद्घाटन किया। परिसर में कार्बन तटस्थता प्राप्त करने के लिए अक्षय ऊर्जा प्रणाली, जल पुनर्चक्रण सुविधाएँ और पर्यावरण के अनुकूल डिज़ाइन एकीकृत हैं। उद्घाटन के दौरान बोधि वृक्ष का औपचारिक रोपण नालंदा की ऐतिहासिक विरासत और “भविष्य के विश्वविद्यालय” के रूप में इसके आधुनिक दृष्टिकोण के बीच संबंध का प्रतीक है।

नालंदा विश्वविद्यालय ने 2014 में अपने शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू किए। आज की तारीख में, विश्वविद्यालय छह स्कूलों में स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट कार्यक्रम प्रदान करता है: ऐतिहासिक अध्ययन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण अध्ययन, बौद्ध अध्ययन, दर्शन और तुलनात्मक धर्म, भाषा और साहित्य/मानविकी, प्रबंधन अध्ययन, और अंतर्राष्ट्रीय संबंध और शांति अध्ययन। इसके अतिरिक्त, चार शोध केंद्र स्थापित किए गए हैं: बंगाल की खाड़ी अध्ययन, सामान्य अभिलेखीय संसाधन केंद्र, संघर्ष समाधान और शांति अध्ययन केंद्र, और नालंदा विश्वविद्यालय केंद्र, नीमराना, राजस्थान।

वर्ष के दौरान, विश्वविद्यालय ने दो नए मास्टर कार्यक्रम शुरू किए, जिससे

कुल कार्यक्रमों की संख्या आठ हो गई। इसके अलावा, एक वैश्विक पीएचडी कार्यक्रम और दो पोस्ट-डॉक्टरेल फेलोशिप हैं। वर्तमान में, कुल नामांकन का लगभग 71% अंतर्राष्ट्रीय छात्र हैं, जो विभिन्न स्नातकोत्तर और पीएचडी कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं।

विश्वविद्यालय पाँच डिप्लोमा कार्यक्रम (एक वर्ष की अवधि) और बारह प्रमाणपत्र कार्यक्रम (छह महीने की अवधि) भी प्रदान करता है। इन कार्यक्रमों में कुल 575 छात्र नामांकित हैं, जिनमें 55 अंतर्राष्ट्रीय छात्र शामिल हैं। सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी पाठ्यक्रमों में शरद ऋतु 2023 में 330 और वसंत 2024 में 185 छात्रों ने भाग लिया, जबकि डिप्लोमा कार्यक्रमों में 60 नामांकन दर्ज किए गए।

छात्रवृत्ति और अनुसंधान सहायता: विदेश मंत्रालय ने आसियान, बिस्मटेक, आईसीसीआर और भूटान छात्रवृत्ति कार्यक्रमों के माध्यम से 140 छात्रवृत्तियों की सुविधा प्रदान की, जिसमें आसियान और बिस्मटेक स्लॉट क्रमशः 50 से 80 और 20 से 50 तक बढ़ गए। इसके अतिरिक्त, पेओंग राय ली छात्रवृत्ति, थाई एंडोमेंट छात्रवृत्ति और तंजानिया छात्रवृत्ति जैसे अंतर्राष्ट्रीय बंदोबस्तों ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का समर्थन करने में योगदान दिया।

विश्वविद्यालय पुस्तकालय ने एमलाइब्रेरीमोबाइल एप्लिकेशन प्रस्तुत किया, जिससे 575 से अधिक उपयोगकर्ताओं के लिए पुस्तकों, पत्रिकाओं और डेटाबेस तक डिजिटल पहुँच सक्षम हुई। पुस्तकालय को दिवंगत प्रोफेसर बृज गोपाल से लगभग 7,000 वस्तुओं का एक महत्वपूर्ण संग्रह भी प्राप्त हुआ, जिससे पारिस्थितिकी, जल विज्ञान और पर्यावरण संरक्षण में इसके संसाधनों में वृद्धि हुई।



प्रधानमंत्री ने जून 2024 में बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया।

वैश्विक पहुंच और सहयोग: नालंदा विश्वविद्यालय ने आसियान, यूरोप और भारत के सलह संस्थानों के साथ समझौते करके अपनी वैश्विक शैक्षणिक साझेदारी को सुदृढ़ किया, जिसमें सलामांका विश्वविद्यालय (स्पेन), प्रबंधन और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय, बट्टामबांग (कंबोडिया) और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण शामिल हैं। आसियान-भारत नेटवर्क ऑफ यूनिवर्सिटीज (एआईएनयू) के अंतर्गत ग्यारह सहयोगों को औपचारिक रूप दिया गया, जो संयुक्त अनुसंधान, संकाय आदान-प्रदान और छात्र गतिशीलता पहलों का समर्थन करते हैं।

शैक्षणिक कार्यक्रम: राज्यसभा अध्ययन यात्रा कार्यक्रम (आरएसएसवीपी) के हिस्से के रूप में, छात्रों ने 21-22 फरवरी 2024 को राज्यसभा का दौरा किया। माननीय उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति श्री जगदीप

धनखड़ ने छात्रों के साथ चर्चा की और शांति, प्रगति और सतत विकास के महत्व पर जोर दिया।

बोधगया वैश्विक वार्ता का छठा संस्करण 16-17 मार्च 2024 को आयोजित किया गया, जिसमें “ज्ञान का परिदृश्य” विषय पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें विरासत, शिक्षा और स्थिरता पर चर्चा की गई।

विश्वविद्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय गणमान्य व्यक्तियों की उच्च-स्तरीय यात्राओं की भी मेजबानी की। फरवरी 2024 में, आसियान के महासचिव महामहिम डॉ. काओ किम होर्न ने नालंदा का दौरा किया और एक पुनर्जीवित शैक्षणिक संस्थान के रूप में इसके महत्व को स्वीकार किया। सितंबर 2024 में, ग्रीस और फ्रांस के राजदूतों ने सांस्कृतिक और राजनयिक संबंधों को सुदृढ़ करते हुए शैक्षणिक सहयोग के अवसरों की खोज की।

अध्याय

37

अभिलेखागार

अभिलेखागार एवं अभिलेख प्रबंधन (ए एंड आरएम) प्रभाग मंत्रालय के अभिलेखागार एवं अभिलेखों का संग्रह है, जिसके पास 1.89 लाख फाइलें हैं। प्रभाग समय-समय पर भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार (एनएआई) को फाइलों का मूल्यांकन और हस्तांतरण करने का कार्य भी करता है।

यह प्रभाग उपयोग और पुनर्प्राप्ति में आसानी के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म पर डिजिटलीकृत डेटा को नए सर्वर पर स्थानांतरित/स्थानांतरित करने की प्रक्रिया कर रहा है। एनआईसीएसआई-सूचीबद्ध विक्रेताओं के बीच सीमित निविदा जांच (एलटीई) पर विचार/अनुमोदन के लिए 05 तकनीकी समिति की बैठकें बुलाई गईं। हमें यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 31 दिसंबर तक 1.89 लाख संसाधित किए जा चुके हैं (टीआईएफ से पीडीएफ रूपांतरण, ओसीआर और मेटाडेटा निर्माण आदि सहित) जिसका अर्थ है कि लगभग 100 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है।

ए एंड आरएम प्रभाग ने आरआरएस 2024 का अंतिम मसौदा 22 अगस्त को भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार (एनएआई) को आवश्यकतानुसार जांच/अनुमोदन के लिए भेज दिया। इसके बाद इसे अनुपालन के लिए सभी संबंधितों को जारी किया जाएगा।

2024 में, कुल 7,38,003 भौतिक फाइलों को हटाया गया और कुल 45,439 ई-फाइलें बंद कर दी गईं, जिनमें मिशन/पोस्ट/आरपीओ/पीओई और मंत्रालय के अन्य अधीनस्थ कार्यालय शामिल हैं, जो 31 दिसंबर तक बंद रहे।

प्रभाग ने अब तक 1.89 लाख फाइलों में से पच्चीस वर्ष (25) से अधिक पुरानी 1,370 अवर्गीकृत फाइलों की पहचान की है, तथा 04 और 05 दिसंबर 2024 को प्रभाग का दौरा करने वाले भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार (एनएआई) के अधिकारियों को उपर्युक्त फाइलों का मूल्यांकन करने में सहायता की है। मूल्यांकन के पश्चात, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और अभिलेखीय मूल्य वाली कुल 212 फाइलों को स्थायी संरक्षण तथा सार्वजनिक डोमेन पर अपलोड करने के लिए एनएआई को भेजा जा रहा है।

इस प्रभाग द्वारा अब तक वर्ष 2024 में अवर्गीकृत/समीक्षा के लिए मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों के संबंधित विभागाध्यक्षों को कुल 2,840 पुरानी फाइलें भेजी जा चुकी हैं।

अनुलग्नक

अनुलग्नक

अनुलग्नक	पृष्ठ संख्या
अनुलग्नक I: 2024 में नेपाल के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों/समझौतों का विवरण (अध्याय 1)	331
अनुलग्नक II: जनवरी 2024 से पूर्ण शक्तियों की सूची (अध्याय 20)	332
अनुलग्नक III: जनवरी 2024 से अनुसमर्थन की सूची (अध्याय 20)	333
अनुलग्नक IV: 2024 में संपन्न संधियों, समझौतों, समझौता-ज्ञापनों की सूची (अध्याय 20)	334
अनुलग्नक V: पासपोर्ट कार्यालय (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार) (अध्याय 22)	348
अनुलग्नक VI: पासपोर्ट सेवा केंद्रों की सूची (आरपीओ-वार) (अध्याय 22)	350
अनुलग्नक VII: कार्यशील डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों (पीओपीएसके) की सूची (अध्याय 22)	353
अनुलग्नक VIII: 2024 में राष्ट्राध्यक्षों/सरकार प्रमुखों/उप-राष्ट्रपतियों/विदेश मंत्रियों और समकक्षों द्वारा भारत में आने वाले दौरों का विवरण (अध्याय 26)	366
अनुलग्नक IX: 2024 में राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति/प्रधानमंत्री/विदेश मंत्री द्वारा किए गए दौरे का विवरण (अध्याय 26)	370
अनुलग्नक X: वर्चुअल शिखर सम्मेलन/कार्यक्रम (अध्याय 26)	372
अनुलग्नक XI: 01 जनवरी से 31 दिसंबर 2024 के दौरान विदेशी मिशन प्रमुखों द्वारा परिचय-पत्र प्रस्तुत करे गए (अध्याय 26)	373
अनुलग्नक XII: 01 जनवरी से 31 दिसंबर 2024 तक विदेशी मिशन प्रमुखों की अंतिम प्रस्थान स्थिति (अध्याय 26)	375
अनुलग्नक XIII: 2024-25 के दौरान मुख्यालय और विदेश में मिशनों में कैडर की संख्या (अध्याय 28)	376

अनुलग्नक I

2024 में नेपाल के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों/समझौतों का विवरण:

क्र.सं.	विषय	हस्ताक्षर की तिथि
1.	सरकारी संगठनों या किसी अन्य संगठन के माध्यम से उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं (एचआईसीडीपी) के कार्यान्वयन के लिए भारतीय अनुदान सहायता के संबंध में नेपाल सरकार और भारत सरकार के बीच समझौता।	04 जनवरी 2024
2.	भारत गणराज्य सरकार और नेपाल सरकार के बीच दीर्घकालिक विद्युत व्यापार पर समझौता	04 जनवरी 2024
3.	सार्वजनिक क्षेत्र लेखापरीक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा नेपाल के महालेखापरीक्षक कार्यालय के बीच समझौता-ज्ञापन	02 मई 2024
4.	नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनईए) और एनटीपीसी लिमिटेड के बीच नवीकरणीय ऊर्जा विकास में सहयोग के लिए समझौता-ज्ञापन	04 जनवरी 2024
5.	नेपाल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अकादमी (एनएएसटी) और न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) के बीच ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी) पर मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण सेवाओं के लिए समझौता	04 जनवरी 2024

जनवरी 2024 से पूर्ण शक्तियों की सूची

क्र.सं.	करार का नाम	जारी करने की तिथि	देश/संगठन का नाम
1.	सैन्य क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत गणराज्य के रक्षा मंत्रालय और अल्जीरिया जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के बीच समझौता	01.11.2024	अल्जीरिया
2.	सीमा शुल्क मामलों में सहयोग और पारस्परिक सहायता पर बेलारूस गणराज्य सरकार और भारत गणराज्य सरकार के बीच समझौता	14.06.2024	बेलारूस
3.	ईएफटीए देशों और भारत गणराज्य के बीच व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता	08.03.2024	ईएफटीए देश
4.	भारत गणराज्य सरकार और वैश्विक जैव-ईंधन गठबंधन (जीबीए) के बीच मेजबान देश समझौता	08.10.2024	वैश्विक जैव-ईंधन गठबंधन
5.	समृद्धि के लिए हिंद-निष्पक्ष अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रशांत आर्थिक रूपरेखा समझौता	20.09.2024	आईपीईएफ
6.	स्वच्छ अर्थव्यवस्था से संबंधित समृद्धि के लिए हिंद-प्रशांत आर्थिक संरचना समझौता	20.09.2024	आईपीईएफ
7.	स्वच्छ अर्थव्यवस्था से संबंधित समृद्धि के लिए हिंद-प्रशांत आर्थिक संरचना समझौता	20.09.2024	आईपीईएफ
8.	भारत गणराज्य सरकार और लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सरकार के बीच सीमा शुल्क मामलों में सहयोग और पारस्परिक सहायता पर समझौता	14.06.2024	लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक
9.	भारत गणराज्य सरकार और मेडागास्कर गणराज्य सरकार के बीच सीमा शुल्क मामलों में सहयोग और पारस्परिक प्रशासनिक सहायता पर समझौता	16.02.2024	मेडागास्कर
10.	स्कायर किलोमीटर व्यूह वेधशाला की स्थापना के लिए सम्मेलन	21.08.2024	बहुपक्षीय
11.	सामाजिक सुरक्षा पर पोलैंड गणराज्य और भारत गणराज्य के बीच समझौता	08.11.2024	पोलैंड
12.	भारत गणराज्य और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच औषधि नीति के संबंध में समझौता-ज्ञापन	20.09.2024	संयुक्त राज्य अमेरिका
13.	उज़बेकिस्तान गणराज्य सरकार और भारत गणराज्य सरकार के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि	23.09.2024	उज़बेकिस्तान

अनुलग्नक III

जनवरी 2024 से अनुसमर्थन की सूची

क्र. सं.	नाम	हस्ताक्षर करने की तारीख	देश/संगठन	मंतालय
1.	वित्तीय प्रौद्योगिकी पर एक संयुक्त कार्य समूह के गठन पर वित्त विभाग, फिलीपींस गणराज्य सरकार और आर्थिक मामले विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के बीच समझौता-ज्ञापन	फिलिपींस	19.06.2023	03.05.2024
2.	भारत गणराज्य सरकार और डेनमार्क सरकार के बीच गतिशीलता और प्रवासन साझेदारी समझौता	डेनमार्क	22.02.2024	02.05.2024
3.	रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर भारत गणराज्य सरकार और इतालवी गणराज्य सरकार के बीच समझौता	इटली	09.10.2023	06.06.2024
4.	अर्जेंटीना गणराज्य और भारत गणराज्य के बीच सामाजिक सुरक्षा समझौता	अर्जेंटाइन	29.09.2023	24.06.2024
5.	भारत गणराज्य सरकार और बेलारूस गणराज्य सरकार के बीच सीमा शुल्क मामलों में सहयोग और पारस्परिक सहायता पर समझौता	बेलारूस	28.06.2024	11.07.2024
6.	आय पूंजीगत लाभ पर करों के संबंध में दोहरे कराधान से बचने और राजकोषीय चोरी की रोकथाम तथा पारस्परिक व्यापार और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए भारत गणराज्य सरकार और मॉरीशस सरकार के बीच कन्वेंशन को संशोधित करने वाला प्रोटोकॉल	मॉरीशस	07.03.2024	12.07.2024
7.	भारत गणराज्य सरकार और मेडागास्कर गणराज्य सरकार के बीच सीमा शुल्क मामलों में सहयोग और पारस्परिक प्रशासनिक सहायता पर समझौता	मेडागास्कर	27.06.2024	11.07.2024
8.	स्कायर किलोमीटर व्यूह वेधशाला की स्थापना के लिए सम्मेलन	एसकेएओ सदस्य देश	28.03.2024	02.05.2024
9.	उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भारतीय अनुदान सहायता के संबंध में किर्गिज़ गणराज्य की सरकार और भारत गणराज्य सरकार के बीच समझौता-ज्ञापन में संशोधन करने वाला प्रोटोकॉल, 11 अक्टूबर, 2021 को बिश्केक में हस्ताक्षरित	किर्गिज़ गणराज्य	22.01.2024	06.06.2024
10.	ब्राजील अंतरिक्ष एजेंसी, राज्य अंतरिक्ष निगम "रोस्कोस्मोस", भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन और दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी के बीच ब्रिक्स रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट तारामंडल पर सहयोग पर समझौता	ब्रिक्स सदस्य देश	18.08.2021	07.06.2024
11.	अंतर्राष्ट्रीय कॉफी समझौता (आईसीए) अंतर्राष्ट्रीय कॉफी समझौता (आईसीए)	आईसीए सदस्य देश	10.06.2024	13.08.2024
12.	उज़बेकिस्तान गणराज्य सरकार और भारत गणराज्य सरकार के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि	उज़बेकिस्तान	27.09.2024	11.10.2024
13.	भारत गणराज्य सरकार और संयुक्त अरब अमीरात की सरकार के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि	संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त अरब अमीरात	13.02.2024	27.02.2024
14.	अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (आईबीसीए) की स्थापना पर रूपरेखा समझौता	आईबीसीए सदस्य देश	18.09.2024	30.10.2024
15.	भारत गणराज्य सरकार और वैश्विक जैव-ईंधन गठबंधन (जीबीए) के बीच मेजबान देश समझौता	जीबीए सदस्य देश	11.10.2024	05.11.2024
16.	इजराइल राष्ट्र में विशिष्ट श्रम बाजार क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों के अस्थायी रोजगार की सुविधा के लिए भारत गणराज्य सरकार और इजराइल राष्ट्र सरकार के बीच समझौता	इजराइल	03.11.2023	02.01.2024
17.	इतालवी गणराज्य की सरकार के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौता	इटली	02.11.2023	09.01.2024
18.	स्वच्छ अर्थव्यवस्था से संबंधित समृद्धि के लिए हिंद-प्रशांत आर्थिक रूपरेखा समझौता	आईपीईएफ सदस्य देश	20.09.2024	11.11.2024
19.	समृद्धि के लिए हिंद-प्रशांत आर्थिक ढांचे पर निष्पक्ष अर्थव्यवस्था से संबंधित समझौता	आईपीईएफ सदस्य देश	20.09.2024	11.11.2024

2024 में संपन्न संधियों, समझौतों, समझौता-ज्ञापनों की सूची

क. मंत्रालयों द्वारा संधियों, समझौतों, समझौता ज्ञापनों की सूची

क्र. सं.	नाम	हस्ताक्षर करने की तारीख	देश/संगठन	मंत्रालय
1.	राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा आवश्यकता से छूट पर भारत गणराज्य सरकार और अंडोरा रियासत सरकार के बीच समझौता	15.03.2024	अंडोरा	विदेश मंत्रालय
2.	बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री अर्थव्यवस्था और समुद्री सहयोग के क्षेत्र में भारत गणराज्य सरकार और बांग्लादेश जनवादी गणराज्य सरकार के बीच समझौता-ज्ञापन	22.06.2024	बांग्लादेश	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
3.	स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग पर भारत गणराज्य सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और बांग्लादेश गणराज्य सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच समझौता	22.06.2024	बांग्लादेश	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
4.	रेल मंत्रालय, भारत गणराज्य सरकार और रेल मंत्रालय, जनवादी गणराज्य बांग्लादेश सरकार के बीच रेल संपर्क पर समझौता-ज्ञापन	22.06.2024	बांग्लादेश	रेल मंत्रालय
5.	मत्स्य पालन के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और बांग्लादेश के बीच समझौता-ज्ञापन	22.06.2024	बांग्लादेश	मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
6.	भारत बांग्लादेश डिजिटल साझेदारी का साझा दृष्टिकोण	22.06.2024	बांग्लादेश	विदेश मंत्रालय
7.	संघोषणीय भविष्य के लिए भारत-बांग्लादेश हरित साझेदारी का साझा दृष्टिकोण	22.06.2024	बांग्लादेश	विदेश मंत्रालय
8.	भारत गणराज्य सरकार और बेलारूस गणराज्य सरकार के बीच सीमा शुल्क मामलों में सहयोग और पारस्परिक सहायता पर समझौता	28.06.2024	बेलारूस	वित्त मंत्रालय
9.	भारत गणराज्य सरकार और भूटान शाही सरकार के बीच भारत से भूटान को पेट्रोलियम, तेल, स्नेहक (पीओएल) और संबंधित उत्पादों की सामान्य आपूर्ति पर समझौता-ज्ञापन	21.03.2024	भूटान	विदेश मंत्रालय
10.	ग्यालसुंग अवसंरचना परियोजना के लिए ऋण के संबंध में भारत सरकार और भूटान की शाही सरकार के बीच समझौता-ज्ञापन	20.01.2024	भूटान	विदेश मंत्रालय
11.	भारत गणराज्य सरकार और भूटान शाही सरकार के बीच खेल और युवा मामलों में सहयोग पर समझौता-ज्ञापन	22.03.2024	भूटान	युवा मामले और खेल मंत्रालय
12.	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और सरकारी प्रौद्योगिकी एजेंसी के बीच अंतरिक्ष सहयोग पर संयुक्त कार्य योजना	22.03.2024	भूटान	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
13.	उपग्रह और प्रक्षेपण वाहनों के लिए टेलीमेट्री ट्रैकिंग और टेलीकमांड स्टेशन के संचालन में सहयोग और अंतरिक्ष अनुसंधान विज्ञान और अनुप्रयोगों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत गणराज्य सरकार और ब्रुनेई दारुस्सलाम के महामहिम सुल्तान और यांग डि-पर्टुआन सरकार के बीच समझौता-ज्ञापन उपग्रह और प्रक्षेपण वाहनों के लिए टेलीमेट्री ट्रैकिंग और टेलीकमांड स्टेशन के संचालन में सहयोग और अंतरिक्ष अनुसंधान विज्ञान और अनुप्रयोगों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत गणराज्य सरकार और ब्रुनेई दारुस्सलाम के महामहिम सुल्तान और यांग डि-पर्टुआन सरकार के बीच समझौता-ज्ञापन	04.09.2024	ब्रुनेई दारुस्सलाम	अंतरिक्ष विभाग
14.	कंबोडिया साम्राज्य के सिविल सेवा मंत्रालय और भारत गणराज्य के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के बीच सिविल सेवा में मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता-ज्ञापन	22.04.2024	कंबोडिया	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

क्र. सं.	नाम	हस्ताक्षर करने की तारीख	देश/संगठन	मंत्रालय
15.	ऑडियो-विजुअल सह-निर्माण को बढ़ावा देने के लिए समझौता-ज्ञापन	15.10.2024	कोलंबिया	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
16.	भारत गणराज्य सरकार और डेनमार्क सरकार के बीच गतिशीलता और प्रवासन साझेदारी समझौता	22.02.2024	डेनमार्क	विदेश मंत्रालय
17.	भारत गणराज्य के बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय और डेनमार्क साम्राज्य के उद्योग, व्यापार और वित्तीय मामले मंत्रालय के बीच समुद्री मुद्दों पर समझौता-ज्ञापन	17.09.2024	डेनमार्क	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
18.	संयुक्त आर्थिक और व्यापार सहयोग पर प्रोटोकॉल (जेईटीसीओ)	12.03.2024	डोमिनिकन गणराज्य	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
19.	भारत और ईएफटीए देशों (स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और लिक्टेन्स्टीन) के बीच व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता (टीईपीए)।	10.03.2024	ईएफटीए देश (स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और लिक्टेन्स्टीन)	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
20.	डिजिटल संचार के क्षेत्र में सहयोग पर इथियोपिया संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य के सूचना नेटवर्क सुरक्षा प्रशासन और भारत गणराज्य के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच समझौता-ज्ञापन डिजिटल संचार के क्षेत्र में सहयोग पर इथियोपिया संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य के सूचना नेटवर्क सुरक्षा प्रशासन और भारत गणराज्य के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच समझौता-ज्ञापन	30.09.2024	इथियोपिया	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
21.	परामर्श तंत्र की स्थापना पर भारत गणराज्य के विदेश मंत्रालय और सेंट क्रिस्टोफर (सेंट किट्स) और नेविस के विदेश मंत्रालय के बीच समझौता-ज्ञापन	06.08.2024	सेंट क्रिस्टोफर (सेंट किट्स) और नेविस संघ	विदेश मंत्रालय
22.	डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर भारत और फिजी के बीच समझौता-ज्ञापन	12.11.2024	फिजी	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
23.	डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या स्तर पर कार्यान्वित सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता-ज्ञापन	03.10.2024	गाम्बिया	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
24.	भारत और जर्मनी के बीच आपराधिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता संधि (एमएलएटी)	24.10.2024	जर्मनी	गृह मंत्रालय
25.	रेलवे क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिए डॉयचे बान एजी और भारत गणराज्य के रेल मंत्रालय के बीच समझौता-ज्ञापन	09.02.2024	जर्मनी	रेल मंत्रालय
26.	भारत गणराज्य के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और जर्मनी संघीय गणराज्य के संघीय शिक्षा और अनुसंधान मंत्रालय और जर्मनी संघीय गणराज्य के संघीय आर्थिक सहयोग और विकास मंत्रालय के बीच कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता-ज्ञापन	24.10.2024	जर्मनी	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

क्र. सं.	नाम	हस्ताक्षर करने की तारीख	देश/संगठन	मंत्रालय
27.	भारत गणराज्य के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और जर्मनी संघीय गणराज्य के आर्थिक सहयोग और विकास के संघीय मंत्रालय के बीच भारत-जर्मनी हरित शहरी गतिशीलता साझेदारी पर संयुक्त निवेश वार्ता	24.10.2024	जर्मनी	आवासन और शहरी मामले मंत्रालय
28.	जर्मनी संघीय गणराज्य के आर्थिक मामलों और जलवायु कार्रवाई मंत्रालय तथा भारत गणराज्य के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच भारत के कॉर्पोरेट अधिकारियों के उन्नत प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग जारी रखने पर संयुक्त सहयोग वार्ता	24.10.2024	जर्मनी	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
29.	भारत गणराज्य के श्रम और रोजगार मंत्रालय तथा जर्मनी संघीय गणराज्य के श्रम और सामाजिक मामलों के मंत्रालय के बीच रोजगार और श्रम के क्षेत्र में संयुक्त सहयोग समझौता	24.10.2024	जर्मनी	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
30.	भारत गणराज्य सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) और जर्मनी संघीय गणराज्य की सरकार के संघीय शिक्षा और अनुसंधान मंत्रालय (बीएमबीएफ) के बीच उन्नत सामग्रियों पर अनुसंधान और विकास में संयुक्त सहयोग के लिए संयुक्त आशय की घोषणा	24.10.2024	जर्मनी	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
31.	भारत गणराज्य सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) और जर्मनी संघीय गणराज्य के डॉयचर एकेडेमिशरऑस्टैशडिएनस्ट (डीएएडी) (जर्मन अकादमिक विनिमय सेवा) के बीच नवाचार, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और उद्यमिता में सहयोग के लिए संयुक्त आशय घोषणा	24.10.2024	जर्मनी	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
32.	बाघ (पैंथेरा टाइग्रिस) और जगुआर (पैंथेरा ओन्का) के संरक्षण पर भारत गणराज्य सरकार और ग्वाटेमाला गणराज्य सरकार के बीच समझौता-ज्ञापन	03.05.2024	ग्वाटेमाला	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
33.	भारत सरकार और गुयाना सरकार के बीच 2024-2027 के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आदान-प्रदान (सीईपी)	20.11.2024	गुयाना	संस्कृति मंत्रालय
34.	भारत सरकार और सहकारी गणराज्य गुयाना सरकार के बीच कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर समझौता-ज्ञापन	20.11.2024	गुयाना	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
35.	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और राष्ट्रीय अनुसंधान एवं नवाचार एजेंसी (बीआरआईएन) के बीच एकीकृत बियाक टेलीमेट्री, ट्रेकिंग एवं कमांड (टीटीसी) सुविधाओं के स्वामित्व के हस्तांतरण पर कार्यान्वयन समझौता तथा उपग्रहों और प्रक्षेपण वाहनों के लिए एकीकृत बियाक टेलीमेट्री, ट्रेकिंग एवं कमांड (टीटीसी) सुविधाओं के संचालन, रखरखाव और उपयोग पर कार्यान्वयन व्यवस्था	19.03.2024	इंडोनेशिया	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
36.	इटालवी गणराज्य के पर्यावरण एवं ऊर्जा सुरक्षा मंत्रालय तथा भारत गणराज्य के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच आशय पत्र	11.06.2024	इटली	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
37.	भारत गणराज्य सरकार और जमैका सरकार के बीच खेलों में सहयोग पर समझौता-ज्ञापन	01.10.2024	जमैका	युवा मामले और खेल मंत्रालय
38.	वर्ष 2024-2029 के लिए भारत गणराज्य सरकार और जमैका सरकार के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम पर समझौता-ज्ञापन	30.09.2024	जमैका	संस्कृति मंत्रालय
39.	केन्या रक्षा बलों को सीटी स्कैन मशीन (हरित परियोजना) उपहार स्वरूप देने के लिए त्वरित प्रभाव परियोजना (क्यूआईपी) शुरू करने के लिए समझौता-ज्ञापन	23.01.2024	केन्या	विदेश मंत्रालय
40.	उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास के कार्यान्वयन के लिए भारतीय अनुदान सहायता के संबंध में किर्गिज गणराज्य की सरकार और भारत गणराज्य सरकार के बीच समझौता-ज्ञापन को संशोधित करने वाला प्रोटोकॉल	22.01.2024	किर्गिज गणराज्य	विदेश मंत्रालय

क्र. सं.	नाम	हस्ताक्षर करने की तारीख	देश/संगठन	मंत्रालय
41.	भारत और लाओ पीडीआर के बीच डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या स्तर पर कार्यान्वित सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता-ज्ञापन	27.07.2024	लाओ पीडीआर	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
42.	भारत गणराज्य सरकार और लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सरकार के बीच सीमा शुल्क मामलों में सहयोग और पारस्परिक सहायता पर समझौता	11.10.2024	लाओ पीडीआर	वित्त मंत्रालय
43.	भारत गणराज्य सरकार और मेडागास्कर गणराज्य सरकार के बीच सीमा शुल्क मामलों में सहयोग और पारस्परिक प्रशासनिक सहायता पर समझौता	27.06.2024	मेडागास्कर	वित्त मंत्रालय
44.	भारत गणराज्य सरकार और मलावी गणराज्य की सरकार के बीच खेलों में सहयोग पर समझौता-ज्ञापन	18.10.2024	मलावी	युवा मामले और खेल मंत्रालय
45.	युवा मामलों के क्षेत्र में सहयोग पर भारत गणराज्य सरकार और मलावी गणराज्य सरकार के बीच समझौता-ज्ञापन	18.10.2024	मलावी	युवा मामले और खेल मंत्रालय
46.	कला और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग पर भारत गणराज्य सरकार और मलावी गणराज्य सरकार के बीच समझौता-ज्ञापन	18.10.2024	मलावी	संस्कृति मंत्रालय
47.	वर्ष 2024-2029 के लिए संस्कृति, कला और विरासत के क्षेत्र में भारत गणराज्य सरकार और मलावी सरकार के बीच सांस्कृतिक सहयोग का कार्यक्रम	18.10.2024	मलावी	संस्कृति मंत्रालय
48.	आयुर्वेद और अन्य पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के क्षेत्र में सहयोग पर मलेशिया सरकार और भारत गणराज्य सरकार के बीच समझौता-ज्ञापन	20.08.2024	मलेशिया	आयुष मंत्रालय
49.	संस्कृति, कला और विरासत के क्षेत्र में भारत गणराज्य सरकार और मलेशिया सरकार के बीच सहयोग पर कार्यक्रम	20.08.2024	मलेशिया	संस्कृति मंत्रालय
50.	डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत गणराज्य सरकार और मलेशिया सरकार के बीच समझौता-ज्ञापन	20.08.2024	मलेशिया	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
51.	भारत सरकार और मलेशिया सरकार के बीच श्रमिकों की भर्ती, रोजगार और प्रत्यावर्तन पर समझौता-ज्ञापन	20.08.2024	मलेशिया	विदेश मंत्रालय
52.	लोक प्रशासन और शासन सुधार के क्षेत्र में सहयोग पर मलेशिया सरकार और भारत गणराज्य सरकार के बीच समझौता-ज्ञापन	20.08.2024	मलेशिया	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
53.	मलेशिया सरकार और भारत गणराज्य सरकार के बीच पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता-ज्ञापन	20.08.2024	मलेशिया	पर्यटन मंत्रालय
54.	भारत गणराज्य सरकार और मलेशिया सरकार के बीच युवा एवं खेल के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता-ज्ञापन	20.08.2024	मलेशिया	युवा मामले और खेल मंत्रालय
55.	भारत और मालदीव के बीच खेल और युवा मामलों में सहयोग पर समझौता-ज्ञापन	07.10.2024	मालदीव	युवा मामले और खेल मंत्रालय
56.	मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण और आर्थिक मामलों के विभाग के बीच मुद्रा विनिमय समझौता	07.10.2024	मालदीव	वित्त मंत्रालय
57.	भारत और मोल्दोवा के बीच राजनयिक/आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश हेतु वीजा छूट समझौते	10.05.2024	मोल्दोवा	विदेश मंत्रालय
58.	राजनयिक मिशन या कांसुलरी पोस्ट के सदस्यों के आश्रितों को लाभकारी रोजगार में संलग्न होने के लिए अधिकृत करने के लिए भारत गणराज्य सरकार और माल्टा गणराज्य सरकार के बीच समझौता	24.06.2024	माल्टा	विदेश मंत्रालय

क्र. सं.	नाम	हस्ताक्षर करने की तारीख	देश/संगठन	मंत्रालय
59.	राजनयिकों के प्रशिक्षण में सहयोग पर भारत गणराज्य सरकार और मॉरिटानिया राजनयिक अकादमी, विदेश मंत्रालय, इस्लामी गणराज्य मॉरिटानिया के बीच समझौता-ज्ञापन	16.10.2024	मॉरिटानिया	विदेश मंत्रालय
60.	भारत सरकार और मॉरिटानिया इस्लामिक गणराज्य सरकार के बीच 2024-2029 के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (सीईपी)	17.10.2024	मॉरिटानिया	संस्कृति मंत्रालय
61.	आय और पूंजीगत लाभ पर करों के संबंध में दोहरे कराधान से बचने और राजकोषीय चोरी की रोकथाम तथा पारस्परिक व्यापार निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए भारत गणराज्य सरकार और मॉरीशस सरकार के बीच कन्वेंशन को संशोधित करने वाला प्रोटोकॉल	07.03.2024	मॉरीशस	वित्त मंत्रालय
62.	राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा आवश्यकता से छूट पर भारत गणराज्य सरकार और माइक्रोनेशिया संघीय राज्य सरकार के बीच समझौता	19.02.2024	माइक्रोनेशिया	विदेश मंत्रालय
63.	अंतर्राष्ट्रीय कॉफी समझौता 2022	10.06.2024	बहुपक्षीय	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
64.	यांगून में सरसोबेइकमन भवन के निर्माण पर समझौता-ज्ञापन	18.03.2024	म्यांमार	विदेश मंत्रालय
65.	त्वरित प्रभाव परियोजना के तहत म्यांमार के मांडले क्षेत्र में बालिका प्रशिक्षण स्कूल के लिए एक मंजिला भवन का निर्माण	14.10.2024	म्यांमार	विदेश मंत्रालय
66.	त्वरित प्रभाव परियोजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के लिए यांगून क्षेत्र के आपातकालीन परिचालन केंद्र (ईओसी) की स्थापना	14.10.2024	म्यांमार	विदेश मंत्रालय
67.	त्वरित प्रभाव परियोजना के अंतर्गत बुनाई एवं व्यावसायिक क्षेत्र विकास परियोजना	14.10.2024	म्यांमार	विदेश मंत्रालय
68.	त्वरित प्रभाव परियोजना के तहत कृषि विकास और किसान कल्याण के लिए ड्रायर और ड्रायर हाउस	14.10.2024	म्यांमार	विदेश मंत्रालय
69.	त्वरित प्रभाव परियोजना के तहत एसीएआरई ज्ञान भंडार का कार्यान्वयन	14.10.2024	म्यांमार	विदेश मंत्रालय
70.	त्वरित प्रभाव परियोजना के तहत म्यांमार के विकास प्रशासन संस्थान के लिए वस्तुओं और उपकरणों का प्रावधान	24.10.2024	म्यांमार	विदेश मंत्रालय
71.	त्वरित प्रभाव परियोजना के तहत म्यांमार के विकास प्रशासन संस्थान के लिए वस्तुओं और उपकरणों का प्रावधान	24.10.2024	म्यांमार	विदेश मंत्रालय
72.	डिजिटल फॉरेंसिक प्रयोगशाला उन्नयन परियोजना	24.10.2024	म्यांमार	विदेश मंत्रालय
73.	त्वरित प्रभाव परियोजना के तहत यांगून टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रयोगशाला की स्थापना	24.10.2024	म्यांमार	विदेश मंत्रालय
74.	त्वरित प्रभाव परियोजना के तहत म्यांमार के ग्रामीण विकास के लिए कृषि अपशिष्ट के धीमी पायरोलिसिस उत्पादों के साथ टार-मुक्त और शुष्क प्रकार के गैसीकरण प्रक्रिया की जांच	24.10.2024	म्यांमार	विदेश मंत्रालय
75.	भारतीय दूतावास, यांगून, भारत गणराज्य सरकार और सीमा क्षेत्रों और राष्ट्रीय नस्लों के प्रगति विभाग, सीमा मामलों के मंत्रालय, म्यांमार संघ गणराज्य सरकार के बीच त्वरित प्रभाव परियोजनाओं के तहत “नागा स्व-प्रशासित क्षेत्र में लाहे-नानयुन के 3/6 मील जंक्शन रोड से लौंगक्यानाउकोने-ताइक्यान-लान्हुटेन जंक्शन तक 20 फीट बेली ब्रिज और चार (5x5x26) फीट बॉक्स कलवर्ट का निर्माण” के लिए समझौता-ज्ञापन	09.01.2024	म्यांमार	विदेश मंत्रालय
76.	भारतीय दूतावास, यांगून, भारत गणराज्य सरकार और सीमा क्षेत्रों और राष्ट्रीय जातियों के प्रगति विभाग, सीमा मामलों के मंत्रालय, म्यांमार संघ गणराज्य सरकार के बीच त्वरित प्रभाव परियोजनाओं के तहत “नागा स्व-प्रशासित क्षेत्र में लाहे टाउनशिप के टिकेयान गांव के पास 60x30x12 फीट स्टील संरचना बहुउद्देश्यीय सामुदायिक हॉल के निर्माण” के लिए समझौता-ज्ञापन	09.01.2024	म्यांमार	विदेश मंत्रालय

क्र. सं.	नाम	हस्ताक्षर करने की तारीख	देश/संगठन	मंत्रालय
77.	भारत और नाउरू के बीच राजनयिक/आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश हेतु वीजा छूट समझौते	17.09.2024	नाउरू	विदेश मंत्रालय
78.	सरकारी संगठन या किसी अन्य संगठन के माध्यम से उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं (एचआईसीडीपी) के कार्यान्वयन के लिए भारतीय अनुदान सहायता के संबंध में नेपाल सरकार और भारत सरकार के बीच समझौता	04.01.2024	नेपाल	विदेश मंत्रालय
79.	भारत गणराज्य सरकार और नेपाल सरकार के बीच दीर्घकालिक विद्युत व्यापार पर समझौता	04.01.2024	नेपाल	विदेश मंत्रालय
80.	भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीमा शुल्क सहयोग व्यवस्था	01-08-2024	न्यूजीलैंड	वित्त मंत्रालय
81.	भारत गणराज्य सरकार के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड तथा न्यूजीलैंड सीमा शुल्क सेवा के बीच सीमा शुल्क मामले में सहयोगात्मक व्यवस्था	06.08.2024	न्यूजीलैंड	वित्त मंत्रालय
82.	भारत सरकार और नाइजीरिया सरकार के बीच 2024-2029 के लिए सांस्कृतिक सहयोग एवं आदान-प्रदान का कार्यक्रम	15.11.2024	नाइजीरिया	संस्कृति मंत्रालय
83.	सूरीनाम में फल प्रसंस्करण उद्योग में सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसईएस) विकसित करने पर समझौता-ज्ञापन	05.11.2024	सूरीनाम गणराज्य	विदेश मंत्रालय
84.	भारत गणराज्य के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा रूसी संघ के आर्थिक विकास मंत्रालय के बीच जलवायु परिवर्तन एवं निम्न कार्बन विकास के मुद्दों पर समझौता-ज्ञापन।	08.07.2024	रूस	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
85.	भारत गणराज्य सरकार तथा सेंट क्रिस्टोफर (सेंट किट्स) एवं नेविस संघ सरकार के बीच खेलों में सहयोग पर समझौता-ज्ञापन	05.08.2024	सेंट क्रिस्टोफर (सेंट किट्स) और नेविस संघ	खेल विभाग, युवा मामले और खेल मंत्रालय, भारत
86.	राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा आवश्यकता से छूट पर समझौता	16.04.2024	सेंट लूसिया	विदेश मंत्रालय
87.	सेंट व्हिसेंट और ग्रेनेडाईस में पत्तेदार सब्जियों और जड़ वाली फसलों के प्रसंस्करण और पैकेजिंग सुविधा के लिए एक संयंत्र की स्थापना पर समझौता-ज्ञापन	29.10.2024	सेंट व्हिसेंट और ग्रेनेडाईस	विदेश मंत्रालय
88.	पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग पर शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की सरकारों के बीच समझौता	04.07.2024	शंघाई सहयोग संगठन	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
89.	कानून और विवाद समाधान के क्षेत्र में सहयोग पर भारत के विधि और न्याय मंत्रालय और सिंगापुर के विधि मंत्रालय के बीच समझौता-ज्ञापन	14.03.2024	सिंगापुर	विधि एवं न्याय मंत्रालय
90.	डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत गणराज्य के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सिंगापुर गणराज्य के डिजिटल विकास और सूचना मंत्रालय के बीच समझौता-ज्ञापन	26.08.2024	सिंगापुर	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
91.	भारत गणराज्य के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सिंगापुर गणराज्य के व्यापार और उद्योग मंत्रालय के बीच भारत-सिंगापुर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम साझेदारी पर समझौता-ज्ञापन	26.08.2024	सिंगापुर	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
92.	स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग पर भारत गणराज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और सिंगापुर गणराज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच समझौता-ज्ञापन	29.08.2024	सिंगापुर	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
93.	भारत गणराज्य के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और सिंगापुर गणराज्य के मंत्रालय के बीच शैक्षिक सहयोग और कौशल विकास पर समझौता-ज्ञापन	29.08.2024	सिंगापुर	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

क्र. सं.	नाम	हस्ताक्षर करने की तारीख	देश/संगठन	मंत्रालय
94.	भारत गणराज्य के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सिंगापुर गणराज्य के व्यापार और उद्योग मंत्रालय के बीच भारत-सिंगापुर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम साझेदारी पर समझौता-ज्ञापन	26.08.2024	सिंगापुर	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
95.	स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग पर भारत गणराज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और सिंगापुर गणराज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच समझौता-ज्ञापन	29.08.2024	सिंगापुर	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
96.	भारत गणराज्य के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और सिंगापुर गणराज्य के मंत्रालय के बीच शैक्षिक सहयोग और कौशल विकास पर समझौता-ज्ञापन	29.08.2024	सिंगापुर	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
97.	दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय और भारत गणराज्य सरकार के बीच आर्थिक सहयोग पर समझौता-ज्ञापन	02.07.2024	दक्षिण अफ्रीका	विदेश मंत्रालय
98.	रेल परिवहन के क्षेत्र में सहयोग पर भारत गणराज्य के रेल मंत्रालय और स्पेन साम्राज्य के परिवहन और सतत विकास गतिशीलता मंत्रालय के बीच समझौता-ज्ञापन	28.10.2024	स्पेन	रेल मंत्रालय
99.	वर्ष 2024-28 के लिए भारत गणराज्य सरकार और स्पेन साम्राज्य सरकार के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम	28.10.2024	स्पेन	संस्कृति मंत्रालय
100.	सीमा शुल्क मामलों में सहयोग और पारस्परिक सहायता के संबंध में भारत गणराज्य सरकार और स्पेन साम्राज्य के बीच समझौता।	28.10.2024	स्पेन	वित्त मंत्रालय
101.	सीमा शुल्क मामलों में सहयोग और पारस्परिक सहायता के संबंध में भारत गणराज्य सरकार और स्पेन साम्राज्य के बीच समझौता	28.10.2024	स्पेन	वित्त मंत्रालय
102.	रेलवे में तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए भारत गणराज्य सरकार के रेल मंत्रालय और स्विट्ज़रलैंड परिसंच के पर्यावरण, परिवहन और संचार संघीय विभाग के बीच समझौता-ज्ञापन	29.10.2024	स्विट्ज़रलैंड	रेल मंत्रालय
103.	भारत और नीदरलैंड के बीच नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता-ज्ञापन	12.09.2024	नीदरलैंड	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
104.	वर्ष 2024-2028 के लिए भारत गणराज्य सरकार और तिमोर-लेस्ते लोकतांत्रिक गणराज्य की सरकार के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम	10.08.2024	तिमोर-लेस्ते	संस्कृति मंत्रालय
105.	राजनयिक और आधिकारिक या सेवा पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा आवश्यकता से छूट पर भारत गणराज्य सरकार और तिमोर-लेस्ते लोकतांत्रिक गणराज्य की सरकार के बीच समझौता	10.08.2024	तिमोर-लेस्ते	विदेश मंत्रालय
106.	भारत गणराज्य सरकार के विदेश मंत्रालय और टोगो गणराज्य की सरकार के विदेश मामले, क्षेत्रीय एकीकरण और टोगोली विदेश मंत्रालय के बीच परामर्श के लिए समझौता-ज्ञापन	27.06.2024	टोगो	विदेश मंत्रालय
107.	भारत गणराज्य सरकार के विदेश मंत्रालय और टोगो गणराज्य की सरकार के विदेश मामलों, क्षेत्रीय एकीकरण और टोगोली विदेश मंत्रालय के बीच राजनयिक, आधिकारिक और सेवा पासपोर्ट धारकों के लिए पारस्परिक वीजा छूट पर समझौता	27.06.2024	टोगो	विदेश मंत्रालय
108.	भारत गणराज्य सरकार और यूक्रेन सरकार के बीच कृषि और खाद्य उद्योग के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता	23.08.2024	यूक्रेन	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
109.	वर्ष 2024-2028 के लिए भारत गणराज्य सरकार के संस्कृति मंत्रालय और यूक्रेन के संस्कृति और सूचना नीति मंत्रालय के बीच सांस्कृतिक सहयोग कार्यक्रम	23.08.2024	यूक्रेन	संस्कृति मंत्रालय
110.	उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भारतीय मानवीय अनुदान सहायता के संबंध में भारत गणराज्य सरकार और यूक्रेन के कैबिनेट मंत्रियों के बीच समझौता-ज्ञापन	23.08.2024	यूक्रेन	विदेश मंत्रालय

क्र. सं.	नाम	हस्ताक्षर करने की तारीख	देश/संगठन	मंत्रालय
111.	भारत गणराज्य सरकार और संयुक्त अरब अमीरात की सरकार के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि	13.02.2024	संयुक्त अरब अमीरात	वित्त मंत्रालय
112.	राजनयिक और कांसुलरी मिशनों के राजनयिक, कांसुलरी, प्रशासनिक और तकनीकी कार्मिकों के परिवार के सदस्यों द्वारा पारिश्रमिक गतिविधियों के निष्पादन पर उरुग्वे गणराज्य और भारत गणराज्य सरकार के बीच समझौता	16.09.2024	उरुग्वे	विदेश मंत्रालय
113.	उज़्बेकिस्तान गणराज्य सरकार और भारत गणराज्य सरकार के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि	27.09.2024	उज़्बेकिस्तान	वित्त मंत्रालय
114.	औषधीय पौधों के क्षेत्र में सहयोग पर वियतनाम समाजवादी गणराज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय के पारंपरिक चिकित्सा प्रशासन और भारत गणराज्य सरकार के आयुष मंत्रालय के राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड के बीच समझौता-ज्ञापन	31.07.2024	वियतनाम	आयुष मंत्रालय
115.	राजनयिक मिशन या कांसुलरी पोस्ट के सदस्यों के आश्रितों को लाभकारी रोजगार में संलग्न होने के लिए अधिकृत करने के लिए भारत गणराज्य सरकार और वियतनाम समाजवादी गणराज्य की सरकार के बीच समझौता	01.08.2024	वियतनाम	विदेश मंत्रालय
116.	वियतनाम के क्वांग नाम प्रांत के माई सन में एफ ब्लॉक के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए भारत गणराज्य सरकार और वियतनाम समाजवादी गणराज्य की सरकार के बीच आशय पत्र	01.08.2024	वियतनाम	विदेश मंत्रालय
117.	विधिक क्षेत्र में सहयोग पर वियतनाम समाजवादी गणराज्य के न्याय मंत्रालय और भारत गणराज्य सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय के बीच समझौता-ज्ञापन	31.07.2024	वियतनाम	विधि एवं न्याय मंत्रालय
118.	गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (एनएचएमसी) के सहयोग और विकास पर भारत गणराज्य के बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय और वियतनाम समाजवादी गणराज्य के संस्कृति, खेल और पर्यटन मंत्रालय के बीच समझौता-ज्ञापन	01.08.2024	वियतनाम	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
119.	वियतनाम के क्वांग नाम प्रांत के माई सन में एफ ब्लॉक के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए भारत गणराज्य सरकार और वियतनाम समाजवादी गणराज्य की सरकार के बीच आशय पत्र	01.08.2024	वियतनाम	विदेश मंत्रालय

ख. सरकारी निकायों द्वारा संधियों, समझौतों, समझौता ज्ञापनों की सूची

क्र. सं.	नाम	हस्ताक्षर करने की तारीख	देश/संगठन	मंत्रालय
1.	17-20 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के 9 ^{वें} संस्करण के दौरान राष्ट्रीय नवाचार फाउंडेशन (एनआईएफ), भारत और आर्मेनिया के राष्ट्रीय नवाचार और उद्यमिता केंद्र (एनसीआईई) के बीच समझौता-ज्ञापन।	17.01.2024	आर्मेनिया	राष्ट्रीय नवाचार फाउंडेशन
2.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), गृह मंत्रालय, भारत और आपदा प्रबंधन एवं राहत मंत्रालय, बांग्लादेश के बीच आपदा प्रबंधन, लचीलापन और शमन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता-ज्ञापन	22.06.2024	बांग्लादेश	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
3.	हिंद महासागर के समुद्र विज्ञान पर संयुक्त अनुसंधान और क्षमता निर्माण के लिए सीएसआईआर, भारत और बीओआरआई, बांग्लादेश के बीच समझौता-ज्ञापन	22.06.2024	बांग्लादेश	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद
4.	भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (इन-स्पेस), भारत और डाक, दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बांग्लादेश के बीच डाक, दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बांग्लादेश द्वारा उपयोग के लिए एक संयुक्त लघु उपग्रह परियोजना पर सहयोग के लिए समझौता-ज्ञापन	22.06.2024	बांग्लादेश	अंतरिक्ष विभाग
5.	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और सरकारी प्रौद्योगिकी एजेंसी के बीच अंतरिक्ष सहयोग पर संयुक्त कार्य योजना	22.03.2024	भूटान	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
6.	नेशनल नॉलेज नेटवर्क ऑफ इंडिया (एनकेएन) राष्ट्रीय सूचना केंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सरकारी प्रौद्योगिकी (गवटेक) एजेंसी (ड्रक रिसर्च एंड एजुकेशन नेटवर्क) के बीच पीयरिंग व्यवस्था पर समझौता-ज्ञापन	22.03.2024	भूटान	राष्ट्रीय सूचना केंद्र
7.	भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भूटान खाद्य एवं औषधि प्राधिकरण (बीएफडीए), स्वास्थ्य मंत्रालय, भूटान की शाही सरकार द्वारा प्रयोग किये जाने वाले आधिकारिक नियंत्रण को मान्यता प्रदान करने के लिए समझौता	22.03.2024	भूटान	भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
8.	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली और ऊर्जा विभाग, ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय, भूटान सरकार, थिम्पू के बीच ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण उपायों के क्षेत्र में सहयोग पर	22.03.2024	भूटान	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
9.	ऊर्जा मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली और ऊर्जा विभाग, ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय, भूटान सरकार, थिम्पू के बीच ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण मंत्रालय के क्षेत्र में सहयोग	22.03.2024	भूटान	भारतीय फार्माकोपिया आयोग
10.	न्यायिक सहयोग के क्षेत्र में भूटान के सर्वोच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बीच समझौता-ज्ञापन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और श्री वजेरा फाउंडेशन और संबद्ध संस्थानों के बीच समझौता-ज्ञापन	09.10.2024	भूटान	भारत का सर्वोच्च न्यायालय
11.	अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और श्री वजेरा फाउंडेशन और संबद्ध संस्थानों के बीच समझौता-ज्ञापन	09.01.2024	ब्राज़िल	अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान
12.	ब्रिक्स के औषधि विनियामक प्राधिकरणों के बीच "मानव उपयोग के लिए चिकित्सा उत्पादों के विनियमन के क्षेत्र में सहयोग" पर समझौता-ज्ञापन	01.02.2024	ब्रिक्स	केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन
13.	चिकित्सा उत्पाद विनियमन के क्षेत्र में सहयोग पर केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत गणराज्य सरकार और चिली के सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान के बीच समझौता-ज्ञापन	18.10.2024	चिली	केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन

क्र. सं.	नाम	हस्ताक्षर करने की तारीख	देश/संगठन	मंत्रालय
14.	भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) और डोमिनिकन गणराज्य के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान कार्यालय (ओएनएएमईटी) के बीच समझौता-ज्ञापन	24.04.2024	डोमिनिकन गणराज्य	भारतीय मौसम विज्ञान विभाग
15.	गन्ना प्रसंस्करण और जनशक्ति विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए एनएसआई, कानपुर भारत और एफएससी, लौटोका, फिजी के बीच समझौता-ज्ञापन	19.03.2024	फिजी	एनएसआई
16.	सुनामी पूर्व चेतावनी के क्षेत्र में अनुसंधान सहयोग के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (आईएनसीओआईएस), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस), भारत और हेल्महोल्ट्ज़ सेंटर पोर्ट्सडैम (जीएफजेड) जर्मन भूविज्ञान अनुसंधान केंद्र, जर्मनी के बीच समझौता-ज्ञापन (एमओयू)	16.10.2024	जर्मनी	भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र
17.	नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च (एनसीपीओआर) और अल्फ्रेड-वेगेनर इंस्टीट्यूट हेल्महोल्ट्ज़ जेंट्रमफ्यूर पोलर और मीर्सफोर्सचुंग (एडब्ल्यूआई) के बीच ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान पर समझौता-ज्ञापन	14.10.2024	जर्मनी	राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र
18.	मैक्स-प्लैंक-गेसेलशाफ्टे.वी. के बीच समझौता-ज्ञापन। (एमपीजी) और नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज (एनसीबीएस), टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (टीआईएफआर)	21.10.2024	जर्मनी	राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केंद्र
19.	भारत गणराज्य के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और हेलेनिक गणराज्य के प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के कार्यालय के बीच सुरक्षा मुद्दों पर वार्ता के लिए समझौता-ज्ञापन	27.02.2024	हेलेनिक गणराज्य	भारत गणराज्य का राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय
20.	भारतीय अध्ययन के आईसीसीआर अध्यक्ष की स्थापना पर आईसीसीआर और आई गुस्ती बागस सुग्रीवा देनपसार के राज्य हिंदू विश्वविद्यालय के बीच समझौता-ज्ञापन	16.05.2024	इंडोनेशिया	भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद
21.	आईसीसीआर और आईजीबी सुग्रीवा, बाली के राजकीय हिंदू विश्वविद्यालय के बीच भारतीय अध्ययन के आईसीसीआर चेयर की स्थापना पर समझौता-ज्ञापन	16.05.2024	इंडोनेशिया	भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद
22.	भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और बैंक इंडोनेशिया (बीआई) के बीच सीमा पार लेनदेन के लिए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक ढांचा स्थापित करने के लिए समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए	07.03.2024	इंडोनेशिया	भारतीय रिजर्व बैंक
23.	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और राष्ट्रीय अनुसंधान एवं नवाचार एजेंसी (बीआरआईएन) के बीच एकीकृत बियाक टेलीमेट्री, ट्रेकिंग एवं कमांड (टीटीसी) सुविधाओं के स्वामित्व के हस्तांतरण पर कार्यान्वयन समझौता तथा उपग्रहों और प्रक्षेपण वाहनों के लिए एकीकृत बियाक टेलीमेट्री, ट्रेकिंग एवं कमांड (टीटीसी) सुविधाओं के संचालन, रखरखाव और उपयोग पर कार्यान्वयन व्यवस्था	19.03.2024	इंडोनेशिया	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
24.	भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) और मिलान विश्वविद्यालय के बीच भारतीय अध्ययन के आईसीसीआर चेयर की स्थापना पर समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर	13.09.2024	इटली	भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद
25.	भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) के तहत आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड, सीपीएसयू और उस्त-कामेनोगोर्स्क टाइटेनियम एंड मैग्नीशियम प्लांट जेएससी, (यूकेटीएमपी जेएससी) कजाकिस्तान के बीच भारत में टीआई स्लैग के उत्पादन के लिए इंडो-कजाख संयुक्त उद्यम कंपनी (जेबीसी): आईआरईयूके टाइटेनियम लिमिटेड की स्थापना के लिए समझौता	05.11.2024	कजाखस्तान	आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड
26.	बहरीन साम्राज्य के राष्ट्रीय लेखापरीक्षा कार्यालय और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के बीच सहयोग बढ़ाने, द्विपक्षीय संबंध विकसित करने और मैत्री, पारस्परिक हितों और आपसी समझ के आधार पर अपने देशों में लेखापरीक्षा गतिविधियों को मजबूत करने के लिए समझौता-ज्ञापन	27.08.2024	बहरीन साम्राज्य	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

क्र. सं.	नाम	हस्ताक्षर करने की तारीख	देश/संगठन	मंत्रालय
27.	पूजी बाजार प्राधिकरण (सीएमए) और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) के बीच वित्तीय उत्पादों, सेवाओं और संस्थानों के विकास और विनियमन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता-ज्ञापन-गिफ्ट सिटी	23.04.2024	कुवैत	अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण
28.	खाड़ी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (जीयूएसटी), कुवैत में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) की भारतीय अध्ययन/हिंदी भाषा की पीठ स्थापित करने के लिए समझौता-ज्ञापन	12.09.2024	कुवैत	भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद
29.	प्रसार भारती और लाओ राष्ट्रीय टेलीविजन के बीच प्रसारण सहयोग पर समझौता-ज्ञापन	11.10.2024	लाओ पीडीआर	प्रसार भारती
30.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद-जीनोमिक्स और एकीकृत जीवविज्ञान संस्थान (सीएसआईआर-आईजीआईबी) और लीपज़िग विश्वविद्यालय के बीच संक्रामक रोग जीनोमिक्स में सहयोगी अनुसंधान और विकास के लिए जेडीआई	21.10.2024	लीपज़िग विश्वविद्यालय, जर्मनी	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद
31.	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद – जीनोमिक्स और एकीकृत जीवविज्ञान संस्थान (सीएसआईआर – आईजीआईबी), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), लीपजिग विश्वविद्यालय और भारत में उद्योग भागीदारों के बीच नैदानिक उद्देश्यों के लिए मोबाइल सूटकेस लैब पर साझेदारी के लिए जेडीआई	24.10.2024	लीपज़िग विश्वविद्यालय, जर्मनी	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद
32.	भारत गणराज्य सरकार और मलावी गणराज्य सरकार के बीच फार्माकोपियल सहयोग पर समझौता-ज्ञापन	18.10.2024	मलावी	भारतीय फार्माकोपिया आयोग
33.	पारस्परिक सहयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) और लाबुआन वित्तीय सेवा प्राधिकरण (एलएफएसए) के बीच समझौता-ज्ञापन	19.05.2024	मलेशिया	अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण
34.	पारस्परिक सहयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) और लाबुआन वित्तीय सेवा प्राधिकरण (एलएफएसए) के बीच समझौता-ज्ञापन	19.08.2024	मलेशिया	अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण
35.	मालदीव अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र और भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के बीच समझौता-ज्ञापन	26.07.2024	मालदीव	भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र
36.	मालदीव के सिविल सेवकों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम पर भारतीय राष्ट्रीय सुशासन केंद्र और मालदीव के सिविल सेवा आयोग के बीच समझौता-ज्ञापन	09.08.2024	मालदीव	राष्ट्रीय सुशासन केंद्र
37.	आर्थिक विकास मंत्रालय और एनसीपीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के बीच मालदीव में भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) को पेश करने के लिए समझौता-ज्ञापन	09.08.2024	मालदीव	एनसीपीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड
38.	भ्रष्टाचार रोकथाम और उससे निपटने पर द्विपक्षीय सहयोग के लिए मालदीव के भ्रष्टाचार निरोधक आयोग (एसीसी) और भारत के केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के बीच समझौता-ज्ञापन	06.10.2024	मालदीव	केंद्रीय जांच ब्यूरो
39.	भ्रष्टाचार रोकथाम और उससे निपटने पर द्विपक्षीय सहयोग के लिए मालदीव के भ्रष्टाचार निरोधक आयोग (एसीसी) और भारत के केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के बीच समझौता-ज्ञापन	06.10.2024	मालदीव	केंद्रीय जांच ब्यूरो
40.	मालदीव के न्यायिक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों पर भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी (एनजेएआई) और मालदीव के न्यायिक सेवा आयोग (जेएससी) के बीच समझौता-ज्ञापन	07.10.2024	मालदीव	भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी
41.	राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और मालदीव के राष्ट्रीय पुलिस और कानून प्रवर्तन कॉलेज के बीच सहयोग के लिए समझौता-ज्ञापन	07.10.2024	मालदीव	राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय

क्र. सं.	नाम	हस्ताक्षर करने की तारीख	देश/संगठन	मंत्रालय
42.	प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के तहत दवाओं की आपूर्ति पर मेसर्स हिल लाइफकेयर लिमिटेड और स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय, मॉरीशस के बीच समझौता	28.02.2024	मॉरीशस	मेसर्स हिल लाइफकेयर लिमिटेड
43	भारतीय फार्माकोपिया आयोग (आईपीसी), भारत गणराज्य सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और नाउरू गणराज्य की सरकार के बीच स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवा विभाग, सरकारी भवन, यारेन जिला, नाउरू गणराज्य के माध्यम से फार्माकोपिया सहयोग पर समझौता-ज्ञापन (एमओयू)	17.09.2024	नाउरू	भारतीय फार्माकोपिया आयोग
44.	नेपाल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अकादमी (एनएएसटी) और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल), अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार के तहत एक सीपीएसई के बीच ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी) पर मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण सेवाओं के लिए समझौता	04.01.2024	नेपाल	न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एनटीपीसी (नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन) लिमिटेड
45.	नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनईए) और एनटीपीसी लिमिटेड के बीच नवीकरणीय ऊर्जा विकास में सहयोग के लिए समझौता-ज्ञापन	04.01.2024	नेपाल	न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एनटीपीसी (नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन) लिमिटेड
46.	सार्वजनिक क्षेत्र लेखापरीक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर भारत गणराज्य के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और नेपाल के महालेखापरीक्षक कार्यालय के बीच समझौता-ज्ञापन	02.05.2024	नेपाल	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
47.	भारतीय फार्माकोपिया आयोग (आईपीसी), भारत गणराज्य सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और निकारागुआ गणराज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच दवाओं के विनियमन के क्षेत्र में फार्माकोपिया सहयोग पर समझौता-ज्ञापन	28.02.2024	निकारागुआ	भारतीय फार्माकोपिया आयोग
48.	परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में सहयोग के लिए वैश्विक परमाणु ऊर्जा भागीदारी केंद्र (जीसीएनईपी), परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत गणराज्य सरकार और पेरू गणराज्य के पेरूवियन परमाणु ऊर्जा संस्थान (आईपीईएन) के बीच समझौता-ज्ञापन	15.03.2024	पेरू	वैश्विक परमाणु ऊर्जा भागीदारी केंद्र
49.	पेरू के केंद्रीय रिजर्व बैंक और एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (एनआईपीएल) के बीच यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के समान पेरू में एक खुदरा भुगतान मंच बनाने के लिए समझौता	04.06.2024	पेरू	भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम अंतर्राष्ट्रीय भुगतान लिमिटेड
50.	बुल्गारिया गणराज्य के राष्ट्रीय लेखापरीक्षा कार्यालय और भारत गणराज्य के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय के बीच सहयोग पर समझौता	17.04.2024	बुल्गारिया गणराज्य	नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
51.	ध्रुवीय क्षेत्रों में अनुसंधान और रसद में सहयोग पर राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार और आर्कटिक और अंटार्कटिक अनुसंधान संस्थान के बीच समझौता-ज्ञापन	09.7.2024	रूस	राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र
52.	प्रसार भारती, भारत और एएनओ "टीवी-नोवोस्ती" (रूस टुडे टीवी चैनल), रूस के बीच प्रसारण पर सहयोग और सहभागिता पर समझौता-ज्ञापन	09.7.2024	रूस	प्रसार भारती
53.	भारतीय फार्माकोपिया आयोग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत गणराज्य सरकार और रूसी संघ के स्वास्थ्य मंत्रालय के संघीय राज्य बजटीय संस्थान "औषधीय उत्पादों के विशेषज्ञ मूल्यांकन के लिए वैज्ञानिक केंद्र" के बीच समझौता-ज्ञापन	09.7.2024	रूस	भारतीय फार्माकोपिया आयोग
54.	भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र और रूसी संघ के चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता न्यायालय के बीच सहयोग समझौता	9.7.2024	रूस	भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र

क्र. सं.	नाम	हस्ताक्षर करने की तारीख	देश/संगठन	मंत्रालय
55.	भारतीय सर्वेक्षण और फेडरल सर्विस फॉर स्टेट रजिस्ट्रेशन, कैडस्ट्रे एंड कार्टोग्राफी, रूसी संघ के बीच समझौता-ज्ञापन	9.7.2024	रूस	भारतीय सर्वेक्षण
56.	केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और संघीय राज्य संस्थान “राज्य औषधि और अच्छे आचरण संस्थान” (एफएसआई “एसआईडी और जीपी”) के बीच सहयोग समझौता	9.7.2024	रूस	केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन
57.	2024 से 2029 तक की अवधि के लिए रूस के सुदूर पूर्व में व्यापार, आर्थिक और निवेश क्षेत्रों में भारत-रूस सहयोग का कार्यक्रम और साथ ही रूसी संघ के आर्कटिक क्षेत्र में सहयोग के सिद्धांत	09.7.2024	रूस	नीति आयोग
58.	सार्वजनिक क्षेत्र की लेखापरीक्षा के क्षेत्र में समझौता-ज्ञापन	29.08.2024	सऊदी अरब	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
59.	डिजिटल सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता-ज्ञापन	16.10.2024	सऊदी अरब	भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, संचार मंत्रालय
60.	सार्वजनिक क्षेत्र की लेखा परीक्षा में सहयोग के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और सेशेल्स के महालेखापरीक्षक कार्यालय के बीच समझौता-ज्ञापन	21.10.2024	सेशेल्स	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
61.	भारत गणराज्य के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और सेशेल्स गणराज्य के महालेखापरीक्षक कार्यालय के बीच सार्वजनिक क्षेत्र लेखापरीक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता-ज्ञापन	21.10.2024	सेशेल्स	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
62.	अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर पारस्परिक मान्यता व्यवस्था (एईओ-एमआरए) के चरणबद्ध वार्ता के लिए संयुक्त कार्य योजना	20.02.2024	सिंगापुर	केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
63.	भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) और स्लोवाक मानक, मेट्रोलॉजी और परीक्षण कार्यालय (यूएनएमएस एसआर) के बीच समझौता-ज्ञापन का 5 वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकरण (जुलाई 2025 तक)	22.02.2024	सिंगापुर	भारतीय मानक ब्यूरो
64.	सूचना, विशेषज्ञों के आदान-प्रदान और संयुक्त वैज्ञानिक एवं नवाचार परियोजनाओं को समर्थन देने के लिए विकासशील देशों के लिए आरआईएस अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली तथा स्लोवेनियाई विज्ञान फाउंडेशन के बीच वैज्ञानिक एवं नवाचार सहयोग पर ज्ञापन	06.02.2024	स्लोवेनिया	विकासशील देशों के लिए आरआईएस अनुसंधान और सूचना प्रणाली
65.	शिक्षा, विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए नोवा विश्वविद्यालय में भारत अध्ययन केंद्र की स्थापना पर आईसीसीआर और न्यू यूनियर्सिटी के बीच समझौता-ज्ञापन	09.09.2024	स्लोवेनिया	भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद
66.	सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के क्षेत्र में सहयोग पर राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी), भारत गणराज्य और उद्योग एवं नवीन प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमआईएनटी), ताजिकिस्तान गणराज्य के बीच समझौता-ज्ञापन	28.10.2024	ताजिकिस्तान	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड
67.	आयुर्वेद और थाई पारंपरिक चिकित्सा में अकादमिक सहयोग की स्थापना पर आयुष मंत्रालय, भारत के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर और सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय, थाईलैंड के थाई पारंपरिक और वैकल्पिक चिकित्सा विभाग के बीच समझौता-ज्ञापन	27.02.2024	थाईलैंड	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान
68.	प्रसार भारती, भारत और रेडियो ई टेलीविआओ डे तिमोर-लेस्ते, एम्प्रेस पब्लिका (आरटीटीएल ई.पी.) के बीच प्रसारण पर सहयोग के लिए समझौता-ज्ञापन	10.08.2024	तिमोर-लेस्ते	प्रसार भारती
69.	संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रीय पुस्तकालय और अभिलेखागार तथा भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के बीच 13-02-2024 को एक (1) वर्ष के लिए सहयोग प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें समान क्रमिक अवधि के लिए स्वतः नवीनीकरण खंड भी शामिल है	13.02.2024	संयुक्त अरब अमीरात	भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार

क्र. सं.	नाम	हस्ताक्षर करने की तारीख	देश/संगठन	मंत्रालय
70.	केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार और यूक्रेन की राज्य सेवा के बीच औषधि एवं औषधि नियंत्रण पर चिकित्सा उत्पाद विनियमन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता-ज्ञापन	23.08.2024	यूक्रेन	केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन
71.	दक्षिणी कैलिफोर्निया स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय और आईटीआरए के बीच समझौता-ज्ञापन	13.01.2024	यूएसए	आईटीआरए
72.	भारत (एएसआई) और अमेरिका के बीच सांस्कृतिक संपदा समझौता (सीपीए)	26.07.2024	यूएसए	भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार
73.	केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, भारत गणराज्य और वियतनाम समाजवादी गणराज्य के वियतनाम सीमा शुल्क विभाग के बीच सीमा शुल्क क्षमता निर्माण में सहयोग के लिए समझौता-ज्ञापन	31.07.2024	वियतनाम	केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
74.	वित्त मंत्रालय (एमओएफ) द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए समाजवादी गणराज्य वियतनाम की सरकार और भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम) के बीच 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि के दो डॉलर क्रेडिट लाइन समझौते	01.08.2024	वियतनाम	भारतीय निर्यात-आयात बैंक
75.	प्रसार भारती, नई दिल्ली, भारत और द वॉयस ऑफ वियतनाम, हनोई, वियतनाम के बीच रेडियो टेलीविजन पर सहयोग के लिए समझौता-ज्ञापन	01.08.2024	वियतनाम	प्रसार भारती

पासपोर्ट कार्यालय (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार)

क्र. सं.	पासपोर्ट कार्यालय	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
1	पासपोर्ट कार्यालय अहमदाबाद	गुजरात
2	पासपोर्ट कार्यालय अमृतसर	पंजाब
3	पासपोर्ट कार्यालय बरेली	उत्तर प्रदेश
4	पासपोर्ट कार्यालय बेंगलुरु	कर्नाटक
5	पासपोर्ट कार्यालय भोपाल	मध्य प्रदेश
6	पासपोर्ट कार्यालय भुवनेश्वर	ओडिशा
7	पासपोर्ट कार्यालय चंडीगढ़	चंडीगढ़
8	पासपोर्ट कार्यालय चेन्नई	तमिलनाडु
9	पासपोर्ट कार्यालय कोचीन	केरल
10	पासपोर्ट कार्यालय कोयंबटूर	तमिलनाडु
11	पासपोर्ट कार्यालय देहरादून	उत्तराखंड
12	पासपोर्ट कार्यालय दिल्ली	दिल्ली
13	पासपोर्ट कार्यालय गाजियाबाद	उत्तर प्रदेश
14	पासपोर्ट कार्यालय गोवा	गोवा
15	पासपोर्ट कार्यालय गुवाहाटी	असम
16	पासपोर्ट कार्यालय हैदराबाद	तेलंगाना
17	पासपोर्ट कार्यालय जयपुर	राजस्थान
18	पासपोर्ट कार्यालय जालंधर	पंजाब
19	पासपोर्ट कार्यालय जम्मू	जम्मू और कश्मीर
20.	पासपोर्ट कार्यालय कोलकाता	पश्चिम बंगाल
21	पासपोर्ट कार्यालय कोझिकोड	केरल
22	पासपोर्ट कार्यालय लखनऊ	उत्तर प्रदेश
23	पासपोर्ट कार्यालय मदुरै	तमिलनाडु
24	पासपोर्ट कार्यालय मुंबई	महाराष्ट्र
25	पासपोर्ट कार्यालय नागपुर	महाराष्ट्र
26	पासपोर्ट कार्यालय पटना	बिहार
27	पासपोर्ट कार्यालय पुणे	महाराष्ट्र
28	पासपोर्ट कार्यालय रायपुर	छत्तीसगढ़
29	पासपोर्ट कार्यालय रांची	झारखंड
30	पासपोर्ट कार्यालय शिमला	हिमाचल प्रदेश
31	पासपोर्ट कार्यालय श्रीनगर	जम्मू और कश्मीर
32	पासपोर्ट कार्यालय सूरत	गुजरात

क्र. सं.	पासपोर्ट कार्यालय	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
33	पासपोर्ट कार्यालय तिरुचिरापल्ली	तमिलनाडु
34	पासपोर्ट कार्यालय तिरुअनंतपुरम	केरल
35	पासपोर्ट कार्यालय विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश
36	पासपोर्ट कार्यालय विशाखापत्तनम	आंध्र प्रदेश
37	पासपोर्ट कार्यालय कोटा	राजस्थान

पासपोर्ट सेवा केन्द्रों की सूची (आर.पी.ओ.-वार)

क्र. सं.	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय का नाम	पीएसके की क्र. सं.	पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके) का नाम
1	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय अहमदाबाद	1	पासपोर्ट सेवा केंद्र मीठाकाली अहमदाबाद
		2	पासपोर्ट सेवा केंद्र राजकोट
		3	पासपोर्ट सेवा केंद्र वडोदरा
		4	पासपोर्ट सेवा केंद्र विजय क्रॉस रोड अहमदाबाद
2	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय अमृतसर	5	पासपोर्ट सेवा केंद्र अमृतसर
3	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय बरेली	6	पासपोर्ट सेवा केंद्र बरेली
4	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय बेंगलुरु	7	पासपोर्ट सेवा केंद्र बेंगलुरु, लालबाग
		8	पासपोर्ट सेवा केंद्र बेंगलुरु, साई आर्केड
		9	पासपोर्ट सेवा केंद्र हुबली, धारवाड़
		10	पासपोर्ट सेवा केंद्र मंगलुरु
		11	पासपोर्ट सेवा लघु केंद्र कलबुर्गी
5	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय भोपाल	12	पासपोर्ट सेवा केंद्र भोपाल
		13	पासपोर्ट सेवा लघु केंद्र इंदौर
6	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय भुवनेश्वर	14	पासपोर्ट सेवा केंद्र भुवनेश्वर
7	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय चंडीगढ़	15	पासपोर्ट सेवा केंद्र अंबाला
		16	पासपोर्ट सेवा केंद्र चंडीगढ़
		17	पासपोर्ट सेवा केंद्र लुधियाना
8	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय चेन्नई	18	पासपोर्ट सेवा केंद्र अमीनजिकराई
		19	पासपोर्ट सेवा केंद्र सालिगरामम
		20	पासपोर्ट सेवा केंद्र तम्बरम
		21	पासपोर्ट सेवा लघु केंद्र पुदुच्चेरी
9	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय कोचीन	22	पासपोर्ट सेवा केंद्र अलाप्पुझा
		23	पासपोर्ट सेवा केंद्र अलुवा
		24	पासपोर्ट सेवा केंद्र कोट्टायम
		25	पासपोर्ट सेवा केंद्र तिशूर
		26	पासपोर्ट सेवा केंद्र त्रिपुनिथुरा, कोचीन
10	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय कोयंबटूर	27	पासपोर्ट सेवा केंद्र कोयंबटूर
11	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय देहरादून	28	पासपोर्ट सेवा केंद्र देहरादून
12	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय दिल्ली	29	पासपोर्ट सेवा केंद्र आर.के.पुरम
		30	पासपोर्ट सेवा केंद्र गुडगांव
		31	पासपोर्ट सेवा केंद्र हेराल्ड हाउस-आईटीओ
		32	पासपोर्ट सेवा केंद्र शालीमार प्लेस
13	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय गाजियाबाद	33	पासपोर्ट सेवा केंद्र गाजियाबाद

क्र. सं.	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय का नाम	पीएसके की क्र. सं.	पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके) का नाम
14	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय गुवाहाटी	34	पासपोर्ट सेवा केंद्र गुवाहाटी
		35	पासपोर्ट सेवा लघु केंद्र आइजोल
		36	पासपोर्ट सेवा लघु केंद्र दीमापुर
		37	पासपोर्ट सेवा लघु केंद्र इंफाल
		38	पासपोर्ट सेवा लघु केंद्र ईटानगर
		39	पासपोर्ट सेवा लघु केंद्र शिलांग
15	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय हैदराबाद	40	पासपोर्ट सेवा केंद्र अमीरपेट
		41	पासपोर्ट सेवा केंद्र बेगमपेट
		42	पासपोर्ट सेवा केंद्र निजामाबाद
		43	पासपोर्ट सेवा केंद्र टोली चौकी
		44	पासपोर्ट सेवा लघु केंद्र करीमनगर
16	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय जयपुर	45	पासपोर्ट सेवा केंद्र जयपुर
		46	पासपोर्ट सेवा केंद्र जोधपुर
		47	पासपोर्ट सेवा केंद्र सीकर
17	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय जालंधर	48	पासपोर्ट सेवा केंद्र होशियारपुर
		49	पासपोर्ट सेवा केंद्र जालंधर-1
		50	पासपोर्ट सेवा केंद्र जालंधर-2
18	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय जम्मू	51	पासपोर्ट सेवा केंद्र जम्मू
19	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय कोलकाता	52	पासपोर्ट सेवा केंद्र बरहामपुर
		53	पासपोर्ट सेवा केंद्र कोलकाता
		54	पासपोर्ट सेवा लघु केंद्र अगरतला
		55	पासपोर्ट सेवा लघु केंद्र गंगटोक
		56	पासपोर्ट सेवा लघु केंद्र सिलीगुड़ी
20	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, कोटा	57	पासपोर्ट सेवा लघु केंद्र उदयपुर
21	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय कोझिकोड	58	पासपोर्ट सेवा केंद्र कन्नूर
		59	पासपोर्ट सेवा केंद्र कोझिकोड
		60	पासपोर्ट सेवा केंद्र मलप्पुरम II
		61	पासपोर्ट सेवा केंद्र, पय्यानूर, कन्नूर
		62	पासपोर्ट सेवा केंद्र वडकारा, कोझिकोड
22	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय लखनऊ	63	पासपोर्ट सेवा केंद्र गोरखपुर
		64	पासपोर्ट सेवा केंद्र कानपुर
		65	पासपोर्ट सेवा केंद्र लखनऊ
		66	पासपोर्ट सेवा केंद्र वाराणसी
23	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय मदुरै	67	पासपोर्ट सेवा केंद्र मदुरै
		68	पासपोर्ट सेवा केंद्र तिरुनेलवेली शहर
		69	पासपोर्ट सेवा केंद्र अंधेरी

क्र. सं.	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय का नाम	पीएसके की क्र. सं.	पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके) का नाम
24	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय मुंबई	70	पासपोर्ट सेवा केंद्र लोअर परेल
		71	पासपोर्ट सेवा केंद्र मलाड
		72	पासपोर्ट सेवा केंद्र नासिक
		73	पासपोर्ट सेवा केंद्र ठाणे
25	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय नागपुर	74	पासपोर्ट सेवा केंद्र नागपुर
26	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय पणजी	75	पासपोर्ट सेवा केंद्र पणजी
27	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय पटना	76	दरभंगा
		77	पासपोर्ट सेवा केंद्र पटना
28	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय पुणे	78	पासपोर्ट सेवा केंद्र पुणे
		79	पासपोर्ट सेवा लघु केंद्र सोलापुर
29	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय रायपुर	80	पासपोर्ट सेवा केंद्र रायपुर
30	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय रांची	81	पासपोर्ट सेवा केंद्र रांची
31	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय शिमला	82	पासपोर्ट सेवा केंद्र शिमला
32	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय श्रीनगर	83	पासपोर्ट सेवा केंद्र श्रीनगर
33	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय सूरत	84	पासपोर्ट सेवा केंद्र सूरत
34	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय तिरुचिरापल्ली	85	पासपोर्ट सेवा केंद्र तंजावुर
		86	पासपोर्ट सेवा केंद्र तिरुचिरापल्ली
35	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय तिरुअनंतपुरम	87	पासपोर्ट सेवा केंद्र कोल्लम नयटीनकारा
		88	पासपोर्ट सेवा केंद्र नेय्याट्टिनकरा, तिरुअनंतपुरम
		89	पासपोर्ट सेवा केंद्र वज़्रहुथाकॉड, तिरुअनंतपुरम
36	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय विजयवाड़ा	90	पासपोर्ट सेवा केंद्र तिरुपति
		91	पासपोर्ट सेवा केंद्र विजयवाड़ा
37	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय विशाखापत्तनम	92	पासपोर्ट सेवा केंद्र विशाखापत्तनम
		93	पासपोर्ट सेवा लघु केंद्र भीमावरम

अनुलग्नक VII

कार्यशील डाकघर पासपोर्ट सेवा केन्द्रों (पीओपीएसके) की सूची

क्र. सं.	पीओपीएसके की अवस्थिति	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पासपोर्ट कार्यालय
1	पोर्ट ब्लेयर	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	कोलकाता
2	कडप्पा	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा
3	कुरनूल	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा
4	नेल्लोर	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा
5	अनंतपुर	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा
6	चित्तूर	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा
7	मछलीपट्टनम (गुडीवाड़ा)	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा
8	गुंटूर	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा
9	ओंगोल	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा
10	बापतला	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा
11	नरसरावपेट	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा
12	नांदयाल	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा
13	राजमपेट (कोडुरु)	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा
14	हिन्दुपुर	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा
15	राजमुंदरी	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम
16	काकीनाडा	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम
17	श्रीकाकुलम	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम
18	अमलापुरम	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम
19	विजयनगरम	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम
20	एलुरु	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम
21	अनाकापल्ले (येलमंचिली)	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम
22	अरुणाचल पूर्व (खोंसा)	अरुणाचल प्रदेश	गुवाहाटी
23	अरुणाचल पूर्व (चांगलांग)	अरुणाचल प्रदेश	गुवाहाटी
24	सिलचर	असम	गुवाहाटी
25	मंगलदोई	असम	गुवाहाटी
26	डिब्रूगढ़	असम	गुवाहाटी
27	तेजपुर	असम	गुवाहाटी
28	कोकराझार	असम	गुवाहाटी
29	डिब्रूगढ़ (तिनसुकिया)	असम	गुवाहाटी
30	कार्बी आंगलोंग	असम	गुवाहाटी
31	धुबरी	असम	गुवाहाटी
32	डुबरी (गोलपाड़ा)	असम	गुवाहाटी

क्र. सं.	पीओपीएसके की अवस्थिति	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पासपोर्ट कार्यालय
33	लखीमपुर (उत्तरी लखीमपुर)	असम	गुवाहाटी
34	नवगोंग	असम	गुवाहाटी
35	बारपेटा	असम	गुवाहाटी
36	जोरहाट	असम	गुवाहाटी
37	कलियाबोर (गोलाघाट)	असम	गुवाहाटी
38	करीमगंज	असम	गुवाहाटी
39	मुजफ्फरपुर	बिहार	पटना
40	पूर्णिया	बिहार	पटना
41	भागलपुर	बिहार	पटना
42	सिवान	बिहार	पटना
43	पश्चिम चंपारण (बेतिया)	बिहार	पटना
44	गया	बिहार	पटना
45	पूर्वी चंपारण (मोतिहारी)	बिहार	पटना
46	बक्सर	बिहार	पटना
47	मधुबनी	बिहार	पटना
48	सारण (छपरा)	बिहार	पटना
49	समस्तीपुर	बिहार	पटना
50	मुंगेर	बिहार	पटना
51	नवादा	बिहार	पटना
52	बेगूसराय	बिहार	पटना
53	नालन्दा	बिहार	पटना
54	हाजीपुर	बिहार	पटना
55	आरा	बिहार	पटना
56	जमुई	बिहार	पटना
57	मधेपुरा(सहरसा)	बिहार	पटना
58	सासाराम	बिहार	पटना
59	सीतामढ़ी	बिहार	पटना
60	अररिया(फारबिसगंज)	बिहार	पटना
61	बांका	बिहार	पटना
62	जहानाबाद	बिहार	पटना
63	पाटलिपुत्र (मनेर)	बिहार	पटना
64	शिवहर	बिहार	पटना
65	उजियारपुर(दलसिंहसराय)	बिहार	पटना
66	खगरिया	बिहार	पटना
67	कटिहार	बिहार	पटना

क्र. सं.	पीओपीएसके की अवस्थिति	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पासपोर्ट कार्यालय
68	काराकाट(डालमियानगर)	बिहार	पटना
69	किशनगंज	बिहार	पटना
70	गोपालगंज	बिहार	पटना
71	औरंगाबाद	बिहार	पटना
72	एकमा	बिहार	पटना
73	सुपौल	बिहार	पटना
74	सरगुजा	छत्तीसगढ़	रायपुर
75	राजनंदगांव	छत्तीसगढ़	रायपुर
76	दुर्ग	छत्तीसगढ़	रायपुर
77	बिलासपुर	छत्तीसगढ़	रायपुर
78	जांजगीर-चंपा	छत्तीसगढ़	रायपुर
79	रायगढ़	छत्तीसगढ़	रायपुर
80	कोरबा	छत्तीसगढ़	रायपुर
81	कांकेर	छत्तीसगढ़	रायपुर
82	बस्तर	छत्तीसगढ़	रायपुर
83	दादर और नागर हवेली (सिल्वासा)	दादर और नागर हवेली	मुंबई
84	दमन और दीव (दमन)	दमन	मुंबई
85	यमुना विहार	दिल्ली	दिल्ली
86	जनकपुरी	दिल्ली	दिल्ली
87	पूर्वी दिल्ली (पटपड़गंज)	दिल्ली	दिल्ली
88	दक्षिणी दिल्ली (नेहरू प्लेस)	दिल्ली	दिल्ली
89	साकेत (महरौली)	दिल्ली	दिल्ली
90	दक्षिण गोवा (मडगांव)	गोवा	पणजी
91	दाहोद	गुजरात	अहमदाबाद
92	बनासकांठा (पालनपुर)	गुजरात	अहमदाबाद
93	कच्छ (भुज)	गुजरात	अहमदाबाद
94	जामनगर	गुजरात	अहमदाबाद
95	भावनगर	गुजरात	अहमदाबाद
96	आनंद	गुजरात	अहमदाबाद
97	खेड़ा	गुजरात	अहमदाबाद
98	भरूच	गुजरात	अहमदाबाद
99	नागढ़	गुजरात	अहमदाबाद
100	जूनागढ़ (वेरावल)	गुजरात	अहमदाबाद
101	मेहसाणा	गुजरात	अहमदाबाद
102	पोरबंदर	गुजरात	अहमदाबाद

क्र. सं.	पीओपीएसके की अवस्थिति	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पासपोर्ट कार्यालय
103	अमरेली	गुजरात	अहमदाबाद
104	सुरेंद्रनगर	गुजरात	अहमदाबाद
105	साबरकांठा	गुजरात	अहमदाबाद
106	पाटन	गुजरात	अहमदाबाद
107	गांधीनगर	गुजरात	अहमदाबाद
108	छोटा उदयपुर	गुजरात	अहमदाबाद
109	पंचमहल (गोधरा)	गुजरात	अहमदाबाद
110	नवसारी	गुजरात	सूरत
111	वलसाड	गुजरात	सूरत
112	बारडोली	गुजरात	सूरत
113	राजपिपला	गुजरात	सूरत
114	करनाल	हरियाणा	चंडीगढ़
115	हिसार	हरियाणा	चंडीगढ़
116	करनाल (पानीपत)	हरियाणा	चंडीगढ़
117	अम्बाला (यमुनानगर)	हरियाणा	चंडीगढ़
118	कैथल	हरियाणा	चंडीगढ़
119	भिवानी महेंद्रगढ़	हरियाणा	चंडीगढ़
120	सिरसा	हरियाणा	चंडीगढ़
121	फरीदाबाद	हरियाणा	दिल्ली
122	भिवानी महेंद्रगढ़ (नारनौल)	हरियाणा	दिल्ली
123	रोहतक	हरियाणा	दिल्ली
124	सोनीपत	हरियाणा	दिल्ली
125	कांगड़ा (पालमपुर)	हिमाचल प्रदेश	शिमला
126	हमीरपुर	हिमाचल प्रदेश	शिमला
127	मंडी	हिमाचल प्रदेश	शिमला
128	मंडी (कुल्लू)	हिमाचल प्रदेश	शिमला
129	कांगड़ा	हिमाचल प्रदेश	शिमला
130	हमीरपुर (ऊना)	हिमाचल प्रदेश	शिमला
131	उधमपुर	जम्मू और कश्मीर	जम्मू
132	उधमपुर (कठुआ)	जम्मू और कश्मीर	जम्मू
133	जम्मू (राजौरी)	जम्मू और कश्मीर	जम्मू
134	लद्दाख (लेह)	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर
135	अनंतनाग	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर
136	बारामूला	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर
137	जमशेदपुर	झारखंड	रांची

क्र. सं.	पीओपीएसके की अवस्थिति	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पासपोर्ट कार्यालय
138	गोड्डा (देवघर)	झारखंड	रांची
139	धनबाद (बोकारो)	झारखंड	रांची
140	धनबाद	झारखंड	रांची
141	दुमका	झारखंड	रांची
142	हजारीबाग	झारखंड	रांची
143	पलामू (मेदिनीनगर)	झारखंड	रांची
144	गिरिडीह	झारखंड	रांची
145	लोहरदगा (गुमला)	झारखंड	रांची
146	कोडरमा(जुमरीतिलैया)	झारखंड	रांची
147	चतरा(शिमरिया)	झारखंड	रांची
148	खूंटी	झारखंड	रांची
149	राजमहल(साहिबगंज)	झारखंड	रांची
150	सिंहभूम(चाईबाशा)	झारखंड	रांची
151	गोड्डा	झारखंड	रांची
152	मैसूर	कर्नाटक	बेंगलुरु
153	बेलगावी	कर्नाटक	बेंगलुरु
154	दावणगेरे	कर्नाटक	बेंगलुरु
155	शिवमोगा	कर्नाटक	बेंगलुरु
156	बेल्लारी	कर्नाटक	बेंगलुरु
157	तुमकुरु	कर्नाटक	बेंगलुरु
158	हसन	कर्नाटक	बेंगलुरु
159	हावेरी (गडग)	कर्नाटक	बेंगलुरु
160	विजयपुर	कर्नाटक	बेंगलुरु
161	चिकमगलूर (उडुपी)	कर्नाटक	बेंगलुरु
162	बीदर	कर्नाटक	बेंगलुरु
163	रायचूर	कर्नाटक	बेंगलुरु
164	कोप्पल	कर्नाटक	बेंगलुरु
165	कोलार(रॉबर्टसनपेट)	कर्नाटक	बेंगलुरु
166	उत्तर कन्नड़ (अंकोला)	कर्नाटक	बेंगलुरु
167	चिन्नदुर्ग	कर्नाटक	बेंगलुरु
168	चामराजनगर	कर्नाटक	बेंगलुरु
169	चिक्कोडी	कर्नाटक	बेंगलुरु
170	चिकबलपुर	कर्नाटक	बेंगलुरु
171	बैंगलोर ग्रामीण (चन्नापटना)	कर्नाटक	बेंगलुरु
172	बैंगलोर उत्तर (जलाहल्ली)	कर्नाटक	बेंगलुरु

क्र. सं.	पीओपीएसके की अवस्थिति	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पासपोर्ट कार्यालय
173	मांड्या (महूर)	कर्नाटक	बेंगलुरु
174	बागलकोट	कर्नाटक	बेंगलुरु
175	मवलिककारा (चेंगन्नूर)	केरल	कोचीन
176	इडुक्की (कट्टप्पाना)	केरल	कोचीन
177	पलक्कड़	केरल	कोचीन
178	नेनमारा	केरल	कोचीन
179	कासरगोड	केरल	कोझिकोड
180	पथानामथिट्टा	केरल	तिरुअनंतपुरम
181	अट्टिगल	केरल	तिरुअनंतपुरम
182	लक्षद्वीप (कवारत्ती)	लक्षद्वीप	कोचीन
183	विदिशा	मध्य प्रदेश	भोपाल
184	सतना	मध्य प्रदेश	भोपाल
185	जबलपुर	मध्य प्रदेश	भोपाल
186	ग्वालियर	मध्य प्रदेश	भोपाल
187	देवास	मध्य प्रदेश	भोपाल
188	बालाघाट	मध्य प्रदेश	भोपाल
189	छिंदवाड़ा	मध्य प्रदेश	भोपाल
190	दमोह	मध्य प्रदेश	भोपाल
191	रतलाम	मध्य प्रदेश	भोपाल
192	होशंगाबाद	मध्य प्रदेश	भोपाल
193	सागर	मध्य प्रदेश	भोपाल
194	बेतुल	मध्य प्रदेश	भोपाल
195	धार	मध्य प्रदेश	भोपाल
196	खजुराहो (छतरपुर)	मध्य प्रदेश	भोपाल
197	टीकमगढ़	मध्य प्रदेश	भोपाल
198	रीवा	मध्य प्रदेश	भोपाल
199	उज्जैन	मध्य प्रदेश	भोपाल
200	सिवनी	मध्य प्रदेश	भोपाल
201	गुना	मध्य प्रदेश	भोपाल
202	मन्दसौर	मध्य प्रदेश	भोपाल
203	शाहडोल	मध्य प्रदेश	भोपाल
204	खंडवा	मध्य प्रदेश	भोपाल
205	अलीबाग	महाराष्ट्र	मुंबई
206	औरंगाबाद	महाराष्ट्र	मुंबई
207	मुंबई उत्तर-पूर्वी (विक्रोली)	महाराष्ट्र	मुंबई

क्र. सं.	पीओपीएसके की अवस्थिति	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पासपोर्ट कार्यालय
208	जलगांव	महाराष्ट्र	मुंबई
209	रत्नागिरी सिंधुगुढ़ (राजापुर)	महाराष्ट्र	मुंबई
210	रावेर(भुसावल)	महाराष्ट्र	मुंबई
211	धुले	महाराष्ट्र	मुंबई
212	मुंबई साउथ-सेंट्रल (सायन)	महाराष्ट्र	मुंबई
213	सांताक्रूज	महाराष्ट्र	मुंबई
214	भिवंडी	महाराष्ट्र	मुंबई
215	डोंबिवली	महाराष्ट्र	मुंबई
216	वसई	महाराष्ट्र	मुंबई
217	नंदुरबार	महाराष्ट्र	मुंबई
218	वर्धा	महाराष्ट्र	नागपुर
219	चंद्रपुर	महाराष्ट्र	नागपुर
220	अमरावती	महाराष्ट्र	नागपुर
221	अकोला	महाराष्ट्र	नागपुर
222	बुलढाना	महाराष्ट्र	नागपुर
223	यवतमाल-वाशिम (यवतमाल)	महाराष्ट्र	नागपुर
224	हिंगोली	महाराष्ट्र	नागपुर
225	गढ़चिरौलीचिमुर् (गढ़चिरौली)	महाराष्ट्र	नागपुर
226	भंडारा गोंदिया (भंडारा)	महाराष्ट्र	नागपुर
227	रामटेक(काटोआल)	महाराष्ट्र	नागपुर
228	कोल्हापुर	महाराष्ट्र	पुणे
229	मावल (पिंपरी चिंचवड)	महाराष्ट्र	पुणे
230	सांगली	महाराष्ट्र	पुणे
231	जलना	महाराष्ट्र	पुणे
232	बीड	महाराष्ट्र	पुणे
233	अहमदनगर	महाराष्ट्र	पुणे
234	नांदेड	महाराष्ट्र	पुणे
235	सतारा	महाराष्ट्र	पुणे
236	सोलापुर (पंढरपुर)	महाराष्ट्र	पुणे
237	बारामती	महाराष्ट्र	पुणे
238	लातूर	महाराष्ट्र	पुणे
239	परभनी	महाराष्ट्र	पुणे
240	शिरडी(श्रीरामपुर)	महाराष्ट्र	पुणे
241	शिरूर	महाराष्ट्र	पुणे
242	उस्मानाबाद	महाराष्ट्र	पुणे

क्र. सं.	पीओपीएसके की अवस्थिति	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पासपोर्ट कार्यालय
243	माढा	महाराष्ट्र	पुणे
244	हातकणंगले (इचलकरंजी)	महाराष्ट्र	पुणे
245	नवी मुंबई (वाशी)	महाराष्ट्र	मुंबई
246	बाहरी मणिपुर (काकचिंग)	मणिपुर	गुवाहाटी
247	तुरा	मेघालय	गुवाहाटी
248	सुंदरगढ़ (राउरकेला)	ओडिशा	भुवनेश्वर
249	संबलपुर	ओडिशा	भुवनेश्वर
250	कोरापुट	ओडिशा	भुवनेश्वर
251	बालासोर	ओडिशा	भुवनेश्वर
252	बेरहामपुर	ओडिशा	भुवनेश्वर
253	मयूरभंज (बारीपदा)	ओडिशा	भुवनेश्वर
254	कालाहांडी (भवानीपटना)	ओडिशा	भुवनेश्वर
255	अस्का	ओडिशा	भुवनेश्वर
256	भद्रक	ओडिशा	भुवनेश्वर
257	कटक	ओडिशा	भुवनेश्वर
258	ढेंकनाल	ओडिशा	भुवनेश्वर
259	जाजपुर	ओडिशा	भुवनेश्वर
260	क्योंझर	ओडिशा	भुवनेश्वर
261	कंधमाल (फुलबनी)	ओडिशा	भुवनेश्वर
262	केंद्रपाड़ा	ओडिशा	भुवनेश्वर
263	बारगढ़	ओडिशा	भुवनेश्वर
264	बोलंगीर	ओडिशा	भुवनेश्वर
265	जगतसिंहपुर	ओडिशा	भुवनेश्वर
266	पुरी	ओडिशा	भुवनेश्वर
267	नबरंगपुर	ओडिशा	भुवनेश्वर
268	पुदुच्चेरी (कराइकल)	पुदुच्चेरी	तिरुचिरापल्ली
269	फिरोजपुर	पंजाब	अमृतसर
270	बठिंडा	पंजाब	चंडीगढ़
271	पटियाला	पंजाब	चंडीगढ़
272	एसबीएस नगर (रोपड़)	पंजाब	चंडीगढ़
273	फतेहगढ़ साहिब (बासी पत्तन)	पंजाब	चंडीगढ़
274	संगरूर(मलेरकोटला)	पंजाब	चंडीगढ़
275	फरीदकोट (मोगा)	पंजाब	जालंधर
276	होशियारपुर (फगवाड़ा)	पंजाब	जालंधर
277	गुरदासपुर (पठानकोट)	पंजाब	जालंधर

क्र. सं.	पीओपीएसके की अवस्थिति	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पासपोर्ट कार्यालय
278	कोटा	राजस्थान	जयपुर
279	बीकानेर	राजस्थान	जयपुर
280	झुंझुनूं	राजस्थान	जयपुर
281	बाड़मेर (जैसलमेर)	राजस्थान	जयपुर
282	झालावाड़ बारां (झालावाड़)	राजस्थान	जयपुर
283	नागौर	राजस्थान	जयपुर
284	पाली	राजस्थान	जयपुर
285	चूरू	राजस्थान	जयपुर
286	गंगानगर (हनुमानगढ़)	राजस्थान	जयपुर
287	श्रीगंगानगर	राजस्थान	जयपुर
288	अलवर	राजस्थान	जयपुर
289	चित्तौड़गढ़	राजस्थान	जयपुर
290	बाड़मेर	राजस्थान	जयपुर
291	अजमेर	राजस्थान	जयपुर
292	करौली (धौलपुर)	राजस्थान	जयपुर
293	बांसवाड़ा	राजस्थान	जयपुर
294	भरतपुर	राजस्थान	जयपुर
295	जयपुर ग्रामीण (कोटपूतली)	राजस्थान	जयपुर
296	दौसा	राजस्थान	जयपुर
297	टोंक-सवाई माधोपुर (सवाई माधोपुर)	राजस्थान	जयपुर
298	भीलवाड़ा	राजस्थान	जयपुर
299	राजसमंद (कांकरोली)	राजस्थान	जयपुर
300	जालोर(सिरोही)	राजस्थान	जयपुर
301	प्रतापगढ़	राजस्थान	जयपुर
302	वेल्लोर	तमिलनाडु	चेन्नई
303	कुड्डलोर	तमिलनाडु	चेन्नई
304	विलुप्पुरम	तमिलनाडु	चेन्नई
305	तिरुवन्नामलाई	तमिलनाडु	चेन्नई
306	अरणि	तमिलनाडु	चेन्नई
307	अरक्कोणम (रानीपेट)	तमिलनाडु	चेन्नई
308	चेन्नई नॉर्थ (चेन्नई जीपीओ)	तमिलनाडु	चेन्नई
309	धर्मपुरी	तमिलनाडु	चेन्नई
310	कल्लाकुरिची	तमिलनाडु	चेन्नई
311	कांचीपुरम	तमिलनाडु	चेन्नई
312	तिरुवल्लुर	तमिलनाडु	चेन्नई

क्र. सं.	पीओपीएसके की अवस्थिति	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पासपोर्ट कार्यालय
313	चिदंबरम	तमिलनाडु	चेन्नई
314	कृष्णागिरी	तमिलनाडु	चेन्नई
315	सलेम	तमिलनाडु	कोयंबटूर
316	नीलगिरी (कुन्नूर)	तमिलनाडु	कोयंबटूर
317	इरोड	तमिलनाडु	कोयंबटूर
318	नमक्कल (रासीपुरम)	तमिलनाडु	कोयंबटूर
319	विरुधुनगर	तमिलनाडु	मदुरै
320	कन्याकुमारी (नागरकोइल)	तमिलनाडु	मदुरै
321	शिवगंगा (देवकोट्टई)	तमिलनाडु	मदुरै
322	डिंडीगुल (कोडाईरोड)	तमिलनाडु	मदुरै
323	तेनकासी (राजपालयम)	तमिलनाडु	मदुरै
324	थेनी(बोडिनेयाकनूर)	तमिलनाडु	मदुरै
325	थुथुकुडी	तमिलनाडु	मदुरै
326	रामनाथपुरम	तमिलनाडु	मदुरै
327	पेरम्बलुर	तमिलनाडु	तिरुचिरापल्ली
328	मयिलादुथुराई (सिरकली)	तमिलनाडु	तिरुचिरापल्ली
329	नागपट्टिनम (थिरुथुराईपूडी)	तमिलनाडु	तिरुचिरापल्ली
330	करूर	तमिलनाडु	तिरुचिरापल्ली
331	मेहबूबनगर	तेलंगाना	हैदराबाद
332	वारंगल	तेलंगाना	हैदराबाद
333	खम्मम	तेलंगाना	हैदराबाद
334	मेडक (सिद्दीपेट)	तेलंगाना	हैदराबाद
335	आदिलाबाद	तेलंगाना	हैदराबाद
336	नालगोंडा	तेलंगाना	हैदराबाद
337	मेडक	तेलंगाना	हैदराबाद
338	भोंगीर	तेलंगाना	हैदराबाद
339	महबुबाबाद	तेलंगाना	हैदराबाद
340	जहीराबाद(कामारेड्डी)	तेलंगाना	हैदराबाद
341	पेद्दापल्ले(मंचेरियल)	तेलंगाना	हैदराबाद
342	नगरकुर्नूल (वानापर्थी)	तेलंगाना	हैदराबाद
343	मल्काजगिरि (मेडचल)	तेलंगाना	हैदराबाद
344	चेवेल्ला (विकाराबाद)	तेलंगाना	हैदराबाद
345	धरमनगर	बिपुरा	कोलकाता
346	पीलीभीत	उत्तर प्रदेश	बरेली
347	मुरादाबाद	उत्तर प्रदेश	बरेली

क्र. सं.	पीओपीएसके की अवस्थिति	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पासपोर्ट कार्यालय
348	बिजनौर	उत्तर प्रदेश	बरेली
349	रामपुर	उत्तर प्रदेश	बरेली
350	बदायूं	उत्तर प्रदेश	बरेली
351	अमरोहा	उत्तर प्रदेश	बरेली
352	शाहजहांपुर	उत्तर प्रदेश	बरेली
353	नगीना	उत्तर प्रदेश	बरेली
354	मेरठ	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद
355	आगरा	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद
356	मथुरा (वृंदावन)	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद
357	बुलन्दशहर	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद
358	अलीगढ़	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद
359	सहारनपुर	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद
360	फतेहपुर सीकरी (अछनेरा)	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद
361	हाथरस	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद
362	मुजफ्फरनगर	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद
363	गौतम बुद्ध नगर (नोएडा)	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद
364	बागपत	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद
365	झांसी	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
366	गाजीपुर	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
367	फैजाबाद (अयोध्या)	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
368	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
369	देवरिया	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
370	उन्नाव	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
371	बलिया	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
372	सुल्तानपुर	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
373	प्रतापगढ़	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
374	आजमगढ़	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
375	बहराईच	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
376	सीतापुर	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
377	गोंडा	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
378	श्रावस्ती (बलरामपुर)	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
379	गोशी (मऊ)	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
380	अमेठी	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
381	रायबरेली	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
382	जौनपुर	उत्तर प्रदेश	लखनऊ

क्र. सं.	पीओपीएसके की अवस्थिति	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पासपोर्ट कार्यालय
383	मिर्जापुर (चुनार)	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
384	फ़तेहपुर	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
385	बाँदा	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
386	हमीरपुर	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
387	भदोही	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
388	डुमरियागंज (सिद्धार्थनगर)	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
389	मिसरिख	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
390	अंबेडकरनगर	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
391	महाराजगंज	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
392	खेरी	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
393	हरदोई	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
394	फरुखाबाद	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
395	इटवा	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
396	जालौन	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
397	अल्मोडा	उत्तराखंड	देहरादून
398	नैनताल (रुद्रपुर)	उत्तराखंड	देहरादून
399	नैनीताल (काठगोदाम)	उत्तराखंड	देहरादून
400	नैनीताल	उत्तराखंड	देहरादून
401	हरिद्वार (रुड़की)	उत्तराखंड	देहरादून
402	गढ़वाल (श्रीनगर)	उत्तराखंड	देहरादून
403	आसनसोल	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
404	रायगंज (उत्तर दिनाजपुर)	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
405	कोलकाता उत्तर (बीडॉन स्ट्रीट)	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
406	नादिया (कृष्णानगर)	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
407	मालदा दक्षिण (मकदुमपुर)	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
408	बर्धमान	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
409	बैरकपुर	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
410	हुगली (चिनसुराह)	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
411	बेलूरघाट	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
412	मेदिनीपुर (खड़गपुर)	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
413	डायमंड हार्बर	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
414	बीरभूम (रामपुरहाट)	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
415	जलपाईगुड़ी	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
416	कूचबिहार	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
417	अलीपुरद्वार	पश्चिम बंगाल	कोलकाता

क्र. सं.	पीओपीएसके की अवस्थिति	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पासपोर्ट कार्यालय
418	आरामबाग	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
419	श्रीरामपुर	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
420	जादवपुर	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
421	दम दम	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
422	बनगांव	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
423	तामलुक	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
424	कांथी	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
425	हावड़ा	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
426	बारासात (अशोकनगर)	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
427	रानाघाट	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
428	दार्जिलिंग	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
429	बांकुड़ा	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
430	बर्धमानपुरबा (कटवा)	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
431	बशीरहाट	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
432	बोलपुर	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
433	उलुबेरिया(अमता)	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
434	बिशुपुर	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
435	जंगीपुर (रघुनाथगंज)	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
436	पुरुलिया	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
437	झारग्राम	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
438	घाटल	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
439	मालदाहा उत्तर(सामसी)	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
440	मथुरापुर (काकद्वीप)	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
441	जयनगर (कैनिंग फेरी घाट)	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
442	मुर्शिदाबाद (जियागंज)	पश्चिम बंगाल	कोलकाता

2024 में राष्ट्राध्यक्षों/शासनाध्यक्षों/उपराष्ट्रपतियों/विदेश मंत्रियों और समकक्षों की भारत यात्रा का विवरण

क्र. सं.	यात्रा	तारीख
1.	डॉ. जोस रामोस-होर्ता, तिमोर-लेस्ते लोकतांत्रिक गणराज्य के राष्ट्रपति श्री फिलिप जैसिंटो न्यूसी, मोज़ाम्बिक गणराज्य के राष्ट्रपति श्री पेट्र फ़िआला, चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति	08-10 जनवरी 2024 09-12 जनवरी 2024 09-11 जनवरी 2024
2.	जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, भूटान के राजा की पारगमन यात्रा	11-12 जनवरी, 2024
3.	डेनिस फ्रांसिस, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष की यात्रा	22-26 जनवरी, 2024
4.	इमैनुएल मैक्रोन, फ्रांसीसी गणराज्य के राष्ट्रपति की राजकीय यात्रा	25-26 जनवरी, 2024
5.	फिजी गणराज्य के उप-प्रधानमंत्री और वित्त, सामरिक, योजना, राष्ट्रीय विकास और सांख्यिकी मंत्री बिमान प्रसाद की यात्रा	4-11 फरवरी, 2024
6.	स्विस परिसंघ के संघीय विदेश मामलों के विभाग के प्रमुख संघीय पार्षद डॉ. इग्राज़ियो कैसिस का दौरा	5 फरवरी, 2024
7.	बांग्लादेश जनवादी गणराज्य के विदेश मंत्री डॉ. हसन महमूद एमपी का दौरा	6-9 फरवरी, 2024
8.	गुयाना सहकारी गणराज्य के प्रधानमंत्री ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) मार्क फिलिप्स का दौरा	6-11 फरवरी, 2024
9.	आसियान महासचिव डॉ. काओ किम होर्न की यात्रा	11-15 फरवरी, 2024
10.	हेलेनिक गणराज्य (ग्रीस) के प्रधानमंत्री श्री किरियाकोस मित्सोताकिस और उनकी पत्नी की राजकीय यात्रा	20-23 फरवरी, 2024
11.	रायसीना वार्ता 2024 1. श्री इगली हसानी, अल्बानिया गणराज्य के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री 2. श्री डी. एन. धुंगेल, भूटान की शाही सरकार के विदेश मामलों और बाहरी व्यापार मंत्री 3. श्री एल्मेडिन कोनाकोविक, बोस्निया और हर्जगोविना के विदेश मामलों के मंत्री 4. श्री जान लिपावस्की, चेक गणराज्य के विदेश मंत्री 5. श्री लार्स लोके रासमुसेन, डेनमार्क गणराज्य के विदेश मंत्री 6. श्री मार्गस त्सखना, एस्टोनिया गणराज्य के विदेश मंत्री 7. एलिना वाल्टोनन, फिनलैंड की विदेश मंत्री 8. शिल्ले अयोर्कोर बोचवे, घाना की विदेश और क्षेत्रीय एकीकरण मंत्री 9. जियोर्गोस गेरापेट्रिटिस, ग्रीस के विदेश मंत्री 10. श्री क्रिसजानिस कर्रिस, लातविया के विदेश मंत्री 11. डोमिनिक हस्लर, लिक्टेन्स्टीन के विदेश मामलों, शिक्षा और खेल मंत्री 12. श्री गेब्रियलियस लैंड्सबर्गिस, लिथुआनिया के विदेश मामलों के मंत्री 13. श्री मनीष गोबिन, मॉरीशस के विदेश मामलों, क्षेत्रीय एकीकरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री 14. श्री एन.पी. सऊद, नेपाल के विदेश मामलों के मंत्री 15. सुश्री हैके ब्रुइन्स स्लॉट, नीदरलैंड की विदेश मामलों की मंत्री 11. डोमिनिक हस्लर, लिक्टेन्स्टीन के विदेश मामलों, शिक्षा और खेल मंत्री 16. श्री गेब्रियलियस लैंड्सबर्गिस, लिथुआनिया के विदेश मामलों के मंत्री 17. श्री मनीष गोबिन, मॉरीशस के विदेश मामलों, क्षेत्रीय एकीकरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री 18. श्री एन.पी. सऊद, नेपाल के विदेश मामलों के मंत्री 19. सुश्री हैके ब्रुइन्स स्लॉट, नीदरलैंड की विदेश मामलों की मंत्री 20. सुश्री जनैना तेवाने मेनकोमो, पनामा की विदेश मंत्री 21. लुमिनिता ओडोबेस्कु, रोमानिया की विदेश मंत्री 22. जुराज ब्लानार, स्लोवाक गणराज्य के विदेश और यूरोपीय मामलों के मंत्री 23. टोबियास बिलस्ट्रोम, स्वीडन के विदेश मंत्री 24. जनवरी यूसुफ मकाम्बा, तंजानिया के विदेश और पूर्वी अफ्रीकी सहयोग मंत्री	21-23 फरवरी, 2024

क्र. सं.	यात्रा	तारीख
12.	हंगरी के विदेश मामलों और व्यापार मंत्री श्री पीटर सिज्जार्तो की यात्रा	21 फरवरी, 2024
13.	संयुक्त राष्ट्र के स्थायी प्रतिनिधियों (पीआर) के प्रतिनिधिमंडल की यात्रा	25 फरवरी-01 मार्च, 2024
14.	थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री और पूर्व विदेश मंत्री डॉ. पार्नप्री बहिद्दा-नुकारा की यात्रा	25-28 फरवरी, 2024
15.	आइसलैंड के विदेश मामलों के मंत्री श्री बजरनी बेनेडिक्टसन की यात्रा	10-12 मार्च, 2024
16.	न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री श्री विंस्टन पीटर्स की यात्रा	10-13 मार्च, 2024
17.	बेलारूस गणराज्य के विदेश मंत्री श्री सर्गेई एलीनिक की यात्रा	11-13 मार्च, 2024
18.	भूटान के प्रधानमंत्री श्री शेरींग तोबगे की आधिकारिक यात्रा	14-18 मार्च, 2024
19.	सिंगापुर के राष्ट्रपति श्री थर्मन शानमुगरत्नम की निजी यात्रा	24-30 मार्च, 2024
20.	यूक्रेन के विदेश मंत्री श्री दिमित्रो कुलेबा की यात्रा	28-30 मार्च, 2024
21.	मालदीव गणराज्य के पूर्व विदेश मंत्री श्री मूसा ज़मीर की यात्रा	मई 08-10, 2024
22.	राजदूत श्री मोहम्मद गुलाम सरवर, सार्क के महासचिव	मई 11-15, 2024
23.	त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के प्रधानमंत्री डॉ. कीथ रोली की कार्यकारी यात्रा	मई 15-18, 2024
24.	शपथ ग्रहण समारोह श्री रानिल विक्रमसिंघे, श्रीलंका के लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद मुइज़ू, मालदीव गणराज्य के राष्ट्रपति श्री अहमद अफ़िफ़, सेशेल्स गणराज्य के उपराष्ट्रपति सुश्री शेख हसीना, बांग्लादेश के जनवादी गणराज्य की प्रधानमंत्री श्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ, मॉरीशस गणराज्य के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, नेपाल के प्रधानमंत्री दाशो शेरींग तोबगे, भूटान के प्रधानमंत्री	09 जून, 2024
25.	मिशन निवासी प्रमुखों का नालंदा का दौरा	19 जून, 2024
26.	बांग्लादेश जनवादी गणराज्य की पूर्व प्रधानमंत्री सुश्री शेख हसीना की राजकीय यात्रा	21-22 जून, 2024
27.	म्यांमार संघ गणराज्य के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री यू थान स्वे की यात्रा	26-27 जून, 2024
28.	बिस्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक 1. श्री मैरिस सांगियाम्पोंगसा, थाईलैंड के विदेश मंत्री 2. डॉ. मुहम्मद हसन महमूद, बांग्लादेश के विदेश मंत्री 3. ल्योनपो डी. एन. धुंग्येल, भूटान की शाही सरकार के विदेश मामलों और बाहरी व्यापार मंत्री 4. श्री थान स्वे, म्यांमार के उप प्रधान मंत्री और विदेश मामलों के मंत्री 5. माननीय थारका बालासुरिया, श्रीलंका के विदेश मामलों के राज्य मंत्री 6. सुश्री सेवा लामसल, नेपाल की विदेश सचिव 7. राजदूत इंद्र मणि पांडे, महासचिव, बिस्स्टेक	12 जुलाई, 2024
29.	तिमोर-लेस्ते के उप प्रधानमंत्री श्री मारियानो असानामी सबिनो की यात्रा	20-27 जुलाई, 2024
30.	भूटान के राजा श्री जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक की यात्रा	22-24 जुलाई, 2024
31.	ब्रिटेन के विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास मामलों के राज्य सचिव श्री डेविड लैमी एमपी की यात्रा	24-25 जुलाई, 2023
32.	राजकुमार रहीम आगा खान और महामहिम राजकुमार अली मुहम्मद आगा खान की यात्रा	26 जुलाई-03 अगस्त, 2024.
33.	वियतनाम के समाजवादी गणराज्य के प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चीन्ह की राजकीय यात्रा	31 जुलाई-03 अगस्त, 2024

क्र. सं.	यात्रा	तारीख
34	सेंट किट्स एंड नेविस (एसकेएन) के विदेश मंत्री डॉ. डेन्ज़िल डगलस का दौरा	04-09 अगस्त, 2024
35	नेपाल के विदेश मंत्री डॉ. आरजू राणा देउबा का दौरा	18-22 अगस्त, 2024
36	मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर इब्राहिम की राजकीय यात्रा	19-21 अगस्त, 2024
37	2+2 वार्ता के लिए जापान की विदेश मंत्री कामिकावा योको और रक्षा मंत्री किहारा मिनोरु की यात्रा	19-21 अगस्त, 2024
38	ब्राजील के संघीय गणराज्य के विदेश मंत्री महामहिम श्री मौरो विप्रा की यात्रा	25-28 अगस्त, 2024
39	19 ^{वाँ} सीआईआई भारत-अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव: मोहम्मद बी.एस. जालो, गाम्बिया के उपराष्ट्रपति कॉन्स्टेंटिनो चिवेगा और जिम्बाब्वे के उपराष्ट्रपति केम्बो मोहदी जेरेमिया कपन कोंग, लाइबेरिया के उपराष्ट्रपति रॉबर्ट हंगले, मॉरीशस के उपराष्ट्रपति प्रोस्पर बाज़ोम्बन्ज़ा, बुरुंडी के उपराष्ट्रपति तियोदोरो न्गुएमा ओबियांग मंगू, इक्वेटोरियल गिनी के उपराष्ट्रपति	20-22 अगस्त, 2024
40	चिली के विदेश मंत्री श्री अल्बर्टो वैन क्लावेरेन की यात्रा	27-31 अगस्त, 2024
41	अबू धाबी के क्राउन प्रिंस महामहिम शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की यात्रा	08-10 सितम्बर, 2024
42	जमैका के प्रधानमंत्री डॉ. एंड्रयू होलनेस ओएन, पीसी, एमपी की भारत यात्रा	30 सितम्बर-03 अक्टूबर, 2024
43	अर्जेंटीना गणराज्य की विदेश मंत्री, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और उपासना सुश्री डायना एलेना मोंडिनो की यात्रा	05-09 अक्टूबर, 2024
44	मालदीव गणराज्य के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद मुहज़ू और प्रथम महिला श्रीमती साजिदा मोहम्मद की राजकीय यात्रा	06-10 अक्टूबर, 2024
45	यूनाइटेड किंगडम की महारानी कंसोर्ट की निजी यात्रा	11-17 अक्टूबर, 2024
46	भूटान के माननीय प्रधान मंत्री दाशो शेरींग तोबगे की यात्रा	20-22 अक्टूबर, 2024
47	जर्मनी के संघीय गणराज्य के चांसलर श्री ओलाफ स्कॉल्ज़ की आधिकारिक यात्रा	24-26 अक्टूबर, 2024
48	वेनेजुएला के बोलिवेरियन गणराज्य की उपराष्ट्रपति सुश्री डेलसी रोड्रिगज़ की यात्रा	25-28 अक्टूबर, 2024
49	डोमिनिका राष्ट्रमंडल के प्रधानमंत्री रूजवेल्ट स्केरिट की यात्रा	25-28 अक्टूबर, 2024
50	नीदरलैंड साम्राज्य के महामहिम राजा विलेम-अलेक्जेंडर की शाही परिवार के सदस्यों के साथ पारगमन यात्रा	26 अक्टूबर, 2024 और 03 नवंबर, 2024
51	महामहिम राजा चार्ल्स तृतीय और यूनाइटेड किंगडम की महारानी कंसोर्ट की निजी यात्रा	27-30 अक्टूबर, 2024
52	स्पेन के प्रधानमंत्री श्री पेद्रो सांचेज़ की उनकी पत्नी के साथ भारत यात्रा	28-30 अक्टूबर, 2024
53	वेनेजुएला के बोलिवेरियन गणराज्य की उपराष्ट्रपति सुश्री डेलसी रोड्रिगज़ की पारगमन यात्रा	30-31 अक्टूबर, 2024
54	थाईलैंड के विदेश मंत्री श्री मैरिस सांगियाम्पोंगसा की यात्रा	31 अक्टूबर -03 नवंबर, 2024
55	भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरींग तोबगे की भारत यात्रा	07 नवंबर, 2024
56	रूसी संघ की सरकार के प्रथम उप प्रधानमंत्री श्री डेनिस मंटूरोव की यात्रा	10-12 नवंबर, 2024
57	सार्क महासचिव श्री मोहम्मद गोলাম सरवर की यात्रा	11-13 नवंबर, 2024
58	सऊदी अरब के विदेश मंत्री महामहिम प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद की यात्रा	12-13 नवंबर, 2024
59	आसियान, बिस्मटेक और प्रशांत देशों के राजदूतों/उच्चायुक्तों की ओडिशा यात्रा	15-16 नवंबर, 2024
60	भूटान के प्रधानमंत्री माननीय दाशो शेरींग तोबगे की यात्रा	24-26 नवंबर, 2024
61	कुवैत राज्य के विदेश मंत्री श्री अब्दुल्ला अली अल-याह्या की यात्रा	03-04 दिसंबर, 2024
62	भूटान के राजा महामहिम जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और महामहिम रानी जेत्सन पेमा वांगचुक की यात्रा	05-06 दिसंबर, 2024

क्र. सं.	यात्रा	तारीख
63	शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान, संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री	11-13 दिसंबर, 2024
64	श्री पाउलो रंगेल, पुर्तगाली गणराज्य के राज्य और विदेश मंत्री	12-15 दिसंबर, 2024
65	श्रीलंका के लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम अनुरा कुमारा दिसानायका की यात्रा	15-17 दिसंबर, 2024
66	मोल्दोवा गणराज्य के उप प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री महामहिम श्री मिहेल पोपसोई की यात्रा	15-17 दिसंबर, 2024
67	नेपाल के विदेश मंत्री माननीय डॉ. आरजू राणा देउबा की यात्रा	19-23 दिसंबर, 2024
68	मॉरीशस गणराज्य के विदेश मामलों, क्षेत्रीय एकीकरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री माननीय धनंजय रामफुल	28 दिसंबर, 2024
69	भूटान के राजा महामहिम जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक की यात्रा	28-29 दिसंबर, 2024

2024 में राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति/प्रधानमंत्री/ विदेश मंत्री द्वारा किए गए दौरे का विवरण

क्र. सं.	देश	तारीख
राष्ट्रपति		
1.	मॉरीशस गणतंत्र	11-13 मार्च 2024
2.	फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर-लेस्ते	05-10 अगस्त 2024
3.	अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी	13-19 अक्टूबर 2024
उपराष्ट्रपति		
1.	इस्लामी गणतंत्र ईरान	22 मई 2024
प्रधानमंत्री		
1.	संयुक्त अरब अमीरात और कतर	13-15 फ़रवरी 2024
2.	भूटान	22-23 मार्च 2024
3.	जी-7 शिखर सम्मेलन के लिए इटली	13-14 जून 2024
4.	रूसी संघ और ऑस्ट्रिया गणराज्य	08-10 जुलाई 2024
5.	पोलैंड और यूक्रेन	21-23 अगस्त 2024
6.	ब्रुनेई दारुस्सलाम और सिंगापुर	03-05 सितम्बर 2024
7.	संयुक्त राज्य अमेरिका	21-23 सितम्बर 2024
8.	लाओ पीपुल्स आर	10-11 अक्टूबर 2024
9.	रूस	22-23 अक्टूबर 2024
10.	नाइजीरिया, ब्राज़िल और गुयाना	16-21 नवंबर 2024
11.	कुवैत	21-22 दिसंबर 2024
ईएएम		
1.	नेपाल	04-05 जनवरी 2024
2.	ईरान	14-15 जनवरी 2024
3.	युगांडा और नाइजीरिया	19-23 जनवरी 2024
4.	ऑस्ट्रेलिया	09-10 फ़रवरी 2024
5.	कोरिया गणतन्त्र और जापान	05-08 मार्च 2024
6.	सिंगापुर, फिलिपींस और मलेशिया	23-27 मार्च 2024
7.	श्रीलंका	20 जून 2024
8.	संयुक्त अरब अमीरात	23 जून 2024
9.	कतर	30 जून 2024
10.	कजाखस्तान	04 जुलाई 2024
11.	मॉरीशस	16-17 जुलाई 2024
12.	लाओ पीपुल्स आर और जापान	25-30 जुलाई 2024
13.	मालदीव	09-11 अगस्त 2024
14.	कुवैत	18 अगस्त 2024
15.	सऊदी अरब, जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड	08 से 13 सितम्बर 2024

क्र. सं.	देश	तारीख
16.	श्रीलंका	04 अक्टूबर 2024
17.	पाकिस्तान	15-16 अक्टूबर 2024
18.	ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर	03-07 नवंबर 2024
19.	संयुक्त अरब अमीरात	14 नवंबर 2024
20.	इटली	24-26 नवंबर 2024
21.	कतर और बहरीन	06-09 दिसंबर 2024
22.	संयुक्त राज्य अमेरिका	25-29 दिसंबर 2024

वर्चुअल शिखर सम्मेलन/कार्यक्रम

क्र. सं.	विषय	तारीख
1.	श्रीलंका और मॉरीशस में यूपीआई सेवाओं का शुभारंभ	13 – 14 फ़रवरी 2024
2.	भारत द्वारा विभिन्न परियोजनाओं का संयुक्त ई-उद्घाटन-मॉरीशस	29 फ़रवरी 2024
3.	वर्चुअल ग्लोबल साउथ समिट	17 अगस्त 2024

अनुलग्नक XI

01 जनवरी से 31 दिसंबर 2024 के दौरान विदेशी मिशन प्रमुखों द्वारा परिचय-पत्र प्रस्तुत करे गए

क्र. सं.	देश	राजदूत/उच्चायुक्त का नाम	परिचय-पत्र प्रस्तुति की तिथि
1.	अज़रबैजान	महामहिम श्री एल्चिन हुसेनली	05.01.2024
2.	लेसोथो	महामहिम सुश्री लेबोहंग वैलेंटाइन मोचाबा	05.01.2024
3.	ज़ाम्बिया	महामहिम श्री पेराय पाटसन चंदा	05.01.2024
4.	श्रीलंका	महामहिम सुश्री क्षेनुकासेनेविरत्ने	05.01.2024
5.	ग्रीस	महामहिम श्रीमती अलिकी कौत्सोमिटोपोलू	05.01.2024
6.	फिलिपींस	महामहिम जोसेल एफ इग्रासियो	27.03.2024
7.	उज़्बेकिस्तान	महामहिम श्री सरदार रुस्तम्बेव	27.03.2024
8.	बेलारूस	महामहिम श्री मिखाइल कास्को	27.03.2024
9.	केन्या	महामहिम श्री पीटर मैना मुन्थिरी	27.03.2024
10.	जॉर्जिया	महामहिम श्री वख्तंग जोशविली	27.03.2024
11.	इक्वाडोर	महामहिम श्री फर्नांडो बुचेली,	31.05.2024
12.	यूनाइटेड किंगडम	महामहिम श्रीमती लिंडी एलिजाबेथ कैमरून	31.05.2024
13.	कुवैत	महामहिम श्री मेशाल मुस्तफा जे अलशेमाली	31.05.2024
14.	न्यूजीलैंड	महामहिम श्री पैट्रिक जॉन राटा	31.05.2024
15.	गिनी गणराज्य	महामहिम श्री अलासेन कॉन्टे	31.05.2024
16.	फिजी	महामहिम श्रीजगन्नाथ सामी	31.05.2024
17.	चीन	महामहिम श्री जू फेइहोंग	31.05.2024
18.	स्पेन	महामहिम श्री जुआन एंटोनियो मार्च पुजोल	11.07.2024
19.	अर्जेंटीना	महामहिम श्री मारियानो अगस्टिन काउसिनो	11.07.2024
20.	सोलोमन द्वीप	महामहिम श्री एंथोनी मकाबो	06.09.2024
21.	नाउरू	महामहिम श्री केन अमांडस	06.09.2024
22.	इटली	महामहिम श्री एंटोनियो एनरिको बार्टोली	06.09.2024
23.	आइसलैंड	महामहिम श्री बेनेडिक्ट हॉस्कूलडसन	06.09.2024
24.	इजराइल	महामहिम श्री रुवेन अजर	06.09.2024
25.	स्विट्ज़रलैंड	महामहिम श्रीमती माया तिसफ्री	18.11.2024
26.	जॉर्डन	महामहिम श्री यूसुफ मुस्तफा अली अब्देल गनी	18.11.2024
27.	पापुआ न्यू गिनी	महामहिम श्री विंसेंट सुमाले	18.11.2024
28.	दक्षिण अफ्रीका	महामहिम प्रोफेसर अनिल सूकलाल	18.11.2024
29.	म्यांमार	महामहिम श्री जॉ ऊ	18.11.2024
30.	मिस्र	महामहिम श्री कामेल जायद गलाल	18.11.2024
31.	इथियोपिया	महामहिम श्री फ़ेसेहा शॉवेल गेबरे	25.11.2024
32.	जापान	महामहिम श्री केइची ओनो	25.11.2024

क्र. सं.	देश	राजदूत/उच्चायुक्त का नाम	परिचय-पत्र प्रस्तुति की तिथि
33.	कोरिया गणतन्त्र	महामहिम श्री ली सेओंग हो	25.11.2024
34.	रोमानिया	महामहिम श्रीमती सेना लतीफ़	25.11.2024
35.	ग्रेनेडा** (ग्रेनेडा में)	महामहिम श्री पसुपुलेटी गीता किशोर कुमार, उच्चायुक्त	25.11.2024
36.	दक्षिण सूडान	महामहिम श्री लुमुम्बा मैकलेलेन्याजोक	11.07.2024
37.	ज़िम्बाब्वे	महामहिम सुश्री स्टेला नकोमो	11.07.2024

अनुलग्नक XII

01 जनवरी से 31 दिसंबर 2024 तक विदेशी मिशन प्रमुखों की अंतिम प्रस्थान स्थिति

क्र. सं.	मिशन	मिशन प्रमुख का नाम	अंतिम प्रस्थान की तिथि
1.	नाउरू गणराज्य	सुश्री मार्लीन इनमविन मोसेस	19.01.2024
2.	क्यूबा	श्री एलेजांद्रो सिमांकस मारिन	19.01.2024
3.	बेलारूस गणराज्य	श्री आंद्रेई रजेउस्की	25.01.2024
4.	अर्जेंटाइन गणराज्य	श्री ह्यूगो जेवियर गोब्बी	10.02.2024
5.	फ़िजी	श्री कमलेश शशि प्रकाश	14.02.2024
6.	दक्षिण सूडान	सुश्री विक्टोरिया सैमुअल अरु	21.02.2024
7.	ज़िम्बाब्वे	डॉ. जी. एम. चिलपरे	06.03.2024
8.	ब्रिटिश उच्चायोग	श्री अलेक्जेंडर वाइकेहम एलिस	28.03.2024
9.	न्यूज़ीलैंड उच्चायोग	श्री डेविड ग्रेगरी पाइन	15.04.2024
10.	सऊदी अरब	श्री सालेह ईद एच. अल-हुसैनी	25.05.2024
11.	पनामा	श्रीमती यासिएल एलाइन्स बुरिलो रिवेरा	14.06.2024
12.	स्पेन	श्री जोस मारिया रिदाओ डोमिंग्वेज़	08.06.2024
13.	इटली	श्री विन्सेन्ज़ो डी लुका	20.06.2024
14.	जॉर्डन हाशमी साम्राज्य	श्री मोहम्मद सलाम जमील ए.एफ. अल-कायेद	18.07.2024
15.	आइसलैंड	श्री गुडनी ब्रैगासन	20.07.2024
16.	इजराइल	श्री नाओर इत्ज़ाक गिलोन	19.08.2024
17.	स्विट्ज़रलैंड	डॉ. राल्फ हेकनर	27.08.2024
18.	जापान	श्री सुजुकी हिरोशी	29.09.2024
19.	मिस्र अरब गणराज्य	श्री वाएल मोहम्मद अवद हमीद	28.09.2024
20.	म्यांमार	श्री मो क्वाव आंग	04.10.2024
21.	कंबोडिया साम्राज्य	श्री कोय कुओंग	05.10.2024
22.	मालदीव	श्री इब्राहीम शाहीब	15.10.2024
23.	कनाडा	श्री स्टीवर्ट रॉस व्हीलर	18.10.2024
24.	कनाडा	श्री पैट्रिक हेबर्ट	18.10.2024
25.	रोमानिया	श्रीमती डेनिएला मारियाना सेजोनोव ताने	25.10.2024
26.	घाना	श्री क्वाकू असोमा-चेरेमेह	23.10.2024
27.	फिलिस्तीन	श्री अदनान एम. ए. अबुलहैजा	28.10.2024
28.	कोरिया	श्री चांग जे बोक्	30.10.2024
29.	श्रीलंका	सुश्री श्रीलंका क्षेनुकासेनेविरत्ते	20.12.2024
30.	बांग्लादेश	श्री मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान	28.12.2024

अनुलग्नक XIII

2024-25 के दौरान मुख्यालय और विदेश में मिशनो में कैडर की संख्या

क्र. सं.	कैडर/पद	मुख्यालय में पद	मिशन में पद	कुल
1.	ग्रेड I	6	29	35
2.	ग्रेड II	11	51	62
3.	ग्रेड III	52	151	203
4.	ग्रेड IV	61	170	231
5.	कनिष्ठ व्यवस्थापक ग्रेड/वरिष्ठ वेतनमान	116	338	454
6.	(i) जूनियर स्केल	20	25	45
	(ii) प्रतिनियुक्ति रिजर्व	76		76
	(iii) छुट्टी रिजर्व	15		15
	(iv) प्रतिनियुक्ति रिजर्व	19		19
	(v) ट्रेनिंग रिजर्व	7		7
	सब टोटल I	383	764	1147
	आईएफएस(बी)			
7.	(i) ग्रेड I	118	126	244
	(ii) प्रतिनियुक्ति रिजर्व	6		6
8.	(i) इंटीग्रेटेड ग्रेड II और III	365	277	642
	(ii) छुट्टी रिजर्व	30		30
	(iii) प्रतिनियुक्ति रिजर्व	16		16
	(iv) ट्रेनिंग रिजर्व	25		25
9.	(i) ग्रेड IV	220	626	846
	(ii) छुट्टी रिजर्व	60		60
	(iii) प्रतिनियुक्ति रिजर्व	54		54
10.	(i) ग्रेड V/VI	173	84	257
	(ii) छुट्टी रिजर्व	60		60
	(iii) प्रतिनियुक्ति रिजर्व	14		14
11.	(i) साइफर कैडर का ग्रेड II	32	76	108
	(ii) छुट्टी रिजर्व	5		5
12.	(i) स्टेनोग्राफर कैडर	523	608	1131
	(ii) छुट्टी रिजर्व	47		47
	(iii) ट्रेनिंग रिजर्व (हिंदी)	10		10
	(iv) प्रतिनियुक्ति रिजर्व	12		12
13.	इंटरप्रेटर कैडर	9	26	35
14.	एलएंडटी कैडर	20	3	23
उप योग II		1799	1826	3625
कुल योग (उप योग I+II)		2182	2590	4772

संकेताक्षर की सूची

ए

एएएलसीओ	एशिया अफ्रीका विधिक सलाहकार संगठन
एबीएएस	एसआईडीएस के लिए एंटीगुआ और बारबुडा एजेंडा
एसीबी	अफगान क्रिकेट बोर्ड
एसीडी	एशिया सहयोग विकास
एसीएमईसीएस	अय्यावडी-चाओ फ्राया-मेकांग आर्थिक सहयोग रणनीति
एसीएमपी	भारत से माल की आवाजाही के लिए चटगाँव और मोंगला बंदरगाहों के उपयोग पर समझौता
एसीटीआरईसी	कैंसर में प्रशिक्षण, अनुसंधान और शिक्षा के लिए उन्नत केंद्र
एडीबी	एशियाई विकास बैंक
एडीएमएम +	आसियान रक्षा मंत्री बैठक प्लस
एईडी	एशिया आर्थिक वार्ता
एईआरबी	परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड
एएफसीएफटीए	अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र
एएफआईएनडीईएक्स	अफ्रीका-भारत अभ्यास
एएफएमएस	सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाएँ
एजी	ऑस्ट्रेलिया समूह
एआईआईए	अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान
एआईआईएमएस	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
एआईडब्ल्यूसी	ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया भारत जल केंद्र
एकेएम	आज़ादी का अमृत महोत्सव
एमआईएक्ससीआईडी	मैक्सिकन एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन
एमएमआर	उन्नत मॉड्यूलर रिक्टर
एएनएमएमआर	राष्ट्रीय समुद्री मामलों का प्राधिकरण, डोमिनिकन गणराज्य
एएनएसटीयू	अफगान राष्ट्रीय कृषि विज्ञान और तकनीकी विश्वविद्यालय
एएनएफ	नेविगेशन फंड के लिए सहायता
एएनआरएफ	अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन
एपीए	एशियाई संसदीय सभा
एपीएमबीसी	एंटी-पर्सनल माइन बैन कन्वेंशन
एपीपीयू	एशिया-प्रशांत डाक संघ
आसियान	दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ
एडीएमएम-प्लस	आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस
एसईएम	एशिया-यूरोप बैठक
एस	अफ्रीका छात्रवृत्ति योजना
एसोचैम	एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
एयू	अफ्रीकी संघ
एवीपी	शैक्षणिक आगंतुक कार्यक्रम

बी

बीएडीपी	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम
बीएआरसी	भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र

बीबीआईएन	बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल (बीबीआईएन)
मोटर वाहन समझौता	मोटर वाहन समझौता
बीबीएनजे	राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे जैव-विविधता
बीसीसीआई	भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड
बीसीजीएसआई	सुरक्षा मुद्दों पर द्विपक्षीय सलाहकार समूह
बीडीएएफ	बांग्लादेश सशस्त्र बल
बीएफडीए	भूटान भूटान खाद्य एवं औषधि प्राधिकरण
बीएचईएल	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
बिम्स्टेक	बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल
बीओआई	आप्रवासन ब्यूरो
बीपीडीबी	बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड
बीपीडब्ल्यूसी	बिम्स्टेक स्थायी कार्य समिति
ब्रिक्स	ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका
बीटीडब्ल्यूसी	जैविक एवं विषैले हथियार सम्मेलन
	सी
सीएजी	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
सीएससी	सामान्य सेवा केंद्र
सीएएमएम	प्रवासन और गतिशीलता पर साझा एजेंडा
सीएआर	मध्य अफ्रीकी गणराज्य
सीएआरआईसीओएम	कैरेबियन समुदाय
सीबीडी कोप 16	जैविक विविधता पर सम्मेलन के लिए पार्टियों का सम्मेलन
सीबीआईसी	केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
सीबीपीआर	सीमा पार भुगतान और रिपोर्टिंग
सीसीसीबी	कमांड और नियंत्रण संगतता बोर्ड
सीसीआईटी	अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने पर सम्मेलन
सीसीयूएस	कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण
सीडी	साइबर कूटनीति
सीडी	निरस्त्रीकरण पर सम्मेलन
सीडीएफ	चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ
सीडीआरआई	आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन
सीडीएससीओ	केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन
सीईसी	केंद्रीय चुनाव आयोग
सीईडीटी	उद्यमिता प्रशिक्षण और विकास केंद्र
सीईआईटी	आईटी उत्कृष्टता केंद्र
सीईएलएसी	लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई राज्यों का समुदाय
सीईपीए	व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता
सीईआरएन	परमाणु अनुसंधान के लिए यूरोपीय संगठन
सीएफएम	मोकामेडिस रेलवे कंपनी
सीजीआईएमए	अवैध समुद्री गतिविधियों पर संपर्क समूह
सीएचजी	सरकार के प्रमुखों की परिषद
सीएचओजीएम	राष्ट्रमंडल सरकार के प्रमुखों की बैठक
सीजेआई	भारत के मुख्य न्यायाधीश

सीआईसीए	एशिया में बातचीत और विश्वास निर्माण उपायों पर सम्मेलन
सीआईआई	भारतीय उद्योग परिसंघ
सीआईएम	वाणिज्य और उद्योग मंत्री
सीआईएस	स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल
सीआईआरडीएपी	एशिया और प्रशांत के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास केंद्र
सीएनईएस	राष्ट्रीय अंतरिक्ष अध्ययन केंद्र (फ्रांसीसी राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी)
सीएनटी	राष्ट्रीय संक्रमण परिषद
सीओएस	सेना प्रमुख
सीओएससीओआर-	विदेश और सामुदायिक संबंध परिषद-कैरेबियाई समुदाय
सीएआरआईसीओएम	
सीओएम	मंत्रिपरिषद
सीओएमईएसए	पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका के लिए साझा बाजार
सीओआरएसआईए	अंतर्राष्ट्रीय विमानन के लिए कार्बन ऑफसेटिंग और न्यूनीकरण योजना
सीपी	कोलंबो प्रक्रिया
सीपीएफ	काउंटर प्रसार वित्तपोषण
सीपीसी	राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन
सीएससी	कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन
सीएसआईएस	रणनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र
सीएसआईआर	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद
सीएसआईआर-एनआईओ	सीएसआईआर-राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान
सीएसएलएम	वाणिज्य सचिव स्तर की बैठक
सीटी	आतंकवाद विरोधी
सीडब्ल्यूसी	रासायनिक हथियार सम्मेलन

डी

डीएई	परमाणु ऊर्जा विभाग
डीबीटी	जैव प्रौद्योगिकी विभाग
डीसीओसी-जेए	जिबूती आचार संहिता-जेद्दा संशोधन
डीडीपी	रक्षा उत्पादन विभाग
डीईए	आर्थिक मामलों का विभाग
डीईडब्ल्यूजी	डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह
डीजीएफटी	विदेश व्यापार महानिदेशालय
डीजीआरआईएस	अंतर्राष्ट्रीय संबंध और रणनीति के लिए महानिदेशक
डीआईए	दस्तावेज जारीकर्ता अधिकारी
डीआईसीएसईपी	संस्कृत महाकाव्यों और पुराणों पर डबरोवनिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन
डीआईजीईएमएपीएस	दवा, खाद्य और स्वास्थ्य उत्पाद महानिदेशालय
डीपीए	विकास भागीदारी प्रशासन
डीपीआई	डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना
डीपीआईआईटी	उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग
डीपीएम	उप प्रधानमंत्री
डीपीआरके	कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य
डीआरसी	कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य
डीआरडीओ	रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन

डीवी डीएवाई
डीडब्ल्यूसीपी
डीडब्ल्यूजी

प्रतिष्ठित आगंतुक दिवस
सभ्य कार्य देश कार्यक्रम
रक्षा कार्य समूह

ई

ईएएम
ईएएस
ईएएस एफएमएम
ईएएस एसओएम
ईबीआरडी
ईसीए
ईसीओएसओसी
ईसीआर
ईसीटीए
ईडीबी
ईईसी
ईईपीसी
ईएफडी
ईजीएंडआईटी
ईएमटीसीटी
ईओआई
ईपीएंडडब्ल्यू
ईपीसीसी
ईपीसीईएस
ईपीसीएच
ईपीसीपी
ईएससी
ईएसजी
ईएसपी
ईयू
ईवी
ई-वीबीएबी
ईडब्ल्यूजी

विदेश मंत्री
पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन
ईएएस विदेश मंत्रियों की बैठक
ईएएस वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक
यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक
निर्यात ऋण एजेंसी
आर्थिक और सामाजिक परिषद
आवश्यक उत्प्रवास जाँच
आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता
आर्थिक विकास बोर्ड
पूर्वी आर्थिक गलियारा
इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद
आर्थिक और वित्तीय वार्ता
ई-गवर्नेंस और सूचना प्रौद्योगिकी
माँ से बच्चे में संचरण का उन्मूलन
भारतीय दूतावास
उत्प्रवास नीति और कल्याण
सांस्कृतिक सहयोग कार्यकारी कार्यक्रम
ईओयू और एसईजेड निर्यात संवर्धन परिषद
हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद
इलेक्ट्रिक प्रणोदन क्षमता भागीदारी
इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद
कार्यकारी संचालन समूह
आर्थिक प्रोत्साहन कार्यक्रम
यूरोपीय संघ
इलेक्ट्रिक वाहन
ई-विद्या भारती आरोग्य भारती
रोजगार कार्य समूह

एफ

एफएबी
एफएएसएफ
एफएटीएफ
एफसीबीडी
एफसीएमएनओ
एफसीएसए
एफई

ब्राज़िल वायु सेना
फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष सेना
वित्तीय कार्रवाई कार्य-बल
वित्त और केंद्रीय बैंक प्रतिनिधि
कॉन्स्टैंसिया मंगु न्सू ओकोमो फाउंडेशन
मुद्रा विनिमय व्यवस्था रूपरेखा
विदेशी नियोक्ता

एफईटी	महिला सहभागिता टीम
एफएफएफसी	मित्र विदेशी देश
एफएफडी4	विकास के लिए वित्तपोषण
फिक्की	भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ
एफआईईओ	भारतीय निर्यात संगठन महासंघ
एफएलएस	अंतिम अवस्थिति सर्वेक्षण
एफएलएस	आधारभूत शिक्षण सर्वेक्षण
एफएमसीबीजी	वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर
एफएमडी	वित्तीय बाजार संवाद
एफएमएफडी	विदेश मंत्रियों की रूपरेखा वार्ता
एफएमएम	फ्रांस मीडिया मॉडे
एफओसी	विदेश कार्यालय परामर्श
एफओजीजी	गिनी खाड़ी के मित्र
एफपीजी	फुकुओका प्रान्तीय सरकार
एफएसबी	वित्तीय स्थिरता बोर्ड
एफएसएसएआई	भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
एफटीएफ	विदेशी आतंकवादी लड़ाके
एफवाईपी	पंचवर्षीय योजना

जी

जीएससीसी	वैश्विक वायु एवं अंतरिक्ष प्रमुखों का सम्मेलन
जीबीए	वैश्विक जैव-ईंधन गठबंधन
जीसीएनईपी	परमाणु ऊर्जा भागीदारी वैश्विक केंद्र
जीसीएम	सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवास के लिए वैश्विक समझौता
जीसीटीएफ	वैश्विक आतंकवाद निरोधक मंच
जीसीटीएस	वैश्विक आतंकवाद निरोधक रणनीति
जीजीई	सरकारी विशेषज्ञ समूह
कानूनों पर जीजीई	घातक स्वायत्त हथियार प्रणालियों के क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों पर सरकारी विशेषज्ञ समूह
जीएमसी	गोवा समुद्री सम्मेलन
जीएमसीओएस	गांधी मंडेला विशेषज्ञता केंद्र
ग्लोबई नेटवर्क	भ्रष्टाचार विरोधी कानून प्रवर्तन प्राधिकरणों का वैश्विक परिचालन नेटवर्क
जीएमसीपी	ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना
जीओएफवीओटी	आतंकवाद के पीड़ितों के मित्रों का समूह
जीओजी	गिनी की खाड़ी
जीओआई-यूएनएससीडीएफ	भारत सरकार-संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग संरचना
जीपीएआई	कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी
जीपीएफआई	वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी
जीएसडीपी	हरित और सतत विकास
जीएससीसी	वैश्विक वायु और अंतरिक्ष प्रमुखों का सम्मेलन
जीएसडीआर	वैश्विक संप्रभु ऋण गोलमेज सम्मेलन
जीएसएल	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड
जीएसएस	वैश्विक मानकीकरण संगोष्ठी

एच

एचएए	उच्च ऊंचाई वाला क्षेत्र
एचएडीआर	मानवीय सहायता और आपदा राहत
एचएएल	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
एचसीसीएच	निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून पर हेग सम्मेलन
एचसीआई	भारतीय उच्चायोग
एचसीओसी	हेग आचार संहिता
एचसीएसएस	रणनीतिक अध्ययन के लिए हेग केंद्र
एचआईसीडीपी	उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना
एचजेसी	उच्च-संयुक्त आयोग
एचएलसीजी	उच्च स्तरीय कोर समूह
एचएलडीएमएम	उत्प्रवास और गतिशीलता पर भारत-यूरोपीय संघ उच्च स्तरीय वार्ता
एचएलपीएफ	उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच
एचएलडब्ल्यू	उच्च स्तरीय सप्ताह
एचआरवीपी	उच्च प्रतिनिधि और उपाध्यक्ष

आई

आईए	कार्यान्वयन समझौता
आईएबीसी	भारत-अर्जेंटीना व्यापार परिषद
आईआईए	अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी
आईएएफ	भारतीय सशस्त्र बल
आईएएफएस	भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन
आईएटीसी	भारत अफ्रीका व्यापार परिषद
आईबीसी	अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ
आईबीसीए	इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस
आईबीएफ	भारत-भूटान फाउंडेशन
आईबीएसए	भारत ब्राज़िल, दक्षिण अफ्रीका
आईसीए	अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन
आईसीएओ	अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन
आईसीसी	अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय
आईसीसीआर	भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद
आईसीईटी	महत्वपूर्ण और उदीयमान प्रौद्योगिकियाँ
आईसीजे	अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय
आईसीएमआर	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद
आईसीएमपीडी	अंतर्राष्ट्रीय उत्प्रवास नीति विकास केंद्र
आईसीपी	आव्रजन जाँच चौकियाँ
आईसीपीआरसीपी	सांस्कृतिक संपत्ति को उसके मूल देश में वापस करने या अवैध विनियोग के मामले में प्रतिपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए अंतर-सरकारी समिति
आईसीआरआईएसएटी	अर्द्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान
आईसीटी	सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी
आईसीडब्ल्यूए	भारतीय वैश्विक परिषद

आईसीडब्ल्यूएफ	भारतीय समुदाय कल्याण कोष
आईडीवाई	अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस
आईईए	अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी
आईईडी	इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस
आईईएसएए	भारत-यूरोपीय विज्ञान एवं कला संघ
आईईटीओ	भारत आर्थिक व्यापार संगठन
आईईडब्ल्यू	भारत ऊर्जा सप्ताह
आईएफसी-आईओआर	सूचना संलयन केंद्र-हिंद महासागर क्षेत्र
आईएफसीपीएआर	उन्नत अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए भारत-फ्रांसीसी केंद्र
आईएफआरईएमईआर	फ्रांसीसी महासागर विज्ञान संस्थान
आईएफटीएम	अंतर्राष्ट्रीय और फ्रांसीसी यात्रा बाजार
आईजीबीएफ	भारत-जर्मन व्यापार मंच
आईजीसी	अंतरसरकारी परामर्श
आईजीएन	अंतरसरकारी वार्ता
आईजीएसटीसी	भारत-जर्मन विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र
आईआईडीईए	अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान
आईआईएफटी	भारतीय विदेश व्यापार संस्थान
आईआईटी	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
आईआईटीएम	भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान
आईएलसी	अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन
आईएलसी	अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग
आईएलओ	अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन
आईएमडी	भारतीय मौसम विज्ञान विभाग
आईएमईसी	भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा
आईएमएफ	अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
आईएमओ	अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन
आईएमआरसी	भारत-मेक्सिको अनुसंधान संघ
आईएमटी	भारत-म्यांमार-थाईलैंड
आईएमटी त्रिपक्षीय राजमार्ग	भारत-म्यांमार-थाईलैंड (आईएमटी) त्रिपक्षीय राजमार्ग
आईएमटी-जीटी	इंडोनेशिया-मलेशिया-थाईलैंड ग्रोथ ट्राएंगल
आईएमडब्ल्यूजी	अंतर-मंत्रालयी कार्य समूह
आईएनएसी	अंतरराष्ट्रीय कला और शिल्प
आईएनबी	अंतर-सरकारी वार्ता निकाय
इंडस एक्स	भारत-अमेरिका रक्षा त्वरण पारिस्थितिकी तंत्र
आईएनआई-सीईटी	राष्ट्रीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा महत्व संस्थान
आईएनएस	भारतीय नौसेना जहाज
आईओसी	हिंद महासागर आयोग
आईओएम	अंतरराष्ट्रीय उत्प्रेवास संगठन
आईओआरए	हिंद महासागर रिम एसोसिएशन
आईपीएसीसी	भारत-प्रशांत सेनाध्यक्ष सम्मलेन
आईपीएएमएस	भारत-प्रशांत मैनेजमेंट सेमिनार
आईपीसीसी	जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनेल

आईपीईएफ	समृद्धि के लिए भारत-प्रशांत आर्थिक ढांचा
आईपीईएन	पेरू परमाणु ऊर्जा संस्थान
आईपीएचईएक्स एलएटीएम	फार्मा और हेल्थकेयर लैटिन अमेरिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी
आईपीएमडीए	भारत-प्रशांत समुद्री डोमेन जागरूकता
आईपीओआई	भारत-प्रशांत महासागर पहल
आईपीयू	अंतर-संसदीय संघ
आईआरईएनए	अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी
आईआरआईजीसी-एमएंडएमटीसी	सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग पर भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग
आईआरआईजीसी-टीईसी	व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक सहयोग के लिए भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग
आईएसए	अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन
आईएसबी	भारतीय बिजनेस स्कूल
आईएसपीएस	अंतर्राष्ट्रीय जहाज और बंदरगाह सुविधा सुरक्षा
इसरो	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
आईटीए	भारत ताइपे एसोसिएशन
आईटीईसी	भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग
आईटीईआर	अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर
आईटीपीओ	भारत व्यापार संवर्धन संगठन
आईटीआरए	कृषि अनुसंधान संस्थान
आईटीयू	अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ
आईयूएसएसटीडी	भारत-अमेरिका सामरिक व्यापार वार्ता
आईवाईएम	अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष

जे

जेएसडीएफ	जापान वायु आत्मरक्षा बल
जेसीईसी	आर्थिक सहयोग संयुक्त समिति
जेसीआईएफएम	बाढ़ और बाढ़ प्रबंधन संयुक्त समिति
जेडीसीसी	संयुक्त रक्षा सहयोग समिति
जे.डी.पी	संयुक्त विकास योजना
जे ई सी	जापानी एंडोव्ड कोर्स
जेईटीआरओ	जापान बाहरी व्यापार संबंध संगठन
जेआईएम	जापान-भारत विनिर्माण संस्थान
जेआईएमईएक्स	जापान-भारत समुद्री अभ्यास
जेआईपीएमईआर	जवाहरलाल सातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान
जेएमसी	संयुक्त मंत्रिस्तरीय आयोग
जेएनपीपी	जैतापुर परमाणु ऊर्जा परियोजना
जेपीओए	संयुक्त कार्य योजना
जेएससी	संयुक्त संचालन समिति
जेएसडीएफ	जापान आत्मरक्षा बल
जेएसटीसी	संयुक्त विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति
जेएसडब्ल्यू स्कूल ऑफ लॉ	जिग्मे सिंग्ये वांगचुक (जेएसडब्ल्यू) स्कूल ऑफ लॉ
जेटीजी	संयुक्त प्रौद्योगिकी समूह
जेडब्ल्यूजी	संयुक्त कार्य समूह

जेडब्ल्यूजी-सीटी
जेडब्ल्यूजी-सीटीटीसी

आतंकवाद-रोधी संयुक्त कार्य समूह
आतंकवाद-रोधी संयुक्त कार्य समूह

के

केआईपी
केएमटीटीपी

भारत को जानें कार्यक्रम
कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना

एल

एलएएडी
एलएसी
एल एंड टी
एलसीएस
एलसीएस
एलडीसीएस
एलआईएफई
एलआईजीओ
एलएलडीसीएस
एलएमए
एलएमआईएस
एलएनजी
एलओसी
एलओसी
एलटीएजी

लैटिन अमेरिकी रक्षा और सुरक्षा प्रदर्शनी
वास्तविक नियंत्रण रेखा
लार्सन एंड टुब्रो
भूमि सीमा शुल्क स्टेशन
स्थानीय मुद्रा निपटान
न्यून विकसित देश
पर्यावरण के लिए जीवनशैली
लेजर इंटरफेरोमीटर गुरुत्वाकर्षण-तरंग वेधशाला
भूमिबद्ध विकासशील देश
श्रम गतिशीलता समझौते
श्रम बाजार सूचना प्रणाली
तरलीकृत प्राकृतिक गैस
ऋण रेखा
नियंत्रण रेखा
दीर्घकालिक आकांक्षात्मक लक्ष्य

एम

एमएचएसआर
एमएएफ
एमआईटीआरआई
एमएएनएजीई
एमएपीएल
एमएआरसीओएस
एमएटीईएस
एमबीसी
एमसीजी
एमडीबी
एमडीटीआई
एमईडीवीएसी
एमएफएफएलआई
एमजीसी
एमआईडीसी
एमआईएफसी
एमआईएफसीओ

मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल
मंगोलियाई सशस्त्र बल
इंडो-पैसिफिक में प्रशिक्षण के लिए समुद्री पहल
राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान
मोतिहारी-अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना
मरीन कमांडो फोर्स
शाली प्रारंभिक-पेशेवरों के लिए गतिशीलता व्यवस्था योजना
मॉरीशस ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन
सैन्य सहयोग समूह
बहुपक्षीय विकास बैंक
व्यापार और निवेश पर मंत्रिस्तरीय वार्ता
चिकित्सा निकासी
मर्क फाउंडेशन प्रथम महिला पहल
मेकांग गंगा सहयोग
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम
मॉरीशस इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर
मालदीव इंडस्ट्रियल फिशरीज कंपनी

एमआईआईएम	मेक इन इंडिया मिटेलस्टैंड
एमआईटी	मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी
एमएलएटी	आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता संधियाँ
एमएमपी	प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी
एमएमपीए	प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी समझौता
एमएनडीएफ	मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल
एमएनआरई	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
एमओए	समझौता ज्ञापन
एमओसीए	नागरिक उड्डयन मंत्रालय
एमओएनयूएससीओ	कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन
एमओएस (एमएल)	भारत की विदेश राज्य मंत्री (मीनाक्षी लेखी)
एमओएस (आरआरएस)	भारत के विदेश राज्य मंत्री (राजकुमार रंजन सिंह)
एमओएस (वीएम)	भारत के विदेश राज्य मंत्री (वी. मुरलीधरन)
एमपीएस	मालदीव पुलिस सेवा
एमपीआई	प्रवासन नीति संस्थान
एमपीएक्स	समुद्री साझेदारी अभ्यास
एमआरसीसी	समुद्री बचाव समन्वय केंद्र
एमएससी	म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन
एमएसडीटीएफ	मॉरीशस सनातन धर्म मंदिर महासंघ
एमएसडीई	विकास कौशल एवं उद्यमिता मंत्रालय
एमएससी	सैन्य सीलिफ्ट कमान
एमएसएमईएस	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
एमटीसीआर	मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था
एमवीआर	मालदीवियन रफिया

एन

एनएएम	गुटनिरपेक्ष आंदोलन
नासा	राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन
एनएसआरडीए	राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान और विकास एजेंसी
एनईए	नेपाल विद्युत प्राधिकरण
एनसीबी	नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो
एनसीसी	राष्ट्रीय कैडेट कोर
एनसीजीजी	राष्ट्रीय सुशासन केंद्र
एनसीएमआरडब्ल्यूएफ	राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र
एनसीक्यूजी	नया सामूहिक परिमाणित लक्ष्य
एनडीसी	राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय
एनडीडीबी	राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड
एनडीएलडी	नई दिल्ली जी20 नेताओं की घोषणा
एनडीवी	परमाणु निरस्त्रीकरण सत्यापन
एनएचपीसी	राष्ट्रीय जलविद्युत निगम
एनआईबीसी	नाइजीरिया-भारत व्यापार परिषद
एनआईबीएसएस	नाइजीरिया अंतर-बैंक निपटान प्रणाली

एनआईएमईटी	नाइजीरिया मौसम विज्ञान एजेंसी
एनआईएमएचएनएस	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान
एनआईओटी	राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान
एनआईएसटी	राष्ट्रीय मानक और प्रौद्योगिकी संस्थान
एनओएए	राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान और वायुमंडलीय एजेंसी
एनपीसीआई	राष्ट्रीय भुगतान निगम भारत
एनआरआई	अनिवासी भारतीय
एनएसए	राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार
एनएसडीसी	राष्ट्रीय कौशल विकास निगम
एनएसआईएल	न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड
एनएसएफ	राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन
एनएसजी	परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह
एनवीवीएन	एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड

ओ

ओसीआई	भारत के विदेशी नागरिक
ओडीओपी	एक जिला, एक उत्पाद
ओईसीडी	आर्थिक सहयोग और विकास संगठन
ओईडब्ल्यूजी	ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप
ओएफए	वन फ्यूचर एलायंस
ओएचसीएचआर	मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त का कार्यालय
ओएनआर	नौसेना अनुसंधान कार्यालय
ओएससीई	यूरोप में सुरक्षा और सहयोग के लिए संगठन
ओपीसीडब्ल्यू	रासायनिक हथियार निषेध संगठन
ओ.आर.पी	तेल रिफाइनरी परियोजना
ओएसओडब्ल्यूओजी	एक सूर्य, एक दुनिया, एक ग्रिड
ओयूएसडी (आरएंडई)	शोध एवं इंजीनियरिंग के लिए अमेरिकी रक्षा अवर सचिव का कार्यालय
ओवीएल	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड

पी

पीएएमईडी	सतत आजीविका सुधार कार्यक्रम
पाससेक्स	पासिंग एक्सरसाइज
पंजाब	प्रसार भारती
पीबीबीवाई	प्रवासी भारतीय बीमा योजना
पीबीसी	शांति स्थापना आयोग
पीबी	प्रवासी भारतीय दिवस
पीबीएसए	प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार
पीकेवीवाई	प्रवासी कौशल विकास योजना
पीसीए	स्थायी मध्यस्थता न्यायालय
पीसीएफडी	विदेशी राजनयिकों के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम
पीसीटीडी	प्रवासी भारतीयों के साथ सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना
पीडीएस	कनाडा के प्रॉस्पेक्टर्स एंड डेवलपर्स एसोसिएशन
पीडीसीटीओ	प्रधान उप मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी

पीडीएनएसए	प्रधान उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार
पीडीओटी	प्रस्थान-पूर्व अभिमुखीकरण प्रशिक्षण
पीजीए	महासभा के अध्यक्ष
पीजीई	प्रवासियों के महासंरक्षक
पीजीआईआई	वैश्विक अवसंरचना और निवेश के लिए साझेदारी
पीजीआईएमईआर	स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान
पीएचएआरएमईएक्ससीआईएल	भारतीय औषधि निर्यात संवर्धन परिषद
पीएचडीसीसीआई	पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
पीएचपीए	पुनात्संगछू जलविद्युत परियोजना प्राधिकरण
पीआईसी	प्रशांत द्वीप देश
पीआईओ	भारतीय मूल के व्यक्ति
पीएमबीजेपी	प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना
पीएमआई	भारतीय स्थायी मिशन
पीओई	डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र
पीओपीएसके	महामारी की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया
पीपीपीआर	प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट
पीपीआर	स्थायी प्रतिनिधि
पीआरआर	अभियोजन, पुनर्वास और पुनः एकीकरण
पीआरआर	परियोजना संचालन समिति
पीएसके	पासपोर्ट सेवा केंद्र
पीएसएलके	पासपोर्ट सेवा लघु केंद्र
पीएसपी	पासपोर्ट सेवा परियोजना
पीटीए	परियोजना बंधी सहायता
पीक्यूआईएस	फाइटो संगरोध निरीक्षण सेवाएँ

क्यू

क्यूसीपीआर	चतुर्भुज व्यापक नीति समीक्षा
क्यूआईएफ	क्वाड इंफ्रास्ट्रक्चर फेलोशिप
क्यूआईपी	त्वरित प्रभाव परियोजना
क्यूएफएमएम	क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक
क्यूयूआईएन	क्वाड निवेशक नेटवर्क

आर

आरए	भर्ती एजेंट
आरएटीएस	क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना
आरसी	पंजीकरण प्रमाणपत्र

आरईसीएएपी	एशिया में जहाजों के खिलाफ समुद्री डकैती और सशस्त्र डकैती का मुकाबला करने पर क्षेत्रीय सहयोग समझौता
आरईटीएपी	नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी कार्रवाई मंच
आरआईएटी	रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू
आरआईआईडीसी	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम
आरआईकेईएन	भौतिक एवं रासायनिक अनुसंधान संस्थान
राइट्स लिमिटेड	रेल इंडिया तकनीकी एवं आर्थिक सेवा लिमिटेड
आरओसी	कांगो गणराज्य
आरपीओ	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय
आरएसडीपी	राखीन राज्य विकास कार्यक्रम
आरवीएनएल	रेल विकास निगम लिमिटेड

एस

एसएडीसी	दक्षिण अफ्रीका विकास सहयोग
एसएजीएआर	क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास
एसएएमएचआईटीए	दक्षिण एशियाई पांडुलिपि इतिहास और पाठ्य संग्रह
एसएटीटीई	दक्षिण एशिया यात्रा और पर्यटन विनिमय
एससीईपी	रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी
एससीएफ	स्टैंडबाय क्रेडिट सुविधा
एससीओ	शंघाई सहयोग संगठन
एससीओसीएचएस	एससीओ राष्ट्राध्यक्ष परिषद
एससीओ आरएटीएस	शंघाई सहयोग संगठन की क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना
एससीओएमईटी	विशेष रसायन, जीव, सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकी
एसडीजी	सतत विकास लक्ष्य
यूएसएसईएएल	अमेरिकी नौसेना समुद्र, वायु और भूमि टीमों
एसईएलएफ	वरिष्ठ सूचीबद्ध नेता मंच
एसईएलएम	अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था नेताओं की बैठक
एसईआरबी	विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड
एसएफएस	स्व-वित्तपोषण योजना
एसजीओएस	सचिवों का क्षेत्रीय समूह
एस.आई.बी.एस	स्वीडन-भारत व्यापार परिषद
एसआईडीएस	छोटे द्वीप और विकासशील राष्ट्र
एसआईसीए	मध्य अमेरिकी एकीकरण प्रणाली
एसआईआई	भारत में अध्ययन
एसआईसीओटी	तमिलनाडु राज्य उद्योग संवर्धन निगम
एसआईपीओ	सिंगापुर-भारत भागीदारी कार्यालय
एसजेवीएल	सतलुज जल विद्युत निगम

एसएलआईडीए	श्रीलंका विकास प्रशासन संस्थान
एसएमआर	लघु मॉड्यूलर रिक्टर
एसओएमएस	मलक्का और सिंगापुर जलडमरूमध्य
एसओपीईसीएम	कैमरून प्रेस और प्रकाशन कंपनी
एसओएसए	आपूर्ति व्यवस्था की सुरक्षा
एसओटीएफ	भावी शिखर सम्मेलन
एसपीडीसी	प्रवासी बच्चों के लिए छालवृत्ति कार्यक्रम
एसपीईईडी	रक्षा में संवर्धित सहभागिता के माध्यम से साझा समृद्धि
एसपीटीसी	सेशेल्स सार्वजनिक परिवहन निगम
एसएसए	सामाजिक सुरक्षा समझौते
एसएसआईएफएस	सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान
एसएसडब्ल्यू	निर्दिष्ट कुशल श्रमिक
एसटीएआर-सी	सौर प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग संसाधन केंद्र
एसटीआईएनटी	अनुसंधान और उच्च शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए स्वीडिश फाउंडेशन
एसटीपी	साओ तोम और प्रिंसिपे

टी

टीएडब्ल्यूजी	विषयगत क्षेत्र कार्य समूह
टीसीसी	सैनिक योगदान देने वाले देश
टीडीसी	त्रिपक्षीय विकास सहयोग
टीईसी	तकनीकी और आर्थिक सहयोग
टीईसीसी	ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र
टीईपीए	व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता
टीआईएफएफ	ताशकंद अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव
टीआईएफएफ	टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव
टीआईआर	ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनल रूटियर
टीओटी	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण
टीपीएफ	व्यापार नीति मंच
टीएसआई	प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल
टीएसयूएल	ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ
टीटीएंडसी	टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कमांड
टीटीसी	व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद

यू

यूडीएचआर	मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा
यूएनआईडीएस	एचआईवी/एड्स कार्यक्रम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम

यूएनसीसीआई	यूएनसीआईटीआरएएल राष्ट्रीय समन्वय समिति भारत
यूएनसीसीटी	संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोधक केंद्र
यूएनसीआईटीआरएएल	अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग
यूएनसीओपीयूओएस	बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर संयुक्त राष्ट्र समिति
यूएनडीसी	संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग
यूएनडीपी	संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
यूएनईपी	संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम
यूएनईएससीएपी	एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग
यूएनईएससीओ	संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन
यूएनएफसीसीसी	जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन
यूएनजीए	संयुक्त राष्ट्र महासभा
यूएनएचआरसी	संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद
यूएनआईडीआर	संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण अनुसंधान संस्थान
यूएनआईडीआरओआईटी	अंतर्राष्ट्रीय निजी कानून एकीकरण संस्थान
यूएनओसीटी	संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोधक कार्यालय
यूएनओडीसी	संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और अपराध कार्यालय
यूएनआरसीसीए	मध्य एशिया के लिए निवारक कूटनीति के लिए संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय केंद्र
यूएनएससी	संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद
यूएनएसजी	संयुक्त राष्ट्र महासचिव
यूपीआई	एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस
यूपीआईटीएस	उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो
यूपीयू	यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन
यूएसडीओडीडीआईयू	अमेरिकी रक्षा विभाग, रक्षा नवाचार इकाई
यूएसएमएससी	अमेरिकी सैन्य सीलिफ्ट कमांड
यूएसटीआर	अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि
यूटीएफ	उथुरुथिलाफाल्हु

वी

वीबीएसएम	वर्चुअल क्रेता विक्रेता मीट
वीडीपीए	वियना घोषणा और कार्रवाई का कार्यक्रम
वीईटी	व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण
वीओजीएसएस	वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट
वीयूसीएल	विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड

डब्ल्यू

डब्ल्यूए	वासेनार व्यवस्था

डब्ल्यूएफपी	विश्व खाद्य कार्यक्रम
डब्ल्यूजीआईएचआर	अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमों में संशोधन पर कार्य समूह
डब्ल्यूएचसी	विश्व हिंदी सम्मेलन
डब्ल्यूएचओ	विश्व स्वास्थ्य संगठन
डब्ल्यूएमसीसी	परामर्श और समन्वय के लिए कार्य तंत्र
डब्ल्यूएमडी	सामूहिक विनाश के हथियार
डब्ल्यूएमओ	विश्व मौसम विज्ञान संगठन
डब्ल्यूएनबीआर	विश्व बायोस्फीयर रिजर्व का नेटवर्क
डब्ल्यूपीएस	महिलाएं, शांति और सुरक्षा
डब्ल्यूटीएसए	विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा

एक्स

एक्सपीडी	बाह्य प्रचार एवं सार्वजनिक कूटनीति

वाई

वाईए	याउंडे वास्तुकला
वाईईपी	युवा विनिमय कार्यक्रम
वाईपीएस	युवा व्यवसायी योजनाएँ

विकास सहायता और एचएडीआर



ऑपरेशन सदभाव



मैत्री परियोजना म्यांमार



जन औषधि केंद्र - मॉरीशस



चिकित्सा खेप - फिजी



आपदा राहत - केन्या

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली

वार्षिक रिपोर्ट 2024

यह वार्षिक रिपोर्ट वेबसाइट पर भी देखी जा सकती है।
www.mea.gov.in